# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 06] चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या : 13

गुरुवार,

17 मार्च 2016

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**

**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)**

**(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोतर

**श्री अध्यक्ष:** नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री मानवेन्द्रसिंह।

**प्रश्न संख्या-253**

श्री मानवेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

### महिन्द्रा सेज (जयपुर) में आरक्षित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन

254. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़):- क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर के महिन्द्रा सेज एरिया में नोन प्रोसेसिंग एरिया के लिए रिजर्व एक हजार एकड़ जमीन में से 500 एकड़ जमीन का लैंड यूज चैंज कर औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बेचने की मन्जूरी दी गई है? यदि हां, तो कब एवं किन आधारों पर? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सेज नियमों के मुताबिक सेज एरिया में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी की थी? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या सुविधाएं कितनी-कितनी जमीन पर कब से उपलब्ध कराई गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गत दो-तीन वर्षों में सेज में निवेशकों का रुझान कम हुआ है? यदि हां, तो क्यों एवं इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उद्योग मंत्री** (श्री गजेन्द्रसिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी नहीं। राज्य ने नोन-प्रोसेसिंग एरिया की हजार एकड़ भूमि में से 500 एकड़ भूमि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को देने के लिए लैंड यूज नहीं बदला है क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा की परियोजना में ग्रामीण क्षेत्र से औद्योगिक, स्पेशल इकोनोमिक जोन में अनुमत अन्य उपयोग एवं मिश्रित भू-उपयोग की स्वीकृति दे दी थी। आदेश की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार की ओर से रीको एवं महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के मध्य दिनांक 04 जुलाई, 2005 को हुए एम.ओ.यू. के अनुसार परियोजना में सेज, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, आवासीय एवं व्यावसायिक सुविधाओं को महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित करनी है। अभी तक महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) मिलिटेड ने 1472.84 एकड़ अधिसूचित भूमि पर सेज विकसित किया है तथा 500 एकड़ भूमि पर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया विकसित कर दिया है।

आई.टी. आधारित सेज (371 एकड़) माह जुलाई, 2008 में कार्यरत हो गया। उसके उपरान्त जून, 2011 में इंजीनियरिंग आधारित सेज (576 एकड़) एवं मई, 2012 में हैंडिक्राफ्ट आधारित सेज (408 एकड़) भी स्थापित कर कार्यशील हो गये।

डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (500 एकड़) माह जून, 2012 में कार्यरत हो गया।

इसके अतिरिक्त 500 एकड़ भूमि पर डोमेस्टिक एरिया और विकसित किया जायेगा। इसके अलावा 446 एकड़ भूमि पर कम्पनी द्वारा सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जायेगा जिसमें आवासीय एवं व्यावसायिक एवं अन्य सुविधाएं भी होंगी। परियोजना का विकास कार्य अभी पूर्ण नहीं है तथा परियोजना अभी कार्यान्वयन में है। कम्पनी ने अभी तक इस परियोजना में निम्न सुविधाएं विकसित की हैं:-

| **सुविधाएं** | **एरिया वर्ग फीट में** |
|---|---|
| कस्टम आफिस | 950 |
| एम्फीथियेटर | 18000 |
| फूड कोर्ट | 22400 |
| जिम और मनोरंजन क्षेत्र | 21500 |
| एटीएम | 360 |
| पुलिस चौकी/पुलिस स्टेशन | 2900 |
| पोस्ट आफिस | 360 |

(श्री गजेन्द्रसिंह)

प्रमुख सुविधाएं वर्ष 2008-09 में ही विकसित कर दी थीं। यहां पर पुलिस स्टेशन भी स्थापित किया है।

(3) वर्ष 2012 के बजट में भारत सरकार ने मिनिमम आल्टरनेट टैक्स (मैट) एवं डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (डी.डी.टी.) सेज पर लागू कर दिया, जिसके फलस्वरूप सेज में निवेशकों का रुझान काफी कम हो गया। इसके परिणामस्वरूप कई विकासकर्ताओं ने अपने सेज परियोजना को निरस्त करवा लिया और जो अधिसूचनाएं जारी हो गयी थीं उन अधिसूचनाओं को वापस लेकर अपने सेज को डिनोटिफाई करवा लिया। राज्य सरकार ने भारत सरकार से सेज पर भी मैट एवं डी.डी.टी. को हटाने के लिए भी निवेदन किया है। पत्राचार की प्रतिलिपियां परिशिष्ट-'स' पर संलग्न हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भिजवाया है उसमें कहीं भी एक पन्ना भी ऐसा नहीं भिजवाया जो सरकार ने एक हजार एकड़ जमीन में से जो नोन-प्रोसेसिंग एरिया घटाया है उसका कोई विवरण या कोई आदेश, आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की, कैबिनेट ने क्या पास किया, एक भी पन्ना, पर्ची मेरे जवाब में नहीं भिजवाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं 04 जुलाई, 2005 को यह सेज का एम.ओ.यू. हुआ, तीन हजार एकड़ थी, एक हजार एकड़ जमीन नो-प्रोसेसिंग के लिए रखी, केन्द्र सरकार की अनुमति थी, केन्द्र सरकार के वाणिज्यिक विभाग और बोर्ड और एप्रूवल के आधार पर यह नोन-प्रोसेसिंग एरिया हुआ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें स्कूल बनना था, हास्पिटल बनना था, पार्क बनना था, जो वहां के लोग रहते हैं उनके लिए सुविधाओं के लिए यह एरिया होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन्होंने बिना वित्त विभाग, बिना विधि विभाग एक हजार के नोन-प्रोसेसिंग एरिया में 446 संशोधित कर दिया, ओपन था 450 एकड़ का उसका 200 कर दिया, कामर्शियल को सौ एकड़ से 45 एकड़ कर दिया, निम्न आय वर्ग का 150 से 66.5 कर दिया, सामान्य वर्ग का सौ 44.6 एकड़ कर दिया और सोशल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बहुत जरूरी है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, स्कूलें हैं, हास्टिपल हैं वो 200 से घटा कर के 89.2 एकड़ कर दिया।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के कारण से उस महिन्द्रा सेज को पांच हजार करोड़ का फायदा हो गया। अगर सरकार किसान से जमीन लेकर के बेचती तो उसको पांच हजार करोड़ रुपये मिलते और महिन्द्रा सेज वाला बेच रहा है तो पूरा का पूरा जो पहले से है उसी में उसका सब कुछ हो गया। यह हमारा सब का नुकसान हुआ है इसलिए मैं आपसे पहला प्रश्न यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया की अनुमति दी है, क्या इस बारे में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के वित्त विभाग, विधि विभाग से अनुमति ली है? और अगर नहीं ली तो किस नियम के तहत आपने कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित करके इसको छूट दी है नोन-प्रोसेसिंग एरिया को प्रोसेसिंग यूनिट, जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बदलने की अनुमति और जो भी अनुमति आपने दी है उसका एक पन्ना भी मेरे को जवाब में क्यों नहीं भिजवाया, इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, यह स्पष्ट करने की कृपा करें, दूसरा क्वेश्चन बाद में।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंशा बिलकुल क्लीयर है और इस सवाल का जो जवाब है, अगर माननीय सदस्य ध्यान से सुनें तो मैं एक पन्ना पढ़ कर आपके सब सवालों का जवाब एक साथ दे दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो महिन्द्रा सेज है इसमें राज्य सरकार का 26 परसेंट स्टेक है और 74 परसेंट महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा का है। तीन हजार एकड़ भूमि की जो मांग करी गयी थी उसमें 2903 Converted land was transferred. जे.डी.ए. ने कन्वर्ट करके मिश्रित यूज के लिए कन्वर्ट करके इन्होंने इनको दी है। शेष जो 97 एकड़ है कोर्ट के विवाद की वजह से यह जो भूमि है अभी और देनी है शेष। 2903 एकड़ महिन्द्रा सेज को दे दी। As per 2005 SEZ Act यह जो तीन हजार एकड़ आयी है इसके अन्दर जो 500 एकड़ है वो डी.टी.ए. के अन्दर अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लिए इसको अलग कर दी गयी।

अब शेष बचा सेज 2500 एकड़। सेज एक्ट कहता है कि जो भी सेज की जमीन आती है उसका कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र आपका प्रोसेसिंग सैक्टर में जाना चाहिए। इसके अन्दर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, प्रोसेसिंग का मतलब कि यह जो 1500 एकड़ है, चारों तरफ आपकी चारदीवारी बनती है,

(श्री गजेन्द्रसिंह)

कस्टम का आफिस आता है and It is meant for export. सेज का मतलब है, मेन फोकस सेज का होता है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो जो 1500 एकड़ है, अगर देखा जाए गवर्नमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि इसके अन्दर 50 परसेंट जाना चाहिए, यह लगभग 60 परसेंट है।

तो पहली चीज जो है कम्पनी ने कोई उल्लंघन नहीं किया, 50 के बजाय 60 प्रतिशत इन्होंने प्रोसेसिंग के अन्दर दे दिया और 500 एकड़ डी.टी.ए. में था और हजार एकड़ नोन-प्रोसेसिंग में है। सेज एक्ट यह कहता है कि नोन-प्रोसेसिंग एरिया के अन्दर जीरो से लेकर मैक्सिमम 50 प्रतिशत तक आप नोन-प्रोसेसिंग में दे सकते हैं।

यह प्रोसेसिंग एरिया जो कि हजार एकड़ है, यह नान प्रोसेसिंग एरिया के अन्दर दिया गया और 1500 एकड़ जैसा मैंने बताया प्रोसेसिंग एरिया के अन्दर दिया गया। 500 गया डीटीए के अन्दर।

अध्यक्ष महोदय, अब इसमें 2013 के अन्दर एक्ट में चेंजेज आये हैं, उन्होंने कह दिया कि 2500 एकड़ के बजाय अब हम सेज को 1250 की मान्यता देते हैं। यह एक नया एक्ट आया है। इसके तहत अगर देखा जाये तो प्रोसेसिंग जो एरिया है वह 625 ही बैठता है। अभी कंपनी ने एप्लाई नहीं किया और न ही उनकी कोई मंशा है।

यह आप कह रहे हैं कि नान प्रोसेसिंग जो हजार एकड़ एरिया है, इसके अन्दर 500 एकड़ इन्होंने डीटीए-2 इंडस्ट्रीज के लिए दिया। देने का कारण यह है कि चाहे कोई भी सेज हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो, मेन जो मुद्दा होता है वह यह कि इंडस्ट्रीज को कैसे लाया जाये, रोजगार कैसे बढ़ाया जाये और स्टेट को इनकम कैसे हो। यह जो नान प्रोसेसिंग एरिया हजार एकड़ है, इसके अन्दर 500 एकड़ वह इन्होंने डीटीए-2 को असाइन कर दिया। डीटीए-1, 500 और 500 डीटीए-2 एवं नान प्रोसेसिंग 446 एकड़ है। नान प्रोसेसिंग के अन्दर आपके यह सब चीजें आ जाती हैं। रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है, कामर्शियल एरिया, माल, मल्टीप्लैक्स, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, हास्पिटल यह सब आ जाता है। 54 एकड़ कोर्ट के फैसले की वजह से जेडीए को सरेंडर करनी पड़ी।

अब जो वर्तमान में स्थिति है, वह ऐसी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें सिम्पल गणित का मामला है। कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है, 3 हजार एकड़ जो जमीन है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): गणित का ही पूछ रहा हूं।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (उद्योग मंत्री): 3 हजार एकड़ जमीन है, राइट? उसके अन्दर 1500 प्रोसेसिंग में है। आप मेरी बात सुन लीजिये। दोबारा फिर पूछ लीजियेगा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, बात सही है। आप इतना बता दो कि आपने क्या आदेश जारी किया? आपके विभाग ने कब, क्या किया? यही पूछा है पहले प्रश्न में मैंने तो। वह तो बताओ न।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (उद्योग मंत्री): नहीं, नहीं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 3 हजार हैं, सेज के नियम बदल गये, क्या हो गया, छोड़ो उसको, सबको पता है। मैं तो इतना सा पूछ रहा हूं कि आपने क्या किया? कौनसा आदेश पारित किया? कैबीनेट में क्या अप्रूवल ली? यही पूछा है मैंने तो।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (उद्योग मंत्री): विभाग ने कोई आदेश नहीं दिया इसके अन्दर। इसके अन्दर कम्पनी ने as per rules, अब आप एक मेरी बात और सुन लें, कि जो 3 हजार एकड़ है, उसके अन्दर वर्तमान में 1500 प्रोसेसिंग एरिया है, उसके अन्दर डीटीए-1 आ गया 500, डीटीए-2 आ गया 500, नान प्रोसेसिंग आ गया 446 और जेड़ीए को दिया 54 एकड़।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आपका टोटल सैट-असाइड़ एरिया जो फैसेलिटीज के लिए है, ओपन फैसेलिटीज के लिए रोड, नालियां, सीवरेज सब हैं, वह है 35 परसेंट। उसका कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है। वह 35 परसेंट का 35 परसेंट ही है। उसके अनुसार चल रहे हैं। 65 परसेंट जो एरिया है वह आपका यूजेबल एरिया है।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न, नम्बर दो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं केवल आपके माध्यम से इतना चाहता हूं मंत्रीजी से कि अगर वहां नान प्रोसेसिंग एरिया एक एकड़ भी रखने की जरूरत नहीं थी तो आपने एमओयू फिर एक हजार रखने का 2005 में क्यों किया। सेज का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यापारी को फायदा दे दो। सेज का मतलब है इनवेस्टर आयें, इनवेस्टमेंट आयें और रोजगार मिले। वहां जो रोजगार के लिए आयें, वहां जो रहने वाले हैं उनको नान प्रोसेसिंग एरिया में सुविधाएं मिलें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एमओयू में आपने डेढ़ लाख लोगों को रोजगार देने की बात की, 2005 से लेकर के 11 साल हो गये 5 हजार लोगों को भी रोजगार मिला नहीं। ऐसी सूरत में आप कह रहे हैं कि एक एकड़ भी रखने की जरूरत नहीं है, वह चाहे तो पूरा का पूरा कर सकता है, फिर 446 क्यों रख रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री महोदय कि इस जमीन को अगर कंपनी से, महिन्द्रा सेज से आप ले लेते, जब आप कह रहे हो कि सेज के नियमों में बदलाव आ गया, यह 2013 में आया है। आपके ही नहीं आया है, 2005 का एमओयू आपका स्टैंड कर रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: सवाल कीजिये, सवाल कीजिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपने मेरा जवाब नहीं दिया कि क्या आपने विधि विभाग से राय ली? क्या आपने वित विभाग से राय ली? इस कंपनी के डायरेक्टर कौन हैं? इसके अध्यक्ष कौन हैं? उन लोगों ने महिन्द्रा सेज को फायदा देने के लिए जो सुविधाओं का क्षेत्र था एक हजार एकड़ जमीन का, उसको 446 किया है। आपके जवाब से तो यह लगता है कि 446 को आप इस 3 साल के अन्दर खतम कर दोगे क्योंकि आप खुद कह रहे हो।

**श्री अध्यक्ष**: सवाल कीजिये। सवाल कीजिये। आपका सवाल कीजिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सवाल यही है। ठीक है साहब, आपकी अनुमति है तो। सवाल यही है मंत्रीजी कि जब पहले से 10-11 साल में कंपनी ने सुविधाएं वहां विकसित नहीं कीं, न तो पार्क है, न स्कूल है, न सड़क है और न ही रोजगार मिल रहे हैं। 5-6 हजार की आप बात कर रहे हैं। डेढ़ लाख का एमओयू किया था। यह 5 हजार करोड़ का राज्य की जनता का घाटा आपने किस नियम और गाइड लाइन के आधार पर किया? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

वित विभाग को और ला डिपार्टमेंट को आपने क्यों नहीं इनवाल्व किया। क्यों नहीं राय ली, यह मैं पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो वहां पर लगभग 11 हजार लोग काम कर रहे हैं, 5 हजार ही नहीं कर रहे हैं। आपको मैं करैक्ट करना चाहूंगा। दूसरा, महिन्द्रा सेज को एक आप्शन था

(श्री गजेन्द्रसिंह)

कि अगर वह चाहती तो नान प्रोसेसिंग एरिया की जो जमीन है वह रेंजीडेंशियल में भी दे सकती थी, वह जमीन को कामर्शियल यूज के लिए भी दे सकती थी। जहां के भाव लगभग 8 हजार रुपये पर स्क्वायर मीटर से लेकर लगभग 10-11 हजार रुपये स्क्वायर मीटर है। जबकि इंडस्ट्रियल प्लाट्स की रेट वहां पर 5 हजार रुपये स्क्वायर मीटर है। वह इनके पास आप्शन था।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सुविधाएं विकसित कर दीं क्या उन्होंने? उन्होंने सुविधाएं विकसित कर दीं क्या? मैं यह पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**: मैं आपको जवाब नहीं दिलाऊंगा। बार-बार डिस्टर्ब किया तो I will ask Minister not to reply. बैठिये।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (उद्योग मंत्री): डोमेस्टिक टैरिफ जो एरिया है 500 एकड़ जो दिया, वह चाहते तो वह 500 एकड़ नहीं देकर के उनको कामर्शियल में यूज कर लेते। वह उन्होंने नहीं किया। as per all norms of SEZ Act इसके अन्दर किसी तरह की एबनार्मेलिटी या किसी तरह का उल्लंघन इसके अन्दर नहीं किया गया है।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न, श्री हबीबुर्रहमान।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब ही नहीं आया। मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं। मेरे दोनों पूरक प्रश्नों का जवाब नहीं।

**श्री अध्यक्ष**: हां, हबीबुर्रहमान।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी अंबुजा की यूनिट लगनी थी।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं, इससे रेलेवेंट नहीं है।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 वर्ष हो गये वहां यूनिट नहीं लग रही है। वहां लोग बेकार हो गये, किसान बेकार हो गये, मंत्रीजी।

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो। अंबुजा नहीं आयेगा। अंबुजा इधर नहीं आयेगा। बैठो, आप। श्री रमेश।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर): बरसों हो गये, अंबुजा नहीं लग रही है। लोग बेकार हो गये, रोजगार नहीं मिल रहा है। मंत्रीजी इसका जवाब देंगे।

**श्री अध्यक्ष:** आप बैठिये। अंबुजा नहीं आयेगा। यह प्रश्न सेज का है। बैठिये, आप बैठिये।

**श्री रमेश** (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के निर्धारित सेज के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका भी उल्लंघन क्यों किया? घरेलू उद्योगों को बढ़ाने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई? 2011-12 में जो डीडीटी टैक्स लगाया है, 2006 से अब तक कोई डवलपमेंट ही नहीं हो पाया, निवेश नहीं ला पाये, उसके बाद उनके ऊपर जो पैनल्टी लगाई है, वह भी वसूल क्यों नहीं की? मंत्रीजी बतायें।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय मंत्री महोदय।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सेज को अभी जो सैट बैक लगा है, कोई महिन्द्रा सेज ने अभी इतनी भारी कमाई नहीं की है, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका कारण है कि एक तो ग्लोबल स्लो डाउन हुआ है। रिसेशन की वजह से सब जगह मंदी चल रही है, चाहे वह प्रोपर्टीज हों, चाहे कोई भी बिजनस हो, अभी मंदी का दौर चल रहा है। उसके अलावा केन्द्र ने जो इंसेंटिव्ज दिये थे, जिसके अन्दर पहले इन्होंने इनकम टैक्स बैनेफिट दिया था, सर्विस टैक्स एग्जम्पशन दिया था, एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन दिया था, यह सब वापिस ले लिये गये। इसके अन्दर मैट टैक्स लगा दिया। डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा दिया। इसमें इनवेस्टर्स का कांफिडेंस गिरा है। यह जो सब कुछ हुआ है वह केन्द्र में आपकी सरकार थी, तभी हुआ है।

**श्री अध्यक्ष:** विराजो। पूरक प्रश्न, श्री अजीत सिंह।

**श्री रमेश** (सपोटरा): इसने सेज के नियमों का उल्लंघन क्यों किया? इसका जवाब दो मंत्रीजी। मेन बात तो यह है, उसको बताओ, उसने सेज के नियमों को फालो क्यों नहीं किया?

**श्री गजेन्द्रसिंह** (उद्योग मंत्री): कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। आप बतायें, कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

**श्री रमेश** (सपोटरा): आपने नियमों को दरकिनार करते हुए 5 हजार करोड़ का फायदा पहुंचाया है महिन्द्रा सेज को।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्रीजी, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जवाब देने की आवश्यकता नहीं है अब इसमें।

**श्री रमेश** (सपोटरा): आवश्यकता कैसे नहीं है। जवाब दे ही नहीं रहे हैं सही।

**श्री अध्यक्ष**: दे दिया उन्होंने जितना है।

**श्री रमेश** (सपोटरा): असत्य जवाब दिया है।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, आपके हिसाब से जवाब नहीं आयेगा। मिनिस्टर जो जवाब देगा वही सुनना पड़ेगा। आप कहो कि गलत आया कि सही आया, यह आप नहीं कह सकते हैं। दूसरे प्रोसेस हैं विषय को। नो, अजीत सिंह ... (व्यवधान) बैठो।

**श्री अजीत सिंह** (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014, इसमें आयल इंडस्ट्रीज को नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**: नो, नो, नो, नोट अलाउड। सैकंड प्रश्न, श्री बच्चूसिंह। (व्यवधान)

## बयाना में संचालित ग्रामीण बसें

255. **श्री बच्चू सिंह** (बयाना): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बयाना में कितनी ग्रामीण बसें किस-किस मार्ग पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौनसे गांव हैं, जो ग्रामीण बस सेवा से वंचित हैं? क्या सरकार उक्त गांवों में ग्रामीण बस सेवा संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में गांव बसई से भरतपुर व बयाना हेतु ग्रामीण बस संचालित थी, जो कि अब बंद कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उसको पुन: चलाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रूदावल से करौली वाया बयाना बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि बंशी पहाड़पुर से जयपुर चलने वाली दो बसें शाम को रूदावल एवं बयाना ही रूक जाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनको नियमानुसार बंशी पहाड़पुर से जयपुर तक समय पर चलाने का विचार रखती है?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**राज्य मंत्री, परिवहन** (श्री बाबूलाल वर्मा): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बयाना में 6 ग्रामीण बसें संचालित हैं जिनका मार्गवार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में निगम एवं ग्रामीण बस सेवा से वंचित गांवों का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त वंचित गांवों में ग्रामीण बस सेवा संचालित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) जी नहीं। पूर्व में गांव बसई में भरतपुर, बयाना हेतु कोई ग्रामीण बस सेवा संचालित नहीं रही अपितु भरतपुर आगार द्वारा पूर्व में भरतपुर से बंशी पहाड़पुर तक निगम सेवा संचालित की जा रही थी किन्तु जनता की मांग पर भरतपुर आगार द्वारा भरतपुर से बंशी पहाड़पुर तक संचालित निगम सेवा का वृद्धिकरण बंशी पहाड़पुर से बसई तक कर दिया गया था। उक्त सेवा बंशी पहाड़पुर से सायं 07.30 पी.एम. पर पहुंचकर बसई रात्रि विश्राम करती थी एवं बसई से प्रातः 05.30 बजे प्रस्थान कर बसई से बंशी पहाड़पुर, रूदावल भरतपुर मार्ग पर संचालित होती थी। बसई से बंशी पहाड़पुर के मध्य पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलने से वर्तमान में सेवा का संचालन बसई तक नहीं किया जाकर बंशी पहाड़पुर तक ही किया जा रहा है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण बसई से बंशी पहाड़पुर एवं बंशी पहाड़पुर से बसई तक सेवा संचालित किए जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(4) निगम के सीमित संसाधनों के कारण रूदावल से करौली वाया बयाना बस चलाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(5) जी नहीं। जयुपर-बंशी पहाड़पुर पूर्व में दो सेवाओं का संचालन किया जा रहा था परन्तु रूदावल से बंशी पहाड़पुर के मध्य कम आय होने के कारण सेवा का संचालन रूदावल तक ही कर दिया गया था। वर्तमान में जन प्रतिनिधियों एवं जनता की मांग पर दौसा आगार द्वारा जयपुर से बंशी पहाड़पुर एवं बंशी पहाड़पुर से जयपुर तक एक सेवा का संचालन निम्नानुसार किया जा रहा है-

| | |
|---|---|
| 1. जयपुर से बंशी पहाड़पुर | 13.00 बजे |
| 2. बंशी पहाड़पुर से जयपुर | 06.00 बजे |

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

**श्री बच्चू सिंह** (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताऊंगा।

**श्री अध्यक्ष**: आप सवाल कीजिए बताइये मत।

**श्री बच्चू सिंह** (बयाना): बंशी पहाड़पुर से दो बस चलती थीं जयपुर वाली तो एक बस जैसे स्टोप करती है रात में बयाना में तो वही पुनः बंशी पहाड़पुर चले और एक बस और चलती है बंशी पहाड़पुर से भरतपुर और अलवर होते हुए तो वह कभी रूदावल रुक जाती है, कभी स्टेशन पर रुक जाती है और वह पूर्ण रूप से वहां पर पहुंच नहीं पाती है। मिंसमां से भरतपुर चलती है बस एक, वह भी बंद की गई है और एक नई मांग है हमारी रूदावल से करौली वाया बयाना, हिंडौन होने हुए करौली से नई बस चले। क्या ये बसें चलाने के लिए मंशा रखते हैं इसका जवाब दें। हमारे दो बस स्टैंडों की मांग है बयाना और रूपवास, उसको बनाना चाहते हैं या नहीं?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री बाबूलाल वर्मा** (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बयाना विधान सभा क्षेत्र एक नगरपालिका क्षेत्र भी है और बहुत बड़ा कस्बा भी है। वहां से 82 बसें तो अप साइड में चलती हैं और 77 बसें डाउन साइड में चलती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस जगह के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है कि रूदावल से बयाना होते हुए करौली जाने के लिए, करौली से बयाना की भी लगभग 13 बसों की सर्विस है, 13 बसें करौली और बयाना के बीच चलती हैं और बयाना से रूदावल के बीच में भी हमारी दो सर्विसेज चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जयपुर से रूपवास जो बस चल रही है वह बयाना रूदावल होकर ही निकलती है और वह शाम को 6 बजे बयाना पहुंचती है और रूदावल 6.45 बजे शाम को पहुंचती है। रूदावल से बयाना जो सुबह सवा छह बजे चल कर सुबह 7 बजे पहुंचती है। इसी प्रकार जयपुर से बंशी पहाड़पुर जो बस जाती है वह भी बयाना रूदावल होकर जाती है, वह बस शाम को 7 बजे पहुंचती है बयाना और 7.45 बजे शाम को पहुंचती है रूदावल। इसी प्रकार वही बस सुबह 7.15 बजे रूदावल से चलकर सुबह 8 बजे बयाना पहुंचती है। रूदावल भरतपुर और बंशी पहाड़पुर के बीच में एक छोटा सा कस्बा है। यह बात सही है लेकिन डाइरेक्ट बस इतनी ज्यादा नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भरतपुर से रूदावल भी सर्विस है और करौली से बयाना भी सर्विस है, डाइरेक्ट

(श्री बाबूलाल वर्मा)

दो सर्विसेज चलती हैं, फिर भी माननीय सदस्य ने यदि कोई बात कही है तो जो सुझाव देंगे उसको मैं एक बार दिखवा लूंगा और उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नम्बर दो, बच्चूसिंहजी।

**श्री बच्चू सिंह** (बयाना): मेरे दो बस स्टैंडों की मांग है उस पर क्या कहना चाहते हैं?

**श्री अध्यक्ष**: मांग क्या, सवाल कर लीजिए।

**श्री बच्चू सिंह** (बयाना): बस स्टैंड खुलवाने की मांग है।

**श्री बाबूलाल वर्मा** (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बस स्टैंड जो माननीय सदस्य ने कहा है वह एक जैन ट्रस्ट के माध्यम से एक बस स्टैंड वहां चलाया जा रहा है उसको रोडवेज के द्वारा 1300 रुपये महीने के किराये से वहां चल रहा है और नियमित रूप से उसको किराये का भुगतान किया जा रहा है। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यदि वहां की नगरपालिका या अन्य के द्वारा कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर हम पूरा विचार करके कार्यवाही करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न, श्री प्रहलाद गुंजल।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से केवल इतना जानना चाहूंगा, बहुत छोटा सा सवाल है, हमेशा ही सदन में परिवहन सेवाओं को लेकर चर्चा होती है इस रूट पर बस नहीं चलती, इस रूट पर बस नहीं चलती। भारत सरकार विचार कर रही है कि निजी क्षेत्र को रूट फ्री कर दिया जाए, क्या राजस्थान में भी यह विचार रखते हैं?

**श्री अध्यक्ष**: आप इधर-उधर मत जाइए, बयाना से सम्बन्धित सवाल है।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): उसी से सम्बन्धित सवाल है। एक छोटा सा पालिसी मैटर से सम्बन्धित कि क्या राजस्थान में निजी क्षेत्र को रूट फ्री करने की योजना रखती है ताकि प्रतिस्पर्द्धा होगी तो सबको सेवा मिलेगी?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री बाबूलाल वर्मा** (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों भी माननीय मंत्रीजी ने इस बारे में, लोक परिवहन सेवा के बारे में

(श्री बाबूलाल वर्मा)

जवाब दिया था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान सरकार की मंशा है कि राजस्थान के लोगों को सस्ती परिवहन सेवाएं सुलभ रहे और उसी के तहत 776 मार्गों का जो डीनेशनलाइजेशन करने का जो डिसीजन लिया था उसके तहत लोक परिवहन सेवाओं को प्रारम्भ भी किया है। यह बात सही है कि कम मात्रा में चल रही है लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी भी है और दायित्व भी है और उसमें हम निश्चित रूप से इस प्रकार की सेवाओं को चालू रखने का विचार करते हैं। इसके लिए माननीय केन्दीय मंत्रीजी ने कमेटी भी बना दी है और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही भी करेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न, श्री भजन लाल जाटव।

**श्री भजन लाल** (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि पूर्व में बयाना से कलसाड़ा, बयाना से खेड़ला और बयाना से महुआ निगम की बसें चलती थीं किस कारण से वह बंद कर दी गई और वहां पीपीपी माडल की बसें चालू कर दी गई, इसका जवाब दें मंत्री महोदय।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री बाबूलाल वर्मा** (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वैर विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, वैर विधान सभा क्षेत्र को क्रोस करके ही बयाना विधान सभा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पीपीपी माडल पर दौसा डिपो की चार क्लस्टर चल रही हैं, एक क्लस्टर की जो सेवा चल रही है उसकी ...(व्यवधान) मैंने कोई गायब नहीं किया, मेरे पास सब चीजों का जवाब है।

**श्री अध्यक्ष**: जवाब ठीक ढंग से दे रहे हैं, देने दीजिए।

**श्री बाबूलाल वर्मा** (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा में 2 क्लस्टर संचालक हैं जिनकी पीपीपी माडल पर बस सेवाएं चल रही हैं जो आपके स्टार रूरल बस लिंक सर्विस उसमें जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया है वह वैर विधान सभा क्षेत्र से होकर ही जाती है लेकिन बयाना विधान सभा क्षेत्र में दौसा डिपो की 157 ग्राम पंचायतों को पीपीपी माडल से जोड़ा गया है और दूसरा जो हमारा क्लस्टर संचालक है प्रशांत इलेक्ट्रोनिक्स जो कि पीपीपी माडल पर बस चला रहा है उसके 6 मार्गो पर 61 पंचायतों को जोड़ा गया है। इस प्रकार मैक्सिमम, यह बात सही है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस पीपीपी माडल की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य वह

(श्री बाबूलाल वर्मा)

2011-12 का अनाउंसमेंट है। 2011-12 के अनाउंसमेंट में यह योजना बनी कि निगम की सेवाओं से वंचित, परिवहन संवाओं से वंचित जो पंचायतें हैं उनको जोड़ने की एक योजना बनाई गई 2011-12 में, वर्तमान में जो स्थिति है वह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 जिलों में 68 क्लस्टर्स के माध्यम से 243 मार्गों पर 1379 ग्राम पंचायतों को पूरे राजस्थान में जोड़ा गया है। और वर्तमान में 6437 ग्राम पंचायतें हैं, निगम सेवा से, पीपीपी माडल से इन सबको जोड़कर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

**श्री भजन लाल** (वैर): मंत्रीजी, मैं बयाना की बात कर रहा हूं पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा। मैं बयाना की बात कर रहा हूं, सिर्फ बयाना की बात बताएं कि वे बसें क्यों बंद कर दी गयीं? बयाना से कलसाड़ा, महुवा से खेड़ला होते हुए निगम की बस जाती थी वो किस रूप में किस कारण से बंद कर दी गयी? एक भी बस वहां पर आज की डेट में उपलब्ध नहीं है, वहां की आम जनता परेशान हो रही है। एक भी बस छोकरवाड़ा से लेकर बयाना तक नहीं है, बयाना से लेकर भरतपुर तक नहीं है। किस कारण से ये बसें बंद कर दी गयीं उसका जवाब दें।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए। पाइंटेड सवाल है, पाइंटेड जवाब दें।

**श्री बाबूलाल वर्मा** (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बयाना, कलसाड़ा, जयपुर, हिण्डौन आगार द्वारा बस संचालित है। जो माननीय सदस्य ने कही कलसाड़ा वाली, वो बस वर्तमान में चल रही है।

**श्री भजन लाल** (वैर): यह बिलकुल असत्य बात है। एक भी बस उस रूट पर नहीं चल रही है।

**श्री अध्यक्ष**: अब बैठिए।

**श्री भजन लाल** (वैर): बिलकुल असत्य बात है, बिलकुल नहीं चल रही है।

**श्री अध्यक्ष**: श्री शत्रुघ्न गौतम।

**श्री शत्रुघ्न गौतम** (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सरवाड़ में ग्रामीण बस सेवा ...

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, नहीं, बयाना से सम्बन्धित है। बयाना से सम्बन्धित है।

**श्री शत्रुघ्न गौतम** (केकड़ी): ग्रामीण बस सेवा से सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है ग्रामीण बस सेवा से...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** बिलकुल नहीं है। डा. राजकुमार शर्मा। सवाल रिलेवेंट होना चाहिए।

## नवलगढ़ के गांव/ढाणियों में स्थापित आर.ओ. प्लांट

**256. डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने गांव/ढाणी भूजल में अधिक फ्लोराइड व लवणता की समस्या से ग्रस्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांव/ढाणियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में कितने गांव/ढाणियों में आर.ओ. प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित था तथा उसके विरुद्ध कितने गांव/ढाणियों में आर.ओ. प्लांट स्थापित किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2015-16 में किन-किन गांव/ढाणियों में आर.ओ. प्लांट स्थापित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री** (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) भारत सरकार की वैबसाइट समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 10.03.2016 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के कुल 20,391 ग्राम एवं ढाणियां भू-जल में फ्लोराइड एवं लवणता की आधिक्यता से प्रभावित हैं । जिलेवार वांछित विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2000 आर.ओ. संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित था तदनुसार 2115 आर.ओ. संयंत्र निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी। प्रथम चरण में 750 से अधिक की आबादी के चयनित ग्राम/ढाणी को लाभान्वित करने हेतु 1066 आर.ओ.संयंत्र की स्थापना के कार्यादेश माह फरवरी, 2016 में जारी किये जा चुके हैं इनका कार्य प्रगति पर है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। द्वितीय चरण में 1049 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण की निविदा प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1000 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी जिसके क्रियान्वयन का कार्य अन्तिम चरण में है । इसके तहत आज दिनांक तक 15 जिलों में 831 आर.ओ. संयंत्र कार्यशील हैं जिलेवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है ।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ग्राम/ढाणियों के स्थानीय भू-जल स्रोतों में टी.डी.एस. की मात्रा 1500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने के कारण इस विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं इससे पूर्व के वर्षों में आर.ओ. संयंत्र के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न डा. राजकुमार।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2015-16 में 2 हजार आर.ओ. प्लांट लगाने की घोषणा की गयी थी। अप्रैल से लेकर जनवरी तक पूरे 10 महीने तक इस विभाग के अधिकारियों ने, मंत्रालय ने इस पर कोई काम नहीं किया। फरवरी माह में 2 हजार में 1066, जैसा मंत्री महोदया ने बताया, आर.ओ. संयंत्र लगाने के कार्यादेश जारी किये। मैं जानना चाहूंगा कि कार्यादेश जारी करने में 10 माह के विलम्ब के क्या कारण हैं और शेष जो 1049 आर.ओ. संयंत्र आपने प्रक्रियाधीन बताये हैं इनके कार्यादेश कब तक जारी कर दिये जाएंगे? कार्यादेश के साथ-साथ 2115 आर.ओ. संयंत्र कब तक स्थापित कर दिये जाएंगे।

मंत्री महोदया, आपने प्रश्न के भाग 3 में नवलगढ़ के ग्राम/ढाणियों के लिए कहा है कि स्थानीय भूजल स्रोतों में टीडीएस की मात्रा 1500 मिलीग्राम से कम है। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर भूजल स्तर नीचे चला गया है। मैं राजस्थान की बात नहीं करूंगा मंत्री महोदया, सिर्फ नवलगढ़ की बात करूंगा। या तो अधिकारियों ने आपको गलत जानकारी दी है, गलत इसलिए नहीं मानता कि आप जैसी समझदार और इंटेलिजेंट मंत्री के सामने कोई अधिकारी झूठे तथ्य पेश कर दे तो मैं नहीं समझता कि उस अधिकारी को आपके विभाग में रहना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: सवाल कीजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): मैं सवाल ही कर रहा हूं, क्योंकि जो भी जवाब अधिकारियों ने पेश किये, इस मामले में नवलगढ़ के लिए बोलना चाहता हूं वे सब के सब मिथ्या हैं। मैं नाम गिनाना चाहता हूं आपको। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है चिराना, बागोरिया की ढाणी, पहाड़िला, रामपुरा, भोजनगर, बारवा, देवपुरा बणी, मोहनवाड़ी, खिरोड़, ऐसे मैं आपको 50 गांव/ढाणियों के नाम बता सकता हूं जहां पर टीडीएस की मात्रा ये बता रहे हैं उससे बहुत

(डा. राजकुमार शर्मा)

ज्यादा है। हाथ जोड़कर विनती है क्या आप दोबारा हमारे नवलगढ़ क्षेत्र का सर्वे कराने का विचार रखती हैं।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): नम्बर तीन और अंतिम मेरा एक पूरक प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष**: इसके बाद नहीं करेंगे पूरक प्रश्न?

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): ठीक है।

**श्री अध्यक्ष**: जवाब दीजिए। आपका एक दूसरा चांस और है।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के अन्दर जो स्वीकृत हुए थे उनकी क्या पोजिशन रही, क्यों अभी तक नहीं हुआ? 8 महीने तक हम क्या करते रहे?

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): 2015-16 में आप ही थे।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): 2015-16 से पहले वाला आपका प्रश्न था, मैं एक-एक करके सबके जवाब दे रही हूं। जो आपने पूछा उसमें अक्टूबर, 13 को, पूर्ववर्ती सरकार ने अक्टूबर, 13 में वर्क आर्डर दिया था। यानी नवम्बर में चुनाव थे और सिर्फ कहने के लिए कि हमने एक हजार आर.ओ. सैंक्शन कर दिये, इन्होंने जो वर्क आर्डर दिया है अक्टूबर, 13 में एक हजार आर.ओ. का वर्क आर्डर दिया। जब हमारी सरकार आयी तो हमने आते ही इसमें काम करना शुरू किया, 8 पैकेजेज 185 करोड़ के थे। उसमें पर यूनिट कास्ट एक आर.ओ. की थी वह 18.5 लाख थी। उसमें काम चल रहा है, 831 हमारे कमीशन हो गये, जो फंक्शनल हैं। इसके अलावा 183 आर.ओ. की कुछ प्रोब्लम है, जिसमें जिस कंपनी ने लगाया था, कुछ में लगाये, कुछ में वह मैंटेन नहीं कर पा रही तो उसको हम रीसाइन कर रहे हैं। वह विद इन ए वीक रीसाइन हो जाएगा। एक तो आपके सवाल का जवाब यह है जिसमें आपने बताया कि इतने थे, उसमें से एक हजार आर.ओ. थे सिर्फ वर्क आर्डर देकर चले गये, ढंग की कंपनियां भी नहीं थीं जिसकी वजह से स्थितियां इस तरीके की हुई कि एक हजार में से 831 ही लग पाये और शेष नहीं लग पाये जो आपके सामने मैंने कहा।

दूसरा, आपने पूछा कि 2015-16 में जो 2 हजार आर.ओ. की घोषणा हुई उसमें 10 महीने क्यों लग गये? इसलिए लग गये कि पूर्व में जो वर्क

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आर्डर आर.ओ. के लिए दिया गया था और जो क्राइटेरिया आर.ओ. के लगाने के लिए बने थे उसमें 2014 में माननीय मुख्य मंत्रीजी का दौरा था, उस दौरे के अन्दर एक आर.ओ. प्लांट उन्होंने देखा और उस आर.ओ. प्लांट को उन्होंने देखा तो सिर्फ एक डिब्बे के रूप में वह आर.ओ. प्लांट लगा था, न तो वहां आर.ओ. का कोई पानी पी रहा था और न ही वह संचालित हो रहा था। तो यह जो एक कारण है कि हम आर.ओ. तो लगा देते हैं, इतना खर्चा भी कर देते हैं उसके बाद में अगर जनता उसका लाभ न ले, उस आर.ओ. का पानी न पीये तो वह आर.ओ. लगाने का कोई अर्थ नहीं है। तो जो आईसी एक्टीविटी होनी चाहिए, जिस तरीके से लोगों को कन्वींस करना चाहिए कि आर.ओ. का पानी पीने से उन्हें क्या लाभ होगा या यह पानी आपके यहां पर शुद्ध पेयजल मिल रहा है, ये सारी चीज जो समझानी चाहिए उसकी कोई एक्टीविटी नहीं थी। पेनिट्रेशन जो होना चाहिए पब्लिक के अन्दर, वह पानी घर-घर तक पहुंचे वह नहीं था। इसलिए हमने जो नये टैण्डर किये वे सारी शर्त बनाने में हमें थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन अब जो शर्त बनी हैं उन शर्तों के अन्दर हमने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि जो आर.ओ. का पानी है उसको पब्लिक यूज करे, पीये और तभी उस कांट्रेक्टर को पेमेंट मिलेगा। कांट्रेक्टर को फुल पेमेंट हम लोगों ने नहीं किया, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार की जो शर्त है उसमें 65 परसेंट पैसा उन्होंने पहले ही दे दिया था। अभी जो हम लोगों ने किया है उसके अन्दर हम लोगों ने फिक्स अमाउंट दिया है और वह अमाउंट देने के बाद हमने पेनिट्रेशन का किया है 5 परसेंट सिक्स मंथ्स के अन्दर, फर्स्ट उसमें होना चाहिए, पहले साल में 15 परसेंट उसके बाद में लास्ट सेवन ईयर्स तक का जो मेंटिनेंस है उसमें लास्ट जो सिक्स मंथ्स रहेंगे 50 परसेंट तक का पेनिट्रेशन होगा, ये हम लोगों ने उसके लेवल तय करके किया है। एक तो शर्त बनाना और दूसरा उसमें जो दो बार टैण्डर हुये वह नहीं कोई टर्न-अप हुआ इस वजह से वह डिले हुआ और तीसरी बार टैण्डर होकर जो वर्क आर्डर दे दिया वह हमने 19.2.2016 को हमने यह वर्क आर्डर दे दिया है। अब वो आर.ओ. लगने शुरू हो जाएंगे। जो वाटर सोर्स हैं, जो ट्यूबवैल्स हैं उन ट्यूबवैल्स का अलग टैण्डर हो गया जिसमें लगभग 30 परसेंट ट्यूबवैल्स के बोरिंग हो चुके हैं और बहुत ही शीघ्र लग जाएगा। जहां-जहां भी लगने हैं उसकी सूची भी मैंने संलग्न है।

नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जी ने जो पूछा कि नवलगढ़

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

क्षेत्र के अन्दर जो क्वालिटी की प्रोब्लम को लेकर उनके मन में बात है कि 1500 टीडीएस से ज्यादा क्वालिटी वहां पर खराब है। लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र की जो वाटर क्वालिटी है वह क्वालिटी 1500 टीडीएस से कम की है। जो मैक्सिमम क्वालिटी खराब हुई है उसमें आपको बता दूं जिन गांवों में 1200 टीडीएस है, आपके दो-एक गांव हैं जिनमें 1200 टीडीएस है। यह पूरी सूची आपके सारे गांवों की मेरे पास है जिसको यहां पर कहने में मुझे लगता है कि सदन का समय व्यर्थ करना है लेकिन इसमें मैं यह जरूर कह सकती हूं कि यह जो हमारा पूरा है उसमें आईएमआईएस की जो होती है, सैण्ट्रल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो वैबसाइट है उस पर अपलोड करना होता है और एवरी ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च को क्वालिटी की पूरी रिपोर्टस हम लोग उस पर अपडेट कर देते हैं और कोई भी व्यक्ति उस वैबसाइट पर जाकर देख सकता है कि उसके फलां गांव का क्या टीडीएस है और यह एवरी ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च को अपडेट होता है। अब जो थर्टी फर्स्ट मार्च आयेगा उसमें अपडेट होगा। अगर क्वालिटी के अन्दर 1500 टीडीएस से ज्यादा आई तो निश्चित रूप से आपके यहां पर भी हम लोग आर.ओ. लगायेंगे। लेकिन जो तीसरी बात आपने पूछी कि जो 1049 जो रेस्ट है, 1066 का तो हमने वर्क आर्डर दे दिया है और 2115 में से जो 1049 रह गये हैं उन आर.ओ. की भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगी कि पूर्व में जो 1000 आर.ओ. अक्टूबर, 2013 में लगे थे उसमें उनमें जनसंख्या 1000 से ऊपर की रखी थी पर हमने जो अभी 1066 किये हैं उसमें 750 की आबादी और 1500 टीडीएस से ऊपर रखा है। अब जो हमारा नया प्रक्रियाधीन चल रहा है उसमें हम 500 की आबादी के जो गांव हैं उनमें या क्लस्टर्स बनाकर भी अगर 500 की आबादी हो जाती है तो ऐसी छोटी-छोटी जगहों पर भी 500 के क्लस्टर्स बनाकर आर.ओ. लगायेंगे जिसके अन्दर टीडीएस 1500 से ऊपर होगा तो उसमें हम लोग करेंगे। यानी हमारी जो अब योजना है वो बिलकुल नीचे तक पूरे तरीके से स्वच्छ पेयजल पिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

इसके अलावा ये तो हमारे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं और लोंग टर्म मेजर्स के अन्दर हमने लगभग 20 जिलों को सतही जल से जोड़ना तय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बांका पट्टी जो अपने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

राजस्थान में है जो नागौर से लेकर अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक तक की है और जिसको हम हमेशा बांका पट्टी कहते थे उस बांका पट्टी में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह सोच है कि इसमें कैसे हम लोग स्वच्छ जल पहुंचायें इसलिए सतही जल से जोड़ने की योजना बनाई है। नागौर के अन्दर लगभग 3 हजार करोड़ की योजना का अक्टूबर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिलान्यास किया है। उससे पहले भी उनका जब 2003 से 2008 का कार्यकाल था तब फर्स्ट फेज 750 करोड़ का उस समय दिया था। इसके बाद में टोंक के अन्दर भी बीसलपुर का पानी लाकर, अजमेर में भी बीसलपुर के पानी से, भीलवाड़ा में चम्बल के पानी से, तो इस तरीके से जहां-जहां फ्लोराइड अफेक्टेड है, हमारा अल्टीमेटली यह कहना है कि जहां पर भी क्वालिटी प्राब्लम है उसको सतही जल से जोड़कर ही हम इस क्वालिटी प्राब्लम का परमानेंट सोल्यूशन दे सकते हैं और उसके अन्दर हमारा काम चल रहा है।

**श्री अध्यक्षः** बहुत विस्तार से आ गया, और क्या पूछेंगे? श्रवण जी आप बैठिये।

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): चालू एक भी नहीं किया है, बात ही कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्षः** दूसरा पूरक प्रश्न।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो भी बात बोली है, मैं कह रहा हूं कि आप एक बार दिखवा लो क्योंकि ये ही अधिकारी महोदय उस समय थे। जो आपके हैं वो हमारे समय भी थे जब मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री था तो पहाड़िला के अन्दर आर.ओ. प्लांट मैंने लगाया था और उस समय उन्होंने कहा था कि साहब, यहां तो ब्लास्ट होना है, सब कूबड़े हो जाएंगे, इतना ज्यादा फ्लोराइड है इसलिए एक बार आप दिखवा लें और उम्मीद है कि आप दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मेरे नवलगढ़ में पानी की भारी कमी है और नवलगढ़ को डार्क जोन घोषित कर रखा है। नवलगढ़ में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस सरकार के समय चौधरी कुम्भराम लिफ्ट नहर से जोड़ने के लिए नवलगढ़ को भी शामिल किया गया था। 2014 में जब मैंने तारांकित प्रश्न किया था तो मंत्री महोदया ने मुझे अपने जवाब में भी बताया है कि आपका नवलगढ़ चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट योजना में सम्मिलित है। अभी दो महीने पहले पूरा स्टाफ, सारे इंजीनियर्स वहां

(डा. राजकुमार शर्मा)

से हटा लिये गये और नवलगढ़ को कुम्भाराम लिफ्ट योजना से वंचित कर दिया। एक तो यह राजनीतिक भेदभाव है और दूसरा माननीय मंत्री महोदया, अगर हमारे यहां पानी की कमी नहीं है तो फिर डार्क जोन में नवलगढ़ को क्यों ले रखा है? डार्क जोन से हटा दो नवलगढ़ को, हम मान जाएंगे कि हमारे नवलगढ़ में पानी की कमी नहीं है और पानी की कमी अगर मानते हो आप तो हाथ जोड़कर विनती है, हम आपकी सरकार के खिलाफ नहीं हैं, मैं हो सकता हूं लेकिन जनता नहीं है, जनता की तरफ देखते हुए बसावा और परसरामपुरा दोनों टंकियों को आप रिसर्जेंट कर दो और कुम्भाराम लिफ्ट योजना में नवलगढ़ को आप वापस जोड़ने का विचार रखती हैं या नहीं रखती हैं? कृपा करके शार्ट में मुझे बता दें हां या ना जवाब के अन्दर।

**श्री अध्यक्ष**: हां मंत्री महोदय। ठीक मांगा है उन्होंने जवाब।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, शार्ट में तो बताऊंगी लेकिन जितने प्रश्न पूछेंगे उनके जवाब तो उनको देने हैं।

**श्री अध्यक्ष**: दे दीजिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपने कहा कि जो आईएमआई के अन्दर कहीं अगर क्वालिटी प्राब्लम है और अधिकारियों ने बराबर से नहीं किया है तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को कहूंगी कि अगर उनके पास समय हो तो हमारे यहां पर क्वालिटी टैस्ट करने की हमारे पास मोबाइल वैन है। ये जाएं और इनके साथ में हमारी वो वैन भेज देंगे और जिन गांवों में भी इन्हें लगता है कि यहां पर गलत मापदण्ड तय हुआ है तो स्वयं जाकर चैक करें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया है तो लिस्ट के अन्दर उस गांव को जोड़ देंगे, उसमें कोई प्राब्लम नहीं है।

सैकिण्ड जो आपने कहा, नवलगढ़ को कुम्भाराम लिफ्ट से जोड़ने का जहां तक सवाल है, जब आप स्वयं पिछली सरकार में मंत्री थे, उस समय जो वर्क आर्डर हुआ था और पैकेजेज तय हुए थे उनमें खेतड़ी को लिया गया था। क्योंकि झुन्झुनूं जो पूरा जिला है उसको पैकेजवाइज ही जोड़ सकेंगे और उसमें जो अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की जिसमें उन्होंने सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी दो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

तहसीलों को जोड़ने के लिए 645 और 685 करोड़ की बहुत बड़ी योजना उन्होंने स्वीकृत की है और अभी हाल ही में बजट में उसकी घोषणा हुई है।

जहां तक नवलगढ़ का सवाल है तो स्टेप बाई स्टेप सबके अन्दर आयेंगे। हमारी योजना ऐसी नहीं है कि हम किसी को नहीं देना चाहते हैं। हम कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करते हैं हमारी योजनाओं में।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं। नवलगढ़ शामिल था उसको क्यों हटाया? मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं, शामिल था उसको क्यों हटाया? नये जोड़ो उसके लिए धन्यवाद, उदयपुरवाटी के लिए धन्यवाद, आपको सूरजगढ़ के लिए धन्यवाद लेकिन नवलगढ़ का अपमान क्यों मंत्री महोदया? नवलगढ़ में क्या लोग नहीं रहते? मैं कह रहा हूं कि मत लगाओ, मत जोड़ो तो डार्क जोन के लिए घोषणा कर दो कि डार्क जोन से नवलगढ़ को अलग कर दिया।

**श्री अध्यक्ष:** अब वो जवाब दे रही हैं। बहुत तैयारी करके आई हैं, आपका जवाब दे देंगी। इसके बाद अगला प्रश्न।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने आज तक किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। पानी सबके लिए है और शुद्ध पेयजल पिलाना हमारा लक्ष्य है और आगे भी नहीं करेंगे, किया भी नहीं, करेंगे भी नहीं और हमारी मन्शा भी नहीं है ऐसी।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): मैं कह रहा हूं कि फिर आज घोषणा कर दो। घोषणा करवा दो साहब।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): और यही कारण है माननीय अध्यक्ष जी, कि जो कांग्रेस के समय में पूर्ववर्ती सरकार घोषणाएं करके गईं वो सिर्फ घोषणाएं ही रहीं और उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर हुआ है तो यह अभी पिछले दो-सवा दो साल में हुआ है।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): मण्डावा, झुन्झुनूं और खेतड़ी के अन्दर लग गये।

**श्री अध्यक्ष:** फिर मैं जवाब नहीं दिलवाऊंगा। मैं मंत्रीजी से कह दूंगा कि बैठ जाएं। बार-बार आप डिस्टर्ब करते हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): जवाब तो दो हमारा।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जवाब ही तो दे रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: बार-बार डिस्टर्ब मत कीजिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपको यह भी जानना जरूरी है क्योंकि आप सदन के माननीय सदस्य हैं इसलिए राजस्थान के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। नवलगढ़ भी जानो और राजस्थान भी जानो कि यह जो वर्तमान सरकार है वो सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। हमारी अगर 67 वृहत् पेयजल योजनाएं चल रही हैं....

**श्री अध्यक्ष**: आप भी अपना जवाब शार्ट कीजिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): शार्ट में ही दे रही हूं माननीय अध्यक्ष जी।

**श्री रमेश** (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रीजी पूरे प्रदेश की बात कर रही हैं, यह नहीं कहें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में एक हैण्डपम्प भी लगाया है क्या सवा दो सालों में?

**श्री अध्यक्ष**: अंकित नहीं हो। मंत्रीजी, रमेश जी जो बोले हैं उनका जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है।

**श्री रमेश** (सपोटरा): ×××

**श्री अध्यक्ष**: आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): नहीं, नहीं, मैं नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के उन्हीं के उसमें कहना चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष**: नवलगढ़ का जवाब दीजिये। रमेश जी जो बोले हैं वो अंकित ही नहीं हो और उसका जवाब भी मत दीजिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): नवलगढ़ कुम्भाराम लिफ्ट के अन्दर कभी था ही नहीं।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): फिर अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा का है और 2014 के अन्दर.....

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये। अब जवाब नहीं आयेगा। पूरक प्रश्न निर्मल कुमावत।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह था

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

नहीं लेकिन इसको जोड़ने के लिए विचार किया जा सकता है। आने वाले समय में देखेंगे और यह बजट की उपलब्धता पर है....

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): यह 2014 का आपका जवाब है।

**श्री अध्यक्ष**: मंत्री महोदय, अब जवाब नहीं।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बजट की उपलब्धता के आधार पर हम आने वाले समय में देखेंगे इसको।

**श्री अध्यक्ष**: किरण जी, आप बैठिये, आप बैठिये। निर्मल कुमावत।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट में डिले तो हुई है परन्तु जो सलेक्शन हुआ है, 2000 आर.ओ. का सलेक्शन राजस्थान में होने वाला है उनमें एक हजार हो चुके और एक हजार का और होगा तो उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है? क्या उसमें जन-प्रतिनिधियों की राय ली गई है या अधिकारियों ने अपने आफिस में बैठकर ही बनाये हैं? जो लवणीय क्षेत्र है, जैसे मेरे यहां बहुत ज्यादा लवणीय क्षेत्र है सांभर झील का, तो उनको कुछ ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? मंत्रीजी इतना सा जवाब दे दें कि इसका क्राइटेरिया क्या रखा है? कुछ रायशुमारी होगी या अपने आप ही बनायेंगे?

**श्री अध्यक्ष**: बैठिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य ने जो पूछा उसका मैं पहले ही जवाब दे चुकी हूं और फिर भी मैं रिपीट कर रही हूं कि इसका क्राइटेरिया यह रखा कि जो 2115 आर.ओ. इस साल करने हैं उनमें से 1066 के टेंडर फरवरी में कर चुके हैं और इसका क्राइटेरिया यह है कि 1500 से अधिक टीडीएस है और 750 की पापुलेशन है तो उसको हम लोगों ने इसके अन्दर लिया है और यही इसका क्राइटेरिया है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ...और सैकिण्ड जो क्राइटेरिया है, वह 500 पापुलेशन और 1,500 टीडीएस से ज्यादा, यह सैकिण्ड जो 1,049 आर.ओज. होंगे, उनका क्राइटेरिया है।

**श्री अध्यक्ष**: श्रीमती अनीता।

**श्रीमती अनीता** (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि मेरे भरतपुर जिले के अन्दर आर.ओज. लगे थे कांग्रेस के

(श्रीमती अनीता)

समय में। जैसा मंत्री महोदय ने बताया है कि 65 परसेंट उनको पैसा दे दिया और 35 परसेंट उनको सात साल के लिए था, जिसमें उनको मेंटीनेंस के लिए करना था। लेकिन यह देखने में आया है कि आर.ओज. खराब हो रहे हैं, उनकी मेंटीनेंस के लिए वह कम्पनी वहां पर नहीं आ रही है और बहुत सारे आर.ओ. एक-एक, दो-दो महीने से वहां खराब रहते हैं और कई आर.ओज. ऐसे हैं फिल्टर की मेम्ब्रेन होती हैं, वह इतनी लो केटेगरी की लगाई कि उससे वह पानी का टीडीएस इतना हाई था कि वह हो नहीं पाया तो क्या मंत्री महोदय, जहां पर हाई टीडीएस था, वहां पर आर.ओज. को बदलकर हाई मेम्ब्रेन है, वह लगाने की घोषणा करेंगी?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह बात सही है, नगर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो कहा है, इसमें सारे वही आर.ओज. हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में थे। उन्होंने इन सारी चीज का ध्यान नहीं रखा कि कौन से रीजन के अन्दर टीडीएस बहुत ज्यादा है, किसी तरीके की कोई भी टैक्नीकली बात देखी नहीं। सिर्फ जल्दबाजी में टैण्डर्स निकालना था। चुनाव आ रहे थे तो 1,000 आर.ओ. का टैण्डर निकाल दिया लेकिन जो बात आपने अभी पूछी है, उसमें यह बात सही है कि जो बहुत हाई टीडीएस के जो हैं, उसमें मेम्ब्रेन लगी है, वह मेम्ब्रेन अगर कहीं चेंज करना है तो वह कांट्रेक्टर से बात करके उसको ठीक करवाकर वह आर.ओ. संचालित हो सकें, उस तरह की पोजिशन ले आयेंगे।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय प्रतिपक्ष के नेता। सवाल करेंगे आप।

**श्रीमती अनीता** (नगर): मंत्री महोदय मेरा कहना था कि उसमें वहां कम्पनी को मेंटीनेंस का आफिस खोलना चाहिए था, जिससे वह आसपास के क्षेत्र में व्यवस्था करता रहे।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। प्रतिपक्ष के नेता।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं। मंत्री महोदय ने यह कहा कि हम कोई भेदभाव नहीं करते। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि 450 करोड़ रुपये...

**श्री अध्यक्ष**: आपके साथ भेदभाव हो गया क्या?

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): हुआ है ना। हुआ है ना। (व्यवधान) क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां बीजेपी का जो...

**श्री अध्यक्ष**: यह आखिरी प्रश्न है। आखिरी है। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): ...बीजेपी का जो उम्मीदवार है, उसके 3,900 वोट आये क्योंकि पूरे हिन्दुस्तान में मैं समझता हूं कि बीजेपी के उम्मीदवार को इतने कम वोट मिले हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3,900 वोट आये हैं। क्योंकि नोखा टोटली फ्लोराइडयुक्त है और इन्दिरा गांधी नहर से पानी लाने की स्कीम पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने बनाई, 450 करोड़ रुपये की स्कीम थी, वह मंजूर हो गई। उसके टैण्डर हो गये। टैण्डर होने के बाद में, रेट ज्यादा आने के बाद में उसको री-टेण्डरिंग किया गया। आपकी सरकार आ गई। उसके रिव्यू के नाम से उसको बंद कर दिया। उसमें एसई और एक्सईएन लगा दिया, पूरा स्टाफ लगा दिया। उसका काम हो गया। लैण्ड एक्वीजिशन का काम हो गया और उसके बाद आपने बंद कर दिया। कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं मंत्री महोदय से कि 450 करोड़ रुपये के टैण्डर हो चुके थे। उसके बाद में उसको क्यों बंद किया गया? इसका क्या कारण था?

**श्री अध्यक्ष**: बस सुझाव दे दो। माननीय मंत्री महोदया।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): वैसे तो यह प्रश्न, जो मूल प्रश्न है, उससे सम्बन्धित है नहीं लेकिन फिर भी जो इन्होंने आरोप लगाया कि हम लोग भेदभाव रखते हैं और हम लोग योजना...

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ही नहीं आया।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इनकी सरकार पूरे पांच साल रही और आज यहां पर बैठे हैं, आप एलओपी हैं। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और आज आपको यह दुखड़ा यहां पर कहना पड़ रहा है कि मेरे यहां का बंद हो गया। पांच साल आपके पास थे। उन पांच साल के अन्दर, पहले साल में स्वीकृत कराते, सब काम कराते। आपने ऐसी योजनाएं जो छह महीने के अन्दर घोषणा की, न जिसके अन्दर कोई बजट रखा, न किसी तरीके का कोई प्रोविजन रखा और बिना बजट के आपने घोषणाएं कीं। यह भी उसी का परिणाम है कि बिना बजट के की गई घोषणा थी, इसीलिए हम लोगों को निरस्त करनी पड़ी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न। श्री बनवारी लाल सिंघल। श्री बनवारी लाल सिंघल। (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): खाली घोषणा नहीं थी। उसकी डीपीआर बन गई, उसके टैण्डर हो गये। टैण्डर होने के बाद में आपने बंद किया है। (व्यवधान)

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): प्रश्न संख्या-257.

**श्री अध्यक्ष**: एक भी इधर से नहीं। (व्यवधान) हो गया जवाब। (व्यवधान) नो, नो, नो, नो। (व्यवधान) इस तरह नहीं चलेगा। (व्यवधान) तीन पूरक प्रश्न हो गये। मैंने सबका जवाब दिलवा दिया और जवाब तो जो वे देंगी, वही सुनना पड़ेगा। आप बैठिये। (व्यवधान) श्री बनवारी लाल सिंघल। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): ×××

**श्री अध्यक्ष**: कृपया बैठिये। कृपया बैठिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। इन्होंने जो बोला है, वह अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): ×××

**श्री अध्यक्ष**: श्रवणजी ने जो बोला है, वह अंकित नहीं हो। (व्यवधान) श्रवणजी जो बोल रहे हैं, वह अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): ×××

## नीमराना (अलवर) को जिला बनाने की योजना

257. **श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नये जिले बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कौन-कौन से नये जिले बनाये जाने के प्रस्ताव किन-किन संस्थाओं/समूहों/जन प्रतिनिधियों आदि से प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीमराना (अलवर) को नया जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**राज्य मंत्री, राजस्व** (श्री अमराराम): (1) जी नहीं। नये जिले बनाने के प्रस्तावों पर राज्य सरकार को सुझाव दिये जाने हेतु आदेश दिनांक 20.1.2014 से पुनर्गठित वर्तमान उच्च स्तरीय समिति के समक्ष विचाराधीन है।

(श्री अमराराम)

(2) सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उच्च स्तरीय समिति के समक्ष नीमराना (अलवर) को नया जिला बनाने का प्रस्ताव/मांग शामिल नहीं है। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा/सुझाव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त राज्य सरकार द्वारा नवीन जिला गठन पर जनहित एवं प्रशासनिक हित में उचित निर्णय लिया जायेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अध्यक्ष**: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार से राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा रिसर्जेन्ट राजस्थान के तहत 321 लाख करोड़ रुपये के एमओयू अभी वर्तमान में किये गये हैं, उसमें अलवर जिले को बहुत बड़ी तादाद में उद्योग मिलने वाले हैं। क्या मंत्रीजी इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? और यदि मानते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर के बाद सबसे बड़ा जिला अलवर है और इसमें दो जिले बनाने की आवश्यकता, कानून व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक कार्यों को तुरन्त दक्षता के साथ निपटाने के लिए आवश्यक है कि नहीं? यदि हैं तो आप जिला बनाने की मांग को स्वीकार क्यों नहीं करते?

**श्री अध्यक्ष**: माननीय मंत्री महोदय।

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा कि आपका कोई प्रस्ताव उच्च स्तरीय कमेटी के पास विचाराधीन नहीं है। आप यदि चाहते हैं तो अपना प्रस्ताव उच्च स्तरीय कमेटी परमेशचन्द्र जी की अध्यक्षता में, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनकी बनी हुई है, उसके समक्ष आप पेश करो। मैंने तो परिशिष्ट-अ में लिखा है कि 24 प्रस्ताव आये हैं, जो हमारे विचाराधीन हैं, लेकिन आपका नीमराना का नया प्रस्ताव आप देना चाहते हो तो आप उस कमेटी को दीजिये और वह अनुशंसा करेगी। सरकार उस पर विचार करेगी।

**श्री अध्यक्ष**: दूसरा पूरक प्रश्न पूछेंगे?

**श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): इतना ही है साहब।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं। जसवन्त सिंह यादव। पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, वह आप ब्यावर का पूछेंगे। मैं अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, नहीं करूंगा। नहीं, आप तो कीजिये सवाल। (व्यवधान) नहीं, आप बैठिये। नो, नो। बैठिये। मुझे मालूम है। आप क्या प्रश्न करेंगे।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि जब पूर्ववर्ती सरकार ने परमेशचन्द्र कमेटी बनाई, उस समय नीमराना और बहरोड़ एक ही थे, तहसील बाद में घोषित हुई है। बहरोड़ के नाम से जिले की मांग की गई थी। सारे जन प्रतिनिधियों ने ज्ञापन दिया था, विभिन्न संस्थाओं ने ज्ञापन दिया था। सभी तरह के मापदण्ड पूरा करते हैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि नीमराना के नाम से नहीं है तो बहरोड़ के नाम से निश्चित होगा तो बहरोड़ बनायें या नीमराना बनायें, एक ही बात है। बहरोड़ का प्रस्ताव भी है और सब जन प्रतिनिधियों की मांग है, बहरोड़ और नीमराना एक ही पार्ट है, तहसील बाद में घोषित कर दी गई तो क्या बहरोड़ आपके उन प्रस्तावों में सम्मिलित है या नहीं है?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। (व्यवधान) विराजिये।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, नकल नहीं चलेगी। नकल करा रहे हैं यहां। आपके सामने नकल करा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): नकल क्या होता है इसके अन्दर।

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सदस्य, आपका बहरोड़ का नाम हाई पावर कमेटी के पास है और 24 प्रस्तावों में आपका नाम भी है। अब इस पर अनुशंसा, परीक्षण करके सरकार के पास आयेगी उस समय विचार किया जायेगा।

**श्री अध्यक्ष**: शंकरसिंह जी रावत अभी बोलेंगे। उनका भी है ब्यावर का। शंकरसिंह जी, आप बोलिये।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): घोषित कर दो नीमराना को जिला।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष**: ब्यावर है 24 में।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कि ब्यावर जिला बनना बहुत जरूरी है। वर्षों पुरानी मांग रही है और यह जो लिस्ट दी है, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, इसमें ब्यावर शामिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर का नाम इन 24 में शामिल है।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, सांभर का भी नाम शामिल है, सांभर का भी।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले से नौ-नौ विधायक हैं और एक ही जिले की मांग कर रहे हैं तो कम से कम यह तो पूरी होनी चाहिए और मुख्य मंत्रीजी वहां गईं, तब भी ज्ञापन दिया गया था नीमराना के लिए, अध्यक्ष महोदय, अलवर में तो बहरोड़ को जिला करें ही करें।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 24 के अन्दर ब्यावर का नाम शामिल है, इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि ब्यावर जिला बने। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। माननीय मंत्री महोदय से एक बार जवाब दिलवा दें। (व्यवधान)

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि समस्त अलवर जिले के लोगों ने सारे विधायकों ने प्रपोज किया है तो मैं जानना चाहूंगा कि किसके कहने से मंत्री महोदय और सरकार करेगी? कमेटी क्या करेगी? कमेटी इन विधायकों से ऊपर है क्या? मेरी मांग भी है इन विधायकों के साथ कि बहरोड़ या दूसरे को जिला बनाना चाहिए मंत्री महोदय को। मेरी मांग है कि जिला बनाना चाहिए।

**श्री अमराराम** (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ब्यावर से आने वालों ने यह कहा है कि ब्यावर को जिला बनाया जाये। उनका तो कई वर्षों से प्रस्ताव विचाराधीन है और इन 24 में इनका नाम है, ब्यावर का नाम है। अजमेर में जिला बनाने के तीन नाम हैं। अब सरकार जो भी विचार करेगी और वहां से प्रस्ताव हमारे पास आएगा, सरकार उस पर पूरा विचार करेगी।

(12.00 बजे)

**श्री अध्यक्ष**: अगला प्रश्न श्रीमती अनिता कटारा। प्रश्नकाल समाप्त। मैं इधर उधर आपकी बात सुन रहा था तो ध्यान चूक गया। ध्यान कभी-कभी चूक जाता है तो अब आप जानते हैं मेरा भी ध्यान चूक गया।

# स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से ग्रेड द्वितीय व तृतीय शारीरिक शिक्षकों को चयन के उपरांत भी नियुक्ति नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर के चीतलवाना क्षेत्र के भंवातडा गांव को जल मार्ग से जोड़ने हेतु पोर्ट बनाए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भजनलाल जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर के चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ एवं जांच उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में डेयरी क्षेत्र में दूध में मिलावट एवं घी की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में किसानों से डिमाण्ड नोटिस राशि जमा न कर विद्युत कनेक्शन से वंचित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री घनश्याम व अन्य पांच सदस्यों की ओर से जिला करौली के कम वर्षा वाले क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित कर राहत दिए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में पेयजल संकट को देखते हुए विशेष बजट दिए जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीएसपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री घनश्याम, श्री मेवाराम जैन एवं श्री पूरणमल सैनी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

# नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री शैतान सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पोकरण में जिला परिवहन कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में आदर्श विद्यालय हेतु भूमि आवंटन प्रक्रिया का सरलीकरण करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर में उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक भर्ती प्रक्रिया में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री बाबू सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समितियों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सीएचसी व पीएचसी में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(6) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से अराई (अजमेर) में एक नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के परकोटे में यातायात की व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में रणथम्भौर अभयारण्य एवं बीसलपुर बांध के विस्थापितों की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जय नारायण पूनियां, सदस्य की ओर से सरकारी भूमि पर वर्षों से आबाद बस्तियों के नियमितीकरण हेतु नीति तैयार करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(11) श्री श्रीचन्द्र कृपलानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में वैदिक विश्वविद्यालय को एण्डोमेन्ट राशि जमा कराने में शिथिलिता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री विद्याशंकर नंदवाना, सदस्य की ओर से कोटा जिले के ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर सिजेरियन प्रसव के लिए व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में।

मानननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

आज दिनांक 17 मार्च, 2016 को शून्यकाल में बोलने हेतु 52 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के रोड 148 डी व 158 के खस्ता हाल होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में सीवरेज व फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी से आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में।

(3) राजकुमारी दिया कुमारी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में मलारना स्टेशन और भाड़ोती में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से बारां जिले के किशनगंज शाहबाद के कतिपय गांवों के बंगाली परिवारों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

## व्यवस्था

### सदन पटल पर रखे गये माननीय सदस्यगण के लिखित भाषण

माननीय उपाध्यक्ष ने दिनांक 15 मार्च, 2016 को मांग संख्या 16 (पुलिस) व मांग संख्या 17 (कारागार) पर जिन माननीय सदस्यों ने वाद विवाद के समय समयाभाव के कारण भाग नहीं लिया था, उन्होंने अपने लिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखने हेतु माननीय उपाध्यक्ष से अनुरोध किया तो उन्होंने निम्न व्यवस्था दी।

मुझे माननीय सदस्यों को एक बात और सूचित करनी है अध्यक्षीय आज्ञा में सिर्फ बजट के वाद विवाद तक ही आपका लिखा हुआ भाषण था। उसको टेबल करने की अनुमति थी व कट मोशन में नहीं थी। इस सम्बन्ध में विधान सभा सचिवालय के बुलेटिन नम्बर-2 संख्या-13 दिनांक 22 फरवरी, 2016 पर पुनर्विचार कर यह व्यवस्था देता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को माननीय सदस्य द्वारा लिखित में अपना भाषण टेबल किए जाने सम्बन्ध में दी गई व्यवस्था को कायम रखा जाए तथा पूर्व में जारी किए गये विधान सभा सचिवालय बुलेटिन-2 संख्या-13 दिनांक 22 फरवरी, 2016 को निरस्त करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सभी सदस्यों से एक निवेदन करता हूं हमारी आज मांगें हैं। मैं चाहता हूं कि समय तो बढ़े लेकिन आठ बजे से आगे नहीं बढ़े और आठ बजे तक मंत्रीगण अपने जवाब दे दें तो यह एक सार्थकता रहेगी। इसलिए इधर के सचेतक भी और उधर के सचेतक भी अपनी सूची को इस तरह तय करें जिससे आज की सारी कार्यवाही समय बढ़ाने के बाद आठ बजे से ज्यादा नहीं बढ़ानी पड़े। यह मेरा निवेदन है, आप स्वीकार करें तो आपके ऊपर है।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि इसमें 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा तो हम आठ बजे तक खतम कर सकते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको नौ बजे तक कर दो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज तीन माननीय मंत्रियों का उत्तर होना है और नौ बजे अगर उत्तर प्रारम्भ करेंगे तो उत्तर ग्यारह बारह बजे से पहले खतम नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि मंत्रियों के उत्तर के माध्यम से जो नीतिगत फ़ैसले हों, वह राजस्थान की आवाम को मालूम पड़े और इसका साधन सिर्फ प्रेस है और प्रेस के लोगों का कहना है कि आठ बजे बाद मंत्री बोलते हैं तो हमारे अख़बार में स्पेस नहीं रहता है इसलिए आप आठ बजे तक कर दें।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सुराना साहब।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जिला झुंझुनूं की काटली नदी के बहाव में जो चालीस-पचास फीट गहरे खड्डे खोद दिए गये हैं। वो मैंने नामजद जिन लोगों के द्वारा की जा रही है और रामकुंवार गुर्जर उस पर आपका निर्णय होना था।

**श्री अध्यक्ष**: सरकार को भेज दिया गया है, आने के बाद फैसला लेंगे उस पर। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): मेरा निवेदन है कि विशेषाधिकार हनन पर सरकार क्या करेगी? यह तो सिर्फ आपके सचिवालय को देखने की बात है।

**श्री अध्यक्ष**: पहले जवाब तो मांगे।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): एक मिनट, मुझे इजाजत दें। जो मूल बात है सरकार के उत्तर में कहा गया है कि खातेदारी है नदी के बहाव में, श्रीमान राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 16 के प्रावधान 2 के तहत कोई खातेदारी नहीं हो सकती।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजिए, विराजिए। आपसे मेरी भी बात हुई है, उसमें तथ्य मंगवाकर के उसमें निर्णय लेकर के और मैं आपको सूचित कर दूंगा या यही कर दूंगा।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पूरे खान विभाग के खिलाफ है। आप सदन में ही सूचित करने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष**: कर देंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और आपके दोनों के बीच में आधा घंटे का फर्क है। आप कहते हैं नौ बजे तक और वो कहते हैं आठ बजे तक। इसको साढ़े आठ कर लेता हूं, समझौता वार्ता साढ़े आठ की है।

**श्री रामेश्वर लाल डूडी** (नेता, प्रतिपक्ष): मैं माननीय संसदीय मंत्रीजी ने जो कहा, अपना सदन कोई प्रेस की वजह से थोड़े ही चलता है, दो-दो बजे तक सदन चला है। नौ बजे तक हमारे बोलने वालों का नम्बर ही नहीं आएगा।

**श्री अध्यक्ष**: ऐसा नहीं है, देखिए, वह उनका अपना विचार है उनसे आप असहमत मत होइए। वो अगर कहते हैं कि प्रेस के माध्यम से जाता है तो जाने दीजिए ना, आपको इसमें क्या एतराज होना चाहिए। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) एक मिनट आप विराज जाएं। मोहन लाल जी विराजिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: साढ़े आठ का तय हुआ है, साढ़े आठ।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): बैठ जाइये तो आपको बोलना थोड़े ही है।

**श्री अध्यक्ष**: यहां बात नहीं। चार आदमी एक टेबल पर बात नहीं। इधर भी बात नहीं।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्रीजी ने आपको निवेदन किया है 295 के बारे में व्यवस्था देने के लिए। आपकी व्यवस्था अगर आ जाए तो उस हिसाब से सदन को...।

**श्री अध्यक्ष**: मैंने व्यवस्था नहीं दी क्या? मैंने सोचा दे दी है। 295 के अन्तर्गत आयी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं।

**(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): धन्यवाद।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## लक्ष्मणगढ़ में किसानों के विद्युत कनेक्शन की समस्या

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में ही दिनांक 14.7.2011 के बाद में ट्यूबवैल खोदने पर पाबंदी है। बिना अनुमति नहीं खोद सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके पहले जिन लोगों ने कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिये और कनेक्शन के लिए किसानों का नम्बर आ गया उनको डिमाण्ड नोट जारी हो गया। मेरे लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्रह ऐसे काश्तकार हैं जिनको डिमाण्ड नोट जारी कर दिया, लाइन खड़ी हो गयी उसके बावजूद उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और 153 ऐसे काश्तकार किसान हैं जिनको डिमाण्ड नोट जारी कर दिया लेकिन यह कह दिया गया कि आपका सर्वे सूची में नाम नहीं होगा तो हम आपके डिमाण्ड नोट को जमा नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे सूची जो जिला कलक्टर के द्वारा बनाई गयी थी उस सर्वे सूची को इग्नोर कर दिया गया और यह कहकर के विद्युत विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है कि आप तहसीलदार से प्रमाण पत्र लाओ। राजस्व मंडल ने तहसीलदारों से, पटवारियों से प्रमाण पत्र देने की प्रथा खतम कर दी और इनके विद्युत विभाग का 4.10.2012 का आदेश है जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्व मंडल ने इनकी जो डिस्काम काआर्डिनेशन की फोरम की 42वीं बैठक थी 13.8.2012 को उसमें निर्णय लिया गया कि स्वयं काश्तकार दस रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र अटैच कराकर के दे देगा तो उस काश्तकार को ये कनेक्शन देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलक्टर ने भी 28.7.2015 को आदेश निकाल दिया कि आपकी सर्वे सूची को इग्नोर करते हुए विद्युत विभाग कनेक्शन देवे और हमारे कलक्टर ने भी 26.6.2015 को प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग को लिखा। पीएचईडी के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रमुख शासन सचिव को भी लिखा। राजस्व के प्रमुख शासन सचिव को भी लिखा लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां जो सत्रह काश्तकार हैं जिनका डिमाण्ड नोट जारी किया, पूरे जिले में ऐसे लोगों के कनेक्शन हो गये केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुए उसमें नरोदड़ा है, चूड़ीमियां है, खेंवासर है, पालड़ी, पनलावा, सांखूं, कल्याणपुरा, भैंरूपुरा, बृजवास, बीदसर, डूडवा, बलारा ये सत्रह तो लाइन खड़ी करने के बाद में भी आज 6 महीने से इनमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है और 153 ऐसे लोग हैं जिनको डिमाण्ड नोट जारी कर दिया, सर्वे सूची को कलक्टर ने इग्नोर कर दिया। राजस्व विभाग प्रमाण पत्र देने के लिए बाध्य नहीं है उसको दिया नहीं जा सकता और केवल शपथ पत्र लेकर के किसान का उनको कनेक्शन देना है लेकिन मेरे काश्तकारों के साथ में माननीय मंत्री महोदय, अन्याय हो रहा है, उनको कनेक्शन मिलना चाहिए। सत्रह लोगों के आपके विभाग की लाइन खड़ी कर दी, उनको जल्दी से जल्दी कनेक्शन दें और 153 काश्तकार जो डिमाण्ड नोट लिये घूम रहे हैं, उनकी डेट निकल चुकी है उनकी डेट बढ़ा करके उनको कनेक्शन देने का निर्णय जारी करें, आदेश जारी करें जिससे उन काश्तकारों की रोजी-रोटी चल सके।

**श्री अध्यक्ष:** विराजिये। मंत्रीजी ने सुन लिया। मंत्री महोदय, रेस्पोंड करेंगे?

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, इनके विधान सभा क्षेत्र में लगभग 17 ऐसे कृषि कनेक्शन हैं जिनके डिमाण्ड नोटिस भी जारी हो गये हैं और लगभग उनकी लाइनें भी खड़ी कर दी गयी हैं और 192 ऐसे कनेक्शन हैं जिसके डिमाण्ड नोटिस तो जारी हो गये पर डिमाण्ड जमा करने से विद्युत विभाग ने मना कर दिया, क्योंकि उनका सर्वे सूची में नाम नहीं था। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा 46 पंचायत समितियों को डार्क जोन नोटिफाइड एरिया में घोषित किया गया है और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उन 46 पंचायत समितियों में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति डार्क जोन में घोषित नहीं है। ये वो पंचायत समिति हैं जिसमें अति दोहन है और स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा लगभग हमारे 150 ऐसी पंचायत समितियां हैं जो अति दोहन में आती हैं। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी बी रिट पिटीशन संख्या 628/2004,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

20.1.2006 को इसका फैसला हुआ फिर डी बी की रिट पिटीशन संख्या पीआईएल संख्या 4754/10 के निर्णय 28.3.2011 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थानीय स्थान पर नये नलकूप, बोरवैल या कुएं खोदने हेतु सक्षम अधिकारी से परमीशन लेने के बाद ही खोदे जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस न्यायालय के आदेश के बाद में कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति अगर डार्क जोन में कुआं खोदना चाहता है या कोई भी अति दोहन क्षेत्र में अगर अपना कुआं खोदना चाहता है तो एक कमेटी के माध्यम से ही कलक्टर उसको ... (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ये तो पहले से खुदे हुए हैं। 14.7.2011 से पहले से खुदे हुए हैं, सर।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उससे पहले उनसे परमीशन लेकर ही वो उस क्षेत्र में कुआं खोद सकता है क्योंकि अभी माननीय सदस्य ने जो बात की है यह अभी हमारे जनरल कैटेगरी की जो फाइल्स चल रही है, 2009 की फाइल चल रही है और राजस्थान उच्च न्यायालय का जो फैसला है, डबल बैंच का फैसला 2011 में आया है। तो जिस दिन हमारा किसान आवेदन करता है फाइल के साथ उसमें जिसने अपना कुआं खोद रखा है तो पटवारी और तहसीलदार उस पर प्रमाणित करता है कि वह कुआं खुदा हुआ है और ऐसी एप्लीकेशंस भी हमने ले रखी हैं जिसमें किसान ने यह कहा है कि हमने प्रस्तावित कर रखा है कि यहां हम कुआं खोदने जा रहे हैं। माननीय सदस्य, हमने 2009 में फाइल जमा की और उसमें उन्होंने प्रस्तावित लिखा कि वे यहां कुआं खोदेंगे और क्योंकि 2011 में डबल बैंच का फैसला आया तो इनका यह कहना है कि 2011 से जब इनको मालूम चला कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आने वाली हैं तो 2011 से पहले हमारे किसानों ने कुएं खोद लिये परन्तु सर्वे सूची में उनका नाम नहीं है। कलक्टर ने भी एक आदेश निकाला है एस.ई. को कि सर्वे सूची में अगर

**(12.17 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

नाम नहीं है फिर भी अपने लेवल पर उसको देखें। उन्होंने यह लैटर हमारे ऊर्जा विभाग के सैक्रेटरी साहब को भी लिखा है, हमारे डिस्काम के एमडी को

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

भी लिखा है। राजस्व विभाग को भी लिखा है और पीएचईडी को भी लिखा है। यह बात भी सही है हो सकता है कि 2011 का फैसला आने के पहले और 2009 में जब यह फाइल जमा की उस दरम्यान कृषकों ने ट्यूबवैल खोदे होंगे तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य को विश्वास देता हूं कि कलक्टर ने भी यह लिखा है कि सर्वे सूची को इग्नोर किया जाए और अपने विवेक से देखें कि वास्तव में कुआं खोदा है कि नहीं खोदा है। तो माननीय सदस्य, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं कोई कमेटी बनाकर जो आपके विधान सभा क्षेत्र में लम्बित कनेक्शन हैं जो आपके 2009 के एप्लीकेंट्स हैं जिनके लगभग 200 कनेक्शन पेंडिंग हैं, उसकी एक कमेटी बना कर उसकी जांच करवाकर फिर ही मैं आपको आगे इसका फैसला दूंगा। अगर उसमें यह पाया गया कि वह 2011 से पहले खुदे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपके कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे और वो अगर 2011 के बाद में कृषि कुएं खोदे हैं ...।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, एक सैकिण्ड। विभाग का यह आदेश है 4.10.2012 का जिसमें आपके विभाग ने लिख रखा है कि काश्तकार से दस रुपये का स्टाम्प लेकर उसको मान करके कनेक्शन किया जाए तो इसकी पालना करवा दो, माननीय मंत्री महोदय।

**श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हम राजस्थान उच्च न्यायालय से ऊपर तो जा नहीं सकते। राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आपकी जो यह मंशा है कि हमने 2011 से पहले कुआं खोदा है तो 2009 में कृषक ने जो फाइल भरी उसमें यह भरा कि वो प्रस्तावित है और प्रस्तावित 2009 में आपने फाइल भरी है। 2011 में ये आदेश आये। आपका यह कहना है कि हमारा सर्वे सूची में नाम नहीं है परन्तु 2011 से ये कृषि कुएं खुदे हुए हैं। पूरे जिले में सब जगह कृषि कनेक्शन दिये जाते हैं, खाली लक्ष्मणगढ़ में ये कनेक्शन रुके हुए हैं तो इसके लिए आप फरमायेंगे तो एक कमेटी बनाकर उपखंड स्तर पर एक कमेटी फोर्म करके यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वास्तव में ये कृषि कुएं 2011 से पहले खुदे हुए हैं। अगर 2011 से पहले जो खुदे हुए हैं तो उनको हम कनेक्शन जारी कर देंगे और 2011 के बाद में है तो कलक्टर से परमीशन लेने के बाद ही कनेक्शन दिये जाएंगे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): 17 के लाइन खड़ी हो गयी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

वो तो करवा दो हुकुम। वो सत्रह तो उस कमेटी में थोड़े है वो तो लाइन खड़ी हो गयी आपकी तो वो तो करवा दो।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन है कि आप पूरे राजस्थान की एक कमेटी गठित करके पूरे राजस्थान की जांच करा दें और राजस्थान में जो योग्य हैं उन सबका आप करायें।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री घनश्याम।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

## करौली के अकालग्रस्त क्षेत्रों को राहत

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में नादौती में आज चार दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नादौती व टोडाभीम सम्पूर्ण करौली जिले में किसान भयंकर अकाल की चपेट में आये हुए हैं। पिछले साल भी कम बरसात होने के कारण वहां अकाल की छाया रही और इस वर्ष तो बरसात नहीं होने के कारण 100 प्रतिशत वहां खराबा है, पर सरकार द्वारा अधिकारियों पर दवाब बनाकर सिर्फ 40 परसेंट खराबा ही वहां दिखाया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां चारे के बिना पशुओं की मरने की हालत हो गई है और आज किसानों के यह हालात वहां पैदा हो गये हैं, सरकार ने वहां नरेगा की योजनाओं को बंद कर दिया है और किसी प्रकार का मुआवजा किसानों को देने का काम सरकार नहीं कर रही है। इसके साथ-साथ पिछली बार जब हम वहां गये तो सरकार ने कलक्टर एवं एसडीएम के मार्फत पटवारियों से जो रिपोर्ट ली, पिछली रिपोर्ट में तो 33 परसेंट खराबा दिखाया और फिर पुन: जांच में उसको 40 परसेंट दिखाया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जब 100 प्रतिशत खराबा है तो 40 परसेंट खराबा क्यों दर्शाया जा रहा है। वहां किसानों की भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, सरकार घड़साना जैसी स्थिति किसानों की न बनाये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, इस मामले में जवाब दें और स्पष्टीकरण दिलावें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो सवाल उठाया, उपाध्यक्ष महोदय, खरीफ की फसल की गिरदावरी का जो प्रोसेस है वह 15 अक्टूबर से प्रारम्भ हुआ था और गिरदावरी की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास नवम्बर तक आई और इसकी अधिसूचना 19 दिसम्बर तक कर दी गई। इस अधिसूचना के अनुसार करौली जिले में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें खराबा 50 फीसदी से ज्यादा हो। हां, यह सही है कि एसडीआरएफ के नोर्म्स में जो बदलाव आया माननीय मुख्य मंत्री और माननीय आपदा राहत मंत्री महोदय ने जब केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया कि इस नोर्म्स को बदला जाना आवश्यक है। पूरे देश में जो नोर्म्स बदले गये उसके अनुसार जो कृषि आदान अनुदान के नियम हैं उसके अनुसार 33 फीसदी अगर किसी काश्तकार के खेत में खराबा हुआ तो उसको अनुदान आदान के आधार पर मुआवजा मिलने का उसका अधिकार बन जाता है। नादौती तहसील में 33545 किसान हैं जिनका 33 फीसदी से अधिक फसल का खराबा हुआ है। अभी जो सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई है 1193 करोड़ 91 लाख रुपये की भारत सरकार ने एसडीआरएफ से, जो उच्च समिति है उसने अनुशंसा की है, राशि प्राप्त होते ही जो 33 परसेंट से ज्यादा खराबा जिन किसानों का है जिनकी संख्या 33545 है, उनको मुआवजा वितरित कर दिया जायेगा। गिरदावरी के पूरे प्रोसेस में, जब गिरदावरी चल रही थी तब माननीय सदस्य ने कभी इस पर एतराज नहीं उठाया, आज उस गिरदावरी की पुन: जांच करायें, उसका कोई आधार बनता नहीं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसमें राज्य सरकार संवेदनशीलता से जिन काश्तकारों का खराबा हुआ उनको निश्चित समय में मुआवजा देगी।

**श्री घनश्याम** (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ नादौती की बात कर रहा हूं। नादौती में 100 परसेंट खराबा है और इसका एतराज किया है। मैं खुद एसडीएम कार्यालय में पटवारियों की मीटिंग में शामिल हुआ हूं। उन्होंने यह कहा कि हम पर सरकार का दवाब है। सरकार हमको यह आदेश कर चुकी है, ऊपर का दवाब है कि आप ज्यादा खराबा न दिखायें। उन्होंने 33 के बजाय 40 दिये हैं, अब आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखें उसमें 40 प्रतिशत खराबा दर्शाया गया है, उसकी कापी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसके साथ-साथ जब 100 प्रतिशत खराबा है तो फिर आप 40 क्यों दर्शा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां किसान हजारों की तादाद में धरने पर बैठे हुए हैं और उसमें लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। मेरा आपसे

(श्री घनश्याम)
करबद्ध निवेदन है कि आप उन किसानों की मांग का ध्यान रखें। पीने के पानी के हालात यह पैदा हो गये हैं, वहां पशु मर रहे हैं और किसानों को वहां से पलायन करना पड़ेगा या बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आप पैदा न करें। माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री मेवाराम।

## बाड़मेर में पेयजल संकट हेतु विशेष बजट

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिये आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। बाड़मेर जिले में पानी की इतनी भयंकर समस्या थी कि जहां गांवों में एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल से पानी नहीं आ रहा था और बाड़मेर शहर में सप्ताह में एक दिन पानी आता था। पिछले समय में हमारी सरकार ने मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का पानी बाड़मेर पहुंचाया, उसको गांवों में पानी पहुंचाना था। बाड़मेर तक पानी खूब आ रहा है। गांवों के लिये स्कीमें बन गईं, टैण्डर हो चुके, पाइप आ गये, एक प्रतिभा कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका भी दिया, अ, ब और स तीन योजना थी, तीनों ही योजनाओं का काम दो साल से करीब करीब ठप्प सा कर दिया है। पानी में जिस तरह से राजनीति हो रही है और भेदभाव हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, वह तो मेरा यह मुद्दा आते ही पता नहीं क्यों जानबूझकर यहां सदन से बाहर गईं या सुनना नहीं चाहतीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बाड़मेर में हालत यह है कि गांवों में हैंडपम्प खराब पड़े हैं, ठीक करने वाला कोई नहीं है। सौ, सवा सौ हैंडपम्प उखाड़ कर लेकर आये उसके बदले में एक नया हैंडपम्प खोदा नहीं, ट्यूबवैल बंद पड़े हैं। पाइप लाइनें टूटी हुई हैं और पानी व्यर्थ बह रहा है। बाड़मेर शहर में पानी की ऐसी हालत हो गई कि जल स्तर इतना बढ़ गया कि डेढ़ फीट ऊपर खोदो तो जितने भी अंडर ग्राउंड हैं उनमें पानी आ रहा है, उस पर सुपरविजन वाला एईएन नहीं। एईएन पहले एक टीए था वह दिन-रात शराब पीये रहता था। उसको मैंने हटाने का कहा तो टीए की जगह उसको शहर में ही लगा दिया। अब न कोई सुनने वाला है, न कोई करने वाला है। एक तरफ तो पानी व्यर्थ बह रहा है और दूसरी तरफ गांवों में बुरा हाल है। एक-एक साल में, छह-छह महीनों में वहां पानी नहीं जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी

(श्री मेवाराम जैन)

बाड़मेर पधारीं। नीमला से बीसाला एक मीठे पानी की पाइप लाइन चल रही थी उसमें 100 जगह लीकेज, 100 जगह पानी रोड पर व्यर्थ बह रहा है। मंत्रीजी को विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 6 किलोमीटर आप पाइप लाइन सैंक्शन कर दो तो यह 15-20 गांवों को पानी आराम से पहुंच जायेगा। मंत्रीजी ने उस मीटिंग में घोषणा की कि हमने यह 6 किलो मीटर पाइप लाइन आज सैंक्शन कर दी और वह अख़बार में आया। उसको एक साल हो गया आज तक वह पाइप लाइन सैंक्शन नहीं हुई। पता नहीं कहां गई। मंत्रीजी को मैं उस घोषणा की याद दिलाते-दिलाते थक गया। विधान सभा में प्रश्न भी लगाया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों ने पाइप लाइनें लगाईं, वाटर वर्क्स से एनओसी ली, पाइप लाइनें लग गईं, पानी चल रहा था और उन्होंने अभी कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काट कर एससी, एसटी, गरीब लोगों पर मुकदमे और दर्ज कराये, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और उनको अन्दर कराने का काम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायतों में टीएफसी, एसफससी जो अन्य फंड हैं, चाहे एमएलए में है, हम चाहते हैं कि जहां पानी की भयंकर समस्या है, कम से कम इस फंड से पाइप लाइन सैंक्शन तो हो। यह एनओसी नहीं दे रहे हैं कि बिलकुल एनओसी नहीं देंगे। इन्होंने एक नीति बनाई है कि 90 एमएम के पाइप हमारा विभाग ही लगायेगा जिसके एक किलोमीटर के पांच लाख रुपये लगेंगे। ग्राम पंचायत स्तर से लगायें तो एक, सवा लाख में एक किलो मीटर पाइप लाइन लगती है और इनका विभाग पांच लाख एक किलोमीटर के ले रहा है। वह पैसे कहां से आये, पंचायत को एनओसी दे नहीं रहे। जो पुरानी पाइप लाइनें लगी हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हैंडपम्प ठीक कर नहीं रहे हैं। जनता जल योजनाओं की हालत क्या है, 10-10 साल का बिजली का बिल एक साथ 10-10 लाख रुपये भेज रहे हैं। पंचायत कहां से 10-10 लाख रुपये जमा करायेगी, यह हालात जनता जल योजना के हैं।

तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, ढाई साल में एक हैंडपम्प दिया नहीं, एक ट्यूबवैल दिया नहीं। जिस तरह से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यह भेदभाव पानी...। इसमें कोई कांग्रेस-बी.जे.पी. की बात नहीं। वोट तो इनको भी दिए होंगे। पानी तो सबको पीने के लिए चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जितनी भी योजनाएं हैं, चाहें हैंडपम्प है, चाहे पाइलाइन है। यह

(श्री मेवाराम जैन)

महत्वपूर्ण जो पानी की समस्या है इसका आप समाधान करावाएं और आज अच्छा तो यह होता कि मंत्रीजी यहां जवाब देते और इस समस्या को हल कराते और इस तरह का भेदभाव जो किया जा रहा है, पानी में नहीं किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री पूरणमल सैनी।

## सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बी एस पी कार्यकर्ताओं पर हमला

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को स्थगित करते हुए आपने मेरे प्रस्ताव पर बोलने की स्वीकृति दी, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि मामला हाड़ौती क्षेत्र के कोटा जिले के दादाबाड़ी थाने का है। वहां मामला माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह था कि 30.11.15 को निकायों में काम करने वाले, ठेके पर लिए गए, स्थायी और अस्थायी श्रमिकों ने हर निकाय में अपनी मांग रखी थी कि हमें 26 दिन जब काम पर लगाया जा रहा है और मजदूरी 20 दिन की दी जा रही है तो हमें जितना काम लिया जा रहा है, उतनी मजदूरी दी जानी चाहिए। दूसरा, मज़दूरों की हाज़िरी 20 भी हुई, न हुई इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारी हाजिरी बायोमैट्रिक मशीन के द्वारा करवाई जानी चाहिए और तीसरी उनकी मांग थी कि हमें जो भुगतान ठेकेदारों और पार्षदों की मिलीभगत से जो कि मजदूरी उठाते कुछ थे और उनको देते कुछ रहे थे। इसलिए उनकी तीसरी मांग थी कि हमारे श्रम का जो भुगतान किया जाए वो बैंक के खातों के माध्यम से किया जाए। इस मांग को लेकर हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब वहां के श्रमिकों के साथ निकाय के अधिकारी से मिलने गए तो वहां अधिकारी से बात करते उससे पहले ही, वहां के ठेकेदार और पार्षदों ने मिलकर वहां अज्ञात लोगों को भिजवाकर हमारे उन कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया, जिसका मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट 01.12.2015 को दर्ज हो गई थी, लेकिन 01.12.2015 को मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद और कोई जांच नहीं करके उस मामले को एफ.आर. लगाकर बंद कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री के रूप में आज का कार्य देख रहे गृह विभाग के माननीय संसदीय मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे आजादी के 69-70 वर्ष बाद भी अगर श्रमिकों की

(श्री पूरणमल सैनी)

जायज मांगों को इस तरीके से डायवर्ट करते हुए उनको ठोका पींदी करके, उनकी पिटाई करके, उन पर हमला करके अगर उनकी वाजिब मांगों को भी दबा दिया जाएगा तो इन श्रमिकों का मानसिक रूप से भी शोषण किया जा रहा है और आर्थिक रूप से भी शोषण किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री के रूप में विराजमान संसदीय मंत्री महोदय से कि उस 30.01.2012 को दर्ज मुकदमे को दोबारा खुलवाकर और जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाएं तथा मानसिक रूप से जो पीड़ा हो रही है उन श्रमिकों को, उनको उससे निजात दिलाएं। साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से कि उनकी जो वाजिब मांग, जो उन हमलावरों ने हमला करके उनका डायवर्जन का काम किया कि ये मुकदमे में लग जाएंगे और वो अपनी वाजिब मांग करेंगे नहीं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि उन मजदूरों की, ठेके पर नियोजित श्रमिकों की जो वाजिब तीन मांगें थीं, नंबर 1 - बायोमैट्रिक से उनकी उपस्थिति करवाना, 2. उनको जो भुगतान-पारिश्रमिक जो दिया जा रहा है वो बैंक खातों के माध्यम से दिया जाना और तीसरी जो उनकी मांग थी कि भई हमें 26 दिन काम पर रखकर 20 दिन का भुगतान दिया जा रहा है, बायोमैट्रिक से उनका समाधान हो जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों माननीय मंत्री महोदय मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए उन गरीब लोगों को निजात दिलवाएं। आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न तो आपका होम मिनिस्टर से सम्बन्धित है।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): इसी पर तो यह आई है।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हमेशा से जितने भी म्युनिसिपल कार्पोरेशन हैं, म्युनिसिपेलिज हैं, नगर परिषद है। उनके अन्दर संविदा पर जो कर्मचारी लगाए गये या ठेकेदार के द्वारा जो कर्मचारी लगाए जाते हैं, जिन्हें बीट कर्मचारी कहते हैं, उन बीट के बारे में लगातार कई प्रकार

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की बातें कई सालों से हम सुन रहे हैं और इसका मुख्य कारण यही है कि जो आप सही बता रहे हैं कि संविदा पर लिए हुए कर्मी को चूंकि संविदा पर जो संविदा कर्मी हैं वो ठेकेदार के, हमारे नहीं हैं। इसलिए हम संविदा कर्मी को पेमेंट करने के बजाय उस ठेकेदार को पेमेंट करते हैं और ठेकेदार उस संविदा कर्मी को पेमेंट करता है। हमेशा यह आरोप लगते हैं कि लोग बीट में काम ही नहीं कर रहे और संविदा कर्मी को बीट पर काम करना बताकर उसके बदले भुगतान ले रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसमें रेसिसटेंस भी होती है करने में, लेकिन हमने पहली बार राजस्थान के जयपुर जैसे शहर से यह काम शुरू किया है कि जिस ठेकेदार के माध्यम से संविदा कर्मी हमने लगाए हैं वो संविदा कर्मी कौन है, इसकी जानकारी हमको दे और सीधे के सीधे संविदा कर्मी के खाते के अन्दर पैसे जमा हो जाएं। इसका काम हमने पहले राजस्थान के जयपुर जैसे शहर से शुरू किया है जो सबसे बड़ी जगह है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी मंशा है कि पूरे राजस्थान के अन्दर जो ठेकेदारों के माध्यम से संविदा कर्मियों को बीट कर्मचारी के रूप में हम काम में ले रहे हैं, उन सारे कर्मचारियों का पेमेंट धीरे-धीरे चरणबद्ध ढंग से सीधे बैंक खाते में जमा कराने का जो काम हमने शुरू किया है, वो पूरे राजस्थान में फैलाएंगे। कई सालों से मैं सुन रहा हूं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब से लेकर आज तक लगातार सुन रहा हूं कि बीट कर्मियों के मामले में घपला है, बीट कर्मियों के लोगों को पैसा नहीं मिलता, पूरे टाइम का पैसा नहीं मिलता। इसका समाधान करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जयपुर से जो काम हमने दो-तीन महीने पहले शुरू किया है, जो रेसिसटेंस आ रहा है, विरोध आ रहा है। विरोध के बावजूद उस काम को हम पूरा करेंगे और पूरे राजस्थान के अन्दर जहां-जहां भी ठेकेदार के माध्यम से संविदा कर्मी लगे हुए हैं। उन संविदा कर्मियों का भुगतान निश्चित रूप से हम बैंक खाते में करा देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने साढ़े तीन महीने पहले की घटना स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन के सामने रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, 01.12.2015 को रामचरण पुत्र मोहन लाल हरिजन, सफाई-ठेका मजदूर के पर्चा बयान पर एक मुकदमा दर्ज हुआ दादाबाड़ी के अन्दर। प्रकरण संख्या 498/30.11.2015 U/s

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

341, 323 और 34 उसमें यह कहा गया कि 30.11.2015 को उसके घर के पास ये घटना बता रहे हैं नगर निगम की। पर्चा बयान में क्या कह रहा है कि 30.11.2015 को रामचरण के घर के पास बसंत विहार सरकारी स्कूल के पास दो लड़कों द्वारा, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था बेस बाल के बल्ले से उसके सिर पर हमला किया। रामचरण के चोट आई। चिल्लाने पर दो व्यक्ति आए। उन्हें देखकर हमलावर भाग गए और इस कारण से यह जो..। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, अनुसंधान के बाद बयान फरियादी और गवाह के दर्ज किए गए। मौका-नक्शा बनाया गया। दो अज्ञात लड़कों की तलाश की गई, परन्तु उनका कोई पता नहीं लगा और अनुसंधान के अन्दर 21.12.15 को अदमपता में न्यायालय में एफ.आर. पेश कर दी। एफ.आर. पेश करने के बाद ना तो इनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट पिटीशन आया। इनके खुद के बयानों के आधार पर भी, जिन पर इन्होंने शक किया, उन सब से पूछताछ हो गयी। कोई मालूम पड़ा नहीं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो चूंकि न्यायालय में पेश हो चुकी है, इसलिए प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करें अगर करें तो।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जैसा बता रहे हैं यह बात सही है। इन्होंने जो इसको काउंटर किया है कि दो लोगों ने आक्रमण किया, उसमें इन्होंने त्रुटि बताई, उसको मैं सुधरवाता हूं कि जब वहां ये प्रार्थना-पत्र देकर आ गये, वो जो बी.एस.पी. के कार्यकर्ता उन श्रमिकों के साथ थे उसके अगले दिन जब अख़बार में छपकर आया तब हमारे उस कार्यकर्ता पर आक्रमण किया गया और जब माननीय मंत्री महोदय, इस बात को काउंटर कर रहे हैं कि आक्रमण हुआ, हमलावार बंद थे, तो फिर आज दिनांक तक इनको एफ.आर. आपके अधिकारियों ने क्यों दे दी? उस पर कार्रवाही क्यों नहीं फरमायी गई? तो, मैं मांग करूंगा कि उन पर माननीय मंत्री महोदय विभाग को पुन: आदेश जारी करके उनके खिलाफ कार्यवाही करवाएं और उनको खोजवाएं।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री राम लाल गुर्जर।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## आसींद की खस्ताहाल सड़कें

**श्री राम लाल गुर्जर** (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज पर्ची पर बोलने का विषय आया। सबसे पहले तो मैं आपको

(श्री राम लाल गुर्जर)

धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे आसींद विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नेशनल हाइवे के दो रोड निकल रहे हैं। एक 148 डी और दूसरा 158 । 158 तो मेरे भीलवाड़ा से ब्याबर जो सीधा रूट जाता है उस पर निकल रहा है तो उसको चले हुए काफी टाइम हो गया।

वहां पर ब्राह्मणों की सरेडी और मोड का निम्बेडा दो गांव, और एक पालड़ी गांव आता है, उसमें से होकर गुजरता है, रोड़ पीडब्ल्यूडी से नेशनल हाइवे वालों ने ले लिया, इसलिए अब पीडब्ल्यूडी वाले उसको ठीक नहीं कराते। नेशनल हाइवे वाले भी इसको ठीक नहीं कराते हैं।

इसी तरह मेरे 148-डी गुलाबपुरा आसींद भीम होकर गुजरता है उसके अन्दर लगभग साढ़े पच्चीस किलोमीटर की दूरी का रोड है, पहले पीडब्ल्यूडी के जिम्मे था लेकिन पीडब्ल्यूडी से नेशनल हाइवे वालों के जिम्मे हो गया। नेशनल हाइवे वालों ने लेने के बाद, रोड़ वहां पर निकाल दिया, उनके कई बाइपास निकाल दिए। उन रोडस को नेशनल हाइवे वालों ने तोड़ा। रैगुलर उनके ट्रक, ट्रोले, डम्पर सब चलते हैं। लगभग दो साल हो गए उनको काम चालू किए हुए लेकिन डेढ़ साल से तो लगभग-लगभग उनका काफी काम हो चुका और साल भर में उनका काम पूरा होने को भी आया। आसींद का रोड़ लगभग निकल गया। उन्होंने मेरे दातंडा, खाइका लंबा, गागेड़ा, भूरड़ा यहां के रोड़ लगभग दस गांवों के रोड़, परासोली, प्रतापपुरा में बहुत ही ज्यादा हालत खस्ता है। डेढ़ साल से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन लोग धरना भी देते हैं, इन रोड्स की दशा सुधार दी जाए ताकि पब्लिक को यह अहसास हो। जनहित में यह अति आवश्यक है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि इन रोड्स को, काफी समय हो गया है, वहां आने-जाने वाले भी परेशान हैं, आम रोड है इसलिए इनको ठीक कराने का कष्ट कराएं।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने एन एच 158 और 148-डी की बात कही है, इनका निर्माण लगभग 95 प्रतिशत हो गया। इसके बाइपास बनने की वजह से कुछ लैफ्ट आउट ऐसे हैं उनको भारत सरकार ने यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उनकी मेंटीनेंस नहीं की। हमने भारत सरकार को इस हेतु लिखा । यह खाली 148 डी और 158 का ही इश्यू नहीं है यह पूरे राजस्थान में जहां-जहां बाइपास बने हैं उनके सब लैफ्ट आउट

(श्री युनुस खान)

वैसे ही पड़े हैं। क्योंकि न तो वह नगरपालिकाओं को मिले, ना राज्य सरकार को मिले, उनका डिनोटिफिकेशन नहीं हुआ। यह इश्यू लेकर हम भारत सरकार के पास गए कि जब आप नई सड़क बना देते हैं और जहां बाइपास की आवश्यकता होती है वहां बाइपास बना देते हैं, तो कम से कम जो उसका लैफ्ट आउट है वह मेंटेन करके राज्य सरकार को दें जिससे हम उस क्षेत्र को डिनोटिफिकेशन करके सम्बन्धित, नगरपालिका या नगर परिषद जो भी है उसको दें, या राज्य सरकार उसकी मैंटीनेंस करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो उनका एक सकुलर था उसके तहत उन्होंने कहा कि जिस दिन एन एच घोषित हो जाता है उसके बाद उसकी मेंटीनेंस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार के माननीय मंत्री ने इस बात की सहमति दी है कि जितने भी राजस्थान के लैफ्ट आउट हैं उनको मेंटेन करके हम देंगे। उसी कड़ी में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2016-17 के बजट में 300 करोड़ की घोषणा की है।

मैं आसींद से आने वाले माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जितनी भी लैफ्ट आउट, जिन गांवों के आपने नाम बताए हैं, विशेष रूप से भीम में, सोमालिया, गुजाना, बड़ा खेड़ा, आसींद, प्रतापपुरा, परासोली, जयनगर, शम्भुगढ़, अंताली, कजारी, गागेड़ा, लांबा, इन सब में बाइपास बने, तो उनकी स्थिति ठीक करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेकर, जो ज्यादा खराब है उनको प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष ले लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 572 करोड़ के और प्रपोजल हमने भारत सरकार को भेज रखे हैं, अगर स्वीकृति मिल गई तो इनके करीब-करीब लैफ्ट आउट ठीक कर दिए जाएंगे।

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, आप पिलानी गए थे। पिलानी शिक्षा की नगरी है, आपने कहा था कि बाइपास ठीक कर देंगे। दस साल से टूटी हुई है। पिलानी गए थे ना आप।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक आग्रह है कि श्रवण जी को एक बार आधा घंटा बोलने का किसी न किसी विषय पर दे दो।

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): दे दिया ना।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो बार-बार इनको खड़ा नहीं होना पड़े।

**श्री श्रवण कुमार** (सूरजगढ़): दे दिया ना, किसमें निहाल कर दिया आपने। तीन बार जाकर भाषण दे आए कि पिलानी की बाइपास ठीक कर देंगे, आज तक तो ठीक हुई नहीं। बोल कर क्या करेंगे आप लोग हमारी बोली सुनते ही नहीं हो।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री जोगाराम पटेल।

## जोधपुर में सीवरेज व प्रदूषित पानी की समस्या

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं पर्ची के माध्यम से जो विषय रख रहा हूं वह विषय आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ जाने-अनजाने में, विश्वास अविश्वास से, विज्ञापन एवं अन्य किन्हीं कारणों से, किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है वह विषय है।

राजस्थान के सबसे बड़े द्वितीय शहर जोधपुर के करीब आस-पास के क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। ऐसा प्राय: सभी शहरों में होता होगा। जोधपुर में रोजाना 230 एमएलडी पानी सप्लाई होता है। इसके अलावा स्वयं के टयूबवैल, बावड़िया, कुआं, आदि से भी बहुत पानी निकलता है। वह सारा का सारा पानी पीने योग्य या अन्य प्रकार से काम आने के बाद सीवरेज लाइन की मार्फत, फैक्ट्रियों की नालियों के मार्फत, या अन्य किसी तरह से जोधपुर के आस पास के 15-20 गांवों में जाता है। यह करीब 230 एमएलडी से ज्यादा ही पानी वापिस निकलकर, प्रदूषित होकर पानी जोधरी नदी के आस-पास जाता है। सरकार की ओर से नादड़ी में 20 एमएलडी की एक सीटीपीटी है, 20 एमएलडी की सालावास में भी एक सीटीपीटी है। इस एमएलडी के अलावा और कोई भी पानी उसमें साफ नहीं होता है, पर जोधपुर नगर निगम द्वारा पानी के ठेके दिए जा रहे हैं। वह ठेके नादड़ी में अलग हैं और सालावास में अलग है। उनको यह बताया जाता है कि पानी साफ होकर वितरित किया जा रहा है। जो ठेका लेता है वह कोशिश करता है कि एक या दो गांव में जहां पानी देना है वह पानी देता है लेकिन जोधपुर तहसील के करीब 20-30 गांव और लूणी तहसील के करीब 15-20 गांवों में ठेकदार सिर्फ ठेका लेने के नाम से या अन्य किसी कारण से, जो प्रदूषित पानी है वह पानी भी पूरा उपयोग करते हैं, पानी उपयोग करके वह सब्जियां उगाते हैं। इस सम्बन्ध में अनेक बार विभिन्न समाचार पत्रों में खूब समाचार प्रकाशित हुए कि इस तरह से है, उसकी जांच भी हुई।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी दो रिट याचिकएं पेश हुईं। एक 11533 शत्रुघ्न राजपुरोहित बनाम सरकार, एक 4050/12 यू. आर. बेनीवाल बनाम सरकार एनजीटी ने भी इसमें काग्नीजेंस ली, एनजीटी ने भी अपने प्रकरण 7932/2011 मुलतान सिंह बनाम सरकार में भी यह सब माना कि यह कैमिकलयुक्त पानी है, सीवरेज लाइन का पानी है, इससे जो सब्जियां उगाई जा रही हैं वह सब्जियां जनता की सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। पानी में जो कैमिकल होता, वह हानिकारक है, जिसका उपयोग भी नहीं हो सकता। इसमें करीब 2 हजार से अधिक क्लोरोफार्मा का पानी होता है जबकि जीरो क्लोरोफार्मा होना चाहिए, जो पानी उपयोग के लिए होता है। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जिसमें पीलिया, हेपेटाइटिस, डायरिया और आजकल तो कैंसर, वगैरह-वगैरह बीमारियां सब होती हैं।

मैं इस मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो पानी सीटीपीटी में साफ होकर वितरित किया जा रहा है वह तो सब सही है लेकिन सीटीपीटी में वितरित होने के अलावा जो पानी ठेकेदार या और कोई लोग उसका उपयोग करते हैं, विज्ञापन यह देते हैं कि यह शुद्ध सब्जियां हैं, खेतों में उगाई गई हैं। जनता के पास विवशता भी है, मजबूरी भी है और विश्वास भी है। वह लाए ता कहां से लाए। उस विज्ञापन से प्रभावित होते हैं, प्रभावित नहीं भी होए तो भी उनके पास कोई आप्शन भी नहीं है।

मेरा इसमें निवेदन है कि चाहे गोभी हो, मिर्च हो, प्याज, टमाटर हो, बैंगन हो या अन्य कोई सब्जियां हो, यह सब्जियां पब्लिक की सेहत का बहुत भारी नुकसान कर रही हैं। धीरे-धीरे इसका बहुत असर हो रहा है इसलिए सरकार विशेष तौर पर इस ओर ध्यान दे। ध्यान देकर चाहे हाई कोर्ट का फैसला है, चाहे एनटीपी का फैसला है, फैसला है या नहीं भी है लेकिन इन कैमिकलयुक्त पानी से जो सब्जियां उग रही है, जनता उसे उपयोग कर रही है और जिससे उसे नुकसान दिनों-दिन हो रहा हैं वह आने वाले समय में कहीं भी एक भयंकर बीमारी के रूप में हो सकता है और अनकंट्रोल भी हो सकता है।

मेरा सरकार से इतना ही निवेदन है कि इस कैमिकल युक्त पानी से सब्जियां नहीं उगें। जनता को झूठे या बनावटी विज्ञापन से भ्रमित नहीं किया जाए। यह जो कैमिकलयुक्त पानी जोधरी नदी में डालने के उपरान्त, जोधरी नदी के जो दोनों तरफ के किनारे हैं, वहां किनारों पर जो सब्जियां उगाई जा

(श्री जोगाराम पटेल)

रही हैं, उससे भी जो नुकसान हो रहा है उसकी रोकथाम की जाए। जनता की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोका जाए। यह भी निवेदन है कि इसकी विस्तृत जांच करवाई जाये कि जिस एरिये में, यह सब्जियां उगाई जा रही हैं उनमें कितना प्रदूषित पानी है और कितना कैमिकलयुक्त पानी है। उससे कौनसी-कौनसी बीमारियां हो रही हैं। मेरा ऐसा निवेदन है, हो सकता है अन्य शहरों में, लेकिन जोधपुर की सारी यह रिपोर्टिंग है। सारे समाचार पत्रों की अलग-अलग जो रिपोर्टिंग है, उसके आधार पर भी मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस गम्भीर विषय पर ध्यान देगी और प्रयास करेगी कि भविष्य में जो सब्जियां उगें वह सी.टी.पी.टी. से जो शुद्ध पानी निकलता है, जो खेती के योग्य पानी है, उसी से ही सब्जियां उगें। इतना ही मेरा निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जोधपुर के अन्दर जोधरी नदी में प्रदूषित पानी की समस्या है। यह बात भी सही है कि प्रदूषित पानी सीवरेज का भी आ रहा है। यह प्रदूषित पानी इंडस्ट्रियल एरिया के एफ्यूलेंस का भी आ रहा है, एफ्यूलेंस्ड वाटर का भी आ रहा है। यह बात भी सही है, जैसा आपने कहा कि जोधपुर में 230 एम.एल.डी. पानी सप्लाई किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के ड्रिंकिंग वाटर का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसके अन्दर जो इनपुट डालते हैं और जो आउटपुट आता है, उसमें बड़ा गैप है। यह बात सही है कि 230 एम.एल.डी. का इनपुट डाला जाता है और आउटपुट 180 के नीचे आ रहा है। इसलिये 180 के नीचे एम.एल.डी. का जो आउटपुट आ रहा है, उसके रेफरेंस में भी यह बात सही है कि ट्रीटमेंट प्लाण्ट की व्यवस्था नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर केवल एक सी.ई.टी.पी. लगा हुआ है जो 220 एम.एल.डी. कैपेसिटी का है। जहां तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की बात है, हमारे पास दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट हैं। एक सालावास का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट है जो 50 एम.एल.डी. का है। एक नांदेड़ी पर एस.टी.पी. लगा हुआ है, जो 20 एम.एल.डी. का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सालावास के अन्दर जो एस.टी.पी. लगा हुआ है, उसका एक्सटेंशन करते हुए एक और 50 एम.एल.डी. का एस.टी.पी. हमारे यहां निर्माणाधीन है। साथ ही आसींबेनड़ा के अन्दर 40 एम.एल.डी. का एक एस.टी.पी. बनाने की निविदा हमने आमंत्रित कर दी है। उसके बाद में मैं समझता हूं कि जो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एस.टी.पी. की और सी.टी.पी.टी. की कम्बाइंड पोटेंशियल आयेगी, पानी को ट्रीट करने की वह एटपार से ज्यादा हो जाएगी जो जोधपुर में पानी की सप्लाई है। वर्तमान में आपने कहा कि एन.जी.टी. ने डिसीजन दिया। एन.जी.टी. के डिसीजन में 3-4 चीजें बार-बार कही गयीं। एक तो यह कहा गया कि जो एग्जस्टिंग सी.ई.टी.पी. है उसको अपग्रेड किया जाये। उसके अपग्रेडेशन के लिये दो डिकंटेनर्स लग चुके हैं। बाकी भी अपग्रेडेशन के जितने काम होने चाहिए वह अपग्रेडेशन के काम जारी हैं। साथ के अन्दर 25 बीघा जमीन रीको को नये सी.ई.टी.पी. के लिये हमें देनी है। लेकिन अभी तक रीको ने वह जमीन दी नहीं है। इसलिये वह अभी तक लग नहीं पाया। जिस वक्त रीको यह 25 बीघा जमीन देगा, उसके अन्दर इसकी कार्यवाही कर ली जायेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर में केवल 78 प्रतिशत इलाके के अन्दर, 78 प्रतिशत कवरेज है सीवरेज के अन्दर। पुराना जो जोधपुर शहर है उस शहर के अन्दर 35 साल पुरानी लाइनें डली हुई हैं। इसकी जो मेन लाइन है, ट्रंक लाइन है, उसके अन्दर सीपेज है। अमृत योजना के तहत उसका हमने प्लान बनाया है। प्लान बनाने के साथ जोधपुर की पुरानी सीवरेज लाइन को बदल देंगे। साथ में और कई इलाके हैं, जहां सीवरेज लाइन नहीं पहुंची है। कुछ इलाकों में अभी काम चल रहा है और बाकी बचा हुआ इलाका है, उस बाकी बचे हुए इलाके के अन्दर भी सीवेरज लाइन डालकर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाकर उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी।

आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गंदे पानी के बारे में जो कह रहे हैं आक्शन दे रहे हैं, पानी कुछ बेच रहे हैं। अब उसकी आड़ में जितना पानी बेच रहे हैं उससे ज्यादा पानी वे निकाल करके लोगों को बेच रहे हैं। यह बात सही है। इसलिये जितना पानी हम लोगों ने उनको बेचने के लिये दिया है, उसके अतिरिक्त जो पानी इण्डस्ट्रियल वेस्ट का आ रहा है, जिसके अन्दर कैमिकल्स हैं, मैटल्स हैं उस पानी को भी जोड़कर वह पानी खेतों में दे रहे हैं। उसके कारण, यह बिलकुल सही बात है कि वहां पर कुछ इलाकों में ऐसी सब्जियां उगाई जा रही हैं, जिन सब्जियों के इस्तेमाल के कारण स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव आ रहे हैं। जोधपुर नगर निगम भी कुछ कार्यवाही कर रहा है। वह कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि और विभाग भी उस क्षेत्र में कार्यवाही कर रहे होंगे। यह चिंता का विषय है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

निश्चित रूप से मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अमृत योजना के बाद में दो एस.टी.पी., जिनकी मैंने चर्चा की है, सालावास के अन्दर 50 एम.एल.डी. का जो एस.टी.पी. का प्लाण्ट हमारा चल रहा है, जिसका काम पूरा हो जाएगा और दूसरा जो 40 एम.एल.डी. का हम प्लाण्ट लगा रहे हैं, और 25 बीघा जमीन रीको से मिलने के बाद में जो 20 एम.एल.डी. का एक और प्लाण्ट लगेगा, उस प्लाण्ट के लगने के बाद में जितने पानी की सप्लाई जोधपुर शहर की जनता को हो रही है, उससे ज्यादा कैपेसिटी के ट्रीटमेंट प्लाण्ट जोधपुर की जनता को मिल जाएंगे। इतनी सी बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): बहुत-बहुत आभार, बस जल्दी कीजिये।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कर देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष:** राजकुमारी दियाकुमारी।

## सवाई माधोपुर के मलारना एवं भाड़ोती में पुलिस थाने की मांग

**राजकुमारी दियाकुमारी** (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर देने के लिये धन्यवाद। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में पुलिस चौकी मलारना स्टेशन और पुलिस चौकी भाड़ोती को पुलिस थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहूंगी।

महोदय, सवाई माधोपुर अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहां कानून-व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिये आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन का समय पर उपलब्ध होना अति आवश्यक है। ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को समय पर रोका जा सके। इसी क्रम में मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहती हूं कि विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में पुलिस चौकी मलारना स्टेशन बनास नदी के आसपास के महत्वपूर्ण गांवों के बीच स्थित है। यह चौकी पुलिस थाना मलारना डूंगर के अन्तर्गत आती है। जहां से इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। बारिश के दिनों में इस इलाके के गांवों का सम्पर्क पुलिस थाने से कट जाता है। अत: आपसे अनुरोध है कि पुलिस चौकी मलारना स्टेशन को पुलिस थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार करें। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर स्थित भाड़ोती, जो कि कोटा-लालसोट मेगा

(राजकुमारी दियाकुमारी)

हाई-वे पर स्थित है, यहां हमेशा ही यातायात का भारी दबाव बना रहता है। इस कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं भी होती हैं। यह कम्युनली भी बहुत सेंसिटिव एरिया है। भाड़ोती में वर्तमान में पुलिस चौकी है जो कि पुलिस थाना मलारना डूंगर के अन्तर्गत आती है। पुलिस चौकी भाड़ोती के पास सुविधाओं का अभाव है और पुलिस चौकी की पुलिस थाने से दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। इस कारण अपराध व दुर्घटना के समय पर वे लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं वहां तक। दूसरा नजदीकी थाना बौंली में है, जो कि वहां से काफी दूर है और विधान सभा भी बामनवास है। इस चौकी के आसपास कई बड़े कस्बे बौंली थाने में आते हैं, जिनसे भी थाने की दूरी बहुत ज्यादा है। यदि भाड़ोती चौकी को पुलिस थाना बना दिया जाये तो इन सभी कस्बों को काफी सुविधा मिल जायेगी। इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को और पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भाड़ोती पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना अति आवश्यक है। वर्तमान में डीवाई.एस.पी. के अन्तर्गत पांच थाने आते हैं। बौंली, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूंगर, खण्डार और भरांवडा कलां। यह लगभग 75 से 100 किलोमीटर को कवर करता है। इसलिये नया डीवाई.एस.पी. सर्किल भी यहां बनाया जाना अति आवश्यक है। जिला स्तर से प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाये जा चुके हैं। भाड़ोती के आसपास बनास होने की वजह से अपराध ज्यादा, इस एरिये में थोड़ा उस तरह का भी माहौल रहता है, कम्युनली भी सेंसिटिव है। भाड़ोती हाई-वे है तो वहां एक्सीडेंट्स भी काफी आये दिन होते रहते हैं। इसके लिये बहुत ही जरूरी है कि अगर इस भाड़ोती चौकी को पुलिस थाना बनाया जाये। मैं तो मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर जरूर-जरूर ध्यान दें और यह कार्य जल्द से जल्द पूरा करायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने मलारना स्टेशन और भाड़ोती, दो पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने की मांग की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी परमेश चन्द्र की अध्यक्षता में बना रखी है। उसमें नये थाने बनाना, थानों का समेकन करना, यह सारी चीजें शामिल हैं। अभी इसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट गृह विभाग को प्राप्त हुई है। उस प्रारम्भिक रिपोर्ट में पुलिस चौकी भाड़ौती और पुलिस चौकी मलारना स्टेशन को क्रमोन्नत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करने की अभिशंसा भी प्राप्त हुई है। पूरे सवाई माधोपुर जिले के अन्दर, जो अभिशंसाएं प्राप्त हुई हैं, गृह विभाग उनका परीक्षण करके गुणावगुण के आधार पर इन पर निश्चित तौर पर विचार करेगा।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री ललित कुमार।

(13.00 बजे)

## किशनगंज-शाहबाद के कतिपय बंगाली परिवारों के जाति प्रमाण पत्र

**श्री ललित कुमार** (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पर्ची के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के बंगाली जाति के लोगों के मामले में बोलने का मौका मिला, मेरे बारां जिले में किशनगंज-शाहबाद आदिवासी क्षेत्र में चार गांव बंगाली जाति के लोगों द्वारा बसे हुए हैं।

1956 में एक घट्टी गांव जिसमें सम्पूर्ण बंगाली जाति, 1976 में नाटई, परानियां, नेहरूपुरा, यह चार गांव मेरे बंगाली समाज के लोग सरकार द्वारा 1956 और 1976 में बसाये गये और तब से लेकर आज तक वह वहां पर निवासित हैं। उस समय सरकार ने उन बंगाली परिवारों को 12 बीघा, 10 बीघा, 8 बीघा, प्रत्येक परिवार को जमीन भी अलाट की और वह आज खातेदारी दर्ज होते हुए आज वह वर्तमान में उस जमीन पर काश्त कर रहे हैं।

वर्तमान में 1956 और 1976 के अलावा 1970 में देवली में, टोंक में, जयपुर में, जोधपुर में, सभी जगह पर, पूरे राजस्थान में सरकार द्वारा, जयपुर में भी बंगाली जाति के लोगों को बसाया गया और वर्तमान में वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में खेती कर रहे हैं और उनके रिश्तेदार आज पश्चिम बंगाल में निवासित हैं और आज चार गांवों में बंगाली समाज के हमारे जन-प्रतिनिधि भी जीतकर आए हैं। सरपंच, पूर्व सरपंच, आज नाटई में हमारे बंगाली समाज का, हमारे सरपंच वर्तमान में विद्यमान हैं, पंच हैं, पंचायत समिति सदस्य रहते हुए उप प्रधान तक किशनगंज में रहे हैं, पिछले कार्यकाल में। उनके राशन कार्ड भी बने हुए हैं। राशन-कार्ड, बी.पी.एल. के, ए.पी.एल. के, स्टेट ए.पी.एल. के, अंत्योदय के और खाद्य सुरक्षा के, सभी उनको सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, वह वर्तमान में मिल रही हैं।

यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के चार गांव के अलावा पूरे राजस्थान का

(श्री ललित कुमार)

एक बहुत बड़ा विषय है। पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला और मैं यह कहूंगा कि उन बंगाली जाति के जो परिवार निवासित हैं, उनमें जो उनकी जातियां हैं- वह एक तो नमो-शूद्र, पोद्र, पोद्रा, यह उनकी जातियां हैं, उनकी जाति के अन्दर उनके गोत्र हैं। इन गोत्र के माध्यम से, उनका सबका यह कहना रहता है और 1976, 1956 में वह बसे, तब से लेकर अभी तक उनको उनके जाति के प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। मैं यह कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में आज वर्तमान में और पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे भारतवर्ष में आसाम, उड़ीसा, मेघालय, उत्तरप्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, यह ऐसे राज्य हैं जहां पर इनको इनकी जाति के प्रमाण-पत्र, चाहे वह एस.टी. का हो बंगाली परिवार, चाहे वह एस.सी. का हो, चाहे ओ.बी.सी. का हो, सबको दिये गये हैं।

आसाम, उड़ीसा और मेघालय में तो इनके जन-प्रतिनिधि, मैम्बर आफ लेजिस्लेटिव, और पार्लियामेंट में भी इनके मैम्बर हैं। उस आधार पर इनको वहां पर सुविधाएं और प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं परन्तु राजस्थान, इस प्रदेश के विषय में यह है कि यहां पर हम उन बंगाली जाति के लोगों को, चाहे सरकार द्वारा बसाये गये, सरकार द्वारा सुविधाएं दी गयी हैं परन्तु वर्तमान में अभी तक उनको जाति प्रमाण-पत्र न देते हुए, उनको केवल जनरल में रखा जाता है। इस कारण मेरे जो चार गांव हैं, इन चारों गांवों के मेरे विद्यार्थी और उनके द्वारा 11वीं, 12वीं में पढ़ने वाले और उसके बाद कालेज में, आज वर्तमान में वह कालेज में, बारां में कालेज में, मेरे आदिवासी पिछड़े किशनगंज, शाहबाद सहरिया क्षेत्र में कैलवाड़ा एक मेरा राजकीय महाविद्यालय 2008 में खुला, उसमें अध्ययनरत हैं पर उनको वहां पर केवल जनरल में गिना जाता है, पूरे राजस्थान और मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो मेरा पर्ची के माध्यम से सरकार से अनुरोध है और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसको देखते हुए इसका सर्वे करवाकर हम इन परिवारों को, बंगाली जाति के परिवारों को, इनकी जो जातियां हैं- नमो-शूद्र, पोद्र, पोद्रा, जो भी जातियां हैं इनकी एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी., जो भी कैटेगरीज हैं उस कैटेगरी के आधार पर हम प्रमाण -पत्र देने का विचार रखते हैं क्या ये प्रमाण-पत्र बनाये जा सकते हैं क्या? यह मेरा सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है। धन्यवाद।

**श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। पश्चिम बंगाल से जो बंगाली राजस्थान में आजीविका की तलाश में आए, मेरे कोटा शहर में भी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 8-

(श्री भवानी सिंह राजावत)

10 हजार बंगाली हैं जिनको सरकार ने विस्थापित किया, मकान भी फ्री में बनाकर दिये लेकिन यह जो मामला है जाति का, आज पश्चिम बंगाल में एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी., इसमें बंगाली समाज के लोग आते हैं जो यहां पर भी विभिन्न जातियों के हैं, जो रह रहे हैं। तो जब पश्चिम बंगाल में, दूसरे प्रांतों में हिन्दुस्तान में वह आरक्षित वर्ग में आते हैं, जो भी उनकी जाति के आधार पर निर्धारित किया गया है तो यहां पर भी जो बंगाली समाज रह रहा है, सरकार को विचार करना चाहिए कि उन्हीं जातियों के आधार पर उस जाति के लोग जो यहां पर निवास कर रहे हैं, उनको एस.टी., एस.सी. या ओ.बी.सी. की श्रेणी में उनको लिया जाना चाहिए ताकि उनको उसका लाभ मिले।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है और मानव सेवा से सम्बन्धित है। मेरे किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में भी काफी बंगाली लोग रहते हैं। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आपसे भी ज्यादा गम्भीर है क्या यह मामला?

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): मेरे किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में भी काफी बंगाली परिवार रहते हैं बंगाली परिवार और जो मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, उनके सिविल लाइन्स क्षेत्र में भी काफी बंगाली परिवार रहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: और कहां-कहां रहते हैं?

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): जयपुर शहर में सब जगह रहते हैं, कालीचरणजी के भी रहते हैं। मैं चाहता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इस पर मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): यह महापौर रह चुके हैं, इनको एक-एक गली, एक-एक घर का पता है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के तो घर में भी बंगाली रहते हैं, यह और है।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): आपने आकर देखा क्या?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह आरोप कैसे लगाया?

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): इसलिए इन लोगों को निश्चित रूप से मानवीय आधार पर सुविधाएं दी जाएं। इनके जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की जाए। इस मांग का मैं समर्थन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्री महोदय।

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे पर्ची है। पर्ची पर ही कई लोगों ने अपना विषय रखा है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप स्पेसिफिकली अगर उससे कन्सर्न्ड अगर कोई और जानकारी इनकी भी हो तो दे दें वर्ना You can limit on your version.

**श्री अरुण चतुर्वेदी** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): किशनगंज से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, पहली बात तो हमारे यहां पर बंगाली जाति नहीं है। बंगाली एक समाज है और विशेष रूप से जितना मैं समझ पाया हूं, आपने जो विषय इंगित किया है, 1971 के बाद जो लोग पूर्वी बंगाल से यहां पर आए और अलग शरणार्थी के रूप में रहे और बाद में कुछ लोग उसमें से बोनाफाइड सिटीजन बन गये। उन लोगों को नागरिक होने के नाते से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपने अभी कहा कि वह चुनाव भी लड़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं। ए.पी.एल., बी.पी.एल. जितनी भी सुविधाएं हैं, वह सारी उनको मिल रही हैं। जहां तक जाति प्रमाण-पत्र देने का विषय है। जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए हमारे कुछ गाइड-लाइन्स हैं और जो स्पेसिफिक जातियां हैं, कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. इन सबको उनकी जाति के आधार पर प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था है और कोई भी सक्षम अधिकारी, उसके पास अगर कोई आवेदन करता है तो अगर रेवेन्यू रिकार्ड में उसका नाम है और रेवेन्यू रिकार्ड में अगर नाम नहीं है तो उसके बाद भी एक शैक्षणिक रिकार्ड नगरपालिका या ग्राम पंचायत के रिकार्ड में नाम है, आवेदन करता है तो एक उसकी कहीं जांच के बाद ऐसे आवेदन देने की व्यवस्था है। कम से कम समाज के आधार पर, बंगाली एक समाज है और समाज के आधार पर अब किसी को जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो सकता। उसकी जाति के आधार पर अगर कोई है, जैसा आपने कहा कि कोई अगर अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, अन्य विशेष पिछड़ा वर्ग का है या अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो ऐसे समाज से होकर कोई आता है तो प्रक्रिया के तहत अगर आवेदन करेगा और पूरी उसकी जो इन्ग्रेडिएंट्स है, जो क्वालिफिकेशन है, वह पूरी करता है तो उसको जाति प्रमाण पत्र जारी होगा।

**श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): मंत्री महोदय, आखिर कब तक यह वंचित रहेंगे? कोई समय-सीमा तय की जाए। आवेदन उनसे मांगे जाएं क्योंकि लगातार वह प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है इसलिए इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय आपको करना पड़ेगा। अगर सरकार

(श्री भवानी सिंह राजावत)

चाहती है कि उनको प्रमाण-पत्र दे देंगे जाति के आधार पर, जो पश्चिम बंगाल में है तो इसका अध्ययन करें। पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट मंगवाएं और यहां बाकायदा उनसे आवेदन लें और उसके बाद प्रमाण-पत्र दें।

**श्री ललित कुमार** (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, जब पूरे भारतवर्ष के यह जो राज्य मैंने बताए हैं, इनमें यह व्यवस्था है तो क्यों न राजस्थान सरकार को या सरकार को भी यह वहां से प्रस्ताव मंगाकर इस पर विचार किया जाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय रणधीर सिंहजी भीण्डर।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

## सलूम्बर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की राशन की चीनी की कालाबाजारी

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का सलूम्बर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की राशन की चीनी की कथित कालाबाजारी के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी निम्न प्रकार प्रेषित है:-

यह कि दिनांक 10.01.2016 को सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, अनाज, उदयपुर द्वारा राजस्थान कृषि विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 27 (बी) के तहत तितरड़ी बाइपास रोड पर वाहन संख्या GJ 06 ZZ 2456 की जांच की गयी। जांच करने पर इस वाहन में 200 कट्टे, 100 क्विंटल चीनी पाई गयी। 200 कट्टे मतलब, 100 क्विंटल चीनी। वाहन चालक श्री प्रेमशंकर भनात को पूछने पर यह चीनी खैरवाड़ा के व्यापारी डालचंद की होना बताई।

चीनी के बिल एवं बिल्टी नहीं मिली एवं खाली एक पर्ची मिली जिसमें मोहित व बृज लिखा हुआ पाया गया। इस पर चीनी मय वाहन के जब्त की गयी। तदुपरान्त सचिव कृषि उपज मण्डी द्वारा नियमानुसार शास्ति वसूल कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने पत्र क्रमांक 4402 दिनांक 14.1.2016 से जिला रसद अधिकारी उदयपुर शहर को लिखा गया, प्रति संलग्न परिशिष्ट-एक पर

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

संलग्न है। यह कि दिनांक 11.1.2016 को जिला कलक्टर उदयपुर से जिला रसद अधिकारी उदयपुर को सायं 4.23 बजे जरिये दूरभाष पर प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में क्रय-विक्रय सहकारी समिति सलूम्बर के मादड़ी स्थित गोदाम की जांच की गयी। वक्त जांच सचिव, कृषि उपज मण्डी, मण्डी कर्मचारी श्री कमलेश माथुर को बुलाया गया तथा उसके समक्ष क्रय-विक्रय समिति सलूम्बर के गोदाम की जांच एवं भौतिक सत्यापन किया गया एवं फर्द मौका तैयार किया गया। भौतिक सत्यापन पर स्टाकवार गणना करने पर चीनी के 1678 कट्टे यानी 50 किलोग्राम प्रति कट्टा पाया गया, जिसका संलग्न योग मुताबिक रजिस्टर से सही पाया गया। प्रति संलग्न परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

यह कि पर्चा मौका एवं जांच में जब्त किये गये दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त दिनांक 14.1.2016 को वाहन संख्या GJ 06 ZZ 2456 में चीनी 100 क्विंटल कृषि उपज मण्डी श्री हेमंत भटनागर कनिष्ठ लिपिक कृषि उपज मण्डी को अधिकृत किये जाने पर श्री भटनागर से ट्रक मय चीनी अपने कब्जे में ली गयी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत प्रकरण बनाया जाकर माननीय न्यायालय कलक्टर, उदयपुर की अदालत में दिनांक 15.1.2016 को पेश किया गया। छाया प्रति परिशिष्ट-3 पर है।

यह कि उक्त ट्रक मय लेवी चीनी 100 क्विंटल का उदयपुर का क्रय-विक्रय सहकारी समिति उदयपुर को सुपुर्दगी दी गयी। परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

यह कि दिनांक 10.1.2016 को पर्चा मौका बनाया गया उसमें चालू बिल बुक, स्टाक रजिस्टर, चालान बुक आदि रिकार्ड जब्त किया जाकर उस ट्रक पर हस्ताक्षर किये गये, जिसका हवाला पर्चा मौका में दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लेवी चीनी का संदिग्ध परिवहन होने से एवं बिलों के अभाव में सलूम्बर क्रय-विक्रय समिति सलूम्बर की चीनी को कब्जे में लेकर तुरन्त 15.1.2016 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के सामने प्रस्तुत करने के लिये कहा गया। प्रकरण की आगामी पेशी 22.3.2016 नियत है। यहां यह भी उल्लेखनीय है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उपरोक्त सभी कार्यवाही श्री कुशाल बिलाला, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री निशांत पंचौली, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर टीम जो वहां पर थी, वहां के आदेश से उदयपुर में राष्ट्रीय

(श्री हेमसिंह भड़ाना)
खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भामाशाह पोर्टल पर राशन कार्डों की सूची एवं लाभार्थियों की सूची के शुद्धिकरण के लिये आये थे, उनको भी जांच के साथ रखते हुए उनकी मौजूदगी में जांच की गयी।

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कुछ बताया वह तो मैंने भी इनको जानकारी दी थी। मेरा यह मानना है कि इसमें चार पार्टी इन्वाल्व हैं। एक तो ट्रक और उसका ड्राइवर, एक जिसके नाम से वह चीनी जा रही थी डालचन्द खैरवाड़ा, एक जिसने चीनी भरवाई दलीचन्द डांगी और एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति सलूम्बर है। ये चार लोग इन्वाल्व हैं इसमें। आपने इनके खिलाफ एफ आई आर लाज क्यों नहीं करवायी? आपने क्रय-विक्रय सहकारी समिति सलूम्बर का लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं किया? यह थोड़ा-सा संदिग्ध मामला है। यदि एक क्विंटल चीनी किसी के कम होती है, तो आप लाइसेंस निरस्त कर देते हो। आप एफ आई आर दर्ज करा देते हैं। लेकिन इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्यों जान-बूझकर इनको बचाया जा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं।

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 6 (ए) की कार्यवाही के तहत मामला कलक्टर न्यायालय में है। कलक्टर अपने गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने के बाद वह दोषी पाये जाते हैं तो निश्चित रूप से तीन बटा सात की कार्यवाही होगी और रहा सवाल विभागीय कार्यवाही करने के लिये हमने जिला कलक्टर महोदय को यह पत्र भेजा है 3.3.2016 को, किसी भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिला रसद अधिकारी के अलावा, प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट करावें।

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय मेरे साथ काफी काम कर चुके हैं और इनकी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है और काफी एक्टिव व्यक्ति हैं, लेकिन इनकी जयपुर की टीम पर मुझे बिलकुल भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं तीन डीलर के वहां से निरस्त कराकर माननीय मंत्रीजी ने यहां पर तीन डीलरों की डीलरशिप निरस्त करने की घोषणा की थी। इनके कमिश्नर ने उनको वापस लगा दिया, वह सब काम कर रहे हैं। एक डीलर की हमने यह शिकायत की कि इसके यहां स्टाक से अधिक सामान है। वहां पर जांच के लिये टीम गयी। टीम ने रात तक उसको तोला और तोलने के बाद में उन्होंने कहा कि अब रात बहुत हो गयी, अपन बाकी बचा सुबह तोलेंगे। उनको सील कर दिया। जिन लोगों ने

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

शिकायत की, उन्होंने कहा कि पीछे भी एक दरवाजा है, उसको भी सील कर दो। बोले, पीछे से सील करने की जरूरत नहीं है। रात को आकर उस पीछे वाली को तोड़कर बोरियां खाली कर दी गयीं। यह तो क्या हुआ कि जो सील तोड़ने वाला आया, उसने देखा कि मैं कहीं इसमें नहीं फंस जाऊं तो उसने पूरी वीडियो रिकार्डिंग कर दी और वह वीडियो रिकार्डिंग भी हमारे पास है। इस तरह की कार्यवाही अगर वहां पर हो रही है तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्पूर्ण कार्यवाही को ए सी बी को आप सौंपो, क्योंकि जिस तरह का आदिवासी क्षेत्र में यह चोरीवाड़ा हो रहा है, इस पर कंट्रोल करने के लिये आपके जयपुर के अधिकारी सक्षम नहीं हैं। वह बैठे हुए हैं कि कौन नीचे से आता है, मैं उसको वापस तुरन्त लगा दूं। इसलिए आप इसको ए सी बी से जांच कराने का आश्वासन मुझे यहां पर दें। उससे लगे कि आप सचमुच उन निर्धन लोगों के हित में बात कर रहे हो।

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सलूम्बर के गोदाम की जांच और भौतिक सत्यापन किया गया तथा फर्द मौका तैयार किया गया। भौतिक सत्यापन कर स्टाक की गणना करने पर चीनी के 1678 कट्टे पाए गए जिनका संकलन योग मुताबिक स्टाक रजिस्टर में सही है। हमारे अनुसार तो हमारे रजिस्टर के मुताबिक उसमें योग सही है। उसके बावजूद भी हमने विभागीय आदेश 3.3.2016 को कर दिये कि हम डी एस ओ के अलावा दूसरी कमेटी से इसकी जांच कराएंगे और उसकी 15 दिवस के अन्दर रिपोर्ट की पालना के लिए कहा हुआ है। मेरे सामने पत्र है और आपने जो पी डी एस डीलर सिस्टम की बात बतायी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संवैधानिक दायरे में जब से संविधान बना है, हर व्यक्ति के हर जगह अपने अपने अधिकार हैं। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अगर कोई केस चलता है और उस वाद का मजिस्ट्रेट निस्तारण उसके पक्ष में करे या विपक्ष में करे, उसका अपना अधिकार है। उसके बाद ए डी जे है, ए डी जे के बाद हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। जो इन्होंने तीन डीलरों की बात बतायी, निश्चित रूप से उनका निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद एक न्यायिक प्रक्रिया है, जो कि यहां पर प्रिंसिपल सेक्रेट्री या एफ सी आई विभाग द्वारा अलग-अलग जिले बांटे हुए हैं, उनके यहां अपील का प्रावधान है और अपील के अन्दर उन्होंने यह माना है। वह सही है तो दुबारा जांच करा देंगे और निष्पक्ष जांच करा देंगे।

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): साहब, कोर्ट में कौन जाएगा, वह लोग जाएंगे जिनको वितरण लेना है। क्या उनकी औकात है कि वे कोर्ट में जाएं? यह मंत्रीजी, आपको देखना पड़ेगा कि उन लोगों को कैसे न्याय मिले? हम लोग आपको प्रूफ के साथ कुछ चीज पेश करते हैं, उस पर अगर किसी ने गबन किया है तो चाहे निचली कोर्ट में हो या ऊपरी कोर्ट में हो, वह तो साबित है तो ऊपरी कोर्ट तो उसको कह रही है कि कोई बात नहीं, तूने किया तो 45 दिन का टाइम हो गया, तेरे को वापस मैं दे देता हूं।

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं दोबारा जांच करा दूंगा। यह निश्चित रूप में मैं सदन को भरोसा दिला रहा हूं, दोबारा जांच करा दूंगा।

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): आप तो ए सी बी से जांच कराओ साहब, इस मुद्दे की। (व्यवधान).

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह मेरे क्षेत्र का है, मैं देखता हूं। (व्यवधान).

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): यह 100 क्विंटल चीनी की बात है।

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करा दूंगा। (व्यवधान).

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): यह पहली बार पकड़ में आए हैं, इनकी आप ए सी बी से जांच कराओ। (व्यवधान).

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के रिकार्ड के मुताबिक 6(ए) की कार्यवाही हमने की है और हमने जब मिलान रजिस्टर का पाया है तो हम कैसे उसमें बता दें कि पी डी एस का गेहूं है या आम बाजार का गेहूं है। तब तक सत्यापन नहीं हो सकता, जब तक कलक्टर 6(ए) की कार्यवाही में उसकी निष्पक्ष जांच कर रहा है, कलक्टर को लगेगा कि वास्तव में यह पी डी एस का है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गबन हुआ है, तो निश्चित रूप से सम्बन्धित न्यायालय में वाद भी चलेगा और सम्बन्धित थाने में मुकदमा भी दर्ज होगा।

**म. रणधीर सिंह भीण्डर** (वल्लभनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रथम सत्र में यह निवेदन किया था कि जितनी भी गाड़ियां आपकी जाती हैं, उन पर जी पी एस लगवा दो ताकि पता चले कि वह डीलर के पास जा रही हैं या

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

किसी मिल में जा रही हैं। हमारे वहां पर यह धंधा हो गया है कि लोग-बाग़ ...(व्यवधान) एक मिनट मंत्रीजी, मेरी पूरी बात सुनो। होता यह है कि गोदाम से माल उठता है, माल उठकर डीलर के वहां जाने के बजाय आटा मिल में जाता है, फिर डीलर को पता चलता है कि आटा मिल में पहुंच गया तो वह डीलर फोन करता है गोदाम में, कि हां माल पहुंच गया है तो वह फिर एण्ट्री करते हैं कि हां, यह माल यहां से जाकर उस डीलर के चला गया है, आप लोग इसकी जांच कराओ। मैं आपको कहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। आप जांच कराओगे तभी इसमें साबित होगा और मैं आपको कह रहा हूं आपके विभाग के अधिकारियों से मत कराओ, नहीं तो कुछ नहीं आएगा इसमें। वह इसी तरह से निर्दोष साबित करते रहेंगे उनको। आपको यह कार्यवाही ए सी बी को देनी चाहिये, जिससे यह एक एक आदमी पकड़ में आए कि इसमें कौन-कौन इन्वाल्व है। धन्यवाद।

**श्री हेमसिंह भड़ाना** (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने आश्वस्त कर दिया कि इसको विभाग के अलावा उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करा लूंगा मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं इन्होंने जिस चीज की शिकायत की है अभी तक तो उसका आन रिकार्ड पी डी एस का होना नहीं बताया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री ललित कुमार। श्री ललित कुमार। (अनुपस्थित)

क्या हो गया उनको? There is 131 also. ललित कुमार। (व्यवधान) is the same, विषय वो का वो है whether he can come and say that. अगर आपका विषय पर्ची पर कवर हो गया and if you do not want it. इसमें आपका सहरिया भी है। You want to speak or you don't want to speak.

**श्री ललित कुमार** (किशनगंज): No. Sir. Same matter for…..

**श्री उपाध्यक्ष:** OK. Thank you. Sit down.

# सूचना

## नगर निगम द्वारा टैक्स वसूली की प्रक्रिया के विरोधस्वरूप विभिन्न व्यापार संघों द्वारा कोटा बंद का आयोजन

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विभिन्न व्यापार संघों द्वारा कोटा बंद का आह्वान किया गया है। सवेरे आठ बजे से लेकर अभी तक कोटा की एक-एक दुकान बंद है और इसके पीछे जो बड़ा कारण है, नगर निगम द्वारा

(श्री प्रहलाद गुंजल)
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में जो टैक्स वसूली की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का वायलेशन करके शक्ति पूर्वक तरीके से यू.डी. टैक्स वसूल रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका में ...

**श्री उपाध्यक्ष:** पाइंट आफ इन्फोर्मेशन में आप सूचना दें ...(व्यवधान)

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): केवल दो मिनट।

बाध्यकारी कर 102 में प्रोविजन है और जो वसूली की प्रक्रिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 में और उसमें साफ लिखा हुआ है ...

**श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): ×××

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): एक मिनट, बात पूरी करने दें। एक मिनट बात पूरी कर लूं मैं।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** How many people are going to inform the Chair? How many of you are going to inform? The whole 200 of you?

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए।

**श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): ×××

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): ×××

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** अब आप सम्पूर्ण कोटा से आने वाले सम्माननीय सदस्यगणों, आप एक बार अपने-अपने स्थान पर विराजो।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के दायरे में एक बात कहना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** अब मैं भी नियमों के आधार पर कुछ बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन चेयर जिसको परमिट करती है He is allowed to address the Chair and inform. No deliberation is required. अगर डेलिबरेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अलग नियम हैं।

(श्री उपाध्यक्ष)

और सरकार के ध्यान में लाने वाली बात है, उनको आप यह सूचना दे रहे हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति विगत चौबीस घंटे के भीतर-भीतर हुई है।

अगर आप में कहीं प्रतिस्पर्धा है आपस में तो उसके लिए बहुत-सी और जगह हैं, यह स्थान तो आप सब का सामूहिक रूप से है और अगर एक व्यक्ति, एक माननीय सदस्य यह सूचना दे रहे हैं तो मैं यह मानता हूं कि बाकी सदस्यों की भावना भी आपकी सूचना में सम्मिलित है। अब आप फरमाओ।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि नियम 131 में साफ लिखा हुआ है, चल सम्पत्ति पर कुर्की का अधिकार कमिश्नर को होगा और अचल सम्पत्ति पर कुर्की का अधिकार नगरपालिका को होगा। आप लिटरेट व्यक्ति हैं, आपने इस अधिनियम में नगरपालिका को परिभाषित किया हुआ है। नगरपालिका से आशय, नगर निगम, नगर परिषद और कोई नगरपालिका का बोर्ड अभिप्रेत है। बोर्ड का फैसला नहीं है, वहां 65 सदस्यों का निर्वाचित बोर्ड है, उन्हें अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखना, व्यापारी का ध्यान रखना और नगरपालिका के, निगम के हितों का भी ध्यान रखना है।

बोर्ड में कोई फैसला पारित नहीं हुआ और अचल सम्पत्तियों को जाकर दादागीरीपूर्वक तरीके से ताले लगाये जा रहे हैं, सीज किये जा रहे हैं। हालात यहां तक पैदा हो गये कि जिन सामुदायिक निजी केन्द्रों के अन्दर शादियों की बुकिंग हैं, दूल्हा-दुल्हन गेट पर खड़े हैं, जाकर ताले लगा दिये। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: सम्माननीय सदस्य, सूचना आ गयी और सूचना पहुंच गयी, सूचना समझ ली गयी।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): इसलिए मैं आपके प्रोटेक्शन में केवल इतना चाहूंगा कि नियमों के दायरे में बोर्ड जब तक प्रस्ताव पारित नहीं करे, सरकार अधिकारियों को डाइरेक्शन दे कि हिटलरशाही वृत्ति को त्यागें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): ×××

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन। श्री कालीचरण सराफ।

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक मिनट, कालीचरण जी सराफ साहब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पाइंट आफ आर्डर पर डिबेट ही हो गयी है ...

**श्री उपाध्यक्ष:** Do you want to react on point of information?

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): I think this is not a point of information. I mean it may be debate also.

**श्री उपाध्यक्ष:** OK. If you feel comfortable, I don't mind.

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): I don't feel uncomfortable. I feel comfortable that on a point of information there can be a deliberation in the House.

आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे जानकारी है, आज कोटा में कुछ लोग बंद कर रहे हैं। कानून सम्मत ढंग से ही काम करेंगे। टैक्स के कलेक्शन की एक प्रक्रिया है, टैक्स के कलेक्शन की प्रक्रिया के तहत टैक्स का कलेक्शन किया जायेगा। लेकिन टैक्स के कलेक्शन का कलैक्टिव विरोध कर के उसको एट्रोसिटी के रूप में दिखाना भी शुभ नहीं है।

मैं देखता हूं, कानून सम्मत ढंग से अगर काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से टैक्स का कलेक्शन कानून सम्मत ढंग से किया जायेगा।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): 131 में प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करके करें तो कोई आपत्ति नहीं है, बोर्ड की एप्रूवल नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष:** आसन की अनुमति के बगैर जो कुछ भी कहा है वो अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण जी सराफ।

## सदन पटल पर रखे गए पत्र

## प्रतिवेदन एवं लेखे

### महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

(श्री कालीचरण सराफ)

अधिनियम, 1987 की धारा-38(4) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री मोहन लाल गुप्ता।

# समिति प्रतिवेदन

## राजकीय उपक्रम समिति (क्रम सं. 37 से 58)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2015-16 के निम्नांकित 22 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-4) वर्ष 2009-2010) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 37वां प्रतिवेदन;

2- बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की संयुक्त कम्पनी) (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 38वां प्रतिवेदन;

3- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-) वर्ष 2010-2011) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 39वां प्रतिवेदन;

4- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 40वां प्रतिवेदन;

5- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2011-2012) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 41वां प्रतिवेदन;

6- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-2) वर्ष 2011-2012) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 42वां प्रतिवेदन;

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

7- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2011-2012) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 43वां प्रतिवेदन;

8- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2012-2013) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 44वां प्रतिवेदन;

9- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-1) वर्ष 2012-2013) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 45वां प्रतिवेदन;

10- राजस्थान वित्त निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2012-2013) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 46वां प्रतिवेदन;

11- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 36वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 47वां प्रतिवेदन;

12- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2003-2004) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 72वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 48वां प्रतिवेदन;

13- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1998-1999) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 74वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 49वां प्रतिवेदन;

14- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 75वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 50वां प्रतिवेदन;

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

15- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 76वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 51वां प्रतिवेदन;

16- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 52वां प्रतिवेदन;

17- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2002-2003) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2012-2013 के 104वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 53वां प्रतिवेदन;

18- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 5वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का 54वां प्रतिवेदन;

19- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2009-2010) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 16वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 55वां प्रतिवेदन;

20- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2010-2011) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 17वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 56वां प्रतिवेदन;

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

21- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण व जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-2) वर्ष 2011-2012) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 18वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 57वां प्रतिवेदन; एवं

22- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (संख्या-4) वर्ष 2010-2011) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के 26वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 का परिपालनात्मक 58वां प्रतिवेदन।

**श्री उपाध्यक्ष:** याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती द्रोपती।

# याचिका

## पीलीबंगा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान

**श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में। श्री कालू लाल गर्जर।

# समिति का गठन

## वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2016-2017 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2016-2017 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2016-2017 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

**(स्वीकृत)**

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री कालू लाल गुर्जर।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** यह तो हो गया।

## वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

'राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1), 231, सहपठित नियम-232 (1), 233-खा (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2016-

(श्री कालू लाल गुर्जर)

2017, प्राक्कलन समिति 'क', 2016-2017, प्राक्कलन समिति 'ख', 2016-2017 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231 सहपठित नियम 232 (1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें'।

**श्री उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये?

**(स्वीकृत)**

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 । श्री वासुदेव देवनानी।

# अनुदान की मांग

## मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 209,22,23,63,000/- (अक्षरे दो सौ नौ अरब बाइस करोड़ तेइस लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

**(मांग संख्या 24 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)**

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री फूलचन्द भिण्डा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री उपाध्यक्ष**: व्यवस्था का प्रश्न है।

## व्यवस्था का प्रश्न

### सदन में मांग पर विचार से पूर्व सम्बन्धित विभागों के प्रतिवेदन मिल जाने चाहिए

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि रुल 127 के तहत डिमांड हो, उससे पहले हाउस में प्रगति प्रतिवेदन ले-आउट होना चाहिए आज शिक्षा के ऊपर है, आपने बार-बार यहां से निर्देश भी दिया है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ। उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने आज महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय का पेश किया है, आज तो सदन में हम आये हैं, माननीय सदस्यों को अभी मिला नहीं।

इस आसन से बार-बार यह व्यवस्थाएं दी गई हैं कि जो डिले करने वाले जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि पहले की व्यवस्था जो आसन की दी हुई है, उसमें तो क्या कार्यवाही हुई और इनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करोगे जिन्होंने यह डिले किया है।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी ...।

**श्री उपाध्यक्ष**: व्यवस्था का प्रश्न था। आसन को जवाब देने दीजिये।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जिस विभाग की मांग होती है, उससे सम्बन्धित सभी प्रगति प्रतिवेदन उससे पहले आ जाने चाहिए। रुल 126 में इस पर उल्लेख भी किया गया है। हम पूरे मामले को दिखवायेंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उसका उतरदायित्व निर्धारण करेंगे और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको सुनिश्चित करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: वैसे आसन विधान सभा सैक्रेटेरिएट को यह भी आदेश देता है कि अब तक जितने प्रगति प्रतिवेदन आने चाहिए थे, उसमें से जो नहीं आए उनकी सूची पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को जरूर पहुंचा दी जाये।

डा. फूलचन्द भिण्डा।

## मांग संख्या 24 पर विचार

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज डिमांड संख्या 24 पर आपने मुझे अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान महिला शिक्षा में अंतिम छोर पर है, 35वां स्थान है। केन्द्र शासित प्रदेशों से भी नीचे स्थान है। पुरुष शिक्षा में हमारा 27वां नम्बर है। जब हम आजाद हुए थे तब 8 परसेंट साक्षरता थी। आज वह साक्षरता बढ़कर के 66 परसेंट हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन महिला शिक्षा हमारे प्रदेश में चिंताजनक है, 3 परसेंट पर 1951 में हम थे महिला शिक्षा साक्षरता में और आज वह 52 परसेंट हुई है। लगभग आधी महिलाएं साक्षर हैं।

आजादी के 67 साल बाद 52 परसेंट महिलाएं साक्षर हों, यह समाज और देश के लिए, राज्य के लिए चिंता की बात है। पिछले 67 वर्ष में शिक्षा में कई नवाचार हुए। लेकिन कभी भी योजनाबद्ध तरीके से या यह कहूं कि संगठित तरीके से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं हुआ।

पिछले 2 साल में, वर्तमान सरकार आने के बाद में गुणात्मक शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया है, नवाचार भी किये गये हैं, 1 से 12 तक के विद्यालयों का एकीकरण किया गया है। उसके कारण से छात्र-शिक्षक अनुपात भी ठीक हुआ है। 2011-12 में एक के बदले 33 शिक्षार्थी थे। आज उसको हम एक के बदले 28 पर ला पाये हैं। यह एक शुभ संकेत है। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में 18 बच्चों पर एक शिक्षक था, उसको हम 14 पर ला पाये हैं। हालांकि पिछले राज्यपाल के अभिभाषण में और बजट में यह आरोप लगा कि शिक्षा पर कुछ नहीं हुआ। यह दोनों ही इस बात के इंडिकेटर हैं कि शिक्षा में कुछ ठीक दिशा में परिवर्तन हुआ है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्य में वह धार नहीं है, वह तेज नहीं है। यह क्या कारण है?

**श्री उपाध्यक्ष**: यह धीरे-धीरे परवान चढ़ेंगे।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): कई बार आप ही कहते हो कि हमारे समझ में नहीं आया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं।

माननीय सदस्य, शिक्षा वह इंडिकेटर है जो समाज देता है और व्यक्ति को प्राप्त होता है, इंडिविजुवल व्यक्ति को प्राप्त होता है। सड़क सबके

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

काम आती है, बिल्डिंग सबके काम आती है, चिकित्सालय सबके काम आता है। शिक्षा ऐसा सूचक है जो व्यक्ति को प्राप्त होता है इस कारण से हमारे पूर्वजों ने ...।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): शिक्षा भी काम आती है। आपके ज्यादा शिक्षा है तो हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता है कि आपसे लेकर के। सबके आता है।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): ज्ञान बढ़ने वाला नहीं, जो ग्रहण करता है वह इंडिविजुवल करता है और यही कारण है कि हमारे यहां गुरु ऋण की व्यवस्था की गई थी कि समाज आपको दे रहा है और आप उसको बाद में चुकाना। ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने की है। यह महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको समझना चाहिए।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आप इनको गुरु बनाओगे, गुरु दक्षिणा दोगे तो शिक्षा आपके पास आयेगी, वरना नहीं आयेगी।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मैं तो देखो, शिक्षा में तो इनको गुरु बनाऊंगा और सोने में आपको गुरु बनाऊंगा।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): वह भी मंजूर है, कोई बात नहीं।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): विवेकानंद जी ने यह कहा है कि शिक्षा अन्तर निहित जो गुण हैं व्यक्ति के, उनको प्रकट करने का काम करती है ...(व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): बैठने में किसको बनाओगे गुरु?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): कम से कम आपको तो नहीं बनाऊंगा। सारे दिन उठते रहते हो।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय को बना लो, जो बैठाने की व्यवस्था कर रहे हैं वह।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपको तो चाइना जाऊंगा ना तब बनाऊंगा। चाइना में क्या-क्या देखना है तब बनाऊंगा आपको।

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): विवेकानंद जी कहते हैं कि अन्तर निहित जो गुण हैं उनको प्रकट करने का काम शिक्षा करती है। लेकिन वह तब प्राप्त होता है गुरु का ज्ञान, जब उसके प्रति संकेन्द्रण हो, श्रद्धा हो। और श्रद्धा

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

तब प्रकट होती है जब गुरु गुणवान हो। यह विवेकानंदजी ने कहा, पढ़ना आप, पढ़ना चाहिए उनको।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2012-13 में हमारे प्रारम्भिक शिक्षा पर 1840 करोड़ रुपए मात्र खर्च हुए थे। इसको हमने 2 साल में ही 5613.82 करोड़ रुपए किया, यह लगभग 94 परसेंट वृद्धि है, यह एक ऐतिहासिक काम है, इसके परिणामस्वरूप ही जो 4447 स्कूलें टेन प्लस टू की थीं। एक बड़ा धक्का, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, प्लानिंग में एक सिद्धांत आता है, बिग पुश थियरी, शिक्षा का विकास करने के लिए बिग पुश थियरी का प्रयोग हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने करके 5000 स्कूलें एक साथ प्रारम्भ कीं। पहले 4447 थीं, एक साथ 5000 खोली हैं, जबकि हमारे विपक्ष के बंधु यह कहते हैं कि कुछ नहीं किया। कक्षा 1 से 12 के विद्यालय होने से उसका परिणाम भी आने लगा है। मैं वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी का भी धन्यवाद दूंगा, पिछले सदन में भी मैंने कहा था कि प्रशासन को ठीक करने का तरीका है कि जो कर्मचारी होते हैं उनकी इच्छा होती है कि हमारा प्रमोशन ठीक समय पर हो। पहली बार है जब इस एक वर्ष में दो बार डीपीसी हुई और इस कारण से जो उच्च पोस्ट है, प्रिंसीपल की पोस्ट है, हैड मास्टर की पोस्ट है, यह 85 परसेंट तक भर दी गई। एक लीडर विद्यालयों को मिला है और उसी का परिणाम यह आया कि साढ़े आठ लाख विद्यार्थी एक साल में बढ़े जबकि पहले गिरावट थी। इसके लिए मैं वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी को और वर्तमान माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शिक्षा में एक गुणात्मक परिवर्तन करने का प्रयास किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि लगभग 22 परसेंट पद प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। 2,38,000 के लगभग पद हैं उनमें से 1,87,000 भरे हुए हैं और 51,000 खाली हैं क्योंकि प्राथमिक विद्यालय और सरकारी विद्यालय में वही बालक जाता है जो अत्यन्त गरीब होता है। सामान्य तौर पर प्राइवेट स्कूलें भी खुली हैं पर फिर भी गरीब का बच्चा, यह जो 25 प्रतिशत का आरटीई में आया है उसके कारण से है लेकिन फिर भी दूरदराज के क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्राइवेट स्कूल नहीं होते, कितनी सुविधाजनक स्कूलें हैं लेकिन दूर है, रहने की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण नहीं आ पाते इसलिए प्राथमिक शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हजारों की संख्या में स्कूलें बंद की जा रही हैं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वहां बिल्डिंग बनी हुई है और उसका कारण बच्चे नहीं हैं, अभिभावक नहीं है, उसका कारण था कि हमने, पिछली सरकार ने बार-बार यह घोषणा की कि चार प्लस एक, कक्षा कितनी आठ, आठ कक्षाओं पर घोषणा की गई सदन में, पिछले मुख्य मंत्री ने की, शिक्षा मंत्री ने की, चार प्लस एक करेंगे, कक्षा आठ है, गरीब का बच्चा पढ़ता है, यह कौनसी दुनिया का फार्मूला है शिक्षा को विकसित करने के लिए कि आठ कक्षाएं हैं, चार प्लस एक में एक हैड मास्टर होगा और चार अध्यापक होंगे। वह भी भरे नहीं गए इस कारण मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और कक्षा के हिसाब से अध्यापक हों, संख्या के हिसाब के अनुसार अध्यापक नहीं, कक्षा के अनुसार अध्यापक हों। गरीब हों तो क्या हुआ, पांच बच्चों पर भी पूरे अध्यापक हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्यालय बंद किए गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए नई प्रकार का पीपीपी मोड डवलप करें। वहां बिल्डिंग सरकार की है, वहां के युवा बेरोजगारों को कहा जाए कि आप जितने बच्चे करेंगे इस विद्यालय में, उनको पढ़ाएंगे उनके हिसाब से हम आपको मानदेय देंगे। ऐसा करने पर और दूसरा तरीका यह है कि बाल घर के रूप में हम विकसित करें जैसे गुजरात में है कि दूसरी कक्षा तक के बाल घर हैं तो बच्चा स्थानीय स्तर पर पढ़ता है, जब वह पांच-छह साल का हो जाता है तो वह डेढ़-दो किलोमीटर तक चला जाता है, तीसरी क्लास में चला जाता है तो एकल शिक्षक विद्यालय के रूप में जो बाल घर गुजरात में उचित प्रकार से चल रहे हैं हमारे यहां भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे यहां पर भी वह बिल्डिंग, करोड़ों की जो बिल्डिंगें हैं, जमीनें हैं, गांव में मिलती नहीं है, वे जमीनें किसी ने दान में दी है और आज उनको बंद किया जा रहा है तो उनको बचाने के लिए भी और एक शिक्षा का जो वेल्थ है एक तरह से वह बिल्डिंग और जमीनें हैं, वहां आने वाले समय में बालकों की जनसंख्या तो बढ़ेगी ही, सुविधाएं भी बढ़ेंगी ही तो निश्चित तौर वहां विद्यालयों को बनाए रखा जाए। लेकिन जो अव्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में पिछले सात-आठ साल में थी उसके कारण से बच्चे घटे हैं। इस पर पूर्ण विचार करके बाल घर की व्यवस्था की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार हमारे बजट में भी अनबैलेंस है। हमारे 50 परसेंट बजट प्राइमरी एजूकेशन पर है, 43 परसेंट माध्यमिक शिक्षा पर है, लेकिन उच्च शिक्षा में केवल 3.7 परसेंट बजट है। जब 5000

(डा. फूलचन्द भिण्डा)
स्कूलें खोल दी गईं तो 5000 स्कूलें खोल देने के कारण से जो ग्यारहवीं खुल गई, बारहवीं खुल जाएगी, जो बालक बारहवीं पास करेगा वह आगे कालेज में एडमिशन चाहेगा और उसी अनुपात में 3.7 परसेंट जो बजट है वह वैसे भी जो नेशनल स्टैंडर्ड है कि कम से कम 6 परसेंट उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाए उसको बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने, उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने जवाब दिया कि संसाधन उपलब्ध होने पर करेंगे। 164 विकास खंड ऐसे हैं, जिन विकास खंडों में कालेज नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिल्डिंग का जहां तक सवाल है, एमएलए लैंड के 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आते हैं, सांसद के 10 करोड़ होने वाले हैं तो उस विकास खंड में 2 करोड़ रुपए एमएलए दे, 1 करोड़ सांसद दे, 3 करोड़ में आराम से बिल्डिंग बन सकती है और प्रत्येक ब्लाक में और उसके लिए भी मैं स्टेटिस्टिक्स के आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि 2 सैक्शन का अगर कालेज खोला जाएगा, एक संकाय का तो आप 2 करोड़ रुपए में साल भर चला सकते हैं। 100 करोड़ में 50 कालेज खोल सकते हैं, हर साल 50 खोल सकते हैं, उसके अगले साल फिर 50 खोल सकते हैं, लगभग 500 करोड़ का जो बजट है इसी में सारी कालेज खोलकर प्रत्येक विकास खंड में क्योंकि प्रत्येक पंचायत का बच्चा है वह बारहवीं पास करके लड़के और लड़कियां दोनों ही कालेज मांगेंगे और हरेक आदमी जा नहीं सकता कालेजों में इस प्रकार की स्थिति है। इसके कारण से यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि उच्च शिक्षा का जो बजट 3.7 है उसको 6 परसेंट करके अगर 6 परसेंट करेंगे तो आपको माननीय मंत्रीजी, आपको 1500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर इसको 6 परसेंट तक ले गए। मेरा निवेदन है कि इस वर्ष कम से कम 1 परसेंट बजट बढ़ाकर हमारे जितने भी सभी साथियों की मांग है कि कालेज खोले जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक सुखद तथ्य यह भी है कि छात्राओं की जो विकास दर है, वृद्धि दर है वह 7.8 है और बालकों की जो वृद्धि दर है स्कूल में वह 4.44 है तो यह एक अच्छी सुखद स्थिति है। 100 बालकों पर 97 बालिकाएं पढ़ने लगी हैं, इन्हें सुविधाएं देना जरूरी है आगे जब 5000 एक साथ स्कूल खोलें हैं तो निश्चित तौर पर विशेष तौर पर बालिकाओं को क्योंकि बालिकाएं दूर तक नहीं जा सकतीं, लटकनी जीपे हैं, साधन नहीं है उस प्रकार से नहीं जा सकतीं इसलिए बहुत आवश्यक है इसलिए यह किया जाए।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा पर भी आज चर्चा है। संस्कृत शिक्षा में 29 कालेज सरकारी हैं, 27 निजी हैं। माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय मिलाकर 1300 के लगभग संस्थाएं हैं और 2 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4 सीनियर हायर सैकण्डरी हैं और विराटनगर प्रोपर में बिल्डिंग भी पर्याप्त है तो चार में से एक में कालेज खोलने की आवश्यकता है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि विराटनगर में संस्कृत का कालेज खोला जाए। इसी प्रकार से कक्षा बारह के जो विद्यालय हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सात नई पंचायतें गठित हुई हैं उनमें एक पंचायत चिमनपुरा में पहले से हायर सैकण्डरी स्कूल है लेकिन दो पंचायतें ऐसी हैं जिनमें दसवीं का स्कूल है उनको बारहवीं का करने की आवश्यकता है। निजी स्कूल भी बारहवीं का नहीं है, पापड़ा और करोड़ी में। इसी प्रकार ऐसी पंचायतें हैं जहां मिडल स्कूल है उसमें भी राड़ाकाबास, प्रेमनगर, वीर तेजाजी और केरली, ये चार स्थान पर सैकण्डरी स्कूल करके सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल करने की आवश्यकता है, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से तकनीकी शिक्षा में अनबैलेंस है। जो इंजीनियरिंग कालेज हैं वो खाली पड़ी है, पोलीटैक्निक कालेज खाली पड़ी हैं लेकिन आईटीआई, जो सरकारी आईटीआई हैं या प्राइवेट आईटीआई हैं उनमें अभी भी दबाव है बच्चों का। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आईटीआई स्कूलें क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो 19000 रुपये फीस है उसमें अभी वृद्धि की गई है, वह बच्चा नहीं दे सकता लेकिन जो भी विकास खंड ऐसे हैं जहां सरकारी आईटीआई नहीं है वहां आईटीआई खोली जाएं उसमें मेरे भी दोनों पंचायत समिति, विकास खंड पावटा और विकास खंड विराटनगर, दोनों में सरकारी आईटीआई नहीं है इस कारण से सरकारी आईटीआई खोली जाए। मैं आपके माध्यम से सुझाव दूंगा कि कम से कम रोजगार की जब हम बात कर रहे हैं, कौशल विकास की बात कर रहे हैं तो आईटीआई के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक आईटीआई खोली जाए जिसके कारण से स्थायी तौर पर क्लासरूम उनको मिले क्योंकि जब कौशल विकास के जो केन्द्र खोल रहे हैं वह अस्थायी हैं लेकिन आईटीआई ऐसे केन्द्र हैं जो स्थायी तौर पर मिल सकते हैं इसलिए आईटीआई सभी विकास खंडों में एक-एक सरकारी आईटीआई खोला जाए

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से राजस्थान में जो महिलाओं का विकास है उसमें बहुत असंतुलन है। 195 सरकारी कालेज हैं और 1432 निजी कालेज है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो अनबैलेंस हैं 41182 की जनसंख्या पर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा संस्थाएं हमारे हैं, 41182 पर एक सरकारी कालेज है। हम जब इसका आकलन करते हैं तो अजमेर सम्भाग में 58900 पर एक कालेज है, बीकानेर में 32000 पर एक कालेज है, जयपुर में 23000 पर एक कालेज है, लेकिन जोधपुर में, दो बार मुख्यमंत्री रहे, पहले भी मुख्यमंत्री रहे, 5-5 मुख्यमंत्री जोधपुर ने दिये, उस जोधपुर सम्भाग में 85000 पर एक कालेज है। उदयपुर में 75000 पर एक कालेज है, कोटा में 81000 पर एक कालेज है और भरतपुर में 43000 पर एक कालेज है। इसमें और ज्यादा विसंगति है। अजमेर सम्भाग में 58000 पर कालेज होते हुए भी भीलवाड़ा में 104000 पर एक कालेज है। हनुमानगढ़ में 21000 पर ही एक कालेज है। झुंझुनूं में, सर्वश्रेष्ठ स्थिति झुंझुनूं की है, 15618 पर ही एक कालेज है। लेकिन बाड़मेर में 104000 पर और जैसलमेर में 168000 पर एक कालेज है। इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, इस अनबैलेंस को ठीक करने की आवश्यकता है। चितौड़गढ़ भी पीछे है, 125000 है, राजसमन्द तो और ज्यादा पीछे है, 165000 पर एक कालेज है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का झालावाड़ जिला है उसमें भी 108000 के लगभग है। धौलपुर जरूर ठीक है कि 24000 पर एक कालेज है। यह अनबैलेंस है इसको ठीक करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को यह कहूंगा कि जो रूल बनाते हैं प्राइवेट कालेजों के लिए और गवर्नमेंट कालेजों के लिए, इसमें आप क्षेत्रवाइज ध्यान देकर जो अनबैलेंस है उसको ठीक करने का करें। अब हर जगह, डूंगरपुर में कोई भी प्राइवेट स्कूल खोलना चाहेगा, जैसलमेर में खोलना चाहेगा, वहां सुविधाएं कहां हैं इस कारण से वहां रियायत और देनी चाहिए। ये एफ डी की चिन्ता करते हैं, बिल्डिंग की चिन्ता करते हैं वहां तो हर प्रकार की सुविधा देकर भी कालेज खोली जानी चाहिए, ऐसा सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं।

इसी प्रकार से राजस्थान में शिक्षा की स्थिति है, 2013-14 के चुनाव में जो घोषणा पत्र था और जो पिछला बजट था उसमें घोषणा की गयी थी कि महिला शिक्षा को नि:शुल्क किया जाएगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि 7 और 4 बालिका कालेज ऐसे हैं जिनमें बच्चियों द्वारा फीस लेकर शिक्षकों को पेमेंट किया जाता है। 7

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कालेज सहशिक्षा के हैं जिनमें बच्चों से फीस लेकर पेमेंट किया जाता है। कम से कम इन कालेजों को सरकारी कालेज बनाया जाय जिससे एक तरह से हमारी जो घोषणा है वह पूरी हो जाय।

## व्यवस्था का प्रश्न

### मांग पर विचार के समय सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि सबसे महत्वपूर्ण मांग पर विचार-विमर्श हो रहा है और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, फिर भी शिक्षा विभाग के सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी जो यहां होने चाहिए वे यहां नहीं हैं। पिछली बार भी, दो दिन पूर्व भी यह विषय उठा था। मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि बिना उनकी मौजूदगी में जो यह चर्चा हो रही है उसका कोई औचित्य नहीं है।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): आपकी सरकार में दम नहीं है इसलिए यहां नहीं आ रहे।

**श्री उपाध्यक्ष**: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप कुछ फरमाना चाहेंगे इस प्रसंग में।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्षमायाचना के अलावा मेरे पास शब्द नहीं है और मुझे इस बात का खेद है कि आसन से स्पष्ट निर्देश के पश्चात आपके हुकम पर संसदीय कार्य मंत्रालय से स्पष्ट आदेश निकलने के पश्चात् भी प्रमुख शासन सचिव अगर उपस्थित नहीं हैं तो मैं तो प्रशासनिक विभाग के मंत्री महोदय से कहूंगा वे लिखकर दें और मैं भी लिखूंगा कि इस प्रकार विधान सभा का अनदेखापन होगा तो उचित नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकार लिया तो मैं एक स्पष्टीकरण और देना चाहूंगा। अभी प्रतिपक्ष के माननीय सचेतक महोदय ने एक बात उठायी थी कि आज शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल का प्रगति प्रतिवेदन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश पर जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो जो वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का है उसके अन्दर यह समावेशित है और हमेशा समावेशित होता आया है। पृष्ठ संख्या *77* पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर, इसका पूरा प्रगति प्रतिवेदन इसके अन्दर सम्मिलित है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना सचिव, राजस्थान विधान सभा को भी उन्होंने दे दी थी कि यह जो प्रगति प्रतिवेदन पाठ्य पुस्तक मण्डल का आया है यह इसमें समावेशित होकर माननीय सदस्यों को वितरित किया जा रहा है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल अलग से आता है, अबकी बार नहीं आया है। आप बचाने की कार्यवाही क्यों कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्रीजी? वे दोषी हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, कुछ कार्य तो आसन पर भी छोड़ दें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसलिए इस स्पष्टीकरण के साथ मैं टेबल करना चाहता हूं ताकि आसन इसका अवलोकन फरमा लें और उसके पश्चात भी आसन का कोई निर्देश होगा तो उसकी पालना करेंगे। इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य सचिव महोदय को पत्र लिखकर फिर कहूंगा।

## व्यवस्था

## मांग पर विचार के समय सम्बन्धित विभाग के अनुपस्थित अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की जाए

**श्री उपाध्यक्ष**: मैं समस्त मंत्रीगण जिनकी आज यह मांग है, आसन आपसे निवेदन कर रहा है और स्पष्ट कर रहा है जिन अधिकारियों को मांग पर चर्चा के समय यहां होना चाहिए था वे नहीं हैं और अभी तक अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ या उनके प्रसंग में आप अपना पत्र संसदीय कार्य मंत्री को सौंपें और उस पर संसदीय कार्य मंत्री को यह निर्देश दिये जाते हैं कि कठोर कार्यवाही की जाय। (व्यवधान)

## अनुदान की मांग

## मांग संख्या 24 पर विचार

**डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। कई बार हम वित्तीय व्यवस्था की बात करते हैं, वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि साइकिलें बांटी जा रही हैं, साइकिल

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बांटने में उन्होंने एक संवाद किया ठेकेदार से और उसमें 22 करोड़ रुपये केवल साइकिल बांटने में बजट में बचे, पिछले वर्ष की तुलना में 22 करोड़ रुपये साइकिलों पर कम खर्च हुए। इस प्रकार का कोई कदम उठाया जाता है तो प्रशंसनीय है।

एक बात और कहना चाहूंगा कि शिक्षा में मानीटरिंग की आवश्यकता है, एक भयंकर विसंगति है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उच्च शिक्षा में 7 गुना ज्यादा प्राइवेट कालेज हैं और एक परसेंट का अंतर है। इसका मतलब है उच्च शिक्षा में जाने के बाद बालक गवर्नमेंट में भागता है और नीचे वह प्राइवेट स्कूल में भागता है। यह विसंगति है, संस्कार डवलप नहीं हुआ। सरकार के स्कूलों में संस्कार प्रमाणित नहीं हुआ कि उनको आकर्षित किया जाय। इसके लिए कुछ नवाचार किये जाने चाहिए। विशेष तौर पर गरीब का बच्चा भी प्राइवेट सैक्टर में भाग लेना चाहता है, कर्जा करके स्कूल में भेजता है। इसलिए ऐसा नवाचार किया जाय कि जिस प्रकार गवर्नमेंट कालेजों में बच्चे जाते हैं उसी प्रकार आकर्षण हो। उसके कारण से शिक्षा में जो अनबैलेंस है वह भी ठीक होगा और उसमें गुणवत्ता में सुधार होगा। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री बाबूसिंह जी।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा पर चर्चा चल रही है। हम कितना भी विकास करें पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, लेकिन शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। शिक्षा किसी प्रदेश व देश की प्रगति का द्योतक है, मेरूदण्ड है। आज प्रदेश की कई प्रतिभाएं देश के कोने-कोने में हैं और देश की प्रतिभाएं विदेशों में कोने-कोने में अपनी प्रतिभा का परचम फहरा रही हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं।

जब देश प्रगति कर रहा है, हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर होते हैं तो हिन्दुस्तान के हजारों की संख्या में वे प्रतिभाएं वहां एकत्रित होती हैं और वहां भारत माता की जय-जयकार का गुंजायमान होता है। ऐसे हालात में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे विरोधी देश हैं, पहले भी हमको आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर विरासत में मिली। यह युवाओं का देश है। यह भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, घी-दूध की नदियां बहती थीं, धन-वैभव था। यहां से गुणवान, संस्कारित लोग हुआ करते थे और आज भी है। देश फिर से विश्व गुरु बने, ऐसी हमारी आकांक्षा है।

(श्री बाबू सिंह)

ऐसे समय में जो विरोधी पड़ोसी देश हैं वे हमारे युवाओं को कमजोर करने के लिए बाहर से चरस, स्मैक, गांजा, अवैध हथियार का प्रलोभन देते हैं।

(14.00 बजे)

ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं और हमारे युवाओं की नसों में नशा फैले, ऐसा काम भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखने को आया था कि विश्वविद्यालय के अन्दर, जो शिक्षा का मंदिर है, ऐसे मंदिर के अन्दर इस प्रकार से स्मेक का प्रलोभन दिया जा रहा है, इस प्रकार से नशा फैलाया जा रहा है। जिस भारत माता पर जिसने जन्म लिया है उसी भारत माता के विरुद्ध उनके टुकड़े करने की बात कही जाए या जिस भारत माता ने उनको पाला उसके खिलाफ बगावत हो, ऐसा देखने को मिला है। वास्तव में यह बालक कोरे कागज की भांति हैं और शिक्षक, गुरुजन के पास उस पर किस प्रकार की तस्वीर बनेगी, किस प्रकार की उसकी तकदीर बनेगी, वो शिक्षक तय करता है और आज हालत विश्वविद्यालय में यह है और शहरों में भी ऐसे प्रकरण प्रकाश में आये हैं कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं या और दूसरे विद्यालय हैं उन विद्यालयों के अन्दर शराब मिलाकर बच्चे विद्यालय में पीते हुए पकड़े गये, वाशरूम में शराब पीते हुए पकड़े गये। यही नहीं, वो जब घर से रवाना होता है और उसके पास मोबाइल होता है तो चाहे वो स्कूटी या बाइक पर जा रहे हैं तो बंक मारकर कहां जा रहे हैं इसकी स्थिति का भी पता नहीं है। इस प्रकार ये जो सारे हालात हमारे सामने आये हैं उनमें मैं तो यह मांग करूंगा कि जो यह मोबाइल है यह आधुनिक टेक्नोलाजी है पर कम से कम स्कूल में मोबाइल ले जाने पर रोक लगनी चाहिए, उस पर बैन लगना चाहिए कि स्कूल में मोबाइल नहीं लायें। पहले जब मोबाइल नहीं थे तब भी प्रतिभाएं आगे आती थीं तो वहां पर तो इस पर रोक लगे।

पहले जब पलायन होता था तो गांवों में जो गरीब आदमी था वो मजदूरी करने के लिए शहर में आता था। आज गांवों में भी मजदूरी की कोई कमी नहीं है लेकिन आज जो पलायन हो रहा है और वो गांव से शहर में आते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पढायेंगे। गांव में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है इसलिए वो शहर की ओर आ रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शहर के आस-पास जितने विद्यालय हैं

(श्री बाबू सिंह)

उनमें शिक्षकों और बालकों का अनुपात पता करें। जितने भी शहरों के आस-पास विद्यालय हैं वहां 1:5, 1:10 का अनुपात, 10 पर एक शिक्षक, 5 पर एक शिक्षक का भी आ रहा है। उसके साथ-साथ जितने पास के विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अगर चार अध्यापक हैं तो दो अध्यापक यह कहेंगे कि इस हफ्ते हम आयेंगे और अगले सप्ताह आप आना। इसके अलावा एवजी में भी शिक्षक लग रहे हैं, ऐसा वातावरण बना हुआ है। इसके साथ ही शहरों में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जहां नामांकन ज्यादा हैं, वहां कच्ची बस्तियां हैं उनमें नामांकन हैं उन विद्यालयों को तो आप शुरू रखो पर कहीं पर नामांकन ही नहीं है और 10-15-20 शिक्षक लगे हुए हैं उस स्थिति को आपको देखना है। वो जो बच्चों का नामांकन है वो नामांकन भी प्राइवेट विद्यालय में है और वो प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे का नाम हमारे यहां रहने दो जिससे हमारी नौकरी बच जाए। आप उस विद्यालय में पांच लाख का वेतन दे रहे हैं तो ऐसी स्कूलों का सर्वे करके, अब जब गांव के लोग पलायन करके पढ़ाने के लिए शहर में आये हैं तो वो लोग अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, सरकारी विद्यालय में बहुत कम पढ़ाते हैं तो शहर में जो नामांकन नहीं हैं और ऐसी स्कूलें चल रही हैं उनको तो बन्द कर देना चाहिए तथा इन शिक्षकों को गांवों में भेजना चाहिए।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि आर.टी.ई. के अन्दर जो 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे वालों के एडमिशन का नियम आया है उसमें मैं तो यह चाहूंगा कि जितने शहर के अन्दर बीपीएल हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं चाहे वो शहर में हैं चाहे गांवों में हैं, सभी बीपीएल परिवारों के बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला दिलाना चाहिए और सरकार की तरफ से यह फीस निर्धारित कर देनी चाहिए कि जब उनको राजस्थान सरकार क्रमोन्नत कर रही है, उनको 8वीं से 10वीं, 12वीं में क्रमोन्नत कर रही है तो उसमें नियम तय कर दें कि कितनी फीस वो प्राइवेट विद्यालय वहन करेगा और कितनी राजस्थान सरकार देगी। मैं तो कह रहा हूं कि पूरी फीस ही अगर सरकार दे तो उन पूरे बीपीएल परिवारों के बच्चों को ऐसे प्राइवेट विद्यालयों में हमें दाखिला दिलाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका का नींव अभियान चल रहा है जिसमें उन्होंने जगह-जगह जिलेवाइज स्कूलों का सर्वे किया है। आज मैंने अख़बार में पढ़ा कि एक गरीब परिवार की बच्ची जो सड़कों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, बालिका बानो का आज अखबार में मैंने पढ़ा है और उसमें

(श्री बाबू सिंह)

लिखा है कि वास्तव में अब वो जमूरा नहीं बनेगी, अब वो डाक्टर बनेगी और लेखनी देखो तो इतने मोती जैसे सुन्दर शब्द हैं, अब वो पढ़ने लगी है। यह जो आर.टी.ई. का अधिकार आया है उसमें 25 प्रतिशत बालकों का दाखिला हुआ है।

इस प्रकार से प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और गांवों में जो प्रकृति की गोद में खेलकर जो प्रतिभाएं हैं उनको तराशने की जरूरत है। शहरों के हालात हमसे कोई छिपे हुए नहीं है। आज बाल वाहिनी घर के आगे गेट पर आती है और वहां बच्चे को बिठाती है और गेट पर ले जाकर छोड़ती है तो अब उनका किस प्रकार से स्कूलों में शारीरिक विकास होगा इस बात की हमें चिंता करनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्रीजी और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का मानस है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। गांवों में देखेंगे कि प्रकृति की गोद में खेलने वाले वो बालक कई किलोमीटर पैदल स्कूल में जाते हैं। पहले का जो वातावरण था, जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी सुबह-सुबह योग कराया जाता था, पी.टी. कराई जाती थी, ध्यान कराया जाता था और उसके बाद में परेड करायी जाती थी। उसमें सप्ताह भर का पूरा का पूरा कलेण्डर होता था कि एक दिन बाल अभियान होगा, उसके अलावा अलग से क्रांस कंट्री होगी, खेलकूद कार्यक्रम होंगे, उनको अलग से नैतिक शिक्षा का पाठ सिखाया जायेगा, उनको अलग-अलग सड़क सुरक्षा का पाठ सिखाया जायेगा। इस प्रकार सप्ताह में अलग-अलग एक दिन का यह कार्यक्रम हमें इस पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए कि चाहे वो सड़क सुरक्षा के लिए पढ़ाया जाए, चाहे उनको डिजिटल के बारे में पढ़ाया जाए, चाहे कौशल शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाए, चाहे उनको नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाए। इस प्रकार का वातावरण बनना चाहिए लेकिन आज जो हिन्दुस्तान के अन्दर हालात हैं, हम संस्कारित करें बच्चों को इसके लिए आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे जो पड़ौसी और विरोधी देश हैं वो हमारे युवाओं को कमजोर करने का काम करते हैं, उनको भी मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। वो आज भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं, भारत माता के खिलाफ नारे लगाने की बात करते हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि अब आप ऐसी शिक्षा लाओ कि वास्तव में वो संस्कारित शिक्षा हो। अब अकबर महान् नहीं महाराणा प्रताप पढ़ाया जाए, वन्दे मातरम् कहना होगा और हिन्दुस्तान में रहना होगा, इस प्रकार की शिक्षा हमें लानी होगी। वास्तव में शिक्षा के अन्दर जो हमारे प्रेरणा पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, महाराणा

(श्री बाबू सिंह)

प्रताप, दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह राठौड़, भक्त शिरोमणी मीरा बाई, सूरजमल और ऐसे हमारे कई महापुरुष हैं जिनकी शिक्षा देकर हम उनको संस्कारित कर सकते हैं।

मैं आपसे खासतौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय भैंरोसिंह जी शेखावत साहब जब मुख्य मंत्री बने तो पंचायत मुख्यालयों पर 5वीं तक की स्कूल हुआ करती थीं तब उन्होंने एक ही आदेश में सभी पंचायत मुख्यालयों पर 8वीं तक की स्कूलें कर दीं। उसके बाद आदरणीय वसुंधरा जी जब मुख्य मंत्री बने तो यह महसूस हुआ कि हमारे वहां की जो बालिकायें हैं वो दूर-दराज के स्कूलों में पढ़ती हैं और 5वीं पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देती हैं या जहां पर 8वीं तक की स्कूल हुई तो 8वीं तक पढ़ने के बाद वो स्कूल छोड़ देती हैं। तो सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उन्होंने 10वीं करने का निर्णय लिया और बगैर राजनीतिक भेदभाव के 10वीं तक स्कूल हो गई और ऐसी 4 हजार स्कूलें उन्होंने 10वीं तक कर दीं। कुछ कांग्रेस के शासन में भी हुई लेकिन पद सृजित नहीं हुए। इस बार जब राजस्थान की सरकार आई तो आदरणीय वसुंधरा जी ने एक ही निर्णय करके 5 हजार स्कूलों को उन्होंने 12वीं तक कर दिया। अब जब हर पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक हो गई तो वास्तव में नामांकन बढ़ा है और कांग्रेस के शासन में तो 12 लाख नामांकन घटा था और अब 12वीं करने के बाद 8 लाख का नामांकन बढ़ा और 11वीं कक्षा में एक लाख का नामांकन बढ़ा।

आज मुझे कहते हुए गर्व होता है हमारी बहन आज वास्तव में पढ़ने लगी है। विपरीत परिस्थितियों में, घर का काम करने के बाद भी उसको पढ़ने का अवसर मिले इसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने काफी योजनाएं शुरू की हैं। उनको 5 लाख साइकिल का वितरण किया गया, लेपटाप दिये गये। मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना, आपणी बेटी योजना, इस प्रकार की योजना है और अब यह नई योजना उन्होंने चलाई है जिसमें मुख्य मंत्री जनसहभागिता विकास योजना, मुख्य मंत्री राजश्री योजना है। मैं यह देखता हूं कि जब साइकिल वितरण का कार्यक्रम हमने रखा, गार्गी पुरस्कार का कार्यक्रम गांव में, ब्लाक स्तर पर हुआ तो बालिकाओं के चेहरों पर मुस्कान थी और जब उनको साइकिलें बांटी गईं तो जो पंचायत मुख्यालय पर स्कूल थी वो अपने राजस्व गांव से चलती थी और सब लोग साथ में चलती थीं और यह नारा लगाती थीं

(श्री बाबू सिंह)

कि आओ साथ चलें, जय-जय राजस्थान। वास्तव में बालिकाओं में पढ़ने की ललक बढ़ी है और बोर्ड के जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों में भी बालिकाएं आगे आ रही हैं तो उनको खूब सारा प्रोत्साहन मिल रहा है।

हम चाहेंगे कि अब जिस प्रकार से 12वीं तक विद्यालय हुए हैं, गांवों में जहां-जहां 12वीं के विद्यालय हैं वहां पर बालक और बालिकाओं की संख्या बराबर है और कहीं पर बालिकाओं की संख्या भी ज्यादा हो गई लेकिन इस बार जब ये स्कूल क्रमोन्नत हुए और शिक्षा का वातावरण बनने लगा तो जगह-जगह हमें आंदोलन झेलने पड़े, लोगों ने तालाबंदी की कि हमारे यहां शिक्षक नहीं हैं, हमारे यहां व्याख्याता नहीं हैं। शिक्षा मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने एक ही निर्णय लिया कि 5,000 स्कूलें क्रमोन्नत हुई हैं तो उन्होंने 5,000 प्रिंसिपल के पद भी सृजित किये और 5,000 प्रिंसिपल तो लगा दिये लेकिन व्याख्याताओं की कमी है। हम आन्दोलन के समय उन्हें समझाने गये। मैंने कहा कि शिक्षक तो कांग्रेस के राज में भी कम थे, अब ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उनसे मांग करते थे और वह मांग पूरी होने की उम्मीद उनसे नहीं थी इसलिए हमने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। लेकिन हमें विश्वास है, भरोसा है कि यह सुराज आया है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारी मांग पूरी होगी। इसलिए आपसे यह मांग करते हैं कि हमें शिक्षक दिये जायें और सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता की शिक्षा मिले, यह हमारी मांग है।

वास्तव में इस बार पहली बार शिक्षा मंत्रीजी ने करीबन 5,000 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय में क्रमोन्नत किया है। इन सभी पंचायत मुख्यालयों पर जो विद्यालय हैं, चरणबद्ध तरीके से तीन साल के अन्दर वह आदर्श विद्यालय बनेंगे तो मैं यह मांग करूंगा कि वास्तव में पंचायत मुख्यालय पर एक आदर्श विद्यालय हो और उसके साथ सारे पद भर दिये जायें। उसके साथ ही पंचायत में एक ही स्कूल आठवीं को भी आदर्श स्कूल करने जा रहे हैं तो दो स्कूलें अगर शानदार बन जायेंगी। एक पंचायत मुख्यालय पर 12वीं, जो आदर्श स्कूल होगा और एक आठवीं, वह भी आदर्श स्कूल होगी। उसमें एक भी पद रिक्त नहीं रहेगा तो वहां गुणवत्ता की शिक्षा मिल सकेगी। गरीब का बच्चा भी गांव में पढ़ सकेगा और प्रकृति की गोद में खेलने वाली वह प्रतिभा उभरेगी, तराशेंगे और आगे बढ़ेंगी और उच्च शिक्षा के लिए वह आगे आयेंगी।

(श्री बाबू सिंह)

मुझे कहते हुए यह बड़ा दु:ख है कि वास्तव में प्राइमरी में जब बच्चा एडमिशन लेता था तो 100 बच्चे आते थे। 10वीं, 12वीं तक वो 27 बच्चे होते थे और उच्च शिक्षा में तो 11-12 बच्चे ही पहुंचते थे। यह राष्ट्रीय औसत से कम था, अब इसमें बढ़ने लगे हैं।

कांग्रेस के समय में जब समानीकरण की बात आई तो समानीकरण नहीं, मनमानीकरण किया गया। जब आंकड़े आये तो उन आंकड़ों के अन्दर ऐसे कई विद्यालय थे, जैसे 142 विद्यालय थे। वह जीरो नामांकन के थे और 252 टीचर्स उनमें लगे हुए थे। ऐसे कई हालात थे। शहर के नजदीक तो बहुत सारे टीचर थे, लेकिन दूर-दराज की ढाणियों के अन्दर जहां 250 बच्चे थे, वहां एक ही अध्यापक था। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का आप सही तरीके से समानीकरण करके दूर-दराज के गांवों के अन्दर इनको भेजें। यह मेरा आपसे खास तौर से निवेदन है।

उसके साथ ही शिक्षकों पर भार रहता है और विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कई बार यह मांग की है कि मिड-डे मील है। अब इस मिड-डे मील के अन्दर जो नामांकन होता है। इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वह जगजाहिर है। जब नामांकन होता है तो उसमें जितना नामांकन होता है और जब परीक्षा का समय आता है तो करीबन वहां 60 परसेंट ही परीक्षा देने वाले होते हैं और 40 परसेंट नामांकन से कम आते हैं। तो इसको भी आप एग्जामिन करायें कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब नामांकन होता है तो पूरे 100 होते हैं और जब परीक्षा देते हैं तो उसमें से 60 ही रहते हैं तो ये 40 परसेंट कम क्यों आ रहे हैं? यह मिड-डे मील का पैसा उठाने के लिए प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा बच्चा है, उसका भी नाम लिख दिया जाता है। डबल नाम लिखे जाते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए तो इसमें भी खास तौर से आपको ध्यान देने की जरूरत है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

उसके अलावा भी पंचायत मुख्यालयों पर पांचवीं तक की स्कूलें थीं, अब वह आठवीं, 10वीं और 12वीं तक की हो गईं। जब 5वीं थी, उस समय डेढ़ या दो बीघा जमीन हुआ करती थी। मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक स्टैंडिंग आर्डर आप जरूर निकालें कि जो 12वीं विद्यालय हैं, वह सभी 12वीं स्कूलों में नियमानुसार कम से कम 16-साढ़े 16 बीघा जमीन हो, इस प्रकार का अलाटमेंट आप जरूर करायें। पहले कम जगह पर बिल्डिंग बनती थी। अब रमसा में माध्यमिक शिक्षा अभियान चल रहा है, सर्वशिक्षा

(श्री बाबू सिंह)

अभियान चल रहा है तो ये अच्छे भवन बनें। हमने तो कई जगह जहां कम जमीन थी, वहां 15-16 बीघा जमीन आबंटित कराई है। उसमें खेल का मैदान भी साथ हो जाये और शानदार बिल्डिंग बनें। एक अच्छा शिक्षा का मंदिर बने। वहां पेड़-पौधे लगे, चारदीवारी हो। इतना सुन्दर भवन हो और वह आदर्श विद्यालय हो तो पूरे राजस्थान के अन्दर एक जैसा रंग-रोगन कराकर उसमें सारे शिक्षक भर्ती करके, उसके सारे रिक्त पद भरकर वह आदर्श विद्यालय के रूप में, उसको एक माडल विद्यालय बनाया जाये।

साथ ही हम संस्कृति की बात करते हैं। ये वीरांगनाएं हैं। जब देश सोता है सरहदों पर हमारे गौरव सेनानी वहां शहादत देते हैं। ऐसे कई शहीद भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। इन गांवों का सर्वे करवा लिया जाये कि कहां पर शहीद और स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनके नाम से विद्यालय नहीं हुए हैं तो इसमें विशेष तौर से पहल करके और सरकार को वहां पर शहीदों के नाम से स्कूल निश्चित रूप से करानी चाहिए। यह मेरा खास तौर से निवेदन रहेगा।

इसके अलावा, मैं सरकार से यह मांग करूंगा। इस बार जो बजट आया है, उस बजट में भी आपने काम किया और मेरे यहां तो एकीकरण के नाम पर और अनार्थिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, उसमें भी आपको चिंता करनी चाहिए कि शिक्षक के अभाव में वह स्कूल अनार्थिक हुए हैं तो ऐसी जगह पर हमारे यहां भारती फाउंडेशन, सती भारती स्कूल ने विद्यालय खोले हैं। वहां उस विद्यालय में 8,000 बच्चे पढ़ रहे हैं जहां विद्यालय खुला है, वहां सरकारी विद्यालय बंद हो गये तो प्यासा कुएं के पास आएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं जायेगा। गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी तो हम चाहेंगे कि ऐसे फाउण्डेशन हैं, वह समाजसेवी संस्था हैं, उनको स्कूलें गोद देनी चाहिए। साथ ही इस प्रकार से जन सहभागिता से वह स्कूल चलें। जन सहभागिता की योजना भी बजट में लाये हैं कि 60-40 के हिसाब से, सरकार 60 परसेंट देगी और 40 परसेंट जन सहभागिता से मिले और भामाशाह आगे आयें और वह विद्यालय चलायें। ऐसे विद्यालयों को गोद देकर भी आप काम कर सकते हैं।

मैं खास तौर से यह कहना चाहूंगा कि मिड-डे मील का भी आप ध्यान करें। आप निर्माण कार्य जो करा रहे हैं, पहले भी यह मांग उठी है कि शिक्षकों से निर्माण कार्य नहीं कराया जाये क्योंकि हमारे यहां जोधपुर जिला है, उसमें एक एईएन है और वह एईएन भी नागौर का है, उसको चार्ज दे रखा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक ब्लाक के अन्दर तीन एईएन बैठे हैं तो इस

(श्री बाबू सिंह)

प्रकार के निर्माण कार्य हैं, मैं तो कह रहा हूं कि ये सार्वजनिक निर्माण विभाग को देने चाहिए, जिससे गुणवत्ता के कार्य भी हों।

उसके अलावा मैं विशेष तौर से सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि पंचायत मुख्यालयों पर आप 12वीं तक की शिक्षा देने जा रहे हैं तो वहां कई निजी विद्यालय भी 12वीं तक के हैं। अब निजी विद्यालयों की फीस ज्यादा है तो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। हमारी पुरानी पंचायतें हैं, उनमें कनोडिया पुरोहितान, सुरखियातलां, खुडियाला, बेरवा राणाजी, देवातू और दूगर, इनमें भी 12वीं विद्यालय नहीं हुए। 26 नई ग्राम पंचायतों पर 12वीं नहीं हैं तो इस प्रकार से यहां भी और पहली बार 12वीं तक के विद्यालय पंचायत मुख्यालयों पर हुए हैं। शारदा छात्रावास खुला है, कस्तूरबा खुला है और राजकीय महाविद्यालय, बालेसर में खुला है तो स्नातक की शिक्षा हमें गांवों में मिलने लगी है। तो, शेरगढ़ मुख्यालय पर भी राजकीय महाविद्यालय हो और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए बालेसर में महिला महाविद्यालय हो। शेरगढ़ का संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय है, उसको शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत किया जाये। यह मैं खास तौर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपको इसमें बधाई देना चाहूंगा कि पहली बार आपने डीपीसी की हैं और डीपीसी में भी आपने करीबन 55,000 शिक्षकों को पदोन्नत किया है। 31,000 से अधिक शिक्षक, व्याख्याताओं, कार्मिकों का नवीन पदस्थापन किया है तो ऐसे में जो आपने कमेटी बनाई है। एक तो विशेष मांग हमारे पैराटीचर्स, विद्यार्थी मित्र और शिक्षाकर्मियों की रही। शिक्षाकर्मी आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत के समय में लगे थे। उनको अभी तक सिक्स पे कमीशन का भी लाभ नहीं मिला। इतने वर्षों बाद वे ओवरएज भी हो गये और उनको आज भी मात्र 6,000 का वेतन मिल रहा है। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इन पैराटीचर्स, विद्यार्थी मित्र और संविदाकर्मियों की समस्याओं का समाधान भी आप निश्चित रूप से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री पब्बाराम।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का समय दिया, आपका आभार। शिक्षा एक ऐसा विषय है। इंजीनियर की गलती या उसकी चूक किसी पुल के ढहने और उसके कारण से कुछ मौतों के नीचे दब जाती है और

(श्री पब्बाराम)

कालान्तर में भुला दिया जाता है। एक डाक्टर अगर गलती करता है तो एक मरीज की मृत्यु होती है और उसके परिजन रो-पीट कर रह जाते हैं और चार दिनों के बाद में उसको भी भुला दिया जाता है। परन्तु एक शिक्षक गलती करता है तो कई पीढ़ियां उसको भुगतती हैं। इसी प्रकार से जो मूल विषय शिक्षा का है, वह यह है कि पाठ्यक्रम अच्छा होना चाहिए और पाठ्यक्रम में कहीं पर चूक होती है, कई पर विकृति होती है तो देश का भविष्य दांव पर लग जाता है। यह पाठ्यक्रम की चूक और इस प्रकार से गलत नीतियों के तहत पढ़ाये जाने के कारण जेएनयू जैसे प्रकरण सामने आते हैं। भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के अन्दर ऐसे जब विषय सामने आते हैं ऐसे प्रकरण सामने आते हैं तो हर कोई देशभक्त व्यक्ति मसोस कर रह जाता है और उद्वेलित होता है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपका ध्यान इस पाठ्यक्रम के द्वारा किस प्रकार से भावी पीढ़ी को संस्कारित किया जा सकता है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं।

सदन के सभी सदस्यों को याद होगा कि 2004-05 के अन्दर एक आंदोलन चला था शिक्षा बचाओ आंदोलन। हमारे परिवार के लोगों ने इस विषय को उठाया तो यह यूं ही उनका कोई जुनून नहीं था, कोई आंदोलन यूं ही नहीं खड़ा हो गया था। पाठ्यक्रम के अन्दर इस प्रकार से विकृत टिप्पणियां की गई थीं उस समय में इस कारण से जनमानस उद्वेलित हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों के अन्दर किस प्रकार से तथाकथित इन साम्यवादी लेखकों द्वारा जो कुछ टिप्पणियां की गई, वो भारत के जनमानस को उद्वेलित करने वाली थीं।

उसमें से कुछ पुस्तकें हैं मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कक्षा-6 की उस समय की पुस्तक और उसके बाद में न्यायालय का निर्णय आ गया और उसके बाद में वो हटा दी गई। परन्तु मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम के अन्दर बदलाव किए गए और उसी प्रकार के लोगों के द्वारा वहां पर वर्कशाप के तहत शिक्षा प्रदान की जाती है। वे लोग लैक्चर देते हैं उन शिक्षण संस्थाओं में और इस कारण से लोगों का माइंडवाश किया जाता है और इस प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं। उस समय कक्षा-6 की प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत, उसमें ये कुछ लेखक हैं जिनके द्वारा पाठ्य पुस्तकें लिखी गई। रोमिला थापर, अर्जुन देव, इंदिरा, रामशरण शर्मा और

(श्री पब्बाराम)

विपिन चन्द्र इनके द्वारा बड़ी ही उद्वेलित करने वाली इस भारतीय जनमानस के ऊपर कुठाराघात करने वाली टिप्पणियां हुईं और यह आंदोलन खड़ा हुआ। रोमिला थापर ये लिखती हैं कक्षा-6 के अन्दर प्राचीन भारत में पृष्ठ संख्या-40 के ऊपर कि गो-मांस का परोसा जाना एक सम्मान का सूचक समझा जाता था। अन्न और मांस खूब खाया जाता था उस समय प्राचीन भारत में और मधु और नशीली सुरा जैसे पेय भी पीये जाते थे और एक अतिथि विशिष्ट पेय था जिसे सोम कहते थे। जो धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था क्योंकि इसे तैयार करना कठिन था, यह उनकी टिप्पणी थी।

इसी प्रकार से महाभारत और रामायण को एक काल्पनिक कथा कहा गया और ये गडरियों के गीत कहे गए। यह भी रोमिला थापर द्वारा प्राचीन भारत इतिहास पृष्ठ-45 पर अंकित था और ये महाकाव्य विभिन्न कविताओं का एक संकलन मात्र कहा गया। ये काल्पनिक चरित्र ही कहा भगवान कृष्ण और राम को, इस प्रकार की टिप्पणियां की गई।

इसी प्रकार से अर्जुन देव के द्वारा सामाजिक विज्ञान-1 और 22 पृष्ठ पर लिखा गया कक्षा-8 में कि जाटों ने भरतपुर में अपना राज्य कायम किया और वे आसपास के इलाक़ों में लूटपाट मचाते थे और लुटेरे के रूप में काम करते थे और दिल्ली दरबार के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे इस प्रकार की टिप्पणियां की गईं।

इसी प्रकार से अर्जुन देव और इंदिरा 166 पेज पर दोनों लिखते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा-8 में 1957 का स्वतंत्रता संग्राम एक विद्रोह था। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान-1 कक्षा-8 में इन्हीं तीनों ने लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपतराय और अरविन्द घोष को उग्रवादी नेता के रूप में प्रसिद्ध होना बताया गया है।

इसी प्रकार से इन्हीं तीनों ने सामाजिक विज्ञान-1, पृष्ठ-200 पर लिखा था कि राष्ट्रीय आंदोलन को केवल हिन्दुओं का आंदोलन बताया गया, मुसलमानों को इससे कोई सरोकार नहीं था। इस प्रकार की विकृत टिप्पणियां की गई।

इसी प्रकार से कक्षा-11 में प्राचीन भारत रामशरण शर्मा द्वारा लिखा गया ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता था। वो एक पशुपालक थे उनकी कोई संस्कृति नहीं थी, उनकी कोई सभ्यता नहीं थी और उनकी अधिकांश लड़ाइयां

(श्री पब्बाराम)
गाय को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ गाय का अन्वेषण है, गाय सबसे उत्तम धन जाती थी।

इसी प्रकार से द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है जब देश आजाद हुआ तो उस समय में यह जिन्ना व मुसलिम लीग का न होकर के वीर सावरकर के उग्र हिन्दू साम्प्रदायिकता के कारण ऐसा हुआ।

इसी प्रकार से आर्यो को उन्होंने यह टिप्पणियां भी कीं कि आर्य भी इस मध्य भारत से यहां पर भारत में आये, वो यहां के मूल निवासी नहीं थे। वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, गोरी चमड़ी वाले घुमंतू जाति के लोगों ने जो आर्य कहलाये, कब्जा किया एवं मोहन जोदड़ों और हड़प्पा आर्य सभ्यता के पहले के अवशेष हैं। माननीय अम्बेडकरजी ने इस बात को नकारा और उन्होंने कहा कि यह एक दिमाग की उपज है। आर्य मूलत: यहीं के मूल निवासी थे।

इसी प्रकार से उन्होंने कक्षा-11 की प्राचीन भारत, रामशरण शर्मा द्वारा लिखी गई है और पेज नम्बर 85 पर लिखा था ऋग्वेद काल में देव आराधना आध्यात्मिक उत्थान व जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए नहीं था। वो सिर्फ अपने देवी-देवताओं की संतति पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि अपने पाने की कामना से किया जाता था।

इस प्रकार से कई ऐसी टिप्पणियां हैं। 1857 को जन द्रोह कहा गया, वह क्रांति नहीं बताया गया। इसी प्रकार से विपिन चन्द्र ने और लिखा है। उग्र राष्ट्रवाद का विभाजन विरोधी आंदोलन की कमान जल्द ही तिलक, विपिन चन्द्र पाल और अरविन्द घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में पहुंच गई और इसके लिए देश का विभाजन हुआ।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन सारी टिप्पणियों की बात कर रहे हैं और जिनके नाम ले रहे हैं वो भी बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं भारतवर्ष के। उनकी जो किताबें हैं वो आज की तारीख में भी जितनी भी अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी पढ़ाई जाती हैं। यह बड़े डिबेटेबल पोइंट हैं कि भरतपुर में जाटों का क्या था और वो लुटेरे थे और वो दिल्ली को लूटते थे। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है जाट होते हुए कि वो ये काम करते थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है जिस तरीके के ऋग्वेद के बारे में पूरी हिस्टोरिकिल आर्यस के बारे में, ये सारी चीज़ें तो बहुत बड़ी डिबेटेबल पोइंट हैं जिसमें बेस्ट आफ इंटेलेक्चुअल ब्रेंस जो हैं उनको डिसकस करना चाहिए।

(श्री नवीन पिलानिया)

तो मेरा सिर्फ इतना सा पाइंट था That was just the point. even जो आई ए एस का एग्जाम है उसके लिए भी जो तैयारी करते हैं जिन आथर्स के नाम दिए हुए हैं ये मोस्ट स्टैण्डर्ड बुक्स हैं जिनको वो लोग पढ़कर के ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। धन्यवाद।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब शिक्षा बचाओ आंदोलन चला और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के निर्णय के द्वारा उक्त अंशों को हटाने के आदेश पारित हुए। इसी प्रकार से रिट पिटीशन सिविल संख्या-17909-13/2005 दीनानाथ बत्रा वगैरह बनाम सरकार वगैरह उसके निर्णय भी आ गए और पाठ्यक्रम की जांच कर कमियों के सुधारने के आदेश दे दिए गए थे। परन्तु मैंने कहा कि दिल्ली के इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में ये सारी स्थितियां क्यों पैदा हुई। ये पाठ्यक्रम के अन्दर इस प्रकार से विकृत लोगों द्वारा विकृत मानसिकता के लेखकों द्वारा जो लिखा गया और तत्कालीन सरकार के द्वारा आंख मींच कर के उनके लेखों को स्वीकार कर लिया गया उसके कारण हुआ और इस कारण से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। इसकी जड़ बहुत पीछे है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वो इस प्रकार से पाठ्यक्रम को लिखे, ताकि वो युगानुकूल हो, देशानुकूल हो, विद्यार्थी अपने गौरवशाली अतीत से जुड़े, लोकरंग से जुड़े, संस्कृति से जुड़े और पर्यावरण से जुड़े। इसके लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में 363 लोगों को पेड़ों के लिए बलिदान देने के लिए एक ऐसी महिला हुई है, अमृता देवी जिन्होंने प्रेरणा देकर के 363 लोगों का विद्रोह स्वरूप आंदोलन किया और उस आंदोलन में सभी मारे गये, उनको काट दिया गया। इस घटना को भी इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अनेक ऐसी बातें हैं, जिस प्रकार से राम सेतु का मुद्दा उठा। राम सेतु को इन लोगों न् यह बताया कि यह मानव निर्मित नहीं है जबकि अमेरिका के सैटेलाइट नासा के द्वारा यह तय हो गया यह निश्चित हो गया है कि यह मानव निर्मित पुल है परन्तु उन्होंने कहा कि यह मानव निर्मित नहीं है और यह एक प्रकार की प्राकृतिक चीज है और इसीलिए उन्होंने उसको तोड़ करके वहां से निकालने का प्रयास किया और आपको याद होगा कि राम सेतु का जिस समय में तोड़ने का कार्यक्रम तत्कालीन सरकार ने किया था, सम्पूर्ण देश आधे घंटे तक रुक गया था और

(श्री पब्बाराम)

लोग सांस थाम करके बैठे थे और यही सोच करके उस सरकार ने इस निर्णय को वापस लिया था। मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने पाठ्यक्रम को भी नये सिरे से लिखाने के लिए और इस प्रकार से गौरवशाली बातों को उसमें शामिल करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह कदम उठाया इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इसी प्रकार से बहुत सारी बातें अन्य सभी मेरे साथी सदस्यों द्वारा बताई गयीं कि पांच हजार स्कूलों का क्रमोन्नयन, इसी प्रकार से पचपन हजार शिक्षकों का, यह अभूतपूर्व कदम था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जो शिक्षक अपना प्रमोशन पाने के लिए तरस रहा था, वह यह समझता था कि मैं इसी एक स्थान पर सड़कर के वापस रिटायरमेंट होकर के चला जाऊंगा और उन लोगों को प्रमोशन दिया गया और लगभग यों समझो पचपन हजार से अधिक शिक्षकों को प्रमोशन दिया गया। एक काम आपने और किया शिक्षा मंत्री जी, आपने सत्तर प्रतिशत पद मौजूदा जो आपके पास में संसाधन थे, उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भी भर दिये और इस बात को सख्ती से लागू किया। कभी जनप्रतिनिधि भी आपके पास में आये और इसके लिए आग्रह किया कि नहीं ऐसे करो, वैसे करो, आपने सख्ती से उसको इंकार करते हुए आज ग्रामीण स्कूलों की जो दशा सुधारी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से पन्द्रह हजार अभी थर्ड ग्रेड के शिक्षक रीट के द्वारा लेना, एक ही परीक्षा के द्वारा लेना, यह भी आपने किया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। तेरह हजार सैकिण्ड ग्रेड के शिक्षक और साढ़े तेरह हजार फर्स्ट ग्रेड के शिक्षक जब स्कूलों में आ जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनसे भी ये विद्यालय आगे निकल जाएंगे और ये साढ़े आठ हजार तो क्या इस समय में नामांकन और बढ़ने वाला है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय कम है और मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहूंगा इस समय में। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी पक्ष या विपक्ष यह नहीं चाहता कि इस प्रकार से दृश्य कहीं भी कोई शिक्षण संस्थान में हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि पाठ्यक्रम को उसी हिसाब से देश आजाद होने के बाद में हर देश ने अपने इतिहास को नये सिरे से लिखाया है, परन्तु हमारे यहां पर इस देश का दुर्भाग्य है देश आजाद होने के बाद भी इस देश के जो पूर्व के शासक अंग्रेज रहे उनके मानस पुत्रों के द्वारा लिखा गया इतिहास

(श्री पब्बाराम)

आज भी हमारे शिक्षणालयों में पढ़ाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको पुन: लिखने की आवश्यकता मैं प्रतिपादित करता हूं।

मैं निवेदन करता हूं प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के माननीय मंत्रीजी से कि क्रमोन्नयन के सम्बन्ध में एक नीति बनायी जाये। जिस प्रकार से आपने सत्तर परसेंट पद सभी जगह भरे। यह नीति बना दी उसी प्रकार से आप एक क्रमोन्नयन के बारे में भी नीति बनायें। यानी पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान जिसमें यहां पर हर जगह दो किलोमीटर में एक पंचायत है और जब यह अरावली के दूसरी साइड में जायेंगे, रेगिस्तान में जायेंगे, हमारे क्षेत्र में जायेंगे, पोकरण और फलौदी में जायेंगे, 40-40 किलोमीटर में एक पंचायत है और एक पंचायत में एक विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है। तेरह किलोमीटर दूसरा विद्यालय सैकण्डरी स्कूल है उसके अन्दर छात्र संख्या पूरी है और छात्र संख्या पूरी होते हुए भी तेरह किलोमीटर दूर छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसके बारे में एक नीति का निर्धारण करना होगा कि उसका आधार दूरियां और विद्यालय की छात्र-छात्राओं की संख्या तय की जा सकती है। दूरस्थ ढाणियों में प्राथमिक शिक्षा हेतु छात्र एवं विद्यालय के मध्य दूरी निश्चित की जानी चाहिए।

इसी प्रकार से उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा के माननीय मंत्रीजी से मेरा आग्रह है। वो अगर सुन रहे हों तो, सदन में उपस्थित नहीं हैं।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं नोट कर रहा हूं।

**श्री पब्बाराम** (फलौदी): ठीक है। विशेष दर्द मेरा उच्च शिक्षा को लेकर के है कि मेरे वहां फलौदी में एक कालेज है जिसमें दो हजार स्टूडेंट्स हैं, उसमें 6 शिक्षक लगाये गये हैं। 6 में से 2 डेपुटेशन पर लगा दिये गये। 4 से वह महाविद्यालय चलता रहा और इतनी इस सरकार के आने के बाद में माननीय वसुन्धराजी की सरकार के आने के बाद में सभी विभागों ने जिस प्रकार से प्रगति की है, लोग बहुत खुश हैं। परन्तु जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं वो सारी की सारी उपलब्धियां बेकार हो जाती हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से एक विद्यालय जिसमें चार सौ स्टूडेंट्स हैं और एक विद्यालय जिसमें दो हजार स्टूडेंट्स हैं तो उसमें चार सौ वाले में सोलह टीचर लगते हैं। मैं उदाहरण दे सकता हूं और दो हजार वाले में अभी 6 शिक्षक हैं और उनमें 2 डेपुटेशन पर हैं। तो वो छात्र जब सड़कों पर उतरे तब जाकर के आपने लगाया वापस। यह समान वितरण हो। स्टाफिंग पैटर्न लागू हो, जिस

(श्री पब्बाराम)

प्रकार से स्टाफिंग पैटर्न आपने लागू किया माननीय प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के मंत्रीजी ने उसी प्रकार से स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाना चाहिए।

उप खंड मुख्यालय पर आपने कहा कि नीतिगत निर्णय ले रहे हैं कि वहां पर हम कालेज की स्थापना करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात को पूरा कर लूंगा। यह सरकार ने निर्णय लिया कि जिन उपखंडों में न तो प्राइवेट महाविद्यालय हैं और न ही गवर्नमेंट महाविद्यालय हैं वहां पर खोला जाएगा। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि आप इसी मांग पर कटौती प्रस्तावों के दौरान यह घोषणा करेंगे कि बाप जो सोलर हब माना जाता है, जहां पर दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आता है वो बहुत विकसित हो गया है। उपखंड है और वहां पर लगभग चालीस किलोमीटर तक कहीं पर भी कोई महाविद्यालय नहीं है और वो महाविद्यालय है वहां पर भी दो हजार स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए वहां पर बाप के अन्दर ही यह खोला जाए।

संस्कृत शिक्षा की तो हालत खराब है। मेरे एक सैकण्डरी स्कूल है जिसमें मात्र तीन शिक्षक हैं। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उनके अन्दर भी आप शिक्षक लगायें।

इस प्रकार से जो इन दो वर्षों में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो आमूल-चूल परिवर्तन किया है और शिक्षा में जिस प्रकार से गुणवत्ता का जो आधार बना है, ग्रामीण लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, माननीय वसुन्धराजी को दुआएं दे रहे हैं। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: डा. मंजू बाघमार।

**डा. मंजू बाघमार** (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मांग संख्या-24 पर शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने सभी ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत करवाया। मैं अपने क्षेत्र की कुछ मांगें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और कुछ ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर माध्यमिक स्कूलें क्रमोन्नत नहीं हो पायी हैं और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है वहां

(डा. मंजू बाघमार)

पर 20-30 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम पंचायत आती है और विशेष रूप से छात्राओं को वहां पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, दूर जाने के कारण छात्राओं की पढ़ाई छूट जाती है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हैं दुगोली, दुगस्तव, सोमना और लूणसरा यह जो चार ग्राम पंचायत स्थल है इनके माध्यमिक विद्यालयों को यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जाये तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र जायल की एक गवर्नमेंट कालेज के बारे में बताना चाहूंगी कि वहां अभी वर्तमान में केवल तीन ही लेक्चरर्स लगे हुए हैं, चार पोस्टें वहां पर खाली पड़ी हैं। कुल 314 स्टूडेंट वहां पर हैं। वहां की बिल्डिंग निर्माण के लिये हमारी मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 3 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये थे, बिल्डिंग का कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यदि वहां पर लाइब्रेरी और लैक्चर थियेटर के एक्सटेंशन के लिये दो करोड़ रुपये यदि और दे दिये जाएं तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को वहां पर सुविधा होगी। साथ ही साथ यदि वहां पर विज्ञान संकाय खोल दिया जाता है, क्योंकि डीडवाना और नागौर जायल मुख्यालय से 50-50 किलोमीटर दूर पड़ता है और इतनी दूरी के लिये ग्रामीण क्षेत्र में काफी परेशानी होती है। इसके अलावा मेरे यहां पर आईटीआई स्वीकृत हो चुकी है और उसके लिये हमने भूमि का आबंटन भी करवा लिया है। वहां पर बिल्डिंग निर्माण के लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी कि वहां पर पांच करोड रुपये की स्वीकृति जारी करवाई जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत को दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था लेकिन विडम्बना है कि दुनिया के श्रेष्ठ पांच सौ विश्वविद्यालयों में हमारे देश में मात्र एक विश्वविद्यालय का नाम हुआ है जो विश्व गुरु कहलाने के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार और उच्च शिक्षा संस्थानों में नकल रोकने के लिये हमारे कुलाधिपति महोदय संकल्पबद्ध हैं। साथ ही साथ हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया भी निरन्तर प्रयासरत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने

(डा. मंजू बाघमार)

के लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है। लेकिन विडम्बना यह है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पिछले कई सालों से टीचिंग और नोन टीचिंग के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसका एक सिम्पल सा एग्जाम्पल मैं मेरे क्षेत्र के विद्यार्थी जो एम डी एस यूनिवर्सिटी अजमेर में अध्ययनरत हैं, अजमेर जो कभी शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल हुआ करता था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उस शहर की स्थिति देखिए कि जिस शहर में मात्र एक विश्वविद्यालय है, हम जोधपुर और जयपुर की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी काफी हैं, लेकिन अजमेर में मात्र एक महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी है और वहां का जो गवर्नमेंट कालेज है वह 192 साल पुराना गवर्नमेंट कालेज है। उपाध्यक्ष महोदय, तीन लाख विद्यार्थी का कार्यभार उस यूनिवर्सिटी में है और वहां पर 58 पोस्ट सैंक्शन हैं लेकिन केवल 18 पोस्टें वहां पर भरी हुई हैं और पिछले डेढ़ साल से भर्ती अटकी पड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि शीघ्र ही इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये और इन पदों को भरने के लिये स्वीकृति जारी की जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो NAAC accreditation में मैं बताना चाहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रूसा के अन्तर्गत यूनिवर्सिटी को 20-20 करोड़ रुपये मिलते हैं और जो गवर्नमेंट कालेजेज हैं उनको 2-2 करोड़ रुपये मिलते हैं लेकिन उनमें एक ही शर्त होती है कि उनको तब तक वह पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि वह NAAC accreditation नहीं करवा ले, ए और बी ग्रेड उनको प्राप्त नहीं हो जाये। लेकिन आज हमारे यहां विडम्बना है कि कोई भी यूनिवर्सिटीज और कालेज इसके प्रति गम्भीर नहीं है। हमारी सरकार को इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाना पड़ेगा, गम्भीरता से विचार करना पडेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देती हूं कि उन्होंने हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई है। उसमें चेयरमैन की भी नियुक्ति की है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई है वह अभी वर्किंग में नहीं है। वहां पर स्टाफ के बैठने की भी जगह नहीं है और जो उन्होंने मेम्बर्स बनाये हैं उनके भी अभी नियुक्ति पत्र उनको जारी नहीं हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगी कि इसे मात्र औपचारिकता न समझकर गम्भीरता से इस ओर प्रयास किया जाय।

(डा. मंजू बाघमार)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी स्वायत्तता पर रोक लगाई जा रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि हमारे यहां प्रिंसिपल सैक्रेटरी, एजुकेशन अनेक कमेटियों में चेयरमैन बने हुए हैं और विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं उनको वहां पर मेम्बर बनाया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे कुलपतियों की गरिमा के खिलाफ है। शिक्षा को बढ़ावा देने वाले इन कुलपतियों को समाज को और सरकार दोनों को इन्हें सम्मान देना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इस दिशा में हमें सकारात्मक कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तो बात करते हैं लेकिन हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पूरे देश में, आज सबसे ज्यादा राजस्थान में 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 29 गवर्नमेंट की हैं लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पर तो कंट्रोल करने के लिये आपने वहां पर आएएस आफिसर को कंप्ट्रोलर लगा रखा है, रजिस्ट्रार लगा रखें है और दो माननीय विधायकों को वहां पर बाम और सिंडिकेट का मेम्बर बना रखा है। लेकिन जो 44 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिये हमने अभी तक कोई भी नियामक आयोग नहीं बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिये तत्काल एक नियामक आयोग बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि समय-समय पर विधान सभा में जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को लेकर कई मामले उठे हैं, कई फर्जी डिग्रियों के मामले उठे हैं कि बीएसई के क्षेत्र में कई फर्जी डिग्रियां बांटी जाती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपनी मर्जी से फीस लेती हैं, अपनी मर्जी से एडमिशन देती है, मर्जी से एग्जाम लेती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि एक नियामक आयोग बनाया जाये और फर्जी डिग्रियों को रोकने के लिये हर महीने की अंतिम तारीख को सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को उन्हें अपनी सूचना भिजवाये क्योंकि बीएसई की डिग्री तीन साल बाद में मिलती है। जब एडमिशन होता है तो उन्हें नहीं बताया जाता है कि हमारे यहां इन-इन स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है और तीन साल बाद डिग्री दी जा रही है तो इस

(डा. मंजू बाघमार)

तरह से फर्जी डिग्रियों पर रोकथाम लगाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो हमारी सरकार कौशल विकास के लिये निरन्तर प्रयासरत है। स्किल डवलपमेंट के लिये निरन्तर कोशिश कर रही है कि हम अपने बच्चों को रोजगार देने के लिये उनकी स्किल को डवलप किया जाये। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि हमारे राज्य में जो पोलीटेक्निक कालेज हैं उनमें पहले सेमस्टर सिस्टम लागू हुआ करता था लेकिन पिछले दो तीन सालों से उस सेमस्टर सिस्टम को खतम करके एनुअल सिस्टम कर दिया है। निश्चित रूप से इससे शिक्षा के क्षेत्र की गुणवत्ता में रुकावट आई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हायर एजुकेशन में सेमस्टर सिस्टम लागू किया जाये ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेक्निकल एजुकेशन के सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर 8 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेजेज हैं लेकिन कभी भी उनकी एकेडमिक आडिट नहीं करवाई जाती है। यदि उनकी एकेडमिक आडिट करवाई जाये कि वहां पर कितनी कांफ्रेसेस हुई हैं, कितने सेमीनार हुए, कितने एक्सपर्ट लेक्चरर्स हुए हैं तो निश्चित रूप से कौशल विकास के क्षेत्र में हम धरातल पर इस दिशा में कार्य कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पूरे नोर्थ इंडिया में गर्ल्स में केवल एक ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज अजमेर में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी जिसकी स्थापना हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 2007 में की गई थी। उस गवर्नमेंट वीमेन इंजीनियरिंग कालेज का नाम हमारी राजमाता विजया राजे सिंधिया के नामकरण पर किया जाये।

माननीय सरकार और हमारी मुख्य मंत्री संवेदनशील हैं और निरन्तर यही प्रयास करती हैं कि छात्राओं को आगे बढ़ाया जाये। उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाये। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट वीमेन इंजीनियरिंग कालेज अजमेर है वहां पर सेल्फ फाइनेंस में जो कोर्सेज चल रहे हैं और 70-70 हजार रुपये फीस ली जा रही है, यदि आधी सीटों की फीस भी गर्ल्स के लिये माफ कर दी जाती है तो निश्चित रूप से यह हमारा एक सकारात्मक कदम होगा।

(डा. मंजू बाघमार)

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी बीओजी की जो कमेटी बनती है उसमें जो चेयरमैन और मैम्बर बनते हैं, उसमें आई आई टी के और आई एम के प्रोफेसर्स को लगाया जाये ताकि उसका एकेडमिक गवर्नेंस ठीक ढंग से चल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया के ठोस एवं सकारात्मक प्रयासों के क्रियान्वयन से राजस्थान शिक्षा जगत में अव्वल हो सकता है और पुन: विश्व गुरु की श्रेणी में आ सकता है, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री गोतम कुमार।

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर जो बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार और सुधार के काम हमारी सरकार कर रही है। सर्वप्रथम तो मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरणजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो वर्षो से चली आ रही हमारे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में महाविद्यालय की हमारी विशेष मांग। चूंकि वहां से 70-70, 80-80 किलोमीटर में भी कोई महाविद्यालय हमारे वहां नहीं था और उस महाविद्यालय को उन्होंने स्वीकृत किया, उसके लिए मैं अपने पूरे क्षेत्र की ओर से और अपने स्वयं की ओर से भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा महाविद्यालय स्वीकृत किया उसके लिए।

एक जो महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया है, शिक्षा के क्षेत्र में। मेरा पहला भी चूंकि हमारा परिवार राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जब हम देखते थे हमारे गांव से जब लोग आते थे और एक सीनियर स्कूल खुलवाने के लिए दो-दो बार, तीन-तीन बार जयपुर के चक्कर लगाने पड़ते थे। बसें भर-भर के लोग यहां आते थे और उनको केवल आश्वासन मिलते थे और हमारी सरकार ने एक आदेश में लगभग पांच हजार नए माध्यमिक स्कूल हर पंचायत स्तर पर खुलवाए। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, हमारे शिक्षा मंत्री देवनानीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसी पहल... चूंकि हमारे वहां गांवों में, हमारे वहां ट्राइबल बैल्ट है और एक-एक माध्यमिक स्कूल में कम-से-कम पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस किलोमीटर दूर वहां जाना पड़ता था, सीनियर स्कूल में पढ़ने के लिए। तो ऐसे में बालिकाएं काफी

(श्री गोतम कुमार)

वंचित रह जाती थीं शिक्षा के क्षेत्र में। तो उसके लिए भी मैं आदरणीय मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा एक काम किया हमारे लिए। वो भी आज दिन तक जितने भी काम हुए वो किसी-न-किसी पार्टी के... दो स्कूल होते थे, चार स्कूल होते थे। इस दल विशेष के होते थे, ये होते थे। लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बिना किसी भेदभाव के पूरे राजस्थान में हर पंचायत स्तर पर खोला, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

इसी तरह से हर ब्लाक स्तर पर जैसे जिले में पहले नवोदय स्कूल होते थे, जिला स्तर पर सिर्फ एक नवोदय स्कूल होता था, लेकिन अब स्वामी विवेकानंद के नाम से जो माडल स्कूल, जो एक स्त्री स्कूल अभी चालू किया है और हमारे यहां बड़ी सादड़ी और डूंगला दोनों ही ब्लाक के उपखंड स्तर पर जो दोनों माडल स्कूल जो आपने स्वीकृत कराए उनकी बिल्डिंग के लिए भी जो सेंक्शंस दी है, उसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्य मंत्री को, आदरणीय शिक्षा मंत्री देवानानी जी को, उनको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि सात-सात करोड़ रुपए के लिए और उनके एडमिशंस भी प्रारम्भ कर दिए, इसके लिए भी मैं आदरणीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा अपने क्षेत्र की ओर से।

ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ स्कूलें खोलना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद आजादी के बाद पहली बार शिक्षकों के लगभग पचास हजार प्रमोशन हमारी सरकार ने इस बार किए हैं। इससे कई सारे काम हुए हैं। अभी जो नामांकन बढ़ाने की बात हो रही थी कि प्राइवेट स्कूल में नामांकन .. प्राइवेट स्कूल की ओर डायवर्शन हो रहा है, लेकिन मेरा जैसा मानना है इस साल जुलाई में लगभग 25 परसेंट गवर्नमेंट स्कूल का नामांकन बढ़ा है और इसमें बहुत सारे काम हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने बालिकाओं का साइकिल के बदले चैक देने का काम किया था और जैसे ही हमारी मुख्य मंत्रीजी वापस सरकार में आईं उन्होंने पहली ही घोषणा की कि चैक के बदले साइकिल देने की। आज जब हम गांवों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं और देखते हैं तो वहां लगता है साइकिलों का एक मेला लगा रहता है और यह भी शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम हुआ है। चूंकि बालिकाएं अगर साइकिल नहीं हो तो कैसे वहां जाए ? तो इसके लिए भी जो साइकिल वितरण किया है चैक के बजाय, यह निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम हमारी सरकार ने उठाया है।

(श्री गोतम कुमार)

हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र में एक वाइल्ड लाइफ एरिया है, जहां आजादी के बाद 70 सालों में कोई बिल्डिंग नहीं थी। वहां छह प्राथमिक स्कूल चल रहे थे। पेड़ों के नीचे वहां पढ़ाई होती थी। सर्व शिक्षा के माध्यम से वहां भी छह स्कूलों के लिए लगभग 90 लाख रुपए की स्वीकृति जो आदरणीय शिक्षा मंत्री देवनानी साहब आपने जारी की, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि वहां एक पारलिया ऐसा इलाका है जहां बीस-बीस, तीस-तीस किलोमीटर दूर तक कोई सड़क नहीं है, ना लाइट है, ना बिजली है। ऐसे में वहां अगर स्कूल हुआ है तो निश्चित रूप से आने वाली कई पीढ़ियां आपको वास्तव में याद करेंगी।

एक मेरी थोड़ी-सी पीड़ा है आपसे कि स्कूल भी क्रमोनत हुए हैं। सब कुछ हुआ है लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्र में 65 स्कूल क्रमोनत हुए हैं माध्यमिक शिक्षा के। लेकिन व्याख्याताओं के अधिकतर पद अभी तक रिक्त हैं। अभी 30 हजार तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती आपने निकाली है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाले सत्र जुलाई से पहले आप जो व्याख्याताओं के पद हमारे यहां रिक्त हैं, लगभग 80 परसेंट पद हमारे वहां व्याख्याताओं और द्वितीय श्रेणी के पद रिक्त पड़े हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि तृतीय श्रेणी के तो लेंगे लेकिन फर्स्ट ग्रेड की पूर्ति नहीं होगी, चूंकि हमारे सभी स्कूल माध्यमिक स्तर के हो गए हैं तो व्याख्याताओं की कमी है। प्रिंसिपल्स लग गए हैं लगभग सभी स्कूलों में लेकिन व्याख्याताओं की कमी से जूझ रहे हैं तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि हमारे प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में जो हमारी विधान सभा है उसमें व्याख्याताओं के पद आप लगाने का प्रयास करें।

इसी तरह से अभी जो स्कूल क्रमोनत हुए हैं, छात्रों की संख्या भी बढ़ी है, नामांकन भी लगभग 25 परसेंट बढ़ा है। उस अनुरूप में हमारे जो विद्यालय हैं, विद्यालय परिसर जो कई वर्षों पूर्व बने हुए थे। उनमें कक्षा-कक्षों की थोड़ी-सी कमी हुई है। वैसे मैं धन्यवाद दूंगा मंत्रीजी को रमसा के माध्यम से हमारे 18 स्कूलों में लगभग 100 कमरों के आसपास की स्वीकृति हमें मिली है। लगभग आठ-नौ करोड़ के काम हमारे विधान सभा में रमसा के माध्यम से आए हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, काफी कमरों की अभी और जरूरत है। मैं उसकी आपको सूची भी दूंगा तो मेरा आपसे आग्रह है कि उनमें भी अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के लिए थोड़ा-सा बजट अगर आप आबंटित कर देंगे तो उसके लिए आपको जितना धन्यवाद दे सकेंगे, उतना कम है।

(श्री गोतम कुमार)

चूंकि ट्राइबल बैल्ट से हम आते हैं तो वहां बहुत सारा शैक्षणिक पिछड़ापन है। चूंकि ये वेकेंट पोस्ट हैं, ये सब चीजें हैं। आज जो हमारे 80 परसेंट जो पद रिक्त हैं, उनका मूल कारण यह है कि हमारे यहां से अभी इतने प्रमोशन हुए हैं। लेकिन हमारे वहां के लोगों को इतना लाभ नहीं मिल पाया प्रमोशंस का और हमारे क्षेत्र में अभी भी सारी पोस्ट वेकेंट हैं तो इन सब चीजों का मूल कारण जो है। यह सारे कारण हैं और सरकार निश्चित रूप से इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है।

**(14.57 बजे)**

**(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)**

प्रमोशंस भी कर रही है, स्कूल भी क्रमोनत कर रही है तो निश्चित रूप से इससे क्षेत्र की जनता, ग्रामीण जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा।

मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए हमारे यहां विद्यालयों में कुछ प्राथमिक स्कूल भी ऐसे हैं और कुछ माध्यमिक स्कूल भी ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। मैं उनकी सूची भी आपको प्रस्तुत करूंगा। चूंकि एक-एक का नाम अगर लूंगा तो थोड़ा-सा लम्बा हो जाएगा, ज्यादा नहीं कहते हुए मैं उनकी सूची भी आपको उपलब्ध कराऊंगा।

मैं इतना ही कहते हुए आपने मुझे इस मांग संख्या 24 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री हनुमान बेनीवाल।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मांग संख्या 24 – शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी बहुत बड़ी उम्मीद राजस्थान के ग्रामीण इलाक़ों के अन्दर जगी थी और उसके बाद राजस्थान के बाद दिल्ली के चुनाव हुए और दिल्ली के चुनावों में भी देश की जनता ने सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप दी।

सभापति महोदय, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान मुख्य मंत्रीजी जिन भी इलाकों में गईं। 2012 के अन्दर पिछली सरकार के टाइम जो भर्ती हुई थी पंचायत राज के माध्यम से, 40 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती हुई और राजस्थान सेवा अधिनियम, 27(बी) के तहत प्रोबेशन का पीरियड सभापति महोदय दो साल का है और 2012 से 2016 तक का समय आ गया। पिछली विधान सभा का सत्र भी था इससे पिछला बजट सत्र था और हजारों की तादाद

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के अन्दर 2012 की भर्ती के शिक्षक जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से लेकर गांव ढाणियों रेगिस्तानी इलाक़ों के अन्दर, पहाड़ी इलाकों के अन्दर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

(15.00 बजे)

सरकार उनको मात्र 13 हजार रुपये दे रही है। अभी भी उनको परिवीक्षाकाल के अन्दर माना जा रहा है। विधान सभा के अन्दर भी उनका टी पाइंट पर चार-पांच दिन पहले बड़ा धरना था। बहुत बड़ा संघर्ष वह लोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करुंगा कि 40 हजार शिक्षकों की भर्ती राजस्थान में की गई थी उनको नियमित वेतनमान में लेकर सरकार उनका परिवीक्षाकाल करे। सभापति महोदय, आज महंगाई के जमाने में 13 हजार रुपये में कोई नौकरी करे, तो 13 हजार रुपये में तो घर का खर्चा भी नहीं चलता। वह 13 हजार रुपये की नौकरी में कहां से अच्छी शिक्षा गांव, ग्रामीण स्कूलों के अन्दर दे पाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार को यही कहना है कि 40 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं, इनको नियमित वेतन श्रृंखला के अन्दर आदेश दें और इनके साथ न्याय करें।

सभापति महोदय, 2015-16 में स्वीकृत प्रगति की बात करें तो नवीन प्राथमिक स्कूलों के 150 भवनों के निर्माण की बात कही थी। 31 दिसम्बर, 2015 तक एक भी स्कूल का निर्माण पूरा नहीं हुआ। यह प्रगति प्रतिवेदन के सरकार के आंकड़े हैं, जो आप हमें हमारे घर पर भेजते हैं। या तो आपके प्रगति प्रतिवदेन असत्य बोल रहे हैं, या आप शिक्षा को बढ़ाने की बात, यहां विधान सभा के अन्दर लम्बे-चौड़े भाषण मंत्रीजी देते हैं, आप यह बात करते हो कि हम राजस्थान को एक नम्बर पर लेकर आएंगे। राजस्थान में सुराज लेकर आएंगे, राजस्थान को नम्बर एक पर लेकर जाएंगे, राजस्थान के अन्दर ऐसा राज होगा, वैसा राज होगा, लेकिन आपके खुद के ही आंकड़े यह कह रहे हैं कि आपने 31 में से 8 पेयजल सुविधाओं पर ही कार्य पूर्ण किया है। मेजर रिपेयर के 946 लक्ष्य में से 227 ही पूर्ण किए। बड़ी विडम्बना है कि 49.80 करोड़ में से मात्र 28 करोड़ रुपये आपने राजस्थान के अन्दर खर्च किए।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2015-16 में मेंटीनेंस एण्ड रिपेयरिंग ग्रांट में 53 हजार 322 स्कूलों को केवल आपने 38 करोड़ रुपये आबंटित किए। पर स्कूल 5 हजार रुपये मिले, 5 हजार में तो कलर भी नहीं होता है। यह कौन आपको किसी तरह लाकर बताता है

(श्री हनुमान बेनीवाल)

और यहां बैठे-बैठे आदेश जारी कर देते हैं कि इतने करोड़ हमने दिए। दिए तो आगे स्कूल कितनी है, कितना इलाका है, 5 हजार के अन्दर तो एक कमरे की सफाई नहीं होती साल के अन्दर।

सभापति महोदय, अगर अपन शिक्षा को मजबूत करने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो सरकारी स्कूलों में ग्रामीण इलाके के लोगों का विश्वास पैदा करना होगा। आजकल तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को डालना ही नहीं चाहता। हम भी सरकारी स्कूल के अन्दर पढ़े हैं। यहां आए हुए ज्यादातर माननीय सदस्य सरकारी स्कूल के अन्दर पढ़कर आए हैं। सभापति महोदय, लेकिन आज सरकारी स्कूल में क्या हालात हैं। आज गांव-गांव के अन्दर प्राइवेट स्कूल खुल गए। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, कोई नियंत्रण नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सरकारी स्कूल की तो आज जो सत्ता पक्ष की सदन में हो रही है ना, वह स्थिति है। 20 आदमी हैं, 20 आदमी, वह ही सरकारी स्कूलों की स्थिति है, यही सदन में सरकारी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की स्थिति है। (व्यवधान) 20 आदमी हैं, गिनों तो सही एक बार। राठौड़ साहब, क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, देखो तो सही आप ... (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): आप किस स्कूल में पढ़े थे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप उप मुख्य सचेतक हैं, आपकी ड्यूटी है कि माननीय सदस्यों को उपस्थित रखो। आप सत्ता पक्ष के लोग हो। हम ही ज्यादा हैं आपसे तो इस टाइम।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सभापति महोदय, सरकारी स्कूलों के अन्दर गांव के लोगों का, ढाणी के लोगों का विश्वास पैदा करना होगा, कि सरकारी स्कूल के अन्दर पढ़ाई अच्छी होती है। अब तो लोग कहने लग गए सरकारी स्कूल में पढ़ाए इसके बजाय तो 5 हजार या 10 हजार रुपये में डिग्री मिलती है यू.पी., बिहार से, वह डिग्री लाकर हम अपने बच्चे को आठवीं की डिग्री दिला देंगे, दसवीं की दिला देंगे। वैसे ही रोजगार राजस्थान में तो मिलता नहीं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुझे सरकार का ध्यान आकर्षित करना है कि सरकारी स्कूलों के अन्दर आप अंग्रेज़ी की प्राथमिकता पहली क्लास से चालू करें। वहां अंग्रेज़ी के अनुभवी टीचर है, आप गांव की स्कूल के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अन्दर लगाएं, ढाणियों की स्कूल के अन्दर लगाएं। आपने एक काम किया। राजस्थान के अन्दर आपका यह तीसरा बजट है, तीसरे बजट में एक भी स्कूल खोलने की घोषणा नहीं करी। लोग हमें पूछते हैं। आपके सब विधायकों को बुलाया, जनप्रतिनिधियों की मीटिंग की, मुख्य मंत्रीजी ने भी बात करी कि सम्भाग स्तर पर बताइये बजट में क्या देना है और आपके एमएलए बोले हमारी बात हो गई, कहा 15 स्कूल खुला देंगे। कहां से खुला दोंगे बताओ आप, आप लोग स्कूल खुला दोंगे क्या, क्या जवाब दोंगे? या तो बढ़-चढ़कर इतनी बात नहीं करनी चाहिए कि यह कर देंगे, वह कर देंगे।

सभापति महोदय, मेरा यह कहना था कि आप जब तक सरकारी स्कूल, जहां ढाणियों का इलाका है आबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। आपके वही स्कूल खुले हुए हैं जो कांग्रेस राज में पिछली बार स्कूल खुले थे पांच साल, उसके बाद एक भी नया स्कूल आपने ढाई साल में नहीं खोला। चौथा बजट आप अगली बार पेश करेंगे, तीन बजट आपने कर दिए।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि सुदूर ढाणियों के अन्दर, जहां आबादी बढ़ रही है, बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आपको नये प्राथमिक विद्यालय राजस्थान के गांव ढाणी के अन्दर खोलने चाहिए। जहां प्राथमिक विद्यालयों में संख्या बढ़ जाती है वहां उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत भी करना चाहिए। आपने इस बार और पिछली बार एक भी माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की बात नहीं की। फिर कैसे शिक्षा के अन्दर गुणवत्ता लाओगे, कैसे आप राजस्थान को आगे बढ़ाओगे। अब लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएंगे। सरकारी स्कूल के अन्दर अध्यापक नहीं है, कोई रख-रखाव नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। पांच की पोस्टिंग होती है, एक हैड मास्टर, दो करके कि तीन आप मत आओ, मैं भर दूंगा हाज़िरी आपकी, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं।

तालाबंदी की सबसे ज्यादा घटना इन दो सालों के अन्दर राजस्थान में हुई। लोग ताला लगाकर बैठ जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन तक ताले नहीं खुलते। डी.ओ. जाते हैं, आश्वासन देते हैं, एमएलएम आश्वासन देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपके दो मास्टर लगा देंगे, जाओ। आप इधर से उठाकर उधर लगाते हो। दूसरे दिन दूसरे ग्रामीण आते हैं डी.ओ. आफिस में तो आप उनकी कैंसिल कर देते हो। तो कानून व्यवस्था की स्थिति राजस्थान के अन्दर इस तरह हो गई कि अब सरकारी स्कूलों से लोगों का भरोसा उठ गया।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, 17 हजार स्कूल आपने सिर्फ इसलिए बंद कर दिए, पता नहीं कौनसा मैसेज आप देना चाहते थे। आपके पास पढ़ाने को अध्यापक नहीं है, बैठने के लिए भवन नहीं है, स्कूल नहीं, तो आप शिक्षा में राजस्थान को कैसे एक नम्बर पर लाओगे। आपको यह व्यवस्था करनी होगी और इसमें पार्टियों से ऊपर उठकर, खींवसर की जनता भी आपकी है। जहां बीजेपी के लोग हार गए, अगर बीजेपी के लोगों की शर्मनाक हार हुई, उनके प्रति भी आप ठीक रखें, बदले की भावना से काम नहीं करें, तब जाकर राजस्थान के अन्दर मैसेज जाएगा। आप कुछ नहीं कर रहे सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल, यह बजट लाए, यह कर दिया, वह कर दिया, आ गया सुराज, आ गया सुराज। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने यह तय कर लिया कि कांग्रेस ने जो रिकार्ड बनाया हार का, 60 साल में 24 सीट पर आई है, अगली बार आप कांग्रेस का रिकार्ड तोड़ोगे, 24 से कम पर आओगे, यह तय कर लिया, या तो यह हो सकता है।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आप तो धन्यवाद दो हनुमानजी, कालेज खोल दिया इसका तो धन्यवाद दो।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अभी उच्च शिक्षा पर तो बाद में आऊंगा। सभापति महोदय, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के सर्वे में 2015-16 में राज्य का स्कोर 19.5 रहा जो देश के अंतिम 10 राज्यों में है। तो आप राजस्थान को किस दिशा की ओर ले जाओगे। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री विराजमान हैं। मैं भी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं, यह भी रहे हैं, यहां कम से कम पांच तो हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, एक जोधपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष विराजते हैं। आपके इस दिशा में सोचना चाहिए।

आप जब पिछली बार विपक्ष में थे, खूब बात उठाते थे आप शिक्षा की। आपका एक भाषण आया खूब लम्बा-चौड़ा, मैंने पढ़ा था। आपने कहा कि यह कर दो, वह कर दो, यह कर देना चाहिए, तो अब आपको कौन मना कर रहा है, कर दो आप।

सभापति महोदय, जो संघर्ष कर रहा है वह यह कहता है कि मुझे एक बार पद पर बिठा दो मैं हिन्दुस्तान को सोने की चिड़ियां बना दूंगा लेकिन जिस दिन उस शीर्ष पद पर पहुंचा वही लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग उसको घेर लेते हैं। मनमाने तरीके से उस व्यक्ति को चलाने लग जाते हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आपको मजबूती के साथ काम करना होगा। हो सकता है कि आप

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कोशिश करते हो, नहीं कर पाते हैं कई काम, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री विराजमान हैं, राजस्थान के अन्दर छात्र संघ चुनाव आपने पहले बंद कराए थे। 2004 में बंद हुए और 2009 के अन्दर राजस्थान में छात्र संघों के चुनाव चालू हुए। आपको पता नहीं कौनसा डर लग रहा है। आप लिंगदोह कमेटी के आधार पर क्यों चुनाव करवा रहे हो। राजस्थान के अन्दर कौनसा नेतृत्व आप देना चाहते हो इन विश्वविद्यालयों से, जो अध्यक्ष बनकर अगर राजस्थान की राजनीति में आयेंगे। देश की राजनीति में छात्र राजनीति से निकलकर जो नेता गये, आप यह बतायें, सभापति महोदय, कि उन्होंने हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ी है, चाहे हिन्दुस्तान की राजनीति हो या राजस्थान की राजनीति। लिंगदोह कमेटी की आड़ के अन्दर आपने छात्रसंघ के लोकतांत्रिक चुनावों की हत्या कर दी। अगर किसी का ड्यू पेपर रह गया वह चुनाव नहीं लड़ेगा, अगर एक बार वह हार गया, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा। प्रेसीडेंट है, वह वी.सी. प्रेसीडेंट को जब चाहे निलम्बित कर सकता है। प्रिंसिपल कालेज के प्रेसीडेंट को कहेगा कि इतनी तारीख के बाद में आपके कार्यालय पर ताला होगा। आप यह नहीं कर सकते, आप वह नहीं कर सकते, आप उस गैस्ट को नहीं बुला सकते, आप उस अतिथि को नहीं बुला सकते, वह सरकार के खिलाफ बोलता है, यह बोलता है। पूरे तरीके से विश्वविद्यालय और कालेज, इनकी उस स्वायत्ता को अगर खतम करने का किसी ने काम किया तो आपने किया। आपने तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर ऐसे कुलपति की नियुक्ति कर दी जो पीएच.डी. नहीं है, जो कहीं प्रिंसिपल नहीं रहा। अग्रवाल कालेज के अन्दर कार्यवाहक प्रिंसिपल रहा है। अब किसकी मेहरबानी से लगा, कैसे हुआ, लेकिन इस देश के प्रथम पांच विश्वविद्यालयों में राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम आता था सभापति महोदय। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपन अपनी सिफारिश के अन्दर कि मैंने लगवाया वी.सी.। यह नम्बर कहां बना रहे हो, यह बताओ आप। इस तरह के व्यक्ति को बैठा दिया जिसे किसी तरह का ज्ञान नहीं, जिसके पास वह डिग्री नहीं जो कुलपति बनने के लिये चाहिये। सभापति महोदय, देश आजाद हुआ, देश में क्रांतियां हुईं उसमें सबसे बड़ा ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप यह ज्ञान की बात कुलपति के लिये कह रहे हो या उच्च शिक्षा मंत्रीजी के लिये कह रहे हो।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): एक मिनट रुकिये। सबसे बड़ा योगदान इस देश को आजाद कराने के लिये इस देश के नौजवान का रहा, देश

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के छात्र का रहा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी मांग मनवाने के लिये अगर छात्र कोई हड़ताल करता है, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देता है, आप लाठीचार्ज करवा देते हो। आपके दो साल के कार्यकाल में छात्रसंघ चुनावों के अन्दर फर्जी तरीके से आपने जोधपुर के अन्दर विश्वविद्यालय अध्यक्ष का रिजल्ट घोषित करवा दिया। जब लड़के मांग कर रहे थे कि मतगणना ठीक नहीं हुई, आपने उनके घर पर लाठीचार्ज किया। पूरे परिवार को थाने के अन्दर बंद कर दिया।

सभापति महोदय, यह कौनसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप इस राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं। युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को दबाओगे, फिर कौन लड़ेगा इस देश के लिये, बताओ आप, जवान ही तो लड़ता है। आप जवान को कमजोर करना चाहते हो। जगह-जगह आपने अभी देखा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आंदोलन कर रहे थे। आपने लाठीचार्ज किया, जेलों के अन्दर डाल दिया, झूठे मुकदमे दर्ज कर लिये। फिर बीकानेर के अन्दर, फिर अजमेर के अन्दर, कम से कम पचास जगह। अपनी मांग मनवाने के लिये आज छात्रसंघ का अध्यक्ष छात्रहितों की बात नहीं करेगा, वह कुलपति कार्यालय के आगे जाकर अगर धरना नहीं देगा, मुख्य द्वार पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा तो कहां पर जाकर अपनी बात कहेगा। आपने तो यह कर दिया कि अब सड़क पर भी आप हमारी खिलाफत नहीं करोगे। नहीं तो अन्दर डाल देंगे, जेल में डलवा देंगे, यह कौनसा काम कर रहे हो आप लोग?

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना था कि आज आपको विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता के अन्दर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। आज तो हालात यह हो गये कि एक वी.सी. मेरे को पिछली बार कह रहे थे, पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर छोटे-मोटे मामलों के अन्दर पुलिस नहीं जाती थी। छोटी-मोटी बात, लड़कों के अन्दर झगड़े हो जाते थे, आप भी अध्यक्ष थे तब भी झगड़े होते थे और आप ही करवाते थे झगड़े, लेकिन पुलिस जाने से पहले हजार बार सोचती थी। कुलपति की परमीशन लेनी पड़ती थी। कालेज के प्रिंसिपल की, चीफ वार्डन की, वार्डन की परमीशन लेनी पड़ती थी। वह वी.सी. साहब तो कह रहे थे कि हमें परमीशन की कह रहे हो, मुझे तो खुद को एक दिन गाड़ी में बैठा लिया था। मुश्किल से हाथा-जोड़ी करके नीचे उतरा कि आप भी चलो साथ में, आपने इस तरफ देख लिया किसी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

को। तो यह हालत है, सभापति महोदय। इसके अन्दर मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी स्वायत्ता पर सरकार को दखलंदाजी कम करनी चाहिये। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि छात्रसंघ चुनाव के अन्दर यह पार्टियां जिस तरह से हस्तक्षेप करती हैं, चाहे कांग्रेस का संगठन हो, बी.जे.पी. का संगठन हो या और कोई अन्य संगठन हो। पार्टियों का हस्तक्षेप कैम्पस में बंद होना चाहिये। कैम्पस के अन्दर स्वतंत्र राजनीति होनी चाहिये। तब जाकर व्यक्ति खुले विचारों की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आगे बढ़ सकता है।

सभापति महोदय, आज बहुत दुख होता है कि राजस्थान के अन्दर जहां भी एक्जाम होते हैं, डर लगता है कि पेपर कितने बजे आउट होगा। करीब-करीब पेपर आउट हो गये। अभी देवनानीजी ...(व्यवधान)

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): हनुमानजी, विश्वविद्यालय छोड़े 15 साल हो गये। अब तो इधर आ जाओ।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): चौमूं आऊं क्या चौमूं।

अब हमारे देवनानीजी नाराज हो जायेंगे। बोर्ड की परीक्षाएं, पेपर आउट हुआ, अभी कहेंगे नहीं हुआ आउट। अभी आपके रीट का एक्जाम, पेपर आ गया व्हाट्स-एप्प पर। जेल सेवा का आपने...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): रीट का कहां आया, हनुमानजी, आप बता दो।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): वह तो आप सुनो।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं जानकारी चाह रहा हूं।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मेरे पास तो आया नहीं, जिनके व्हाट्स-एप्प पर आया था, मैंने देख लिया। मैंने कहा ना, आप अभी कहोगे।

आज जो भी एक्जाम होगा, सबसे पहले तो इस बात का डर लगता है। बच्चे आते हैं। भाई साहब, पेपर बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन सलैक्शन होगा कि नहीं। क्यों, क्या हुआ? वह आउट हो गया तो फिर उनके नम्बर ज्यादा आ जाएंगे। वह तो फिर सौ में से 90, 92, 98 लाएंगे और हमने 80 सवाल सही किये हैं। मतलब हर कहीं डर सता रहा है कि पेपर आउट हो गया। इसके लिये आप क्या करोगे, बताओ आप। हां, आपको इस बात का धन्यवाद देंगे कि आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन को आपने जेल में डाला। लेकिन हमने उस समय एक बात कही थी कि आर.पी.एस.सी. के अन्दर पहली बार घपला नहीं हुआ है। पिछले दस साल के अन्दर, जिनके सैकिण्ड डिवीजन थी, बोर्ड के अन्दर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

थर्ड डिवीजन थी, जिन्होंने ग्रेजुएशन सैकिण्ड डिवीजन से की, वे एक-एक परिवार के पांच-पांच, सात-सात लड़के आर.जे.एस. और आर.ए.एस. बन गये। आप सारी जांच कराते दस साल की सी.बी.आई. की, तब जाकर लगता कि आप कुछ कर रहे हो। राठौड़ साहब बैठे हैं सामने। मेडिकल पी.एम.टी. का घोटाला। आपने एक्जाम तो रद्द करवा दिया लेकिन आपने उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की क्या जो घोटाले में लिप्त थे। करते आप कार्यवाही। आपने कहा था यहीं पर कि हम कर देंगे। कहां कर दिया, अच्छी पोस्टिंग मिल गई उन लोगों को। अब तो हालत यह हो गई कि इस विधान सभा में मजाक सा हो गया कि हम बात कहें, लोग कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा भाषण देने से। होता तो कुछ है नहीं, यह स्थिति हो गई सारी। तो सरकार को इस मामले में गम्भीर होना चाहिये।

**(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)**

दो मिनट। ठीक बोल रहा हूं, क्यों कर रहे हैं। दो मिनट बोलने दीजिये।

सभापति महोदय, अपने को राजस्थान को बचाना है, राजस्थान के जवान को बचाना है और सरकारी स्कूलों में आमजन का भरोसा कैसे बढ़े, इस दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिये। उसमें आपको कांग्रेस, बी.जे.पी., निर्दलीय नहीं देखने चाहिये। अब देखते हैं, कई लोग, कह रहे हैं, हमने तो पिछली बार एक चीज देखी। मैं कोई पिछली सरकार की पैरवी नहीं कर रहा हूं। बी.जे.पी. के 80 एम.एल.ए. थे, मैं भी उनमें एक था। जो भी एम.एल.एज. को काम मिलते थे, वे 80 बी.जे.पी. के विधायकों को मिलते थे, दोनों तरफ, विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो काम होगा वह विधायक की अभिशंसा पर होगा। पहली बार हमने देखा है कि इतनी कम संख्या में विपक्ष होते हुए भी आपको यह भी नहीं सुहा रहा है कि 20-22-24 जने हैं, इनके काम होने ही मत दो बिलकुल। आप क्या करना चाहते हो, अब की बार 163, अगली बार 200 जीतना चाहते हो क्या राजस्थान में कि अगली बार 200 के 200 हम कर लेंगे। ऐसा कतई नहीं हो सकता। आपको बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिये।

राजस्थान के अन्दर शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, इस दिशा के अन्दर आपको काम करना चाहिये। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराजे हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर प्रोफेसरों के आप क्यों नहीं इंटरव्यू

(श्री हनुमान बेनीवाल)

करवा रहे हैं, बताओ, लम्बा टाइम हो गया है। आपको कराने चाहिये प्रोफेसरों के इंटरव्यू। इस राजस्थान के अन्दर जितने प्रोफेसरों के पद रिक्त हैं, आपको वह भी करना चाहिये। आप कालेज तो खोल देते हो, कला संकाय, एक कला संकाय से क्या होगा। क्या हमारे गांव का लड़का कालेज में कला संकाय की पढ़ाई पढ़ेगा जिन्दगी भर। आप तीनों संकाय साथ खोलें। ऐसी व्यवस्था करें या कालेज खोलें ही मत। जब कालेज खोलो और जब सीनियर माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करो, सीनियर के अन्दर क्रमोन्नत करो तो सारे ही सब्जैक्ट्स की व्यवस्था वहां पर करो। सारे टीचर्स की व्यवस्था करो, 17 हजार स्कूल आपने बंद किये। स्कूल बंद करने के साथ-साथ अभी डेढ़ लाख पद राजस्थान के अन्दर शिक्षकों के रिक्त हैं, सभापति महोदय, आपको इस दिशा में काम करना चाहिये। इसके अन्दर दे दिया आपने कि बजट बढ़ा दिया आपका। आप भर्ती कब करेंगे, यह बताओ ना। आज राजस्थान का विद्यार्थी मित्र 25 हजार की संख्या के अन्दर जो बैठा है, कल टंकी पर चढ़े 12 विद्यार्थी मित्रों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन आपने क्या किया। आपने कहा, शिक्षा सहायक के रूप में आपको नियुक्ति दे रहे हैं। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आपने कहा कि हम विद्यार्थी मित्रों को लगायेंगे, पैरा टीचर्स को लगायेंगे, प्रबोधक को नियमित करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। ये चाहते हैं कि आप इनका काम करो।

इनके हाथ में नियुक्ति का आदेश दो कि प्रोपर यह सेवाएं करें। तीन हजार, चार हजार रुपये में विद्यार्थी मित्र वहां पर जाता है। ग्रेजुएट विद्यार्थी मित्र है चूंकि, वह बेरोजगार है इसलिए रोजगार के अभाव के अन्दर अपने परिवार का पेट पालने के लिए वह पढ़ाने के लिए जाता है और आप उसको तीन हजार, चार हजार रुपये देते हो।

प्रबोधक, पैराटीचर्स का मामला, आप गम्भीरता से लेकर इनको नियमित करें। जो चीजें आपने सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर रखी थीं, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि शेखावाटी विश्वविद्यालय, महाराजा सूरजमल और भर्तृहरि विश्वविद्यालय के साथ-साथ खेल यूनिवर्सिटी, झुंझुनूं, शेखावाटी का, आपने श्रेय लेने के लिए, हर बार हमने देखा, पिछली बार भी, उससे लास्ट में आपने जाते-जाते शायद यह तीनों विश्वविद्यालय खोले। पिछली बार खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की लेकिन वहां पर है कहां, यह तो बताओ? यहां लड़के फर्स्ट ईयर के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अन्दर से हम देखते थे कि बोले कि मैं तो मेरी टी.सी. लेकर जा रहा हूं, मैं तो शेखावाटी विश्वविद्यालय में एडमिशन लूंगा, मैं सूरजमल में लूंगा। अब वह न यहां के रहे और न वहां के रहे। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं और दो-तीन वी.सी. और रजिस्ट्रार लगा दिये जो नेताओं के रिश्तेदार हैं, उनको बैठा दिया और गाड़ियां दे दीं। अब इस काम के लिए है क्या यह सारे? (व्यवधान)

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, यह विश्वविद्यालय नियामक आयोग की आप बात कर रहे हैं। कब बनाओगे, इसको आप बताओ। बनाइए, पुख्ता मानिटरिंग होनी चाहिए।

राइट टू एजुकेशन के अन्दर आप कह रहे हैं कि 25 प्रतिशत बी.पी.एल. और गांव के ग्रामीण लड़के होंगे। कहां हो रहे हैं, बताओ आप? यह आपकी जयपुर की इतनी टाप स्कूल है, सेंट जेवियर, एस.एम.एस., यह सेंट एंसल्म, हो रहे हैं क्या गांव के लड़कों के एडमिशन? वहां पर प्रिंसिपल बात तो नहीं करते, फादर बात तो नहीं करते नेताओ से। नेता अपने एडमिशन के लिए घूमते रहते हैं सड़कों पर। तो कब आएगा राइट टू एजुकेशन बताइये आप?

माननीय सभापति महोदय, सरकार पर मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ठीक संदेश देगा तो ठीक होगा। अब आपके मानव संसाधन मंत्रालय की मंत्री की डिग्री के बारे में ही संशय है लोगों को, बताओ आप।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, अपनी ...(व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): डिग्री फर्जी है, अब मुझे तो आप रोक देंगे, मैं बैठ जाऊंगा घंटी बजाकर। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** नहीं, बैठना है आपको तो। (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): लेकिन वह करोड़ों-अरबों लोगों को ... (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** अब आपको बैठना है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, जो यह कह रहे हैं कि इनकी मानव संसाधन, जो दिल्ली की मंत्री हैं, उसकी डिग्री ही फर्जी है। तब लोग फिर कह रहे हैं कि पूरा मामला ही फर्जी है। इसको कैसे ठीक करेंगे, बताओ आप? तो आपको इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। आप हंसी-मजाक में ले रहे हो मेरी बात को। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अब आप बैठें। श्री रमेश।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): 2018 के अन्दर आपको कहेंगे बोलने के लिए। कैसे 2018 तक ...(व्यवधान)

**श्री सभापति**: अब आपका अंकित नहीं होगा। श्री रमेश।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री सभापति**: अब आपका अंकित नहीं होगा।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री सभापति**: अब आपका अंकित होगा नहीं।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। कल भी केवल हमारे 40 में से 2 सदस्यों को बुलावाया गया। मैं आसन से संरक्षण चाहता हूं। बोलने की आजादी है, हम प्रतिपक्ष में हैं। मतलब, दस-दस आदमी सत्ता पक्ष के बोल जाएं, उसके बाद में भी कांग्रेस के सदस्य का नम्बर नहीं आए तो यह व्यवस्था इस तरह की क्यों बनाई जा रही है कि प्रतिपक्ष बोल ही नहीं पाए, कांग्रेस बोल ही नहीं पाए, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप व्यवस्था देंगे। इस तरह से कम से कम आवाज दबाने का काम नहीं किया जाए, आसन से मेरा आग्रह है।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आपके दल के लिए जो समय निर्धारित हुआ है, उसमें आपको ज्यादा बोलने का मौका मिला है, कम नहीं मिला है। फिर भी आपने जो प्रश्न उठाया है ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इसमें समय का नहीं होता है, माननीय सभापति महोदय, इसमें समय नहीं होता है, इसमें प्रति दिन होता है। आपने यह व्यवस्था कर रखी है कि चार उधर से बोलेंगे, एक कांग्रेस का बोलेगा, एक, चार फिर बोलेंगे, इसमें समय नहीं होता है। डिमांड में समय नहीं है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: जितनी सदन की सदस्य संख्या दलों के अनुसार है, उसके अनुरूप ही आपके दल के व्यक्ति को बोलने के लिए अवसर दिया जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): कितने सदस्य हैं हमारे? हमारे कितने सदस्य हैं? कांग्रेस के 24 हैं। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** हां।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): निर्दलीय 7-8 हैं, जो लगभग-लगभग, 2-3 को छोड़कर आपको समर्थन दे रहे हैं। आपके विधायक दल की बैठक में जाते हैं और उसके बावजूद आप प्रतिपक्ष को मौका नहीं देते हो, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** बिलकुल, आपके सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह आवाज दबाने की बात है। अगर आसन की यही मंशा है तो फिर दूसरी बात करें। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** आपके सदस्यों की संख्या के अनुसार आपके सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): हम 24 हैं, आप फिर सुन लें। आसन फिर सुन लें कि हम 24 हैं और 24 के अनुपात में ही बोलने की आजादी चाहते हैं लेकिन बोलने की आजादी मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** बोलने की आजादी सब सदस्यों को है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इस तरीके से इधर से उप मुख्य सचेतक के इशारे से अगर बुलाया जाएगा, आसन काम करेगा तो मैं समझता हूं कि वह आसन निष्पक्ष नहीं हो सकता। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, बैठिए आप। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इसलिए मैं आपके, आसन पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, कि कांग्रेस के सदस्यों का, जो प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, इस सदन में। (व्यवधान)

**श्री सभापतिः** श्री रमेश।

**श्री रमेश** (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-24 पर चर्चा हो रही है। पक्ष और प्रतिपक्ष अपने विचार रख रहा है, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रदेश की विकास की धुरी है और सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पक्ष अपनी बड़ाई करेगा, हम उनकी कमियां निकालेंगे और बात आई गयी हो जाएगी और अनुदान की मांग पारित हो जाएगी।

(श्री रमेश)

लेकिन, उससे ऊपर उठकर सभी माननीय सदस्यों को सोचना होगा कि जो गरीब का बच्चा अंतिम छोर पर रहता है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था और उसको हमें कैसे पढ़ाना है, उसको कैसे शिक्षित करना है, वहां पर स्कूल खोलना है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारे माननीय सदस्यों की बनती है। आज हमारे माननीय सदस्यों ने अभी अपने-अपने आंकड़े दर्शाये कि हमारे समय में हमने यह किया, हमारे समय में हमने यह किया, सबने अपने-अपने आंकड़े दिखाए, बड़ाई की, अच्छी बात है।

लेकिन, जिस प्रकार राजस्थान की जो स्थिति है शिक्षा में, हम बात करते हैं शिक्षा की तो कितनी दयनीय स्थिति है कि भारतवर्ष में हमारे राजस्थान की शिक्षा की दर कितनी है, वह नीचे से बात करें तो चौथे नम्बर पर आता है और ऊपर से 36 की लिस्ट में बात करें तो 33वें नम्बर पर है, प्रदेश हमारा राजस्थान और यह मैं नहीं कहता कि इसकी जिम्मेदार अब जो सरकार सत्ता में बैठी है, वह है। हम सभी जिम्मेदार हैं इस व्यवस्था के कि हम शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ा पाए। जो होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जो सरकार है, उसकी मंशा होनी चाहिए कि शिक्षा का प्रतिशत बढे और यदि शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश विकास की तरफ बढ़ेगा और होता क्या है कि जो भी सरकार आती है, वह कहेगी हमने इतने नामांकन कर दिये। अभी कुछ दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 7 लाख बच्चों के नामांकन हमने बढ़ा दिये। जब रिजल्ट आता है विद्यार्थी का तो आंकड़े कुछ और ही कहते हैं कि परीक्षा एग्जाम में इतने लोग बैठे, वह ड्राप-आउट हो गये या कहां चले गये? या फिर मिड डे मील के आंकड़ों के माध्यम से पता लगता है कि वास्तविक आंकड़ा क्या था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था आज से 45-46 वर्ष पहले जब कोई भी अभिभावक से बात की जाती शिक्षा के प्रति तो उससे पूछा जाता कि आपका बच्चा कहां पर पढ़ता है? तो वह बड़े गर्व के साथ कहता था कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और आज स्थिति क्या हो गयी है? किसी से पूछा जाए तो वह किसी इंग्लिश स्कूल की बात करेगा, किसी ईसाई स्कूल की बात करेगा तो ऐसी स्कूल्स की बात करेगा, सरकारी स्कूल की बात नहीं करेगा। उसे शर्म आती है मैं बता दूंगा कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो यह शायद मेरे से बात ही नहीं करे, मेरे से जो जान-पहचान बढ़ा रहा है, वह भी बंद हो जाएगी।

(श्री रमेश)

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि ऐसा वातावरण बने, ऐसे नियम बनाए जाएं, ऐसा कानून बने कठोरता के साथ कि शिक्षा की दृष्टि से हमारे जो बच्चे हैं, वह ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ें और हमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। आज स्थिति यह हो रही है कि गरीब, मजदूर, ठेले चलाने वाला, वह भी यह प्रयास करता है, यह सोचता है कि मैं मेरी रोजी रोटी है, मैं कम रोटी खा लूंगा लेकिन मेरा बच्चा पढ़े तो फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़े।

सरकारी स्कूल की तरफ उसका ध्यान नहीं है। उसका विचार बदल चुका है तो, माननीय सभापति महोदय, आज जिस प्रकार राजनीति में शिक्षा हावी हो गयी है। हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं सभी को डर लगता है कि शिक्षकों का तबादला कर दिया, शिक्षक पर कंट्रोल कर दिया या कोई ऐसी प्राब्लम क्रिएट कर दी जो संगठन आ जाएंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा।

शिक्षा मंत्री को यह भी सताता रहता है कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वह चुनाव हार जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि इस चुनाव की हार से मत डरो आप। आप अच्छा काम कर जाओगे और मैं जो यहां कई गुरुजन बैठे होंगे, या शिक्षक होंगे, हमारे विधायक भी कुछ ऐसे हैं कि ऐसी विचारधारा या शिक्षकों में ऐसा मन बने, विचार आए या अपने हृदय से सोचें, दिल से सोचें कि हमारी जो रोजी-रोटी चल रही है, हमारा घर चल रहा है, जिसकी रेवेन्यू से हमारा पूरा परिवार चल रहा है, हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसकी हम कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए लेकिन व्यवस्था बदल गयी है। शिक्षा में आज राजनीति घुस गयी है, अन्दर आ गयी है तो वह सारा वातावरण बदल गया है। मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि हमारी राजस्थान की जो लिट्रेसी दर थी 1991 में 38.55 परसेंट, जिसे हमने 2001 में बढ़ाया है 60.41 परसेंट तक ले आए और 2011 के अनुसार जो लिट्रेसी दर है, 67.06 परसेंट और जो हमारी राष्ट्रीय दर है शिक्षा की, वह 74.04 है, तो बहुत कम है। इसमें भी हम महिलाओं की देखें तो पुरुष की 76.16 परसेंट और महिलाओं की 45.8 परसेंट। तो, मैं कहना चाहूंगा कि स्थिति हमारी इस तरह बद से बदतर होती जा रही है और यदि ऐसा ही चलता रहा और सरकारें भी इसी तरह धक्के देती रहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है नजदीक ही

(श्री रमेश)

समय है, कितने भी प्रयास आप कर लें, यह सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाने नहीं जाएगा। सारी जगह धीरे-धीरे प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): आपने ही तो की थी लागू इसीलिये सत्यानाश हुआ है इससे।

**श्री रमेश** (सपोटरा): मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): आपके राज में हुआ है। आप यह इल्जाम मत लगाओ। हमारे राज में बोर्ड बन गया उसका। आपने पहली से आठवीं तक ...(व्यवधान)

**श्री रमेश** (सपोटरा): वह भी बात करेंगे। आप बैठ जाएं माननीय सदस्य, वह भी बात कर लेंगे। वह भी बता देंगे, आप चिन्ता न करें, धैर्य तो रखें। मेरा निवेदन है एक दिन ऐसा आएगा धीरे-धीरे कि हर जगह प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं और जो योग्यता नहीं रखते हैं, पात्रता नहीं रखते हैं, उन स्कूलों की मैरिट अच्छी आ रही है और ऐसा दिन आएगा, जिस दिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रहेंगे, हमारे अध्यापक, जो गुरुजन है कि चार का तो दाखिला करा दो, पांच का तो करा दो। कोई नहीं जाएगा पढ़ने, तो इतनी भारी लाखों की संख्या है हमारे गुरुजनों की, उस फौज को इस सरकार में कहीं मर्ज करना पड़ जाएगा। इससे पहले आप लोगों का सोचना होगा और तय करना होगा कि हमारी शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले और इसमें हम कैसे आगे बढ़ें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए।

आज आप बात करते हैं प्राइमरी स्कूलों की, जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, उनमें जो सिस्टम है छोटे-छोटे प्राइमरी धीरे-धीरे खुल रहे हैं। हमारे बच्चों की जो संख्या है प्राइवेट की तरफ उनका रूझान और लगाव बढ़ रहा है। हमारे सरकारी स्कूलों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है तो 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं, इनका एनरोलमेंट प्राइवेट विद्यालयों में 2006 की बात करें तो 25.20 परसेंट था, वह अब 40 परसेंट से अधिक हो गया है। इसके बाद अगर सरकारी की बात करें तो प्रथम और द्वितीय कक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी का जो प्रतिशत रह गया है, 53 से 60 प्रतिशत है, जबकि पांचवीं कक्षा तक का यह 40 प्रतिशत है और स्थिति यह है कि आप सभी जानते हैं माननीय सदस्य, कि हम पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में चले जाते हैं और वहां औचक निरीक्षण या डी.ई.ओ. के माध्यम से या कलक्टर जब जाता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है कि तीसरी

(श्री रमेश)

चौथी का विद्यार्थी शुद्ध हिन्दी नहीं लिखना जानता। चौथी-पांचवीं का हमारा विद्यार्थी गणित का जोड़ना नहीं जानता तो हमारी ऐसी कैसी शिक्षा की विवशता है, इसको हमें सुधारना होगा।

इसके बाद आपने जो समानीकरण के नाम पर किया। राज्य के लगभग 17 हजार विद्यालय बंद कर दिये। इसको भी आप सही नहीं कर पाए फिर बाद में आपने सिस्टम को थोड़ा बहुत बदला, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि मर्ज करने वाला एकीकरण, समानीकरण इससे कुछ स्थितियां ऐसी भी उत्पन्न हुईं कि आज प्राथमिक स्तर के ड्राप-आउट का जो स्तर है, वह 9 परसेंट है, जनजाति का 10 परसेंट है और सबसे जो ज्यादा नीचे जा रहा है मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम माइनोरिटी का 18 परसेंट से भी अधिक है। इससे ऊपर की कक्षाओं की बात करें तो 70 प्रतिशत मुस्लिम लड़कियां हैं माइनोरिटी की और इसी तरह एस.सी., एस.टी. के ड्राप-आउट 12 प्रतिशत है और राज्य में छात्राओं का ड्राप आउट प्रतिशत बढ़ा है। यह देश के औसत ड्राप आउट से दोगुना अधिक हो गया है, जो अपने देश का है।

इसी तरह राज्य में सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों की संख्या लगभग 25 प्रतिशत है, लेकिन जो उनके बच्चों की संख्या है वह 40 परसेंट है और जबकि शेष बच्चे हमारे 75 परसेंट विद्यालयों में 60 प्रतिशत बच्चे हैं तो राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यय की बात करें, सरकार कितना खर्च कर रही है एक स्टूडेंट पर, तो 37 से 40 रुपये ही आ रहे हैं सरकार के। सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती हैं पर वर्तमान स्थिति लगभग यही है।

आज नामांकन की बात करें। माननीय मंत्री महोदय और सरकार के माध्यम से भी पहले भी कहा जा चुका है कि सात लाख नामांकन हमने बढ़ाए तो राज्य में 11 से 14 साल के उम्र की बच्चियों की स्कूल में नामांकन की दर को हम नहीं बढ़ा पाए। यह अभी भी 11 से 14 प्रतिशत है इसलिये छात्राओं के अनुसार विद्यालयों में सुविधाओं का काफी अभाव है और इसका दूसरा कारण भी है निजी विद्यालय, जो उनको अधिक सुविधाएं देते हैं, वह भी एक कारण है।

मैं कहना चाहूंगा राज्य में इस प्रकार के कुछ विद्यालयों में जो आपने समानीकरण किया उसकी वजह से छोटे-छोटे बच्चे अधिक दूरी होने के कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो ड्राप आउट का या छात्र उपस्थिति कम होने का एक कारण यह भी रहा है। फिर आपने इस चीज को माना तो इसको मर्ज करने

(श्री रमेश)

का दबाव रहा, आपने उसको ड्राप कर दिया तो आपने यह ठीक किया। लेकिन इस समय इस तरह का सिस्टम चला, तो समय खराब हुआ। महीने, दो महीने बच्चों के खराब हो गये तो शिक्षा की दृष्टि से जो इस सैशन में हुआ, इसका आने वाले समय विद्यार्थियों का जो रिजल्ट रहेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा।

अभी आपने कहा था सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कि हम सत्ता में आएंगे तो पालिसी लाएंगे और पालिसी का शायद मैंने पढ़ा भी है, जो आपने घोषणा की है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आपने सबसे पहले हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, जिनको उच्च शिक्षा मंत्री का प्रमोशन दे दिया तो अब एक प्रश्नवाचक विषय है कि शिक्षा मंत्री से इनको क्यों बदल दिया गया, इनका प्रमोशन क्यों कर दिया गया। दिल्ली तक शिकायतें हुईं, उसके बाद मंत्री बदला गया, फिर जब दूसरे मंत्रीजी पधारे तो उसके बाद में भी शिकायतें हुईं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर सरकार ने एक जोरदार काम किया कि एक कमेटी गठित कर दी ...(व्यवधान) सुन तो लो आप, हमने जो कुछ किया है उसका परिणाम आप देख रहे हो, हम यहां बैठे हैं तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। आप सुन लें धैर्य से। उसके बाद कमेटी गठित कर दी, अब उसमें न तो कोई जन-प्रतिनिधि है, न कोई मंत्री है। बहुत शर्म की बात है कि ऐसे राज्य की जनता, जिसमें मंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है और कोई जन-प्रतिनिधि भी नहीं है, और ऐसी कमेटी का गठन कर दिया जिसकी सिफारिश से तबादले हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने वैसे तो जिलों में बैन लगा रखा है कि प्रतिबन्धित जिलों से ट्रांसफर नहीं होंगे।

और बड़ी-बड़ी बातें भी की हैं। अभी आपने पालिसी बनायी है उसमें ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आपने अपने नजदीकी लोग, जो हमारे माननीय सदस्यों के होंगे या मंत्रीजी के होंगे या सरकार के होंगे, 127 शिक्षकों को प्रशासनिक कारणों से जो भी जिले प्रतिबधित थे उनसे स्थानान्तरण कर दिया गया है और बाहर आप दूसरी बात कर रहे हो कि आपके लिए हम पालिसी ला रहे हैं। तो एक अच्छी बात है लेकिन जो भी करना है आप बिना भेदभाव के करें, सभी का निस्तारण करें।

आपने एक काम किया सुराज संकल्प यात्रा के दौरान कि हम टैट को हटाकर रीट लायेंगे, और बड़ी-बड़ी बातें कीं, उसमें आपने कहा कि इसमें चैंज करेंगे, बदलाव करेंगे, सरलीकरण करेंगे लेकिन टैट को रीट कर दिया, हुआ

(श्री रमेश)
कुछ नहीं उसमें, नाम ही तो बदला है। जैसे राजीव गांधी केन्द्र था उसको अटल सेवा केन्द्र कर दिया।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): हुआ है न, एक काम किया है न। पहले जब हमारी रीट थी न तो उसमें राजस्थान का 60 परसेंट जी.के. आता था और अब जो आपने रीट की है न उसमें राजस्थान का जी.के. 10 परसेंट है। तो राजस्थान के लड़के बाहर होंगे और बाहर के लड़के आयेंगे, यह भला काम किया आपने।

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, फिर खड़े हो गये, आप अपने वक्ता को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): राजस्थान के लड़कों का हित मारा है।

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आप अपने वक्ता को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, वो अच्छा बोल रहे थे तो बोलने दो न उनको। आपके काम्पीटिशन आपस का है यहां क्यों दिखाते हो सदन में?

**श्री रमेश** (सपोटरा): कोई नहीं है, माननीय उप मुख्य सचेतक।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में आर.टी.ई. के प्रवेश के माध्यम से हजारों की संख्या में स्कूलों में आप आर.टी.ई. के माध्यम से एडमिशन कराने की बात करते हैं उनमें फर्जी नामांकन बता कर आपसे कई गुना फीस वसूल कर रहे हैं। कुछ स्कूलों की स्थिति तो यह है कि उसमें जो छात्रों की संख्या है, जो प्रवेश बता रहे हैं, कुल संख्या भी नहीं है उसके बावजूद भी पूरे, जितने भी छात्र उस स्कूल में पढ़ते हैं उतने की ही आपसे फीस वसूल कर रहे हैं। तो इस सरकार में यह क्या हो रहा है? यह सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है या सरकार के ध्यान में नहीं है? तो इस तरह की जो व्यवस्था हो रही है और राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की हानि पहुंचायी जा रही है, माननीय मंत्री महोदय, इसकी एक जांच करवाएं। इसमें दिखवाएं कि वास्तव में हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं उनका स्कूलों में दाखिला हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारे कितने बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है, बड़े-बड़े स्कूल हैं उनमें प्रवेश लेते ही नहीं हैं, लेते हैं दो-चार दिन में उसको परेशान करके भगा देते हैं लेकिन सरकार से पैसा जरूर वसूल कर रहे हैं।

दूसरी बात जो रिक्त पदों की है, रिक्त पद की व्यवस्था आज से नहीं

(श्री रमेश)

है, अभी मंत्रीजी जवाब देंगे, बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। रिक्त पद इस सरकार में इतने हैं और आपने प्रमोशन दे दिया। हमारे माननीय विधायक कह रहे थे कि पूरे राजस्थान में जितने भी सैकण्डरी स्कूल थे ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर उनको प्रमोट करके आपने सीरियर सैकण्डरी स्कूल कर दिया, सब लोगों ने धन्यवाद दिया, हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसे स्कूल क्रमोन्नत करने से क्या फायदा है जहां अध्यापक ही नहीं है, जहां पढ़ाने वाले थर्ड ग्रेड के टीचर भी नहीं हैं? एक-एक सैकण्डरी स्कूल में एक है, दो है तो एक तो नोडल में चला जाता है, एक वहां रह जाता है। तो वहां की व्यवस्था बिलकुल गड़बड़ा गयी है और इससे ऐसा नहीं लगता है, उलटा काम नेगेटिव हो गया है कि शिक्षा के प्रति आपने तो स्कूल को क्रमोन्नत किया लेकिन वहां तो शिक्षा मिल ही नहीं रही है। पहले जो व्यवस्था थी वो ठीक चल रही थी, उसको भी आपने बिगाड़ दिया। इसके साथ हमारे माननीय विधायक कह रहे थे कुछ 30 ऐसे सैकण्डरी स्कूल हैं जहां पर आपने उनको भी क्रमोन्नत नहीं किया तो सरकार वहां भी क्रमोन्नत करे, अध्यापक लगाये।

बाड़मेर का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि मुरटाला गाला ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर है लेकिन आज तक वो आठवीं तक ही है, यह भी आप लिख लें कि इसको क्यों नहीं किया?

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

माननीय सभापति महोदय, मेरा भाषण मेरे समय के अनुसार ही कर रहा हूं। वैसे तो आपने मुझे लेट बुलवाया, आपने समय का दिया, समय आप जितना दें उतना ही ठीक है क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के विधायक हैं, सरकार को डर लग रहा है हमारी बात सुनने में।

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, आप बोलने से पहले थोड़ी घड़ी पर नजर ...

**श्री रमेश** (सपोटरा): नहीं, बात सुनने में यदि आपको भय है तो हम पूरे ही वाकआउट कर जायेंगे, हम आयेंगे ही नहीं सदन में अगर ऐसा लग रहा है। पांच, छह, सात आदमियों के बाद में हमें बुलवा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से मैं पहला व्यक्ति हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं आसन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन आप तीन-चार के बाद में हमें बुलवाएं तो अच्छा लगे, समय कम दो ...(व्यवधान)

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, जिस समय आप बोलने के लिए खड़े हों उस समय आप घड़ी देख लिया करो कि आपको समय ज्यादा दिया कि कम दिया। थोड़ी घड़ी आप देख लिया करो।

**श्री रमेश** (सपोटरा): बीच में भी बोल गये हैं माननीय सदस्य तो उसको भी देखें बीच में आप, ऐसा नहीं करें, सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है मेरे हितों की रक्षा करें।

**श्री सभापतिः** आप थोड़ा समेटने का प्रयास करो।

**श्री रमेश** (सपोटरा): हां, ठीक है। (व्यवधान) सच ही बोल रहे हैं।

आपको बता देते हैं कि रिक्त पदों की जो स्थिति है वो यह है कि वर्तमान में राज्य की सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में कुल 20 लाख 75 हजार से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, क्रमोन्नति के बाद व्याख्याताओं के केवल 32 हजार 90 पद स्वीकृत हैं लेकिन क्रमोन्नयन के बाद कुल पदों की संख्या 46 हजार 928 हो गयी है। व्याख्याताओं के 46 हजार 928 स्वीकृत पदों में से अभी केवल 24 हजार 928 पद कार्यरत हैं और 22 हजार पद रिक्त हो गये हैं जिसे भर पाना अभी राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

राज्य के हजारों से अधिक जो स्कूल हैं उनमें प्रिंसिपल नहीं हैं। इसके कारण इसी साल 250 से अधिक स्कूलों में, 250 तो लिखा है, इससे ज्यादा तालाबंदी क्या हजारों स्कूलों में तालाबंदी हो चुकी है। स्थिति यह है कि आप टीचर तो लगा नहीं पाते बल्कि टोंक में तो आपने डंडे बरसा दिये। राजसमंद में भी आपने कठोरता से तालाबंदी दबाने का प्रयास किया और बच्चियों के आगे आपको हार माननी पड़ी।

स्थिति आपकी और बता दूं कि भौतिक विज्ञान में आपके जो विषय अध्यापक हैं, 900 स्कूलों में कमी है भौतिक विज्ञान में टीचर्स की, व्याख्याताओं की। रसायन विज्ञान में 800 स्कूलों में, इतिहास में 2000 स्कूलों में, राजनीति विज्ञान में 1800 स्कूलों में, हिन्दी में 3000, अंग्रेजी में 2500 स्कूलों में, वाणिज्य में 3000 स्कूलों में और अन्य विषय देखें तो 5 हजार स्कूलों में, यह आपके अध्यापन की व्यवस्था है टीचर्स की।

आपने राज्य में 33 हजार 689 विद्यालय सहायक की भर्ती की घोषणा की लेकिन वो अभी तक नहीं हो पायी है। उसके बाद हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं वो प्रदेश में आत्म हत्याएं कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार गम्भीर नहीं है,

(श्री रमेश)

सरकार सोई हुई है। प्रबोधक भी आपकी सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, आपके कार्यालय तक जा रहे हैं लेकिन उनकी भी जन सुनवाई नहीं हो रही है, आप जन सुनवाई की बात करते हो। तो कोई रास्ता निकालो ताकि उनको भी रोजगार मिले, उनका परिवार चले, उनकी भी कोई व्यवस्था हो।

उसके बाद आपने जो बात कही थी स्टाफिंग पैटर्न की वापस लेने की, इसमें भी आपने ढिलाई दे दी। स्कूल समय घटाने पर विवाद हुआ, फिर घटा दिया आपने। स्कूलों में छात्र कम संख्या है या न के बराबर लेकिन फिर भी अभी आपने अध्यापक लगा रखे हैं और नियमों के विपरीत, जो पद केवल प्रतिनियुक्ति से भरने का प्रावधान था उनमें भी आपने तबादला कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान के उप-निदेशक की बात करें। उसमें आपको प्रिंसिपल को आवेदन करना होता है, साक्षात्कार होता है उसके बाद प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है जबकि वर्तमान में सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए इन पदों पर तबादले कर दिये।

शिक्षा नीति में इस तरह के कुछ पाइंट्स जो आये हैं, मैंने अख़बार में पढ़ा है कि प्रारम्भिक शिक्षा हेतु नवीन तबादला नीति में जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को विशेष श्रेणी से बाहर रखा गया है जबकि इससे पहले जिसको राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार मिलता है उसका तो आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए था।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप अख़बार की जगह जो नैट पर डली हुई है नीति उसको पढ़ने का प्रयास करें।

**श्री रमेश** (सपोटरा): ठीक है अगर आपने सुधार किया है तो, अच्छी बात है।

आपने नीति में जो रखा है, जिन शिक्षकों का रिजल्ट 75 परसेंट रहेगा प्रतिबंधित जिलों में आप उनका ही तबादला करेंगे, तो यह तो आपकी पालिसी हो जायेगी कि यहां रिजल्ट नहीं रहा तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा 20 साल, 30 साल से क्योंकि वहां पद नहीं भरे जायेंगे। वो भी आपकी दूसरी कंडीशन है कि 75 परसेंट पद नहीं भरेंगे तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा। जिनका रिजल्ट 30 परसेंट से कम होगा, डी-ग्रेड रहेगा उसको आप दूरस्थ भेज देंगे इस पालिसी में, तो फिर आ गये आप तो गरीबों पर कुठाराघात करने के लिए कि आपका कोई टीचर है उसको आप सुधार तो नहीं रहे हो और आपको इंटीरियर

(श्री रमेश)

में, या किसी डांग में, या जंगल में, या पिछड़े हुए क्षेत्र में लगाने का जो प्रयास है उससे क्या करेगा वो। वहां पहले ही बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, शिक्षा के प्रति सरकार गम्भीर नहीं है।

वहां यदि उस टीचर को लगा देंगे तो वहां उस गरीब की शिक्षा का बिलकुल ही बंटाधार हो जायेगा। उस गरीब के बारे में सरकार को सोचना है कि ऐसे टीचर्स को वहां नहीं लगायें। उसको ऐसे काम पर लगायें जो आपके रोजाना हाजिरी दे या आपके कंट्रोल में रहे, देखरेख में रहे। ऐसी जगह उनको लगाया जाये।

राज्य में अधिकांश विद्यालयों में प्रबंधन समिति कोई काम नहीं करती। प्रदेश में 7 लाख 88 हजार एसएमसी सदस्य हैं और 52 हजार से अधिक एसएमसी अध्यक्ष हैं, जिनमें अधिकांश अभिभावक हैं। प्रदेश के 62 हजार 254 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का हस्तांतरण प्रारम्भिक शिक्षा से आपने माध्यमिक शिक्षा में किया। इसी बहाने आपने इनका स्थानांतरण भी कर दिया।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, अपनी बात अब समाप्त करें।

**श्री रमेश** (सपोटरा): हां, बिलकुल, लास्ट है अब। पेपर लीक हो रहे हैं। चाहे आपके कालेजों के स्तर की बात कर लें। एक मैं बात करना चाह रहा हूं, उच्च शिक्षा की। राज्य सरकार ने अप्रैल, 2015 में निजी महाविद्यालयों के लिए नई नीति जारी की कि जिसका रिजल्ट निकटतम यूनिवर्सिटी से कम आयेगा, उसकी मान्यता को अस्थायी कर दिया जायेगा और अच्छा आने पर वापिस स्थायी कर दिया जायेगा, लेकिन समाप्त करने का कोई आप्शन नहीं रखा। केवल कालेज वालों को परेशान करना है? आपका उद्देश्य क्या है? यह भी बतायें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री। आपने बी.एड. कालेजों में फीस बढ़ा दी है।

**श्री सभापतिः** आपने लगभग सारी बात कह दी है।

**श्री रमेश** (सपोटरा): गरीब बच्चा है, जो पात्रता रखता है इंजीनियरिंग कालेज में, मेडिकल कालेज में जाने की। इससे गरीब का बच्चा तो पढ़ नहीं पायेगा क्योंकि उसमें फीस ज्यादा है। उसका पैकेज ज्यादा है। जो अयोग्य है और पात्रता नहीं रखता है और धनवान व्यक्ति का बच्चा है तो मेडिकल, इंजीनियरिंग में आराम से आयेगा। वह प्रदेश के लिए फिर कैसी सेवा देगा,

(श्री रमेश)

उसकी क्वालिटी क्या होगी, उस बारे में भी आपको सोचना है कि गरीब का लड़का भी आये। मैनेजमेंट में आपने उसको चाहे जमीन दी हो, शिक्षण संस्थाएं हों, चाहे कालेज हों, जिसने टोकन मनी के नाम पर आपसे भूमि ली है, उसकी व्यवस्था देखें कि वह हमारे कंट्रोल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी व्यवस्थाओं को भी आप सुधारें।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्य, अब अपनी बात आप समाप्त करें।

**श्री रमेश** (सपोटरा): एक मिनट, कोई ज्यादा नहीं हैं। जो रह गयी हैं मेरी बात। ज्यादा नहीं हैं। एक बिन्दु बोलूंगा।

सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि काफी विद्यालयों में शराब पार्टी हो जाती है, कभी शारीरिक शोषण की भी बात आती है। चाहे राज किसी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे अध्यापकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें ताकि शिक्षा का वातावरण बना रहे।

समाज में अध्यापक का, गुरु का एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, ना कि ऐसा लगे कि गुरु ऐसा है जिससे पढ़ाने लोग अपनी बच्चियों को नहीं भेजें। ऐसी विचारधारा और ऐसा प्रयास सरकार को करना होगा कि जो टीचर गलत कार्य करता है या पढ़ाने के प्रति उसकी मंशा ठीक नहीं है। उसका रिजल्ट ठीक नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है तो सरकार ऐसा कठोर नियम बनाये जिससे वह और अन्य अध्यापक ऐसा कार्य नहीं करें। हमारे समाज में गुरु के प्रति जो लोगों की सोच थी, वही सोच बनी रहे।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो भी टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** प्रतिपक्ष के माननीय मुख्य सचेतकजी, आसन पर तो आप उंगली उठाते हो लेकिन आपके जो भी वक्ता हैं उनका समय भी आप उनको पहले ही बता दें। जो सत्ता पक्ष के सदस्य बोल रहे हैं उनका एवरेज लगभग 12 मिनट का आ रहा है, किसी का 9 मिनट है, किसी का 10 मिनट, किसी का 20 मिनट। आप अपने वक्ता को भी कम से कम बोलने के लिए पहले से ही समझाइश करें ताकि बार-बार टोकना नहीं पड़े।

श्री नवनीत लाल।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): सभापति महोदय, छोटे दलों का भी संरक्षण करो। हमारा भी नम्बर कहीं न कहीं इस रोटेशन में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी के ही आ रहे हैं। हमे तो आप लास्ट में 9 बजे ही बुलवाते हैं।

**श्री सभापति**: बैठें, आप बैठें।

**श्री नवनीत लाल** (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे देश भारत पर विदेशी लोगों का कब्जा था। हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने 1857 में शरीक होकर ऐसा निर्णय लिया कि हमारे देश को आजाद किया जाये। इस बात की योजना बनाकर 1857 से लेकर के 1947 तक, 90 साल के दरमियान लड़ाई चलती रही और आखिर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद हमारे देश के अन्दर आज विधान सभा हैं, लोक सभा है, राज्य सभा है और बड़ी-बड़ी पंचायतें चल रही हैं। जो आज हम इस सदन में विचार कर रहे हैं, वह हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं की बदौलत है।

मान्यवर, मैं लम्बा न कहकर के यह कहना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां हैं, कि हमारी सरकार जनसंख्या के आंकड़ों पर चल रही है। गांव की आबादी हो, उसके अनुसार ग्राम पंचायत। गांव की संख्या, वार्ड की संख्या के अनुसार डीलर। इसी तरह से विद्यालयों में छात्रों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों की व्यवस्था पर विचार होना चाहिए।

केन्द्रीय और राज्य सरकार का आंकड़ा मैंने 15 साल पहले देखा था कि एक अध्यापक 40 से 43 लड़कों को शाला में पढ़ायेगा, 3 लड़के गैर हाजिर रहेंगे, 40 लड़के उपस्थित रहेंगे। यह व्यवस्था 15 साल से पहले की थी, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि जनसंख्या के आधार पर पढ़ाई की व्यवस्था तो करनी चाहिए और हमारे विद्यार्थी सहायक जो मांग कर रहे हैं, उस पर हमारी सरकार को विचार करना चाहिए।

मान्यवर, स्कूलों के ग्राउंड के बारे में आज से 20 साल पहले एक पुस्तक निकली थी शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें लिखा गया था कि प्राथमिक विद्यालय में 5 बीघा का ग्राउंड होना चाहिए। आठवीं क्लास तक के विद्यालय में 8 बीघा का ग्राउंड होना चाहिए और सीनियर में 11 बीघा का ग्राउंड होना चाहिए।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): आप नोट करो मंत्रीजी, इतनी महत्वपूर्ण बात है।

**श्री नवनीत लाल** (घाटोल): उसी अनुसार हमारे शिक्षा विभाग की शालाओं में निर्णय वह हुआ लेकिन आज स्थिति विपरीत हो गई है। क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय हैं वही आठवीं क्लास के हो गये तो पांचवीं क्लास का ग्राउंड है वह आठवीं के विद्यार्थियों के खेल में कहां उपयोग होगा। जो पहले प्राथमिक विद्यालय था, वह आज सीनियर हो गया। उसको 11 बीघा जमीन चाहिए तो सब जगह यह दिक्कतें हो गई। आज विद्यालयों में जब टूर्नामेंट होते हैं, लड़के खेलने जाते हैं, फुटबाल का मैदान तो है ही नहीं, खेलेंगे क्या।

मेरा ऐसा आग्रह है कि पढ़े-लिखे व्यक्ति भले ही हैं, लेकिन अगले दिन का विचार उसमें कम रहता है। कल क्या होगा, इसमें हर पढ़े-लिखे व्यक्ति का ध्यान कम रहता है। मेरा आग्रह है कि इन ग्राउंडों की व्यवस्था के लिए कुछ विचार करना चाहिए और जहां-जहां ग्राउंड हैं इनकी बाउंड्रीवाल पर तुरन्त विचार कर लेना चाहिए ताकि नाजायज कब्जे ना हों और स्कूल की व्यवस्था सही ढंग से चल सके।

(16.00 बजे)

मान्यवर, हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सुराज यात्रा में घूम-फिरकर जानकारी ली। और यह समानीकरण का विचार किया गया। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को समानीकरण के लिए तो धन्यवाद देता हूं लेकिन इसमें एक दिक्कत खड़ी हो गई। दिक्कत यह है कि सीनियर सैकण्डरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कैसे सुचारु रूप से चले इस विचार से समानीकरण किया गया, यह बात तो ठीक है लेकिन जहां प्राथमिक विद्यालय खाली हो गए और वहां सरकारी भवन हैं, उन भवनों का मालिक कौन है? वह भवन खुर्द-बुर्द हो रहे हैं, तोड़-फोड़ हो रही है। तो, माननीय शिक्षा मंत्रीजी से और सरकार से आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि ऐसा विचार हो जाना चाहिए हमारे जो सरकारी भवन हैं, सरकारी भवन अव्यवस्थित हो रहे हैं उनका रखवाला कोई न कोई होना चाहिए। या तो वे ग्राम पंचायत को सुपुर्द किए जाएं या किसी न किसी समाज की कमेटी बनाकर सुपुर्द किया जाए ताकि उस भवन की सही देखरेख हो सके। मैंने कई सरकारी भवनों में जाकर देखा कि वहां लोग चौके उठाकर ले जा रहे हैं, खिड़कियां तोड़कर ले जा रहे हैं तो यह स्थिति ठीक नहीं है। इस पर अपने को विचार करना चाहिए।

(श्री नवनीत लाल)

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन मिड डे मील के बारे में है। प्राथमिक विद्यालय का लड़का सीनियर विद्यालय में चला गया समानीकरण के नाते और वहां पर खानपान या नाश्ता दिया जाता है, उस स्कूल के बरामदे में सीनियर का लड़का खड़ा है और वह प्राथमिक विद्यालय का लड़का नाश्ता कर रहा है, या तो बीच में कोई पर्दा होना चाहिए या फिर सबको देना चाहिए, यानी यह दिक्कत है तो उस मिड डे मील की किसी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। उस बरामदे में जो नाश्ता परोसा जाता है तो उस टीचर के सामने, उस अध्यापक के सामने भी समस्या है, जो लड़का नाश्ता करता है उसके सामने भी समस्या है कि मेरा बड़ा भाई देख रहा है और छोटा भोजन कर रहा है तो यह जो दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही दक्षिणी राजस्थान, जिला बांसवाड़ा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां ट्राइबल और आदिवासी इलाका है, बिखरी हुई आबादी है। जहां समानीकरण किया गया है, जहां स्कूल दूर पड़ती है वहां के छात्रों को क्या दिक्कत आई, उसका सर्वे करवाया जाए ताकि जो स्कूल दूर पड़ती है ऐसे स्कूल का यदि समानीकरण कर भी दिया गया है तो भी उस पर पुनर्विचार होना चाहिए ताकि वह स्कूल आबाद रहे और लड़कों की पढ़ाई भी वहां होती रहे, ऐसा मेरा आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा घोषणा हुई है कि उप खण्ड मुख्यालयों पर महाविद्यालय खोला जाए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र घाटोल में जो सीनियर स्कूल है जिसमें डेढ़ हजार छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं लेकिन वह सीनियर पास करने के बाद वहां आगे कालेज नहीं है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, वहां कालेज तो हैं लेकिन वह प्राइवेट कालेज हैं और आदिवासी व गरीबों के बच्चे इतने ज्यादा पैसे जमा नहीं करवा सकते, ऐसी स्थिति में सीनियर पास करने के बाद छात्र-छात्राएं पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आपने गत सत्र में कहा कि जहां प्राइवेट कालेज है वहां सरकारी कालेज नहीं खोला जाएगा लेकिन जब यह टीएसपी का और ट्राइबल का इलाका है, वहां पर छात्रावास खोले जा रहे हैं, टीएडी से खोले जा रहे हैं, समाज कल्याण विभाग के खोले जा रहे हैं तो उस पर भी विचार करना जरूरी है क्योंकि इनके मां-बाप इतने पैसे दे नहीं सकते और वह छात्र-छात्राएं आगे पढ़ नहीं सकतीं इसलिए ऐसे में उदयपुर सम्भाग में जहां ट्राइबल का

(श्री नवनीत लाल)

इलाका है वहां पर सरकारी महाविद्यालय खोलने पर आपको विचार करना चाहिए यह मेरा आपसे आग्रह है। यहां बीए यानी आर्टस, साइंस, वाणिज्य, यह दो-तीन सब्जैक्ट हैं वह सब्जैक्ट भी खोलें ताकि गांव के व्यक्ति भी उसमें पढ़ सकें, ऐसा मेरा आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि संस्कृत, संस्कृत भाषा वह भाषा है जो हमारे वैज्ञानिकों का, साधु संतों का सबका आज कहना है कि संस्कृत भाषा देश की सबसे वृद्ध और पुरानी भाषा है और मां भाषा है। विद्या की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे संतों का यह कहना है कि विद्या की उत्पत्ति संत वाल्मिकी ऋषि ने की थी और उस समय संसार में कागज नहीं था, कागज की कम्पनी ही नहीं थी तो वह पत्थरों पर और पत्तों पर लिखा गया जिसके कारण बारिश से वह अक्षर धुल गए और जानवर काटने से पत्ते खंडित हो गए जिससे इस भाषा का नाम 'संस्कृत' रख दिया गया। जब कम्पनी का कागज आया तो उसमें सुधार करके रामायण का उद्धार हुआ। तो, मेरा ऐसा आग्रह है कि इस पुरानी भाषा की किस तरह से व्यवस्था की जाए, देखा जाए, रखा जाए, उसी अनुसार मैं बांसवाड़ा जिले की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि वहां संस्कृत भाषा का महाविद्यालय है। तहसील गनोड़ा में जनजातीय अंचल का क्षेत्र है, यहां स्वतंत्रता के पूर्व का संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए एक प्रख्यात स्थान है। गनोड़ा तहसील मुख्यालय पर राजकीय संस्कृत पीजी महाविद्यालय स्थित है। संस्कृत शिक्षा की दृष्टि से जिले का यह महत्वपूर्ण स्थान है।

माननीय सभापति महोदय, उक्त तहसील क्षेत्र के वाशिंदों की कई वर्षों से यह मांग चली आ रही है, प्रमुख मांग है उनकी कि गनोड़ा में बीएसटीसी प्रशिक्षण संस्थान खोला जाए क्योंकि गनोड़ा व आस पास में कई संस्कृत विद्यालय हैं। वहां प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए सैकड़ों छात्र-छात्राएं हैं,। वहां आस पास के संस्कृत, बीएसटीसी सेंटर नहीं होने से सैकड़ों किलोमीटर दूर जयपुर, अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। अतः मेरा आग्रह है माननीय शिक्षा मंत्री महोदयजी, इस बजट सत्र में ही बीएसटीसी प्रशिक्षण केन्द्र गनोड़ा खोला जाए ताकि वहां के पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर नहीं बैठना पड़े, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए खूब-खूब आदर।

(श्री नवनीत लाल)

हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे देश के संतों ने जो देश की लड़ाई लड़ी, हमारा देश आजाद हुआ, देश के अन्दर राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश में लहरा रहा है, लेकिन इसमें हमारे राजस्थान का नाम नहीं है, फिर भी बराबर चल रहा है। इसी तरह से हमारे देश में जो संस्थाएं चल रही हैं...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय के आदेश पर है। आपने मुझे बोलने का समय दिया जिसके लिए धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती अलका सिंह।

**श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 24 शिक्षा, कला व संस्कृति पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आभारी हूं। शिक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है क्योंकि जो कुप्रबंधन पुरानी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किया था उसको सुधारने के लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, अब उच्च शिक्षा मंत्रीजी हैं और अभी जो शिक्षा मंत्रीजी हैं उनको साधुवाद देना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हमारी सरकार ने किया है। पहली बार इतने ज्यादा लार्ज स्केल पर प्रमोशंस हुए हैं क्योंकि प्रोत्साहन देने के लिए और कोई व्यक्ति आगे अच्छा काम कर सके उसके लिए जरूरी है कि जो उसका वाजिब हक है वह उसे दिया जाय। हमारी सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर पहली बार प्रमोशंस किये।

इसके अलावा पुराने समय में जो विद्यालय थे, कई विद्यालय ऐसे थे जहां जीरो नामांकन था और 2-2, 3-3 अध्यापक कार्यरत थे। कई ऐसे थे जहां बिलकुल ही शिक्षक ही नहीं थे। इस विसंगति को ठीक करने के लिए हमारी सरकार ने विद्यालयों का एकीकरण किया और यह भावना ध्यान रखी कि एक किलोमीटर पर प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे को प्राप्त हो। इसके अलावा पहली बार स्कूली शिक्षा का बजट 23177.15 करोड़ है जो हमारे पुराने बजट का 14.47 परसेंट ज्यादा है।

हमारे यहां मैकाले की शिक्षा पद्धति चलती है उस वजह से रोजगार प्राप्त करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने टोटल 670 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की है। इससे बच्चे शिक्षा ग्रहण करके खुद का रोजगार चालू कर सकेंगे और इस तरह की उनको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी कि

(श्रीमती अलका सिंह)

वे स्वरोजगार भी कर सकें और कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाकर काम करना चाहें तो वह भी कर सकें।

हमारी सरकार ने एट्थ, टेंथ और ट्वैल्थ के बोर्ड मैरिट में चयनित छात्रों को लैपटाप वितरित करने के लिए 60 करोड़ का बजट आबंटित किया है। साइकिल वितरण के लिए 85 करोड़ का बजट दिया है। कांग्रेस की सरकार ने जाते-जाते लास्ट ईयर में साइकिल वितरण के लिए 2500-2500 रुपये छात्राओं को दिये थे। मैं कहना चाहूंगी कि यह एक गलत प्रवृत्ति है जो हम बच्चों में डाल रहे थे। कोई भी बाजार में 2500 रुपये में अच्छी साइकिल नहीं आ सकती है। हमारी सरकार ने उस व्यवस्था को सुधारा।

हमारी सरकार ने एक शाला दर्पण पोर्टल शुरू किया है। उसमें कोई भी लाग-इन करके जानकारी प्राप्त कर सकता है कि किस विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं और शिक्षा क्या है, क्या-क्या सब्जैक्ट्स वहां पर है।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना चालू की है। इसमें जो मैरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट व सैकण्ड पोजिशन पर जो आएंगे उनके लिए छात्रवृत्ति देने की योजना है।

अब थोड़ा-सा मैं कांग्रेस के समय जो स्थिति थी उसको बताना चाहूंगी। एसएसआई योजना के अन्तर्गत कांग्रेस के समय में 399.8 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। दो साल में इन्होंने उसमें 64.75 परसेंट ही खर्च किया था, क्योंकि इसमें मानिटरिंग की कमी थी, शिक्षा के प्रति गम्भीरता नहीं थी। सबसे बड़ी बात जो विजन सरकार के पास होना चाहिए, प्रशासनिक विजन की कमी थी।

बालिका शिक्षा पर 40.23 करोड़ का राज्य सरकार को पैसा देना था, लेकिन दो साल के अन्दर इन्होंने पैसा दिया डबल जीरो। कांग्रेस के मुख्य सचेतक यहां उपस्थित नहीं हैं, डबल जीरो वे बहुत बार बोल रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो डबल जीरो है वह बताना चाहूंगी। कस्तूरबा गांधी छात्रावास के लिए 20.87 करोड़ राज्य सरकार को देना था, वह भी दो साल बाद दिया गया, फिर डबल जीरो। शारदा छात्रावास के बारे में कहना चाहूंगा कि शुरू के तीन सालों में एक ही अमाउंट तीनों सालों के लिए आया था, लेकिन जो छात्रावास खोले गये, 80, 47, 20, उनमें कहां अनियमितता थी, कहां गड़बड़ी थी जो इस प्रकार की गम्भीर चूक हुई है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि इसकी जांच कराएं और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्यवाही कराएं। शिक्षा मंत्रीजी, शारदा छात्रावास की बात कर रही हूं।

(श्रीमती अलका सिंह)

इनके समय में 55 स्कूलों में एक भी अध्यापक नहीं था, 15744 स्कूलों में एक-एक अध्यापक था, 24272 स्कूलों में दो अध्यापक थे। अति तो यहां हो गई थी 2013 में बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिये गये थे, जो प्रमाण-पत्र दिये गये थे उसमें गार्गी का नाम गायब था। कोटा में तो यह स्थिति थी कि बच्चियों को जो चैक दिये गये थे 356 चैक, वे बाउंस हो गये थे। जब सरकार की ही गम्भीरता नहीं होगी तो आफिसर्स, कर्मचारी, विभाग कभी गम्भीर नहीं हो सकता। प्रशासनिक रूप से कोई पकड़ नहीं थी और शिक्षा के लिए इनका कोई विजन नहीं था।

बालिका शिक्षा की गम्भीरता के बारे में और बताना चाहूंगी, लास्ट के दो ईयर में इन्होंने थोड़ी गड़बड़ की और बहुत स्पीड से ये लोग दौड़े। इन्होंने आखिरी दो सालों में स्कूल खोले 2776 नई प्राथमिक शालाएं, 3877 मिडिल स्कूल्स, 1319 सैकण्डरी टू सीनियर। लेकिन न तो इनके लिए भवन की व्यवस्था की, न अध्यापकों की व्यवस्था और न ही बजट की व्यवस्था। जो स्थिति शिक्षा की थी वो और भी खराब हो गई। 2010-11 में एक बात और बताना चाहूंगी 2010-11 में 504 करोड़ केन्द्र ने इनको दिये थे, 2392 स्कूल्स में 11200 निर्माण कार्यों के लिए, लेकिन एक भी काम ये शुरू नहीं कर पाये। इसका परिणाम यह हुआ कि 2011-12 केन्द्र सरकार ने एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया। फिर इनके मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी जाकर मिले तो 2013-14 में फिर 124 करोड़ का बजट केन्द्र सरकार ने रिलीज किया, लेकिन फिर भी इन्होंने बिलकुल भी काम नहीं कराया और उसका परिणाम यह हुआ कि 5 साल में बजट 204 करोड़ बढ़ गया। हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने सदाशयता दिखायी और शिक्षा के प्रति राजस्थान के हर वर्ग के विकास के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी संकल्परत है। उन्होंने जो 244 करोड़ ज्यादा बजट बढ़ गया था उसका प्रावधान भी बजट में किया।

अब हमारी सरकार ने टीचर्स की परफोर्मेंस बढ़ाने के लिए टीचर्स परफोर्मेंस एप्रेजल की व्यवस्था की है कि हर तिमाही में टीचर्स आकर अपनी परफोर्मेंस के बारे में बताएंगे, बच्चों के स्तर के बारे में बताएंगे और इससे जो क्वालिटी आफ एजुकेशन देने का सपना हमारी सरकार ने किया है वह क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी।

अभी शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मिड डे मील के बारे में बता रहे थे। उसके बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी। हमारे यहां मिड डे मील

(श्रीमती अलका सिंह)

नामांकन के आधार पर दिया जाता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी चोरी पिछले दरवाजे से होती है। आप नामांकन के समय देखिए, एक अलग संख्या होती है और जो बच्चे परीक्षा में अपीयर होते हैं उनकी संख्या और नामांकन की संख्या में बहुत अंतर होता है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर थोड़ी मानिटरिंग रखिए और जो बच्चे वास्तविक रूप से एग्जाम में बैठते हैं निश्चित रूप से वही संख्या होती है जो स्कूलों में नामांकन होता है। थोड़ा सा इसको चैक करें ताकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगी मेरे क्षेत्र में अभी सीनियर सैकण्डरी स्कूल हर पंचायत हैडक्वार्टर पर खोलने की हमारी सरकार ने योजना बनायी थी। उसमें यह था कि या तो प्राइवेट विद्यालय हो या फिर सरकारी विद्यालय। मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगी, मैंने पर्ची के माध्यम से भी यह बात उठायी थी। मेरे यहां दो महत्वपूर्ण पंचायतें हैं पिचूपाड़ा खुर्द और एक कुन्दरपाडा। जहां न तो प्राइवेट विद्यालय है और न कोई सरकारी विद्यालय है तथा दोनों जगह बच्चों की संख्या 600-700 से ज्यादा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक देखें ताकि बच्चे वहां सरकारी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करें क्योंकि ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, ज्यादा फीस वे नहीं दे पाते हैं।

एक चीज और बताना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय, हमारी सरकार की यह मंशा थी और है कि भामाशाहों द्वारा जो भवन दिये जाते हैं। उन विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जायेगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बसवा पंचायत है, वहां पर स्वर्गीय हेमंत जैन की पत्नी ने 1995-96 में 2 करोड़ की लागत का भवन, जिसमें 30 कमरे हैं, खेल मैदान है और पानी-बिजली, सबका कनेक्शन है, यह दान में दिया था और उस स्कूल का नाम फिर स्वर्गीय हेमंत जैन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गया था, लेकिन अभी एकीकरण किया गया तो 22 अगस्त, 2014 को उस स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया और भामाशाह का नाम उसमें से हटा दिया जो कि बिलकुल नियम विरुद्ध है और हमारी सरकार ने जो मानक बना रखे हैं उनके विरुद्ध है। इसकी जांच करायी जाए। आज भी स्थिति यह है कि उस स्कूल में 256 बच्चे पढ़ते हैं और आज भी बच्चे उसी स्कूल में, उसी भवन में बैठकर पढ़ते हैं, दूसरे भवन में इतनी जगह ही नहीं है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगी कि इसकी जांच करायें कि किस इंटेंशन से यह

(श्रीमती अलका सिंह)

काम किया गया और पुन: उस भामाशाह द्वारा जो दान दिया गया विद्यालय का भवन है उसका नाम स्वर्गीय हेमंत जैन के नाम से किया जाए।

कालेज शिक्षा के बारे में बताना चाहूंगी। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, थोड़ा सा ध्यान दें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंत्रीजी पधारे थे, वहां राजेश पायलट नाम से उच्च शिक्षा का महाविद्यालय है और उसकी जो भूमि पूजन हुआ था वो अमिताभ बच्चन ने की थी। वह बहुत पुराना महाविद्यालय है और वहां उच्च शिक्षा मंत्रीजी घोषणा करके आये थे। वहां साइंस और हिन्दी विषय एस.एफ.एस., सैल्फ फाइनेंस स्कीम में चलता है, बच्चे खुद फीस देते हैं और उसके बाद वहां शिक्षा खुद के खर्चे पर प्राप्त करते हैं। वहां पर पूरी साइंस की लैब भी है लेकिन अभी तक उसकी घोषणा बजट में नहीं की है, तो मैं थोड़ी सी उच्च शिक्षा मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी कि वहां यह जो एसएफएस में दो सब्जैक्ट चल रहे हैं इनका सरकारीकरण किया जाए।

एक और निवेदन करना चाहूंगी स्कूटी वितरण के बारे में। जो मैरिटोरियस छात्राएं होती हैं उनको देवनारायण योजना के अन्तर्गत भी स्कूटी का वितरण किया जाता है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 83 स्कूटीज, सबसे ज्यादा स्कूटीज राजस्थान में इस बार आई थीं, पिछली बार भी ज्यादा थीं लेकिन हर बार हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि वो स्कूटीज हैडक्वार्टर्स पर आ जाती हैं और वहां से फिर प्रिंसिपल और जो भी अथोरिटी होती है वो उनको तहसील लेवल पर भेजने में आनाकानी करते हैं और हर बार मुझे उच्च शिक्षा मंत्रीजी को फोन करना पड़ता है, इनके अधिकारियों को फोन करना पड़ता है और उसके बाद वो स्कूटीज रिलीज होती हैं। तो क्यों नहीं राज्य सरकार के स्तर पर यह निर्देश दे दिया जाए कि जिस हैडक्वार्टर की, जिस तहसील की वो स्कूटीज हैं उनका वितरण वहीं किया जाए क्योंकि बच्चियों को एक तो आने-जाने में परेशानी होती है और एक मां-बाप ग्रामीण अंचल के लोग हैं, हर जगह पहुंच नहीं सकते तो उनको भी गर्व होगा कि उनकी बच्ची ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतनी अच्छी पढ़ाई की कि उनको इस तरह की स्कूटी मिली है।

एक और निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे यहां पर एक महिला महाविद्यालय संचालित है जो कि स्व-वित्त पोषित है। 2003-04 से यह महिला महाविद्यालय संचालित है और इसमें 600 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। महाविद्यालय का भवन भी है, लाइब्रेरी भी है, जो भी लैब्स वगैरह होती हैं वो

(श्रीमती अलका सिंह)

सब भी हैं और महाविद्यालय के बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपये से ज्यादा भी हैं। वो सब राज्य सरकार को समर्पित करना चाहते हैं ताकि बच्चियों के इस महाविद्यालय का सरकारीकरण हो जाए और ग्रामीण अंचल की बच्चियां कम फीस में सरकारी खर्चे पर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। वैसे भी हमारी सरकार का विजन है बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाना, तो कृपया इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

थोड़ा सा कला और संस्कृति के बारे में बोलना चाहूंगी, अच्छा हुआ मंत्री महोदया आ गईं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत आभानेरी है और यह यूनेस्को के जो प्रोटेक्टेड मान्यूमेंट्स हैं उनमें सम्मिलित है। वहां रोज एक हजार से दो हजार पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक वहां पर बहुत आते हैं, वहां पर जापानी पर्यटक आते हैं और जापानी कई मूवीज की शूटिंग भी वहां पर हुई है लेकिन अभी तक पूर्ववर्ती सरकार ने इस ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया था। हमारी सरकार आने के बाद 52 लाख का काम वहां पर हुआ है। वहां पर पार्किंग बनी है, रोड्स बनी हैं और मैंने मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अन्तर्गत भी उस पंचायत का चयन किया है। लेकिन फिर भी उस मान्यूमेंट की सैंक्टिटी के हिसाब से बहुत पैसा और देने की जरूरत है। मैं पर्यटन मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि अभी जो फण्ड रिलीज हुआ है उसमें आभानेरी के विकास के लिए भी कुछ फण्ड दिया जाए और हमारा जो टूरिज्म कलैण्डर है उसमें आभानेरी को सम्मिलित किया जाए।

एक और पुरातत्व महत्व का स्थान मेरे विधान सभा क्षेत्र में झांझीरामपुरा है। 14वीं शताब्दी के वहां मंदिर हैं और साल में दो बार वहां मेले लगते हैं। उसकी विशेषता यह है कि वहां गौमुख से पानी 365 दिन 24 घंटे आता है और कई लोग स्किन डिजीज ठीक करने के लिए उस जगह पर जाते हैं। दोनों ही जगह, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से झांझीरामपुरा का विकास करने में आप सहयोग करें और फोरेन रेवेन्यू, फोरेन मनी राज्य सरकार में आये और निवेश आये उसके लिए आभानेरी के विकास के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति:** श्री मानसिंह किनसरिया।

**श्री मानसिंह किनसरिया** (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर अपना पक्ष रखना चाहूंगा। माननीय

(श्री मानसिंह किनसरिया)

सभापति महोदय, आजादी के 70 साल बाद भी हम विकसित राष्ट्र तो नहीं बन पाये, साथ ही शिक्षित राष्ट्र भी नहीं बना पाये। शिक्षित राष्ट्र की श्रेणी में भी नहीं आ पाये जबकि हमारा राष्ट्र शिक्षा के मामले में विश्व गुरु कहलाता था जिसके ग्रंथों पर आज भी विश्व में शोध किया जाता है, उन पर चर्चा की जाती है और उनका जो फायदा है उसके बारे में पूरे संसार से शोधकर्ता आते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थान और सरकारी शिक्षण संस्थान में काम्पीटिशन है और सरकारी शिक्षण संस्थाओं को स्कूल लेवल तक कमजोर माना जाता है और यहां के नागरिक उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती कि हम ऐसे विद्यालयों में भेजें जहां पर हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाये। उनकी मन:स्थिति ऐसी रहती है कि निजी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा होती है और सरकारी विद्यालयों में कुछ कमजोर स्तर की शिक्षा होती है। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि हम ऐसी शिक्षण व्यवस्था को हमारे राजस्थान में लायें जिसमें एकरूपता हो, निजी और सरकारी में कोई फर्क नहीं हो। यहां के नागरिक, सब यह तय करें, उनके मन में विश्वास हो कि हम हमारे बच्चों को चाहे सरकारी में भेजें चाहे निजी में भेजें, कहीं पर भेजें, एक समान शिक्षा मिलेगी, एक समान वहां व्यवस्था होगी तभी उन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वो अपने बच्चों को आगे भेज पायेंगे। इसमें अंग्रेजी भाषा और हिन्दी भाषा की भी जो एक खाई है उसको भी पाटना चाहिए कि सरकारी शिक्षण संस्थान में भाषा का जो ज्ञान है वह अंग्रेजी माध्यम भी रहे और हिन्दी माध्यम भी रहे। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है, उस राष्ट्र भाषा का ध्यान रखते हुए हिन्दी का भी समायोजन किया जाए और साथ में उस बच्चे को भाषायी ज्ञान के कारण कहीं उसको इन्फिरियारिटी काम्प्लेक्स में नहीं आना पड़े उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था विद्यालयों में होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है उस ओर भी ध्यान देना होगा। जो निजी विद्यालयों की फीस है, उनकी बुक्स हैं, गाड़ी का है और जो सारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। आज या तो हम ऐसी शिक्षा दें जिसमें कि कहीं कोई फर्क नहीं हो या हमें उसको कंट्रोल करके जो गरीब विद्यार्थी हैं उन लोगों को उसका फायदा मिल सके। हमारी सरकार ने इस ओर प्रयत्न किये भी हैं लेकिन उसमें और

(श्री मानसिंह किनसरिया)

कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे कि गरीब छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में एक ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में खोला गया है। उस विश्वविद्यालय को सात साल हो गये परन्तु आज भी हिन्दी माध्यम शुरू नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम नहीं होने के कारण कई विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अख़बार में आया था। एक शोध विद्यार्थी ने पेपर में प्रश्नों के जवाब हिन्दी माध्यम से लिख दिये तो उसको जीरो मान लिया गया। उसके लिए फिर वापस परीक्षा ली गई और उस छात्र ने अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा दी और उसमें कई शब्द ऐसे थे जिनको उसको रोमन भाषा में लिखना पड़ा। राजस्थान में एक ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम की शुरूआत की चर्चा चल रही है कि वहां हिन्दी माध्यम भी हो लेकिन उसमें अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की हमारी माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने, शिक्षा मंत्रीजी ने, आप लोगों ने, शिक्षा की अलख जगाई थी। माननीय भैरोंसिंहजी ने प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे राजस्थान में एक साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सिफारिश के खोले और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी ने पंचायत हैडक्वार्टर पर सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया और उसके बाद अभी पिछले बजट में इन्होंने माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले तो मेरा मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद। आप लोगों को साधुवाद कि आपने राजस्थान की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य किया है।

शिक्षा मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हमारे सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए उनका प्रमोशन किया। उनको अध्यापक से लैक्चरर बनाया। इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि यह प्रक्रिया कई सालों से रूकी हुई थी। इस प्रक्रिया को आपने आगे बढ़ाया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। आप लोगों ने, मुख्य मंत्रीजी ने अभी बजट में कई महाविद्यालय खोले हैं। वह निश्चित ही सराहनीय

(श्री मानसिंह किनसरिया)

कदम है और एक अच्छी प्रक्रिया है तो मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र में जहां एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। साथ में परबतसर के आस पास 40-50 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है। तो, मेरा आप से निवेदन है कि आप परबतसर में सरकारी महाविद्यालय खोलें।

श्री देवनानीजी से भी मेरा निवेदन है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जहां ग्राम पंचायत में प्राइवेट विद्यालय है, वहां पर आप लोगों ने खोले नहीं हैं। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि कई ऐसे निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, वह इतनी दूरी पर पंचायत हैडक्वार्टर पर नहीं होकर, उस ग्राम पंचायत की सीमा के ऊपर हैं तो उन विद्यालयों में जाने में वहां के बच्चों को भी काफी परेशानी होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा में तीन उच्च माध्यमिक विद्यालय बचे हुए हैं, उनको खोलने की आप अनुशंसा करें।

एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन वहां माध्यमिक विद्यालय नहीं है। वहां आठवीं पास करने के बाद में माध्यमिक विद्यालय तक जाने के लिए उनको 10 किलोमीटर तक आगे जाना पड़ता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक-दो मेरे यहां ऐसे विद्यालय हैं, जिनको भी आप इसमें आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में लें वहां पर माध्यमिक विद्यालय खोलकर।

सभापतिजी, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि लैक्चरर को तो राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से नवाजा जाता है लेकिन जो लैक्चरर महाविद्यालय में हैं, उनको उनसे सीनियर होने के बावजूद भी वह पदनाम नहीं मिलता है, मेरा आपसे निवेदन है, आप लोगों की यह शायद प्रक्रिया में है। शीघ्र ही उनको पदनाम देकर आप उनके सम्मान में यह कार्य करवायें।

ये महाविद्यालय खुले हुए हैं। इनमें 1,500 व्याख्याताओं के और 1,500 नोन-टीचिंग के पद रिक्त हैं। निवेदन है कि वह भी शीघ्र ही भर्ती करवाकर आप लोग उस व्यवस्था को ठीक करें।

एक निवेदन है शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, दो जिलों के बीच एक विश्वविद्यालय खोला जाये। जैसा कि अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के अण्डर में कई महाविद्यालय आते हैं। लेकिन कई विश्वविद्यालय ऐसे खुल गये जो कि खाली एक आफिस में चल रहे हैं, एक कमरे में चल रहे हैं। उनके संघटक कोई

(श्री मानसिंह किनसरिया)

महाविद्यालय नहीं है। तो ऐसे विश्वविद्यालय खोलने के लिए उसमें आप समय पर सावधानी रखें जिससे कि दो जिलों में एक विश्वविद्यालय खुले। उससे संघटक कुछ महाविद्यालय उसके साथ में हो जाये। जैसे निजी महाविद्यालय होते हैं वह उस संघटक विश्वविद्यालय से हो जाये।

अभी उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने शिक्षा के सुधार के लिए बायोमैट्रिक लगाने का, व्याख्याताओं की उपस्थिति को सुनिश्चित किया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि बायोमैट्रिक लगाने से लैक्चरर तो वहां पर मिल जाते हैं लेकिन छात्र नहीं पहुंचते हैं तो ऐसी कोई व्यवस्था की जाये, जिससे छात्र भी क्लास में पहुंचे।

एक मेरा निवेदन है आपसे, यह जो परीक्षाओं का आयोजन होता है, वह छुट्टियों के समय होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जब छुट्टियां हो जाती हैं, उस समय होती है। इसके लिए आप लोगों को एक दिन की तनख्वाह, पी एल अवकाश उनको दिया जाता है। अगर यह परीक्षाएं समय पर हो जायें तो आप लोगों पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ेगा और एक दिन की तनख्वाह पी एल अवकाश के रूप में देनी पड़ती है, वह नहीं देनी पड़ेगी। आपके ऊपर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा में हजारों शिक्षक वीक्षक का कार्य करते हैं और राजस्थान के सभी अन्य विश्वविद्यालयों में वीक्षक कार्य के मानदेय में वृद्धि हो गई है, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय में इनके मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी वृद्धि भी करवायें।

एक प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उसमें सभी विश्वविद्यालयों में विधायकों को सिंडीकेट का मैम्बर बनाया जाये जिससे कि विधायक का भी सम्मान होगा और वहां पर उसकी व्यवस्था में भी सुधार होगा।

मेरा शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि यह जो व्यवसायीकरण हो रहा है, यह रुक जाये और साथ में जैसे बीएड और फार्मासिस्ट, कई ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें विद्यार्थी को महाविद्यालय में जाना नहीं पड़ता और उनको घर बैठे एक मोटी फीस लेकर, पैसा लेकर डिग्रियां दे दी जाती हैं, ऐसी संस्थाओं पर आप

(श्री मानसिंह किनसरिया)

लगाम कसें, उनको नियंत्रित करें। यह मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री अजीत सिंह।

**श्री अजीत सिंह** (टोंक): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है। यह बात जरूर है कि उसके परिणाम आने में समय लगता है लेकिन हम देखते हैं कि 69 सालों की आजादी के बावजूद भी शिक्षा, चिकित्सा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी आज हम लोग वंचित हैं। आज उसके लिए भी हमको मांग और डिमांड के माध्यम से अपने विचार रखने पड़ रहे हैं। यह दुर्भाग्य रहा इस देश का कि 50-55 वर्षों तक इस देश के अन्दर कांग्रेस ने शासन किया।

मैं प्रतिपक्ष के मेरे बड़े भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर कम से कम अपने अच्छे सुझाव दें उस पर कोई राजनीति करने का प्रयास नहीं करें। यह मेरा उनसे विनम्र निवेदन है क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है क्योंकि शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिससे हम राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। मैं आज देखता हूं कि राजस्थान के परिवेश के अन्दर दुर्भाग्य से कांग्रेस के शासन में आठवीं तक बच्चा परीक्षा दे और उसका परिणाम पास ही होता था। यह हमारी शिक्षा पद्धति का दुर्भाग्य ही रहा होगा कि अगर ऐसा निर्णय करने से पहले उनके मन में विचार भी नहीं आया था कि हमने एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय इस प्रदेश के अन्दर लिया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी का और शिक्षा मंत्रीजी का जिन्होंने राजस्थान के शिक्षा के पैटर्न को पुन: परिवर्तन करने का प्रयास किया और मुझे गर्व भी है कि राजस्थान के अन्दर आज सरकारी विद्यालयों में आठ लाख का नामांकन बढ़ा है। जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय बारह लाख की नामांकन में कमी आई थी।

मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पांच हजार माध्यमिक विद्यालयों को, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जब सुराज संकल्प यात्रा में गांव का दौरा किया था 13 हजार 500

(श्री अजीत सिंह)

किलोमीटर का, राजस्थान का भ्रमण किया था, शिक्षा की जो हालत देखी, गांव के विद्यालयों की स्थिति देखी थी उन्होंने उसके बाद एक साथ पांच हजार माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। यह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी की बहुत बड़ी घोषणा इस प्रदेश के लिए है। आप देखिए, विद्यालयों में शौचालय का मामला, समायोजन का मामला हमारी सरकार के टाइम पर हुआ। नि:शुल्क साइकिल वितरण का मामला हो, चाहे लैपटाप वितरण का मामला हो, चाहे राजश्री योजना हो, ये सब योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी की देन हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टोंक जिला मुख्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नम्बर-12 जो छावनी पर है वहां सन् 1981 से विद्यालय चल रहा है। आज यह विद्यालय जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र रहते हैं उसमें छात्र और छात्राओं की संख्या ज्यादा है। इस विद्यालय में कला एवं विज्ञान विषय स्वीकृत है। विद्यालय भवन में पांच कमरों पर तो पुलिस विभाग का ताला लगा हुआ है और एक में डिस्पेंसरी खोल दी गई है। इसका भवन जीर्ण-शीर्ण भी है और इस विद्यालय के अन्दर बच्चे टीन-शेड के अन्दर पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि मैंने मेरे विधायक कोष से उसके अन्दर दस लाख रुपये भी दिए हैं लेकिन उसके बावजूद भी उस विद्यालय की पूर्ति नहीं हो सकती। चारदीवारी नहीं है, उसमें काफी गंदगी भी है और कांग्रेस के शासन में उस वक्त वहां पर उर्दू और भूगोल शुरू की गई थी लेकिन आज दुर्भाग्य से उस विद्यालय के अन्दर उर्दू विषय पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं। तो मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है, मैंने आपको एक दो बार पत्र भी लिखा है कि इस विद्यालय में उर्दू विषय में छात्र-छात्राओं की न्यूनतम संख्या होने के कारण उर्दू के विषय को समाप्त करके इसके स्थान पर हिन्दी एवं संस्कृत ऐच्छिक विषय खोला जाना आवश्यक है तथा पांच कमरों को पुलिस विभाग से मुक्त कराकर शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने की कृपा करेंगे ऐसा मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है।

(श्री अजीत सिंह)

एक माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि टोंक जिले सहित कई जिलों में 25 वर्षो में विद्यालयों की संख्या तीन गुनी हो गई है। किन्तु जिला शिक्षा अधिकारी के पदों की बढ़ोतरी नहीं की गई है इससे निरीक्षण व्यवस्था चौपट हो गई है। यह मेरा विशेषकर निवेदन है, इस ओर आप ध्यान देंगे। सरकार द्वारा आईसीटी योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई है किन्तु पूर्णकालिक कंप्यूटर शिक्षकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण नहीं हो रहा है इसलिए सभी विद्यालयों में पूर्णकालिक कम्प्यूटर शिक्षक लगा ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा यू-डाइस (U-DISE) डाटा के आधार निर्माण कार्य स्वीकार किए जा रहे हैं। किन्तु पूर्ण जानकारी के अभाव में शिक्षकों द्वारा यू-डाइस (U-DISE) सही नहीं भरी जा रही है जिसके कारण निर्माण कार्य ज्यादा आवश्यक वाले विद्यालयों में स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र टोंक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सौराण, हरचन्दला, चन्दलाई, चिरोंद, गोपालपुरा, खोवाड़ाखुर्द आदि में विद्यार्थी खुले में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, 25 प्रतिशत निर्माण के कार्य विशेष आवश्यकता वाले विद्यालयों में करने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया जाए ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

राज्य सरकार विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कम्प्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लास एवं ई-लर्निंग जैसी योजनाएं चलाकर महंगे उपकरण उपलब्ध करा रही है जिनकी विद्यालय से रोजाना चोरी हो रही है। जहां राजकीय विद्यालयों में सहायक कर्मचारियों के बहुत कम पद स्वीकृत हैं उनमें से अधिकांश रिक्त विद्यालयों के सहायक कर्मचारियों के पद नियमित भर्ती होने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी से भरे जाने चाहिए ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में एक विद्यालय को तीन चरणों में आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा की है किन्तु इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। विद्यालयों द्वारा अपने संसाधनों एवं भामाशाहों की मदद से योजना को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है किन्तु विद्यालय पूरी तरह आदर्श विद्यालयों के मानदण्ड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है। प्रारम्भिक शिक्षा में कई शिक्षक कई वर्षो से अनुपस्थित चल रहे हैं तथा उन्हें वेतन का भुगतान किया गया है। ऐसे शिक्षकों व अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। टोंक जिले में ऐसे कई शिक्षक हैं। टोंक जिले के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जांच के नाम पर लीपापोती की जा

(श्री अजीत सिंह)

रही है। अल्पसंख्यक छात्रवृति में केवल वर्ष 2012-13 की जांच की जा रही है जबकि वर्ष 2011-12 में इसका मुख्य आधार रहा है तथा भ्रष्टाचार के मूल सूत्रधार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी वर्ष 2011-12 की जांच कराई जाए। गत वर्ष खोले गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दूर दराज के क्षेत्रों में विज्ञान संकाय खोले गए हैं जहां छात्रों ने...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले से ही इस आसन से व्यवस्था दी हुई है कि माननीय मंत्रीगण के लिए विधान सभा परिसर में चैम्बर हैं। चार मंत्री इधर बात कर रहे हैं, एक मंत्रीजी उधर तीन माननीय सदस्यों से बात कर रहे हैं तो जब सदन के प्रति गम्भीर ही नहीं है मंत्रीगण ही तो फिर माननीय सदस्यों का तो कहना ही क्या है?

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, कोई भी मंत्री बात नहीं कह रहा है। जिनकी आज मांगे हैं वे बिलकुल शांति से अक्षरशः अध्ययन और मनन कर रहे हैं और आप जबरदस्ती में यूं ही बातें कर रहे हैं। कहां बातें कर रहे हैं?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): आदरणीय, ये व्यवस्था का प्रश्न कौन से नियम में हैं? आपने यह व्यवस्था का प्रश्न इस बुक में से कौन से नियम में उठाया है यह बता दें कृपया?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह राठौड़ साहब पूछेंगे तब बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): राठौड़ साहब नहीं, मैं पूछ रहा हूं कौनसी व्यवस्था में है?

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): इसका मतलब आप कोई नियम में नहीं बोल रहे हैं। आप राठौड़ी में बोल रहे हैं, यूं ही राठौड़ी कर रहे हैं?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इस हरी किताब में नियम है और यहां से परम्परा दी हुई है। यहां से अध्यक्षीय परम्परा दी हुई है आप कहें तो पढ़कर के सुना देता हूं कि माननीय मंत्रीगण को चैम्बर मिले हुए हैं कृपया सदन में बात नहीं करेंगे, चैम्बरों में बात करेंगे।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आप पढ़कर के कहां सुना रहे हैं आप तो कह रहे हो राठौड़ साहब को बताऊंगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप राठौड़ी कर रहे हैं?

**श्री सभापतिः** आप बैठिये, आप बैठिये।

**श्री अजीत सिंह** (टोंक): गत वर्ष खोले गए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दूरदराज के क्षेत्रों में विज्ञान संकाय खोले गए थे जहां छात्रों की संख्या नहीं थी। प्रवेश में रुचि नहीं ली, इसके स्थान पर क़स्बों में स्थित पुराने विद्यालयों में विज्ञान संकाय के अतिरिक्त विषय खोले जाने चाहिए ऐसा मेरा मंत्रीजी से निवेदन है। टोंक जिले सहित सभी जिलों में जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विद्यार्थी सहायता केन्द्र स्थापित नहीं है वहां प्रारम्भ किया जाए ऐसा मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सत्रांक योजना का दुरुपयोग करते हुए कई गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 30 से 35 आयु वर्ग के लोगों को नियमित अध्ययनरत बता कर परीक्षा में सम्मिलित कराया जा रहा है जिस पर बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। या तो सत्रांक योजना पर रोक लगाई जाए या फिर इसका दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। अब मेरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक में जीव विज्ञान एवं संस्कृत के विषय नहीं है जिसमें छात्र व छात्राओं को इन विषयों में अध्ययन हेतु अन्य दूरस्थ ज़िलों में जाता पड़ता है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं संस्कृत विषय खोलने की आज घोषणा करें। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में वर्ष 1995 से चल रहा है। इस ओर कभी भी कांग्रेस की सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। वर्तमान में इस कन्या महाविद्यालय में 600 छात्राएं अध्ययनरत हैं। टोंक जिले का एकमात्र महाविद्यालय होने के कारण विज्ञान संकाय नहीं होने के कारण विज्ञान विषय पढ़ने के लिए छात्राओं को अन्य जिलों में जाकर अध्ययन करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस इकलौते कन्या महाविद्यालय में आज ही विज्ञान विषय खोलने तथा इसे पीजी कालेज में क्रमोन्नत करने की घोषणा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, जय हिन्द।

**श्री सभापतिः** श्री भंवर सिंह (अनुपस्थित), श्री धीरज गुर्जर।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने शिक्षा पर मुझे बोलने का मौका दिया और जो परम्परा चली आ रही है...

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, पांच पर एक था।

**श्री सभापति**: बैठिये, बैठिये आप।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपके कोई बोलने वाला तो है नहीं, खड़े हो जाते हो पांच एक का है। कोई बोलते ही नहीं है सारे पढ़-पढ़कर के बोल रहे हैं। शिक्षा पर बहस है और सारा सदन खाली पड़ा है। फिर खड़े हो जाते हो, कोई बोलने वाला है तो उनको बोलने दो।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): हां, साहब शुरू करूं। व्यवस्था के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हो तो मैं अपनी बात कहूं। मैं भी शुरू करता हूं इस परम्परा के साथ कि मैं शिक्षा मंत्री पर इल्जाम लगाऊं कि राजस्थान में आपके शिक्षा मंत्री बनने के बाद में 788 स्कूलें भवन विहीन हैं।

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): बच्चों को पढ़ाना है आपको ... (व्यवधान)

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): राठौड़ साहब, आप सुन लो। (व्यवधान) नाम राठौड़ होने से ही आप राठौड़ी मत करो। राठौड़ी करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): उसमें आप माहिर हैं।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): फिर मैं इल्जाम लगाऊं कि शिक्षा मंत्री जी आपके होते हुए हमारे राजस्थान के हजारों स्कूलों में भवनों की बाउंड्रियां नहीं बनी हैं फिर हां पक्ष से आवाज आएगी कि हम क्या करें हमने तो राजस्थान में दस-पन्द्रह साल ही राज किया है, पचास साल आपने राज किया, आप लोगों ने क्या किया। फिर मैं आप पर इल्जाम लगाऊं कि आपने एकीकरण किया, आपने समानीकरण किया, आपने विद्यार्थी मित्रों को धोखा दिया, आपने पैराटीचर्स को धोखा दिया, फिर उधर से आवाज आएगी और उसके बाद मैं आपकी आलोचना और आप मेरी आलोचना। शिक्षा पर हमारी बहस खतम हो जाएगी। मेरी पार्टी मेरी पीठ थपथपा देगी। आपकी पार्टी मेरा विरोध करने वालों की पीठ थपथपा देगी।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

**श्री सभापतिः** क्या सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाए?

**(स्वीकृत)**

सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाता है।

# अनुदान की मांग

# मांग संख्या 24 पर विचार

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): फिर क्या इससे हम नये राजस्थान का निर्माण कर देंगे? क्या विधान सभा के अन्दर हम सब इसलिए आते हैं, राजस्थान के साढ़े सात करोड़ लोग हमें इसलिए चुन कर भेजते हैं कि हम आप पर आरोप लगायें और आप हम पर आरोप लगायें। ऐसे समय में हम यह भूल जाते हैं कि बिना शिक्षा के हमारा समाज उसी तरह से है जिस तरह से बिना प्राण का शरीर। समाज की सभ्यता के लिए, समाज के निर्माण के लिए शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और संस्कारमय होनी चाहिए और इस शिक्षा में जब तक हम भगवा और हरे की बात करते रहेंगे और तिरंगे को भूल जाएंगे, जब हम देशभक्ति को भूल जाएंगे, जब हम भारत माता को भूल जाएंगे और हम अपने-अपने धर्म की बात करेंगे तो वह शिक्षा कभी एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर पाएगी जिस पर चल कर हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बने।

मैं आपके सामने आज बात रखना चाहता हूं और इस विश्वास से रखना चाहता हूं कि हमें इस सदन में इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि राजस्थान में जो भी सरकारें रहीं उन्होंने 72500 स्कूलों का निर्माण किया। हमें इस सदन में हमारे वरिष्ठ सदस्यों को जो इस सदन में हैं या नहीं हैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए दोनों पार्टी के लोगों को कि राजस्थान में सवा तीन लाख अध्यापक लगाकर एक संरचना खड़ी करने का प्रयास किया, लेकिन हमें शर्मिंदा इसलिए भी होना चाहिए कि राजस्थान में कई पार्टियों की सरकारें रह गईं, कई आदमियों का भला हो गया, लेकिन आज भी हमारी बालिकाओं के लिए स्कूलों में शौचालय अलग से नहीं बने हुए हैं। हमें मिल कर इस बारे में चिन्तन करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात कि यह भवन बनने से, बिजली के तार हटने से, बाउंड्रीवाल बनने से या स्कूल में अध्यापक मात्र होने से हमारा भला नहीं हो सकता। हमारा भला तब होगा जब ये लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति अंग्रेज इस देश में छोड़ कर गये जिनके कारण बच्चा अपने हाथ में किताब लेकर स्कूल जाता है आज तो स्थितियां फिर भी बदल गयीं

(श्री धीरज गुर्जर)

लेकिन जिस समय हम स्कूल में जाते थे, उस समय हमारे माता-पिता सोचते थे कि हमारा बेटा स्कूल जा रहा है फिर जब वो किसान का बेटा कालेज में आता था तो मां-बाप के मन में एक सपना रहता था कि मेरा बेटा जब कालेज से बाहर आयेगा तो उसकी नौकरी लग जायेगी। उनको यह पता नहीं कि इस शिक्षा पद्धति में बीए पास एमए पास आदमी भी फोर्थ क्लास चपरासी बनने के लिए तरसता है फिर भी उसका उस शिक्षा पद्धति से भला नहीं हो सकता।

जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगारोन्मुखी नहीं होगी, जब तक स्कूलों में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि बच्चे को वहां पर पढ़ाई के साथ-साथ ऐसा सिखाया जाए जिसमें सिर्फ किताबी ज्ञान हमारा आधार नहीं हो, बल्कि उसमें हमारा आधार हो कि जब वो कालेज से या स्कूल से बाहर निकले तो अगर वो पढ़ाई नहीं भी करना चाहे विषम परिस्थितियों के कारण तो उसके हाथ में रोजगार हो। उसके पास ऐसी स्किल्ड डवलपमेंट की व्यवस्था हमको स्कूल से ही करनी पड़ेगी कि वो कालेज पास करने के बाद में आये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है कि हम इस बात का निर्णय करें कि समाज के अन्दर सबसे ज्यादा आने वाली पीढ़ी में इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि पढ़-लिख कर आदमी डाक्टर बन गया, पढ़-लिख कर आदमी नेता बन गया, पढ़-लिख कर आदमी अधिकारी बन गया, समाज में फर्क इस बात का पड़ता है कि आदमी स्कूल से क्या सीख कर आया है। क्या वह एक अच्छा नागरिक बना। क्या वह एक अच्छा हिन्दुस्तानी बना, क्या वह एक अच्छा भारतीय बना। अगर वह हिन्दू, मुसलमान, सिख और इसाई के अन्दर उलझा रह जाएगा तो वह एक जाति का अच्छा आदमी तो बन सकता है लेकिन वह एक अच्छा हिन्दुस्तानी, एक अच्छा भारतीय, एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकता और जब तक हमारी शिक्षा में ये बात हम शामिल नहीं करेंगे कि आदमी हिन्दू और मुसलमान बनने से पहले एक अच्छा हिन्दुस्तानी बने। उसको भारत माता की जय लगाने में गर्व महसूस हो तो तब तक हम अपनी शिक्षा को किसी कीमत पर पास नहीं कर सकते। इस सदन में खड़े होकर मैं मांग करता हूं कि हमें इस बारे में प्रयास करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या हम आज एक संकल्प करने के लिए तैयार हैं, आज राजस्थान में स्कूल की दशा हमने देखी है क्या?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): एक निवेदन था। आपको तो उधर से हट कर इधर ज्वाइन करके यह भाषण देना चाहिए था तब बहुत अच्छा लगता।

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): इधर से ही संस्कारित हुआ है यह व्यक्तित्व। संस्कार इधर के लिए और उधर जाकर के भूमिका बना रहे हैं।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): एक बात बताइये जोगारामजी, जिस पार्टी ने माननीय सदस्य...

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आप देखो पीहर में संस्कार ले गये और ससुराल में जाकर प्रकट कर रहे हो, यह अच्छी बात है करो आप।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): फिर भी आपके मंत्री हमारे घर-परिवार के पीछे पड़ रहे हैं कि कैसे इनको नेस्तनाबूद कर दें। (व्यवधान) तो मैं आपको यह कह रहा था माननीय सदस्य, जिस पार्टी के महात्मा गांधी ने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया हो, जिस पार्टी ने इस हिन्दुस्तान के तिरंगे झंडे का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभायी हो, जिस पार्टी ने इस देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए अपने हजारों-सैकड़ों आदमियों के प्राण दिये हों, उस पार्टी में अगर देशभक्त नहीं रहेंगे तो क्या बेइमान रहेंगे क्या? आपको तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज इस विषय पर बात नहीं करना चाहता।

मैं आज आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूं कि क्या हम इस बात का संकल्प इस सदन में पारित करने की मन:स्थिति में हैं कि आज हम हाथ खड़े करके निर्णय लेवें और यह देवनानी साहब, आप करवा सकते हो कि राजस्थान के किसी भी आईएएस का, राजस्थान के किसी भी आईपीएस का, राजस्थान के किसी भी अधिकारी का, राजस्थान के किसी भी विधायक का और राजस्थान के किसी भी सांसद का और खास कर के जो स्कूलों में अध्यापक लगे हुए हैं इनके बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे न कि निजी स्कूलों में पढ़ें। हमारा दुर्भाग्य देखो आप कि जिस व्यवस्था के अन्दर हमारा सरकारी अध्यापक खुद पढ़ाता है वह अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में नहीं कराता। इससे ज्यादा हमारी शिक्षा व्यवस्था पर और हमारी शिक्षा प्रणाली पर कोई सवालिया निशान करने वाली कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए हम निर्णय लें। यह सिर्फ आदर्शों की बात नहीं है जब इस चीज को आप गहराई से महसूस करेंगे तब आपको अहसास होगा और मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि धीरज गुर्जर जब भीलवाड़ा की कालेज में गया था तो मुझसे दस साल

(श्री धीरज गुर्जर)

पहले मेरे समाज का कोई आदमी कालेज के अन्दर नहीं पहुंच पाया था। इसलिए मुझे पता है कि शिक्षा का जीवन में कितना वजूद होता है, शिक्षा का जीवन में क्या महत्व होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं हिन्दुस्तान नहीं राजस्थान की ही बात करूं कि राजस्थान में अगर शिक्षा का और स्कूलों का स्तर हम सुधारना चाहते हैं हमारी मानसिकता है तो हमें नियम बनाना पड़ेगा कि चाहे आईएएस, आईपीएस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो उसका बेटा जिस दिन राजस्थान की सरकारी स्कूल में पढ़ने-लिखने चला जाएगा उस दिन स्कूलों का भविष्य निर्माण नये सिरे से हो जाएगा और राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली भी बदल जाएगी। मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं इस सदन में खड़े होकर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों हम एक निर्णय नहीं लेते कि राजस्थान का हर विधायक अपने-अपने क्षेत्र में सबसे पिछड़ी हुई स्कूल को गोद लेगा। मेरी इच्छा थी, मैंने बीईओ से बात भी की लेकिन बीईओ फोन उठाते हुए डरता है, वो देखता है कि मेरे से एमएलए साहब ने बात कर ली तो इस राज में मेरा तबादला हो जाएगा। शिक्षा में आदमी को यहां लाने के लिए राजनीतिकरण होना चाहिए लेकिन भगाने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि हमें एक निर्णय पारित करना चाहिए कि राजस्थान का हर विधायक अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की सबसे पिछड़ी हुई स्कूल को गोद लेगा और एक सब्जैक्ट तय करेंगे कि फलां विधायक इस सब्जैक्ट में पढ़ायेगा और उसके बाद में हम कम से कम महीने में एक बार उस स्कूल में जाएं और हम अपने हाथ से वहां पर पाठ पढ़ायें और उसके बाद में जब वह परीक्षा पेपर तैयार होता है लोकल लेवल पर तब हमें पता लगेगा कि हमने जिन बच्चों को खड़ा रह कर पढ़ाया, तब हम एक शिक्षक की गरिमा को भी समझ जाएंगे, शिक्षक की मन:स्थिति को भी समझ जाएंगे और उस स्कूल में भी अगर हम जाएंगे तो उस स्कूल का भी भला हो जाएगा वो स्कूल भी आगे बढ़ जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि बिना स्वस्थ शरीर के स्वस्थ भारत का निर्माण नहीं हो सकता। मिड-डे मील योजना हमने लागू की। हममें से कितने आदमी, यह दुर्भाग्य है, ... (व्यवधान) घूघरी मान लो, मिड-डे मील मान लो, हमने का मतलब इस सदन ने की। पिछली बार भी जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा था कि इस सदन को हां पक्ष और ना पक्ष में बांट कर हम लोगों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। हिन्दुस्तान का अगर भविष्य सुधारना है तो इस सिम्बोलिक प्रक्रिया से

(श्री धीरज गुर्जर)

चुनाव होना बंद हो जाए, जिस दिन डाइरेक्ट चुनाव शुरू हो जाएंगे न उस दिन सदन की सार्थकता इस देश में सामने आ जाएगी। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमने का मतलब इस सदन ने, मैं तो पहली बार का एमएलए हूं मेरा अनुभव भी राजनीति में ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिड-डे मील योजना को कितनी बार चैक करने के लिए हम लोग गये और हम जाते हैं तो पहले सूचना कर देता है बीईओ स्कूल में कि आज मंत्रीजी फलां स्कूल चैक करेंगे तो वहां तो टकाटक खाना मिलना ही मिलना है। जब एमएलए किसी स्कूल में जाता है तो पहले फोन कर देता है तो वहां जायेगा तो उसको खाना अच्छा मिलना ही मिलना है। हमें इस बात का निर्णय करना चाहिए

(17.00 बजे)

कि महीने में एक बार किसी भी एक स्कूल में एक हफ्ते में बीडीओ, एक हफ्ते में तहसीलदार, एक हफ्ते में एसडीएम और एक हफ्ते में विधायक, चार सप्ताह में किसी भी दिन किसी भी वक्त औचक जाकर अपने साथ बीईओ को ले जाय लेकिन इसके लिये हमें मन:स्थिति मजबूत करनी पडेगी। मैं अगर यह करना भी चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसफर का डर इन अध्यापकों को सताता है, सबसे ज्यादा डर इन बीईओ को रहता है। शिक्षा मंत्रीजी, अगर आप हिम्मत करके एक नियम पारित कर दें कि एमएलए चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वह बीईओ को अपने साथ लेकर अचानक किसी स्कूल में जाये और उन बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील खाये, मिड डे मील चैक करे तो आपकी यह सारी प्रणाली जिसमें केन्द्र सरकार बच्चों को अच्छा पोषण देना चाहती है, वह व्यवस्था सुधर जायेगी। मैं आपसे मांग करता हूं कि हफ्ते में चार बार यह अधिकारी जायेंगे। एक बार कलक्टर जायेगा, एक बार एसपी जायेगा तो निश्चित रूप से इस सारे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन आयेगा। लेकिन दु:ख तब होता है, मुझे पता है कि यह हमारे साथ जायेंगे नहीं। इसलिए मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी आपको इसमें कुछ कदम उठाना चाहिये।

हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, आप नियम निर्धारित कर दीजिए कि प्रत्येक विधायक का कम से कम 10 लाख रुपये छात्राओं के शौचालय स्कूल में अलग बनें, इस बात पर खर्च करना होगा, क्योंकि अगर हम अपनी बेटी की इज्जत को नहीं सम्भाल सकते तो फिर कोई दूसरा आदमी आकर हमारी बच्ची की इज्जत को बचाने वाला नहीं है। उसके साथ हमें एक निर्णय

(श्री धीरज गुर्जर)

ओर लागू करना पड़ेगा आज स्कूल यूनिफार्म, यह बच्चों के जीवन में फांसी लगती है, लेकिन आपको एक निर्णय लेना चाहिये कि पूरे राजस्थान में एक ही तरह की, दो तरह की यूनिफार्म लागू होगी। एक सरकारी स्कूल का बच्चा, एक निजी स्कूल का बच्चा। निजी स्कूलों में कभी चैक्स वाली शर्ट, कभी महंगी शर्ट, कभी हजार रुपये की शर्ट, कभी पांच हजार रुपये की ड्रेस और सरकारी स्कूलों में अलग तरह की ड्रेस। एक पैमाना निश्चित कर दीजिए कम से कम अभिभावकों और बच्चों का, क्योंकि स्कूल यूनिफार्म एहसास कराती है कि हम सब एक हैं। न हिन्दू, न मुसलमान, न अमीर, न गरीब, न रंक, न राजा, सबके बेटे जब एक जैसी ड्रेस पहनकर एक जैसी व्यवस्था में स्कूल में जाकर बैठेंगे तो कम से कम उस छोटे बच्चे के मन में कभी यह नहीं आ पायेगा कि मेरा बाप गरीब है, मेरा बाप खेत में खेती करता है और इसका बाप अमीर है, इसका बाप गाडी में चलता है। यह स्कूल कहने में बहुत मुश्किल लगती है लेकिन यह अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें समानता का, एक हिन्दुस्तान का, एक भारत का, श्रेष्ठ भारत का सपना दिखाती है। इसलिए मैं आपसे इस सदन में मांग करना चाहता हूं।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। आज स्कूलों में छठी का बच्चा, आठवीं की बच्चा, नवीं का बच्चा और दसवीं का बच्चा मोबाइल लेकर जाता है। उसमें तरह-तरह की जैसी आजकल संस्कृति फैल रही है, कई बच्चे छोटी उम्र में भटक जाते हैं, गलत राह पर चले जाते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में प्रतिबंध लागू हो कि मैं तो बारहवीं की मांग कर रहा हूं, लेकिन बारहवीं में बच्चे कहते हैं मां-बाप बाहर पढ़ने लिखने भेजते हैं, लेकिन कम से कम दसवीं तक के बच्चे और बच्ची को स्कूल में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध होना चाहिये। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिये जो स्कूल में मोबाइल ले जाये। इनको रोकने वाला कौन, अध्यापक। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अध्यापक भी आजकल फेसबुक और व्हाटसएप की बीमारी से ऐसे ग्रसित हो गये कि बच्चा क्लास में घूमता फिरता है और उनको मोबाइल पर व्हाटसएप डाउनलोड करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। यह नियम बच्चों पर भी लागू हो और इन अध्यापकों पर भी लागू हो कि अगर स्कूल में कोई थ्री जी मोबाइल का उपयोग करके फेस बुक और व्हाटसएप चलायेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

(श्री धीरज गुर्जर)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज एसडीएमसी का स्तर गिरा है। एसडीएमसी में पहले विधायकों के मैम्बर होते थे, उस व्यवस्था को हमने भंग कर दिया। आप एसडीएमसी में विधायक के मैम्बर रखिए, छात्रों के अभिभावक को मैम्बर बनाइए और यह नियम बनाइए, आज प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे के मां बाप को बुलाते हैं तो किसी भी स्थिति में वह हो निजी स्कूल में उस बच्चे के माता-पिता जाते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है, जिस स्थिति में उनका बच्चा रहता है, कोई भी आदमी जाकर अपने बच्चे की स्कूल को देखने की जहमत गवारा नहीं करता। यह नियम लागू होना चाहिये कि आपको कम से कम हर छह महीने में शिक्षा विभाग में उस स्कूल की मीटिंग हो। एसडीएमसी स्कूल और वहां का स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंच हो, सीआर हो, डीआर हो और उस स्कूल में आने वाले बच्चे के मां-बाप जिस दिन वह स्कूल में जाकर बैठेंगे, जिस दिन वह अपने बच्चों को देखेंगे, जिस दिन वह अपने बच्चे की हालत पर निगाह रखेंगे उस दिन निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस स्कूल का सिस्टम बदल जायेगा।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से निजी स्कूलों में हम एक चीज को भूल गये, राजस्थान में निजी स्कूल कुकुरमुत्ते की तरह फैल रही हैं। हम कहते हैं कि सरकारी स्कूल का हमारा भवन नहीं बना। हम कहते हैं कि सरकारी स्कूल की हमारी बाउंड्री नहीं। राजस्थान में शहरों को आप छोड़ दीजिए 90 प्रतिशत गांवों में जो निजी स्कूलें हैं वह सब स्कूलें आपकी सरकारी स्कूल से छोटी बिल्डिंग में चल रही है। राजस्थान में जितने लोग अध्यापक बनते हैं, वह बैस्ट होता है उसका सरकारी नौकरी में नंबर आता है जो रिजैक्ट हो जाता है वह प्राइवेट स्कूल में पढा रहा है। ऐसे कितने आदमी हैं जो सरकारी स्कूल से जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हैं। जिसका सरकारी स्कूल में नंबर नहीं आया वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं और निजी स्कूल में सिर्फ इसलिए भेजते हैं क्योंकि इनके दिखावे में, उनकी यूनिफार्म के झटके में, उनकी अंग्रेजी किताबों के सिलेबस के चक्कर के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि कैसे बच्चे को सरकारी स्कूल में

(श्री धीरज गुर्जर)

लाया जाये और कैसे उसके माता-पिता को उस स्कूल तक लाया जाये। तब जाकर जब सामाजिक जागरूकता आयेगी तब हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ पायेगा।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं हर स्कूल में एक शिकायत पेटी लगवाइये और स्कूल में अनाउंस करवाइये कि आप बिना नाम लिखे उस पेटी में, एक जमाना था तब पहले कहते थे कि मास्टर जी घर से छाछ मंगा रहे हैं, मास्टर जी घर से मक्का मंगा रहे हैं। आज जमाना बदल गया है, आज कई स्कूलों में हम सुनते हैं कि लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार हो गया। हम कई स्कूलों में सुनते हैं कि अध्यापक पढ़ाता नहीं है। या तो कभी राजनीतिक संरक्षण के कारण, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूर करते हैं यह सब जानते हैं कि कांग्रेस के राज में धीरज गुर्जर का कार्यकर्ता कौन है उसके घर पर पहुंच जायेंगे, उसको चाय पिलायेंगे, उसको घुमायेंगे, उसका कोई काम होगा तो कर देंगे। बीजेपी के राज में देख लेंगे कि मदनजी राठौड़ के मिलने वाला कौन है, उसके घर पहुंच जायेंगे। उसको चाय पिलायेंगे, उसको मोटर साइकिल पर घुमायेंगे तो वह कार्यकर्ता दवाब बनाकर इनकी मनमर्जी से काम करायेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिकायत पेटी प्रत्येक स्कूल में हो और उसमें यह हो कि कौन अध्यापक आपको पढ़ाता है, कौन अध्यापक आपको नहीं पढ़ाता है। कौन स्कूल समय पर आता है, कौन स्कूल समय पर नहीं आता है। बच्चे को इतनी पावर हो कि अपना नाम लिखे बिना, क्योंकि मैंने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि शिकायतकर्ता की जांच वही करता है जिसके खिलाफ शिकायत होती है। अगर बच्चा अपना नाम लिख कर बीईओ को देगा तो बीईओ उसके नोडल को देगा और नोडल स्कूल के मास्टर को देगा और स्कूल का मास्टर उस बच्चे का स्कूल में इलाज कर देगा। इसलिए शिकायतकर्ता का नाम उस कागज में नहीं होना चाहिये और उसकी अलग से बीईओ स्तर पर या जिला स्तर पर उस शिकायतपेटी को इकट्ठा करके जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी छंटनी करके जांच होने लग जायेगी तो निश्चित रूप से कई ऐसी बातें हमारे पकड़ में आयेंगी जिनको हमें पकड़ना चाहिये।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी हो गई। हमने एक सिस्टम बना लिया, मैंने रोज़गारोन्मुखी शिक्षा की बात की थी लेकिन सोच क्या बना ली कि हम बच्चे को ट्रेनिंग देंगे स्किल डवलपमेंट करेंगे

(श्री धीरज गुर्जर)
तो स्किल डवलपमेंट में क्या होगा कि मोची का बेटा मोची बन जायेगा, किसान का बेटा किसान बन जायेगा, दूधिया का बेटा दूधिया बन जायेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई बन जायेगा। क्यों? आप नहीं चाहते कि गरीब का बेटा डाक्टर बने? आप नहीं चाहते गरीब का बेटा कलक्टर बने? जिस तरह से राम राज में, जिस राम राज की हम और आप बात करते हैं उस राम राज में एक सिस्टम था कि जो उस क्षेत्र का गरीब आदमी होता था उसका जो श्रेष्ठ होता था, होनहार होता था, उसको सरकारें गोद लेती थी और सरकारें गोद लेकर गुरुकुल में रखती थीं राजा के बेटे के साथ में और उस गुरुकुल में उस गरीब का बेटा, बिलकुल चतुर्थ श्रेणी आदमी का बेटा अगर वह श्रेष्ठ होता था तो राजा के बेटे के साथ शिक्षा प्राप्त करता था। क्या हम एक ऐसे राजस्थान की कल्पना नहीं कर सकते कि पूरे स्टेट में जो बीपीएल के आदमी हैं, जो बिलकुल निम्न दर्जे की तनख्वाह वाले आदमी हैं उनके बच्चों की एक प्रतियोगी परीक्षा कराये और उनमें जो बच्चे श्रेष्ठ हो सरकार उनको गोद लें और सरकार अपने खर्चे पर उनको डाक्टर बनाये, उनकी कोचिंग करवाये, उनको अपने पास रखें, कलक्टर बनाये, उस दिन राजस्थान में गरीब के बेटे नौकरी पर लगेंगे और जिस दिन गरीब का बेटा ऐसी कुर्सी पर बैठ जायेगा और कुर्सी पर बैठकर नीतियों का निर्धारण करे उस दिन सच्चे मायने में इस देश में और इस राजस्थान में राम राज आ जायेगा।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): डोटासराजी, अब आपके पद को खतरा हो गया है, धीरजजी बहुत बढिया बोलने लगे हैं, अब चीफ व्हिप वह बनेंगे, आप ऐसे ही रहोगे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपके समझ में ही नहीं आई यह बात, क्या बोल रहे हैं। समझ में आ जाये तब बता देना, उत्तर दे दूंगा।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): साथ ही रहने वाले हैं, सब समझते हैं। आपको समझा रहे हैं वह समझ लो।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): कालूलालजी, राजस्थान कांग्रेस का सचिन पायलेट जब तक अध्यक्ष है ना तब तक हमको कभी कोई पद नहीं चाहिये।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): धीरजजी, मेरी एक सलाह है कि आप राहुलजी के बहुत नजदीक हैं वह आपको व्यक्तिगत खूब जानते हैं,

(श्री कालू लाल गुर्जर)

आपको टिकट भी दिलाया तो आप यह राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति, जैसी आपने शुरूआत की थोड़ी उनको भी तो बताते।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): राहुल गांधी में तो देश भक्ति है। जिसने अपने पिता को खो दिया...

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): जेएनयू में जाकर ऐसा भाषण नहीं देते अगर थोड़ा बहुत आप उनको सिखा देते तो।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): जेएनयू में राहुल गांधी ने कन्हैया का समर्थन ... गोविन्दजी एक मिनट बैठो ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपके इस अल्पज्ञान के कारण से वसुंधराजी ने आपको केबिनेट मंत्री नहीं बनया।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): कोई बात नहीं, मेरे नहीं बनने से राहुल गांधी सुधर जाए तो मैं उसमें ही राज़ी हूं।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): कालू लालजी, आप मेरे सम्मानीय हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जिसने अपने बाप को इस देश के लिए खो दिया। जिसने अपनी दादी को आतंकवादियों की गोलियों से मरते हुए... इस राहुल गांधी के बारे में हमें चर्चा नहीं करनी और दूसरी बात राहुल गांधी जे.एन.यू. में गया था। (व्यवधान) मेरे लिए राहुल गांधी भगवान हैं। उससे बड़ा कोई दुनिया में भगवान नहीं है लेकिन मैं जो कह रहा हूं। (व्यवधान) आज राहुल गांधी और जनता...

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): भगवान मत बोलो (व्यवधान)

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): मान सिंहजी मेरे भगवान हैं। एक मिल मजदूर के बेटे को...(व्यवधान) अब आप मेरी बात का जवाब ले लो। मेरे बाप ने मुझे धीरज गुर्जर बना के पैदा किया। लेकिन राजनीति में मुझे जन्म राहुल गांधी ने दिया। अगर राहुल गांधी टिकट नहीं देता और जनता वोट नहीं देती तो धीरज गुर्जर आज यहां पर नहीं होता, चौराहे पर खड़ा होता।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): एक इंसान को भगवान कहकर भीलवाड़ा की शान मत तो बिगाड़ो। (व्यवधान)

**श्री सभापति**: माननीय सदस्य, अपनी बात को आप बहुत सीमित कर दें। आप घड़ी देखो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय सदस्य को सदस्या कह रहे हैं।

**श्री सभापति**: आपने सुनने में गलती की है मैंने सदस्य ही कहा है और घड़ी देख लें आप।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): मैं आपसे नैट सात मिनट और लूंगा।

**श्री सभापति**: आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर लीं। अपनी बात को सीमित कर दें अब।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): सभापति महोदय, मैं किसी की आलोचना में नहीं जाना चाहता। मैं यह चाहता हूं कि मैंने ....।

**श्री सभापति**: आप तो पहले सही दे रहे थे, बोल रहे थे आप।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): एक गरीब आदमी का बेटा अगर इस सदन में। ऐसा मैं नहीं, सदन के कई मैम्बर यहां पर ऐसे होंगे जिनके माता-पिता का कोई इतिहास नहीं होगा।

**श्री सभापति**: आप तो शिक्षा में सुझाव दो ना कोई।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): मैं शिक्षा पर ही आपको बता रहा हूं कि आज...।

**श्री सभापति**: बहुत ही कम शब्दों में अब।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): शिक्षा में हमने एक परम्परा बना ली। (व्यवधान) रामलालजी, अब मेरी बात सुनो। अगर आप अच्छी बात सुनना चाहते हो मैं बैठ जाऊं। मैंने बी.जे.पी. पर अंगुली उठाई कि अब तक।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): नहीं, नहीं। मैं तो यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं। (व्यवधान)

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): और आप चाहो तो आधा घंटा का टाइम दो तो मैं सिर्फ अंगुली उठाऊंगा आधा घंटे के अन्दर। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उठाना क्या है ? +++

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): मैं आपसे जो कहना चाह रहा था। आप लोग मुझसे सीनियर हैं। आपके समय में स्कूल का एक खेल का पीरियड होता था। जिस खेल के पीरियड का सब लोग इंतजार करते थे उस खेल के पीरियड को हमने उठाकर शून्य काल के अन्दर डाल दिया। आज भी पी.टी.आई. स्कूलों के अन्दर लगे हुए नहीं हैं। शारीरिक शिक्षक नहीं हैं। खेल का भत्ता हम ऊंट के मुंह में जीरे के समान देते हैं। कैसे हम कल्पना करेंगे कि हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के बच्चों को ओलंपिक मिल जाए ? आप ओलंपिक की बात छोड़ो, राजस्थान के अन्दर मैडल मिलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए खेल का जो

(श्री धीरज गुर्जर)

हमारा पीरियड है उस खेल के पीरियड को शून्यकाल से निकालकर हमें अलग करना पड़ेगा और जो खेल का भत्ता मिलता है। जो पी.टी.आई. टीम लेकर जाते हैं इनको भरपूर भत्ता देना होगा। जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको एक्स्ट्रा खुराक देनी होगी त बजाकर हमारा बच्चा खेल के अन्दर कहीं न कहीं आगे आ पाएगा।

दूसरी, मैं आपसे मांग करता हूं, कभी-कभी अख़बार के अन्दर पढ़ते हैं कि अध्यापक ने स्कूल में बच्चे से झाडू लगवा लिया। कभी-कभी करते हैं कि बच्चा थाली-बर्तन साफ कर रहा था। क्या गलत है ? जिस घर के अन्दर हम रहते हैं क्या उस घर के अन्दर हम झाडू नहीं लगाते ? जिस बर्तन में हम रोटी खाते क्या हम उस बर्तन धोते नहीं हैं ? निश्चित रूप से हमें एक नियम बनाना होगा वापस। पहले हमारे समय श्रम दान का कालांश हुआ करता था। उस श्रम दान के कालांश के अन्दर हम सब बच्चे मिलकर ..। मैं जिस स्कूल के अन्दर पढ़ा भीलवाड़ा के अन्दर, उसके अन्दर हम सब लोग, बच्चे और हमारे साथ हमारा टीचर और हमारा प्रधानाध्यापक। हम सब मिलकर पूरी स्कूल की झाडू लगाया करते थे। पूरी स्कूल की सफाई करते थे। सारी गंदगी को उठाकर हम बाहर फेंक कर आते थे। हमें नियम बनाना होगा कि प्रत्येक हफ्ते में या कम-से-कम पंद्रह दिन के एक घंटा श्रमदान का होगा और उस श्रमदान के घंटे में स्कूल का अध्यापक, स्कूल का छात्र, स्कूल का प्रधानाध्यापक, सब मिलकर अपनी स्कूल के अन्दर सफाई करेंगे।

एक मैं कहना चाहता हूं, हम बार-बार मांग उठाते फलां माफिया, ढिमका माफिया, पुछ़ का माफिया। यह जो एजुकेशन माफिया डवलप हो रहा है राजस्थान के अन्दर। राजस्थान की कभी यह परंपरा नहीं रही कि राजस्थान के अन्दर एजुकेशन माफिया डवलप हो। लेकिन आज निजी स्कूलों वालों के, निजी कालेज वालों के और सबसे ज्यादा यह जो कोचिंग क्लास राजस्थान के अन्दर खोलकर बैठे हैं कोटा के अन्दर और जयपुर के अन्दर । इनके हाथ विस्तृत हो गए हैं कि जो भी इनके ऊपर हाथ उठाता है उसका मुंह पैसों से बंद करने की कोशिश करते हैं। इन कोचिंग संस्थानों के कारण, न तो यहां पूरी सुविधाएं हैं, लाखों रुपए ग़रीबों से लूट रहे हैं। इससे अच्छा, इससे कम खर्चे में अगर सरकार कोचिंग सेंटर खोल दे और वहां पर बैस्ट आदमियों को पढ़ाने के लिए रख दें और जितनी ये फीस दे रहे हैं और उसकी आधी फीस लेंवें तो उस आधी फीस के अन्दर बच्चा पढ़-लिख जाएगा और ये कोटा के एलन संस्थान,

(श्री धीरज गुर्जर)

फलाना संस्थान, ढिमका संस्थान। सैकड़ों बच्चे यहां बाहर से आकर रहते हैं। हजारों की मौत हो रही रोज। ये लोग फांसी खाकर मर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर हमें कुछ करना होगा।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

आखिरी बात मैं इन शब्दों के साथ खतम करना चाहता हूं कि मुझे आप पर आरोप नहीं लगाना। लेकिन हमने एक लोगों को सपना दिखाया कि विद्यार्थी मित्रों को हम स्थाई कर देंगे। जिसको हमने लगाया उसी को हम मारना चाहते हैं। हमने संविदा कर्मी को सपना दिखा दिया। जो व्याख्याता 2008 में हमने संविदा कर्मी लगाए थे, उनके साथ हमने धोखा कर दिया। उनमें 69 की ओवरएज हो गई। 162 आदमी 7900 रुपए के अन्दर काम कर रहे हैं। कम्प्यूटर शिक्षक, इस सरकार के सामने भरी तपती दुपहरी के अन्दर वो महिलाएं जो कम्प्यूटर शिक्षक हैं वो बी.जे.पी. कार्यालय के बाहर गईं रेंगते-रेंगते। मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी कोई कमी है, लेकिन हमने ऐसा सपना, जब हमारी चादर छोटी थी तो हमने लम्बे पांव फैलाए ही क्यों? हमने क्यों सपना दिखाया पैरा टीचर को? हमने क्यों सपना दिखाया विद्यार्थी मित्र को? हमने क्यों सपना दिखाया पी.टी.आई. को? हमने क्यों सपना दिखाया राजस्थान के युवा को नौकरी का? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो हमें वादे नहीं करने थे और अगर हम अपनी क्रिएटिबिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं तो वादे हमने किए, उन वादों पर हमें खरा उतरना पड़ेगा। कोर्ट का सहारा लेना, वित्तीय संसाधनों का सहारा लेना हमें छोड़ना पड़ेगा। दस चीजों में कटौती हो सकती है, लेकिन एजुकेशन। एजुकेशन राजस्थान की 48 परसेंट 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए हम 18 पर्सेंट अपना फंड देते हैं और शिक्षा के फंड में से 95 परसेंट पैसा सिर्फ सैलेरी के अन्दर चला जाता है। कैसे पढ़ाएंगे हम ? कैसे हम निर्माण करेंगे? इसलिए शिक्षा का फंड इस राजस्थान के अन्दर हमें बढ़ाना होगा। दूसरे किसी फंड के अन्दर हम कमी कर लें तो कर लें, लेकिन हमें इसका फंड बढ़ाना पड़ेगा।

**श्री सभापतिः** माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कालीचरणजी से एक बात कहते हुए कि 2008 के अन्दर आपकी सरकार में वसुंधराजी जहाजपुर के अन्दर घोषणा करके आई थीं कि मैं कालेज खुलवाऊंगी। आपकी पार्टी का एम.एल.ए. जीता। आपने कलेज नहीं खोली।

(श्री धीरज गुर्जर)

पिछले राज के अन्दर गहलोत सरकार थी, हमने उनके हाथ जोड़कर जहाजपुर में कालेज खुलवाई। 90 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा मुख्यालय से आसपास 40 किलोमीटर तक इस जिले के अन्दर कोई भी कालेज नहीं । एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. की जनसंख्या 70 परसेंट। जहाजपुर में खुली हुई कालेज को आपने सिर्फ इसलिए रोक लिया, क्योंकि वहां से कांग्रेस का एम.एल.ए. जीत गया। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कालीचरणजी सराफ। आप बहुत दरियादिल आदमी हैं। मेरे जहाजपुर के अन्दर जो कालेज खुली हुई है उसको आपने मंत्रिमंडलीय समीक्षा के नाम पर रोक रखा है। मैं कहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी आप में इंसानियत हो तो राजनीति से ऊपर उठकर मेरी कालेज, मेरे को दे दो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। राम राम। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री सभापति:** श्री शंकर सिंह ।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय,...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ब्यावर को जिले...(व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): यह जिले का नहीं है, शिक्षा का है आज। माननीय सभापति महोदय ..। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): नहीं तो वैल में आ जाना आप।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): यह काम आपको दे रखा है हमने। यह वैल में आने का काम आपको दे रखा है ।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): शिक्षा में ही जिला मांगते थे इसलिए बता रहा हूं...(व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): जब बोलते हैं तो टाइम कम हो जाता है इसलिए आप तो बोलो मत। चाहे इधर से बोलें, चाहे उधर से बोलें। हाथ जोड़कर निवेदन है। इनका टाइम खतम हो जाता है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): मैं नहीं बोलूंगा तो सब सो जाओगे आप।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): नहीं कोई सोएगा।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से अभी प्रतिपक्ष के भाई बोल रहे थे, धीरजजी बोल रहे थे। उनसे भी मेरा

(श्री शंकर सिंह)

निवेदन है कि बहुत अच्छा बोला। लेकिन लास्ट में सारा पानी फेर दिया। उधर से हमारे सम्माननीय सचेतक महोदय भी आपके बहुत अच्छे नंबर बढ़ा रहे थे, हम सब भी इधर बढ़ा रहे थे और धीरे-धीरे ताली भी बजा रहे थे कि धीरजजी बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन लास्ट के टाइम में आपने बिलकुल एकदम पकी-पकाई खेती के ऊपर रोजड़ा के रूप में घुमा दिया। (व्यवधान)

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): कालीचरणजी सक्षम नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर): हमारे सचेतक महोदय ने बहुत बढ़िया और अच्छे रूप में आपके लिए बताया था। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय वसुंधराजी ने जब इस राजस्थान में शिक्षा का बंटाधार जो पूर्व की सरकार ने जब किया था और सुराज संकल्प यात्रा लेकर पूरे राजस्थान में उन्होंने दौरा किया। उस समय में एक ही आवाज हर जगह से उठ रही थी कि इस कांग्रेस के शासन में। जिस प्रकार से पहली क्लास से आठवीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं करने का जो काला कानून इस राजस्थान में बना रखा था।

हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक ही संकल्प लिया कि हमारी सरकार आने के बाद इस काले कानून को समाप्त करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को भी कि इन्होंने मिलकर इस काले कानून को सबसे पहले आकर खतम किया। इस काले कानून की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आगे पढ़ने का काम ही नहीं है। इन्होंने परमानेंट इलाज कर रखा था कि पहली से आठवीं क्लास तक के बच्चों को अनिवार्य पास करने का कानून बनाकर ताकि दसवीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा वह कैसे दे पाएगा, पास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए गरीब के बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए ऐसा कानून था उसको हमारी सरकार ने समाप्त किया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

जिस प्रकार शिक्षा के अन्दर सुधार करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने, यह सरकार बनने के बाद 5 हजार 40 विद्यालयों को इन्होंने क्रमोन्नत किया है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यापकों की पदोन्नति करके पूरे प्रदेश में एक जबरदस्त कार्य

(श्री शंकर सिंह)

निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव से निपटाया है, यह बहुत अच्छा कार्य है, धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे-अच्छे काम तुलनात्मक दृष्टि से हमारी सरकार ने किये हैं। मेरा एक निवेदन है कि सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई का अंतर है उस अंतर को कैसे समाप्त किया जाए, उस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

मिड डे मिल बनाने वाली महिला है उसको आप हजार रुपये दे रहे हैं। हजार रुपये में कुछ भी नहीं होता है। उसका पेमेंट बढ़ाया जाना चाहिए। नरेगा का मजदूर भी 180 रुपया पाता है। उनके लिए भी हमारे को सोचना चाहिए। ऐसा हमारा निवेदन है।

स्कूल, भवन, प्रत्येक विद्यालय में ऐसा आदेश जारी कराएं कि विद्यालय में कभी भी चैक करने के लिए कोई जाए उस टाइम, ऐसी टीम बनाकर कभी भी जाए तो खाने की गुणवत्ता चैक की जाए। विद्यालय रंग रोगन होकर, विद्यालय विद्या मंदिर के रूप में दिखे ऐसा एक नियम बनाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर शौचालय निर्माण का कार्य हो रहा है इसको अनिवार्य रूप से प्रत्येक विद्यालय में लागू किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय के अन्दर शौचालय निर्माण हो। योजना कोई भी हो सकती है, किसी भी योजना के अन्दर इस काम को पहले हाथ में लिया जाना चाहिए। जितना सुधार हमारी इस विद्या के अन्दर कर सकते हैं उसको करना चाहिए। विद्या से ही पूरा प्रदेश, ग्रामीण क्षेत्र के, गरीब के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ेंगे।

मेरा इसमें निवेदन है कि प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल में अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उनको एडमिशन नहीं देते हैं। गरीब के बच्चे के लिए आपने एक नियम बनाया था कि 25 परसेंट बच्चे, कोई भी विद्यालय हो, उसके अन्दर, बीपीएल का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो या ग्रामीण क्षेत्र, किसी भी जाति का हो, उसको आपको एडमिशन देना पड़ेगा, लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि उसमें कड़ाई से पालना होनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल के अन्दर 25 परसेंट बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। आज प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र वाइज, आपको एक आदेश जारी करना चाहिए कि सम्बन्धित विधायक उस क्षेत्र का है, उसके पास जिला शिक्षा

(श्री शंकर सिंह)

अधिकारी, वह रिपोर्ट देगा और वह उस स्कूल की रिपोर्ट लेगा कि 25 परसेंट बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भर्ती किए हैं कि नहीं किए हैं। चाहे वह ग्रामीण का हो या शहर का हो, गरीब के बच्चों को एडमिशन देने के नियम को कड़ाई से लागू करवाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

विद्यार्थी मित्रों को भी हमें, इस पूर्ववर्ती सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अच्छी भावना रखते हुए इनके ऊपर भी ठंडी नजर रखकर हमको इनको रोजगार वापिस देना चाहिए, विद्यार्थी मित्रों को लगाने के लिए। हमने यह नहीं कहा है कि सिर्फ बीजेपी के विधायक को ही उसकी रिपोर्ट दें, हमने यह कहा है कि विधान सभा का सदस्य, चाहे वह किसी भी दल का है लेकिन सम्बन्धित विद्यालयों की रिपोर्ट उनके पास मिले कि 25 परसेंट बच्चों को आरक्षण मिला है कि नहीं मिला है।

जिस प्रकार आज क्षेत्र के अन्दर ग्राम पंचायत के अन्दर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने की योजना बना रखी है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि, कहीं भी आप भाषण देते हैं तो पूरे राजस्थान के अन्दर प्रत्येक विद्यालय के ऊपर, प्रत्येक पंचायत के ऊपर, प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा कर रखी है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हमारे अजमेर जिले में ही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय रहते हैं और हमारे ही अजमेर जिले में जवाजा पंचायत समिति में दो ग्राम पंचायत ऐसी बची हुई हैं जिनके अन्दर सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। उसमें खास राजकीय माध्यमिक विद्यालय ब्यावर, जो पंचायत मुख्यालय भी है और राजकीय माध्यमिक विद्यालय धधालिया यह ग्राम पंचायत मालातो की भी है, यह दो विद्यालय खुलना बहुत जरूरी हैं। तब जाकर पूरी पंचायत समिति में, एक-एक पंचायत पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जाएगा। चार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे बागमाल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोडमाल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय अनाकर, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय राजावास, इनको सीनियर करना बहुत जरूरी है। राजावास में इतनी बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं लेकिन सीनियर स्कूल नहीं होने की वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है।

साथ में, उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है जो बहुत समय से, पूर्ववर्ती सरकार के समय से इनकी मांग हो रही है लेकिन अभी तक वह नहीं हुए हैं। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक

(श्री शंकर सिंह)

विद्यालय गोविन्दपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकराना, मेंदरातन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणेशपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर प्रथम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालीपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाउसिंग बोर्ड ब्यावर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपनगर, अरनाली, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेनरा रोड ब्यावर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालींजर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा दुड़धा इन विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिए भी मेरा आपसे आग्रह है।

शिक्षा मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमें पढ़ाई के अन्दर गुणवत्ता का, प्राइवेट स्कूल में, अभी मेरे से पूर्व माननीय विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे कि निश्चित तौर पर सरकारी स्कूलों में कितने सदस्यों के बच्चे पढ़ते हैं। जब आप पढ़ाई के अन्दर कड़ाई से लागू कर देंगे किसी कानून को बनाकर, ऐसी कोई व्यवस्था करो। आज प्राइवेट स्कूल के अन्दर दस हजार से ज्यादा उस टीचर को तनख्वाह नहीं मिलती होगी लेकिन उस स्कूल में एडमिशन के लिए किसी न किसी से सिफारिश करानी पड़ेगी, इस व्यवस्था को सुधारा जाए। आज सरकारी विद्यालयों के अन्दर स्कूल में पढ़ाई कराने वाले का 35 हजार, 40 हजार से पेमेंट कम नहीं है। इस ओर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा तब जाकर शिक्षा में सुधार होगा।

हम विपक्ष की सरकार पर आरोप लगा देते हैं, आज अपनी सरकार आई है यह आरोप लगाते हैं लेकिन मेरा तो उन सब की बातों से ऊपर उठ कर कि इनके अन्दर सुधार कैसे हो इसके लिए आपको कड़ाई से ऐसा कोई कानून बनाकर इसमें सुधार करवाने की आवश्यकता है।

खेलकूद मंत्रीजी भी यहां विराजमान है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम ब्यावर में, जब मैं पिछली सरकार में सदस्य था उस समय विधायक कोष से 2012 में सहभागी योजना के अन्तर्गत 20 लाख रुपये का चैक खेल स्टेडियम विभाग को भेजा हुआ है। उसके एवज में एक करोड़ 80 लाख उनको दे करके दो करोड़ का चैक वापस वहां खेल स्टेडियम के लिये पहुंचाना था। लेकिन जिस प्रकार आज ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया था और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह सब दावे खोखले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 2012 के अन्दर जो बीस लाख रुपये का चैक दिया था

(श्री शंकर सिंह)
उसका अभी तक भी अता-पता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि निश्चित तौर पर इन्होंने जो दो साल तक नहीं दिया है लेकिन अभी भी मेरा निवेदन है कि चैक को नोट करके उसका वापस बजट भेजा जाये ताकि वह सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम ब्यावर में भव्य तरीके से बन सके।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा के अन्दर सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसके अन्दर गरीब के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिये शिक्षा के अन्दर अब सुधार की बहुत आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि गांव में एक महिला अपने घर में सफाई करने के लिये झाड़ू निकाल रही थी। यह विशेष करके प्रतिपक्ष के जो सदस्य बोल रहे थे, उनके लिये है। तो झाड़ू निकालने के टाइम पर एक कागज का टुकड़ा साथ में नजर आया, उस महिला ने देखा कि यह तो मार्कशीट है। वह अपने बच्चे की पिटाई करने लग गई कि इतने कम नम्बर लेकर आया है। रात-दिन अच्छा खाना खिला करके भेजती हूं, पढ़ाई कैसे नहीं करता है, बच्चे की पिटाई कर दी। बहुत पिटाई करने के बाद बच्चे ने कहा, मम्मी, मेरे को क्यों मार रहे हैं, यह तो पापा की मार्कशीट है। तो यह आप लोगों की वजह से शिक्षा के अन्दर इतनी अव्यवस्था हुई है। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें निश्चित सुधार करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्री हमीरसिंह भायल।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं।

देश व प्रदेश में शिक्षा का बड़ा महत्व है। आजादी के 70 साल बाद में जब-जब भारतीय जनता पार्टी का देश व राजस्थान में शासन रहा है उस समय शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़कें इनमें परिवर्तन आया है। उदाहरण के तौर पर भारत में जब प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विराजे, उन्होंने पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण में बिना भेदभाव सड़कों की एक नीति बनाई। उसके आधार पर गांव और ढाणी, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इन सड़कों का फायदा मिला। राजस्थान में जब पहले स्व. भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री

(श्री हमीरसिंह भायल)

बने, उन्होंने भी गांव और ढाणी और गरीब तक पहुंचने के लिये और उन तक शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और पेयजल पहुंचाने के लिये पंचायत हैड-क्वार्टर तक पांचवीं से आठवीं स्कूल बनाई। अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, हर चीज में परिवर्तन किया। राजस्थान में 2003 से 2008, जब हमारी मुख्य मंत्रीजी परम आदरणीय वसुन्धराजी राजे बनीं तो उस समय में उन्होंने पूरे राजस्थान में बिना भेदभाव, आठवीं से दसवीं पंचायत हैड-क्वार्टर तक क्रमोन्नत करके स्कूलें बनाईं। प्रतिपक्ष के भाई कहते हैं कि भेदभाव करते हैं। भेदभाव तो आजादी के बाद में 52 या 55 साल में आपकी जब भी सरकारें रही हैं उस समय में हुआ है।

वर्तमान में मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान में पांच हजार से ऊपर दसवीं से सीनियर करके ग्रामीण जनता को जो तोहफा दिया है, इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। शिक्षा मंत्रीजी ने प्रमोशन करके 70 प्रतिशत जो लैक्चरर और अध्यापक लगाये हैं, इसके लिये भी मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बच्चियों के लिये साइकिल वितरण, स्कूटी वितरण, लैपटाप, यह सारी सुविधा ग्रामीण जन के लिये दी, इसके लिये भी मैं धन्यवाद करता हूं। जब-जब भी, हर क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, बिना भेदभाव गांव और गरीब तक हर-एक का ध्यान रखते हुए जो भी योजना बनी है सबको फायदा मिले, यह मूल परिवर्तन करके मेरे भाई जो कह रहे थे धीरजजी, कि परिवर्तन की आवश्यकता है, आज की तारीख में भी ब्लाक स्तर, तहसीलदार, बी.डी.ओ., एस.डी.एम. सब स्कूल चैक करते हैं। आप खुद भी ध्यान देकर इसको देखें।

मंत्रीजी से मेरा निवेदन रहेगा कि जहां शहरी क्षेत्र में इतने अध्यापक लगे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कम हैं, नामांकन के अनुपात में जहां अध्यापक ज्यादा हैं वहां ग्रामीण क्षेत्र में भेजने की आवश्यकता है। यह अगर हो जाएगा तो शहरों में सरकारी स्कूलों में नामांकन नाममात्र का है और ग्रामीण में जहां 200 या 300 छात्र पढ़ते हैं, वहां भी अध्यापकों की संख्या कम है। हमें इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। पहले तो धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आपने मेरे सिवाना में कालेज दे दिया। भूमि-आबंटन हो गया, बजट की आवश्यकता है। वहां भी परमानेंट लेक्चरर्स लगाने की आवश्यकता है।

(श्री हमीरसिंह भायल)

सरकार को धन्यवाद देता हुआ मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांग माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। सिवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विज्ञान विषय आरम्भ करने की मांग, 1500 का नामांकन उस स्कूल में छात्रों का है, जो कि सबसे ज्यादा है। पूर्व में संचालित संस्कृत साहित्य विषय को पुन: आरम्भ करने की मांग। समदड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व में संचालित गणित विषय को पुन: आरम्भ करने की मांग। क्षेत्र में संचालित शिक्षाकर्मी विद्यालयों को क्रमोन्नत करके राजकीय विद्यालयों में समायोजित करने की मांग। क्योंकि इन विद्यालयों में नामांकन होते हुए भी न तो अध्यापक लगा सकते हैं और न ही इनको क्रमोन्नत किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में मांगला उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षाकर्मी है जिसमें लगभग 350 छात्राएं अध्ययनरत हैं। लेकिन वहां पर शिक्षाकर्मी विद्यालय कह कर अतिरिक्त अध्यापक नहीं लगाये जा रहे हैं। इसलिये उसे उच्च प्राथमिक से सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की मांग की जाती है। विधान सभा क्षेत्र में पंचायत पुनर्गठन से लगभग 19 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। जिसमें राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय होना चाहिये। नवीन पंचायतों में अब सभी जगह प्राथमिक स्तर का विद्यालय होना ही है। अत: मेरे क्षेत्र में नवीन पंचायत मुख्यालय बिलासर, नाकोड़ा, सिणधरी चारणान, चारणों का तला, लुकों की ढाणी, भाटा लोहिड़ी, अरनियाली खारा, मेचान, पोंग, गेरानाडी, इंटवाड़ी, नाल, पादरली कला, खेजड़ियाली, बरला का वाड़ा, समदड़ी स्टेशन, थापन, इन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समदड़ी तहसील मुख्यालय पर बालिका महाविद्यालय खोलने के साथ आई.टी.आई. प्रशिक्षण संस्थान भी खोले जाने की मांग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिणधरी में विज्ञान विषय शुरू करने की मांग तथा स्वीकृत अर्थशास्त्र विषय की जगह पर भूगोल विषय आरम्भ करने की मांग। सिणधरी के सीनियर बालिका विद्यालय में गृह विज्ञान विषय आरम्भ करने की मांग करता हूं।

आदरणीय कला एवं संस्कृति मंत्री महोदया भी विराजी हैं। मेरा निवेदन रहेगा, प्रसिद्ध हल्देश्वर मन्दिर जो छप्पन की पहाड़ियों में स्थित है,

(श्री हमीरसिंह भायल)

इसे राजस्थान धरोहर संरक्षण स्वीकृति प्राइज में प्रस्तावित कर पेनोरमा बनाने की मांग।

सिवाना दुर्ग को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु इसकी मरम्मत करवाकर दुर्ग की दीवारों पर लाइट का प्रबंध करके सुन्दर बनाने की मांग।

सिवाना क्षेत्र में दर्शनीय स्थल पंच-तीर्थ में हिंगलाज माता मंदिर, चारभुजा माता मंदिर, भीम-गोड़ा, धंताला दर्गाएं, मौकलसर की बावाड़ियां, ब्रह्म-धाम आसोतरा, रानी-भटयानी मंदिर, जसौल, नाकौड़ा तीर्थ, सामुजा महादेवजी, आदि दर्शनीय स्थलों को कला एवं संस्कृति विभाग में सम्मिलित करने की मांग।

सिवाना के राजकीय उच्च, मैं धन्यवाद दूंगा मंत्रीजी को कि मेरे यहां बजट का प्रावधान करके कालेज दी। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के प्रति, किसान के प्रति समर्पित भाव से, बिना भेद-भाव पूरे राजस्थान को जो बजट दिया है, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात पूर्ण करने से पहले एक, यहां पर कुछ कहना चाहूंगा कि- 'आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाएं, मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे, जीवन ऐसा हो जो शब्दों की कद्र करे', जय भारत, जय हिन्द। धन्यवाद।

**श्री सभापति**: श्रीमती द्रोपती।

**श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या-24- शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा देश भारत विश्व गुरु रहा है और वर्तमान में भी पूरे विश्व में भारत की जय-जयकार हो रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, कला की विश्व स्तर पर पहचान है और हमारे देश में विश्व के लोग यहां की कला संस्कृति को देखने के लिए आते रहते हैं।

जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहां के किले, दुर्ग, मंदिरों के संरक्षण की बात भी करते रहते हैं। जब-जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो राजस्थान की कला-संस्कृति के संरक्षण की जनता को एक प्रकार से आशा दिखाई देती है। यहां पर अनेक प्रकार के किले, स्मारक हैं जिनकी देखभाल राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा की जाती है जैसे- जंतर-

(श्रीमती द्रोपती)

मंतर, आमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, आदि ताकि यहां की जनता को इन स्मारकों से प्रेरणा मिल सके।

महोदय, ऐसा ही हमारे हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी में माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे के नेतृत्व में गोगाजी महाराज का भव्य मंदिर और स्मारक का निर्माण 18 करोड़ 95 लाख की लागत से किया जा रहा है। यहां पर देश-विदेश से यात्री आते हैं।

महोदय, हमारी प्राचीन कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक स्थान पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में कालीबंगा भी है। कालीबंगा का क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा है। यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं।

माननीय सभापति महोदय, कालीबंगा में हुई खुदाई में हड़प्पा से पुराने संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की खुदाई में मानव की ओर से करीब पांच हजार वर्ष पूर्व की की गयी प्रगति शामिल है। कालीबंगा का क्षेत्र कृषि, नगर निर्माण कौशल, दुर्ग आदि क्षेत्रों में हजारों साल पहले ही उन्नति कर चुका है। महोदय, कालीबंगा में इन पुरातत्वों को संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। कालीबंगा के संग्रहालय को देखने के लिए यहां पर देश-विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। कालीबंगा में पर्यटकों के आने-जाने के लिए, ठहरने के लिए, खाने-पीने के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूं माननीय मंत्री महोदय से कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के कालीबंगा को विश्व धरोहर स्तर पर पहचान दिलाई जाए ताकि यहां पर आने-जाने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पुन: निवेदन करती हूं कि आप इसी वर्ष में कालीबंगा को हैरिटेज सिटी में शामिल करें ताकि कालीबंगा का विश्व धरोहर के तहत विकास करवाया जा सके। ऐसा होने से हमारे देश में पर्यटकों की संख्या अधिक होगी। यहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री- वसुन्धराजी राजे के नेतृत्व में शिक्षा विभाग के संकल्प भरे कदमों से नए कीर्तिमान अर्जित किए गये हैं। महोदय, शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा का स्वर साध न सकेगी, अगर नैतिकता का आधार नहीं, अगर नैतिकता का आधार नहीं।

(श्रीमती द्रोपती)

महोदय, इसी भावना को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं शिक्षा मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने शिक्षा जगत में इतना शानदार और जानदार बजट प्रस्तुत किया है।

महोदय, हमारे प्रदेश में गत वर्षों से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। राज्य के राजकीय स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लोक कल्याणकारी माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय, हमारे सभी के आदर्श एवं प्रेरणादायी स्वामी विवेकानंदजी के नाम से स्वामी विवेकानंद माडल स्कूल, शारदे छात्रावास, शाला दर्पण, लैपटाप वितरण, साइकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष स्कूली शिक्षा के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिये जाने वाले बजट में 23 हजार 177 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 14.47 प्रतिशत अधिक है। यह हमारे लिए गौरव की बात है।

माननीय सभापति महोदय, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्टाफ छात्र संख्या के अनुपात में कम है। कुल स्वीकृत पद 1141 में से 312 पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से छात्र हित में मांग करती हूं कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कृपा करें और साथ ही, विद्यार्थी मित्रों के प्रति भी ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरलिया के ग्राम खिराजवाला में राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। ग्राम पंचायत मुख्यालय खरलिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है और वह स्वीकृत भी है। खिराजवाला से खरलिया की दूरी लगभग पांच किलोमीटर दूर है।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम खिराजवाला से आस-पास की तीन ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं और ढाणी चक भी इसी विद्यालय में ढाणी से, चकों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय खिराजवाले का विद्यालय भवन ग्राम-वासियों के अपने निजी कोष से, सहयोग से वह स्कूल बनाया गया है, जिसका खर्चा वह स्वयं भुगतते हैं। आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जब भी आप हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आएं तो हमारे पीलीबंगा में खिराजवाले चक का स्कूल जरूर देखें, यह मैं आपसे आग्रह करती हूं।

(श्रीमती द्रोपती)

महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से मांग करना चाहती हूं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खिराजवाला को उच्च माध्यमिक कला वर्ग में क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। क्रमोन्नत होने वाले विद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं:-

ग्राम पंचायत-अलायकी, ग्राम पंचायत-लोंगवाला, ग्राम पंचायत-मानकथेड़ी, ग्राम पंचायत-पंडितावाली, ग्राम पंचायत-सूरावाली, 10 एम.ओ.डी. ग्राम पंचायत डबलीबास कुतुब, चक-12 जे.डब्ल्यू.डी. (मलकोका) ग्राम पंचायत डबलीबास पैमा, चक-12 एस.टी.बी. ग्राम पंचायत मानकथेड़ी, चक-2 एस.जी.आर., ग्राम पंचायत डिंगवाला, चक-26 पी.डी.एन. रामपुरा, चक-3 एस.पी.डी. हरदयालपुरा, चक-35 एल.एल.डब्ल्यू. ग्राम पंचायत उम्मेवाला, चक 6 बी.एस.एम. चक पंचायत जाखड़ावाली, चक-6 एच.एल.एम. जाखड़ावाली, अहमदपुरा-ग्राम पंचायत अमरपुरा राठान, गोलूवाला निवादान ग्राम पंचायत, चक लबाणा की ढाणी ग्राम पंचायत 18 एस.पी.डी., लुढाणा ग्राम पंचायत अमरपुरा राठान, निहालपुरा-ग्राम पंचायत पीलीबंगा गांव, नूरपुरा-ग्राम पंचायत डबलीबास मिढारोही, पीलीबंगा मंडी-तहसील पीलीबंगा, सरामसर-ग्राम पंचायत अमरपुरा राठान, सिंगपुरा-ग्राम पंचायत खोथावाली, ठाकरूवाला चक ग्राम पंचायत बड़ोपल, एक एल जी डब्ल्यू डबलीबास कुतुब, 45 एन डी आर ग्राम पंचायत पंडितावाली, चक 9 डी डब्ल्यू एम ग्राम पंचायत 29 डी डब्ल्यू डी रावतसर, मसरूवाला 20 एस टी बी ग्राम पंचायत डबलीवास चुगता, 4 एस पी डी ग्राम पंचायत 7 डी डब्ल्यू डी, 29 डी डब्ल्यू डी, वार्ड नं. 2 रावतसर तहसील रावतसर, चक 16 डी डब्ल्यू डी तहसील रावतसर, चक 2 के डब्ल्यू डी तहसील रावतसर, सदासिंह वाला तहसील पीलीबंगा, 44 एन डी आर ग्राम पंचायत दौलतावाली।

**(17.50 बजे)**

**(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत खोड़ा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित है। ग्राम पंचायत खोड़ा के आसपास चार ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं। आसपास 2 सी ए डी चक, एक सौ साढ़े 22 आर डी, एक सी एल डी चक, दो एम जी एम चक के बच्चे भी इसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं।

(श्रीमती द्रोपती)

उपाध्यक्ष महोदय, खोडन गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए बच्चों को 5 से 7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। एक बहुत बड़ी नहर भी क्रोस करनी पड़ती है तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत खोड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का श्रम करें।

**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी वाणी को विराम देती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब से केन्द्र में माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, तब से पूरे विश्व में भारत माता की जय-जयकार हो रही है। अब वह दिन दूर नहीं है, जिसकी वर्षों पहले ऋषि-मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन भारत देश फिर से विश्व गुरु बनेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सभी का एक धर्म है, वह धर्म है राष्ट्र धर्म, यानी भारत माता की जय।

सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करें।
वर्ण भेद, मतभेद मिटाकर, नव रचना निर्माण करें।
राष्ट्र धर्म हमारा जग में अभिनव, अक्षय है अविनाशी,
इसी कड़ी से जड़े हुए हम, युग-युग से हैं भारतवासी।

गत 60 वर्षों से हमारे देश में कभी नेहरू की जय बोलते थे, कभी इंदिरा गांधी की जय बोलते थे, क्योंकि ये प्रधान मंत्री थे, सही बात है ना माननीय कांग्रेसी सदस्यों?

उपाध्यक्ष महोदय, गत 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार केन्द्र में गत प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी के नेतृत्व में बनी रही थी, तब भी जय बोली जाती थी, लेकिन माननीय मनमोहन प्रधान मंत्रीजी की नहीं, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमारे देश में गौरवशाली माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, अब भी जय बोली जाती है। जय तो माननीय अब भी बोली जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की जय नहीं बोली जाती, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय बोली जाती है। धन्यवाद । जय हिन्द। जय भारत।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आसन व्यवस्था दे कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम बार-बार नहीं आना चाहिए। (व्यवधान) मैंने नहीं लिया। आपने लिया था। आप मेरी बात सुनो। फिर बार-बार राहुल गांधी का नाम इस सदन में आता है तो आटोमैटिक व्यवस्था दे दें कि जब भी नाम आए तो वह एक्सपंज हो जाया करे। अगर कोई विवादित टिप्पणी हो तो।

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं है, यह व्यवस्था है। आपको शंका कैसी थी?

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): अख़बार में आ रहे हैं न रोज उपाध्यक्ष महोदय। जो यहां बोला जाता है, रिकार्ड में आता है तब ही फिर अख़बार में छपता है। कम से कम विवादित टिप्पणी तो एक्सपंज हो जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: इस प्रकार की व्यवस्था है और इसको आप लोग ध्यान में रखकर, जो सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है या कोई भी व्यक्ति का नाम लिया जाए, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम लिया जाए तो वह अंकित नहीं होगा।

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): इन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरा भगवान है।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): मेरा भगवान है।

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): वो भी एक्सपंज हो जाए।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आप तो देवनारायण के भक्त हो और आप पता नहीं और नया देवता और देवनारायण पैदा कर रहे हो। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। अब तक तो आप भाषण देते हो कि देवनारायण भगवान, आप कह रहे हो और भगवान दिल्ली में पैदा हो गए आपके।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): अमेठी के माननीय सांसद मेरे भगवान हैं, और रहेंगे। अमेठी के माननीय सांसद मेरे भगवान हैं और रहेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष**: और कोई शंका हो तो वह भी पूरी कर दें ये।

श्री देवेन्द्र कटारा (अनुपस्थित) श्री संदीप शर्मा।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुदान की मांग संख्या 24 – शिक्षा, कला और संस्कृति पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत आभार। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे शिक्षा

(श्री संदीप शर्मा)

मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस बजट में राज्य के शिक्षा के स्तर को बेहतर और उत्कृष्ट करने के लिए कई सराहनीय कदम उठाये हैं। प्रदेश के कई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे, उनके निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। साथ ही ऐसे 628 विद्यालय, जिनमें विद्युतिकरण नहीं था, उन्हें विद्युत से जोड़ने के लिए विद्युत कनेक्शन उनमें लगाने के लिये 13 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के साथ अन्य भी कई महत्वपूर्ण कदम शिक्षा के बजट में निर्णय के रूप में लिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण और विकास में प्रदेशवासियों की भागीदारी हो। सरकार और प्रदेशवासियों के सम्मिलित सहयोग से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति को और अधिक बेहतर किया जाए। इसके लिये हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जन सहभागिता योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है। राज्य में आवश्यकता के अनुसार सरकारी विद्यालयों में नये संकाय खोलने का भी निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सी.बी.एस.ई. और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर में काफी अन्तर देखने को मिलता है। सी.बी.एस.ई. में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के पास अपनी कुशल अंग्रेजी ज्ञान के कारण रोजगार के काफी अवसर होते हैं, जबकि सरकारी विद्यालय के हिन्दी मीडियम वाले विद्यार्थी पढ़ने में सी.बी.एस.ई. के जो छात्र हैं, उनसे काफी पिछड़े माने जाते हैं। इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान शिक्षा के अवसर मिले। इसलिये आवश्यक है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को सी बी एस ई और एन सी ई आर टी के समान किया जाए व पाठ्यक्रम वैकल्पिक चलाया जाए जिससे छात्र अपनी रूचि के अनुसार अध्ययन कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की संस्कृत शिक्षा भी आज उपेक्षा का शिकार हो रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षा के काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसलिये जिस उद्देश्य को लेकर संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना की गयी, हम उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नई पीढ़ी संस्कृत शिक्षा के पठन-पाठन में रुचि नहीं ले रही। यदि समय रहते हमने प्रयास नहीं किये तो इस भाषा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं कोटा दक्षिण,

(श्री संदीप शर्मा)

वह पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है, साथ ही शिक्षा नगरी के रूप में पूरे देश में अपनी विशेष पहचान रखता है। कोटा शहर के कोचिंग संस्थानों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में विद्यार्थी आई आई टी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर आज देश और विदेश की कम्पनियों में शीर्ष पदों पर कार्य कर रहे हैं, कोटा और राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कोटा शहर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। आज आवश्यकता है कि कोटा जैसी शैक्षणिक नगरी में इन विद्यालयों की स्थिति में सुधार किये जाएं।

कई सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, कम्प्यूटर लैब सुचारु रूप से नहीं चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर शिक्षा नगरी के रूप में स्थापित हो चुका है। शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज तथा नामी कोचिंग संस्थान होने से यहां विद्यार्थियों में विज्ञान संकाय के प्रति विशेष रूचि है। कोटा शहर के अधिकांश कोचिंग संस्थान और नामी विद्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही हैं। लेकिन उस हिसाब से कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में विज्ञान संकाय नहीं है। कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के केवल दादाबाड़ी, गुमानपुरा में ही विज्ञान संकाय संचालित है, जबकि तलवंडी और महावीर नगर में जो विज्ञान संकाय हैं, वह भी स्व-वित्त पोषित विद्यालय हैं।

(18.00 बजे)

जहां समय-समय पर जो आवश्यकता होनी चाहिए उसके मुताबिक विद्या अध्ययन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही कोटा शहर के विद्यार्थियों का वाणिज्य संकाय के प्रति भी रुझान बढ़ा है लेकिन कोटा क्षेत्र के विद्यालयों में आवश्यकता के हिसाब से वाणिज्य संकाय नहीं है।

रमसा और सर्व शिक्षा अभियान के तहत किये जाने वाली योजनाओं की गति भी काफी धीमी है, इस कारण सरकारी विद्यालयों में समय पर निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे। रमसा और सर्व शिक्षा के प्रस्तावों को स्वीकृत होने में काफी समय लगता है अत: इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें बड़े स्तर पर कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय श्रम रोजगार मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक केन्द्र कोटा में भी खोला है। साथ ही, माननीय

(श्री संदीप शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सदन में यह बोलते हुए काफी खुशी है कि आज कौशल विकास में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं और पिछले दो वर्षों में हम लगभग छह लाख युवाओं को रोजगार दे चुके हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार और हमारे तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2014 में राजकीय महाविद्यालय एवं जे.डी.बी. गर्ल्स कालेज का पुनर्गठन कर तीन नये महाविद्यालय कोटा में खोलने की घोषणा की। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दो वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभी वो जस के तस पड़े हुए हैं। वहां पर ना तो जमीन अलाट हुई है, ना उस पर कोई निर्माण कार्य चालू हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा का राजकीय महाविद्यालय और जे.डी.बी. गर्ल्स कालेज लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से कोटा में उच्च शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा है। दोनों ही कालेजों में लगभग 20 हजार विद्यार्थी वर्तमान में अध्यनरत हैं तथा लगभग 40 हजार बच्चे इनमें प्राइवेट नामांकन भरते हैं। इन कालेजों की अच्छी शिक्षण व्यवस्था एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के कारण यहां कोटा जिले के साथ-साथ हाड़ौती सम्भाग के दूर-दराज से विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन महाविद्यालयों के पुनर्गठन से कोटा जिले के साथ-साथ समूचे हाड़ौती सम्भाग की शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इन महाविद्यालय के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप इन तीनों नये महाविद्यालयों को 12 बी और 2 एफ में आवेदन करना होगा जिससे यू.जी.सी. द्वारा इन कालेज को मिलने वाली अनुदान राशि प्राप्त करने में काफी परेशानी होगी क्योंकि यू.जी.सी. ने अभी तक अनुदान राशि दी है वह संयुक्त महाविद्यालयों को दी है। अलग-अलग महाविद्यालय खुल जाने से इन दोनों महाविद्यालयों का स्वरूप और यहां की व्यवस्थाएं भी प्रभावित होंगी। महिला शिक्षा में प्रदेश में अग्रणी राजकीय जे.डी.बी. गर्ल्स कालेज और राजकीय महाविद्यालय के स्तर में गिरावट आयेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अजमेर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, भीलवाड़ा और राजकीय अन्य ...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सारा अक्षर से अक्षर पढ़ रहे हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी पढ़कर के बोल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
रहे हैं, इससे ज्यादा खस्ता हालत मैंने देखी नहीं। क्या कर रहे हो यह? शिक्षा पर बोल रहे हो, सारा ही पढ़ रहे हो। फिर टेबल ही कर दो।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): विराजें आप तो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): कोई तैयारी तो करके आओ कुछ बोलने के लिए नहीं है तो, ऐसा नहीं होना चाहिए।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): पाइंट तो देखेंगे। डोटासराजी, आप तो बार-बार उठकर...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय की जगह अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष महोदय।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): डोटासराजी, आपकी कुर्सी पर कांटे तो नहीं लग रहे आप तो विराजो, सुनो आराम से।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय सदस्य अपनी जो बात है, अपने क्षेत्र की बात है, शिक्षा विभाग की बात है वो ही तन्मयता से रख रहे हैं।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): एक बार देखेंगे, भई।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ऐसा लगता है कि कोई गम्भीर आप इस विषय में हैं ही नहीं और बिना गम्भीरता के कुछ न कुछ बोलना है, पांच मिनट हो गये, अब कुछ बोलना है तो कुछ न कुछ बोल दें।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): डोटासराजी, बार-बार उठते हो, अच्छी बात है क्या? आप वरिष्ठ विधायक हो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सदन की गरिमा क्यों समाप्त कर रहे हो?

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): आप कर रहे हो।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): सदन की गरिमा तो आप समाप्त कर रहे थे ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप और हम ही बनायेंगे। यह गैलेरी नहीं बनायेगी ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): बिना आसन की अनुमति से बोलना सदन की गरिमा को खतम करना है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सदन की गरिमा गैलेरी से नहीं बनेगी, सदन की गरिमा माननीय सदस्यों से बनेगी। (व्यवधान)

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): यह क्या है ...(व्यवधान) सब लोगों के पास संदेश जाता है यह।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): जरूरी नहीं है बार-बार बीच में बोलना। (व्यवधान) बीच में टोकना आपके लिए जरूरी नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): पहली बार राजस्थान के इतिहास में सत्ता पक्ष के सारे के सारे माननीय सदस्य लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। यह कौनसी परम्परा है?

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): यह आपका विषय नहीं है, यह आसन का विषय है।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): डोटासराजी, यह सब जगह संदेश जाता है जिस प्रकार से आप व्यवधान उत्पन्न करते हो न, यह उचित बात नहीं है। कम से कम सुनो आप, नहीं सुन सकते तो ...

**एक माननीय सदस्य**: चुप बैठे रहो।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): हां।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा सम्भाग में भूगर्भ शास्त्र राजकीय महाविद्यालय के लिए प्रवादित है और चूंकि भूगर्भशास्त्र कोटा में नहीं होने की वजह से कोटा का जो स्टोन उद्योग है, सिलिका सैंड उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, अन्य खनिज उद्योगों में रोजगार की बहुत अपार सम्भावना है, यदि यहां पर भूगर्भ शास्त्र खोला जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर एडमिशन लेंगे और उसका उपयोग ले सकेंगे। अतः मेरा निवेदन है उच्च शिक्षा मंत्रीजी से...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): खण्डेला का दे दो, हमारे खण्डेला में भूगर्भ शास्त्र इन्होंने दिया है, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, वहां साइंस है नहीं, विज्ञान का विषय है।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): यह बोल लें, साहब, बाद में बोल लेंगे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): इनको दे दो, मैं तो सीकर जिले की तरफ से पूरा सर्वसम्मति ...(व्यवधान)

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): इन्होंने पांच साल में शिक्षा को गर्त में पहुंचा दिया। अब यह कहते हैं बजट, बजट, बजट, डोटासरा साहब, अगर आप पांच साल तक इस सरकार को चला रहे थे, उस समय आपने अगर सरकार के

(श्री संदीप शर्मा)

रहते हुए जनता जनार्दन के विषय में सोचा होता तो मैं कहता हूं कि आज आप लोगों की यह स्थिति नहीं बनती जो आज 22 में यहां तीन लोग बैठे हुए हो आप।

**एक माननीय सदस्य:** आठवीं तक फेल। (व्यवधान)

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): आठवीं तक फेल, जो चाहो जो निर्णय ले रहे हैं उलट-सुलट। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल** (निवाई): और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी पढ़कर ही बोलते हैं।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): ऐसी-ऐसी यूनिवर्सिटियां खोली हैं आपने जिसमें दस बच्चे भी नहीं हैं और उसे यूनिवर्सिटी का नाम, गजब होता है। (व्यवधान) हां, चल रही है, अब बंद करायेंगे इसे ही। उसका क्या उपयोग है? पैसा खर्च कर रहे हैं जबरदस्ती का, अनाप-शनाप रेवड़ियां बंट रही हैं लास्ट में लोगों को, क्या हाल कर दिया आपने प्रदेश का। (व्यवधान) बरबाद कर दिया, यह सत्य है, साहब।

साथ ही कोटा सम्भाग के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय जे.डी.बी. गर्ल्स कालेज, कोटा में भूगोल, गृह विज्ञान, अंग्रेजी और उर्दू विषय भी नहीं हैं अतः मेरा सदन से अनुरोध है कि कोटा शहर के राजकीय महाविद्यालय वहां जे.डी.बी. कालेज में यह विषय खुलवाये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से तीन वर्ष पूर्व जब कांग्रेस का शासन काल था तो कोटा में आई.आई.टी. का पूरी तरीके से तय हो गया था कि आई.आई.टी. खोली जायेगी चूंकि कोटा पूरे देश में आई.आई.टी. के रूप में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को चयनित करके भेजता है लेकिन इन्हीं कांग्रेस की सरकार ने उसे जोधपुर में भेज दिया और आज हमारी यह स्थिति है कि हम उस आई.आई.टी. के विषय में इतना कुछ दे रहे हैं विद्यार्थी के रूप में चयनित करके, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग करने पूरे भारतवर्ष से हमारा बच्चा आई.आई.टी. पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए बच्चा कोटा आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में आईआईआईटी की घोषणा हुए तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया, आईआईआईटी की स्थापना में अभी कोई विशेष प्रगति नहीं हो पायी है। मेरा तकनीकी शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि आईआईआईटी के भवन निर्माण का कार्य, जो काफी धीमी गति से चल रहा है, वर्तमान में अभी वहां पर सिर्फ बाउंड्रीवाल हुई है, मेरा आपसे निवेदन है कि उसको तेजी से चलाया जाए क्योंकि

(श्री संदीप शर्मा)

आईआईआईटी भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने की वजह से, आई.आई.टी. चली जाने की वजह से वहां पर विद्यार्थियों में और जनता में आशंका का भय है इसलिए वहां पर इस कार्य को प्रारम्भ करा कर तेजी से आईआईआईटी का कार्य शुरू किया जाए।

इसके साथ ही वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा और उच्च शिक्षा से जोड़ने का था।आज केवल परीक्षा करवाने वाली संस्था रह गयी है, नये कोर्सेज नहीं चलाये जा रहे, शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से ऐसे विद्यार्थी और व्यक्ति जुडते हैं जो आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित रह गये हैं। इस दूरस्थ महाविद्यालय में जो फीस ली जा रही है वो भी काफी अधिक है। ऐसे प्रदेश के शिक्षा से वंचित वर्गों को दूरस्थ शिक्षा से जोड़ने का कार्य तभी सार्थक हो सकता है जब यहां पर निर्धारित फीस कम की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में देश -विदेश में अपनी एक पहचान रखता है। हर वर्ष हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक राजस्थानी संस्कृति को जानने-समझने के लिए राजस्थान आते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान संस्कृति और यहां की स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला को अभी तक राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिल पायी है जिससे यहां का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।

अत: मेरा पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन है कि विशेष प्रयासों के द्वारा अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रयास किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं एक विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा संविदा पर व्याख्याता कालेज शिक्षा में लगाये गये थे। इनकी संख्या 162 थी, इनको 7,950 रुपये का मानदेय दिया जाता था। इनमें से वर्तमान में 59 व्याख्याता ओवर एज हो गये हैं और 2008 में यह पूरी योग्यता रखते थे। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इन्हें परमानेंट करे और इस विषय में सदभावनापूर्वक विचार करे। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री भंवरसिंहजी।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे शिक्षा और संस्कृति की मांग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार।

आज सुबह ही जब मैंने अख़बार पढ़ा तो एक बहुत बड़ी खबर थी कि राज्य में शिक्षकों के 1 लाख 37 हजार 492 पद रिक्त हैं। जब मैंने विस्तार से देखा तो माध्यमिक शिक्षा में 79 हजार 378 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में 48 हजार 114 शिक्षकों के पद रिक्त बताये गये। राजस्थान में 11 हजार 212 स्कूल ऐसे हैं जहां संस्था प्रधान नहीं हैं। बिना इंचार्ज के वह स्कूल चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, शिक्षा मंत्रीजी ने आदर्श विद्यालय तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बना दिये। लेकिन उन आदर्श विद्यालयों की स्थिति आज यह है कि जुलाई में शुरू हुए सत्र में जिन बच्चों ने नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं में दाखिला लिया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए व्याख्याता की आवश्यकता होती है, लेकिन राजस्थान के 50 प्रतिशत के लगभग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के, वरिष्ठ अध्यापकों के, प्रधानाध्यापकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षाएं चालू होने वाली हैं। दसवीं बोर्ड की परीक्षाएं चालू हो गयीं, बारहवीं की भी हो रही हैं। लेकिन उस विद्यालय के परिणाम के बारे में सोचिए, जिसमें किसी भी विषय का व्याख्याता नहीं है और वह छात्र परीक्षा में बैठ रहा है। उसके परिणाम की कल्पना यदि हम आज इस सदन में बैठकर के सही मन से करें तो मैं समझता हूं कि उस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में वर्ष 2012-13 में 40 हजार शिक्षक लगाये गये। उन 40 हजार शिक्षकों को सेवा करते हुए, स्कूलों में पढ़ाते हुए आज 37 महीनों से भी ज्यादा का समय हो गया, 2 साल के बाद सरकारी नौकरी में लगने वाले किसी भी कर्मचारी को कन्फर्म कर दिया जाता है, उसे पूरी तनख्वाह दी जाती है लेकिन राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं, आप बीकानेर पधारे थे तो उन 40 हजार अध्यापकों ने आपके सामने प्रदर्शन किया, मांग की, आपकी गाडी के आगे लेट गये, लेकिन शिक्षा मंत्रीजी को दया क्यों नहीं आ रही है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

10 हजार रुपये में किसी भी शिक्षक का क्या परिवार चल सकता है?

(श्री भंवरसिंह)

उसने क्या गुनाह किया है सरकारी नौकरी में आने का, संविदा का जो समय होता है कन्फर्मेशन का, उससे डबल टाइम होने के बाद भी उन 40 हजार थर्ड ग्रेड शिक्षकों को कन्फर्म करने का आदेश नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई शोषण नहीं हो सकता है सरकारी कर्मचारी का।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2013 में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती की परीक्षा 2015 में हुई और परिणाम जून, 2015 में आया। उसके बाद 7 अक्टूबर, 2015 को कोर्ट का स्टे आ गया, 7 जनवरी, 2016 को कोर्ट का स्टे हट भी गया। मूल दस्तावेजों का सत्यापन 14 जनवरी, 2016 को बीकानेर में हो गया। विभागीय मेल पर जिलों की प्राथमिकता भी उन शारीरिक शिक्षकों से मांग ली गई। लेकिन आज 58 दिन से वह राजस्थान के थर्ड ग्रेड और सैकिण्ड ग्रेड के 4 हजार शारीरिक शिक्षक बीकानेर शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे हैं। पिछले 10 दिनों से उनमें से बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षक जो प्रतीक्षा में हैं, वह अनशन पर भी बैठे हैं। कई लोगों को वहां के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। मैं समझता हूं कि जो बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं, जो लम्बे समय से प्रतीक्षा में हैं कि हमें सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिलेगा, उनकी माननीय शिक्षा मंत्रीजी नहीं सुन रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इन बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को जो धरने पर बैठे हैं, जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी पुकार सुनिये और उनको सरकारी सेवा में लेने का आदेश करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अगस्त, 2007 में पूरे राजस्थान में शिक्षकों की कमी होने की वजह से, उस समय 2003 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के रहते हुए आपके शिक्षा मंत्रीजी ने राजस्थान में विद्यार्थी मित्रों को लगाने का आदेश सभी तरह की स्कूलों में दिया था। वह विद्यार्थी मित्र 2007 से लेकर 2014 तक इस उम्मीद में काम करते रहे कि शायद सरकार उनकी तरफ कभी देखेगी और उन्हें नियमित करेगी या उनका कोई कैडर बनाया जायेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में विद्यार्थी मित्रों को, कम्प्यूटर शिक्षकों को और शिक्षा कर्मियों को समायोजित करने का लिखा होने के बावजूद भी, इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने अप्रैल, 2014 में एक आदेश निकालकर के राजस्थान के 24 हजार से भी अधिक विद्यार्थी मित्रों को घर भेजने का आदेश दे दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में जब ज्यादा विरोध हुआ, पूरे राजस्थान से आवाज आई कि इन

(श्री भंवरसिंह)
विद्यार्थी मित्रों को समायोजित किया जाए तो एक विद्यालय सहायक का कैडर बनाया गया। लेकिन उसे भी कोर्ट की पेचीदगियों में लटका दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन 24 हजार विद्यार्थी मित्रों में से 12 हजार विद्यार्थी मित्र ऐसे हैं जिन्होंने बी.एड. और एस.टी.सी. की ट्रेनिंग भी कर रखी है। वह पूरी तरह से अध्यापक की पात्रता भी रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से करबद्ध निवेदन है कि इन विद्यार्थी मित्रों को जो पूरे राजस्थान से आवाज आ रही है, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी लोगों ने विद्यार्थी मित्रों को राजकीय सेवा में लेने की बात कही है और सरकार को आवश्यकता भी है, इसलिए इनका समायोजन भी आने वाले शैक्षणिक सत्र से पहले-पहले किया जाये। यह मैं मांग करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि विद्यालयों का एकीकरण किया गया। शिक्षकों की कमी के लिए आपने पिछली सरकार पर काफी आरोप लगाये। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारी 1998 से लेकर के 2003 तक जब सरकार थी तो राजस्थान के दूरदराज के गांव और ढाणियों में लोगों को, उनके परिवार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 18 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं। आज वह पाठशालाएं अच्छी स्थिति में चल रही थीं। उनमें थोड़ी-थोड़ी संख्या में गांव और ढाणियों में बच्चे पढ़ रहे थे। 2008 से 2013 तक भी जब कांग्रेस की सरकार रही तो हजारों की संख्या में नये प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया और खोला गया। आपकी जब सरकार आई 2013 में, भारतीय जनता पार्टी की तो, सबसे पहले आपने जो काम किया माननीय शिक्षा मंत्रीजी, राजस्थान के 17 हजार विद्यालयों को एकीकरण के नाम पर बंद करने का आदेश आपने दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन 17000 विद्यालयों को बंद करने के बाद जो करोड़ों रुपये एक-एक विद्यालय की लागत होती है, आप आज उन विद्यालयों की हालत जाकर देखिए, लोग खिड़कियां और दरवाजे उतारकर ले जा रहे हैं। वह भवन धीरे-धीरे खण्डहर बनते जा रहे हैं। राजस्थान में बरसों से जिस प्रकार से परिसम्पत्तियां बनी हैं, आज उन परिसम्पत्तियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता

(श्री भंवरसिंह)

उन 17 हजार का दर्द भूली ही नहीं थी कि इन्होंने 2016-17 में भी साढ़े चार हजार विद्यालय बंद करने की तैयारी कर ली है। इन्होंने 15 से कम नामांकन वाले विद्यालय बंद कराए जाने की आगामी सत्र में शुरूआत की है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो छात्र संख्या का आंकड़ा आपने जुलाई से सितम्बर का लिया है, मैं मेरे बीकानेर जिले और पश्चिमी राजस्थान की बात करना चाहूंगा कि जुलाई में बरसात का समय होता है और अधिकांश लोग जो गांवों में रहते हैं वह बरसात के समय खेतों में चले जाते हैं और उनके बच्चों का जो नामांकन है वह नहीं हो पाता है। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि 15 से कम के नामांकन वाले आपने जो साढ़े चार हजार विद्यालय चिन्हित किए हैं उन विद्यालयों की आप एक बार पुन: अक्टूबर के बाद का जो नामांकन है उसकी सूची मंगवाइये और उस छात्र संख्या के अनुसार विद्यालय एकीकरण की बात करिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिन विद्यालयों में 15 से कम नामांकन हैं उन विद्यालयों को एक मौका और दिया जाए। उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यह कहा जाना चाहिए कि आने वाले समय में छात्र संख्या बढ़ जानी चाहिए, और यदि छात्र संख्या फिर भी नहीं बढ़ती है तो इन स्कूलों को बंद किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' का नारा देने वाली यह सरकार, इन्होंने राजस्थान में एक भी बालिका विद्यालय नहीं खोला और अब यह जो एकीकरण की बात कर रहे हैं उसमें राजस्थान में जो साढ़े चार हजार स्कूल, 4441 विद्यालय बंद होने जा रहे हैं उसमें बीकानेर जिले में 20 बालिका विद्यालय हैं जो सिर्फ और सिर्फ बालिकाओं के हैं। इन बालिका विद्यालयों को बंद करने की इन्होंने तैयारी कर ली है। एक तरफ तो ये बालिकाओं को पढ़ाने की कहते हैं और दूसरी तरफ बालिका विद्यालय बंद करने की बात की जा रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप सचेतक महोदय सत्ता पक्ष में माननीय सदस्यों को ढूंढ रहे हैं कि कोई बोलने वाला भी है क्या सत्ता पक्ष से। (व्यवधान) हम हैं न, हम बोल लेंगे आप क्यों चिंता क्यों करते हो? (व्यवधान) अगर कोई नहीं बोलना चाहता शिक्षा पर, हम हैं न बोलने के लिए। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि इनके खुद के वालों की तो गिनती का पता ही नहीं है, 21 से 20 हो गये और बैठने को 10 ही नहीं है और हमारी संख्या जो 100-200 के आसपास आ रही है और अभी हाउस में भी 90 के आसपास है उनकी यह चिंता कर रहे हैं, यह कौन से प्रोविजन में चिंता जाहिर कर रहे हैं। (व्यवधान) अपने खुद के गिरहबान में झांककर देखो तो सही पहले। क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, कहां बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? फिर दूसरों की चिंता करो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): गिरहबान के लिए ही कह रहा हूं कि आप अपने गिरहबान में झांको ...(व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): पहले आप अपने गिरहबान में झांको। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कोई बोलने वाला माननीय सदस्य नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) आप आग्रह कर रहे हो कि आप हमारी इज्जत रखो, बोलो आप। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): हम आपकी तरह हर कुछ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं व्यवस्थित बोलते हैं और क्रम में बोलते हैं और आसन की परमिशन से बोलते हैं आपके जैसे नहीं कि जब मर्जी आए तब खड़े हो गए यूं ही। (व्यवधान)

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब किसी भी मंत्री के यहां क्वेश्चन लगाते हैं तो एक ही जवाब आता है कि फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है। फिर सरकार किस काम की चल रही है, कोई फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): सरकार तो ऐसे ही चलेगी, बढ़िया चलेगी, जोरदार चलेगी, बार-बार चलेगी।

**श्री गिर्राज सिंह** (बाड़ी): किसी भी मंत्री के यहां से जवाब आता है तो यही आता है कि फाइनेंस की व्यवस्था नहीं है। फिर आप यहां ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? इस नौटंकी को बंद करके बैठ जाओ। (व्यवधान)

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): हाउस में कितने दिनों बाद आए हो।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी ही हास्यास्पद बात है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** आसन की बगैर इजाजत से जो कोई भी माननीय सदस्य बोला, वह अंकित नहीं होगा।

कम से कम आप अंतर्यामी होने का तो प्रयास न करें। (व्यवधान)

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले गए हैं, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इन्होंने जो शुरूआत की है उसमें जो नई पंचायतें बनी हैं या जो वंचित रह गई हैं उन ग्राम पंचायतों के विद्यालयों को भी उच्च माध्यमिक विद्यालय तक क्रमोन्नत किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बजट में पढ़ा कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने अलग-अलग जिलों में संकाय खोलने की व्यवस्था की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार देखने को मिला है कि बीकानेर जिले में 2, सीकर में 3, जालौर में 4, इस तरह से संकाय खोलने की घोषणा होते हुए बजट में मैंने पहली बार देखी है। उसमें भी 2-2, 3-3 संकाय पूरे जिले में खोले गए हैं। 200-200 विद्यालय एक-एक जिले में हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और 2 संकाय खोल रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में नए संस्थान, मैं समझता हूं कि कोई खोले नहीं गए और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो संस्थान खोले गए थे, चाहे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की बात करें चाहे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर की बात करें, चाहे राजस्थान के अलग-अलग उप खण्ड मुख्यालयों पर खोले गए कालेजों की बात करें, उन सबको बंद करने का काम किया है तो हमारे सामने विराजे हुए माननीय मंत्रीजी ने और इनकी सरकार ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर के सम्बन्ध में कुछ बात रखना चाहूंगा। इस बजट में तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में खोला जाना, दोबारा प्रस्तावित किया गया है। मेरा कालीचरणजी सराफ से आग्रह रहेगा कि आपने बीकानेर की जनता के लिए यह घोषणा की है लेकिन इस तकनीकी विश्वविद्यालय को कहीं आप दो साल बाद खोलें तो इससे कोई अभिप्राय नहीं रहेगा। जुलाई के सत्र से आप तकनीकी विश्वविद्यालय को चालू कराएं। 46 महाविद्यालयों में से मेरे कोलायत का जो महाविद्यालय है, कालेज है, जो राजकीय महाविद्यालय है उसको भी समीक्षा कमेटी में ले रखा है। मेरा मंत्री महोदय से करबद्ध आग्रह रहेगा कि कोलायत विधान सभा क्षेत्र 200 किलोमीटर

(श्री भंवरसिंह)

से भी ज्यादा के दायरे में फैला हुआ है और आपने कहा है कि हम पक्ष और विपक्ष, सबको साथ लेकर चलेंगे। तो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जब आज घोषणा करें तो कम से कम कोलायत के राजकीय महाविद्यालय को खोलने की घोषणा करे, यह पूरी कोलायत की जनता आपसे उम्मीद करना चाहेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बीकानेर में स्टेट के टाइम से, आजादी के बाद से शिक्षा निदेशालय खोला गया लेकिन बीकानेर का शिक्षा निदेशालय नाममात्र का रह गया है। वहां जो भी डाइरेक्टर लगाये जाते हैं, वह महीने में 5 दिन बीकानेर रहते हैं और 25 दिन जयपुर रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का अभिप्राय यह रहेगा कि बीकानेर में जो निदेशालय है, जिन्हें निदेशक लगाया जाता है उन्हें पाबंद किया जाए कि बीकानेर में जो निदेशालय है चाहे माध्यमिक का है चाहे प्रारम्भिक का है, दोनों बीकानेर में रहें। हमें यह लग रहा है कि धीरे-धीरे कहीं बीकानेर के निदेशालय को जयपुर शिफ्ट करने की कोई साजिश तो नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपके घोषणा पत्र में यह साफ-साफ लिखा गया था कि बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय और महारानी सुदर्शना महाविद्यालय जो पूरे सम्भाग के सबसे बड़े कालेज हैं, इन दोनों कालेजों को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का संघठक महाविद्यालय बनाया जाएगा। ढाई साल का समय हो गया लेकिन अभी तक इन दोनों कालेजों को संघटक महाविद्यालय बनाने की तरफ मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपके सुराज संकल्प पत्र में भी यह बात लिखी गई है। इसके अलावा राजस्थान का जो एकमात्र शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर में है, पूरे राजस्थान में एकमात्र स्पोर्टस स्कूल है, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की थी लेकिन ढाई साल से उस शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल की तरफ सरकार ने देखा नहीं है, एक पैसे का कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया है। मेरा आग्रह रहेगा कि उस शार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल का दोबारा जीर्णोद्धार करवाया जाए। इसके अलावा बीकानेर संभाग में जो उप निदेशक कार्यालय अभी चूरू में है उसको बीकानेर में खोलने की मौखिक तौर पर माननीय देवनानीजी, शिक्षा मंत्रीजी ने बीकानेर प्रवास के दौरान सहमति भी दी थी। लेकिन इस बजट में घोषणा नहीं की गयी है। मेरा निवेदन रहेगा कि बीकानेर में उप निदेशक कार्यालय (प्रारम्भिक) खोला जाय। माडल स्कूल

(श्री भंवरसिंह)

में मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो माडल स्कूल खोला जाना है वह अभी तक नहीं खोला गया है, झज्जू में प्रस्तावित किया गया है, लेकिन उस माडल विद्यालय को खोला नहीं गया है। अत: मेरा आग्रह रहेगा कि माडल विद्यालय भी खोला जाय। आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

**श्री उपाध्यक्ष:** वैसे आप सबके मन में जो संशय है उसको दूर कर दूं। अभी तो 12 माननीय सदस्यों के बोलने की सूची सत्ता पक्ष की और है। इसलिए यदि आप यह सोच रहे हैं कि इनके पास बोलने वाले नहीं हैं, ये तो बड़े धैर्य से आपको समय दे रहे हैं वरना आपका समय तो...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): अभी आदरणीय मानिकजी ने बताया था कि उनकी पत्नी बीमार है, उनको अभी होस्पिटल जाना है इसलिए पहले उनको बोलना था। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे दो-तीन बोल दें उसके बाद बोलो, लेकिन उन्होंने कहा मैं घर चला जाऊंगा, तब मैंने यह बात कही।

**श्री उपाध्यक्ष:** अब आपने देखा कि कितने संवेदनशील हैं उप सचेतक महोदय। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): डोटासरा साहब को बड़े ह्रदय से कहना चाहिए कि मुझे मिसइंफार्मेशन थी कि बोलने वाले नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 पर बहस है। मांग संख्या 24 में हमारे राजस्थान का पूरा राजस्व जो 1 लाख 23 हजार करोड़ का है उसमें से 23 हजार करोड़ माननीय कालीचरणजी सराफ और माननीय देवनानी साहब के पास वह विभाग है जिसमें यह खर्च होना है। राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग है। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की इस बजट में घोषणा करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि गत वर्ष 2014-15 का जो बजट था उसमें तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए पूरा प्रावधान था, उसके खर्चे का जितना भी प्रावधान बजट में था। मैंने बहस में उसका पेज और जिस पर वह कोटेड है बजट के कागजों में, वह भी मैंने आपको कोट किया था। यह जो विश्वविद्यालय बंद हुआ यह वास्तव में बंद

(श्री मानिक चन्द सुराना)

होना ही नहीं चाहिए था, पर मैं इसको सिल्वरलाइनिंग मानता हूं कि हमने गत वर्ष बंद किया और इस साल खोला। यह सही है कि बीकानेर शहर में प्रबल मांग उठी और सब तरफ से उठी। वह आम जनता की मांग बनी और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब 25 जनवरी को बीकानेर आये, 26 जनवरी के पहले और उन्होंने जन-प्रतिनिधियों को बुलाया तो जन-प्रतिनिधियों ने भी एक स्वर से इस तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रकरण रखा। मुझे खुशी है कि उस प्रकरण को रखे जाने के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया और उसमें उसके खोलने की घोषणा हुई है। हमारे कोलायत के माननीय सदस्य को यह शंका है कि यह दो साल बाद खुले। दो साल का प्रश्न नहीं है, यह घोषणा इस वर्ष की है और मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी का काम है कि इसका स्पष्टीकरण करें। मेरा विश्वास है कि यह जून-जुलाई में खुलना तय है और इसके लिए दो-ढाई करोड़ के बजट के लिए कोई परेशानी नहीं है, जिसके पास 1 लाख 23 हजार करोड़ है उसके लिए कोई परेशानी इसमें आने वाली नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का शिक्षा का रिकार्ड है, मैंने एक सवाल 2014 में पूछा था जब शिक्षा मंत्री कालीचरणजी सराफ थे कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में कितनी वैकेंसीज हैं और किस-किस ग्रेड की हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, फर्स्ट ग्रेड, सैकिण्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, क्लर्क, शारीरिक शिक्षक भी। मुझे अच्छी तरह से याद है आपने 70 हजार का आंकड़ा बताया था। सन् 2015 में जब मैंने सवाल पूछा जिसका जवाब 2015-16 में आया, सम्भवत: जनवरी में। माननीय देवनानी साहब ने कहा कि 76 हजार की वैकेंसी है। मैं समझता हूं कि मेक्रो लेवल का काम तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास में है, क्योंकि कितनी स्कूलें खोलनी हैं यह घोषणा मुख्य मंत्रीजी करेंगी, पर उनकी जो घोषणा हुई कि 5 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हैं वह श्रेय तो उनको जा ही रहा है, पर उन 5 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मैनेज करने का काम आपका है, आपका पहले था और अब माननीय देवनानी साहब का है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बात को भूल जाएं, ये दोनों विधान सभा में मंत्रीजी के उत्तर हैं 70 हजार, 76 हजार। आपको कोई प्रश्न की कापी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा मैं दोनों माननीय मंत्रियों को दे दूंगा। आप यह बताएं कि आज दो वर्ष तीन महीने पूरे हो गये, दिसम्बर को ध्यान में रखें, विधान सभा समाप्त होगी तब तक दो वर्ष चार महीने पूरे हो जाएंगे। मैं फिर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अगस्त-सितम्बर में सवाल पूछने वाला हूं कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि मुझे ध्यान है कि 15 हजार थर्ड ग्रेड टीचर आ रहे हैं, कुछ और टीचर्स की भर्ती हो रही है। मेरा निवेदन होगा कि यदि अगले वर्ष तक यह आंकड़ा, जो 70 हजार आपने बताया था वह 35 हजार पर नहीं आता है तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, यह रिक्त पदों का आंकड़ा आप दोनों के लिए ही शुभ नहीं होगा और न राजस्थान की जनता के लिए शुभ है। मैंने माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बीसों पत्र भेजे हैं अनेक-अनेक गांवों के और यह कहा है कि यहां उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12 पद हैं और मौके पर तीन हैं। बाकायदा प्रिंसिपल से सर्टिफाइड कराकर भेजे हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि 12 पद हैं और वर्तमान में 3 हैं। ऐसे मेरे बीसों पत्र बराबर मंत्रीजी को जा रहे हैं। मुझे पता नहीं, उसको कौन हैण्डल करता है। कोई हैण्डल करे जिम्मेदारी आपकी है कि आपको यह सूचना मिलने के बाद में, साबनिया तो अनुसूचित जाति का गांव है। आज तो कम्प्यूटराइज्ड युग है। आप अपने कागजों में नोट करें कि कौन-कौन से गांव अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रमुख गांव हैं, कौन-कौन से पिछड़े वर्ग बाहुल्य के गांव है। मेरा निवेदन है कि इन रिक्त पदों की समस्या का आप समाधान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 80 हजार सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्ध संस्थाएं हैं। पिछले 3-4 साल से एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है, हमारी स्कूलों में एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। देश के अनेक प्रान्तों में एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी कोर्स पढ़ाने के अच्छे नतीजे हुए हैं कि हमारा विद्यार्थी किसी भी प्रान्त में जाकर भर्ती हो तो उसकी कोर्स बुक्स नहीं बदलती, उसका कोर्स नहीं बदलता चाहे हिन्दुस्तान का आदमी किसी भी कारण से राजस्थान आये, क्योंकि देश में मूवमेंट फ्री है कांस्टीट्यूशन के अनुसार, वह यहां आएगा तो उसके बच्चों को परेशानी नहीं होगी और वे उसी पाठ्यक्रम को पढ़ लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 9 लाख विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने भी बहुत प्रयत्न किया है और उन प्रयत्नों के लिए तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि हमारे विद्यार्थियों की अंकन की संख्या है छात्र-छात्राओं की उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ समाचार आ रहे हैं। इस एनसीईआरटी की 50 हजार टैक्स्ट बुक्स आपके बोर्ड में पड़ी हैं और जानकारी यह आ रही है कि कोई नया पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है और नया पाठ्क्रम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आने वाले साल, दो साल में लागू किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं पर मेरा निवेदन यह है कि जब भारत में भी भाजपा की सरकार है, आपको यदि पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव कराना है, आपको अकबर को ड्राप करना है, महाराणा प्रताप को पढ़ाना है तो आप एनसीईआरटी के कोर्सेज में ही बदलाव कराइये ना, आज तो आप सक्षम हैं। जिस विचाराधारा की सरकार यहां है उसी विचारधारा की सरकार दिल्ली में है। मेरा निवेदन होगा कि पाठ्य पुस्तकों को बदलने में जल्दबाजी न करें। जो नई पाठ्य पुस्तकें आपने प्रस्तावित की हैं उनको विद्वतजनों से दिखवाइये, शिक्षाविदों से उनको दिखवाइये, जो कोर्स के प्रकांड पंडित हैं उनको दिखवाइये। जो सूचना मुझे मिली है वो कुछ खतरनाक है।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): शिक्षा का भगवाकरण नहीं हो, राष्ट्रीयकरण हो।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): बिलकुल, बिलकुल। नहीं, भगवाकरण हो रहा है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं पर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण क्या है, मेरी समझ से परे है। (व्यवधान) शिक्षा का तो विद्या प्राप्त करने में न राष्ट्रीयकरण का कोई मुद्दा है और न कोई फिलहाल भगवाकरण का मुद्दा है। मुद्दा यह है कि जो पाठ्य पुस्तकें भारत सरकार द्वारा और जिसका नेतृत्व आज स्मृति ईरानी कर रही हैं उनके सब जगह लागू है उसको हम क्यों बदल रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जो बदलाव आ रहा है उसमें मुझे जानकारी मिली है कि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' जो महान् साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई और देश के बड़े-बड़े कवि, उनके नाम तो हटाये गये हैं, उनके नाम हटाये गये या उनका पाठ्यक्रम में हटाया गया और कुछ कम महिमामंडित लोगों को उसमें डाला गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी से, चाहे वो नहीं हैं, मेरा उनसे निवेदन होगा कि पाठ्यक्रमों को बदलने के पहले राज्य सरकार की कैबिनेट किन्हीं विद्वतजनों को अपाइंट करे, सारे पाठ्यक्रमों को एग्जामिन करे और उसके बाद ही उसमें कोई बदलाव करे। बदलाव यदि भारत सरकार के स्तर से करवा लें तो मैं समझता हूं कि वो सर्वोत्तम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बहुत अच्छे नवाचार हमारी सरकार ने किये हैं। वर्तमान सरकार ने किये हैं, हमारी सरकार तो मुंह से निकल गया है क्योंकि भाजपा में रहे हैं इसलिए गलती से निकल गया है। भाजपा के फ्रिंज पर तो हम भी हैं, वैचारिक भाजपा हम भी हैं वो आपको ध्यान भी होगा और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप ट्रांसपोर्ट वाउचर जो लड़कियों को दे रहे हैं नवीं क्लास में कि माध्यमिक स्कूल में जाकर वो पढ़ ले बहुत सही बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब शिक्षा का प्रसार करना है, मेरा एक गांव है रानीसर, रानीसर की लड़कियां तो जाकर सेरेना पढ़ ले और रानीसर का लड़का, उसके परिवार को वो सुविधा नहीं मिले कि वो भी पढ़ ले। तो मैं मांग करना चाहूंगा कि यह लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है तो बिलकुल करिये, उनको कोई वजीफा बढ़ा दीजिये पर ट्रांसपोर्ट वाउचर जो उसको एनेबल करता है कि पढ़ो, 6-7-8 किलोमीटर की स्कूल में जाकर वो उच्च माध्यमिक का कोर्स पढ़ ले, निश्चित रूप से आप लड़की को दे रहे हैं तो लड़के को भी दीजिये। सरकार गरीब नहीं है। आपको कोई वहम् हो गया क्या हमारे कुछ मित्रों के कहने से या पत्रिका में खबर छपने से कि साहब 50 करोड़ है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का खजाना कभी खाली नहीं होता और जिसके पास 1 लाख 23 हजार करोड़ साल में आने हैं, 500 करोड़ रोज आना है, 10-12 हजार करोड़ हर महीने में आना है उसके खजाने को आप आज की बैलेंस शीट से न मापें।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): वो जा कहां रहे हैं? इनसे पूछों कि वो जा कहां रहे हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): वो बजट है न 1 लाख 23 हजार करोड़ का, पढ़िये उसको कि वो कहां जा रहे हैं। वो 23 हजार करोड़ रुपये तो ये कालीचरणजी और देवनानीजी ले जा रहे हैं। आप रोक लीजिये रोकना हो तो। वित्त मंत्री के जेब में कुछ नहीं होता है, आज के वित्त मंत्री की जेब में कुछ नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आप सफल वित्त मंत्री रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी ने आपको फिर भी टिकट नहीं दिया।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): क्या?

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सफल वित्त मंत्री रहे हैं फिर भी पार्टी ने नाइंसाफी की, टिकट नहीं दी और फिर भी जीतकर आ गये।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): चलो कोई बात नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ट्रांसपोर्ट वाउचर लड़कों को भी दीजिये। आपने जो आदर्श विद्यालय खोले हैं, कालीचरणजी साहब, आपको याद होगा कि समानीकरण और एकीकरण का मुद्दा हुआ तो आपने अर्जेंट मीटिंग बुलाई। हम लोग उसमें आये, आपने सब विधायकों को

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बुलाया, डिवीजनवाइज बुलाया या किस तरीके से भी बुलाया, हम लोग उसमें हाजिर थे, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू सभी थे। पर एकीकरण में जो आदेश आपने भी दे दिये उन आदेशों की पालना नहीं है। खारड़ा में संस्कृत विद्यालय डोनेशन से बनी हुई है, खारड़ा गांव मेरे लूणकरणसर क्षेत्र का गांव है और मैं आपको दो बार पत्र दे चुका हूं। आपने बराबर संस्कृत शिक्षा डायरेक्टर साहब को भेजा। कौनसे कुएं में जाकर के वो कागज पड़ रहा है? संस्कृत शिक्षा के डायरेक्टर साहब क्यों उसको इग्नोर कर रहे हैं? आखिर दो साल हो गये, मंत्रीजी का आदेश हो गया कि बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं खुल रहा है? मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं पर मैंने एक उदाहरण दिया है आपको। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लूणकरणसर की बालिका विद्यालय, माननीय देवनानीजी, उसके लिए भी आदेश हुआ था कि यह डोनेशन से बनी हुई है इसलिए बन्द नहीं होगी पर आज तक बन्द पड़ी है। इस तरह के जो भी उदाहरण हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह बहुत हैवी डिपार्टमेंट है शिक्षा का इसलिए एक नहीं, दो कैबिनेट मंत्री लगाइये। एक नहीं, देवनानीजी जैसे दो लोगों को लगाइये। उनके काम का बंटवारा कर दीजिये। शिक्षा का काम ही इतना फैला हुआ है कि जब मई-जून आयेगी तो देवनानी साहब के पास तो कोई 50 हजार, 80 हजार प्रार्थना पत्र ट्रांसफर के आयेंगे। उनको हैंडल करने के लिए एक नहीं, दो मंत्री देवनानी साहब जैसे चाहिए। मेरा मतलब है कि जितना वर्क लोड है.....

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपको इनकी सक्षमताओं पर संदेह है क्या? इनकी सक्षमता पर आपको संदेह है क्या? ये एक नहीं, ऐसे तीन-तीन डिपार्टमेंट हैंडल कर सकते हैं। ये प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर हैं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): इनकी सक्षमता पर संदेह नहीं है पर श्रीमान् राजेन्द्र सिंहजी, वर्क लोड इतना है कि it justifies handling by an equally important person like Shri Devnani ji. अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): पर साहब इन्होंने करके दिखाया है। राठौड़ साहब, सही कह रहे हैं कि करके दिखाया है। कालीचरणजी को शिक्षा मंत्री हटा दिया और अब देवनानीजी का नम्बर है क्या?

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): थोड़ा इंटरवीन नहीं करें तो मैं बोल लूं। मैं भी जल्दी में हूं और सदन भी जल्दी में है। जो स्कूलें बन्द हो रही हैं जिनका जिक्र अभी कोलायत के साथी ने किया.....

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): मानिक चन्दजी का सुझाव मान लिया और शिक्षा विभाग के दो विभाग कर दिये, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा तो मेरे को दे दी और बाकी शिक्षा उनको दे दी। इसमें हटा दिया और लगा दिया यह आपके यहां होता है, हमारे यहां नहीं होता है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): मेरा यह निवेदन है कि वर्क लोड को देखते हुए, आखिर 80 हजार दरख्वास्तें कोई माननीय देवनानी साहब पढ़ रहे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं। देवनानी साहब उसमें से जिस्ट पढ़ रहे हैं उसके बाद उनका जो भी आफिस है वो उसको हैंडल कर रहा है। हम यही कह रहे हैं कि यह जो समानीकरण हुआ, एकीकरण हुआ, दो स्कूलें बंद हो रही हैं, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्षजी, मुझे थोड़ा समय चाहियेगा, जो स्कूलें बन्द हुई हैं उनका आप पुनः परीक्षण करें। जो निर्णय आपने लिये हैं उनकी क्रियान्विति नहीं हुई है इसलिए इसको देखें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर में आप जब उसको नया रूप देंगे, नया एक्ट लायेंगे, मेरा निवेदन है कि उस एक्ट को इसी सत्र में लाइये। अनेक बार इसी सत्र में बिल आते हैं और एक्ट बनता है। एक्ट बने बिना हमारा विश्वविद्यालय आर्डिनेंस की भेंट चढ़ गया था ध्यान करिये, आर्डिनेंस की भेंट चढ़ गया था जो आर्डिनेंस इनकी सरकार ने जारी किया था। (व्यवधान) सुनिये, सुनिये। उस आर्डिनेंस की तारीख खतम हो गई थी, आपने अक्टूबर में किया। जब घोषणा आपकी बजट में हो गई तकनीकी विश्वविद्यालय की तो आपने एक्ट क्यों नहीं बनाया? आपकी भूल है और आपकी सरकार कोटा के शांती धारीवाल के दबाव में थी इसलिए उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आपने एक्ट नहीं बनाया।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी कोटा के माननीय विधायक ने कहा है कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय का औचित्य नहीं है, हमने अखबारों में पढ़ा है। कहीं यह सरकार भी भवानी सिंहजी राजावत के दबाव में नहीं आ जाए।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): भवानी सिंहजी का कोई दबाव नहीं है।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): नहीं, वह बोले हैं कोटा में। अख़बार में आया है कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अभी भी बजट में प्रस्तावित ही लिखा है, खोली नहीं है। प्रस्तावित ही है इस बजट में।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): आपके चाहने या ना चाहने के बावजूद खुलेगी और इसी सत्र में खुलेगी। यह मामला बीकानेर का है, सीकर का नहीं है, बंधु।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन): कोटा और बीकानेर के बीच में मारवाड़ जंक्शन है, वहां खोलो। दोनों के सेंटर में है, दोनों का झगड़ा मिट जायेगा।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): मैं अर्ज करूंगा। बात कहने दो। उपाध्यक्ष महोदय, एक मामला मैंने वर्ष 2014 के बजट में उठाया था, शायद आपको ध्यान होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट आप विराज जायें हुकुम। आप लोगों को आसन की भी आवश्यकता है या नहीं है? करीबन सारे दिन भर से मैं यह देखता आ रहा हूं और मुख्य सचेतक, आपको भी मैं निवेदन कर रहा हूं, आसन की आवश्यकता है आपको?

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): बिलकुल आवश्यकता है, मैं इसीलिए प्रस्ताव रख रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: रखो।

# सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग पूरी होकर पारित होने तक, मंत्रीजी का जवाब आने के बाद मांग पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाये।

**श्री उपाध्यक्ष**: क्या सदन आसन को यह आश्वस्त कर सकता है कि आप विवेक से, माननीय सदस्यों का ध्यान रखते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, इस सदन का समय बढ़ाने का आसन आपको आग्रह कर ले?

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग के पारण होने तक समय का समय बढ़ाया जाये?

**(स्वीकृत)**

समय बढ़ाया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना।

# अनुदान की मांग

# मांग संख्या 24 पर विचार

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय,...

**श्री उपाध्यक्ष**: अब कन्क्लूड कर रहे हैं आप because it's more or less around twenty five minutes since you have been speaking.

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): मैं निवेदन कर रहा हूं, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप ध्यान दें। राजस्थान नोलेज कारपोरेशन लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है। इसमें जब कम्पनी प्रमोट हुई तो 30 परसेंट शेयर तो जो महाराष्ट्र की कम्पनी थी, जिसका नाम राजस्थान में आने से राजस्थान नोलेज कारपोरेशन लिमिटेड हुआ, जो महाराष्ट्र में फंक्शन कर रही थी और वही उसके डाइरेक्टर्स थे। उन्होंने इसको इन्कोरपोरेट किया और 30 परसेंट राजस्थान सरकार, 10 परसेंट वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय, 10 परसेंट शेयर राजस्थान विश्वविद्यालय, 10 परसेंट शेयर महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय।

मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से एक ही प्रश्न पूछता हूं कि क्या कारपोरेट वर्ल्ड में रुपया लगाने की और रुपया नियोजन करने की विश्वविद्यालय को छूट है? आज उन्होंने नोलेज कारपोरेशन में लगाया, कल रिलायंस में लगायेंगे। आप कैसे रोकोगे? आपने लक्ष्मण रेखा तोड़ दी उच्च शिक्षा मंत्रीजी। विश्वविद्यालयों का काम रुपया लगाना नहीं है। मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आपको 30 परसेंट रुपया लगाने की कहां जरूरत है? आपके 30 परसेंट रुपया लगाने और 10-10 परसेंट तीन विश्वविद्यालय, नामी विश्वविद्यालयों के रुपया लगाने से वह कम्पनी, जो कम्पनीज एक्ट के तहत आज भी गवर्नमेंट कम्पनी नहीं है। गवर्नमेंट कम्पनी के लिए 51 परसेंट शेयर राज्य सरकार के चाहिए। वह अपने आपको गवर्नमेंट की प्रमोटेड कम्पनी कहती है। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी से कहता हूं, आपको मोनोपोली क्रिएट करनी है तो बजरी के खनन में करिये, आपको 2,000 करोड़ रुपये आएगा और यह जो 10-10 रुपया आपको जो मिल रहे हैं। आपने ऐसी कम्पनी बना दी, जिसने सिर्फ तीन महीने का आरएस-सीआईटी का कोर्स बनाया और राजस्थान के सभी विभागों में आदेश हो गये कि आरएस-सीआईटी पास, तीन महीने का ट्रेनिंग किया हुआ, तीन महीने का आरएस-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सीआईटी के सर्टिफिकेट वाला आदमी सरकारी नौकरी में आने के योग्य होगा और रूल्स बदल दिये कि नोलेज कारपोरेशन लिमिटेड से पास आरएस-सीआईटी का कोर्स होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के 'ओ' लेवल और जो भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा 'सीसी' लेवल का छह महीने का कम्प्यूटर का कोर्स है, हमने उनको क्यों नहीं एडाप्ट कर लिया छह महीने वालों को? यह तीन महीने के कोर्स के प्रशिक्षित कम्प्यूटर, जो जाते हैं ना पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में, उनका बुरा हाल होता है। वह कुछ जानते ही नहीं हैं, कुछ समझते ही नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार मोनोपोली क्रिएट ना करे और जो शेयर्स आपने लिये, यह यूनिवर्सिटीज के शेयर के लिए मैं आपके माध्यम से अर्ज करूंगा चांसलर महोदय तक कि वह एग्जामिन करे कि क्या उन्होंने अपने-अपने इस अधिनियम के जो नियम, सिद्धान्त हैं, उनकी लक्ष्मण रेखा को तोड़ा नहीं है? और यदि तोड़ दिया है तो शेयर भी सरकार ले ले क्योंकि वह मुनाफे की कम्पनी है। मुझे यह मंजूर है कि सरकार के पास शेयर हो और उसमें आपका कंट्रोल होगा और महाराष्ट्र वाले जो भी हैं, वह उससे उनको छुट्टी पानी पड़ेगी।

मैं निवेदन करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण सवाल पर आप गम्भीरता से विचार करें और तीनों यूनिवर्सिटीज के, कोटा विश्वविद्यालय ने आरटीआई में सूचना दी है उपाध्यक्ष महोदय, कि आरएस-सीआईटी का कोर्स न डिप्लोमा के बराबर है, न किसी सर्टिफिकेट के बराबर है। मेरे पास वह कागज है और वह कागज मैं आपको पेश कर दूंगा। मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं समय के कांस्ट्रेंट को जानता हूं कि इस उच्च शिक्षा को यह आरएस-सीआईटी का बाजारीकरण और इसको मोनोपोली क्रिएट नहीं करें और कम्प्यूटर के क्षेत्र में राजस्थान को यदि आगे जाना है तो आप इन कोर्सेज को 'सीसी' का जो कोर्स है भारत सरकार का छह महीने का, उसके पैमाने पर आप अपना कोर्स बनायें, चाहे उसको एडोप्ट करें लेकिन छह महीने की कम्प्यूटर की ट्रेनिंग से पहले राज्य सरकार में नौकरियों में भर्ती के लायक कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन का समय बहुमूल्य है। मैं इन्हीं दो-तीन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: मास्टर मामन सिंह।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा सुझाव है। मैं यह कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग सुबह से बोल रहे हैं। हमारी पार्टी के लिए कोई रोटेशन का सिस्टम कर देंगे, 10 के बाद या 5 के बाद, हमारा कभी तो नम्बर आएगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट आप विराज जायें। Actually you were to speak before Manik Chand Ji Surana but I will give chance to two speakers from there then I will get back to you. मास्टर मामन सिंह।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग पर मुझे आपने बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है। जो भी गांव, घर, व्यक्ति, प्रदेश और देश, विश्व, जहां पर शिक्षा की वृद्धि हुई है, चरम सीमा पर शिक्षा का बढ़ावा हुआ है, वही देश और प्रदेश, गांव, घर-परिवार उन्नति की ओर बढ़ा है। इसलिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसी सोच को ध्यान में रखते हुए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे माननीय भैरोंसिंहजी की सरकार रही हो, चाहे 2003 से 2008 तक हमारी पूर्व में सरकार रही हो और चाहे अब 2013 में माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजेजी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें शिक्षा की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। दोनों बजट में चाहे पूर्व बजट था और चाहे यह बजट है। एक मिसाल है, इतना बड़ा बजट शिक्षा के लिए समर्पित और कई ऐतिहासिक काम किये।

1952 से अब तक पहला उदाहरण है कि एकमुश्त, एक ही कलम से 5,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय बना देना। कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम है। सरकारें पूर्व में कांग्रेस की भी रही हैं, कभी 200, कभी 400 और अधिकतम इन्होंने 1,000 स्कूल खोले हैं। यह रिकार्डेड है। यह शिक्षा की तरफ सोच का और शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास है।

पदोन्नतियां, अब माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। इन्होंने बड़ी सूझबूझ और इतना इंतजार कर रहे थे शिक्षक वर्ग कि कई सालों से

(मास्टर मामन सिंह यादव)

प्रमोशन नहीं हो रहे थे। 20-20 साल की नौकरियां और वहीं थर्ड ग्रेड में बैठा था, कोई सैकण्ड ग्रेड का सैकण्ड ग्रेड में। जो भी ग्रेड थी उनकी।

(19.00 बजे)

पहला ऐतिहासिक काम हुआ है दस हजार के लगभग पदोन्नतियां हुई हैं। किसी शिक्षक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं प्रिंसीपल बनूंगा, मैं गजेटेड अफसर बन जाऊंगा, मैं लैक्चरर बन जाऊंगा और उनकी पदोन्नतियां ही पदोन्नतियां, यह ऐतिहासिक काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जब-जब भी नौकरी लगाने के लिए बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, टैस्ट लिए जाते हैं कभी पेपर आउट हो गया, कभी कुछ हो गया। यह पहली मिसाल है इतना सुनिश्चित प्रबंध, अभी हाल ही में थर्ड ग्रेड की परीक्षा हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने हल्ला मचाया, नकली पेपर वाट्सअप पर भेज दिए, लेकिन हुआ क्या? सबके सामने है बिलकुल निष्पक्षता से सफल परीक्षा का आयोजन बोर्ड के द्वारा कराया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार ने स्कूल विद्यालय भी, ये माननीय सदस्य कई बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के विधायकों से ही पूछा जाता है, कांग्रेस वालों से नहीं।

माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाये उसमें नीतिगत फैसला दे दिया कि पांच हजार स्कूल जो खोले और उसके बाद दस हजार पंचायतें, प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर मुख्यालय पर स्कूल बनेगा। इसमें चाहे वो कांग्रेस के गांव हैं, चाहे अन्य पार्टियों के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे किसी भी जाति वर्ग के गांव हों तो यह एक निष्पक्षता दर्शाता है। इसके लिए आप सबको, प्रतिपक्ष को भी माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिए। इसमें कोई दुर्भावना नहीं रखी गई है और न कोई भेदभाव किया गया है क्योंकि पानी और शिक्षा यह सबका है, धर्म की चीज है। इसके अन्दर जन आंदोलन भी होना चाहिए, सबका सहयोग भी होना चाहिए। जैसे जल है कोई प्याऊ लगाये, चाहे अपना हैंडपम्प लगाओ, चाहे मोटर लगाये, हर व्यक्ति पानी पी सकता है कोई मना नहीं कर सकता है उसको। इसलिए विद्या मंदिर में भी कोई पढ़ने जाए वह सबका है, हर जाति का है, हर आदमी का है, हर व्यक्ति का है तो इसके अन्दर कोई मतभेद की बात नहीं होनी चाहिए और सबका सहयोग होना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी चार, पांच बार मेरे भिवाड़ी और तिजारा में उनका दौरा हो चुका है। वहां भामाशाहों से जल के लिए भी और विद्यालयों में

(मास्टर मामन सिंह यादव)

विकास के लिए भी प्रेरणा देती हैं, एक प्रेरक के रूप में काम किया और उनकी प्रेरणा से हमारे माननीय मंत्रीजी हेमसिंह भड़ानाजी भी अधिकारियों की और कलक्टर साहब से बैठकर के वो प्रेरित हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं उन भामाशाहों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 8889.39 लाख रुपये जन सहयोग से शिक्षा पर समर्पित हमारे अलवर जिले में हुआ है। वहां के भामाशाहों ने, वहां के उद्योगपतियों ने शिक्षा के लिए दिया है और पानी के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी गईं थीं। कितने ही लोग कोई 25 लाख का, कोई 50 लाख का सहयोग दिया है तो यहां हम सबको शिक्षा और जल दोनों के लिए कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यह जन आंदोलन होगा, सबका सहयोग होगा तभी सफल होगा। क्योंकि शिक्षा की उन्नति, देश की उन्नति, परिवार की उन्नति, गांव की उन्नति, शहर की उन्नति सबकी उन्नति तभी होगी जब हम सब शिक्षित होंगे।

मैंने अभी आपको बताया है 9 करोड़ रुपया कम नहीं होता है चंदा यह तो शिक्षा पर है। जल पर हमारे मंत्री महोदय हेमसिंहजी यहां विराजमान हैं, ये हर महीने मीटिंग लेते हैं, जन सुनवाई करते हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार उनको प्रेरित करते हैं और उसका ही यह परिणाम है 9 करोड़ रुपया दिया है। भामाशाहों ने जगह-जगह कमरे भी बनाये, शौचालय भी बनाये और विभिन्न कार्य विद्यालयों में किए हैं। इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो जल स्वावलम्बन योजना है इसके तहत भी काफी दिए हैं तो हम सबको मिलकर यह काम करना चाहिए।

एकीकरण के मामले में हल्ला मचा रहे हैं हमारे प्रतिपक्ष के भाई बहन कि एकीकरण में स्कूलें बंद कर दीं। जानबूझकर के आंख मींच कर चलना तो अच्छी बात नहीं है। एकीकरण का मतलब यह नहीं था कि ढाणियों के स्कूल बंद कर दिए, गांव की स्कूलें बंद कर दीं। आप सबके क्षेत्र में ईमानदारी से बता दीजिए किस गांव का स्कूल बंद किया है। उस गांव के अन्दर उसी गांव के पंचायत हैडक्वार्टर और अगर छोटे-छोटे तीन स्कूल थे उनका एकीकरण किया है कि एक बड़ा विद्यालय हो जिसके अन्दर कम्प्यूटर शिक्षा, लैब और हर तरह की पूरी सुविधाएं दी जाएं। केवल उस गांव का डेढ़ किलोमीटर या एक किलोमीटर से दूरी का कोई विद्यालय बंद एकीकरण में नहीं किया गया है। यह गलत प्रचार है कि एकीकरण में स्कूल बंद कर दिया। यहां आप सब बैठे हो ऐसा कोई गांव हैं जिस गांव का स्कूल बंद हो गया हो मुझे एक भी उदाहरण

(मास्टर मामन सिंह यादव)

दे दीजिए? यह कुप्रचार है, जिस गांव के अन्दर विद्यालय है उसको प्लस टू करके और उसको क्रमोन्नत करके उसके अन्दर सारी सुविधाएं दी गई हैं यह किया गया है। बताइए इसमें कौनसा स्कूल बंद हो गया? यह कु-प्रचार है तो ये बातें अच्छी नहीं हैं, आप अच्छी सोच रखिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि शिक्षा की तरफ यह हमारी सरकार की सोच है कि दसवीं पास किया पंचायत चुनावों में। यह कितनी बड़ी अच्छी पहल है इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आज हर व्यक्ति सोचने लगा है कि लड़की को पढ़ाओ, बहुओं को पढ़ाओ, नहीं तो अगला चुनाव महिला का रिजर्व है और वह कैसे सरपंच बनेगी। विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, हमारे मेवात क्षेत्र में इनमें पढ़ाने का बढ़ावा मिला है, हमारी शिक्षा को बढ़ावा मिला है। इससे प्रेरणा ली है और ने भी जैसे हमारे सीमावर्ती प्रदेश हरियाणा है। जैसे ही हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां लागू किया। उसमें हमारे प्रतिपक्ष के भाई बहन चिल्ला रहे थे कि ये गलत हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आप शिक्षित बनिए, जो अनपढ़ होगा वो क्या तो मस्टररोल भर लेगा, क्या पंचायत के कार्य करेगा और क्या उसके कार्य को देखेगा? वह कैसे करेगा उस काम को? उसको सैक्रेटरी जेल की राह दिखा देगा। हमारी सोच से ही पड़ौसी प्रदेश हरियाणा है उसने भी और भी कई प्रदेशों ने हमारा अनुकरण किया है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे वहां पर भी यही व्यवस्था लागू हो गई दसवीं पास की। हरियाणा के कुछ लोगों ने केस भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही व्यवस्था माना है जो हमारी मुख्य मंत्रीजी की सोच है। वहां से उनकी अपील खारिज हुई और वहां पर यह लागू हुआ। शिक्षा के लिए हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारी सरकार ने यह बहुत अच्छी पहल की है। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने एक अभियान चलाया प्रत्येक विद्यालय में और जन प्रतिनिधियों को चाहे वह सरपंच हैं, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, सबको निवेदन किया है, चिट्ठियां गईं सबके घर पर कि आप जन जागरण कीजिए और गांव, मौहल्लों में रैलियां निकालिए और सबको प्रेरित कीजिए। सभाएं कीजिए, कार्यकर्ताओं की बैठक कीजिए, जनता की बैठक कीजिए और नामांकन बढ़ाइए सरकारी स्कूलों में। उसका परिणाम रहा कि नामांकन में एकदम काफी वृद्धि हुई। (व्यवधान) मांगें तो पूरी हो रही हैं सब अपने आप ही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन चाहूंगा कि मैं

(मास्टर मामन सिंह यादव)

शिक्षक रहा हूं तो मुझे दो-तीन मिनट थोड़ी ज्यादा दे दीजिए। शिक्षा के प्रति समर्पण भारतीय जनता पार्टी का आज नहीं, पहले से ही रहा है। मुझे याद है उस समय मैं शिक्षक था 2003 से 2008 तक हमारे छोटे-छोटे गांवों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मिडिल स्कूल खोल दिए तो यह था शिक्षा का स्तर।

अब प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल खुले इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, यह भी एक व्यवस्था है। प्राइवेट स्कूल खोलो, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दो उसमें और अभी हमारी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि उनमें पच्चीस परसेंट प्रथम क्लास में अनिवार्य रूप से गरीब लोगों को प्रवेश दिया जायेगा तो उनमें प्रवेश मिल रहा है। पच्चीस परसेंट मिल रहा है उनमें प्रवेश तो यह हमारे शिक्षा मंत्रीजी की सोच और इनकी कार्यकुशलता है इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अब एक बात थोड़ी रह गयी। शिक्षा मंत्रीजी कहां पधार गये हमारे? (व्यवधान) तो कोई बात नहीं नोट हो रहा है। पांच हजार स्कूल पिछली बार खोले और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बिलकुल आदेश कर दिये कि दस हजार स्कूल सभी पंचायत मुख्यालयों पर खोल दिये जाएं, लेकिन एक निवेदन है मेरा थोड़ा सा समझ का फर्क रह गया। मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नोट कर लो, ये नोट कर रहे हैं जो भी, भिवाड़ी नगर परिषद बन गई जिसमें आठ पंचायतें थीं, आज आपकी सूची में पंचायतें नहीं हैं क्योंकि वो नगर परिषद् बन चुकी हैं तो कृपा करके वहां भिवाड़ी में पैंतालीस हजार मतदाता और डेढ़-दो लाख की आबादी है वहां पर केवल एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल है केवल मात्र एक। माननीय शिक्षा मंत्रीजी अगर यहां पर हैं तो नोट करें। सात ऐसी पंचायतें हैं जो हैडक्वार्टर थी आज से चार साल पहले लेकिन आज नगर परिषद् में शामिल होने के बाद उस पंचायत सूची में नहीं होने के कारण वो गलती से रह गयी। तो उसमें सुधार करते हुए उनमें सातों में शाहदपुर, साड़ोद, आलमपुर, सांतलका, मिरकपुर, गूजर और खिजूरीवाल ये सात पंचायतें ऐसी हैं जो पंचायत हैडक्वार्टर थीं लेकिन अब नगर परिषद् में शामिल होने के कारण इनकी सूची में नहीं होने के कारण वो रह गयीं। इसमें गलती किसी की नहीं है तो कृपा करके इस बजट में उनको खोल दिया जाए। चार पंचायतें ऐसी रह गयीं बिरामपुर, मुण्डाना, सलारपुर और मसीद जिनके अन्दर बता दिया गया कि प्राइवेट स्कूल हैं। अब प्राइवेट स्कूल ऐसा कोई खास नहीं था लेकिन वो पता नहीं सर्वे किसने की, किसने नहीं की तो इस तरह से उनको भी कृपा करके खोला जाए। एक नयी तो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर ही दी और मंत्री महोदय इसको तो करेंगे ही, 11

(मास्टर मामन सिंह यादव)
पंचायतें नयी बनी हैं तिजारा में। इन 11 नयी पंचायतों में एक में भी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है क्योंकि नयी बनी है। यह कोई विभाग की गलती नहीं है न मंत्री महोदय की है तो अब उन 11 को भी तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि 11+4=15 और 7=22 पंचायतों में तिजारा में खोलने की आवश्यकता है।

**श्री उपाध्यक्ष:** अभी कुछ और रह गया क्या?

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): सर, उच्च शिक्षा का और है। एक है विद्यार्थी मित्रों का भी रोना रोज रहता है, इसमें भी थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और साहब इनको भी कर दो ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** सदन से आसन निवेदन करता है कि आदरणीय सदस्य पहले शिक्षक रहे हैं, शिक्षाप्रद बात कह रहे हैं तो थोड़ा धैर्य से आप भी सुन लें।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): बहुत-बहुत धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय आपको।

**श्री उपाध्यक्ष:** चूंकि शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं इसलिए आप लोग नोट कर लें और उनको बता दें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): नोट हो रहा है, साहब। आप सब नोट कर लीजिये। (व्यवधान) अब ये तो प्राइमरी शिक्षा की बात थी। एक यह मिड-डे मील का है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो स्कूलों में मिड-डे मील दी जाती है उसमें खाना बनाने वाली एक गरीब औरत या आदमी लगाते हैं, बिलकुल गरीब अब उसको एक हजार रुपये दिये जाते हैं। यह पहले से ही है। तो पहले तो कांग्रेस सरकार थी अब वो तो शोषण का काम करते ही थे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान करके कृपा करके इसमे पैसा बढ़ाओ, एक हजार में कुछ नहीं होता है। उसके पैसे बढ़ा कर गरीब के हजार से दो हजार तो कम से कम कर ही दो नहीं तो सौ रुपये रोज के हो जाने चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष:** अब आदरणीय विराज जाएं। मेरे ख्याल से यह वैसे ही इतना ज्यादा हो गया इनके लिए कि अब ये समझकर उस पर कार्यवाही करेंगे वरना फिर वो बिलकुल नहीं समझ पायेंगे।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): नहीं, साहब अब उच्च शिक्षा रह गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट। अब उच्च शिक्षा रह गया है।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी कालीचरणजी को मैं बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जाते-जाते तिजारा में कालेज खोल दिया। न तो बजट है, न कहीं स्कूल, न कहीं बच्चे, न प्रिंसिपल और न बिल्डिंग। एक नया पैसा नहीं दिया। सरकार आयी, मंत्री महोदय ने मंत्री पद की शपथ ली। उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आठ करोड़ तीन लाख रुपये का बजट दिया और वह बिल्डिंग अब बनकर एक महीने में तैयार हो जाएगी, आप उद् घाटन करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए और एक और धन्यवाद के पात्र हैं ये।

**श्री उपाध्यक्ष:** अब धन्यवाद आप विराज जाओ।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): एक मिनट साहब। एक और धन्यवाद के पात्र हैं कि कांग्रेस सरकार ने तुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए आईटीआई कालेज मेरे तिजारा में खोला जिसमें सोलह ट्रेड, ...

**श्री उपाध्यक्ष:** सम्माननीय सदस्य, एक मिनट विराज जाएं आप। एक मिनट विराज जाओ। एक मिनट विराज जाओ।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): ..बिल्डिंग नहीं बनायी। पैसे तो अभी दिये हैं। वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए किया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** एक मिनट विराज जाएं आप।

**मास्टर मामन सिंह यादव** (तिजारा): तो वो...(व्यवधान) कर दिया उसके लिए भी धन्यवाद और साहब, भिवाड़ी में कालेज खोल दो यह मेरी एक ही मांग है और कोई मांग नहीं है। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी है 2600 कम्पनियां हैं और वहां पर मांग बहुत पुरानी है। एक सैनिक ट्रस्ट ने उसको चला भी रखा है और बिल्डिंग बन रही है, 38 बीघा जमीन है सारा कुछ है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत माफी चाहता हूं यह कालेज का कहना जरूरी था।

**श्री उपाध्यक्ष:** मैं सभी सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो भी बोलें, आप अपने ही सदस्यों के समय पर अतिक्रमण कर रहे हैं। तकरीबन चार मंत्रियों का जवाब आएगा और अभी भी दस सदस्यों को बोलना है और इन दस सदस्यों का भी अपना एक अधिकार है। इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ सदस्यों ने आधा-आधा घंटे तक बोला और प्रतिपक्ष आपके तीन सदस्यों ने तो डेढ़ घंटे बोला है, लेकिन मैं सारे सदन को और समस्त सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि इस सूची में नौ सदस्य और शेष रह

(श्री उपाध्यक्ष)

गये हैं और एक बीएसपी पार्टी के हैं, उनका खुद का भी एक समय है उनका अधिकार बनता है। हम संख्या बल पर उनके अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकते इसलिए अब मैं निवेदन करता हूं कि मैं अधिकतम, तथ्यात्मक कोई बात हो तो आप जरूर बताएं लेकिन जो बात माननीय सदस्य पहले जिक्र कर चुके हैं तो बार-बार उस बात का जिक्र न करके आप अपने विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रहिये, अपने कटौती प्रस्ताव जो आपने लगाये हैं उस पर आप बोलिये और मंत्री का ध्यान आकर्षित करिये तो मैं आशा करता हूं कि मेरी यह साधारण सी बात आपके मस्तिष्क में समा गयी होगी।

श्री रामपालजी।

**श्री रामपाल** (बारां-अटरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-24 पर बोलने का जो सुअवसर दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प को ध्यान में रख कर प्रदेश को बीमारू राज्य से उबार कर देश में प्रथम पायदान पर पहुंचाने का भागीरथ प्रयास किये वो सराहनीय हैं। साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने पंचायत मुख्यालयों पर पांच हजार विद्यालयों को क्रमोन्नत करके ग्रामीण क्षेत्र की बालक-बालिकाओं का उद्धार किया। साथ ही आदर्श विद्यालय का दर्जा भी दिया। पूर्व कांग्रेस सरकार ने आठवीं तक के छात्रों को फेल न करके प्रदेश की शिक्षा के स्तर को निम्न स्तर पर लाने का जो प्रयास किया उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सत्ता सम्भालते ही आठवीं में बोर्ड की परीक्षा कर सराहनीय पहल की। समय की मांग को ध्यान में रख कर ब्लाक स्तर पर विवेकानन्द माडल स्कूल की स्थापना करना, पचपन हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति करना, 31 हजार व्याख्याताओं के नवीन पदस्थापन देना शिक्षकों की भर्ती के लिये अब केवल रीट की परीक्षा ही देना, साथ ही नवीं की पांच हजार छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण करना। बालिकाओं के लिये ट्रांसपोर्ट वाउचर की स्कीम, लैपटोप वितरण, स्कूटी वितरण। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1 जून, 2016 के बाद जन्म देने वाली बालिकाओं के लिये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की पहल पर कक्षा एक में प्रवेश लेने पर चार हजार रुपये, पांचवीं पास करने पर पांच हजार रुपये और दसवीं पास करने पर ग्यारह हजार रुपये और बारहवीं पास करने पर पच्चीस हजार रुपये, यानी बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। यह बेटी बचाओ, बेटी पढाओ की स्वर्णिम योजना की अनूठी

(श्री रामपाल)

पहल की है। साथ ही बालकों का विशेष ध्यान रखते हुए छात्रावासों में वाटर हीटर लगाना, प्रत्येक विद्यालय में संस्कृत के पद स्वीकृत करना, 628 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन देकर बालकों को एक सुविधा प्रदान की। गत सत्र की अपेक्षा इस सत्र में 14.47 प्रतिशत बजट अधिक देकर शिक्षा को और बढ़ावा दिया है। राजकीय विद्यालयों में 8 लाख का नामांकन बढ़ना शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मेरी क्षेत्र की मांगों पर आता हूं। मेरे क्षेत्र में जो समस्या है ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले। मेरे क्षेत्र में जीरोद ग्राम पंचायत मुख्यालय है। पहले उसमें माध्यमिक विद्यालय चलता था और वहां 3-4 कमरे थे जो बिलकुल जर्जर हो रहे थे और स्थिति यह बनी उन कमरों को गिरवाना पड़ा। इधर सरकार ने पंचायत मुख्यालय पर आदर्श विद्यालय, सीनियर विद्यालय खोल दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं इस राजस्थान में यह उच्च माध्यमिक स्तर का पहला विद्यालय होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई भवन हीं नहीं है। वहां के बालक खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भूमि पर्याप्त है पर सुविधाएं कुछ भी नहीं हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से विशेष निवेदन करूं, गांव वाले कई बार बहस कर चुके हैं, तर्क दे चुके हैं कि आगामी सत्र में हम आपके इस विद्यालय को नहीं चलने देंगे। माननीय मंत्रीजी से मेरा विशेष निवेदन है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय जो प्रदेश स्तर पर भवन विहीन हो, ऐसा विद्यालय पूरे प्रदेश में नहीं है, अत: इस विद्यालय को अभी इसी बजट सत्र में इस मांग पर स्वीकृति प्रदान करें तो अति उत्तम होगा और उस पंचायत मुख्यालय पर कई बालकों का भला होगा।

साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये हैं। मेरे क्षेत्र में भी पाठेड़ा पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला, कारण वहां से 7 किलो मीटर दूर एक छोटे से गांव में किसी निजी विद्यालय ने पता नहीं कहां की डिग्री लेकर सीनियर स्कूल चला रखा है। मैंने माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन किया तो आशय पाया कि आपके पंचायत में सीनियर विद्यालय है परन्तु जो सीनियर विद्यालय है वह निजी विद्यालय है और वह 7 किलोमीटर दूर है, पंचायत मुख्यालय पर नहीं है। मेरा निवेदन है पाठेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय

(श्री रामपाल)

पर सीनियर विद्यालय खोलें। साथ ही मंडाला विद्यालय में भी यही स्थिति है। एक नवीन ग्राम पंचायत रतनपुरा जो अभी गठित की है वहां पर भी सीनियर विद्यालय खोलने का मेरा आग्रह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी है जो पंचायत मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है। उस गांव में केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय है। आसपास कोई सैकण्डरी स्कूल या उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है। वहां के बालकों को आठवीं करने के बाद शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा विशेष आग्रह है कि आप किशनपुरा मसालदारान विद्यालय कम से कम माध्यमिक विद्यालय में तो क्रमोन्नत करें ताकि वहां के बालक-बालिकाओं का उद्धार हो सके, वहां के जन जीवन में शिक्षा का स्तर बढ़ सके।

इसके साथ ही मेरा विशेष निवेदन है मेरे क्षेत्र में अटरू उप खण्ड मुख्यालय है और वहां की आबादी 35 हजार के लगभग है, 55 सीनियर विद्यालय भी उसके आसपास हैं परन्तु महाविद्यालय पहुंचने के लिये बालक-बालिकाओं को 35 से 60 किलोमीटर दूरी पार करनी पड़ती है। इस स्थिति में सीनियर करने के बाद बालक-बालिकाएं विद्यालय छोड़ देते हैं। मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे अटरू उप खण्ड मुख्यालय पर यदि कालेज खुल जाता है तो उस क्षेत्र का बहुत बड़ा भला होगा।

माननीय, मेरे अटरू उप खण्ड मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय है और 600 बालिकाएं वहां पर अध्ययन करती हैं और उनके बैठने के लिये पर्याप्त जगह नहीं है। बरामदे में या खुले चौक में उनको बैठना पड़ता है। मेरा निवेदन है सीनियर कन्या विद्यालय के लिये कम से कम चार या पांच कमरों की यदि स्वीकृति प्रदान करते हैं तो उन बालिकाओं का बहुत उद्धार हो जायेगा।

इसी के साथ मेरा एक निवेदन है अटरू सीनियर विद्यालय बरसों पुराना विद्यालय है और उसमें बायोलोजी और गणित दोनों विषय चलते थे। गत सरकार ने पता नहीं क्या कारण रहे और गणित विषय को हटा दिया। मेरा निवेदन है कि उप खण्ड केन्द्र है और सबसे बड़ा विद्यालय है, अत: वहां गणित विषय के साथ-साथ कृषि विषय भी खोलने के लिये स्वीकृति प्रदान करें ताकि वहां के बालकों का भला हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आये।

मेरे विपक्षी भाई बार-बार वाद विवाद करते हैं तो संतों ने एक श्लोक लिखा है विद्या विवादाये धनमअदाय, सतीपरेशा परपीढ न आये, खलस्ये साधो

(श्री रामपाल)

प्रीत मेतत ज्ञानाआये अदानाये छहरक्षणाये। मेरा कहना यह है कि किस प्रकार की शिक्षा है यह अंतर आप कर लेंगे। इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री मनोज कुमार।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की महत्वपूर्ण मांग पर सदन में सुबह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अपने-अपने गुणगान करते हुए इस शिक्षा के भविष्य पर विचार कर रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान प्रदेश और भारत देश का भविष्य इस शिक्षा के माध्यम से हमारे देश का उद्धार, हमारे देश की प्रगति इस शिक्षा के माध्यम से होनी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्किल डवलपमेंट की, व्यावसायिक शिक्षा की, हमारे बजट में दिया कि हम वर्तमान में 290 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा से संचालित कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने व्यावसायिक शिक्षा का नाम तो इन 290 विद्यालयों को दिया है लेकिन आपने उसमें कौन-कौन से ट्रेड, जिस नाम से आप व्यावसायिक शिक्षा उनको प्राप्त करायेंगे आपके पास वह सारी व्यवस्थाएं हैं क्या। जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से आप उनको अपने हाथ का हुनर और काम सिखाने की व्यवस्था अगर आपने की हो, विद्यालय में नाम लिखने से नहीं काम कराने से होगा ऐसा एक भी ट्रेड राजस्थान में 290 विद्यालयों में नहीं है, जिसको ये किसी व्यक्ति को अपने हाथ का काम करने का ट्रेड प्रदान करेंगे। सिर्फ इनके पास प्रमाण-पत्र देने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। प्रमाण-पत्र जरूर देंगे क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र में भी शिक्षा के नाम से स्किल डवलपमेंट के नाम से खूब चला, लेकिन तीन-तीन महीने प्रशिक्षण दिया और प्रमाण-पत्र दिया। प्रमाण-पत्र के अलावा व्यावसायिक शिक्षा में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हू कि आप जहां-जहां भी व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय में शुरू करें उन विद्यालयों में पूरी व्यवस्था आप छात्रों के लिए करें। एक मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आपने राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा की बात की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां आकर के तो इनको प्रैक्टिकल के रूप में देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में जैसे आप थ्योरिटिकल शिक्षा इस व्यवसाय की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुरू करें जिससे थ्योरी की

(श्री मनोज कुमार)

जानकारी उनको समय पर मिल जाए और प्रैक्टिकल की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के समय मिल जाए।

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार लम्बे समय से रही। दोनों सरकारों ने राजस्थान में डार्क जोन जिसमें 15 साल हो गए। वो अध्यापक जिनको आपने सज़ा के रूप में एक लिमिटेड अध्यापकों को आपने दंड दे रखा है कि आप डार्क जोन में हैं इसलिए आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? आप ऐसी पालिसी बनाइए कि इस डार्क जोन जिले में आपके परिवर्तन होते रहें दो साल में, पांच साल में या दस साल में। आप एक ऐसी नीति बनाइए कि पर्टिकुलर अध्यापकों को...। डार्क जोन के नाम से आपने 15 साल से, ये कांग्रेस सरकार ने भी और आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन अध्यापकों के साथ लगातार 15 साल से आप इस तरीके का अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो अध्यापक क्या इस राजस्थान में नहीं है? इसलिए आप सभी को इस डार्क जोन से हटाकर पूरे राजस्थान में आप उनके साथ न्याय करने का काम करें। आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक वेतन विसंगति के लिए, पिछले लम्बे समय से आपके साथ यह आंदोलन भी किया है, यहां धरना-प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन आज भी आपने उन द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की वेतन-विसंगति, जो लम्बे समय से उनको चार हजार रुपए मासिक उनका नुकसान हो रहा है। सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। उन द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के साथ जो अन्याय हो रहा है माननीय मंत्री महोदय, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करके आप एक ही बात कहकर निपटाना चाहते हैं कि वित्त विभाग के पास चर्चा के लिए गया हुआ है। क्या वित्त विभाग इस सरकार से बाहर है? क्या वित्त विभाग इस सरकार के नियंत्रण में नहीं है? आप इस तरीके की बात कहकर इस राजस्थान के उन द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के साथ अनदेखी ना करें। वित्त विभाग भी आपका है और सरकार भी आपकी है। इसलिए इस पर निर्णय करके द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की वेतन -विसंगति को दूर करके इनका न्याय करने का काम करें।

राजस्थान में आप 15 लाख विद्यार्थी मित्रों को नौकरी देने की बात, रोजगार देने की बात सरकार कर रही थी। आपके सुराज संकल्प में भी था, लेकिन विद्यार्थी मित्रों को आपकी सरकार ने नियुक्ति दी और आपकी सरकार ने पिछले साल से इन विद्यार्थी मित्रों को घर का रास्ता दिखा दिया। कल माननीय मंत्री महोदय को और हमारे संसदीय कार्य मंत्री महोदय को उन

(श्री मनोज कुमार)

विद्यार्थी मित्रों की आखिर आपकी सरकार से तंग और परेशान होकर मरने तक की नौबत आ गई थी। वो टंकी पर चढ़ गए थे लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आप उनको स्वत: ही रोजगार न्यायालय का नाम लेकर नहीं देना चाह रहे कि हमारी पेचीदगी के कारण न्यायालय में चला गया। मैं कहता हूं न्यायालय में आप उनके लिए उचित पैरवी करें, शक्ति के साथ पैरवी करें और तब तक इनको अस्थाई रोजगार की व्यवस्था करें। आपने आज लिखा है कि आपने उप समिति बना दी है और हम जल्द ही निर्णय करेंगे। मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री महोदय से कि आप उसका समय निर्धारित कर दें कि आपकी उप समिति एक महीने में, पंद्रह दिन में, दो महीने में इस पर उनको अस्थाई रोजगार देने का निर्णय करेगी। यह विद्यार्थी मित्र भी इस राजस्थान के नागरिक हैं, जिनको आपने आठ साल तक नौकरी पर रखा और उनको आज घर भेजने का काम किया है। दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने नहीं किया उनके साथ न्याय और मैं कहना चाहता हूं कि इन विद्यार्थी मित्रों के साथ न्याय करने का काम करें आप नहीं तो 2018 में आप भारतीय जनता पार्टी वाले और ये कांग्रेस के लोग अपने आप में खुश हो रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा। मैं कहता हूं तीसरा विकल्प हम भी बैठे हैं। हमारा नंबर आ सकता है। आप दोनों वंचित रह सकते हो अगर विद्यार्थी मित्रों के साथ, द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के साथ आप लोगों ने अगर अन्याय करने का यह निर्णय फाइनल रखा तो।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में आपकी राज्य सरकार एक प्रस्ताव लेकर आ रही है कि सामान्य श्रेणी के लोग, ओ.बी.सी. के लोग, जिन लोगों को 25 प्रतिशत शिक्षा प्राइवेट विद्यालयों में नि:शुल्क मिल रही थी। अब यह सरकार ला रही है कि सिर्फ बी.पी.एल. और एस.सी, एस.टी. को देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य वर्ग के भी गरीब लोग इस राजस्थान में रह रहे हैं। उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर सरकार की नजर में ऐसा कोई प्रस्ताव हो तो सरकार उसको वापस लेने का प्रयास करे। इस ढाई लाख का जो क्राइटेरिया था, इनकी आय का निर्धारण जो ढाई लाख है, उसी को रखते हुए इन राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ न्याय करने का काम करें।

तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को एक साल का उनको उम्र का, अगर विज्ञप्ति सरकार ने जारी नहीं की है तो एक साल का रिलेक्सेशन देने का प्रावधान आपके कानूनी प्रावधान में है और हाई कोर्ट ने भी इसके लिए आपको

(श्री मनोज कुमार)
निर्णय दे दिया उसके बाद भी एक साल जिनका, ओवर ऐज हो रहे हैं, उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। उन तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को भी शामिल करने का प्रयास सरकार करे।

इसी के साथ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अभी डी.पी.सी. के माध्यम से आपने जिन अध्यापकों का प्रमोशन किया है, एक सरलीकरण से आपने उनकी नियुक्ति में बड़ी पारदर्शिता रखी है, लेकिन कल मेरी जानकारी में आया, उस हिसाब से आपके डायरेक्टर महोदय उनमें पारदर्शिता रखना नहीं चाहते। जिसका मैंने माननीय मंत्री महोदय को कल लिखित में दिया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतिहास की सात पोस्टें खाली हैं, लेकिन आपके डायरेक्टर महोदय ने उस सूची में जिनका चयन करना है, मैरिट के आधार पर उनमें उनको शामिल नहीं किया। इसलिए मंत्री महोदय ने कल जागरुकता के साथ उनको शामिल करने का काम किया। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन भविष्य के लिए डायरेक्टर को पाबंद करें कि जो-जो पोस्ट रिक्त हैं, वो आनलाइन पर आपकी पोस्ट दिखाएं जिससे लोग अपने चयन में अपना उचित स्थान चयन कर सकें।

आज भवनों के बारे में यहां लिखा है आपके इसमें कि 108 माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों की स्थिति जर्जर है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान का एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जिसके भवन जर्जर स्थिति में ना हों। इसलिए पूरे राजस्थान के इन जर्जर भवनों पर आप पूरा गौर करें, पूरी शक्ति के साथ इनकी जांच कराएं। आज के हालात यह है कि कहीं न कहीं आपको एक दिन बरसात के समय ऐसा हादसा सुनने को मिलेगा कि आपके जर्जर भवन के कारण छात्रों की मौत हो गई। इसलिए कहना चाहता हूं पूरा निरीक्षण कराएं जिससे इस राजस्थान की जनता को इन जर्जर भवनों से कम-से-कम भय मुक्त होकर अभिभावक छात्रों को भेजने का काम करें।

इसी के साथ ही साथ आपने छात्राओं को साइकिल वितरण का बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन छात्राओं को आपने विद्यालयों में साइकिल वितरण किया है, उन विद्यालयों में, कुछ विद्यालयों में साइकिल वहां तक जा नहीं सकती। वहां तक आपके पक्के रास्ते नहीं हैं। इसलिए जहां-जहां जिस विद्यालय में आपने छात्राओं को साइकिल वितरण की है, उनके रास्ते पक्के कराकर उनको साइकिल से वहां तक जाने

(श्री मनोज कुमार)

की व्यवस्था आपकी सरकार करे, जिससे उन छात्राओं को साइकिल का लाभ मिल सके।

छात्राओं को साइकिल के बाद अब मिड-डे-मील योजना, यह एक ऐसी योजना राजस्थान में चल रही है मैं कहना चाहता हूं हमारा अध्यापक वर्ग बड़ा ईमानदार था, लेकिन ना चाहते हुए भी इनको बेईमान होना पड़ रहा है। इनको आंकड़े मिलाने हैं, मिलाते-मिलाते कहीं-न-कहीं आंकड़ों में ग्रामों में गलती हो जाती है और ये अध्यापक बेईमान हो जाते हैं अपने आप में। इसलिए मिड-डे-मील का जिस तरीके से मुख्यमंत्री, भामाशाह योजना से सारी पारदर्शिता रखना चाहती हैं कि सीधा पैसा उसके पास जाए। माननीय राजीव गांधी के नाम से जो कह रहे थे कि एक रुपए में दस पैसा पहुंच रहा है। ऐसा ही इस मिड-डे-मील में हो रहा है। इसलिए इस मिड-डे-मील पर पर-छात्र जो खर्चा हो रहा है वो उस अभिभावक को, उस छात्र के खाते में दिया जाए। जो अपनी उच्च शिक्षा में उस पैसे का काम ले। एक भी छात्र भूखा घर से नहीं जाता। इसलिए इस मिड-डे-मील योजना के इस खर्च को छात्र के अभिभावक को या छात्र के खाते उस शिक्षा के लिए सुरक्षित किया जाए, जिससे इसका लाभ मिल सके।

मैं इसी के साथ मंत्री महोदय से मेरी दो गुजारिश जरूर करुंगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, पंचायत हैडक्वार्टर है। 1977 में माध्यमिक विद्यालय था और अब भी आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया । इसलिए इस विद्यालय को, एक मात्र विद्यालय की मांग कर रहा हूं कि आप उसको उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का काम करें।

एक हमारे बालिका शिक्षा में बहुत जोर दे रखा है, लेकिन मेरा सांनखू गांव बहुत बड़ा गांव है। वहां उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन छात्राओं के लिए अलग से कोई विद्यालय नहीं। इसलिए कन्याओं के लिए सांनखू में छात्राओं के लिए विद्यालय अलग से खोलने का काम करें। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री विराजमान हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद एक बात के लिए जरूर दूंगा क्योंकि दो साल पुराना है धन्यवाद तो । आपने हमारे महाविद्यालय तो खोल दिया लेकिन अधूरा धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूं कि अभी हमारे भवन का निर्माण नहीं हो पाया, भूमि आबंटित नहीं करा पाए। इसलिए आप इसी सत्र में उसको भूमि आबंटित कराकर भवन का

(श्री मनोज कुमार)

निर्माण कर दें उसके बाद इसी सदन में मैं आपको दोबारा धन्यवाद दूंगा, उस दिन हमारा परिपूर्ण धन्यवाद होगा। आप इस पर प्रयास करें।

इसी के साथ-साथ कहना चाहता हूं बीएड और एसटीसी के जितने भी प्राइवेट महाविद्यालय हैं उनमें राजस्थान के छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है। वहां अनुपस्थिति के नाम से 30-30 हजार रुपये पर-छात्र से लेते हैं। दिन में कम से कम 10-20 छात्रों के हमारे पास फोन आते हैं कि विधायक महोदय, हमसे यहां अनुपस्थित रहने के नाम से पैसे मांग रहे हैं। एक तो वह पढ़ाते नहीं, उनके पास सुविधा नहीं, उनके पास अध्यापक नहीं और उसके बाद छात्र से 30-30 हजार रुपये वार्षिक फीस के अलावा लेते हैं । इसलिए उच्च शिक्षा मंत्री महोदय कहना चाहता हूं कि आप इनका औचक निरीक्षण कराएं। जिन छात्रों की शिकायत आई, इनकी जांच कराएं, जांच कराकर इनकी मान्यता रद्द करें। हमारे बीएड और एसटीसी के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे राजगढ़ में आपकी ही गाइड लाइन के अनुसार, आपकी सरकार की मंशा के अनुसार मैं चाहता हूं कि मेरे राजगढ़ में कन्या महाविद्यालय की आप इसी सत्र में घोषणा करें। मेरे राजगढ़ की जनता को इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ ही साथ माननीय हम आपके पड़ौसी मंत्री, चिकित्सा मंत्रीजी से एक सिफारिश मैं करना चाहता हूं कि वहां की जनता भी मेरे पास आई है कि हमारे भी वहां पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने कन्या महाविद्यालय की घोषणा कर दी थी लेकिन आपकी सरकार ने बंद कर दी, इसलिए माननीय मंत्री के प्रति यह ध्यान देते हुए, आपके कैबिनेट मंत्री होते हुए, मैं चूरू जिले का होते हुए, लोग मेरे से मांग कर रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनट और साहब। इसलिए चिकित्सा मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय को खुलवाकर चूरू की जनता को लाभ देने का काम करें।

शेखावाटी यूनिवर्सिटी, जिसका भवन निर्माण नहीं। आप लम्बे समय से उसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमने शेखावाटी यूनिवर्सिटी खोल दी। मैं निवेदन करना चाहूंगा उसका भवन निर्माण कर वहां की जनता को उसका लाभ दें जिससे हमारे शेखावाटी क्षेत्र को उसका पूरा लाभ मिल सके। हमारे क्षेत्र के नजदीक विश्वविद्यालय हो जाए तो उसका लाभ हमारे लोग ले सकें।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, एक मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ओ. पी. जे. एस. यूनिवर्सिटी है, जिसकी मैं चार

(श्री मनोज कुमार)

बार आपको शिकायत कर चुका हूं । जिस तरीके से जोधपुर में, जोधपुर यूनिवर्सिटी वाले ने फर्जी मार्कशीट बांटने का काम किया उसी तरीके से फर्जी मार्कशीट, जो कोर्स उसके पास सौ सीट है वहां हजार-हजार छात्रों को...

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): क्या नाम बताया ?

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी, रावचर कूंजरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। जो खुले आम भ्रष्टाचार कर रहा है और फर्जी डिग्री बांटने का काम कर रहा है। मैं आपको चार बार लिख चुका हूं। आपकी कमेटी आज तक जांच करने नहीं गई है। हमारे वहां छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो इसके लिए आप कमेटी गठित कर दें। आज ही घोषणा करें और इसकी पूरी जांच करें कि इसने कितने छात्रों के साथ अन्याय करने का काम किया है।

इसी के साथ एक छोटा सा मामला, रीट की बात कर रहे थे, कि हमने राजस्थान में रीट का सफल एग्जाम करा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आपने सफल रीट का एग्जाम करा दिया लेकिन इसमें रोजाना अख़बार के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो संदेहास्पद हैं, उन पर आप कैसे निर्णय कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 32 क्वेश्चन संदेहास्पद हैं, जिनको आपके पेपर बनाने वाले लोग, उसमें कौन-कौन दोषी हैं जो इस तरीके से उसको न्यायालय में ले जाना चाह रहे थे, अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना चाह रहे थे। उन 32 क्वेश्चन के लिए, रीट का एग्जाम देने वाले छात्रों के साथ आप कैसे न्याय कर पाएंगे, इसका निर्णय माननीय मंत्री महोदय बहुत गम्भीरता से करना है, 32 क्वेश्चन अगर संदेहास्पद हो तो वह परीक्षा कराने का औचित्य नहीं होगा। जिस तरीके से मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए उनको पूरा रद्द करना पड़ा इसलिए कहीं इसको पूरा रद्द न करना पड़े, क्योंकि आपके पास मैरिट बनाने का कोई आधार नहीं रहेगा। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा को, इस राजस्थान की शिक्षा को, हमें अगर सुदृढ़ीकरण करना है, राजस्थान के गरीब, असहाय लोगों को पढ़ाने की हमारी मंशा है तो आप पूरी मोनीटरिंग के साथ, पूरी सख्ती के साथ, इन गरीब, असहाय छात्रों को पढ़ाने के काम को आप ताकत के साथ लें। शिक्षा का उच्च स्तर बढ़ाया जा सके, ऐसा निर्णय करने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। साथ ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी

(श्री मनोज कुमार)

और कांग्रेस के जितने माननीय सदस्य हैं उनको, कि हमारे अधिकारों का भी आप हनन नहीं करें। हमारा भी क्रम से कहीं न कहीं नम्बर ड़ालें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा रोजाना रात को आठ बजे नम्बर आता है। इसलिए हमें किसी क्रम में डाल दें आप, 8, 10, 15 के बीच में। हमारा तय हो जाए कि हम निश्चित समय बोलेंगे। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत।

**श्री उपाध्यक्षः** श्री शंकर लाल शर्मा।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): आपकी पार्टी के लोग शिक्षा पर बोल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। बसपा वाले भी शिक्षा पर बोल रहे हैं।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): सबसे ज्यादा बाबा भीमराव अम्बेडकर का...(व्यवधान) संविधान लिखने वाली पार्टी से हम लोग आते हैं। जिनका आप नाम लेना सीख रहे हैं, आपने आजकल उनकी जयंती मनाने का शुरू कर दिया। वोटो के लिए आपने जयंती मनाना शुरू कर दिया। आपने उनके नाम से जयंती मनाना शुरू कर दिया, बाबा साहेब के नाम से। आपको भी खतरा हो गया है कि वोट हमारे पास नहीं रहेगा।

**श्री विश्वनाथ** (संसदीय सचिव): माननीय सदस्य, हम तो हमेशा ही जयंती मनाते हैं 14 अप्रेल को।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): नहीं मनाते थे, अब मनाना शुरू किया है आपने। नहीं मनाते थे। (व्यवधान) उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी सरकार होगी चिंता मत करो।

**श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संया 24, शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के गुणों पर, शिक्षा की गुणवत्ता पर, अभी-अभी हमारे एक गुरुजी तिजारा वाले सदस्य जी ने बताया कि अगर शिक्षा है तो गांव, शहर, देश का विकास है। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से हूं, किसान हूं और किसान का लड़का हूं, सदन में कभी भी शायद ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसान की बात नहीं हो। हम हर समय किसान के गुणगान करने में कभी कमी नहीं छोड़ते।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बात शिक्षा की है। आज गांव का छोटे से छोटा कारीगर इस बात को जानता है कि मुझे मकान बनाना है तो उससे पहले नींव मजबूत करनी है। आज गांव का किसान जानता है कि खेजड़े का

(श्री शंकर लाल शर्मा)

पौधा लगाएंगे, उसकी नींव अगर अन्दर जाएगी तो वह टिकाऊ रहेगा। एक जूलीफ्लोरा अमेरिका से आया, जो थोड़ी सी हवा के अन्दर नीचे लड़खड़ा जाता है। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि बात शिक्षा की है, किसान की है। आज 70 परसेंट किसान गांवों में रहता हैं। गांव में रहने वाले अधिकतर किसान ही हैं। हमारे विपक्ष के भाई बहुत तो जा चुके। मैं जहाजपुर से आने वाले सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने वाकई कुछ बात कही है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले बार-बार टोकते हैं, मुझे दु:ख है आज वह यहां नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि किसान के हमदर्द, किसान को केवल मात्र वोट की राजनीति के अन्दर दें या उसके विकास के अन्दर दें, शिक्षा को जितना ज्यादा खतरनाक हालत में, किसान को बरबाद करने में, आज उसके पास केवल 2-2, 3-3 बीघा जमीन के टुकड़े बच गए। कमाई का साधन नहीं है। अगर साधन है तो क्या, केवल शिक्षा लेकर वह आगे बढ़ लें। लेकिन इन किसान के हमदर्द मेरे भाइयों से यह पूछना चाहता हूं कि जिस किसान के बच्चे की नींव ही आपने जमीन के ऊपर रखी है, आठवीं तक कोई फेल नहीं होगा। वह क्या बिल्डिंग बनाकर आगे बढ़ जाएगा। आठवीं तक का फेल बच्चा, डिग्री मिल भी जाएगी तो वह नाइंथ क्लास में आकर क्या पढ़ लेगा। क्या वह नींव टिकाऊ रहेगी। इसका मतलब ही यही है कि यह केवल किसानों को यूज करते थे, किसान कहीं पढ़ लिख जाए, हमारे वोट नहीं छिन जाए, केवल इसी आस पर कायम रहे। मैं हमारे शिक्षा मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने गांव के किसान भाइयों के बच्चों को शिक्षा के अन्दर, अपने आप पास करने का तरीका छोड़कर, एग्जामिनेशन के द्वारा हमारी नींव मजबूत करने का कार्य किया है, सर्वप्रथम मैं उसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम का, ग्रामवासियों का, ग्राम के बच्चों का विकास होगा। कई बार शिक्षा की गुणवत्ता की बात आती है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार इस सभा-सदन में कोई सदस्य आपस में गलत बातचीत करते हैं या टोकते हैं या कोई ज्यादा उग्र होने की स्थिति में होते हैं तो आप कई बार आवेश के अन्दर कुछ बोल जाते हैं। हम सदस्यों को एक-दूसरे में देखना पड़ता है कि उपाध्यक्ष महोदय ने क्या बोला। क्योंकि हमारे को आठवीं तक तो ए-बी-सी-डी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। नवीं में जाकर

(श्री शंकर लाल शर्मा)

ए-बी-सी-डी हमने पढ़ी। इसीलिये हम सदस्य देखते हैं कि उपाध्यक्ष महोदय ने अंग्रेजी के अन्दर हमारे को किस बात का डांटा है या कोई आदेश दिया है, यह आज हमारी हालत है।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में मत डांटा करें। हिन्दी में डांटा करें।

**श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): कृपलानीजी, सदस्यों से पूछ लो, यह असलियत है। हमारी यह कमी है। मैं भी बी.काम., एल.एल.बी. हूं लेकिन असलियत यही है कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता जब तक गांव के अन्दर नहीं होगी, हमारे गांव के बच्चों तक यह नहीं आयेगी, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये कि हमारे को आई.ए.एस., आई.पी.एस. और ये अधिकारीगण पूछते नहीं हैं। उसका अगर कोई कारण है तो हमारी पिछली सरकारों का कि शिक्षा की उन्होंने गुणवत्ता के ऊपर ध्यान नहीं दिया और मजबूरन आज हम उनके सामने, जो गैलेरी में बैठे हुए हैं, उनके सामने बात करो तो या तो वह ला की किताब या अंग्रेजी के शब्दों के अन्दर किताब खोल कर बता देंगे कि यह कानून में नहीं है, यह बात यह नहीं है या थोड़ी-बहुत अंग्रेजी में बात करके चुप करा देंगे। हमें जरूरत शिक्षा की गुणवत्ता की है, किसान के बेटे के गुणवत्ता की। जब 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है तो हमारा गांव का बच्चा आठवीं तक, दसवीं तक ए-बी-सी-डी अगर नहीं जानेगा तो वह क्या आगे जाकर विकास कर लेगा? हमारे बच्चे अपने आप में आत्म निर्भर हो जाएंगे? आपसे एक ही निवेदन है मांग-पत्र जो आज है तो उसके अन्दर हमारी सबसे पहली मांग यही है कि हमारे गांव की, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाये जिससे कि हमारा बच्चा भी अगर क-ख-ग-घ-ड. पढ़ रहा है तो उसके साथ ए-बी-सी-डी को भी स्टार्ट किया जाये। तब ही जाकर, यह जो 30 प्रतिशत शहरी वातावरण गांवों के ऊपर पूर्ण कायम है, तभी उसके साथ जाकर मुकाबला कर पायेंगे।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी को, हमारे शिक्षा मंत्रीजी को कि जो हालत हमारे प्राइमरी स्कूलों में थी, आज एकीकरण और समानीकरण के अन्दर करके उसके अन्दर गुणवत्ता बढ़ाने का काम किया। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी की सोच को। अभी बात आ रही थी संस्कृति की। आज संस्कृति के ऊपर हमें दुःख है कि आज हमारे बड़े से बड़े, जिन्होंने राजस्थान के अन्दर नाम कमाया, चाहे वह कवियों में हो,

(श्री शंकर लाल शर्मा)

चाहे संतों में हों, चाहे युद्ध के कारण अपना कौशल दिखाया हो, उनका कहीं नामोनिशान हमारी किताबों में नहीं था। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे कुशल शिक्षा मंत्रीजी ने उन महान हस्तियों को हमारे राजस्थान की संस्कृति को जीवंत रखने के लिये उनका नाम पाठ्यक्रम में लिया। आज मैं दौसा से आया हूं। दौसा के संत सुन्दरदासजी, जिन्होंने कि 38 काव्य-पाठ ग्रंथों को लिखा, जो कि अपने आप में संत दादूदयालजी के परम शिष्य थे, जिनको कोई भी नहीं जानता था। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उनके नाम से छह बीघा जमीन देकर पैनोरमा की स्वीकृति दी। अब पैनोरमा बनने वाला है। मैं मेरे शिक्षा मंत्री कालीचरणजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन संत सुन्दरदासजी के नाम पर दौसा के गर्ल्स कालेज का नाम किया। आज ऐसे महापुरुषों को अगर हम याद रखेंगे। वैसे ही कम्प्यूटर और मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई, अभी हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय दौसा के अन्दर गये थे और पोलोटेक्निक कालेज में गये।

**(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)**

हुकुम, मैं तो लास्ट वाला हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** दो मिनट आप और ले लें।

**श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): थोड़ा सा, हुकम, मैं अभी दौसा पर तो आया ही नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप दौसा पर जल्दी आ जाएं।

**श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): वैसे भी पहली बार सदस्य हैं। कम से कम भी हमको थोड़ा-बहुत बोलने के अन्दर हिम्मत बढ़ाने का।

**श्री उपाध्यक्ष:** आप पांच मिनट और बोलिये।

**श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): Thank you.

मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद अगर देना चाह रहा हूं तो इसके लिये देना चाह रहा हूं कि आप पधारे थे दौसा में, पोलोटैक्निक कालेज में जब गये, वहां की प्रिंसिपल ने आपको बताया कि हम मोबाइल बाहर रखवाते हैं। कालेज की अटैंडेंस लेते हैं। आपने महसूस किया वहां के वातावरण को, उस कालेज के वातावरण को। लेकिन आज मोबाइल हर स्कूल के बच्चे तक के हाथ में है। अगर वाकई शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो कम से कम भी स्कूल के अन्दर और इनके अन्दर मोबाइल लाने के ऊपर प्रतिबंध लगाना वाकई जरूरी

(श्री शंकर लाल शर्मा)
है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उच्च शिक्षा मंत्रीजी को, जहां तक डिमाण्ड का सवाल है कि दौसा पी.जी. कालेज को उन्होंने दो भागों में विभाजित करके साईंस और कामर्स को अलग और आर्ट्स को अलग किया। गर्ल्स कालेज के अन्दर भी दो सब्जैक्ट अभी दिये। हमारे पी.जी. कालेज में भी एक सब्जैक्ट समाज शास्त्र आपने दिया। संस्कृत कालेज, जो कि पूरे एरिया के अन्दर एक है, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे संस्कृत कालेज की बिल्डिंग में सुबह कालेज चलता था, शाम को स्कूल, वह बिल्डिंग साठ साल पुरानी। हालत यह है कि उसके झाड़ू कौन लगाये। दोनों में कम्पीटीशन होता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे शिक्षा मंत्रीजी को कि उन्होंने स्कूल और कालेज को अलग-अलग बिल्डिंग्स के अन्दर, रमसा के तहत स्कूल बिल्डिंग अलग और कालेज बनाने के लिये दो करोड़ रुपये स्वीकृत किये।

आज जहां तक शिक्षा का सवाल है, आदरणीय, थोड़ा-बहुत जिस तरीके से आपने संस्कृति के हिसाब से राजस्थान की पाठ्य-पुस्तकों में जीवन परिचय के रूप में मीरा बाई का, महाराणा प्रताप का, सूरजमलजी का, दुर्गादासजी का, पृथ्वीराज चौहानजी का, सभी का नाम दिया, इसी तरह से आपने कवियों का नाम, मीरा बाई और संत सुन्दरदासजी, इनका नाम दिया। उसके लिये भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा आपने फैसला कर रखा है कि जिस पंचायत समिति में कोई भी कालेज नहीं हो, आज हमारी लवाण पंचायत समिति पर कोई कालेज नहीं है। उसके बिलकुल अटैच्ड बस्सी है और पास में लालसोट का आधा एरिया आता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप उसके अन्दर कालेज दे दें तो बहुत-बहुत मेहरबानी होगी। साथ ही पी.जी. कालेज में आप पधारे थे, तब आपसे बच्चों ने डिमाण्ड की थी कि हमारे को भूगोल और हिन्दी, दो सब्जैक्ट और दिये जायें। साथ ही गर्ल्स कालेज के अन्दर भी आपने दो सब्जैक्ट देने की बात की थी। मैं आपसे चाहूंगा कि आप जैसा बोलते हैं, उसके ऊपर हर समय खरे उतरते हैं और मुझे उम्मीद है कि गर्ल्स कालेज में भी हिन्दी, जो कि अपने आप में राजस्थान के अन्दर ढाई हजार लड़कियां उस कालेज में पढ़ती हैं, के अन्दर अगर आप हिन्दी और राजनीति विज्ञान और दे देंगे तो मेरे एरिया के ऊपर बहुत-बहुत मेहरबानी होगी।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

मैं शिक्षा मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि हमारे एरिया के अन्दर पिछली बार पंचायत हैड-क्वार्टर के ऊपर स्कूल खोला। लेकिन उसके अन्दर तीन पंचायतें, कुण्डल...।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): लिखा हुआ दे दीजिये।

**श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा): मैं बिना पढ़े ही बोल रहा हूं, हुजूर। आप लेकिन एक बात इतनी ध्यान रखना, ये गांव के नाम हैं, जिसके अन्दर मैं बोल रहा हूं, कुण्डल है, सिंडोली है, उनके अन्दर स्कूल नहीं खोली। मैं यह चाहूंगा कि उनके अन्दर भी स्कूल खोल दी जाये। मेहरबानी करके आपने गांव का, किसान का जितना लोस किया है, उसके ऊपर कुछ तो शर्म करो बोलने से पहले।

अन्याय कर दिया, हमारे किसान के बेटे को आपने कभी नहीं चाहा कि वह आगे पढ़े और जहां तक काम का सवाल है, मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं हमारे शिक्षा मंत्रीजी से, हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी से और हमारे मुख्य मंत्रीजी से कि हमारी मांगें तो पूर्ण होंगी ही लेकिन शर्म आपको दिलवाना चाहता हूं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री मानसिंहजी।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मंत्रीजी खोल देना।

**(20.00 बजे)**

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-22-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर बहस चल रही है और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने लगभग सब विषयों को टच किया है। मैं समय की नजाकत को देखते हुए इर्रेलेवेंट बात नहीं कहूंगा और माफी चाहूंगा मेरे विपक्ष के साथियों से कि आप सुनने का काम करें।

जो हमारी शिक्षा ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उप मुख्य सचेतक को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभापति पैनल में नहीं रख सकते क्या आप? सारा झंझट ही मिट जाए।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): डोटासराजी, यहां पर हमारे जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस सदन को एक संकल्प पारित करना चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि इस देश में गरीबी,

(श्री मान सिंह)
अमीरी के भेद को, गरीब को गरीब दिखाने का काम, लाल बहादुर शास्त्री ने शिक्षा कहां प्राप्त की? इंदिरा गांधी ने शिक्षा कहां प्राप्त की? स्वर्गीय राजीव गांधी ने शिक्षा कहां प्राप्त की और जिसको वह भगवान कह रहे थे, उस बबुआ ने कहां शिक्षा प्राप्त की है? एक बार जरा दिल में सोचने का काम करें।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): आपका बेटा कहां पर पढ़ रहा है?

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): राजस्थान में, इंडिया में। राजस्थान, इंडिया में। पहले सरकारी स्कूल और राजस्थान में और उसके बाद में कहां पढ़ रहा है, वह अलग बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा जिस प्रकार से माध्यमिक से सीनियर स्कूल क्रमोन्नत किये गये, आठवीं का बोर्ड लागू किया गया, शिक्षा मंत्रीजी के प्रयासों से स्कूलों का जो एकीकरण हुआ, उस एकीकरण और समानीकरण के माध्यम से राजस्थान में साढ़े आठ लाख बच्चों का जिस प्रकार से नामांकन बढ़ा, बालिका शिक्षा में 4.8 परसेंट की वृद्धि हुई, उन सब बातों को ज्यादा लम्बे समय के लिए दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा के बजट को बढ़ोतरी करके और पिछले दो साल में जिस प्रकार का वातावरण बनाया है, शिक्षा को जिस प्रकार से एक महत्व देकर आज आठवीं का बोर्ड हो, चाहे हमारा जो माध्यमिक से सीनियर करने का हो, चाहे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का हो, इन सारी बातों को हमारे सदस्यों ने लगभग-लगभग सब कहा है।

मैं इस समय अपनी पीड़ा आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा कि हमारे जो सरकारी स्कूलों की हालत है, उस पर हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, दलों की सीमाओं से ऊपर हटकर करना चाहिए और मैं अनुरोध करूंगा शिक्षा मंत्रीजी, आज जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों के अन्दर और प्राइवेट स्कूलों में जो कम्पीटीशन हुआ है, उस पर निश्चित रूप से हमको हमारी मॉनिटरिंग, हमारा शिक्षा का जो कैलेंडर जब हम देखते हैं तो शिक्षा का कैलेंडर प्राइवेट स्कूल से अच्छा होता है। प्राइवेट स्कूल वाले सरकारी कैलेंडर की नकल करते हैं कि किस प्रकार से हमारा नामांकन चलेगा, किस प्रकार से हमारा प्रवेशोत्सव चलेगा, किस प्रकार से हमारी छुट्टी होगी, किस प्रकार से हमारा शैक्षिक सम्मेलन होगा, किस प्रकार से हमारा वार्षिक उत्सव होगा, किस प्रकार से हमारी रिपोर्ट वार्षिक जाएगी, वह सारे काम कागज पर जो करने के हैं, वह सरकारी अध्यापक मैं समझता हूं कि

(श्री मान सिंह)

सरकारी डाक में ज्यादा समय देता है। इस पर हमको एक बार सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से सरकारी स्कूल को किस प्रकार से हमको बढ़ोतरी देनी चाहिए। पिछले पांच साल में एक भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग तो दूर, जब उसकी रंगाई-पुताई भी नहीं हुई तो मैं पुन: धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि माननीय वसुन्धराजी ने 2013 में सरकार सम्भालते ही सबसे पहले प्रत्येक स्कूल को पांच-पांच हजार रुपये देकर उनका रंग-रोगन करने का काम किया है। जो झाड़ फ़ानूस उनके अन्दर लगे हुए थे, उनको सफाई करने का काम किया और यह विश्वास दिलवाने का काम किया कि यह विद्या के मंदिर हैं, इन विद्या के मंदिर को सुधारने का काम करेंगे और गांव का विद्यार्थी भी वही अधिकार रखता है जो शहर में रहने का काम करता है।

शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम जिस शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, उस शिक्षा में हम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उसमें मेरा व्यक्तिगत एक निवेदन है, उसको मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि हम लोग क्यों नहीं इस हाई स्कूल पर दो तरह के स्कूल कर दें? एक टैक्निकल हाई स्कूल हो और एक नार्मल हाई स्कूल हो। आज हम जब आई.टी.आई. की तरफ जाते हैं, आई.टी.आई. में जिस प्रकार से आपके क्यू.सी.आई. के नियम हैं, जिस प्रकार से आपके तकनीकी शिक्षा परिषद के नियम हैं, एक काकस उसके अन्दर भी बना हुआ है। उस काकस के माध्यम से आई.टी.आई. की किस प्रकार से स्कालर-शिप आती है, गरीब के बच्चे का वहां पर भी शोषण होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम टैक्निकल हाई स्कूल का माडल राजस्थान में, हिन्दुस्तान में एक माडल देने का काम करें तो हमको किसी भी टैक्निकल आई.टी.आई. की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर टैक्निकल हाई स्कूल हम बना देते हैं तो वह बच्चे को वही डिग्री मिलेगी जो आई.टी.आई. के बराबर होगा और वह बच्चा हमारा उस डिग्री को लेने के बाद में, आज जो हम स्किल्ड डवलपमेंट का जो सर्टिफिकेट से नौकरी देने का काम कर रहे हैं, वह डिग्री उसको वहीं मिल जाएगी और उस गरीब के बच्चे को उस ALLEN की कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उस कोचिंग से उसको फायदा उससे पहले ही मिल चुका होगा। तो जिस बच्चे को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, हमारी लोकल सर्विसेज में जाना है, एविएशन में जाना है, सिविल में जाना है, वह नार्मल हाई स्कूल के माध्यम से अपनी शिक्षा को लें लेकिन एक माडल के रूप में अगर सम्भाग स्तर पर भी एक बार

(श्री मान सिंह)

हम प्रयास करने का काम करें तो राजस्थान की शिक्षा के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन करने का हम विचार कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर हमारे को एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी भी एक लकीर की फकीर, ढर्रे पर जिस प्रकार से अगर कोई एक बात तय हो गयी कि हमको इसी प्रकार से चलाना है, नहीं। क्योंकि, यह शिक्षा हमारे समाज की बुनियाद है और इस बुनियाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस पर हमको विचार करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रोजगारोन्मुखी शिक्षा किस प्रकार से हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों को किस प्रकार से रोजगार से हम जोड़ सकते हैं? राजस्थान को हम किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं? आज स्किल्ड डवलपमेंट पर हमको गर्व है कि राजस्थान हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर है लेकिन निश्चित रूप से मैं इस बात का हामी हूं, मानिकजी सुराना यहां से चले गये, वह कह रहे थे कि वह सर्टिफिकेट छह माह का होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए।

आज हमारा थ्री ईयर डिग्री कोर्स, जब कालेज का चलता है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, हाई स्कूल तक तो ठीक है लेकिन कालेज के लेवल पर सरकारी कालेजों की जो वैल्यू है, उसमें हर बच्चा सरकारी कालेज में जाना चाहता है, वह हमारे लिए एक संतोषप्रद चीज है। उसको जिस प्रकार से हमने मेन्टेन किया है, जिस प्रकार से और मेन्टेन कर सकते हैं, उसको भी हमको करना चाहिए लेकिन जब कालेज के अन्दर जो बच्चा होता है, उसको हम न कोई इंटर्नशिप के बारे में सोचते हैं। आज अगर कालेज के बच्चे से आप पूछ लो कि 'महानरेगा' क्या है और 'महानरेगा' का काम किस प्रकार से चलता है? तो वह नहीं बता सकता है। क्यों नहीं हम हमारे बच्चे को पंचायत समिति के अन्दर, 50-50 बच्चों को उनको वहां पर भेजने का काम करें? क्यों नहीं हम एस.डी.एम. कोर्ट, तहसीलदार के यहां पर उन बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करें? क्यों नहीं हमारा बच्चा बैंकिंग सिस्टम को समझने का काम करे? क्यों नहीं हमारा बच्चा रेलवे के सिस्टम को समझने का काम करे? लेकिन हम उस चीज को लागू नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा जिस प्रकार का शिक्षा का ढर्रा बन चुका है, वह केवल किताबी ज्ञान के आधार पर जब बच्चा जाता है, और उसको वहां कालेज में उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है तो वह चाय

(श्री मान सिंह)

की थड़ी पर बाहर बैठता है और फालतू की बातें करता है। उसको रास्ता दिखाने का काम हमको करना होगा। उसको रोजगार से जोड़ने का, उसको इंटर्नशिप से जोड़ने का काम हमको करना होगा। अगर हम वह नहीं करेंगे तो हमारी कालेज शिक्षा के अन्दर विकरालता आएगी इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से हमारा...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): कोई खास बात नहीं है, माननीय सदस्य, मंत्रीजी, वैसे भी सो रहे हैं। कोई खास बात नहीं है, नहीं कहो तो भी चलेगा।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर): मैं कोई भी इर्रेलेवेंट बात एक भी नहीं बोलूंगा। आप सुन लीजिए, मैं एक भी इर्रेलेवेंट बात नहीं बोलूंगा, मेरी बात अगर दर्ज होगी, कोई उसको पढ़ेगा, कोई उसको इम्प्लीमेंट करेगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। इर्रेलेवेंट बात, मैंने पहले ही कह दिया उपाध्यक्षजी से कि मैं बोलूंगा नहीं। मैं केवेल रेलेवेंट बात बोलूंगा जो मेरे मन की है और मन की पीड़ा इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस पवित्र सदन में हैं, उस सदन का आपने जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से उस शिक्षा नीति को वहां पर पहुंचाने का काम किया, आज हमको उस पर विचार करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ में मेरे क्षेत्र की जो हमारे माध्यमिक से सीनियर स्कूल किये गये थे, उसमें हमारी भी दो पंचायत श्यारोली और महुकलां, केवल इसलिए छोड़ दी गयी कि वहां पर प्राइवेट स्कूल है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल गरीब के लिए आज भी महंगा है। सरकार को इस पर खुले मन से विचार करना चाहिए, पूरे राजस्थान में जो पंचायतें रह गयी हैं, सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहेंगे कि उन पंचायतों के अन्दर प्राइवेट स्कूल के नाते हमको नहीं छोड़ना चाहिए और वहां पर भी सीनियर हमको करना चाहिए। क्योंकि यह हमारे शिक्षा के हित में है, जनता के हित में है।

इसी के साथ में शिक्षा मंत्रीजी, आपने पी.जी. कालेज में जो कामर्स का विषय शुरू किया है, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कामर्स के ए.बी.एस.टी. और स्टेटिस्टिक्स के दो विषय चालू किये हैं, इसी के साथ-साथ में आर्टस में भूगोल विषय, जिसके लिये हमारे वहां के बच्चों की मांग है, उस भूगोल विषय को चालू करने के बाद में हमारे पी.जी.

(श्री मान सिंह)
कालेज में तीनों फैकल्टी हैं और तीनों फैकल्टीज के हिसाब से हमारा कालेज पूर्वी राजस्थान का सबसे अधिक संख्या वाला कालेज है। वह बहुत अच्छा चल रहा है और आपसे अनुरोध करूंगा कि वहां की एस.टी. के बच्चों की संख्या को देखते हुए वजीरपुर उपखण्ड में एक कालेज की आवश्यकता है और जिस प्रकार से हमारा बजट है, उस बजट के अन्दर मैं समझता हूं हमारा 50 परसेंट पैसा तो प्राथमिक शिक्षा पर है, 43 परसेंट पैसा हमारा माध्यमिक शिक्षा पर है और 3.7 परसेंट पैसा हमारा उच्च शिक्षा पर है। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इस पर एक परसेंट भी बढ़ाती है तो हमारे सारे कालेज, करीब 70 कालेज एक परसेंट में और बढ़ सकते हैं। इस पर सरकार को विचार करके आने वाले समय में इसको करना चाहिए जिससे हमारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसी के साथ में, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे कला और संस्कृति में सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेशजी की धरती है। सवाई माधोपुर में केवल रणथम्भौर का ही टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे धार्मिक हिसाब से जो कोरिडोर बनता है, करौली और सवाई माधोपुर, दोनों को मिलाकर हमारा रणथम्भौर का त्रिनेत्र गणेशजी का मंदिर, कैला देवी का मंदिर, चौथ माता का मंदिर, चौथ माता और कैला देवी के लिए सरकार ने विकास की सूची में ले लिया है, उसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन इसको पूरा जोड़ने के लिये हमारे शिवाड़ का घुश्मेश्वर महादेव तेरहवां ज्योतिर्लिंग है, उससे मिलाते हुए महावीरजी गम्भीरी नदी पर होकर महावीरजी का स्थान है और गंगापुर सिटी के अन्दर जो हमारा धूणेश्वर धाम है, इसको एक धार्मिक कोरिडोर अगर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि लाखों पर्यटक वहां आते हैं और सरकार सब जगह अच्छी रोड़ देती है, मैं कला एवं संस्कति मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस विषय पर सोचने का काम करें। इसी के साथ-साथ सरकार ने अब की बार जो पैनोरमा बनाने का काम किया है, मैं इस सदन में एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे करौली जिले के कमलराम जी, जिनको विक्टोरिया क्रोस मिला था द्वितीय विश्व युद्ध के अन्दर, राजस्थान के एक मात्र व्यक्ति हैं जिनको एलिजाबेथ ने विक्टोरिया क्रोस दिया था और उन्होंने किसी और उपाधि को लेने से मना कर दिया था, उस व्यक्ति के नाम पर भी वहां पर पैनोरमा बने, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिन्द। जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री कन्हैया लालजी (अनुपस्थित) श्री कैलाश वर्मा। सम्मानित सदस्य, एक मिनट। I missed one name, Hiralal ji, sorry.

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-24 शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिये मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। सचेतक और उप सचेतक साहब का भी बहुत-बहुत आभारी हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आभारी तो आप एक ही व्यक्ति का कहिये, उनका कोई लेना-देना नहीं है। आसन के आभारी हो जाइए आप।

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत को जगतगुरु पूरा विश्व मानता है और आज भी है। यहां हमारे देश में ऐसी हस्तियां हैं जिनको पूरा विश्व याद करता है। हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में नालन्दा, तक्षशिला, वाराणसी और काशी विश्वविद्यालय, यह प्राचीन समय से हैं और इसीलिए भारत को जगतगुरु कहा जाता है और आज भी वह प्रतिभाएं हमारे छात्रों में और शिक्षकों में मौजूद हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका वालों, सचेत हो जाओ, जागो, नहीं तो भारतीय आ जाएंगे। निश्चित रूप से भारत के छात्र और यहां के शिक्षक विश्व में अपना एक स्थान रखते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की सीधे ही मांगों पर आऊं, उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने शिक्षा और कला संस्कृति पर बहुत अपने सारगर्भित और ज्ञानवर्धक भाषण दिए। आज का बालक राष्ट्र का दर्पण है, राष्ट्र का निर्माता है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बालक का कैसे विकास करना चाहते हैं, उसको राष्ट्र निर्माता कैसे बनाना चाहते हैं, उसका विकास कैसे करेंगे, इस पर सोचिये। फालतू बातें करने से तो कोई मतलब नहीं होता है। बच्चों के विकास के लिये शिक्षा जरूरी है और शिक्षा जरूरी होगी तो उसकी चिकित्सा भी जरूरी है। शिक्षा, चिकित्सा और जन सुरक्षा, पुलिस, यह तीन महकमे ऐसे हैं, जो हमारे बच्चों के विकास के लिये, प्रदेश के विकास के लिये, देश के विकास के लिये अपना एक स्थान रखते हैं। शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा, इनके लिये हमें और भी ज्यादा बजट खर्च करना पड़े, कई संसाधन जुटाने पड़ें तो हमें जुटाना चाहिये, तब ही हमारे प्रदेश का विकास होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वसुन्धराजी ने प्रदेश की सत्ता 2003 में संभाली थी। उनका कार्यकाल और विकास पूरे राजस्थान और देश ने जाना है। आपकी जो सरकारें रही हैं, उनको भी प्रदेश जानता है। माननीय वसुन्धराजी ने पुनः ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, आज वह बात नहीं है, जो होनी चाहिये।

**श्री हीरालाल** (निवाई): माननीय 2013 में वसुन्धराजी ने पुन: राजस्थान की बागडोर संभाली और उनके नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरणजी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री देवनानीजी ने भी शिक्षा में नये आयाम पैदा किये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये निवेदन करना चाहूंगा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से, कि सब जगह उपखण्ड पर कालेज खोल रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि पीपलू बहुत पिछड़ा हुआ इलाका और उपखण्ड है, वहां पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। मेरे निवाई में महाविद्यालय है उसको पी.जी. महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का आदेश फरमाएं। यहां पांच हजार स्कूलें खोलीं, सबने बताया तो मैं उसमें ज्यादा बहस में नहीं पडूंगा, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में छह पंचायतें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत होने से रह गयी हैं, उसमें कोई तकनीकी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे यहां छह स्कूलें हैं – लुहारा, शहीद जयनारायण जाट के नाम पर है, ढाणी जुगलपुरा, नटवाड़ा, सुनारा, सेदरिया और बिडोली, यह छह पंचायतें रह गयी हैं। इन छह पंचायतों में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत इसलिए नहीं किया गया कि यहां पर निजी क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। मेरा माध्यमिक शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस तरह की तकनीकी खामी को दूर करके कोई एक नीति बनाकर करें। सभी ने कहा कि मेरे यहां रह गयीं, मेरे यहां रह गयीं। मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र में छह स्कूलें रह गयी हैं, जिनको क्रमोन्नत किया जाए। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भूगोल विषय खोला जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई में भूगोल और कृषि विज्ञान विषय खोला जाए। मेरा निवाई का सबसे बड़ा कस्बा झिलाय है उस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय खोला जाए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कई बार माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भी निवेदन किया है कि मेरे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलू, रानोली, कठमाड़ा, झिराना, बनवाड़ा में अध्यापकों की कमी है, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इस बार तो परीक्षाएं होने वाली हैं लेकिन अगले सत्र में इन रिक्त पदों को भी भरने की कृपा करें।

(श्री हीरालाल)

साथ ही विद्यालयों में इस तरह का भी संज्ञान में आया है कि स्कूल में शिक्षक शराब पीकर आ जाते हैं, कहीं शिक्षक छात्राओं से ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे भी मैटर आये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे शिक्षकों को तुरन्त टर्मिनेट किया जाए। जो इस तरह की उनकी हरकतें हैं, चाहे वो शराब पीये हों, चाहे हमारे छात्राओं से कोई इस तरह की हरकत करे तो उनको नौकरी से टर्मिनेट कर देना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को शिक्षा मिले, दूसरे अध्यापकों को शिक्षा मिले। वो सारे शिक्षा जगत में, सारे स्कूल की शिक्षा का एक तरह का कलंक है।

स्कूलों में महापुरुषों के श्लोक अंकित किये जाएं। स्कूलों के आसपास जर्दा और गुटका की दुकानें हैं जबकि सौ मीटर की परिधि तय कर रखी है, उस सौ मीटर की परिधि में अगर जर्दा और गुटके की कोई दुकान हो तो वो बच्चों को खराब करते हैं। बच्चे खाते हैं, तो उन दुकानों के दुकानदार के प्रति भी कठोर कार्यवाही की जाए क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, जर्दा, गुटका खाते हैं। एक छोटी सी उम्र में जर्दा, गुटका खाते हैं, स्कूलों में वो क्या शिक्षा लेंगे इसलिए मेरी यह प्रार्थना है।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में सांस्कृतिक दृष्टि से देव महाराज का स्थान है और हमारे टोंक जिले में डिग्गी श्री कल्याण जी और देव महाराज, देव नारायणजी का लक्खी मेला भरता है, मैं माननीय पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से जोड़ा जाए। वहां मांसी डैम है, बहुत बड़ा बंधा है और लाखों लोग इकट्ठे होते हैं तो धार्मिक दृष्टि के साथ ही एक सांस्कृतिक दृष्टि से उनको लिया जाए।

साथ ही मेरे क्षेत्र में निवाई में महिला कालेज नहीं है इसलिए मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे उप-खण्ड निवाई में महिला कालेज खोला जाए चूंकि छात्राओं को बड़ी दिक्कत होती है, या तो पढ़ने वो जयपुर जाएं या टोंक जाएं इसलिए।

दूसरा, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय वसुन्धराजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरे यहां महाविद्यालय खोला और आपने उस कालेज का निर्माण करने के लिए तीन करोड़ रुपया दिया, जो बहुत युद्ध स्तर पर बन रहा है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री कैलाश वर्मा।

**श्री कैलाश वर्मा** (बगरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा जैसी मांग के ऊपर आज सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच में वाद-विवाद चल रहा है और यह बात सही है कि एक राज्य की स्थिति को और देश की स्थिति को सुधारने में कहीं न कहीं शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है।

इस दो साल के कार्यकाल के अन्दर राजस्थान की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना जबरदस्त कार्य किया है जो आने वाले समय के अन्दर इस राजस्थान के इतिहास के पन्नों में लिखा जायेगा। कहीं न कहीं शिक्षा की जहां पर बात आयेगी तो विकास के साथ में शिक्षा को आधारशिला मानकर क्योंकि यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं, विपक्ष के अन्दर साथी बड़े कम हैं और जब सुबह वैसे तो क्वेश्चन लगते हैं, सभी सदस्यों के लगते हैं मगर पर्ची के माध्यम से भी सदस्य बोलना चाहते हैं, एक माननीय सदस्य महोदय ने मेरे को बोला, पहली बार राजस्थान के अन्दर हर क्षेत्र के अन्दर इतना विकास हो रहा है, हमारा तो धर्म है, हम बोलना नहीं चाहते मगर क्या करें धर्म के नाते हम विपक्ष के अन्दर हर मांग को उठाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर ...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सुबह कह रहे थे कि मैं केवल कला पर बोलूंगा और आप शिक्षा पर बोलने लग गये।

**श्री कैलाश वर्मा** (बगरू): अब आप बैठो तो सही, सुनो तो सही।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अब आप कलाकार से लग रहे हो तो कला पर बोलो न, काहे की शिक्षा पर। कला पर किसी ने नहीं बोला, थोड़ा आप बोलो।

**श्री कैलाश वर्मा** (बगरू): बैठो, बैठो।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़): इसका मतलब आपने कहा था, आपने जवाब दे दिया...(व्यवधान)

**श्री कैलाश वर्मा** (बगरू): आज हमारे समाज के अन्दर वाकई में यह बात सही है कि जब तक गांव का व्यक्ति पढ़-लिख कर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान और हिन्दुस्तान में उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहां पर हमारे विकास की रूपरेखा तय होती है, जहां पर देश के कानून बनते हैं तब तक हम कितना ही कुछ कर लें, शिक्षा के इस बिगड़े हुए ढर्रे को नहीं सुधार सकते और यह कहीं न कहीं इन लोगों के ऊपर जरूर लागू होता है। यह इनको पता भी है

(श्री कैलाश वर्मा)

कि आजादी के बाद के समय में अगर यह लोग शिक्षा तंत्र को इतना मजबूत किया होता और आज वाकई में गांव का व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ इतना मजबूत होकर राजस्थान और हिन्दुस्तान की उन कुर्सियों पर जाकर बैठा होता तो शायद शिक्षा की यह स्थिति आज राजस्थान और केन्द्र के अन्दर नहीं होती।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, यह कांग्रेस की ही देन है कि आप इतना शानदार बोल रहे हो। आप इतना शानदार बोल रहे हो न, यह कांग्रेस ने ही पढ़ाया था, आपको शिक्षा दी थी तभी बोल रहे हो। (व्यवधान)

**श्री कैलाश वर्मा** (बगरू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रति सरकार बड़ी गम्भीर है और इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में चाहे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया, चाहे मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे बालिकाओं को साइकिल के माध्यम से, स्कूटी के माध्यम से प्रोत्साहन देकर किया।

आप हमेशा एक ही बात के ऊपर तर्क करते हो, आने वाले समय के अन्दर भारतीय जनता पार्टी ने यह कर दिया, हमारी योजनाएं थीं, उनको बंद कर दिया, मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा नीति की योजनाओं को बंद करने का काम नहीं किया, सुधारने का काम किया है जो आप लोगों ने बिगाड़ रखा था।

आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र का युवा हर क्षेत्र के अन्दर शिक्षा के माध्यम से, तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वैज्ञानिक हो, हर युवा ने अपने आपको आने वाले समय के अन्दर तकनीकी शिक्षा में, कम्प्यूटर की शिक्षा में इतना मजबूत कर दिया कि आने वाले समय के अन्दर एक युवा शिक्षा के माध्यम से इस देश का कर्णधार बनेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आज विशेषकर यहां पर शिक्षा पर लगभग दो बजे से वाद-विवाद चल रहा था, शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण डिमांड के माध्यम से मेरे को पता है कि मेरे को दस मिनट इस सदन के माध्यम से बोलना है और मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो प्रमुख मांगें हैं उनके ऊपर भी आऊंगा और विशेषकर जो आप लोगों ने किया शिक्षा तंत्र का बंटाधार, बंदरबांट लूट, उसके बारे में भी बताऊंगा क्योंकि बताना जरूरी है।

(श्री कैलाश वर्मा)

आप हर क्षेत्र के अन्दर, हम तो पहली बार चुनाव जीतकर आये हैं। विशेषकर, जैसे यहां पर पूर्व अध्यक्ष के रूप में हनुमान जी बेनीवाल भी बोल रहे थे। धीरज जी भी बोल रहे थे। अभी सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आने वाले समय में हम सत्ता में आयेंगे। यह फैसला तो जनता करेगी। यह फैसला तो जनता को करना है कि कौन सत्ता में आयेगा और कौन सत्ता में नहीं आयेगा। किसने जनता के साथ धोखा किया और किसने जनता की नीतियों को गांव, ढाणी और गरीब तक पहुंचाया। यह आने वाले समय में जनता फैसला करेगी।

पहली बार शिक्षा के प्रति सरकार इतनी गम्भीर है कि शिक्षा की नीतियों को इस बजट के माध्यम से लागू कर रही है। आप बोलते हो कि योजनाएं लागू कर दो। नेताओं के, आईएएस अधिकारियों के भी लड़के सरकारी स्कूलों के अन्दर पढ़ें। सरकारी कालेजों के अन्दर पढ़ें। बड़े-बड़े वादे करते हैं। बड़े-बड़े भाषण यहां पर देते हैं। एक जन प्रतिनिधि का अधिकार बनता है कि प्रोटोकाल के रूप में बीडीओ, एसडीएम, डीईओ, तमाम शिक्षा अधिकारी, मैं इस बात को मानता हूं कि एक एमएलए डीईओ को फोन करे, एसडीएम को फोन करे या बीडीओ को फोन करे तो वह क्षेत्र में जाये। चाहे एमएलए पक्ष को हो और चाहे विपक्ष का हो। वह अधिकार समझकर के जाता है। मगर हम हमारे अधिकारों को नहीं समझते।

जब समय आता है तो पक्ष-विपक्ष के तौर पर बाण चलते हैं, इधर से और उधर से। मगर आपको मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि विपक्ष के जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, आप अपनी आत्मा से देखें कि आजादी के बाद आपने कितने समय राज किया और शिक्षा के क्षेत्र को कितना मजबूत किया। अंग्रेजों की शिक्षा नीति को कितना बढ़ाया और जब समय आया गरीब का, जब समय आया किसान का तो उसी के साथ छलावा कर दिया। क्या हो रहा है उस अन्नदाता के साथ में? आज लगभग 80 से 90 परसेंट बच्चे गांवों के अन्दर सरकारी स्कूलों में अन्नदाता के पढ़ते हैं।

मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं जिन्होंने माडल स्कूल के तहत पंचायत स्तर पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया। इससे शिक्षा तंत्र मजबूत होगा। आने वाले समय में इससे शिक्षा को मजबूती मिलेगी चाहे वह बालिका शिक्षा हो, चाहे बालक शिक्षा हो। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से भी आज पूरे राजस्थान में चाहे मेडिकल कालेज के रूप

(श्री कैलाश वर्मा)

में हो, चाहे आर्ट्स कालेज के रूप में हो, जगह-जगह शिक्षा का वातावरण बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह शिक्षा को वाकई में बहुत मजबूत करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ठेठ ढाणी के अन्दर बैठा हुआ कोई वहां का प्रतिनिधि हो, चाहे वह किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि हो, आज सरपंच गांव की चौखट पर बैठा हुआ इतना मजबूत प्रतिनिधित्व करता है। कहीं न कहीं जैसे अभी मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे कि टीचर चाहे अश्लील हरकत करे, चाहे वह जर्दे के माध्यम से हो, चाहे शराब के माध्यम से हो, वह स्कूल के अन्दर जाता है तो उसके खिलाफ कोई न कार्यवाही होनी चाहिए।

यह बात बिलकुल सही है कि जब यह बात जन प्रतिनिधि के पास पहुंचती है, चाहे सरपंच के माध्यम से पहुंचे, चाहे प्रधान के माध्यम से पहुंचे, चाहे जिला प्रमुख के माध्यम से तो एमएलए मंत्रीजी से मिलता है और उसके ट्रांसफर के आर्डर निकलवाता है तबादला नीति के रूप में और वही टीचर कोर्ट से उस आर्डर के ऊपर स्टे लेकर के बैठ जाता है। यह क्या नीति है? क्या यह देश का दुर्भाग्य है? स्टे लेने के बाद में बालक और बालिकाओं के साथ में जो हरकत होती है, उनके भविष्य के साथ में कुठाराघात वह करता रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में इस तबादला नीति में भी ऐसा कोई प्रोविजन बनायें जिससे इन बालक-बालिकाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होने से रुके।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांग के ऊपर कहना चाहता हूं कि 30 ग्राम पंचायतें आती हैं बगरू विधान सभा क्षेत्र में, 5 ग्राम पंचायतें नई बनी हैं। विशेषकर इन नई ग्राम पंचायतों में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रोसेस चल रहा है, उसमें एक उच्च माध्यमिक विद्यालय इन ग्राम पंचायतों में खुल जाये।

सम्माननीय मंत्रीजी की भी आस्था गोनेर जगदीश महाराज मंदिर में है। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि 250 करोड़ रुपया लगाकर के गोनेर के जगदीश महाराज के मंदिर को राजस्थान के उन मंदिरों के अन्दर ला खड़ा किया जिनकी बहुत बड़ी आस्था है। वहां पर डाइट, गोनेर जो शिक्षा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, आने वाले समय में उसके लिए भी एक ऐसी नीति बन जाये जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिले, मजबूती मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बगरू नगरपालिका है। उप

(श्री कैलाश वर्मा)

खण्ड स्तर पर सरकार अगर कालेज खोलने का विचार रखती है तो 44 हजार जनसंख्या की यह नगरपालिका है, एक बालिका महाविद्यालय उस बगरू उप खण्ड पर भी खुल जाये। वैसे तो मांगें बहुत हैं, मैंने लिखित में दी हैं।

जो विपक्ष के साथी यहां पर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर, इस राज्य के अन्दर अगर सबसे बड़ा भगवान है तो वह है माता-पिता। राजनीति के अन्दर हम माता-पिता को भूल गये। राजनीति में ही आ गये। यह सब विधाता की बात है कि किसको टिकट मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या होगा। विशेषकर, इस राजनीति के लिए माता-पिता को भूल जायें और एक ऐसे व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए, हम तो भगवान मानते हैं और हमारा तो भगवान है। क्या हो गया इस देश की व्यवस्था को? क्या होगा इस देश की शिक्षा का? मैं बधाई देता हूं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि शिक्षा नीति को इतना मजबूत इन्होंने किया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बोलते हैं कि डीईओ, शिक्षा अधिकारी, बीईओ, एसडीएम, बीडीओ, मंत्री गांव के अन्दर नहीं जाते। राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि आने वाले समय में जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, हम उस व्यक्ति को पंच बनायेंगे, सरपंच बनायेंगे, प्रधान बनायेंगे। जीवन के अन्दर एमएलए, एमपी बनना, लाल बत्ती की गाड़ी लेकर गांव में घूमना, कीर्ति प्राप्त करना, यह तो इस देश की परम्परा चली है। इस परम्परा को गांव, ढाणी तक कौन पहुंचाता है, इस बात को देखने की जरूरत है।

मैं विपक्ष के साथियों को यह भी कहना चाहूंगा कि देश आजाद होने के बाद सरकारें आईं और गयीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया और कांग्रेस ने भी राज किया, गठबंधन की सरकारों ने भी राज किया। मगर जब विपक्ष के साथी, सब लोग यहां पर बैठे नहीं हैं, मगर फिर भी यहां पर प्रतिपक्ष के नेता और सचेतक महोदय, डोटासराजी, मेरी बात को उन तक पहुंचा देना, कि रात को जब यहां से फ्री होने के बाद में जाओ, सारे काम से आप फ्री हो जाओ, जब बंद कमरे में सोने का समय आपका आये, तब लाइट बंद करके दो मिनट यह सोचना कि हमने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, सब समझ में आ जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपको बारम्बार प्रणाम करता हूं। बहुत-बहुत बधाई। राम राम।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री सुखारामजी।

**श्री सुखाराम** (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज शिक्षा की मांग संख्या 24 पर बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक साथ 5 हजार स्कूलें क्रमोन्नत करके शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। जो इस राजस्थान में पहली बार हुआ है। इसी के साथ मास्टरों की डीपीसी करवाकर 95 प्रतिशत प्रमोशन देने का कार्य भी सराहनीय है।

आज दसवीं एवं बारहवीं की स्कूलों में मास्टर करीब 90 परसेंट लगे हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी छात्राओं को नि:शुल्क साइकिलें देने का भी काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आने के बाद आठवीं बोर्ड परीक्षा शुरू की, इससे गरीबों के बच्चों को भी फायदा होगा।

मेरे नागौर जिले में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने मास्टरों की भर्ती में नैट, स्लैट को खतम कर रीट परीक्षा चालू कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे सभी शिक्षा में फायदा होगा। इस प्रकार हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। पंचायती राज में सरपंचों की योग्यता आठवीं पास कर गांवों में शिक्षा के प्रति पर्याप्त जागृति पैदा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत संवेदनशील हैं और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयास करती हैं। हमारे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय, यूजी कालेज बने हुए करीब 20 साल हो गए हैं, तब से लेकर आज तक क्षेत्र के करीब 200 गांवों के लगभग 5,000 छात्र यहां पढ़ने आते हैं, बारहवीं कक्षा के बाद तीन साल तक यहां पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद उनको पीजी के लिए 100 किलोमीटर दूर, नागौर 120 किलोमीटर, अजमेर 100 किलोमीटर, जोधपुर 135 किलोमीटर जाना पड़ता है, इस क्षेत्र में कोई पीजी कालेज नहीं है इसलिए इसे पीजी कालेज करवाने की कृपा करें। इस कालेज में पिछले 20 सालों से किसी प्रकार की मरम्मत नहीं हुई है, शिक्षा मंत्रीजी वहां

(श्री सुखाराम)

खुद मौके पर आकर देख चुके हैं तो कुछ इस मीरा बाई की नगरी के वास्ते हमारे को मरम्मत का पैसा 2 करोड़ रुपया दिलवाने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमारे 8 पद भरे हुए हैं, बाकी सारे पद रिक्त हैं इसलिए मैं कहता हूं कि वे पद भी भरे जाएं। आपने भी आश्वासन दिया था जब आप क्षेत्र में पधारे थे, हमारे ज्योग्राफी विषय भी खुलवाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं बालिका कालेज की भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वह भी हमारे यहां खुलवाई जाए, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्रीमती शकुन्तला रावत। (व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, ...(व्यवधान) नाम नहीं था तो आप चौंक क्यों रहे हो, यह तो उपाध्यक्ष महोदय की मेहरबानी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की मांग रखना चाहूंगी। अलवर जिले में जो यूनिवर्सिटी का काम अधूरा है उसमें बच्चों को फार्म भरने में बहुत दिक्कत आ रही है मेडिकल कालेज का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो कई बार कालेज की मांग की बानसूर के लिए, स्थगन के जरिए, 295 और याचिका के जरिए भी लेकिन जवाब यही आता है कि बानसूर में 5-5 प्राइवेट कालेज हैं इसलिए अभी सरकार की मंशा नहीं है तो मुझे इंतजार रहेगा कि कब तक आपकी मंशा बनेगी। एक तरफ तो आप शिक्षा के लिए इतनी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं पर यह मंशा कब बनेगी? यह भी बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो माननीय मंत्रीजी, मैं यह मानूंगी कि आप भेदभाव करते हैं। (व्यवधान)

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): विचार कर रहे हैं।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): ...(व्यवधान) विचार वही बात है क्योंकि मैं तो समझूंगी कि भेदभाव ही कर रहे हैं हमारे साथ में। जैसा अभी कालूलालजी कह रहे थे। एक बार कालूलालजी ने भी यही जवाब दिया कि आपके यहां कालेज है। इनको जानकारी में नहीं था कि वहां सरकारी कालेज नहीं है।

बालिकाओं के विद्यालय में विषय अध्यापक नहीं है। बार-बार मामला विधान सभा में उठाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया मंत्री महोदय। अन्य

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

विद्यालयों में लगे हैं पर सरकारी विद्यालयों में अधिकतर बालिकाएं पढ़ती हैं तो उन विद्यालयों में जरूर लगाएं। कई जगह दो-दो अध्यापक रहते हैं और एक अध्यापक डाक देने के लिए चला जाए तो कई-कई दिनों तक विद्यालयों की छुट्‌टी रहती है तो यह भी शिक्षा का कहना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में नमूना है।

सीनियर सैकण्डरी स्कूल और सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूलों में आज तक रमसा में या एसएस के तहत कोई भी काम नहीं हुआ है दो वर्ष के अन्दर। बार-बार हमने प्रस्ताव भिजवाएं हैं, तभी भी नहीं हो पा रहे हैं लिस्ट मैंने भिजवा दी है आफिस के जरिए भी और उदाहरण के लिए जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि हर ग्राम पंचायत में सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो जाएगा, नई खुलने वाली थी वह बात तो और है लेकिन जो पंचायत हैं, उनमें भी नहीं हुआ है, शाहपुरा है, खेड़ा है, माजराई, बाजदयाल, देवसन, रसनाली, बगूकाबास, बबेरा, सबलपुरा आदि अनेक पंचायत हैड क्वार्टर हैं और इनमें लड़कियां सैकड़ों की मात्रा में पढ़ रही हैं इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध है कि ये विद्यालय जल्दी से जल्दी क्रमोन्नत किए जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन काल की हमारी जो धरोहर हैं चाहे किले हैं, चाहे बानसूर का किला है, चाहे पुराने हमारे जो मंदिर ऐसे हैं जो पर्यटक स्थल है, चाहे ताल वृक्ष, शीतलनाथजी, भर्तृहरिजी का मंदिर है ऐसी चीजों को और जो पुरानी बावड़ियां हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अनुरोध और है मेरा कि जितना शहरों के अन्दर गार्डन हैं या पर्यटक स्थल हैं वहां पर भी गार्ड लगाए जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि वहां असामाजिक तत्व नहीं पहुंचे। जयपुर के ही किसी भी गार्डन में जाकर देखें तो बहुत बुरा हाल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का और जो नौकरी कर रहे हैं सारे प्रेरक, विद्यार्थी मित्र, कम्प्यूटर शिक्षक और रोजगार सहायक, यह सारे ही बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक उम्मीद लगाकर के बैठे हैं कि सरकार शायद हमारी कोई मंशा सुन ले। कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कि एसएस के तहत या रमसा के तहत शौचालय, भवन, आफिस दे सकते हैं। मैंने तो कई विद्यालयों में दिया है खुद ही जाकर के, जहां भी जाती हूं, जिस गांव या ढाणी में जाती हूं तो विद्यालय में जाकर देखती हूं कौनसी चीज की कमी है और जितना मेरे से बन

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
पड़ता है वह पूरा करते हैं लेकिन आप तो इस तरीके का कोई फंड नहीं देते जिससे शिक्षा पर या किसी और चीज पर उसको खर्च कर सकें।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): वह आपका पैसा नहीं है माननीय सदस्य, वह सरकार का पैसा है।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): सरकार राजस्थान की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आपको ज्ञान होना चाहिए, सरकार राजस्थान की है, राजस्थान की जनता की सरकार है किसी एक सदस्य की सरकार नहीं है।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे घर से पैसे दे रही हों। (व्यवधान)

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार मेरा भी है इस सरकार पर यह ध्यान रखें आप। (व्यवधान)

इतनी देर से गीत गा रहे थे, ग्रामीण-ग्रामीण-ग्रामीण में हम शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। किसानों का गला घोंटा है आपने। एकदम से आप एमपी में शिक्षा शुरू करते हैं एमएलए में शिक्षा शुरू करते हैं, सीधा जो दस साल से, बीस साल से मेहनत कर रहा था, सरपंच बनने के ख्वाब देख रहा था, पार्षद बनने के ख्वाब देख रहा था, एकदम ऐसा डंडा मारा कि किसान तो बैठ गया, बाट देखता का देखता रह गया। बड़ी शर्म की बात है।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आप शिक्षा पर बोलो शिक्षा पर।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): 80 परसेंट राजस्थान की ग्रामीण जनता रह गई, उनकी आस, उम्मीद पर पानी फिर गया। वे नेता बनने से रह गये, उनके ख्वाबों पर पानी फेरने वाले आप हैं। शिक्षा का प्रचार कहते हैं इसको? 80 परसेंट किसानों की भावनाओं को समझते हैं आप? उन किसानों की जो खेत में काम करके आस लगा रहा था, मैं सरपंच बनूंगा, मैं जनता की भलाई करूंगा। फिर उसमें भ्रष्टाचार कैसे हुआ, फर्जी मार्कशीट बनी, फर्जी मार्कशीट में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार हुआ। सरपंच, महिला कोर्ट के चक्कर लगा रही है। (व्यवधान)

**श्री विश्वनाथ** (संसदीय सचिव): आपको और आपकी पार्टी को केवल अंगूठा टेक सरपंच चाहिए। (व्यवधान) पढ़े-लिखे नहीं चाहिए, अंगूठा टेक सरपंच चाहिए। शिक्षा पर बोलो।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): बोलने के लायक नहीं हो। गांव के लिए बोलने के लायक नहीं हो। पंचायत राज का गला घोंटने वाले आप हो।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): इनको भाव आ गया।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): महिलाओं की बात कर रहे थे। छात्राओं ने जब अध्यापक मांगे तो आपने लाठियां बरसा दीं। कम से कम शर्म करो, सरकार में बैठे हो। बच्चियों की स्कूल में तो अध्यापक लगा दो, 100-100, 200-200 बच्चियां जिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ रही हैं, लड़कों को सब प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं। इतनी तो शर्म करो कम से कम कि बच्चियों की स्कूल में तो अध्यापक लगा दो, बाद में बोलना आप लोग। ग्रामीण की बात कर रहे थे इतनी देर से।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): शकुन्तलाजी, आप गुस्सा मत करो, आप तो शिक्षा पर बोलो। यह कहां आप इनके पीछे लग रहे हो। आप तो शिक्षा पर बोलो। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): कालूलालजी, अच्छा बोलने की बात नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई। एक गांव के अनपढ़ आदमी से पूछकर देखो। जिस दिन पंचायत में यह फरमान जारी हुआ, यह फरमान अंग्रेजों की तरह जारी कर दिया आपने। बिलकुल गलत है, अनपढ़ गांव के ग्रामीण क्षेत्र में आपके दादा-दादी पढ़े-लिखे नहीं हैं।

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): हम भी गांव के हैं। आप मेरे से ज्यादा गांव की नहीं हो और आपने जितना काम नहीं किया होगा खेतों में जितना हमने किया है। इसलिए यहां विद्वता मत झाड़ो, आप तो शिक्षा पर बोलो।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): बोलने से पहले सोच लो। एक गांव का आदमी अनपढ़ सरपंच नहीं बन सकता, पार्षद नहीं बन सकता, प्रधान नहीं बन सकता, जिला प्रमुख नहीं बन सकता। यह आपके लिए बड़ी शर्म की बात है। (व्यवधान) बच्चियां जब कम्पीटिशन में परीक्षा देने गयी थीं तो जुराबें उतरवा दीं, उनकी चुन्नियां उतरवा दीं, उनकी जर्सियां उतरवा दीं। यह हमारे राजस्थान की संस्कृति है?

**श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर): शकुन्तलाजी, बेटियों की शिक्षा का जो आंकड़ा है वह हमारी सरकार में बढ़ा है, आप देख लीजिए।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): यह हमारे भारत की संस्कृति में नहीं था। यह गलत है, ऐसा नहीं था।

**श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर): बेटी बचाओ के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कुछ कर रही है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है बेटी के लिए।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): आप महिला होकर चुन्नी उतारकर कहीं जा सकती हो क्या? नहीं, यह हमारे यहां की संस्कृति में नहीं है। यह हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है।

**श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर): आपकी पिछली सरकार के नेता किस कारण से जेल में बंद हैं यह देखो। औरतों के साथ क्या किया आपके पिछले नेताओं ने?

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर): हमारे रीति-रिवाजों में नहीं है, हमारे देश की संस्कृति में नहीं है। (व्यवधान) ऐसा कानून उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, महिला, अगर कोई अध्यापक मरीज है वह अपनी एप्लीकेशन देता है, कई कैंसर से पीड़ित हैं तो जो भी अधिकारीगण बैठे हैं उनकी एक एप्लीकेशन पर इंसानियत के नाते आपको आर्डर कर देना चाहिए। उसमें किसी की सिफारिश नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद साहब।

**श्री उपाध्यक्ष**: उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरणजी सराफ।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्यों ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में 101 कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि तीनों विभागों के कटौती प्रस्तावों के जवाब आपको तीन दिन में लिखित में भिजवा दिये जाएंगे।

आज की चर्चा में 27 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने-अपने तरीके से बहुमूल्य सुझाव दिये हैं।

**श्री रमेश** (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है, कोई आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मेरा निवेदन है कि जो कटौती प्रस्ताव आप दो दिन पूर्व हमारे माननीय सदस्यों से लेते हैं और उसके बाद में तुरन्त 24 घण्टे के अन्दर जवाब देते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो हमारे कटौती प्रस्ताव हैं उनका एक तरह से जवाब तुरन्त देते हैं। इन सदस्यों की जो चर्चा सदन में हो जाती है उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो सदस्य सदन में नहीं चर्चा कर पाते उनके महत्वपूर्ण कटौती प्रस्ताव होते हैं

(श्री रमेश)

व्यय के सम्बन्धित या उनकी डिमाण्ड के सम्बन्ध में। इस पर एक तरह से महत्वपूर्ण गम्भीर विषय उनके होते हैं, उन पर आप 24 घण्टे में चर्चा करके उनको समाप्त कर देते हैं। उनको आप आगे आने वाली योजनाओं में उनके बारे में गम्भीर विचार करें, मेरा यह निवेदन है। आप लिफाफे के माध्यम से भेज देते हैं, इसमें अतिरिक्त पैसा व्यय भी होता है, समय भी खराब होता है, लेकिन जो माननीय सदस्य नहीं चर्चा कर पाये, नहीं बोल पाये, उनके विषय में आप बिलकुल गम्भीर विचार करें, यह मेरा निवेदन है।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): मैंने जैसा कहा कि उन सबका जवाब तीन दिन में लिखित में भिजवा दिया जाएगा।

**श्री रमेश** (सपोटरा): आप उनके बारे में, जो भेजा है उनके काम करें। हमारा काम नहीं करें, जो चर्चा नहीं कर पाये, हम नहीं कह रहे कि आप हमारा काम करें आप। सत्ता पक्ष के लोग हैं वे भेजते हैं, उनके विशेष महत्वपूर्ण विचार हैं, उनकी मांग हैं।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो काम ही करते हैं, आपकी जैसे केवल बातें ही नहीं करते। मैं अभी नमूना बताऊंगा आपको। 2015-16 के बजट में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेट हायर एजुकेशन डवलपमेंट प्लान तैयार किया और यह कहा कि 8 वर्षों में हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चरणबद्ध रूप से विकास का काम करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है और मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष बजट में 173 करोड़ रुपये की इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट ग्रांट के लिए घोषणा की है। निश्चित रूप से इस 173 करोड़ रुपये की घोषणा हुई है उससे हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का काम होगा और गुणवत्ता बढ़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दो साल में हमने 16 नये कालेज खोले और 6 जो बड़े कालेज थे उनका पुनर्गठन करके 8 नये कालेज उसमें से खोले। इस वर्ष 8 नये कालेजज की घोषणा की है। आपने क्या किया? जब कांग्रेस का राज था तो 2009-10 में आपने एक भी कालेज नहीं खोला। 2010-11 में आपने एक कालेज खोला। 2011-12 में एक कालेज नहीं खोला, 2012-13 में फिर दो कालेज खोले। यानी चार साल में आपने तीन कालेज खोले और जाते-जाते, जब यह पता था कि हमारी सरकार अब नहीं आनी तो जनता को गुमराह करने के लिए आपने अंतिम छह महीने में 35 कालेजज की एक साथ घोषणा की, बिना किसी बजटीय प्रावधान के। केवल

(श्री कालीचरण सराफ)

जनता को गुमराह करने के लिए 35 कालेजज की आपने घोषणा की। वह तो वसुन्धरा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसमें से 27 कालेज का हमने आपका सम्मान रखा। (व्यवधान) अभी आप कह रहे थे कि राजनीतिक भेदभाव।

मैं बताना चाहूंगा कि जब भैरोंसिंह जी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हर पंचायत में उन्होंने मिडिल स्कूल खोले। उसके बाद जब 2003 से 2008 के बीच में वसुन्धराजी जब राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं तो एक साथ बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हमने जितनी भी ग्राम पंचायतें थीं, 3 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें जहां सैकण्डरी स्कूलें नहीं थीं वहां हमने सैकण्डरी स्कूल खोले। इस बार जब पुनः प्रचण्ड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का राज बना और वसुन्धराजी राजस्थान की मुख्य मंत्री बनीं तो हमने 5 हजार से ज्यादा इस प्रकार की ग्राम पंचायतें जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं थे वहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह देवनानीजी का विषय का है। देवनानीजी क्या बोलेंगे?

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आप विराजो, विराजो।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उच्च शिक्षा मंत्रीजी, उच्च शिक्षा पर बोलो, शिक्षा पर मत बोलो, वे बोलेंगे, वे भी मंत्री हैं।

**(21.00 बजे)**

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आप बैठिये, बैठिये। अभी जो 8 नये कालेज खोले हैं, आपके हैं 200 में से 40 विधायक, 24 तो आपके और बाकी निर्दलीय और अन्य पार्टियों के और 160 विधायक हैं बीजेपी के तो 8 में से दो कालेज आपको दिये हैं। यानी 8 में से 6 कालेज भारतीय जनता पार्टी के जहां विधायक हैं उनके लिए खोले और 2 कालेज राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य प्रद्युम्न सिंह जी के यहां और खींवसर से आने वाले हनुमान जी बेनीवाल के यहां खोला।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मेरे कहने से ही खोला है न? पहले यह तो बता दो।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): विराजो, विराजो। बैठो तो सही, बीच में क्यों बोल रहे हो?

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): कालेज मेरे कहने से खोला या अपने आप ही खोला है? आप यह तो बता दो। यह क्या बात है।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): प्रश्न यह है, नहीं है, मैं यह नहीं कह रहा कि आपके कहने से खोला या गजेन्द्र सिंह जी के कहने से खोला....

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): किसके कहने से खोला? फिर क्यों गीत गा रहे हो? बार-बार मेरा नाम क्यों ले रहे हो, यह बताओ।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): पर खींवसर विधान सभा क्षेत्र में नया यह जो कालेज खोला है वो आपके क्षेत्र में खोला है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मेरे कहने से मेरे क्षेत्र में खोला कालेज?

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): यह नमूना है कि हम राजनीतिक भेदभाव नहीं करते।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): या मेरे नहीं कहने से? आप बताओ तो सही। आप ही तो कह रहे हो।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आप विराजो, विराजो। बैठो भाई। इतना ही नहीं, हमने जो पिछले दो सालों में 16 नये कालेज खोलने की घोषणा की उसमें 11 महाविद्यालयों में तो भवन निर्माण का कार्य चल रहा है और 2 कालेज पुराने भवनों में चल रहे हैं और 3 कालेजज की भूमि आबंटन की प्रक्रिया चल रही है। हमने बजटीय प्रावधान करके खोले हैं, आपके जैसे फर्जीवाड़े में नहीं खोले। (व्यवधान) बैठो, बीच में मत बोलिये।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): मंत्रीजी, जहाजपुर कालेज के अन्दर प्रिंसिपल लग गया था, स्टाफ लग गया था उसके बाद आपने द्वेषतापूर्वक उसको हटाया।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं खुद ही कह रहा हूं कि जाते-जाते 6 महीने में, यह आपको पूरा विश्वास था कि इस बार हमारी सरकार नहीं आनी, 35 कालेज खोल दिये बिना बजटीय प्रावधान के, प्रिंसिपल कागजों में लगा दिया कि हमने कालेज खोल दिये। 4 साल क्या कर रहे थे आप? 3 कालेज। दो साल एक भी कालेज नहीं खोला, एक साल में एक कालेज और एक साल में 2 कालेज और लास्ट में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए 35 कालेजज की घोषणा कर दी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वसुंधरा जी को कि उन्होंने....

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): आप उस कालेज के आधार पर ही तो जीते थे।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): इस बार जो 8 नये कालेज खोले हैं उनके लिए भी हमने 104 करोड़ 50 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया है जिससे कि नये कालेजज खुल जाएं। अब जयपुर का कालेज, जयपुर में भी इन्होंने घोषणा कर दी कि राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा और एक जो टैक्नीकल डिपार्टमेंट का भवन था उसमें कालेज खोल दिया। कोई वित्तीय प्रावधान नहीं, कोई लेना-देना नहीं। यह तो वसुंधराजी ने उसके लिए जवाहर लाल नेहरू मार्ग की प्राइम लोकेशन, जहां कामर्स कालेज, राजस्थान कालेज, यूनिवर्सिटी, सब है वहां 27886 वर्ग मीटर भूमि का आबंटन किया और उसके लिए वित्तीय प्रावधान किया, रुपये सैंक्शन किये और उसका पूरा तखमीना बन रहा है और इसी साल उसका शिलान्यास होगा।

अब यूनिवर्सिटी की बात करूं। जब 2003 से 2008 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने तीन नये विश्वविद्यालय भरतपुर में महाराजा सूरजमलजी के नाम से ब्रज विश्वविद्यालय, अलवर में भर्तृहरिजी के नाम से मत्स्य विश्वविद्यालय और शेखावाटी सीकर में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की घोषणा की। हमने इन तीन विश्वविद्यालयों की घोषणा की और उसमें वित्तीय प्रावधान किया और ओएसडी नियुक्त कर दिया। परन्तु दुर्भाग्य से आपकी सरकार आई तो आपने साढ़े चार साल तक उसको ठण्डे बस्ते में रख दिया। फिर जाते-जाते जनता को गुमराह करने के लिए तीनों विश्वविद्यालय बनाये जायेंगे, वी.सी. बना दिये। बाकी क्या किया आपने? उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुन: बनी तो हमने भरतपुर, अलवर और सीकर की जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी थी उनके लिए जमीन चिह्नित की और वहां पर अभी भवन निर्माण का काम चल रहा है, चारदीवारी का काम चल रहा है। इतना ही नहीं किया, हमने उनका क्षेत्राधिकार भी तय किया। आज भरतपुर जिला और धौलपुर जिला, उनके जितने भी महाविद्यालय हैं चाहे वो गवर्नमेंट के महाविद्यालय हैं चाहे प्राइवेट महाविद्यालय हैं, उन सबको उसके साथ एफिलियेट कर दिया। इसी प्रकार से अलवर जिले के जितने भी महाविद्यालय हैं वो अलवर का जो मत्स्य विश्वविद्यालय है उससे एफिलियेट कर दिये। जो सीकर और झुन्झुनूं के महाविद्यालय हैं वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी से एफिलियेट कर दिये और आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी जो फर्स्ट ईयर और एम.ए. प्रिवियस की परीक्षा हो रही है वो इन तीनों

(श्री कालीचरण सराफ)

विश्वविद्यालयों में हो रही है। क्षेत्राधिकार तय कर दिया। आपने क्या किया? उसको साढ़े चार साल तक ठण्डे बस्ते में रखा।

इतना ही नहीं, आपने ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 2 कमरे में उदयपुर में राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी, 2 कमरों में वो विश्वविद्यालय चल रहा है। हमने कहा कि नहीं, हम मंत्रिमण्डल में प्रस्ताव लाये और गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में खोलने का निर्णय किया और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इनके जितने भी जो कालेजज हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के, वो इससे एफिलियेट होंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका विधेयक इसी विधान सभा सत्र में हम लायेंगे। हम लोग केवल बात नहीं करते। राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय दो कमरों में उदयपुर में चल रहा है, ट्राइबल का कोई लेना-देना और नाम कर दिया जनजातीय विश्वविद्यालय।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): आपने इन विश्वविद्यालयों का बजट दे दिया क्या? यह मालवीय नगर के बाजार में नहीं बोल रहे हो, सदन में बोल रहे हो और मंत्रीजी, रिकार्ड में आ रहा है। आपने दे दिया क्या पैसा भवन बनाने के लिए? इन शेखावाटी विश्वविद्यालय को, भरतपुर के विश्वविद्यालय को आपने दे दिया क्या बजट का पैसा? वो बता दो।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): रिकार्ड में आ रहा है इसीलिए बोल रहा हूं। आप बैठो। बजट नहीं, परीक्षा ले रहे हैं वो, परीक्षा ले रहे हैं। विराजिये, विराजिये। बैठिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह मालवीय नगर के बाजार में भाषण नहीं दे रहे हो, यह रिकार्ड में आ रहा है, मंत्री हो आप।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): रिकार्ड में आ रहा है मुझे पता है, बैठिये। मुझे आपसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यह रिकार्ड में आ रहा है। वहां परीक्षाएं हो रही हैं श्रीमान् जी, जरा पता करो कि ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर जिले की और धौलपुर जिले की जितनी कालेजज हैं उनकी फर्स्ट ईयर की परीक्षा कौन ले रहा है? कौनसी यूनिवर्सिटी ले रही है? पता करिये।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को टोक नहीं रहा हूं, मंत्रीजी, एक मिनट रुको तो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो आपको हमेशा सुनता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि आप सच

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं? कौन सच बोल रहा है? आप कह रहे हो हमने दे दिया।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): यह तो आप असैस करो।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सुनो, आप कह रहे हो कि हमारे एग्जाम हो रहे हैं और ये कह रहे हैं बजट ही नहीं दिया तो फिर सच कौन बोल रहा है?

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जो करती है वो कहती है। कांग्रेस की जैसे फर्जीवाड़ा नहीं करती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी जो कालेजज और जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आज यह स्थिति है कि बच्चे क्लासेज में नहीं जाते क्योंकि अटेंडेंस कम्पलसरी नहीं है। इसलिए हमने इस बार यह तय किया है कि टीचिंग स्टाफ और नान टीचिंग स्टाफ की बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस ली जायेगी और 75 परसेंट अटेंडेंस जिस बच्चे की नहीं होगी उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह घोषणा ही रहेगी।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): सुनिये। उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या किया है कि क्लास टीचर जो कक्षा लेता है वो हर महीने किस बच्चे की कितनी अटेंडेंस है उसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल को करेगा और प्रिंसिपल एसएमएस के जरिये उनके अभिभावकों को भेजेगा कि आपके बच्चे की इतनी अटेंडेंस शार्ट है। यह व्यवस्था हमने की है। अब आप कहेंगे कि यह फलां जगह लागू नहीं हुआ, फलां जगह लागू नहीं हुआ तो शुरूआत है, हो सकता है कि कुछ स्थानों पर....

**श्री राजपाल सिंह शेखावत** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अपने टाइम पर शुरू हो जाती तो?

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): यह बात सही है, अपने टाइम तो कम्पल्सरी थी, हमारे टाइम तो कम्पल्सरी थी और आपके टाइम का पता नहीं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उस समय हो जाती तो आप दोनों रह जाते और मैं ही आता।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आपके और इनके टाइम का

(श्री कालीचरण सराफ)

पता नहीं पर मेरे टाइम तो कम्पल्सरी थी और मेरी अटेंडेंस पूरी थी, इतना बता सकता हूं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): तभी इतने विद्वान हो, यह बात माननी पड़ेगी।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आज तक जो प्राइवेट कालेजज की एनओसी दी जाती थी उसमें भ्रष्टाचार होता था। पिक एण्ड चूज, जो सिफारिश आ गई उसकी तो एनओसी जारी कर दी और जो सिफारिश नहीं आई उसमें रोज आब्जेक्शन लगाकर कि यह कमी है, यह कमी है और चक्कर कटवाते। हम लोगों ने ये निर्देश दिये हैं, एक तो एनओसी की यह लिखित में पालिसी बना दी और यह निर्देश दिये हैं कि रजिस्टर मेन्टेन करिये कि जो पहले आया है, उसका निस्तारण पहले करिये और जो बाद में आया है, उसका निस्तारण बाद में करिये। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 110 कालेजेज की एनओसी हमने कैम्प लगाकर कि सारी फाइलें ले आओ भई और एक साथ सबकी एनओसी जारी कर दी और अभी भी प्राइवेट कालेजेज की एनओसी की फाइल, जो भी आता है मेरे पास, यहां फाइल 10 मिनट से ज्यादा नहीं रूकती है। पूर्णतया भ्रष्टाचार वहां समाप्त हो गया।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, फिर पैट्रोल पम्प पर भीड़ किस बात की रहती है, मंत्रीजी?

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): पैट्रोल पम्प पर तो आप पैट्रोल भरवाने जाते होंगे, मुझे पता नहीं है। मैं चुनौती देता हूं माई डियर, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक महोदय, एक व्यक्ति यदि इस प्रकार का बता दें...

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है। यह इस तरह से बार-बार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? कोई तरीका है क्या यह?

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): ...जो यह कहते हो कि निजी महाविद्यालय की एनओसी देने में एक नये पैसे का भ्रष्टाचार हुआ हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं आप दे देना इस्तीफा। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं।

**श्री जयराम जाटव** (अलवर ग्रामीण): इस तरह का माहौल हमने कभी नहीं देखा। इस तरह का माहौल हमने कभी नहीं देखा। सारे सदन को भी

(श्री जयराम जाटव)

कब्जे में कर रखा है। (व्यवधान) हम इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हैं। इस तरह से माननीय उपाध्यक्षजी, आसन से अनुरोध है। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): श्रीमानजी, आप बैठो। विराजो। बैठिये। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): ऐसे तो आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। (व्यवधान) ये फिर आरोप लगा रहे हैं इस तरह।

**श्री सुरेन्द्र गोयल** (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और जिस प्रकार से ये टोकाटोकी कर रहे हैं। 15 मिनट के अन्दर कम से कम 50 बार टोक दिया।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): आप सचेतक हो विपक्ष के। (व्यवधान) आप जवाब दो इसका।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आप बैठो, बैठो। मैं देख लूंगा। मैं जवाब देने में सक्षम हूं, चिंता मत करो आप।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्री महोदय, एक मिनट विराज जाओ। आप आसन को क्या समझते हैं? ऐसे तो जिस प्रकार का आचरण आप कर रहे हैं, वह सभ्यता की परिभाषा में आता नहीं है। फिर भी आसन आपसे निवेदन कर रहा है कि शिक्षा भी और वह भी उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दे रहे हैं तो उचित तो यह होगा कि उस ज्ञानवर्द्धक वक्तव्य को आप मर्यादित आचरण से सुनें। (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रदेश में इन्ट्रोड्यूस किया और आज उसका यह परिणाम है कि 43 नये यूनिवर्सिटीज हमारे प्रदेश में खुले और नये-नये सब्जैक्ट्स जो सरकारी विश्वविद्यालयों में नहीं हैं, उनका अध्ययन भी उन निजी विश्वविद्यालयों में हो रहा है। आज एक एजुकेशन हब के रूप में हमारा स्टेट डवलप हो रहा है और उसके साथ-साथ कई निजी विश्वविद्यालयों की शिकायतें भी हमारे पास आई हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार, वहां की जब शिकायत आई तो हमने उसकी एसओजी से जांच करवाई, कमेटी से जांच करवाई और वहां डिग्रियां फर्जी पाई

(श्री कालीचरण सराफ)

गईं तो हमने जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी पर प्रशासक नियुक्त कर दिया। वहां के जो संभागीय आयुक्त हैं, उनको वहां का प्रशासक बना दिया और जो फर्जी डिग्रियां थीं, उनको वैबसाइट पर डाल दिया कि भई, ये सब फर्जी डिग्रियां हैं। और भी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की शिकायतें थीं। आज अभी मनोज कुमारजी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की शिकायत कर रहे थे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसकी भी जांच की जायेगी और यदि वहां अनियमितता पाई गईं तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्यवाही की जायेगी।

आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन में पहले जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होते थे, उसमें परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होते थे। अब सीबीएसई में मार्किंग इजी होती है। एक लाख बच्चे तो सीबीएसई से पासआउट करते हैं और सात लाख बच्चे बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन और ओपन बोर्ड से पासआउट करते हैं। उससे होता क्या था कि 80 परसेंट तो सीबीएसई के बच्चों का एडमिशन होता था और 20 परसेंट एडमिशन केवल बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के बच्चों का होता था। हमने परसेंटाइल सिस्टम लागू किया और आज उसका यह परिणाम है कि जो बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन राजस्थान के ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनका तो 80 परसेंट एडमिशन हो रहा है और जो सीबीएसई के बच्चे हैं, उनका केवल 20 परसेंट एडमिशन हो रहा है।

इसी प्रकार से पहले क्या सिस्टम था कि फर्स्ट ईयर जिसने पासआउट कर लिया, वह सैकण्ड ईयर में दोबारा एडमिशन लो। सैकण्ड ईयर पासआउट कर लिया तो थर्ड ईयर में दुबारा एडमिशन लो। हमने यह सिस्टम कर दिया कि जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, पासआउट करने के बाद सैकण्ड ईयर में दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सैकण्ड ईयर जिसने कर लिया, उसको थर्ड ईयर में दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) और सरकारी कालेजेज हैं, आपको यह जानकर खुशी होगी कि सबमें हमने आनलाइन एडमिशन की व्यवस्था कर दी और जो पीजी कालेजेज बचे हैं, इसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि इस साल से पीजी क्लासेज में हम आनलाइन एडमिशन करेंगे।

अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज थीं, कहीं पर 10 साल से डिग्रियां नहीं मिल रही थीं, कहीं पर 15 साल से डिग्रिया नहीं मिल रही थीं, कहीं पर पांच साल से डिग्रियां नहीं मिल

(श्री कालीचरण सराफ)

रही थीं। हमने सभी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाई और यह सुनिश्चित किया कि जितनी भी डिग्रीज बाकी हैं, वे वितरित होनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि सब विश्वविद्यालयों में मिलाकर कम से कम 25 लाख से ज्यादा डिग्रियां, सब जगह दीक्षांत समारोह आयोजित करवाये और दीक्षान्त समारोह आयोजित करवाकर सबको डिग्रियां वितरित कीं। उसमें गुलामी का प्रतीक काला गाउन पहनकर लोग डिग्रियां लेते थे। हमने कहा कि यह गुलामी का प्रतीक है तो हमने उस परम्परा को बंद किया और जो छात्र थे, उनके लिए सफेद कुर्ता-पाजामा और जो छात्राएं थीं, उनके लिए सफेद साड़ी या सलवार सूट, यह तय किया। इसमें वे आयेंगी और डिग्री लेंगी। हमने उस काले गाउन की प्रथा को समाप्त कर दिया।

अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक जितने लैक्चरर्स की नियुक्ति होती थी, वह आरपीएससी के माध्यम से सेंट-परसेंट इन्टरव्यू के आधार पर होती थी। उसमें भाई-भतीजावाद चलता था। उसमें भ्रष्टाचार चलता था। हमने यह व्यवस्था खतम कर दी। हमने नियमों में परिवर्तन करके, 88 प्रतिशत का लिखित पेपर होगा और 12 प्रतिशत का केवल इन्टरव्यू होगा। अब इसमें हमने 150 नम्बर का सब्जैक्ट पेपर, 50 नम्बर का राजस्थान की जनरल नोलेज का पेपर और 24 नम्बर का इन्टरव्यू। इससे जो टेलेंटेड बच्चे होंगे और जो राजस्थान के बारे में नोलेज रखेंगे, ऐसे बच्चों का ही सलेक्शन हो पायेगा, बाकी का नहीं हो पायेगा। अब आप ये देखिये कि एक तो आपका राज था और अब हमारा राज है। 2003 से 2008 के बीच में जब हमारा राज था तो वसुन्धराजी ने 913 रिक्त पदों को भरने की घोषणा की थी और यह कहा था कि दो फेज में हम इन पदों को भरेंगे। 456 पद तो हमने भर दिये थे और 457 पद जो वसुन्धराजी ने घोषणा की थी, स्वीकृत किये थे, उनकी भर्ती आपने की। आपने एक भी नई स्वीकृति जारी नहीं की और इस बार हमारा राज आते ही हमने प्राथमिकता के आधार पर जो 1,339 पद जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं, 30 परसेंट पद रिक्त हैं, 5,000 समथिंग का टोटल कैडर है, उसमें से 1,300 पद रिक्त हैं। हमने आरपीएससी को रिक्विजीशन भेजी। आरपीएससी के चेयरमैन साहब से बात की और उन्होंने हमें बताया है कि अप्रैल-मई में हम एग्जाम करवा लेंगे और एक जुलाई के पहले-पहले हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देंगे।

(श्री कालीचरण सराफ)

आज भी कई माननीय सदस्यों ने अभी यहां यह कहा कि साहब, हमारे यहां प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं, लेक्चरर्स के पद रिक्त हैं तो मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक जुलाई को जब नया सत्र प्रारम्भ होगा, उस समय किसी भी कालेज में कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा और अशैक्षिक कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी हमने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है जिससे महाविद्यालयों में इनकी भी कमी दूर हो जायेगी। पीटीआई और पुस्तकालयाध्यक्षों के नियमों में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नियमों में परिवर्तन होते ही विभाग में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अब एक मजेदार बात और बताता हूं। पांच नये बीएड कालेज, हमारे गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने आरवीआरएस के जो बीएड के टीचर्स आये थे उस समय घोषणा की थी कि हम पांच नए कालेज खोलेंगे और उन लेक्चरर्स को उसमें लगाएंगे। उन्होंने कोई कालेज वालेज नहीं खोले और उनको घर बैठे तनख्वाह देते रहे। हमने आने के बाद वो पांचों बीएड कालेज प्रारम्भ किए और आज मुझे खुशी है यह बताते हुए कि पांचों कालेजज में आज बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बीएड के जो लैक्चरर्स आए थे जो खाली बैठे थे वो आज उनका अध्ययन करवा रहे हैं। इसी प्रकार से कालेज शिक्षा विभाग द्वारा एक डायनामिक वैबसाइट विकसित की गई है जिस पर प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय की सूचना देने वाले वैब पृष्ठ भी उपलब्ध हैं। इस वैबसाइट के द्वारा विद्यार्थी विभाग की सभी जानकारी एवं सुविधाओं का उपयोग आनलाइन कर सकते हैं।

ई-क्लास रूम योजना। बजट घोषणा 2015-16 के अनुरूप प्रथम चरण में 34 नए चयनित राजकीय महाविद्यालयों एवं आयुक्तालय कालेज शिक्षा जयपुर में डायनामिक ई-क्लास रूम स्थापित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। इस योजना को चरणबद्ध रूप से सभी राजकीय महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा। इस योजना में महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की आनलाइन और आफलाइन कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी।

इसी प्रकार से ई-लाइब्रेरी योजना। समस्त राजकीय महाविद्यालयों को यूजीसी की ई-लाइब्रेरी योजना से जोड़कर 97 हजार ई-बुक्स और 6 हजार ई-जनरल्स की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कर्मचारियों के लिए राजकीय

(श्री कालीचरण सराफ)

महाविद्यालयों में कार्यरत 197 व्याख्याताओं को कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत पे-बैण्ड-4 का लाभ स्वीकृत किया गया है। अशैक्षणिक कार्मिकों की पदोन्नति समय पर सम्पन्न की गई है तथा शैक्षणिक कार्मिकों की पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र ही सम्पन्न कर पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूर्ण की जाएगी।

अब मैं आपको बताना चाहूंगा तकनीकी शिक्षा।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन है 2008 में...

**श्री उपाध्यक्ष:** सम्माननीय सदस्य I can't just allow this thing. Once in a while it is alright.

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा में प्रधान मंत्रीजी की स्टार्टअप योजना के अन्तर्गत आई आई एम अहमदाबाद की सहायता से प्रदेश की सभी सातों सम्भागों में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में इंक्यूवेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। आगामी सत्र से सेंटर कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

थ्रीडी प्रिंटिंग और रोबोटिक लैब की स्थापना। राज्य में पहली बार 5 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक थ्रीडी प्रिंटिंग एवं रोबोटिक लैब की स्थापना राज्य की सेंटर फोर इलेक्ट्रोनिक गवर्नेंस संस्था (सीईजी) जयपुर में स्थापित की जा रही है। राज्य में आई आई टी, मुम्बई की सहभागिता से सम्भाग स्तर पर पोलीटैक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेजों में आधुनिक ई-यंत्र लैब स्थापित की जा रही है। शिक्षण प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय जोधपुर, महिला अजमेर और भरतपुर में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित कर विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है।

शिक्षकों के लिए उच्च अध्ययन नीति। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शिक्षकों को उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए दी जाने वाली अनुमति में भेदभाव किया जाता रहा है। इसको दूर करते हुए हमने राज्य में तकनीकी शिक्षकों के लिए एक उच्च अध्ययन नीति जारी की है जिससे दी जाने वाली अनुमति में भेदभाव समाप्त हो जाएगा। राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश पहले आरपीईटी के माध्यम से परीक्षा आयोजित करके दिया जाता था। इससे धन और समय की बरबादी होती थी इसको समाप्त करते हुए हमने अखिल

(श्री कालीचरण सराफ)

भारतीय स्तर पर जेईई के माध्यम से जो परीक्षा होती है उसके माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से एमबीए और एमसीए में भी परीक्षा प्रक्रिया को समाप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के आधार पर ही केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया के द्वारा मैरिट से प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था की है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य में संचालित पोलीटैक्निक और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में नए संस्थान व नई शाखा खोलने, बंद करने एवं नाम परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देते समय भेदभाव किया जाता था। इस प्रक्रिया को समाप्त कर राज्य स्तरीय नीति शीघ्र जारी की जाएगी जिसके माध्यम से बिना भेदभाव के सभी इच्छुक संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं पोलीटैक्निक महाविद्यालयों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एवं पोलीटैक्निक परीक्षाओं के सफल एवं बेहतर प्रबंधन के लिए हम जयपुर क्षेत्रीय परीक्षा उत्तर पुस्तिका एकीकरण वितरण एवं मूल्यांकन केन्द्र एवं संयुक्त निदेशक कार्यालय इसी वर्ष प्रारम्भ कर रहे हैं। समय पर परीक्षाओं के आयोजन एवं परिणाम को जारी करने के लिए वार्षिक कलैण्डर भी जारी किया जाएगा और पोलीटैक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न कम्पनियों द्वारा कैम्पस प्लेसमेंट की व्यवस्था की गई और आपको यह जानकर खुशी होगी कि 1 हजार से ज्यादा छात्रों को हम रोजगार देने में सफल हुए। राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय में 343 व्याख्याताओं की भर्ती के लिए एक्विजिशन राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इनके लिए जनवरी, 2016 में परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, परीक्षाएं ले चुके हैं और शीघ्र ही हमें चयनित लैक्चरर्स उपलब्ध हो जाएंगे। और राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों के लिए 242 अशैक्षणिक रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थना राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड को भिजवा दी गई है।

अब संस्कृत शिक्षा। इस विभाग को गति प्रदान करने के लिए आप आश्चर्य करेंगे कि संस्कृत में 40 परसेंट से ज्यादा पद रिक्त हैं और उनके संस्कृत के नियम ही नहीं हैं। हमने प्रयास करके और स्कूल संस्कृत शिक्षा के नियम तो बना दिए और वो मंत्रिमण्डल ने अप्रूव भी कर दिए। और अब जो कालेज शिक्षा के नियम हैं वो बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी ही वो

(श्री कालीचरण सराफ)

भी हो जाएंगे तो इससे जो सालों से डीपीसी लम्बित पड़ी है और जो नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, उसका रास्ता खुल जाएगा। हमने पिछले बजट सत्र में यह घोषणा की थी कि हमारी सरकार के गठन के पश्चात हमने प्रथम कक्षा से संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन आरम्भ करने का निर्णय लिया था और मुझे आप लोगों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रथम कक्षा की पुस्तकें प्रकाशित होने के लिए भेज दी गई हैं और आगामी सत्र से पहली क्लास से संस्कृत की शिक्षा प्रारम्भ हो जाएगी। और दूसरी क्लास से और आठवीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी संस्कृत के विद्वानों के साथ मिलकर हमने नए पाठ्यक्रम के आधार पर पुनर्लेखन की व्यवस्था कर ली है और नए सत्र से वो भी चालू हो जाएगी।

हमने एसटीसी महापुरा को राज्य स्तरीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है। यह घोषणा संस्कृत के विकास की दृष्टि से दूरगामी परिणाम देने में सहायक होगी। अब संस्कृत शिक्षा में कार्यरत सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण इसी संस्थान द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे विषयगत प्रशिक्षण के साथ-साथ संस्कृत सम्भाषण का भी प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाएगा। जिससे संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत सम्भाषण का वातावरण बनाने में सहयोग मिलेगा। संस्कृत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का भी हमने गठन किया है जो संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करेगा। अब तक कुल 1 हजार प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। इसी प्रकार से जुलाई मास में सम्भाषण मास के रूप में इसका हमने आयोजन करने का तय किया है। अभी तक 1 लाख 80 हजार छात्रों ने सम्भाषण मास के अन्तर्गत संस्कृत सम्भाषण का अभ्यास किया है। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आदरणीय हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी नरेन्द्रजी मोदी जो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया तो हमने अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक योग केन्द्र हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित करने का तय किया है और वहां पर योग साधना केन्द्र की स्थापना हो गई है और इसके लिए शैक्षणिक मीटिंग रूम और योग साधना केन्द्र का तो निर्माण हो गया है हमारी मंशा है कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर का योग साधना केन्द्र वह बने। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि संस्कृत के प्रति भारतीय जनता पार्टी की कितनी रुचि है। यह मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री कालीचरण सराफ)

संस्कृत विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार और नव निर्माण के लिए 23 करोड़ 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी है और यह राशि आगामी तीन वर्षों में योग केन्द्र के भवन का विकास, ओपन-एयर थिएटर और मंत्र प्रतिष्ठान भवन के निर्माण के साथ-साथ जीर्णोद्धार के कार्य में लगेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे प्राइमरी एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान है और माध्यमिक शिक्षा के लिए रमसा है। इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद का गठन किया है। जो हायर एजुकेशन के कालेजज की, यूनिवर्सिटीज की गुणवत्ता सुदृढ़ करने के लिए और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए काम करेगा और आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि 352 करोड़ रुपये की स्वीकृति रूसा ने हमें दी है। 96 राजकीय महाविद्यालयों को और 4 संस्कृत महाविद्यालयों को 2-2 करोड़ रुपये, 5 राजकीय विश्वविद्यालयों को 20-20 करोड़ रुपये और बारां और बाड़मेर में नये इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने के लिए 26 करोड़ रुपये उन्होंने स्वीकृत किये हैं और हमारा प्रयास है कि जो बाकी कालेज बचे हैं वो भी उनके जो सारे मापदंड हैं पैसे देने के, वो पूरे करने के बाद उनको भी रूसा के माध्यम से सहायता मिल पायेगी। इसमें साठ परसेंट पैसा केन्द्र सरकार का है और चालीस परसेंट पैसा राज्य सरकार का है। हमने विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में तीन कुलपतियों की एक समिति का गठन किया है। यह कमेटी दो विषयों पर कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एवं प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के अधिक से अधिक विद्यार्थियों का चयन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप रिवाइज करने का काम यह कमेटी करेगी, योजना प्रस्तुत करेगी और कक्षाओं में विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उपस्थिति के प्रतिशत के आधार पर बोनस अंक दिये जाने की कार्य योजना भी ये प्रस्तुत करेगी। सभी विश्वविद्यालयों में समान कैलेण्डर बने। राज्य के समस्त विश्वविद्यालय अपने-अपने स्तर पर एकेडेमिक कैलेण्डर तैयार करते हैं, परन्तु इसके द्वारा घोषित इस कैलेण्डर की पूर्ण रूप से पालना नहीं की जाती। अत: हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सभी के लिए एक माडल कैलेण्डर तैयार किया जाएगा। उक्त कलेण्डर में प्रवेश परीक्षाएं, उनके

(श्री कालीचरण सराफ)

परिणाम, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया, ग्रीष्मावकाश एवं राजपत्रित अवकाश आदि समान रूप से प्रभावी होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अब तक प्रदेश के जितने भी राजकीय विश्वविद्यालय हैं उनमें एक ही कोर्स के भिन्न-भिन्न परीक्षा शुल्क लिये जाते हैं और परीक्षा कार्यों को सम्पन्न कराने वाले कार्मिकों को जो मानदेय दिया जाता है वो भी अलग-अलग है तो इसके लिए भी हमने यह तय किया है कि उनका एक समान परीक्षा शुल्क, परीक्षा कार्यों से सम्बन्धित समान मानदेय और अन्य भत्ते इसके लिए भी हमने एक कमेटी का निर्माण किया है और वो हमें सुझाव देगी उसके आधार पर समान रूप से लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो आदरणीय प्रधान मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने जो आदर्श गांव ...।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकंड। क्यों हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो? टेबल कर दो न क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो मान रहे हैं न। साढ़े नौ बज गये हैं दो-तीन मंत्रियों को और बोलना है।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आप चिन्ता मत करो। दो मिनट और बोलूंगा, बैठो आप। अब ये घोषणाएं हो रही हैं तो आपके पेट में मरोड़ा क्यों आ रहा है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी तय किया है कि जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं वो एक गांव गोद लेंगे और अपने संसाधनों से उसका पूरा विकास करेंगे और इसी प्रकार से जो निजी विश्वविद्यालय हैं 43, उनकी मैंने मीटिंग ली थी और उसमें हमने उन सबसे अनुरोध किया है कि पांच-पांच गांव एक-एक निजी विश्वविद्यालय गोद लेगा और उसका विकास अपने स्तर पर अपने संसाधनों से करवायेगा।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): उनसे बात हो गयी न? (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): हां, बात हो गयी। हायर एजुकेशन बैब पोर्टल-प्रदेश की उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के लिए हायर एजुकेशन बैब पोर्टल का निर्माण आईटी विभाग की सहायता से प्रक्रियाधीन है जिसके अन्तर्गत प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक सम्पूर्ण प्रक्रिया आन लाइन की जायेगी तथा कालान्तर में ई-लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण सामग्री भी इस पोर्टल के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस पोर्टल पर

(श्री कालीचरण सराफ)

विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का डेटा बेस भी तैयार किया जायेगा। आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कालेज शिक्षा में तीस, तकनीकी शिक्षा में बारह और संस्कृत शिक्षा में चौंतीस मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति हमने प्रदान की है और विभाग को निर्देशित किया है कि इस प्रकार के यदि कोई और भी लम्बित प्रकरण हों तो उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कालेजों के छात्र सामाजिक सरोकारों के प्रति भी जागरूक रहें, इसके लिए हमने पांच सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। पहला कार्यक्रम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे चिकित्सा मंत्रीजी को, इनके सहयोग से पिछले साल पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर जरूरतमंद गरीब लोगों को जिनको रक्त की आवश्यकता है उनको रक्त दिया जाए तो इसके लिए रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया और आप आश्चर्य करेंगे कि उस दिन ईद की छुट्टी होने के बावजूद भी 10,052 बच्चों ने रक्तदान किया और 1 लाख 27 हजार लोगों ने संकल्प पत्र भरे और उनकी हमने एक डिजिटल डायरी बनायी है जिसको भी आवश्यकता हो रक्त की वो वहां फोन करके रक्त ले सकते हैं और इस बार हमने यह तय किया है कि एक तो 25 सितम्बर को पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर और एक 23 जनवरी को सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' तो इन दोनों दिन हम रक्तदान का कार्यक्रम रखेंगे।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): मतलब आप लोगों से खून ही खून निकालोगे।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): विराजिये। और दूसरा कार्यक्रम जो हमने तय किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो आह्वान किया था कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत तो इसके लिए हमने तय किया है कि हर महाविद्यालय के छात्र जिस स्थान पर वह महाविद्यालय स्थित है उस कस्बे या शहर में एक महीने में एक बार कोई न कोई सार्वजनिक स्थान चुनकर उसकी सफाई करेंगे। तीसरा कार्यक्रम हमने तय किया है कि मानसून के सत्र में सभी कालेजज के विद्यार्थी अपने-अपने कैम्पस में पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण का काम करेंगे और चौथा कार्यक्रम महापुरुषों से हमें मार्गदर्शन मिले इसलिए हमने यह निर्देश जारी किये हैं कि जो महाविद्यालय की चारदीवारियां हैं जो गैलेरीज की दीवारें हैं

(श्री कालीचरण सराफ)

उसमें महापुरुषों के कोटेशंस लिखे जाएं। महात्मा गांधी, पं. जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, लाला लाजपतराय, चन्द्रशेखर आजाद, हेडगेवारजी, गोलवलकरजी, उन्होंने क्या कहा ये कोटेशंस लिखे जायेंगे। और इसके अलावा पांचवां जो महत्वपूर्ण काम हमने किया है कि बुक बैंक की स्थापना। उसमें वहां के छात्र संघ के निर्वाचित पदाधिकारी, प्रिंसीपल और दो लैक्चरर्स ऐसे करके सात लोगों की कमेटी बनेगी और जो बच्चा फर्स्ट ईयर पास आउट करता है सैकंड ईयर में जाता है और वह अपनी किताबें रद्दी में बेच देता है तो उसको यह आग्रह किया जायेगा कि वो अपनी किताबें बुक बैंक में जमा कराये और फिर जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो किताबें नहीं खरीद सकते, ऐसे बच्चों को वो किताबें उपलब्ध करायी जायेंगी। यह हमने पांचवां कार्यक्रम तय किया है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): यह बहुत अच्छा किया है।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): काम तो सारे ही अच्छे किये हैं हमने। इसके अलावा अभी जिस प्रकार से जेएनयू की घटना हुई। भारत विरोधी नारे लगाये गये तो हमने हमारे प्रदेश में यह तय किया है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं सरकारी और निजी और जो सरकारी कालेजज हैं उनमें सबको हमने निर्देश दिया है कि देश की भावना से लोगबाग अवगत हों इसलिए वहां रोज तिरंगा झंडा फहराया जायेगा और इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों को जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनको हमने निर्देश दिया है कि युवाओं के प्रणेता स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति अपने कैम्पस में पहले चरण में सरकारी विश्वविद्यालय अपने यहां लगवायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कई बातें यहां रखी हैं। एक तो अधिकांश सदस्यों ने यह कहा है कि हमारे यहां महाविद्यालय खोले जाएं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 289 इस प्रकार के उप खण्ड हैं जिनमें से 164 उप खण्ड ऐसे हैं जहां सरकारी महाविद्यालय नहीं हैं और हमारा यह कमिटमेंट है कि हम हर जगह उप खण्डों पर सरकारी महाविद्यालय खोलें। 24 तो हमने खोल दिये और आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सीधा ही कह दो कि यह मुख्य मंत्रीजी का विशेषाधिकार है। एक लाइन में निपट जाएगा।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आप बैठ जाइये, बीच-बीच में डिस्टर्ब मत करो। बैठिये-बैठिये। तो इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

(श्री कालीचरण सराफ)

के आधार पर जहां-जहां सम्भव होगा, हम यह प्रयास करेंगे कि सरकारी उपखण्डों पर हम सरकारी महाविद्यालय खोलें। कई माननीय सदस्यों ने अपने यहां स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर सब्जेक्ट्स की बात की है तो मैंने जैसा बताया कि 13 स्नातक और 11 स्नातकोत्तर विषयों की तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बाकी जगह भी हम प्रयास करेंगे कि जो जो माननीय सदस्यों ने कहा है उसके अनुरूप हम नये विषय खोलें। पद रिक्त होने की बात मैंने आपको बता ही दी, कइयों ने कहा कि पद रिक्त हैं। तो इसके लिये यह व्यवस्था हो जायेगी।

इसके अलावा हमारे बेनीवालजी ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर बने हैं पीएचडी नहीं हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आरपी पाधी 1973 से 1974 तक यह वाइस चांसलर रहे, वह भी पीएचडी नहीं थे। वेदपालजी त्यागी जो 1977 से 1979 तक वाइस चांसलर थे, वह पीएचडी तो थे पर प्रोफेसर नहीं थे। इसी प्रकार से हरिमोहन माथुर यह प्रोफेसर नहीं थे। वीआई राजगोपालन, यह भी पीएचडी भी नहीं थे और प्रोफेसर भी नहीं थे।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): वह तो मेरे लिये ही लगे थे। कुछ नहीं थे, उनको तो सिर्फ विश्वविद्यालय का भट्ठा बैठाने के लिये लगाया था आपकी सरकार ने।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): ऐसे कई वाइस चांसलर बने हैं जो पीएचडी भी नहीं थे। एक आदरणीय सुराना साहब ने राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय शेखसर खोडाला लूणकरणसर बीकानेर के एकीकरण का विषय आपने उठाया, इस विषय का परीक्षण करवाकर उचित कार्यवाही की जायेगी। (व्यवधान) जो आदेश किया उसको लागू करवाया जायेगा।

इसी प्रकार मंजू बाघमार जी ने कई प्रश्न उठाये हैं। एक तो इन्होंने कहा, राज्य के आठ अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अकादमिक अंकेक्षण नहीं होती। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता कार्यक्रम टेक्युप के तहत अकादमिक अंकेक्षण होता रहता है एवं भविष्य में भी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता बनाये रखने हेतु अकादमिक अंकेक्षण जारी रहेगा। AICET से भी ...(व्यवधान) संस्थान को अनुमोदन कराना होता है इस बाबत भी AICET द्वारा संस्थान में उपलब्ध शिक्षकों एवं संसाधनों के आधार पर ही अनुमति पत्र जारी किया जाता है। AICET द्वारा शिक्षकों के सीएस के अन्तर्गत

(श्री कालीचरण सराफ)

शिक्षकों द्वारा भाग लिये गये प्रशिक्षण सेमीनार एवं कांफ्रेंस एवं उनके द्वारा आयोजित करवाये गये प्रशिक्षण सेमीनार और कांफ्रेंस में प्रकाशित शोध पत्रों के आधार पर पदोन्नति में नियमानुसार प्रोत्साहन दिया जाता है।

एक इन्होंने यह कहा कि राज्य की एकमात्र महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय का नाम राजमाता विजया राजे सिंधिया के नाम रखा जाये। बीओजी से अनुमोदन के उपरांत राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा।

एक इन्होंने कहा कि महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय में आधी सीटों पर एसएफएस सीटों की फीस 70 हजार के स्थान पर राज्य पोषित सीट के बराबर फीस ली जाये। उक्त हेतु एसएफएस सीटों को राज्य पोषित सीटों में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर विचाराधीन है। अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की बीओजी में आईआईटी एवं आईआईएम के प्रोफेसरों को सदस्य बनाया जाये। राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में आईआईटी एवं आईआईएम के सदस्य उपलब्ध अनुसार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भविष्य में भी इन सभी महाविद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा आईआईटी एवं आईआईएम के प्रोफेसरों को मार्गदर्शन और सदस्यों के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

संदीप शर्माजी ने कोटा में स्थापित होने वाले ट्रिपल आईटी संस्थान के भवन निर्माण कार्य को तेजी से करवाने के सम्बन्ध में कहा। मैं बताना चाहूंगा कि ट्रिपल आईटी कोटा की स्थापना पीपीपी मोड में की जानी है। इस हेतु लागत की 50 परसेंट राशि केन्द्रीय सरकार, 33 परसेंट राशि राज्य सरकार और 15 परसेंट राशि निजी सहभागियों द्वारा उपलब्ध करवाई जानी है। राज्य सरकार द्वारा रानपुर कोटा में 100 एकड़ भूमि नि:शुल्क आबंटित की गई है। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा 4 करोड़ 59 लाख रुपये और निजी सहभागियों द्वारा 9 करोड़ 71 लाख रुपये इस संस्थान के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं। इस तरह संस्थान के भवन निर्माण हेतु 14 करोड़ 30 लाख रुपये उपलब्ध हैं तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। प्रारम्भिक चरण में संस्थान की चार-दीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और आगामी चरणों में भवन, प्रयोगशालाएं व अन्य निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य भंवर सिंहजी और मानिक

(श्री कालीचरण सराफ)
चन्दजी सुराना ने यह कहा कि बीकानेर में जो प्रस्तावित तकनीकी विश्वविद्यालय है उसको इसी सत्र से चालू किया जाये। उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रशासनिक स्तर पर विचार-विमर्श कर बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में आगामी कार्यवाही की जायेगी। यह सारे जो थे वह मैंने बता दिये।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): प्राइवेट बीएड कराने वाले और एसटीसी कराने वालों ने लूट मचा रखीं, उसके लिये आप क्या कहना चाहते हैं?

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): आवाज नहीं आई, आईटीआई का मंत्री मैं नहीं हूं, सुरेन्द्र पालजी टीटी हैं वह इसका जवाब देंगे।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): बीएड और एसटीसी वाले विद्यालय जहां फर्जी पैसे ले रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो एक टैक्निकल बिन्दु है।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो तकनीकी विश्वविद्यालय शीघ्रातिशीघ्र खोलने के लिये जो आपने फरमाया है उसके लिये मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** सम्माननीय सदस्य, कुछ विषय ऐसे हैं जो आप मंत्री जी से मिलकर सैटल कर सकते हैं। Now if he has to react to every grammar of a question probably then it is true that we are running short of time. (व्यवधान) You are not allowed, Sir. Please sit down. श्रीमती कष्णेन्द्र कौर।

**श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** (दीपा) (राज्य मंत्री, पर्यटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

**श्री उपाध्यक्ष:** We are running short of time. Hon'ble Minister, in case, if you would like to table your speech, you could go through the first para in case.

**श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)** (राज्य मंत्री, पर्यटन): Just two minutes. जो 28 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं मैं इनका जवाब कल तक पहुंचा दूंगी और जो माननीय सदस्य विभाग के द्वारा बोले हैं, उनका भी जवाब मैं दे दूंगी। बाकी मैं टेबल कर देती हूं।

**(कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री के शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)**

**श्री उपाध्यक्ष:** आप टेबल कर दीजिए। गजेन्द्र सिंहजी।

**श्री गजेन्द्रसिंह** (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने आज अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में एवं खेल विभाग से सम्बन्धित तीन कटौती प्रस्ताव जो प्राप्त हुए हैं, उनका जवाब कल तक पहुंचा दिया जायेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 84 करोड़ रुपये का उन्होंने इस वर्ष स्पोर्ट को बजट दिया है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिलों में विधान सभा क्षेत्र में विभाग मैचिंग फंड के जरिये, सीएसआर फंड के जरिये और पीपीपी मोड के जरिये हम स्पोर्ट को एक नई दिशा देने में बिलकुल कमिटेड हैं। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आपके आदेशानुसार मैं अपना वक्तव्य टेबल कर रहा हूं।

**(उद्योग मंत्री के शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)**

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री वासुदेव देवनानी।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान के चौदहवीं विधान सभा के छठे सत्र में शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांग संख्या 24 के उत्तर के लिये उपस्थित हुआ हूं। आज 27 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। 231 कट मोशन प्राप्त हुए। सभी सदस्यों ने अलग-अलग अपने विचार रखे और इन सब कट मोशन के अगले 24 घंटे में उत्तर उनको भेज दिये जायेंगे। आज जिस प्रकार से शिक्षा की स्थिति पर चर्चा हुई, मुझे लगता है शिक्षा के बारे में हम लोग इसको आगे बढ़ायें। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी श्रीमती वसुंधरा राजे जी का आभार व्यक्त करुंगा जिन्होंने शिक्षा के लिये 14.47 पिछले संशोधित अनुमानों से अधिक बजट आबंटित किया। मैं उनका कोटि-कोटि अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा सम्बल बजट प्रतिमान, स्वच्छ शिक्षित विकसित राजस्थान, इस थीम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिये जिससे चरित्र बने, बुद्धि का विकास हो, मानसिक तेज बढे और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक परम पूज्य गुरुजी ने लिखा है, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रकटीकरण और कसौटीकरण करती है। भर्तृहरि महाराज कहते हैं, विद्याहीन व्यक्ति पशुतुल्य होता है। महाभारत में भी कहा गया है, चरित्रवानी विद्वाने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन भारत में शिक्षा देने का दायित्व समाज का था। गांव–गांव में गुरुकुल चलते थे। 1850 के आंकड़े बताते हैं कि देश में 7

(श्री वासुदेव देवनानी)

लाख 50 हजार गांव थे और उस समय 7 लाख 32 हजार गुरुकुल थे। आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या स्तर रहा होगा? ईस्ट इंडिया कम्पनी को भी कहना पड़ा कि शिक्षा की दृष्टि से भारत के अनेक गांव की जो उन्नत स्थिति है, वैसी स्थिति दुनिया के किसी भी कोने या देश में नहीं है। अंग्रेजों ने भी यहां की स्थिति को देखकर विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि यदि यही शिक्षा प्रणाली लागू रही तो किसी दिन हम यहां बहुत शीघ्र और निर्लज्ज रूप से खदेड़ दिए जाएंगे। अत: बहुत सोच-विचार करके 1854 में वो डिस्पैच नाम से प्रसिद्ध पत्र गवर्नर लार्ड डलहौजी को भिजवाया, उसमें लिखा कि शिक्षा की नई योजना का आशय शासन तंत्र के प्रत्येक विभाग को विश्वसनीय और काबिल नौकर, क्लर्क दिलवाने का है। अंग्रेज चले गए। आधी-अधूरी हमको आजादी मिली। और आजाद भारत में शिक्षा को देखने के लिए अंग्रेज़ियत के चश्मे वाले लोगों ने विश्वसनीय और काबिल नौकर, क्लर्क दिलवाने वाली शिक्षा चलने दी। जैसे जहाजपुर के मेरे माननीय विधायक ने लार्ड मैकाले की शिक्षा का जिक्र किया और क्योंकि जो सत्ता में आए उस समय, उनका भी उद्देश्य राज करना था। सही शब्दों में कहूं, हम रास्ता भटक गए और राज-सत्ता के मोह में ऐसे अटके कि भारत का विचार गौण हो गया। शिक्षा से संस्कार इसीलिए हटा दिए गए कि सत्ता में बैठे लोगों को वो साम्प्रदायिक दिखने लगे।

महोदय, शिक्षा के जितने आयोग बने, सब ने कहा कि चरित्र का समावेश हो, नैतिक शिक्षा का समावेश हो, भारत के विचार का समावेश हो, परन्तु शिक्षण पद्धति से आई ब्यूरोक्रेसी ने और इस सत्ता के सलाहकारों ने उन सिफ़ारिशों को दरकिनार कर दिया। नतीजा क्या रहा कि हमारे युवकों में धीरे-धीरे संस्कार का लोप होता गया। भारत की धरती पर शिक्षा के मंदिरों में भारत माता की जय के स्थान पर देश के बंटवारे के नारे लगते रहे। जो हमने जे.एन.यू. और बाकी कुछ विश्वविद्यालयों में देखे। और शर्मनाक तो यह हुआ कि देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखने का दम्भ भरने वाले लोग उनको मासूम बताने लगे। यह तो भारत की जनता ने उनको इस काबिल नहीं समझा। अब वक्त आ गया है हमें शिक्षा के वर्तमान ढांचे को समझना होगा, देखना होगा कि हम किधर जा रहे हैं। यूनेस्को ने भी शिक्षा के प्रारूप के प्रतिवेदन में कहा है, "The education of each and every country should be rooted to its culture and relate to its growth." अर्थात् प्रत्येक देश की शिक्षा की

(श्री वासुदेव देवनानी)

जड़ें उसकी संस्कृति में तथा उसका सम्बन्ध देश के विकास से होना चाहिए। आज की प्रणाली की जड़ें भारतीय संस्कृति में नहीं, बल्कि अंग्रेजों की मानसिक गुलामी वाली अंग्रेजी संस्कृति की हैं। आजादी के बाद जिन लोगों को शासन करने का मौका मिला उन्होंने सूचना को ज्ञान और साक्षरता को शिक्षा मान लिया। उन्होंने इन्फार्मेशन को ज्ञान मान लिया और साक्षरता, साइन करना आया उसको शिक्षा मान लिया। विडम्बना देखिए, जो विश्व गुरु भारत था उसको शिक्षित भारत की नहीं, अपितु साक्षर भारत की योजना चलाने के लिए आगे आना पड़ा है।

महोदय, हमारी सरकार का लक्ष्य है 'स्वच्छ, शिक्षित व विकसित राजस्थान'। साक्षरता की दृष्टि से माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान पीछे है। देश का जो साक्षरता का एवरेज है वो 72.99 है, राजस्थान का एवरेज 66.11 है। उसमें भी महिला साक्षरता यह सही है कि 52.12 है। मुझे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस विभाग की जिम्मेदारी दी है, वहां 4 लाख 61 हजार से अधिक शिक्षक हैं और लगभग 90 लाख विद्यार्थियों का एक बड़ा परिवार है। इस परिवार के लिए हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जब इस परिवार में मैंने जिम्मेदारी सम्भाली तो मेरे सामने चुनौतियां थीं। जैसा सब लोगों ने चर्चा की। सरकारी स्कूलों का स्तर गिर रहा है, उसमें गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। सरकारी विद्यालयों में लगातार गिरता हुआ नामांकन, सरकारी विद्यालयों के प्रति निरन्तर घटती विश्वसनीयता, स्कूलों की जर्जर हालत, शैक्षिक वातावरण का अभाव और शिक्षकों में प्रोत्साहन की कमी। हर वर्ष चार लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में कम होते गए। 2010-11 में 72 लाख थे। घटते हुए जब यह सत्ता संभाली उस समय 60 लाख जाकर नामांकन बचे। तो मेरे लिए चुनौती थी कि यह नामांकन कैसे बढ़े ? हमने एक अभियान चलाया और मुझे आज आपके माध्यम से सदन को बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता है। इस सत्र में राजकीय विद्यालयों में 8.5 लाख नामांकन बढ़ा है। जो आज तक के इतिहास में, चार लाख तो रुका लेकिन साढ़े आठ लाख नामांकन बढ़ा। स्कूल वही थीं, शिक्षक वही थे, अधिकारी वही थे, बदली थी तो केवल नेतृत्व की वह सोच कि सरकारी विद्यालय भी कमतर क्यों रहें।

इस सदन के माध्यम से मैं शिक्षा विभाग के उन लाखों शिक्षकों का, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों का और आप सब जन प्रतिनिधियों को

(श्री वासुदेव देवनानी)

धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने प्रवेशोत्सव के माध्यम से किए गए हमारे प्रयासों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और मुझे विश्वास है कि आगामी सत्र में भी हम सब लोग मिलकर के सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता बढ़ाएंगे। क्यों ये मेरे मन में भाव आया कि जब गत वर्ष मैंने बजट प्रस्तुत किया, 197 अरब का जब स्कूल शिक्षा का बजट जा रहा है, उसके लिए समाज को दे क्या रहे हैं। मेरी सरकारी स्कूलों की यह स्थिति क्यों है? और आज जब प्रस्तुत किया 209 अरब तो यह मैं समझता प्रत्येक जन प्रतिनिधि के मन में एक भाव आना चाहिए। सरकारी स्कूलों से जो हम रिजल्ट दे रहे हैं उसको किस प्रकार से हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए जिस प्रकार की चर्चा चली कि यह कैसे हुआ। हमने स्कूल शुरू किए कक्षा एक से दस, कक्षा एक से बारह। पहले विद्यार्थी को कक्षा 1 से पांच जाना है तो टी.सी. लेकर घूमता है। ड्राप आउट हो जाता है फिर आठ में फिर टी.सी. लेकर घूमता है फिर नवीं के लिए जाता है। कुछ स्कूल छह से आठ चलते हैं, कुछ नौ से बारह चल रहे थे, कुछ एक से पांच, कुछ छह से आठ। यानी इस प्रकार की जो विडम्बना थी, उसको हमने रोकने का प्रयत्न किया और आज राजस्थान के अन्दर जो एक से दस और एक से बारह है। मैं आज सदन को यह जानकारी भी देना चाहूंगा, हमारा प्रयास अगले वर्ष राजस्थान के अन्दर यदि स्कूल चले तो कक्षा एक से पांच, कक्षा एक से आठ, कक्षा एक से दस, कक्षा एक से बारह। यह बीच की कड़ी को हम मिटाकर कंटीन्यू विद्यार्थी, उससे ड्राप आउट्स भी कम होंगे क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है हमारी ड्राप आउट्स की।

विद्यालयों के क्रमोन्नयन की बात चली। सबने लगभग चर्चा की। इसकी सराहना भी की। क्योंकि आजादी के बाद 65 वर्षों में केवल इस राजस्थान में यदि सीनियर सैकेण्डरी स्कूल थे तो 4,447 विद्यालय थे। ये स्कूल कैसे बढ़ें, मेरी बच्चियां कैसे बढ़ें? इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जो राजनीति कह रहे थे हमने बिना राजनीतिक पक्षपात के सारी जगह एक ग्राम पंचायत में एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल पांच हजार नए क्रमोनत करके हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया। उसका परिणाम रहा कि इस बार 11वीं में एक लाख नामांकन बढ़ा, जिसमें 60 प्रतिशत बच्चियां थीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पेयर तो नहीं करना चाहता लेकिन पिछली सरकार ने दो वर्षों में केवल 20 विद्यालयों को ही क्रमोनत किया था।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अध्यापक तो लगाओ। (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): वो आगे आ रहा हूं। आपको हर बात बताऊंगा, (व्यवधान)। आप तो धैर्य केवल आज। इस बार हमने 114 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए वर्षों से चली आ रही मांग को भी पूरा किया। राजकीय मूक बधिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, लोधा, जिला बांसवाड़ा, बीकानेर, और बीकानेर के राजकीय उच्च प्राथमिक अंध विद्यालय को हमने माध्यमिक विद्यालय में क्रमोनत कर दिया है। जिससे हमारे दिव्यांग बच्चे आगे भी अध्ययन कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। यह जो एक से बारह केवल विद्यालय नामांकन के लिए नहीं किया कि बच्चा आए और पढ़े, उसको आदर्श विद्यालय के लिए किया। एक ग्राम पंचायत में एक आदर्श विद्यालय बने और उसके लिए कक्षा एक से बारह तक उसमें अध्ययन की व्यवस्था हो, भौतिक संसाधन हों। जैसा उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक वहां पर कार्यरत हों। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। इसलिए पिछले वर्ष 1,340 विद्यालयों का लक्ष्य रखा और इस वर्ष प्रदेश के 3,097 विद्यालयों को भी आदर्श विद्यालय बनाएंगे और उसके अगले वर्ष 5,498 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय खड़ा करके राजस्थान को स्कूल शिक्षा में एक आदर्श खड़ा करेंगे।

आपने कही अध्यापकों की बात। महोदय, प्रदेश की शिक्षा के बुरे हाल क्यों न हों। ना शिक्षा का ध्यान रखा गया, न शिक्षकों के सम्मान की रक्षा हुई। शिक्षक संगठनों के सम्मेलनों में हम जाते रहे। केवल घोषणा करते रहे। हमने तय किया कि जब तक शिक्षक कुंठित रहेगा तब तक वो स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। उसका हक उसको मिलना चाहिए। इसके लिए जो वर्षों से पदोन्नति नहीं हो रही थी। एक साथ पदोन्नति की। आश्चर्य होगा, पांच सौ से अधिक डी.पी.सी. करवाकर 55 हजार लोगों की पदोन्नति हमने शिक्षकों को दी। आज तक स्वतंत्रता के बाद कोई बता दे, 55 हजार किसी एक वर्ष में

**(22.00 बजे)**

हो और 500 से अधिक डीपीसी हो। यह बड़ा श्रमसाध्य था, जिसके लिए मैं अपने अधिकारियों को अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा के हालत बेहतर हुए हैं। चर्चा चली थी कि 20 हैं, कितने रहेगें, मैं कहता हूं कि इस शिक्षा के माध्यम से 2018 के आम चुनाव में हम फिर जीतेगे। हमारा एक सपना है कि 2020 में राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में पहले तीन राज्यों

(श्री वासुदेव देवनानी)

में शामिल करेंगे। आज हम 21वें स्थान पर हैं। हमारे पिछले प्रयत्नों से लगभग हम 7-8 पायदान ऊंचे हो गए हैं लेकिन पहले दस राज्यों में हम आगामी वर्ष तक पहुंचे, हमारा विचार है। यह स्थिति क्यों बनी, आप मन से पूछेंगे, खुद टटोलेगे कि पिछले 1998 से डीओज के केवल 40-45 पद ही भरे हुए थे। एक-एक के पास तीन-तीन चार्ज, चार-चार चार्ज, पद क्यों नहीं भर रहे हो। हमने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया वन टाइम हमको परमीशन दीजिए और आज 185 जिला अधिकारियों से भर गये। एक भी पद जिला अधिकारी का पूरे राजस्थान में खाली नहीं है, हमने सारे पद भर दिए। इसके साथ 13 उप निदेशक भी बनाये। प्रमोशन में 8 हजार 40 प्रधानाचार्य, 11261 प्रधानाध्यापक, 15 हजार 413 व्याख्याता, 25 हजार 516 वरिष्ठ अध्यापक, 2 हजार 189 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, 91 कार्यालय अधीक्षक, 224 कार्यालय सहायक और 1314 वरिष्ठ लिपिक इन सबको हमने पदोन्नति दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्य बहुत श्रमसाध्य भी था, समयसाध्य भी था। विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों ने कितनी मेहनत की होगी इसका अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। एक ओर शिक्षकों को न्याय मिला, कार्मिकों को हक मिला, दूसरी ओर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिले हैं। उससे शिक्षा का वातावरण बना है। नये बने प्रधानाचार्यों ने नवाचार किया है। आप भी सरकारी स्कूलों में गये होंगे, कमियां है इसको स्वीकार करने में मेरे को कोई मन में संकोच नहीं है लेकिन इन नये-नये प्रिंसिपल्स ने जो काम किए हैं, कुछ सरकारी स्कूल तो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर साबित हुए हैं। आप सिलोरा चले जाइये, सीकर चले जाइये, कुछ स्कूलें है, वहां के प्रिंसिपल को उन्होंने परीक्षा परिणामों के बाद भेंट की और कहा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं। इसलिए इन 55 हजार से दूरस्थ विद्यालयों में भी पहुंचे हैं।

मैं आज एक घोषणा और करता हूं कि यह केवल इस बार डीपीसी नहीं की है अगले सत्र से 2016-17 की डीपीसी कराने की हमने तैयारी कर ली है। 15 अप्रैल से अगले वर्ष की भी डीपीसी कराकर हम सारे पदों को भरेंगे। जो डी.डी. के पद खाली है, डी.डी. के 33 पदों में से हमारे पास केवल 7 हैं क्योंकि डीओज का आपने प्रमोशन नहीं किया वह उस योग्य नहीं थे। अगले वर्ष 33 डी.डी. भी पदोन्नत होकर हमको प्राप्त हो जाएंगे जिससे सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मानवीय उपाध्यक्ष महोदय, महिला शिक्षकों को.....

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह भी आ रहा हूं सारे बिन्दु एक-एक बोलूंगा आज, धीरज जी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, महिला शिक्षकों को हक नहीं मिला था। महिलाएं केवल गर्ल्स कालेज में ही प्रिंसिपल लगती थी। को-एड में या पुरुषों में नहीं लगती थीं इस कारण से 10 और 15 साल पीछे छूट रही थीं। मैंने कहा नियम कहां है, कोई नियम नहीं है। आपके समय की एक परम्परा चली आ रही थी। मैंने कहा कि कामन डीपीसी कराओ। आज कामन डीपीसी कराने से आधे से अधिक स्कूलों में महिला प्राचार्य पहुंची हैं जिसके आधार पर स्कूल का वातावरण भी इम्प्रूव हुआ है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): उन्होंने अपना काम किया है, मैं अपना काम कर रहा हूं।

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): हम एक हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री कालीचरण सराफ** (उच्च शिक्षा मंत्री): ×××

**श्री कालू लाल गुर्जर** (मुख्य सचेतक): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विषय ऐसे थे जिनकी वर्षों तक किसी सरकार ने डीपीसी नहीं कराई। जैसे वाणिज्य, कृषि, कला, संगीत, विशेष शिक्षा इन सबको भी हमने उन्नति करा दी। फिर जो बताया कि कहीं 5 अध्यापक है, विद्यार्थी कम हैं, कही विद्यार्थी ज्यादा हैं अध्यापक कम हैं। हमने तय किया कि पूरे राजस्थान के अदंर हम स्टाफ पैटर्न लागू करेंगे। जिसके जितने विद्यार्थी, जितना विषय, उसके अनुसार करेंगे। जहां विद्यार्थी कम थे और शिक्षक ज्यादा थे उनको हमने ठीक किया। आज उसके परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। इस बार तो हमने माध्यमिक शिक्षा में स्टाफ पेटर्न लागू किया। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वर्ष हम

(श्री वासुदेव देवनानी)

प्राइमरी एजुकेशन में भी इसी तरह स्टाफ पैटर्न लागू करके सब जगह बराबर की संख्या में अध्यापकों में पहुंचेंगे। यह निर्धारित मापदण्डों से ही हुआ कि माध्यमिक शिक्षा के अन्दर 1 लाख 39 हजार 38 अध्यापक थे वह शैक्षणिक पदों की संख्या 2 लाख 16 हजार हो गई, यह है। आप कहते हैं कि अध्यापक कम किए। अध्यापक कम नहीं किये उसका रेशनलाइजेशन किया है जो वर्षों से कहीं न कहीं इसी प्रकार की विसंगतियां थीं उसको ठीक करने का प्रयत्न किया है।

यह कहते हैं कि अध्यापकों की कमी है, क्या अध्यापकों की कमी एक साल में ही हो गई, दो साल में ही हो गई, पहले बिलकुल ठीक था, 100 परसेंट थे, दो साल में ही सब गायब हो गये। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसको राजनीति से दूर रखिये।

कई बार जैसे, मेरा बैक ग्राउण्ड था, मैं तो एक नारा लगाया करता था राजनीति के पंजों से शिक्षा को आजाद करो, मेरा वही सोच है। उस सोच के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। उस आधार पर केवल छोटी सी टेबल के बारे में, आपको केवल जानकारी दूंगा। (व्यवधान) भगवाकरण तो लागू करेंगे, उसका विषय का जवाब दूंगा।

दिसम्बर, 2013 में प्रधानाचार्य के 40.51 प्रतिशत पद खाली थे। आपके पद थे 4 हजार 435, रिक्त पद थे 1797 और हमने 5 हजार स्कूल नये क्रमोन्नत किये, क्रमोन्नत हो जाते थे, पद सृजित नहीं होते थे, हमने पद सृजित कर लिए और आज स्वीकृत पद हैं 9 हजार 588 केवल 14 प्रतिशत पद खाली हैं। वह भी आगामी अप्रैल में हम इसको भर देंगे यह मैं सदन को आश्वस्त करता हूं। एक भी प्रधानाचार्य का पद हम खाली नहीं रखेंगे।

प्रधानाध्यापक, उसमें आपके समय 39.68 प्रतिशत खाली थे, हमारे समय अभी केवल 18 प्रतिशत खाली हैं, इनको भी हम भरेंगे। व्याख्याता की बात जरूर है, व्याख्याता भी आपके समय 50 परसेंट पद खाली थे, आज कह रहे हो व्याख्याता नहीं है, अध्यापकों के पद खाली हैं। दिसम्बर, 2013 में जब सत्ता मिली उस समय 50 परसेंट पद खाली थे आज भी 44 परसेंट खाली तो हैं इसको स्वीकार करने में सदन के सामने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है लेकिन एक आश्वस्त करता हूं कि जो पद खाली हैं उनकी संख्या 20 हजार 917 है, इसमें से 13 हजार पद आरपीएससी को अर्चना भी भेज दी, वहां

(श्री वासुदेव देवनानी)

विज्ञापित भी हो गये, परीक्षा की तिथि भी मई में तय हो गई। आगामी 01 जुलाई से सारे 13 हजार पद भी मिल जाएंगे। बाकी जो 6 हजार, 7 हजार पद है उसमें से अधिकांश पद डीपीसी से भरकर व्याख्याताओं की कोई कमी नहीं रखेंगे।

सैकण्ड ग्रेड टीचर्स में आपके समय 27.13 प्रतिशत पद खाली थे। आज 22 परसेंट खाली हैं, उसको भी भरने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज इस सदन में घोषणा कर रहा हूं कि 11 हजार 500 पद जो सैकण्ड ग्रेड के थर्ड ग्रेड से प्रमोशन होकर आए थे, कोर्ट की सारी प्रक्रिया में अटके हुए थे, आज ही कोर्टों ने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया, इनका भी हम एक महीने के अन्दर सारे पोस्टिग कर देंगे। 11 हजार यह उससे भर जाएंगे ... (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): अच्छा और धीरे बोलूं। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आज शारीरिक शिक्षकों की बात उठी। शारीरिक शिक्षक 4 हजार 100 पद खाली हैं, आपके समय 43 परसेंट खाली थे लेकिन हमारे पास आरपीएससी से 3 हजार 800 पद आ गए हैं। हाई कोर्ट से सारा निस्तारण करके इस एक महीने के अन्दर तो कोशिश तो करेंगे 31 मार्च से पहले इन सबको भी हम पोस्टिंग दे दें। शारीरिक शिक्षकों के पद हम पूरे भर देंगे, एक भी स्कूल माध्यमिक का नहीं रहेगा जिसमें कोई शारीरिक शिक्षक न भरे।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): ×××

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: मैं आप सबको स्मरण कराना चाहूंगा कि आसन की बगैर आज्ञा से कोई बोला है तो वह अंकित नहीं होगा।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, ये नई नियुक्तियों की बात करते हैं। गत दो वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न संवर्गों में.....।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): ×××

**श्री उपाध्यक्ष:** सीटें तो चुनाव आयोग अंकित करेगा।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 32,486 नई नियुक्तियां की हैं। 707 प्रधानाध्यापक, 4,520 व्याख्याता, 12,786 वरिष्ठ अध्यापक, 12,840 अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय, 251 शारीरिक शिक्षक, 1,040 कनिष्ठ लिपिक, 337 सहायक कर्मचारी एवं 5 संगणक सांख्यिकी, कुल 32,486 हमारी सरकार ने दो वर्षों में नियुक्तियां दी हैं।

हमसे आप पूछते हो, आपने कितनी विज्ञप्तियां जारी कीं। 13,098 व्याख्याताओं की की हैं। कभी भी हम विशेष शिक्षा को नहीं भूले। 228 वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती के लिये भी हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया उनको भेज दी और शुरू कर दी। थर्ड ग्रेड की बात चली, रीट की परीक्षा की। 15,000 रीट के लिये हमने अर्चना भेजी। परीक्षा हो चुकी है।

आपने कहा 150 प्रश्नों में से 32 प्रश्न। यह पहली बार है। उसके पहले सारी परीक्षाओं में कोई न कोई पेपर आउट हो रहा था। मैं सदन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अभिनन्दन करूंगा, धन्यवाद दूंगा वहां के कर्मचारियों को, जिन्होंने रीट की परीक्षा सफलतापूर्वक कराकर निर्विघ्न करा कर एक इतिहास को रचा है। उसमें, जो आपने कहा उसका भी उत्तर दूंगा। यह जो आपने 32 प्रश्न कहे। यह 150 में से 32 नहीं हैं। यह अलग-अलग भाषा के हैं। किसी में दो हैं, किसी में तीन हैं। कुल मिला करके जो नौ-दस पेपर होते हैं, उसमें से 32 हैं। प्रति पेपर तो 150 में से 3-4 से ज्यादा किसी पेपर में नहीं हैं। यह भी इसीलिये किया। कहीं बाद में कोर्ट्स के चक्कर, क्योंकि पिछली सरकार, जो भी नियुक्तियां करती थीं, कोर्ट में चेलेंज होती थीं और वह नियुक्तियां नहीं दे पाती थी। यह अपने को ध्यान है। मैं इसको पोलिटिकल नहीं ले रहा हूं। पिछली बार जब सत्ता में आये तब 586 रिट याचिकाएं पैंडिंग थीं। उस समय हमने निस्तारण करवाकर आर.पी.एस.सी. से करवाना शुरू किया। फिर आपने उसमें कुछ बदलाव किया। आज भी कोर्टस में उसी को भुगत रहे हैं। युवा भी भुगत रहे हैं, आप भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। यह स्थिति बनी है। इसलिये हमने इसकी जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जांच करवा ली। उसके बाद कुंजी डाल करके लोगों से मंगवा ली। उसकी भी जांच हो रही है। ताकि निर्विघ्न इनकी नियुक्ति हो सके। मुझे लगता है इसकी भी नियुक्ति अगले सत्र से पहले कर लेंगे।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से निवेदन करना चाहता हूं। मैंने प्रोसीडिंग्स में कहा है कि आपका जवाब जनवरी, 2016 में यह है कि 76 हजार पद रिक्त हैं। माननीय कालीचरणजी सराफ का सन् 2014 में जवाब था कि 70 हजार पद रिक्त हैं। आपने अभी फरमाया कि 32 हजार नई नियुक्तियां दी हैं। तो क्या मैं यह मानूं कि 76 हजार में से यह 32 हजार कम हो गयीं।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह जनवरी में, जो इन्होंने दिया। निश्चित रूप से सही दिया होगा। यह 32 हजार उसमें से कम होंगी। लेकिन जिस प्रकार नामांकन बढ़ रहा है, कुछ पद बढ़ रहे हैं तो पद बढ़ते रहेंगे, भरते रहेंगे और चलते रहेंगे। यह तो एक निरन्तर प्रक्रिया है।

कभी भी आज तक कोई सत्ता आई हो, इसको दोहराने में मुझे, कोई भी सत्ता आई हो तो 100 प्रतिशत ...।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह मैंने नहीं कहा। नो, नो। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी। लेकिन शिक्षा के साथ सब मिलकर, यदि एकमुखी होकर प्रयत्न करेंगे तो शिक्षा में सुधार भी होगा और उसके आधार पर पद, यदि कोई कहे कि आपके इतने पद खाली हैं तो क्या किसी राज में नहीं रहे। 100 प्रतिशत किस राज के अन्दर पद भरे रहे। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना बंद कर देना चाहिये। हां, कोशिश करनी चाहिये, सुझाव देने चाहिये कि वह कैसे ठीक हो। और उस पर प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान आगे बढ़ेगा।

अब विस्तार से आगे ज्यादा न करते हुए, गुणात्मक सुधार। आपने शिक्षा में कहा कि बहुत कमी आ रही है। स्कूल जाते हैं, चौथी के बच्चे को नाम लिखना नहीं आता। यह मुझे कई लोगों ने कहा है। आखिर यह स्थिति क्यों बनी। आपके आर.टी.ई.-राइट टू एजुकेशन का जब निर्णय किया, कक्षा एक से लेकर आठ तक फैल नहीं करेंगे। क्यों भाई, जब विद्यार्थी को आप फेल नहीं करेंगे, वह कक्षा में क्यों आयेगा। शिक्षक क्यों पढ़ायेगा। अभिभावक क्यों भेजेगा। तो स्थिति तो दयनीय होगी। फिर तो परीक्षा के ये परिणाम आएंगे। इसीलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा और हमने विधान सभा में आप और हम सबने विधेयक पारित किया।

जब मैंने दिल्ली में यह बात रखी तब उस समय यह कहा गया था

(श्री वासुदेव देवनानी)

कि बच्चों के लिये हम आगे बढ़ें और योग्यता के लिये हम आगे बढ़ते रहें। उसमें मुझे ध्यान है, केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रीजी से बात हुई। संयोग से जब यह विषय राजस्थान ने रखा तो उन्होंने मुझे 'नो डिटेंशन पॉलिसी' का अध्यक्ष बनाया। हम उसमें 8 राज्यों के शिक्षा मंत्री थे। आठ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक ने, अन्य 22 राज्यों ने अपने प्रस्ताव भेजे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 22 में से 18 राज्यों ने इस 'नो डिटेंशन पालिसी' को बंद करने के लिये कहा। यानी परीक्षा करवाएं। इसका हमने प्रयत्न किया।

आज आठवीं के अन्दर जो बोर्ड की परीक्षा, पिछली बार वैकल्पिक परीक्षा करवाई तो डेढ़ लाख विद्यार्थी बैठे। इस बार 12 लाख विद्यार्थी इसमें बैठे हैं। इसमें निश्चित रूप से परिणाम आयेंगे। लड़का पढ़ने लगा है। इसमें हमने केवल यहीं तक कदम नहीं रखे, रुके नहीं। अगले वर्ष से पांचवीं के स्तर पर भी डाइट के माध्यम से जिला स्तरीय परीक्षाएं हम करवाएंगे ताकि गुणवत्ता में सुधार आये। उसमें निश्चित रूप से एक बात आई थी कि इससे तो ड्राप आउट बढ़ेंगे। लोगों का अनमन होगा। तो उसमें भी हमने एक सुझाव दिया केन्द्र को कि कक्षा एक से चार तक परीक्षा तो ली जाये लेकिन बच्चे को रोका नहीं जाये। पांचवीं में आप उसकी परीक्षा लो फिर जो लोग फेल हों उसको एक महीने का टाइम और दो। उसमें वह इम्प्रूवमेंट कर ले, उसको छठी में भेजो। जो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सके उसको पांचवीं में रोका जाये। इसी तरह छठी, सातवीं में नहीं रोकेंगे। आठवीं की परीक्षा में फिर एक महीने का टाइम देंगे। फिर भी इम्प्रूव नहीं करता तो उसको वापस हम आठवीं में रखेंगे ताकि गुणवत्ता के अन्दर सुधार हो।

अब गुणात्मक सुधार के लिये कोई नवाचार तो करने पड़ते हैं। नवाचार करने के लिये हमने हमारे राजकीय माडल स्कूलों को माध्यम बनाया। कहते हुए प्रसन्नता है कि सारे स्कूलों का नाम स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल रखा। केवल नाम नहीं रखा, हर स्कूल के अन्दर स्टेच्यू स्वामी विवेकानन्द की हमने बनवाई है। किसी स्कूल में बन रही है, कुछ में बनवा ली है। इन विद्यालयों में वर्तमान में कक्षा 6 से 9 तक 20 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ये कौन विद्यार्थी हैं। दूर-दराज गांवों के हैं। जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अंग्रेजी के माध्यम से इस प्रकार के अच्छे स्कूल हमको मिलेंगे। आज वे बच्चे पढ़ करके आगे बढ़े हैं। 71 तो माडल स्कूल बन गये, 61 नवीन माडल स्कूलों के भवन के निर्माण का काम, 628.8 करोड़ की लागत से हमने प्रारम्भ कर दिया।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माडल स्कूल आपने बनाये नहीं ना आपने तो, पैसा उल्टा बचा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, बजट से वह करा देंगे, 744 करोड़ आपके पास आये। आप दो साल नहीं रहे। 2013 में जब बात आगे बढ़ी तो मार्केट वेल्यू बढ़ गयी थी। कहा कि 244 करोड़ और चाहिये। लेकिन आपकी सरकार किसी कारण से नहीं दे सकी होगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब आईं। हमने उनसे राज्य बजट से 244 करोड़ रुपये ले करके आज वह सारे निर्माण के कार्य शुरू कर दिये। इन विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, सैट काम होगा, इंग्लिश लेंग्वेज लैब होगी। इन सबको आगे, और आज उसके अन्दर आपके क्षेत्रीय विधायकों का भी रोल बढ़ाया है। एक सीट, उस क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा से बिना किसी पोलिटिक्स के, जो जहां का विधायक है, उसका एक सीट नोमिनेशन करने का हमने उसको दिया है। एक राज्य सरकार के पास है, उसमें एक जिला प्रमुख के पास है। हमने जन प्रतिनिधियों को उसके साथ जोड़ा है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां, एक सीट।

**श्री युनुस खान** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत): ×××

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): जवाब पूरा हो जाये। फिर जितने प्रश्न पूछने हैं, उत्तर दूंगा।

फिर माडल स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की बात चली, 290 स्कूलों में शुरू कर चुके, 380 विद्यालयों में और शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिये 58.6 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। उससे 22800 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस आधार पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पैसा दिया। इनमें भी कोई छोटे-मोटे ट्रेड नहीं हैं। जो आधुनिक ट्रेड चल रहे हैं वह सारे हमने उसके अन्दर वह ट्रेड रखे हैं। उस ट्रेड में आटोमोबाइल है, आई.टी. है, हैल्थ केयर है, ब्यूटी एण्ड वैलनेस है, रिटेल है। सिक्योरिटी है। इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल है। आटोमोबाइल से ले करके इन सारों को हमने जोड़ा है। उन्होंने कहा कुछ क्वालिटी में अंतर है। निश्चित रूप से इसकी भी मैं निगाह रखूंगा। उन बच्चों को वास्तव में शिक्षित करके रोजगार के लिये बनाना हमारा लक्ष्य है। उसके अन्दर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, कोई कम्प्रोमाइज नहीं। हमारी नीयत साफ है। हम करेंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आपको भी कोई कमी ध्यान आये, आप मुझे व्यक्तिगत भी बताएंगे, हम उसको ठीक करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं आयेगी।

फिर जो बच्चे आठवीं के थे, हमने देखा कि रेमेडियल टीचिंग शुरू की जाए और पिछली बार आठवीं बोर्ड की परीक्षा में 1 लाख 32 हजार 512 विद्यार्थी डी ग्रेड से कम में आए, उन विद्यार्थियों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान नहीं आता था। हमने इस बार 1 लाख 22 हजार बच्चों को प्रशिक्षण दिया, उसका परिणाम है कि दसवीं में प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गयी।

फिर एक समस्या और थी कि शिक्षक कहां काम कर रहा है, विद्यार्थी कितने हैं? किसी को नहीं पता और विगत पचास-साठ वर्षों से एक जिस तरह से बहीखाता होता है मुनीम का उसमें हमारा रिकार्ड रहता था और उसमें बाबू चाहे तो उसमें करक्शन कर दे और चाहे तो करेक्शन नहीं करे। तो पता ही नहीं लगता था कि कौन कहां पर काम कर रहा है। जब मैंने प्रमोशन किये, उस समय कई बार शिकायतें आईं कि साहब, गलत पोस्टिंग हो गयी, उसकी वहां पर एंट्री ही नहीं थी, जहां पहले काम करता था, वही थी। पीड़ा ध्यान में आई कि गलती कहां है इसलिए हमने शाला-दर्पण पोर्टल बनाया और उस पोर्टल के अन्दर आपको हर चीज, आपमें से कोई भी चाहे, जनता का कोई आदमी चाहे तो उसमें क्लिक करके उस स्कूल में नाम क्या है, कितने विद्यार्थी हैं, कितने अध्यापक हैं, कितने समय से हैं, बच्चों की जन्म तिथि क्या है? पूरा उसमें 13,401 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का हमने शाला दर्पण एक शुरू कर दिया है और जब हमने शाला दर्पण किया तो लगा कि प्राइमरी एजुकेशन में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, वहां पर सबसे बड़ी कमी है और आज भी है तो उसका नाम दिया शाला-दर्शन, एक का तो दर्पण देख लीजिए और एक के दर्शन कर लीजिए इसलिए दोनों का नाम शाला-दर्पण और शाला-दर्शन रखा।

दर्पण में तो आपकी वह परछाई दिखेगी लेकिन दर्शन से आपको सीधा-सीधा साक्षात् भी ध्यान होगा।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): दर्पण भी करवाओ।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह दोनों करवाएंगे। फिर यह सारा जो पाठ्यक्रम बन रहा है, टेक्नोलोजी का युग है, डिजिटल भारत है तो राज्य ई-ज्ञान पोर्टल हमने शुरू किया उसमें कक्षा 1 से 12 तक की समस्त पाठ्य-सामग्री हमने उपलब्ध करवा दी है। यहां तक ही नहीं, इस पोर्टल पर

(श्री वासुदेव देवनानी)

यह विशेषता है कि कोई भी शिक्षक, कोई भी विद्यार्थी अपने स्वयं के द्वारा तैयार की गयी पाठ्य सामग्री को भी अप-लोड कर सकता है ताकि कोई स्पेशल विद्यार्थी होता है, स्पेशल टीचर्स होते हैं, केवल वह ही नहीं, जो कंटेंट हमने पाठ्य पुस्तकों का डाल दिया, वही केवल पढ़ेगा तो डेली उसमें नई-नई सामग्री हो, वह पढ़ें और अप टू डेट हो। इसलिए डिजिटल इंडिया में हमने वर्चुअल क्लास रूम, 7700 राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम बनाने जा रहे हैं और उसमें क्या होगा? उसमें कम्प्यूटर होगा, एक आपका प्रोजक्टर होगा, उसके वहां से हम बेस्ट उसको एजुकेशन, उसमें कहीं से भी लोड करके सी.डी. लाकर उन बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं ताकि लेटेस्ट नालेज उसको मिले। इस तरह का हमने प्रयत्न किया है।

इन प्रयत्नों में चौथा जो नवाचार, पांचवां किया वह यह किया कि आज तक हमने प्रमोशन से डी.ई.ओ. तो कर दिये लेकिन डी.ई.ओ. को प्रशासनिक अनुभव नहीं है। वह कैसे काम करें? पहली बार मेरे सारे डी.ई.ओज. को फ्लाइट से बैंगलोर भेजकर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से इनकी ट्रेनिंग करवाई ताकि आप लोग वहां पर शिक्षित होकर प्रशासनिक दृष्टि से आगे बढ़ो और इसके साथ डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत डिजिटल लिट्रेसी कार्यक्रम चला रहे हैं और उस डिजिटल लिट्रेसी कार्यक्रम के अन्दर 31 हजार शिक्षकों को आर.के.सी.एल. से कम्प्यूटर की शिक्षा हम दे चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस बार और अध्यापकों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुझे लगता है कि 52 हजार अध्यापकों को हम, और आगे बढ़ेंगे।

बच्चियों की बात चलती है। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी महिला हैं। बेटियों के प्रति उनकी बहुत संवेदनशीलता है। हमने एक नई योजना कि- 'मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना', उसके अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो राजकीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा में प्रत्येक जिले में पहला और दूसरा स्थान, मिनिमम 75 परसेंट वाली दो मेधावी छात्राएं होंगी, कक्षा 11 और 12 में पाठ्य-पुस्तक, स्टेशनरी, यूनिफार्म के 15 हजार रुपये वार्षिक और स्नातक, स्नातकोत्तर में 25 हजार रुपये एकमुश्त हम उनको सहायता देंगे और कक्षा 11 में पढ़ने के पश्चात् आगे जब कालेज जाएंगी तो उसमें छात्रावास शुल्क और समस्त शुल्क, कोचिंग शुल्क इत्यादि में 1 लाख रुपये तक और कक्षा 12 के पश्चात् स्नातकोत्तर, 2 लाख रुपये प्रति वर्ष हम उस बच्ची को सहायता देंगे। इस प्रकार इस वर्ष 2015-16 में 66 मेधावी बालिकाओं को इस योजना से हम लोग लाभान्वित करेंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अब साइकिल की बात चली तो आपने तो ढाई हजार कैश दे दिया। अब गरीब, गांव में जाकर उस बच्ची से पैसे मां-बाप ने ले लिये। कहां खर्च किया? साइकिल खरीदी या नहीं खरीदी? इसका कोई पता ठिकाना नहीं लगता था। हमने तय किया कि हम साइकिल देंगे और इन दो वर्षों में साढ़े पांच लाख, 9वीं में पढ़ने वाली हर बच्ची को हमने साइकिल उपलब्ध करवाई ताकि बच्ची साइकिल चलाकर आएं और उसके साथ में अगले वर्ष यह साइकिल समय पर मिले। कई बार लेट, पिछले सत्र में तो फरवरी, मार्च तक गयी थी, इस बार हमने दिसम्बर तक किया लेकिन इस बार हमारी योजना है कि दीपावली तक वह साइकिल मेरी बच्ची को मिल जाए। 9वीं की बच्चियों को तो मिल गयी लेकिन बाकी 12वीं तक की जो दूसरी बच्चियां हैं और वह यदि पांच किलोमीटर दूर से आती हैं तो हम उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर भी उपलब्ध करवाते हैं।

अब इन बच्चियों के लिए शारदे बालिका छात्रावास और कस्तूरबा बालिका छात्रावास, यह भी चल रहे हैं। इस समय 143 शारदे छात्रावासों का हमने निर्माण करवाया है और उन छात्रावासों में भी चूंकि, पैसा तो केन्द्र सरकार ने, आपके समय, हमारे समय कम दिया तो उस समय केवल 38 लाख रुपये दिये तो उनकी संख्या 100 होनी चाहिए थी तो 100 के नहीं बन पाए। डोरमेट्री नहीं बने कुछ तो इस बार हमने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 47.88 लाख रुपये देकर प्रत्येक छात्रावास को 100 की संख्या बढ़ाने के लिए हमने निर्णय किया है। वह निर्माण का काम करेंगे अगले सत्र से, यह 100-100 संख्या हो जाएंगी और इसके अलावा जो बाकी 37 छात्रावास हैं, वह हमने नए निर्माण के काम शुरू किए हैं और आज राजस्थान में 200 जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हैं, इनमें चलाकर 20309 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।

अब प्रतिभा को प्रोत्साहन मिले, प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलने के लिए हमने लैपटाप योजना हमने शुरू की।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): बूंदी के अन्दर एस.सी. की बच्चियों को लैपटाप लेने के लिए मुर्गा बनना पड़ा और फिर हमने कलक्टर पर दबाव डालकर सी.एस.आर. से दिलवाया। (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): बताता हूं मैं, उसका है मेरे पास केस।

हमने 8वीं, 10वीं और 12वीं, इन तीनों की बोर्ड परीक्षाओं में पहले छह -छह हजार जो बच्चे मैरिट में आएंगे उनको लैपटाप देंगे लेकिन यहां तक ही

(श्री वासुदेव देवनानी)

सीमित नहीं रहे क्योंकि छह हजार मैरिट तो कई बार 8-10 जिलों से ही आ जाती है। मेरे दूरदराज के जो अपने जिले हैं, पिछडे जिले हैं, उनके बच्चे छह हजार में कहीं नहीं आ पाते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस दर्द को समझा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के 100-100 और जो मैरिट वाले बच्चे हैं उनको भी लैपटाप दिया जाए। इस तरह टोटल मिलाकर 27,900 बच्चों को हम लैपटाप उपलब्ध करवा रहे हैं। इस बार तो दो वर्षों के थे, इसलिए 43,174 बच्चों को हमने लैपटाप दिये हैं।

आपने जो कहा, कुछ मेरे पास दो-तीन जगह से शिकायतें आई हैं, उनका मैं परीक्षण करवा रहा हूं और यदि परीक्षण में उस नियम-बंधन में आती है, कोई भी बच्ची या कोई भी बालक तो उसको यह सरकार लैपटाप उपलब्ध करवाएगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। हो गया न?

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): दिलवाए, साहब, बूंदी में तो ... (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं पूरे राजस्थान के अन्दर, पूरे राजस्थान में किसी भी जन-प्रतिनिधि के पास कोई भी शिकायत आए तो उसका निस्तारण करेंगे।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): माननीय मंत्रीजी, मेरा रिक्वैस्ट है कि 24 साइकिल्स और 24 लैपटाप इनको भी दे दो आप।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनको तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, विधायकों को देती हैं न लैपटाप।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): अपनी बात के लिए पांच ... (व्यवधान) रख लो, बस काम चल जाएगा।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): फिर हमने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो परीक्षा होती है, उसमें निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को एकमुश्त दस हजार रुपये पुरस्कार दे रहे हैं और राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को 1,250 रुपये प्रतिमाह राशि प्रदान कर रहे हैं। फिर हमने इससे प्रेरणा लेकर राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा भी इस बार करवाई तो ऐसे विद्यार्थियों को, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के, पहले-पहले 50-50 विद्यार्थियों को हम प्रति माह 1,250 रुपये और उसके बाद शिक्षा के लिए 2 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे।

और, आधुनिकीकरण, 2 हजार विद्यालयों में हमने आई.सी.टी. लैब

(श्री वासुदेव देवनानी)

स्थापित किये हैं। उसके आधार पर कहीं से भी हम उसको पढ़ा सकते हैं और आज 525, इस बार विद्यालय में लैब स्थापना की हमने स्वीकृति जारी कर दी है। इनको सैटेलाइट के माध्यम से गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कम्प्यूटर शिक्षण का हम लोग काम कर रहे हैं।

स्टेट इनीशियेटिव फार क्वालिटी एजुकेशन हम लोग चला रहे हैं। अब आपने कहा कि सफाई नहीं होती, स्वच्छ भारत की माननीय प्रधान मंत्रीजी की जो योजना है, स्कूलों में टायलेट्स की बात आई लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसमें सारे स्कूलों में बच्चे और बच्चियों के लिए टायलेट्स बन गये हैं। कहीं से आपने कहा कि एकाध शिकायत मेरे पास आई। मैंने परीक्षण करवाया, वहां पर शौचालय तो है लेकिन कुछ जगह पर...(व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड सिर्फ, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, आप एक तो गुस्सा इतना ज्यादा करते हैं कि कोई वह शिक्षकों का प्रतिनिधि-मंडल घर पर आया होगा, आपने इतनी डांट-डपट की, उसका विडियो वायरल हो गया। नहीं, इतना गुस्सा क्यों करते हैं, साहब, आप? वह दर्पण ...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): वह भी बता दूंगा, जरा आप तो लैपटाप लेकर बैठ जाओ, मैं बता दूंगा।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय मंत्रीजी नोट करें, आप गांव का नाम पूछ रहे हैं, बालाजेसर लिखिए।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप मेरे को लिखकर दे दीजिए। मैं देख लूंगा।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): वह तो हम लिस्ट दे देंगे पूरी, पर आप कह रहे हो न, किसी में नहीं है, तो इसलिये मैंने तत्काल आपको बताया है कि बालादेसर में नहीं है। ऐसे ही सैकड़ों, हजारों उदाहरण होंगे। आप ध्यान करें, 200 विधायक हैं हम। आपको 5-5 और 10-10 की लिस्ट भेज देंगे कि कौन-कौनसी स्कूलों में लेट्रिन नहीं बनी है। अभी तक तो कमरों के लिये, आपके रमसा में कमरों के लिये भी जितनी मांग आपसे की गयी है, माफ करें आप, माननीय कालीचरण जी की चिट्ठी है कि झिरेरा में माध्यमिक भवन बनेगा। आपका भी पत्र है और आज तक माध्यमिक विद्यालय के भवन का पता नहीं है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सुराना साहब, इतना बता दीजिये, आप सत्य-सत्य पर मत जाइए, यह कालीचरण जी सराफ साहब से बढ़िया बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं?

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी जिम्मेदारी अपनी सबकी है। यदि मेरे पास जानकारी में कहीं कोई, आपको लगता है कि किसी स्कूल में नहीं है, आप सहर्ष 24 घंटे कभी भी मेरे को मेल कर सकते हैं, एस एम एस कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं, मैं उस समस्या को दूर करूंगा।

अब एस एन सी और एस डी एम सी की बात चली कि मीटिंग नहीं होती। हमने पहली बार तय किया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: इसमें मंत्री महोदय, मेरा आपको एक सुझाव है, When you already have a 'SHAALA DARPAN', why don't you call your Principal to upload?

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसमें तो आया है, सब जगह है।

**श्री उपाध्यक्ष**: Upload the infrastructure. That information should be…(Interruptions)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाला दर्पण में तो फिक्स है, सब जगह है यह रिपोर्ट, भरा हुआ है फिर भी यदि व्यक्तिगत प्रेक्टिकली किसी को ध्यान आता है तो We will correct it. और एस एन सी और एस डी एम सी, इनकी बैठकें कई बार होती नहीं थीं। कारण यह था दूरदराज गांव का जो कमजोर वर्ग है, वह अपने धंधे पर जाता है, वह आ नहीं पाता है। मीटिंग कब हो गयी। हमने तय किया कि अमावस्या के दिन एस एन सी और एस डी एम सी की मीटिंग होगी, ताकि उस अमावस्या के दिन वह कहीं नहीं जाता। वहां रहकर वह मीटिंग में आता है। इस आधार पर हमारी उपस्थिति बढ़ी है और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थानान्तरण नीति की बात चलती है। ट्रांसफर पालिसी की बहुत चर्चा चलती है। हर सरकार आई पिछले 68 साल में, केवल चर्चाएं होती रहीं। हमने पहली बार नीति बनाई और नीति बनाकर नेट पर डाल दी। नेट पर डालने के बाद में सुझाव मांगे। सबके सुझाव आ गये। मंत्रिमण्डल उप-समिति की तीन मीटिंगें भी हो गयीं। अब चौथी मीटिंग होने के बाद अब इसको विधान सभा में लाएंगे। फिर प्रारम्भिक शिक्षा की भी इसी तरह से करेंगे। हमारी एक पारदर्शिता के साथ आजादी के बाद पहली बार एक ट्रांसफर पालिसी बनाकर आप लोगों के सामने लाए।

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे का विषय लूं, शिक्षा के अन्दर संस्कार। बातचीत चलती है शिक्षा में संस्कार। (व्यवधान) हमने भी पीसफुली सुना है। मैं भी सुबह से सुन रहा हूं। साल में एक ही बार होता है और मैं सुनाऊंगा। मैं अपनी पूरी बात कहूंगा। पौन घंटे आपका सुना तो मैं भी इतना ही बोलूंगा। (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): इतना अच्छा भाषण सुनने को मिलेगा नहीं बाद में। इतना बढ़िया बोल रहे हो आप।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब शिक्षा में गुणवत्ता, टीचर्स, नवाचार ये सब बातें अपन ने कीं, लेकिन उसमें संस्कार जब तक नहीं होगा, तब तक शिक्षा अधूरी रहेगी और संस्कार के लिए शिक्षा के मंदिर संस्कार के भी केन्द्र हैं, लेकिन बीच में इसको भुला दिया गया और इसलिए दो वर्षों से हमने तय किया कि बसंत पंचमी उत्सव प्रत्येक विद्यालय में मनाया जाएगा। पहले कहीं मनाते थे, कहीं नहीं मनाते थे। अब हमने कहा बसंत पंचमी का उत्सव मनेगा और मां सरस्वती की पूजा वहां पर होगी। फिर हमने हमारी प्रार्थना सभा, बच्चा सवेरे स्कूल आता है उसको संस्कार मिलने चाहिए। प्रार्थना सभा में क्या होना चाहिए? हमने वन्दे मातरम् को उसमें कम्प्लसरी किया और उसके साथ हमने सूर्य नमस्कार, योग ध्यान, प्राणायाम और नैतिक शिक्षा प्रार्थना सभा की कड़ी बनी है। उसके आधे घंटे की सी.डी. मेरे अजमेर के ई.टी. सेल से बनवाकर सारे स्कूलों को हमने भेज दी है ताकि किसी को योग और सूर्य नमस्कार नहीं आते दो तो उससे सीख लें और वह बच्चों को करवाएं। क्योंकि मेरी इसमें सोच है कि आज की शिक्षा में हम बच्चे की आई.क्यू. बढ़ा रहे हैं। इन्फोर्मेटिव बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ उसका ई.क्यू. बढ़े, एस.क्यू. हो, यानी इमोशनल शिक्षा उसको मिले और साथ में स्प्रिच्युअल शिक्षा मिले। इन तीनों का, आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू का जब तक समावेश नहीं होगा, तब तक उस बच्चे को संस्कार नहीं मिल सकते। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि छुपा हुआ एजेण्डा है। कोई छुपा हुआ एजेण्डा नहीं है। हमारा यह एक ही एजेण्डा है और वह यही है।

अटलजी शब्दों में कहूं। अटलजी के शब्दों में कह रहा हूं-

'आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो,
राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो।'

स्कूलों की लाइब्रेरी ठीक हो, पुस्तकालय उदास से पड़े हुए थे, बच्चों

(श्री वासुदेव देवनानी)

की चहलकदमी नहीं थी। हमने प्रदेश में नव-सृजित 50 पंचायत समिति मुख्यालयों में पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों को राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित किया है। इसके अलावा दो साल के अन्दर 40 राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों को निर्माण करवाया है, 19 पर काम चल रहा है। इस पर 6 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत आई है। शिक्षा मंत्री का 4 लाख का विवेकाधीन कोटा होता है। उससे पुस्तकें मंगवाकर भेज सकता है। उसके अन्दर हमने तय किया है कि हमारे बच्चे डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को पढ़ें, महाराणा प्रताप को पढ़ें, शिवाजी को जानें, हेमू कालाणी को जानें, वीर सावरकर को पहचानें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को समझें, पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा, भगत सिंह का बलिदान, शहीद अशफाक उल्लाह खान की देशभक्ति को समझें, श्रीमद्‌भागवत गीता के कर्म पथ पर चलने के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात् करें। इन सबको पढ़कर राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जागृत हो, ताकि जे.एन.यू. की तरह राजस्थान के किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में कोई कन्हैया तैयार न हो। इसीलिए मुझे अटलजी की फिर एक कविता चार लाइनें याद आती हैं –

'जो वर्षों तक लड़े जेल में, उनकी याद करें,
जो फांसी पर चढ़े खेल में, उनकी याद करें,
याद करें काला पानी को, अंग्रेजी की मनमानी को,
कोल्हू में जुतते, तेल पेलते, सावरकर से बलिदानी को,
याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को,
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के,
आत्मसर्ग पावन को, उनको याद करें।'

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अब सबको माफ करे दो न, मंत्रीजी। इतना क्या है? माफ कर दो अब, बस इतना ठीक है। हो गया आपका।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब दो-चार छोटी बातें ही कहूंगा। अभी पाठ्यक्रम की बात चली। माननीय सुरानाजी ने और कई लोगों ने पाठ्यक्रम की बात छेड़ी। पाठ्यक्रम हर तीन साल में, चार साल में बदलता है। उसी कड़ी में पाठ्यक्रम सरकार नहीं लिखवाती। पाठ्यक्रम विशेषज्ञ लिखते हैं। कक्षा एक से लेकर आठ तक एस.आर.टी. लिखती है। कक्षा 9 से 12

(श्री वासुदेव देवनानी)
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखता है। वही अपने विशेषज्ञों को तय करती है, वही लिखते हैं और इसके तहत केवल नीतिगत कुछ बातें होती हैं, जैसे मैंने उनको एक सुझाव दिया था कक्षा एक से लेकर पांच तक, अरे हम अमेरिका को पढ़ा रहे हैं, ओबामा को पढ़ा रहे हैं, मेरे कक्षा एक से लेकर पांच तक के बच्चे को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसको 75 प्रतिशत राजस्थान और 25 प्रतिशत भारत पढ़ाएंगे। छठी, सातवीं और आठवीं में 50 प्रतिशत राजस्थान और 50 प्रतिशत भारत पढ़ाएंगे। नवीं के बाद वह आगे विश्व की ओर बढ़े। घर को तो जाने नहीं और विश्व की ओर आगे बढ़ चले। इसलिए मेरे से किसी ने पूछा कि आप कैसे चेंज कर रहे हो? मैं तो पहले पढ़ाते थे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा। मैंने कहा यह हम नहीं पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे क से कम्प्यूटर, ख से खगोल ओर ग से गणेश पढ़ाकर हम इसको संस्कृत के साथ जोड़ेंगे। फिर पूछा ए, बी, सी कहा ए फोर एप्पल, बी फोर बैट, सी फोर कैट, अरे बैट और कैट पढ़ाने का अब जमाना नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा ए से अनंत, बी से मेरा भारत और सी से कम्प्यूटर, यह सोच है पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए एक दिशा तक। इसीलिये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम विद्यार्थियों के...(व्यवधान)।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात पूछूं।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप एक बार मुझे बोल लेने दो। एक बार बोल लूं, उसके बाद आप बोल लेना।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): विवेकानन्द माडल स्कूल में एन सी ई आर टी का कोर्स आपके डिप्टी डायरेक्टर, जस्सारामजी ने सबको निर्देश दिया है कि एन सी ई आर टी का कोर्स ही पढ़ाया जाएगा।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं इसका उत्तर दे रहा हूं न।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): जब माडल स्कूल में, आप बात सुन लें। आप माडल स्कूल में जब एन सी ई आर टी को पढ़ा रहे हैं तो एन सी ई आर टी के कोर्स को दूसरे विद्यार्थियों को न पढ़ाने का कारण क्या है? आप पाठ्यक्रम बदलिये, मैंने मना नहीं किया। मैंने यह कहा है कि आपने जो भी बनाया है, वह विद्वतजन की कमेटी उसका परीक्षण कर ले।

आप इसमें बहुत अधिक शीघ्रता या जल्दबाजी न करें, जो करिये धीरज से करिये और विद्वतजनों की राय के बिना मत करिये।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हो रहा है विद्वतजनों की राय से हो रहा है। लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम पढ़ाते थे अकबर महान, इस राजस्थान के अन्दर अकबर महान नहीं पढ़ायेंगे, हम पढ़ायेंगे प्रताप महान क्योंकि प्रताप महान रहा है। कारण उसका यह है, मैंने मित्रों से पूछा, महात्मा गांधी इस देश के महान हैं, क्या एलिजाबेथ महान हो सकती है क्या? क्योंकि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेज महान इस देश में नहीं हो सकते। महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ स्वतंत्रता का आन्दोलन किया इसलिए महान होंगे तो प्रताप होंगे। इसलिए हमको पाठ्यक्रम में संस्कार देने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी और हम परिवर्तन कर रहे हैं।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): इन्दिरा गांधी भी पढ़ायेंगे ...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): जो भी वीर है, सारे वीर महापुरुष हमने किसी का पाठ नहीं हटाया, जोड़ा है।

इसलिए मैंने कहा आज के विद्यार्थियों को इतिहास के नाम पर जो पढ़ाया जाता है वह वास्तविक इतिहास नहीं है बल्कि विजेताओं की वरदावली है, कहते हैं शेरों के इतिहासकार नहीं होते इसलिए शिकार कथाओं में केवल शिकारियों को ही महिमा मंडित किया जाता है, उसकी आज इतनी आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार संस्कार और सामाजिक सरोकारों के साथ नैतिक शिक्षा भी किया है इसीलिए यह मैंने आपको किया।

इसके लिए संस्कृत की बात चली, हमने इस बार सीनियर हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूलों में सब में एक-एक पद संस्कृत का सृजित कर दिया है ताकि बच्चे संस्कृत पढ़ें और आगे बढ़ें। इस आधार पर मैं चार लाइनें कह दूं सुरानाजी, आपकी अनुमति हो तो, 'पाश्चात्य संस्कृति के भ्रम मिटायेंगे, सूरजमल, प्रताप पराक्रम पढ़ायेंगे, पाठ्यक्रम में ऐसा समावेश होगा, सबसे ऊपर हमारा देश होगा।, जय जवान, किसान, जय ज्ञान विज्ञान, बच्चे पढ़ेंगे मेरा भारत महान।'

अब चूंकि सब लोग कह रहे हैं, अब संक्षेप में अंतिम पांच-दस मिनट में बात पूरी करता हूं।

अब बात चली कि, साहब, संवाद नहीं होते। अपने में से कई एम.एल.एज. को पता है, मैं राजस्थान के 33 जिलों में से 25 जिलों में गया, वहां पर मैंने जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया और वहां पर सामने शिक्षा विभाग

(श्री वासुदेव देवनानी)

के अधिकारियों को बैठाया, आमने-सामने संवाद किया, जिसकी जितनी समस्याएं थीं उसका निस्तारण करने का हमने प्रयत्न किया और यह संवाद प्रक्रिया हम लगातार जारी रखेंगे और इसी के साथ में शिक्षक संगठनों के साथ भी ...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): केवल बी.जे.पी. वालों को बुलाया होगा, हमको तो नहीं बुलाया।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, सभी, सभी गये थे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): नहीं, हमें नहीं बुलाया, सीकर गये थे आप।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): बैठो, उसका जवाब देता हूं। आपने आज तक शिक्षा में रुचि लेकर के मेरे को कभी समस्या ही नहीं बतायी, जिसकी समस्या है उसको बुलाऊंगा न। आपकी समस्या हो आइये, आपको भी खबर करूंगा। आप समस्या तो बताओ। आप में से कोई कह दे कि मैंने शिक्षा मंत्रीजी को समस्या बताई उन्होंने मेरे से बात नहीं की या मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया तो तो मैं गुनहगार। यदि आप बताओगे ही नहीं तो मैं सोचता हूं आपको कोई समस्या ही नहीं है, फिर बुलाने की इसलिए मैंने हिम्मत नहीं की।

इसके साथ ही मैं सारे शिक्षक संगठनों के साथ बैठा, उनके साथ बुला करके बात की। इसके लिए हमने शिक्षा समाधान वेब पोर्टल और हैल्प लाइन शुरू की है और उसके आधार पर हमने किया और यहां कहते हैं। अब्दुल कलाम के जन्म दिन को, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने उनके जनम दिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में सारे स्कूलों में मनाने का निर्णय किया, जिसको हमने मनाया ...(व्यवधान)

फिर इस बार 12 जनवरी को हमने विशेष अभियान चलाया कैरियर डे। अरे, कैरियर डे क्या, स्कूल में बैठकर के कोई कार्यक्रम होता है क्या, उस दिन हमने सारे आर.ए.एस., आई.ए.एस., डाक्टर्स इनको एक-एक स्कूल में भेजा, जरा बच्चों को कैरियर के बारे में बताएं और इस बार यह प्रयोग काफी सफल रहा, हम सोचते हैं कि इसको हम लागू करेंगे।

यह सारी जो व्यवस्थाएं हुईं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है जो नामांकन बढ़ा, जो शैक्षिक वातावरण बढ़ा उससे भामाशाहों का मन बना है। आज आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान में एक वर्ष के अन्दर, पिछली बार 20 करोड़ रुपये

(श्री वासुदेव देवनानी)

भामाशाहों ने दिये, इस बार केवल 26 जनवरी को प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में भामाशाहों के माध्यम से दस करोड़ से अधिक राशि हम को उपलब्ध हुई है। यानी लोगों का रुझान, यह वातावरण बनता है। आप और हम आइये, नेगेटिव बात को छोड़े, पाजिटिव बात पर चलें, समाज में बहुत पैसे वाले हैं, उनका मन तैयार करें। स्कूल में आयेंगे, कमरों की और यह सारी बातें धीरे-धीरे पूरी होंगी। राज में जितने पैसे जिसके पास होंगे उतने खर्च करेगा लेकिन आज भामाशाहों के पास विद्या के लिए दान करने की बहुत बड़ी इच्छा है, केवल उनको एप्रोच करना है, वातावरण बनाना है, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, यह वातावरण बनायेंगे तो वो पैसा भी देंगे, नहीं तो फिर पैसा अपने को नहीं मिलता।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात चली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पिछली सरकार के कार्यकाल में ...

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आराम फरमा सकते हैं, उप मुख्य सचेतक महोदय बैठे हैं।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): बस केवल दो ही हैं, दो-चार पन्ने हैं।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन भागना चाह रहा है। सब इधर-उधर ताक झांक कर रहे हैं, बहुत गलत बात है।

**श्री मदन राठौड़** (उप मुख्य सचेतक): कोई नहीं भाग रहा। (व्यवधान)

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): डोटासराजी कह रहे हैं (व्यवधान) अपने सचेतक महोदय को कहो आप, यह जल्दी कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): जितना बोलोगे, उतनी और देर होगी।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): यह जो पूरी जान दे रहे हैं।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपनी एक प्रतिष्ठा थी परन्तु गत सरकार के समय उसकी विश्वसनीयता पर दाग लगे, भ्रष्टाचार का गढ़ हो गया, इसमें नये सुधार किये। आज बायोमैट्रिक अटेन्डेंस, सी.सी. टी.वी. कैमरे स्थापित किये हैं और उत्तर पुस्तिका में पहली बार बारकोड का प्रयोग किया गया है जिससे उत्तर

(श्री वासुदेव देवनानी)

पुस्तिकाओं के जांचने में किसी प्रकार की सांठ-गांठ न हो। इसलिए बोर्ड की प्रतिष्ठा बढ़ायी है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके तो सभापति ही नहीं है, कोई दिक्कत हो गयी, सभापति पैनल में से कोई नहीं है और न अध्यक्ष जी हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आसन को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यह बता दीजिए कि आप 18 में पास करवायेंगे या 19 में पास करवायेंगे? यह आप बता दीजिए।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): 18 में नहीं होगा 19 में होगा, मैं यही कहने वाला था। आराम से, अभी अपने पास डेढ़ घंटा है, आप आराम से।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): कोई चिंता नहीं, पूरा पढ़ूंगा। सुनना तो पड़ेगा। काम किया है तो बताऊंगा और सुनना भी पड़ेगा।

आधारभूत ढांचे की बात चली। रमसा की, एस.एस.ए. की, यहां कमरे नहीं हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2009-10 में, 2010-11 में माध्यमिक विद्यालय में न तो कोई भवन निर्माण हुआ, न कोई अतिरिक्त कक्षा कक्ष बना, न कोई बजट आबंटित किया गया और जब मैं दो वर्षों की 2014-15 और 2015-16 से तुलना करता हूं तो 62 माडल स्कूलों के 276 करोड़ रुपये खर्च हुए, इसके लिए राज्य सरकार ने 438 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

इसी प्रकार हमने 965 नवीन प्राथमिक भवन, 37 यूपीएस, 6105 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 1310 विद्यालयों की चारदीवारी, 2712 शौचालय, 231 प्रधानाध्यापक कक्ष, 596 मरम्मत और 12316 निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को पूरा करने में 470 करोड़ रुपये इन दो वर्षों में हमने खर्च किये हैं। कमी तो है, आज भी बहुत कमी है।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): यह तालियां घोषणा के लिए नहीं बजा रहे हैं, यह किसी को नींद नहीं आ जाए इसलिए बजा रहे हैं।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि इस बार 445 विद्यालयों में उन्होंने 180 करोड़ रुपये की लागत से 1667 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय यह हमको दिये हैं और रमसा को गति देने के लिए हमने 1750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। और मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने 628 जो

(श्री वासुदेव देवनानी)

सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी हो, जहां बिजली नहीं थी वहां इस बार हमने बिजली के कनेक्शन और फिटिंग के कार्य का भी प्रावधान किया है।

मैंने अपने भाषण में कहा था कि हमारे सामने चुनौती बहुत है, कई जगह अभी भी कमरे नहीं हैं तो आपसे अपील करता हूं कि आप एम.एल.ए. फंड से, एम.पी. फंड से, रमसा से, एस.एस.ए. से, भामाशाहों से, शिक्षा देना केवल अकेले सरकार का काम नहीं है, हम सब सरकार के पार्ट हैं, हम सब मिलकर के उसको करें। इसके लिए जब चारदीवारी और खेल के मैदान की बात चली, आपको जानकारी देते हुए हर्ष है नरेगा के अन्दर चारदीवारी बनाने का तो मना है लेकिन फैंसिंग वायर के लिए परमिशन है तो हमने सारे कलक्टर को कहा है कि फैंसिंग वायर करके अतिक्रमणों से इन जमीनों को बचाया जाय और जेसीबी बुलाकर के वहां पर मैदानों को इस प्रकार किया जाए ताकि वो लोग खेल सकें।

अब कुछ जो आगामी वर्ष के लिए घोषणाएं हैं उसके बाद इसको कन्क्लूड करूंगा। महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि अगले सत्र से पाठ्यक्रम में युगानुकूल और देशानुकूल करते हुए हम नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करेंगे। फिर विद्यार्थियों को, हमारे परिवहन के माननीय मंत्रीजी भी बैठे हैं, इनसे बात हुई, सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष हजारों लोग मर रहे हैं तो क्या शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती, हमने कहा कि यह सड़क सुरक्षा का पाठ हम अपने पाठ्यक्रम में जोड़ रहे हैं।

जल स्वावलंबन के लिए, स्वच्छता के लिए जागरूक करने की दृष्टि से स्वच्छता जैसे विषय को हमने शामिल किया है। साथ में एक बहुत बड़ा मेरे ध्यान में आया, छात्रवृत्तियां सामाजिक अधिकारिता विभाग भी देता है, हमारे विद्यार्थियों को देता है, बच्चों का पता ही नहीं है कौनसी छात्रवृत्ति मिलती है कौनसी नहीं मिलती है, अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं इसलिए हमने तय किया कि प्रत्येक पुस्तक के पीछे के पृष्ठ पर जितनी छात्रवृत्तियां मिलती हैं उसको हम प्रिंट करेंगे ताकि हर बच्चा उसको पढ़े, उसको जाने कि छात्रवृत्तियां कैसे ली जाती हैं, क्या ली जाती हैं। इसलिए भामाशाह और आरोग्य राजस्थान, हमने सभी डिपार्टमेंट्स को साथ लिया। हमने चिकित्सा मंत्रीजी को भी आग्रह किया। उसमें भामाशाह और आरोग्य राजस्थान जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को भी पाठ्यक्रम का अंग बनाया है।

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जल स्वावलंबन का है?

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): जल स्वावलंबन का है। जल स्वावलंबन का बनाया है।

अब काफी लोग कहते हैं कि मानीटरिंग की कठिनाई है, इसलिए मानीटरिंग की कठिनाई को कम करने के लिए जैसे कई बार मेरे 9 सेन्टर्स पर डीईओ 2-2 हैं, लेकिन दोनों का केन्द्र एक ही है। इसलिए हमने सोचा कि डीईओ के और डीडी के जो केन्द्र हैं, वहां पर एक का मुख्यालय रहेगा और एक का जिले में अन्यत्र रहेगा। साथ में मैं परीक्षण करवा रहा हूं, अभी प्रक्रियाधीन है कि इनकी मानीटरिंग करने के लिए कोई क्राइटेरिया तय किया जाये। हमने तय किया कि 350 स्कूलों का एक डीईओ देखे, उसके बाद नेक्स्ट 250 पर दूसरा डीईओ देखे, फिर तीसरा डीईओ देखे। इस तरह से डीईओ के नये प्रस्ताव बनाकर के हम तैयार कर रहे हैं ताकि शैक्षणिक व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके।

अभी फैकल्टी की बात चली। कई प्रस्ताव आये। लेकिन आज तक राजनीतिक दृष्टि से फैकल्टी खुलती थी। राजनीतिक दृष्टि से स्कूल खुलते थे। उसके कारण से स्कूल तो खुलते गये लेकिन ना कहीं मेरे बच्चे हैं, ना कहीं फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं। 3-3 लैक्चरर वहां लग जाते फैकल्टी के, इसलिए तय किया कि जहां पर दसवीं के अन्दर 100 से अधिक नामांकन हैं, वहां हम नई फैकल्टी खोलेंगे। ऐसे 152 स्कूलों को तो हमने चिह्नित किया है। यदि इसके अलावा भी कोई स्कूल आयेगा तो वहां भी हम नई फैकल्टी खोलेंगे। चाहे वह वाणिज्य खोलें, चाहे कृषि खोलें, चाहे विज्ञान होगी, वह हम खोलेंगे।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो हमने जो शिक्षा विभाग में कमियां बताईं, वह शब्द हमारे वापिस लेते हैं।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने अभी हमारी 'मुख्यमंत्री बेटी योजना' की चर्चा की। पहले तो हम 2 छात्राओं को देते थे। इस बार बीपीएल परिवार की एक और मेधावी छात्रा का भी प्रत्येक जिले में चयन होगा ताकि 66 और 33, 99 बालिकाओं को हम यह सुविधाएं देंगे।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने आदर्श स्कूल, सीनियर सैकण्डरी तो खोल दिया। लेकिन मेरा प्राइमरी एजुकेशन क्या करेगा। हमने कहा कि मिडिल स्कूल भी हर ग्राम पंचायत में एक-एक आदर्श शुरू करेंगे। हर ग्राम पंचायत में एक आदर्श मिडिल स्कूल भी हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

अब नेतृत्व क्षमता बढ़े, इसके लिए गोनेर डाइट की चर्चा आई। राजस्थान लीडरशिप एकेडमी के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। 9 जो सम्भाग केन्द्र हैं, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, चूरू आदि ऐसे स्थानों पर डिजिटल लर्निंग सोल्युशन रूम की स्थापना कर रहे हैं।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): सराफ साहब ने आपके 2 पन्ने उठा लिये।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): कोई नहीं जायेगा। मुझे याद है कि यह नहीं भी रहेंगे तो भी उसकी चिंता मत करो।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): पीछे के 2 फोल्डरों में 20-20 पन्ने हैं अभी।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप कितना ही कह दो। अब जो डाइट्स हैं, इन डाइट्स की कई बार शिकायतें आती हैं कि डवलप नहीं होती। प्रत्येक डाइट के अन्दर डाइट डवलपमेंट्स सोसायटी का गठन कर रहे हैं ताकि उसका डवलपमेंट हो सके। प्रत्येक डाइट के अन्दर बीएसटीसी वालों की कमी है, वहां 50 की जगह 100 की क्षमता बीएसटीसी की बढ़ा रहे हैं।

बहुत बड़ी एक समस्या थी जिसकी आज चर्चा की कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, मान्यता के लिए फाइल डीईओ के यहां लगाते हैं। डायरेक्टर के यहां जाती है। उसको मान्यता नहीं मिल पाती है। साथ में बोर्ड के अन्दर भी कई बार भेजते हैं। अगले वर्ष से प्राइवेट स्कूलों की मान्यता आनलाइन की जायेगी। किसी को भी आफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। कोशिश करेंगे कि बोर्ड के अन्दर संबद्धता का भी हम आनलाइन करें।

दूसरी समस्या प्राइवेट स्कूलों की आरटी से पुनर्भरण की, उसके लिए भी हम एक नीति बना रहे हैं जिससे कि एक निर्धारित प्रक्रिया और जवाबदेही सुनिश्चित होकर के उनको समय पर भुगतान हो।

**एक माननीय सदस्य:** अब तो प्रतिपक्ष के सदस्य भी मेज थपथपा रहे हैं।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसलिए मैंने कहा था कि पहले मुझे बुलवा लो। पहले यह बोल गये तो मुझे बोलना है।

**श्री उपाध्यक्ष:** मंत्री महोदय, you take your time. There is no hurry what-so-ever.

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए और हम सबकी भागीदारी बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला शिक्षा बोर्ड का हम गठन करने जा रहे हैं। जिसमें प्रत्येक जिले के 2-2 विधायक होंगे। एक एमपी होगा, एक जिला प्रमुख होगा और 3-4 शिक्षाविद होंगे। उसमें कलक्टर भी होंगे। इस तरह जिला स्कूल शिक्षा बोर्ड का गठन हम लोग कर रहे हैं।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): एक मिनट मंत्रीजी। देखो, मैं सुन रहा हूं आपको। 11 बज रहे हैं। मैं बैठा रहूंगा जब तक आपका भाषण हो। यह 3 दिन से हम भाषण सुन रहे हैं, कटारियाजी का सुना, कालीचरणजी का सुना और देवनानीजी का सुना। मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि मैं इनका भाषण सबसे अच्छा मानता हूं।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर): आप तो भक्त हो गये और यह मूर्छित हो गये उसका क्या इलाज है।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब शिक्षकों की कुछ समस्याएं थी, कर्मचारियों के कई समस्याएं रहती हैं। उसको हम शिविर लगाकर के दूर करेंगे। लेकिन बायोमैट्रिक्स मशीन अध्यापकों के लिए सुनिश्चित हो। इसलिए प्रयोग के तौर पर झालावाड़ और अजमेर के 125-125 विद्यालयों में हम बायोमैट्रिक्स मशीनें लगाकर के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं।

शिक्षा सम्बलन, कई बार आता है कि फरवरी में होता है उसमें कोई लाभ नहीं होता है। आगे से शिक्षा सम्बलन अभियान 25 सितम्बर, दीनदयाल उपाध्याय जयंती से 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती के मध्य होगा और दूसरा चरण 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जयंती से लेकर के 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के मध्य होगा। पांचवीं की मैंने घोषणा कर ही दी आपको।

एक बहस में बात आई थी कि शहीदों के नाम, कई बार स्कूल का नाम नहीं होता। मेरे पास 151 प्रकरणों की सूची है। आगामी महीने भर के अन्दर हम इन 151 स्कूलों का शहीदों के नाम पर नामकरण कर देंगे। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि अभी विगत दिनों राजस्थान की पहली महिला सरपंच जो सौभाग्य से जहाजपुर विधान सभा की थी, उनका देहावसान हुआ। हमारी विधान सभा के अन्दर एक स्कूल उनके नाम पर आप करा दें।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप प्रस्ताव भिजवा दें।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): पहली महिला सरपंच राजस्थान की।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): भामाशाह नहीं कह रहे हैं। शहीद होगा जो सेना में शहीद हुआ हो। आप निश्चित हों, आप प्रस्ताव भिजवा दें। नियमानुसार उनका परीक्षण गुणावगुण के आधार पर करके करेंगे।

फिर एक समस्या और आई कि शिक्षा विभाग के नियम सन् 1970 और 1971 के बने हुए हैं और उसमें अलग-अलग शिक्षा, अधीनस्थ का अलग, शिक्षा का अलग और पृथक-पृथक नियमों की विसंगतियां बहुत हैं। इनको हटाकर के राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा नियम, 2016 हमारे प्रस्तावित हैं। अगले सत्र में हम इन नये नियमों को लागू करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी हमको 2 करोड़ रुपये ईटी सैल के लिये दिये। ईटी सैल में स्वतंत्रता के पहले की और बाद की कई फिल्में हैं। वह खराब हो रही थीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2 करोड़ रुपये जो दिये हैं, इससे ईटी सैल से उन सारी फिल्मों का हम री-इंस्टालेशन कराकर के इसका सदुपयोग करेंगे। जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, 10 मिनट की पानी-पेशाब की छुट्टी दे दो।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): नहीं, एक मिनट ही है। आपने ही कहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस यह लास्ट है। हमारी मान्यता है कि राष्ट्र की तरक्की के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली औजार है। गरीबी से लड़ने के लिए सबसे ताकतवार हथियार है। इसको पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति, धरोहर, इतिहास पर गर्व करें। भारत की जीवंतता पर विश्वास हो। मेरा यह मानना है कि प्रत्येक देश की अपने विकास की अवधारणा खुद विकसित करनी होगी। उधार ली गई अवधारणाओं से अनेक विकासशील देशों का विनाश ही हुआ है।

आज विश्व तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन के दौर में यदि हम समयानुकूल और देशानुकूल अपने आपको तैयार नहीं करेंगे तो पीछे छूट जायेंगे। मुझे 'बूट पालिश' फिल्म के गाने की पंक्तियां याद आती हैं, 'नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुठ्ठी में क्या है'। आधुनिक तकनीकी के युग में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी भी कहते हैं कि विद्यार्थी का हक उसकी हथेली पर क्यों ना हो। यानी इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

सरकारें आती हैं और जाती हैं, कल अर्थात काल अपनी गति से बढ़ता जाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था, 'जब भावी संतति की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो वास्तव में हमारी उनके प्रति उपकार की भावना नहीं रहती, अपितु हमें जो कुछ धरोहर अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, उसे आगे की पीढ़ियों को सौंपकर उनके ऋण से उऋण होने की मंशा रहती है'।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि विद्यार्थियों को शिक्षित, दीक्षित करने में हम सब मिलकर के सामूहिक प्रयास करें। हम लोग अपने प्रवास पर जाते हैं तो पास के किसी स्कूल में चले जायें, कस्तूरबा छात्रावास में चले जायें, शारदा छात्रावास में चले जायें, वहां बच्चियों के साथ बैठें, निरीक्षण करें और कोई कमी हो तो तत्काल उसकी जानकारी देकर के जो तात्कालिक ठीक हो सकती, वह करें।

स्कूल में कभी चले जाएं, अध्यापक समय पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको चैक करें, यदि हम सब लोगों ने अपनी सहभागिता की तो मुझे विश्वास है कि इस सदन में उपस्थित प्रत्येक माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होगा कि व्यक्ति हित से बड़ा राष्ट्र हित होता है और राष्ट्र हित के लिए शिक्षा एक अहम आयाम है। हम सब मिलकर यदि तय कर लें कि राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान भारत में सिरमौर बनकर खड़ा हो सकता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान एक राजस्थानी के रूप में होती है वहां किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के रूप में नहीं होती, यह कांग्रेसी आ गया, यह बीजेपी का आ गया, यह एसपी का आ गया, वहां पर हमारी पहचान राजस्थानी के रूप में होती है इसलिए इस पवित्र सदन में अपने सम्बोधन के अंत में मैं कहना चाहूंगा,

सभी सदस्यों से करता आह्वान,
सब मिल बनाएं शिक्षित राजस्थान,
जन गण मन, वंदे मातरम् गान,
जय जय हिन्द, जय जय राजस्थान।

अब अंत में जिनके कट मोशन आए...(व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्रीजी से बार-बार बीच में पूछना ठीक नहीं है, आपकी इजाजत हो तो मैं अंतिम एक सवाल पूछूं, वह सवाल यह है कि हमने जो ...(व्यवधान) आपका भाषण खतम हो गया इसलिए हम इजाजत ले रहे हैं पूछने की। (व्यवधान)

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप विद्यार्थी मित्र, डार्क जोन के अध्यापक, अध्यापकों की वेतन विसंगति का क्या हुआ? (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी मित्रों के बारे में कुछ नहीं बोला। (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सदस्य, आप विराजें, मैं बोल रहा हूं। आपकी समस्या पर ही बोल रहा हूं। आप बैठिए तो सही, उत्तर तो पूरा कर लूं।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): हमने सोचा कि आपका भाषण पूरा हो गया। (व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने अभी उत्तर खतम नहीं किया है, मैं अभी बैठा नहीं हूं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं जो विपक्ष के माननीय सचेतक महोदय ने कहा कि इसमें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का प्रतिवेदन नहीं आया। यह प्रारम्भिक शिक्षा का प्रतिवेदन है, इसमें सभी एसएसए का, साक्षरता, सतत शिक्षा का, एसआईईआरटी का, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड का, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल का, सारा ही इसके अन्दर प्रतिवेदन है इसलिए नियमानुसार हर साल इसी प्रकार से आता रहा है। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): अकाउंट्स नहीं है।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): अकाउंट्स हम दे चुके। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): कहां दे चुके? हमारे पास तो नहीं आया, सदन में भी नहीं आया, यह कह रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो ...

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): मेरे मित्रों ने ...(व्यवधान) आप पूरे भाषण के बाद बोल लेना आप तो इतने वरिष्ठ हो। (व्यवधान)

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर): तो अभी क्या भाषण हो रहा है?

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): अभी हो रहा है, अभी बैठा थोड़े ही हूं? (व्यवधान) आपको अस्पताल जाना है इसलिए थोड़ा लेट शुरू किया है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने विद्यार्थी मित्रों की बात कही। ...(व्यवधान) मैं एक-एक पर आऊंगा। विद्यार्थी मित्रों के बारे में सभी जानते हैं कि इनको 2006 में नियुक्ति दी और 2013-14 तक ये कार्यरत थे, इनमें से कुछ लोग कोर्ट गए और याचिका त्रिलोक सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक 21.10.2013 को जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने पारित किया, विद्यार्थी मित्र योजना को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया और राज्य सरकार को विद्यार्थी मित्रों को न चाहते हुए भी कानूनी व्यवस्था न्याय व्यवस्था के मजबूरन, हम सबकी सहानुभूति है, हम सब चाहते हैं, हम संवेदनशील हैं, हमारी सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं, आप और हम सबकी भावनाएं एक हैं लेकिन इस न्यायिक प्रक्रिया के कारण हम उनको आगे नहीं रख पाए। इसके समायोजन के लिए हमने शिक्षा सहायक सेवा नियम बनाए। उसमें आप लोगों ने 10, 20, 30 बोनस अंकों का जो प्रावधान किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको भी खारिज करके अधिकतम 15 अंक बोनस के रखे। उक्त निर्णय की पालना में हमने शिक्षा सहायक भर्ती को अधिकतम बोनस अंक 15 तक सीमित रखते हुए उसमें भी लगा कि अधिकतम विद्यार्थी मित्रों का चयन नहीं हो सकता। फिर इसके लिए माननीय कटारियाजी की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप समिति बनी, इन जटिलताओं को देखते हुए हमने शिक्षा सहायक भर्ती, 2013 को निरस्त किया और विद्यालय सहायक का नया संवर्ग गठित करने का हमने निर्णय लिया। मंत्रिमंडल उप समिति के अनुसार हमने 33493 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की। एक दूसरे पर आरोप लगाना बहुत सरल है पर आप चाहे इधर बैठ जाओ चाहे उधर बैठ जाओ, निर्णय करते समय आपको लीगीलटी को पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो पहले की तरह कोई भी कोर्ट चला गया तो वह वहीं के वहीं रहेंगे और हश्र भी यही हुआ कि 33493 की जो पोस्टें हैं, जो हमने विज्ञप्ति जारी की, आवेदन आ गए लगभग 7 लाख के आसपास आवेदन आये, एक्जेक्ट संख्या याद नहीं है लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए। हमने तो इन विद्यार्थी मित्रों को एडजस्ट करने के लिए उसमें लिखा, सरकारी स्कूलों में

(श्री वासुदेव देवनानी)

जिन्होंने पढ़ाया है उनको ही हम 5, 10, 15 अंकों के अनुभव का लाभ देंगे। कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, यह असंवैधानिक है आपको प्राइवेट स्कूलों को भी देना होगा। उसके बाद आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि जो एनजीओ हैं, उनके भी लोगों को देना पड़ेगा और उसमें तो सारे विद्यार्थी मित्र दो-तीन हजार के अलावा सबने दे दिया। इसलिए हम एसएलपी में गए हैं। हम इन्तजार कर रहे हैं कोर्ट का लेकिन आपकी भावनाओं के अनुसार हम भी इनके जो चल रहा है, हम कोई न कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं, राठौड़ साहब और हमारे युनुस खानजी, हम सब समिति के सदस्य हैं, हमने बैठकर विचार किया, इनको भी कहा कि आपका भी कोई वकील हो, हमारे एजी के साथ बैठो, अपन मिलकर समाधान निकालें ताकि आप लोगों को नियुक्ति देने का हमारे मन में है, हम देना चाहते हैं लेकिन कानूनी अमली जामा तो इसको पहनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ मार्ग हम सोच रहे हैं और जैसे ही वह फलीभूत होगा, विश्वास रखिये कि सरकार विद्यार्थी मित्रों के प्रति संवेदनशील है, इतना ही मैं कह सकता हूं।

दूसरा आपने 2012 वाला विषय उठाया। 2012 में आपने तृतीय श्रेणी के अन्दर 37317 पदों पर नियुक्ति प्रदान की। इन नियुक्तियों में यह नियुक्तियां पंचायती राज अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत हुई उसमें आरटेट के 20 प्रतिशत और जिला परिषद द्वारा 80 प्रतिशत जोड़कर वरीयता बनती थी। जो रीट की परीक्षा कहते हैं न कि कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले दो परीक्षाएं होती थी, पहली एक आरटेट की होती थी फिर जिला परिषद लेती थी अब दोनों को मिलाकर हमने एक परीक्षा की है, भाइयों, कुछ जानों, रीट और दोनों परीक्षाओं में अंतर है। यह रीट रिपीटेशन, कई बार मैं राजनेताओं के भाषणों के बारे में पढ़ता हूं, यह अलग है, रीट एक ही परीक्षा है, इसमें आपने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, इसमें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में 60 प्रतिशत में 10, 15 और 20 प्रतिशत छूट दी थी जिसको माननीय उच्च न्यायालय में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में जो छूट दी थी उसको अपास्त कर दिया। अब सरकार के सामने संकट आ गया। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेटसको का आदेश दिया गया है। वर्तमान में उक्त एसएलपी विचाराधीन है, इसकी पहली पेशी 29 फरवरी को भी होने

(श्री वासुदेव देवनानी)

वाली थी, उस दिन नहीं हो पाई, फिर 16 मार्च को थी, कांस्टीट्यूशन से सम्बन्धित कोई टीम का गठन है इससे वो जज फ्री नहीं हो पाए। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, हमने हमारे वकील को कहा है कि अच्छी पैरवी करके इन बच्चों को आप राहत दिला दें और इसके कारण से जो फर्क पड़ रहा है, इसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व में चयनित लगभग 13339 अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित होता है। 2012 में जिला परिषद भर्ती परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है...(व्यवधान) वह भी उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार परिवर्तित हो गई है जिसके कारण 37317 अभ्यर्थियों में भी उनका चयन प्रभावित हो सकता है। इसलिए 2012 में स्थायी करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने एक पृथक याचिका में आदेश दिया है परन्तु प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेटसक्को के कारण प्रोब्लम है इसके लिए दो-तीन बार हम लोग भी बैठे हैं, उसका हल निकालने की कोशिश की है और हमने तय किया है कि हमारे दोनों पंचायती राज विभाग और हमारा सेक्रेटरी दिल्ली जाएंगे वहां हमारा जो वकील है, सुप्रीम अथोरिटी, उससे राय लेंगे, यदि उसने राय दे दी तो इसमें निश्चित रूप से हम कदम आगे बढ़ाएंगे लेकिन जो कुछ करेंगे वह न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से करेंगे। आप और हम इस मुद्दे पर एक है। यहां पर भले ही बोलें, आप कहें कि करना चाहिए लेकिन आप विधि तो बताओ, हम करने को तैयार हैं, हमारे कहीं भी मन में नहीं है कि हम तैयार नहीं हों। (व्यवधान)

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): जब यह स्थिति आपको पता थी तो हमारी सरकार पर बार-बार आरोप क्यों लगाते थे कि कोर्टों में छोड़ दिया, अटका दिया, गहलोत सरकार ने यह कर दिया। जब आपको विधि पता ही नहीं थी तो उन लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया? उनको क्यों बहलाया कि हम कर देंगे, हम कर देंगे।

**श्री वासुदेव देवनानी** (राज्य मंत्री, शिक्षा): ...(व्यवधान) सुनिए। किसी ने भी नहीं कहा कि हम कर देंगे। (व्यवधान) हमने जो कहा उन शब्दों को भी रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा था कि इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे और आज भी हम कमिटेड हैं इनकी समस्याओं का हम निस्तारण निश्चित रूप से करके रहेंगे इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

(श्री वासुदेव देवनानी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 24, शिक्षा, कला, संस्कृति को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष:** Are you sure, you have finished? (व्यवधान)

## मांग संख्या 24 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 209,22,23,63,000 (दो सौ नौ अरब बाइस करोड़ तेईस लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 23.10 बजे शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 2016 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)**

# अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

## प्रदेश में व्यक्तिगत लाभ के कार्य की योजना "अपना खेत अपना काम" में पात्रता का निर्धारण

253. **श्री मानवेन्द्रसिंह** (शिव) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मनरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" के तहत करवाये जाने हेतु कोई पात्रता निर्धारित है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भारत सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में लघु/सीमान्त काश्तकारों की परिभाषा को समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भारत सरकार के द्वारा उक्त नोर्म्स समाप्त करने के पश्चात् मनरेगा योजना के व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" में भी लघु/सीमान्त की परिभाषा को समाप्त कर उक्त काश्तकारों को भी व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा 5 में पात्रता निर्धारित है। अनुसूची-1 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 5 में वर्णित पात्र काश्तकार परिवारों को ही यह लाभ दिया जा सकता है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 में "कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम 2008" के अनुसार परिभाषित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में संशोधन के उपरान्त ही कार्यवाही की जा सकती है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

# सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

## डूंगरपुर जिले में कृषकों को कृषि यंत्रों पर दिया गया अनुदान

**258. श्रीमती अनिता कटारा** (सागवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कृषकों को किन-किन कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डूंगरपुर जिले में गत 5 वर्षों में कृषकों को किन-किन कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खेती के काम आने वाले कृषि यंत्रों एवं उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है। योजनावार एवं श्रेणीवार कृषि यंत्रों पर देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) डूंगरपुर जिले में गत 5 वर्षों में अनुदान पर वितरित किये गये कृषि यंत्रों एवं उपकरणों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में श्रमिकों के विवाह सहायता के लम्बित प्रकरण

**259. श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 31 जनवरी, 2016 तक श्रमिकों हेतु विवाह सहायता के अन्तर्गत किन-किन जिलों में कितने-कितने एवं कौन-कौनसे श्रमिकों को कितनी-कितनी सहायता राशि का भुगतान किया गया। संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 31 दिसम्बर, 2015 तक सरकार द्वारा दिये आदेशों की पालनार्थ अधिकांश लम्बित विवाह सहायता प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है?

(3) 1 जुलाई, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक विवाह सहायता प्रकरणों में से कुल कितने-कितने प्रकरण किस-किस श्रम कार्यालय में निस्तारित किये गये?

(4) क्या यह सही है कि विवाह सहायता प्रकरणों में वरीयता के स्थान पर अन्य को विवाह सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जिससे लम्बित आवेदनों का निस्तारण नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) 1 अप्रैल, 2009 से 31 जनवरी, 2016 तक कुल कितने आवेदन सरकार को आनलाइन/आफलाइन विवाह सहायता हेतु प्राप्त हुये? उक्त आवेदन पत्रों में से कितनों को किन-किन कारणों से निरस्त किया गया है, कितने लम्बित हैं तथा कितनों को सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना दिनांक 1 अगस्त, 2011 से प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत रुपये 51,000/- विवाह सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। उक्त योजना में प्रारम्भ से 31.1.2016 तक विभिन्न जिलों में 21367 श्रमिक लाभान्वित किए गए। लाभान्वित हिताधिकारियों का संख्या विवरण संलग्नक-"क" प्रस्तुत है।

(2) जी हां। योजनाओं के लम्बित आवेदनों के निस्तारण के लिए दिए गए आदेशों की पालनार्थ लम्बित विवाह सहायता प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया है।

(3) 1 जुलाई, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक श्रम कार्यालयों में विवाह सहायता योजना के निस्तारित किए गए प्रकरणों का जिला/कार्यालयवार विवरण अनुलग्नक-"ख" प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। विवाह सहायता योजना के प्रकरणों का निस्तारण वरीयता तथा आवेदनों के भौतिक सत्यापन होने के क्रम के आधार पर किया गया है।

(5) विवाह सहायता योजना के प्रारम्भ से अब तक प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त तथा लम्बित आवेदनों का जिला/कार्यालयवार संख्या विवरण संलग्नक-"ग" प्रस्तुत है।

आवेदनों को निरस्त करने का कारण योजना के लिए निर्धारित मापदण्ड या शर्तों को पूरा नहीं करना अथवा भौतिक सत्यापन में निर्माण श्रमिक नहीं होना पाया जाना है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में स्वच्छ परियोजना में स्वीकृत कार्य

**260. श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में स्वच्छ परियोजना द्वारा कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत से कहां-कहां पर स्वीकृत किये गये?

(2) उक्त क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में स्वच्छ परियोजना में स्वीकृत किये गये कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण, कौन से प्रगति पर व कौन-कौन से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में 29 मां-बाड़ी भवन स्वीकृत किये गये। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, जिसमें प्रति मां-बाड़ी हेतु राशि रुपये 6 लाख 60 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए परन्तु तकनीकी तखमीने अनुसार 4 लाख 80 हजार में निर्माण कराया जा रहा है।

वर्ष 2013-14 में 7 छात्रावासों में शौचालय निर्माण एवं 7 छात्रावासों में मरम्मत कार्य स्वीकृत किये गये। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

वर्ष 2014-15 में 3 छात्रावासो में मरम्मत कार्य स्वीकृत किये गये। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) बारां जिले में शाहाबाद-किशनगंज क्षेत्र में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत कार्यों का पूर्ण/प्रगति पर एवं अपूर्ण का विवरण परिशिष्ट 4, 5 व 6 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में नवसृजित पंचायत समितियां

**261. श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् प्रदेश में कितनी पंचायत समितियां कहां-कहां नवसृजित की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू में नया पंचायत समिति कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् राज्य में 47 पंचायत समितियां नवसृजित की गई हैं। नवसृजित पंचायत समितियों का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2014 में ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव जनवरी, फरवरी-2015 में ही सम्पन्न करवाये गये है। अत: पीपलू में अभी नया पंचायत समिति कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जोधपुर में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए अतिरिक्त सी.ई.टी.पी. की स्थापना

262. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी, 2010 को सर्वाधिक औद्योगिक प्रदूषित क्षेत्रों के सूचकांक में शामिल होने पर इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही रीको ने यह फैसला लिया है कि प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी औद्योगिक संगठनों द्वारा संभाली जाएगी? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रदूषण के रोकथाम की जिम्मेवारी भी रीको को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जोधपुर में औद्योगिक प्रदूषण के मद्देनजर एक अतिरिक्त सी.ई.टी.पी. स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी, 2010 को सर्वाधिक औद्योगिक प्रदूषित क्षेत्रों के सूचकांक में शामिल क्षेत्रों में होने के कारण जोधपुर में प्रूदषण की रोकथाम हेतु पी.डी. कोर द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना रिपोर्ट तैयार करवायी गयी थी। उक्त परियोजना रिपोर्ट राजस्थान राज्य

(उद्योग मंत्री)

प्रदूषण मण्डल द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमोदनार्थ भेजी गई थी।

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जोधपुर क्षेत्र में प्रदूषण की रोकथाम के लिए विभिन्न विभाग यथा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस यातायात नियंत्रण विभाग, वन विभाग, जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट, जोधपुर के औद्योगिक संगठनों, रीको, उद्योग विभाग, जिला आपूर्ति अधिकारी, आर.यू.आई.डी.पी., सिंचाई विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आयुक्त, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.02.2012 को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक (राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 के कार्यान्वयन के लिए घटित कार्यकारी समूह की बैठक) में परियोजना रिपोर्ट की पी.डी. कोर के द्वारा प्रस्तुतिकरण के पश्चात यह निर्णय लिया गया था कि औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयासों पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का वहन सम्बन्धित क्षेत्रों के औद्योगिक संगठनों द्वारा ही वहन किया जायेगा की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य में प्रदूषण की रोकथाम हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया हुआ है एवं उनके द्वारा ही उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986, जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य में स्थित विभिन्न उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए औद्योगिक इकाइयों को स्थापना व संचालन की सम्मति जारी करता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के दौरान स्थापना व संचालन की सम्मति में प्रदूषण रोकथाम के लिए अधिरोपित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाती है। दोषी पाये जाने वाले उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी रीको को देने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जोधपुर में औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्सृजित की जा रही

(उद्योग मंत्री)

उच्छिष्ठ को उपचारित करने हेतु वर्तमान में 20 एम.एल.डी. क्षमता की उपचार संयंत्र औद्योगिक क्षेत्र सांगरिया में कार्यरत है। जिसका संचालन जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त जोधपुर में औद्योगिक प्रदूषण को देखते हुए वर्तमान में संचालित उपचार संयंत्र की क्षमता बढ़ाने तथा एक अतिरिक्त सीईटीपी की स्थापना की आवश्यकता है।

वर्तमान में स्थापित सीईटीपी के क्षमता 20 एमएलडी से बढ़ाकर 30 एमएलडी करने हेतु जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट को 10 बीघा भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने हेतु रीको द्वारा सैद्धान्तिक निर्णय लिया जा चुका है तथा निर्णय का आशय पत्र दिनांक 29.01.2016 जारी किया गया है। (परिशिष्ट-ब पर संलग्न है)

नये सीईटीपी की स्थापना के लिए भूमि आबंटन हेतु इच्छुक नवगठित मारवाड़ प्रदूषण निवारण कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए निगम द्वारा मारवाड़ प्रदूषण निवारण कम्पनी लिमिटेड को प्रस्तावित परियोजना की 25 प्रतिशत लागत राशि (अनुमानित 50 करोड़) की उपलब्धता सम्भावित उद्यमी सदस्यों से सुनिश्चित कराने हेतु दिनांक 23.10.2015 को पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है। (परिशिष्ट स पर संलग्न है) उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करने के पश्चात् अतिरिक्त सीईटीपी की स्थापना हेतु भूमि 15 बीघा आबंटन की आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। (परिशिष्ट-स पर संलग्न है)

वर्तमान में स्थापित सीईटीपी के क्षमता 20 एमएलडी से बढ़ाकर 30 एमएलडी करने के लिए तथा एक नये सीईटीपी की स्थापना हेतु रीको द्वारा ग्राम सालावास तहसील लूणी की 25 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकारण को रुपये 2,56,16,244/- भुगतान कर रीको के पक्ष में दिनांक 19.02.2015 को आबंटित करवाई जाकर दिनांक 04.03.2015 को कब्जा प्राप्त किया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## किशनगढ़ बास की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की योजना

**263. श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगगढ़ बास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(1) क्या सरकार प्रदेश की जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कौन-कौनसी सड़कें जीर्ण-शीर्ण हैं? उक्त सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित अलीपुर से पुर, कलगांव, तिजारा, हरसौली से खैरथल, विजयमंदिर, कोटकासिम से कतोपुर, बूढीबावल, हरसौली से बासकृपाल नगर, मोठूका, बाघौड़ा, मुबारिकपुर, कोटकासिम से लाड़पुर, तिजारा तक सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि किशनगढ़ बास मुख्यालय से वाया कोटकासिम हरियाणा सीमा तक सड़क का चौड़ाईकरण करते समय नयागांव से बीबीरानी तक की सड़क का चौड़ाईकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कर दिया जावेगा?

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गत 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं में कुल 2237 कार्य 10874.805 किमी. लम्बाई में राशि रु. 6274.44 करोड़ के स्वीकृत कर नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण एक निरन्तर सतत् प्रक्रिया है। जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जायेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में 25 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी लम्बाई 68.11 किमी. है। उक्त 25 सड़कों में से 4 सड़कों, जिनकी लम्बाई 5.300 किमी. है, आर.आई.डी.एफ.-21 योजना के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्यादेश दिया जा चुका है। शेष सड़कों का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। (विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।)

(3) अलीपुर से पुर-कलगांव-तिजारा एम.डी.आर.-197 हरसौली से खैरथल-विजयमंदिर एम.डी.आर.-198 कोटकासिम से कतोपुर-बूढीबावल स्टेट

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

हाईवे-108, हरसौली से बासकृपाल नगर-मोठूका-बाघौड़ा-मुबारिकपुर एम.डी.आर.-200 तथा कोटकासिम से लाड़पुर-तिजारा एम.डी.आर.-170 श्रेणी की सड़कें हैं। इन सड़कों की वर्तमान कैरिजवे चौड़ाई 3.00 मीटर है। इन सड़कों का चौड़ाईकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। (विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।)

(4) जी हां। किशनगढ़ बास से वाया कोटकासिम हरियाणा सीमा तक सड़क लम्बाई 33.00 किमी. है। उक्त सड़क की किमी. 0/0 से 12/0 के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सी.आर.एफ. योजना में वर्ष 2011-12 में स्वीकृत हुआ था। कार्य में निविदा दर अधिक होने के कारण 3 किमी. (9/0 किमी. से 12/0 किमी.) तक का कार्य सम्पादित नहीं करवाया जा सका। शेष रही 3.00 किमी. सड़क का चौड़ाईकरण करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। किमी. 12/0 से 33/0 (हरियाणा सीमा तक) चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य अन्तरराज्यीय सड़क योजना के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2014 को पूर्ण किया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## टोंक के गांवों को बीसलपुर योजना से पेयजल की आपूर्ति

**264. श्री अजीत सिंह** (टोंक) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि देवली, उनियारा तथा टोंक में पेयजल की समस्या को मध्यनजर रखते हुए बीसलपुर देवली उनियारा, टोंक पेयजल योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोंक के कौन-कौनसे ग्रामों को उक्त योजना से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे ग्रामों को इस पेयजल योजना से कब तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित था तथा अब तक कितने ग्रामों को लाभान्वित किया गया है? शेष ग्रामों को कब तक लाभान्वित कर दिया जायेगा? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीसलपुर बांध सतही जल स्रोत से टोंक जिले के 3 शहर क्रमश: टोंक, देवली एवं उनियारा तथा तहसील टोंक, उनियारा एवं देवली के वर्ष 2001 की जनगणनानुसार क्रमश: 106, 196 एवं 134 ग्राम, इस प्रकार कुल 436 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बीसलपुर-देवली-उनियारा-टोंक वृहद् पेयजल परियोजना की प्रथम बार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.09.2005 को राशि रुपये 85.00 करोड़, संशोधित स्वीकृति दिनांक 01.02.2007 को राशि रुपये 247.00 करोड़ एवं पुन: संशोधित स्वीकृति दिनांक 24.08.2012 को राशि रुपये 542.11 करोड़ की जारी की गई थी।

उक्त योजना के कार्यों को तीन पैकेजों में विभक्त किया जाकर प्रथम पैकेज (मुख्य ट्रांसमिशन मेन एवं आधारभूत संरचनाओं के कार्य) पर राशि रुपये 169.99 करोड़, द्वितीय पैकेज (436 ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली से जोड़ने का कार्य) पर राशि रुपये 43.54 करोड़ एवं पैकेज तृतीय (डिपोजिट मद के कार्य) पर राशि रुपये 22.01 करोड़, इस प्रकार कुल 235.54 करोड़ की राशि माह फरवरी, 2016 तक व्यय की जा चुकी है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोंक के कुल 183 राजस्व ग्रामों में तहसील टोडारायसिंह के 59 एवं तहसील टोंक के 124 ग्राम सम्मिलित हैं। तहसील टोडारायसिंह के 59 ग्राम बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत वर्ष 2014 तक लाभान्वित हो चुके हैं। तहसील टोंक के 124 ग्रामों में से 106 ग्राम बीसलपुर-देवली-उनियारा-टोंक वृहद् पेयजल परियोजना में तथा 8 ग्राम बीसलपुर-टोंक-निवाई की दिनांक 24.08.2012 को राशि रुपये 112.88 करोड़ की स्वीकृत परियोजना में सम्मिलित हैं। शेष 10 ग्रामों को बीसलपुर-टोंक-निवाई परियोजना से जोड़ने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत कराकर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

बीसलपुर-देवली-उनियारा-टोंक वृहत् पेयजल परियोजना से विधान सभा क्षेत्र, टोंक की तहसील टोंक के कुल 106 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा दिनांक 31.08.2017 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है। ग्रामवार वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार। बीसलपुर-देवली-उनियारा-टोंक वृहत् पेयजल परियोजना में विधान सभा क्षेत्र, टोंक की तहसील टोंक के 106 ग्रामों सहित

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सम्मिलित टोंक जिले के उक्त 3 शहर एवं 436 ग्रामों को कार्यादेश अनुसार दिनांक 03.08.2016 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है परन्तु आदेशित दो फर्मों द्वारा कार्य धीमी गति से किये जाने के कारण सम्पूर्ण परियोजना दिनांक 31.08.2017 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है। टोंक तहसील के 106 ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है। इनमें से कोई भी ग्राम वर्तमान में लाभान्वित नहीं हुआ है।

परियोजना के प्रथम पैकेज (मुख्य ट्रांसमिशन मेन एवं आधारभूत संरचनाओं के कार्य) एवं द्वितीय पैकेज (436 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली से जोड़ने का कार्य) का कार्य आदेशित दो फर्मों द्वारा धीमी गति से किये जाने के कारण प्रथम एवं द्वितीय पैकेजों के अन्तर्गत विभाग द्वारा फर्मों से अब तक क्रमशः रुपये 3.29 करोड़ एवं 3.68 करोड़, इस प्रकार कुल रुपये 6.97 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि रोकी गई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## रोहट (पाली) में गैर आबादी भूमि का आबादी में परिवर्तन

265. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले की रोहट तहसील के किस-किस गांव में कितनी-कितनी अवधि से कौन-कौन से परिवार गैर आबादी भूमि पर निवास कर रहे हैं?

(2) उक्त गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने हेतु कौन-कौनसा प्रकरण कितनी-कितनी अवधि से किस-किस स्तर पर लम्बित है?

(3) इनमें से किस-किस भूमि पर सरकारी सुविधा विद्युत, पेयजल हेतु जी.एल.आर. विद्यालय सड़क या अन्य सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन प्रकरणों का परीक्षण करवाकर उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) पाली जिले के रोहट तहसील के 48 ग्रामों में कुल 970 परिवार गैर आबादी भूमि पर काबिज हैं, जिनकी सूची प्रपत्र-क में संलग्न है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) उक्त गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने हेतु कुल 6 प्रकरण लम्बित हैं, जिनकी सूची प्रपत्र-ख में संलग्न है।

(3) उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 में वर्णित तहसील क्षेत्र रोहट में गैर आबादी भूमि पर काबिज परिवारों में से 5 ग्रामों में (ग्राम चाटेलाव, निम्बली ब्राह्मणान, डूंगरपुर, सोनाईलाखा) बिजली जो वि.वि.एन.एल. द्वारा एवं पानी के जी.एल.आर. ग्राम सोनाईलाखा व निम्बली ब्राह्मणान में पी.एच.डी. विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, जिसकी सूचना प्रपत्र-ग में संलग्न है।

(4) नियमानुसार समस्त कमी-पूर्ति पूर्ण होने एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर आबंटन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## चित्तौड़गढ़ जिले के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

**266. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'** (चित्तौड़गढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों के कितने-कितने पद किस-किस स्तर के सृजित हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में स्वीकृत पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा अधिकारियों व अन्य चिकित्सा कर्मियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों को उपलब्धता एवं प्राथमिकता अनुसार भरा जाता है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## डूंगला (चित्तौड़गढ़) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

**267. श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपखण्ड मुख्यालय डूंगला (जिला-चित्तौड़गढ़) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

जी हां। प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। (संलग्न परिशिष्ट-1), क्रम संख्या 17 पर डूंगला (जिला-चित्तौड़गढ़) में आई.टी.आई. खोलने हेतु स्वीकृति जारी की गई है। भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (संलग्न परिशिष्ट-2), भूमि आवंटन पश्चात भवन निर्माण किया जाना है। तत्पश्चात आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पोहरी खातुरात (डूंगरपुर) में बालिका छात्रावास खोलने की योजना

**268. श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायत पोहरी खातुरात में बालिका एवं बालक छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उपखण्ड सीमलवाड़ा में खेल छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्तमान में पोहरी खातुरात में नये छात्रावास स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) क्षेत्रीय आवश्यकता, बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर खेल छात्रावास खोलने पर विचार किया जावेगा।

## कोटा जिले में विधायक अनुशंसित कार्यों में विलम्ब पर कार्यवाही

**269. श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधायक स्थानीय विकास कोष के अन्तर्गत विधायकों द्वारा अनुशंसित कार्यों की अनुशंसा करने के उपरान्त प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति, कार्य की एन.आई.टी. जारी करने, कार्यादेश जारी करने, कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो किस-किस प्रक्रिया के लिए कितनी-कितनी? सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा जिले में विगत 2 वर्षों में कब-कब, किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि की अनुशंसा विधायक कोष से की गई? उक्त अनुशंसाओं पर कब-कब प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं एवं किन-किन संस्थाओं को कार्य एजेन्सी बनाया गया? विधायक अनुशंसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने के उपरान्त कब-कब कार्य के लिए एन.आई.टी. जारी की गई? कब-कब कार्यादेश जारी किए गए? वर्तमान में प्रत्येक कार्य की क्या-क्या प्रगति है? उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे? विधायकवार, अनुशंसावार, कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वित्तीय स्वीकृतियां जारी होने के बाद भी कौन-कौन से कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए अथवा निर्धारित समय के बजाय विलम्ब से प्रारम्भ किए गए? क्या सरकार कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं कराने के लिए दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के अनुच्छेद 22.0 के अनुसार माननीय विधायक महोदयों द्वारा अनुशंसा करने के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति 10 दिन, तकनीकी स्वीकृति के जारी होने के 25 दिन तक तथा वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त अधिकतम 10 दिन में जारी हो जानी चाहिए।

एनआईटी जारी करने, कार्यादेश जारी करने सम्बन्धी समय सीमा, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग कार्यकारी संस्था होने की स्थिति में पंचायती राज विभाग के नियमों एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के

(ग्रामीण विकास मंत्री)

अनुरूप होंगें। इसी प्रकार कार्यकारी संस्था लाइन विभाग होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग के नियमों के अनुरूप होंगें।

ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के अनुच्छेद 22.10 के अनुसार कार्य सम्पादित करने की अवधि परिशिष्ट-अ में दर्शायी गई है।

(2) कोटा जिले में विगत दो वर्षों में माननीय विधायक महोदयों द्वारा की गई अनुशंसाओं का विवरण परिशिष्ट-ब में संलग्न है।

माननीय विधायक महोदयों द्वारा जिन कार्यों में ग्राम पंचायतों को कार्यकारी संस्था बनाया गया था, उनमें कार्य एनआईटी के माध्यम से नहीं कराये गये। कार्यों की प्रगति विवरण परिशिष्ट-ब में दर्शाया गया है।

(3) जिन कार्यों में कार्यकारी संस्था अन्य विभाग बनाये गये हैं, उनकी एनआईटी जारी करने की तिथि, कार्यादेश जारी करने की तिथि तथा प्रगति का विवरण परिशिष्ट-ब में संलग्न है।

(4) तकनीकी विभाग यथा सा.नि.वि., नगर निगम, यू.आई.टी. में वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात टेण्डर प्रक्रियां में देरी होने के फलस्वरूप कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं हो पाते हैं। उपरोक्त कारणों के अलावा यदि अन्य कारणों यथा लापरवाही, शिथिलता की प्रकरण विशेष में जानकारी प्राप्त होने पर सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश के उद्योगों द्वारा अर्जित लाभ के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी

**270. श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में बड़े एवं मझले उद्योगों की संख्या 31 मार्च, 2015 को कितनी थी, इनमें भारत की एवं बाहर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां कितनी थीं? वर्ष 2004 से 2009 तक तथा 2009 से 31 जनवरी, 2016 तक इसमें कितनी-कितनी वृद्धि हुई एवं उक्त अवधि में इन उद्योगों में कितने श्रमिकों को रोजगार मिला? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उद्योगों द्वारा मानदण्डों के अनुकूल विभिन्न श्रेणियों-अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों को रोजगार दिया गया है?

(3) क्या कार्यरत कुशल श्रमिकों/कर्मचारियों के कार्य करने की शर्तें तथा एक दिन में एक व्यक्ति से अधिकतम कितने घंटे काम लेना है, निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कुशल व दक्ष कर्मचारियों को देय वेतन/पैकेज उस उद्योग

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के अनुकूल है? क्या इस सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में बड़े एवं मंझले उद्योगों की संख्या 31 मार्च, 2015 को 503 थी, इसमें भारत की 472 एवं बाहर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां 31 थीं।

2004 से 2009 तथा 2009 से अब तक इसमें हुई वृद्धि की वर्षवार सूचना निम्नानुसार है -

| वर्ष | वृद्धि |
|---|---|
| 2003-04 | 4 |
| 2004-05 | 14 |
| 2005-06 | 8 |
| 2006-07 | 11 |
| 2007-08 | 35 |
| 2008-09 | 28 |
| 2009-10 | 28 |
| 2010-11 | 13 |
| 2011-12 | 22 |
| 2012-13 | 42 |
| 2013-14 | 24 |
| 2014-15 | 26 |
| 2015-16 (जनवरी, 2016 तक) | 17 |

उक्त अवधि के दौरान 219343 श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ, का वर्षवार संख्या विवरण निम्नानुसार है

| वर्ष | वृद्धि |
|---|---|
| 2003-04 | 864 |
| 2004-05 | 1495 |
| 2005-06 | 5571 |
| 2006-07 | 1620 |
| 2007-08 | 9796 |
| 2008-09 | 15103 |

(उद्योग मंत्री)

| वर्ष | वृद्धि |
|---|---|
| 2009-10 | 2653 |
| 2010-11 | 11029 |
| 2011-12 | 4956 |
| 2012-13 | 9579 |
| 2013-14 | 4952 |
| 2014-15 | 5457 |
| 2015-16 (जनवरी, 2016 तक) | 2563 |

(2) अकुशल अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के रोजगार देने के कोई मापदण्ड उद्योग विभाग स्तर पर निर्धारित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान निवेश प्रोजेक्ट योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदित नई इकाइयों को दस व्यक्तियों को रोजगार तथा विस्तार एवं विविधिकरण करने वाली इकाइयों को पूर्व नियोजित कार्मिकों का 25 प्रतिशत अतिरिक्त नियोजन करने का प्रावधान है।

(3) भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-54 के अन्तर्गत कोई व्यस्क कर्मकार किसी कारखाने में 9 घण्टे से अधिक काम के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा तथा धारा-59 के अन्तर्गत अतिकाल (ओवरटाइम) की मजदूरी की गणना हेतु एक सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करने की दशा में अतिकाल कार्य करने के लिए निर्धारित मजदूरी से दोगुनी दर से मजदूरी पाने हकदार होगा। प्रावधनों की प्रति परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(4) इस सम्बन्ध में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## खेतड़ी की ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण

271. **श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में ओ.डी.आर. सड़कों की कुल लम्बाई 26.00 किमी. है जिसके पुनर्निर्माण वास्ते राशि रु. 468.00 लाख की आवश्यकता होगी तथा ग्रामीण सड़कों की कुल लम्बाई 59.400 किमी. है,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जिनके पुनर्निर्माण के लिये राशि रु. 1067.20 लाख की आवश्यकता होगी। विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर प्रस्तुत है। उपरोक्त में से 8.00 किमी. लम्बाई की सड़कों का नवीनीकरण के लिये कुल राशि रु. 142.00 लाख की स्वीकृति की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट-2 के क्रम संख्या 19 व 20 पर अंकित है। शेष 77.40 किमी. लम्बाई के पुनर्निर्माण हेतु राशि रु. 1393.20 लाख की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में डार्क जोन घोषित करने के मानदण्ड

**272. श्री श्रीराम भींचर** (मकराना) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में डार्क जोन घोषित करने हेतु क्या-क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? गत 5 वर्षों में कब-कब किस-किस स्तर की बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई एवं किस-किस क्षेत्र को डार्क जोन से निकाला गया एवं किस-किस क्षेत्र को नया डार्क जोन घोषित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में प्रदेश में किस-किस जिले में भू-जल का स्तर क्या रहा? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में भू-जल स्तर नीचे आने के कारण डार्क जोन क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होने के कारण किसानों को कृषि कार्य हेतु दिये जा रहे अनुदान एवं सहायता से वंचित होना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों की उक्त समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्य योजना बनाई जा रही है? प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में किसी भी क्षेत्र के श्रेणी निर्धारण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा गठित भू-जल आकलन समिति-1997 के निर्देशानुसार किया जाता है। वर्तमान में इस गाइड लाइन के आधार पर भू-जल विकास स्तर के प्रतिशत को दर्शाने के लिए निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :-

सुरक्षित (Safe)-जहां भू-जल विकास स्तर 70 प्रतिशत से कम हो, अर्धसंवेदनशील (Semi Critical)- जहां भू-जल विकास स्तर 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत हो, संवेदनशील (Critical)- जहां भू-जल विकास स्तर 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत हो, एवं अति दोहित (Over-exploited) जहां भू-जल विकास स्तर 100 प्रतिशत से अधिक हो अर्थात भू-जल का दोहन भूजल रिचार्ज से अधिक हो रहा है। इसके साथ ही भू-जल स्तर की दीर्घकालीन स्थिति को भी मद्देनजर

(भू-जल मंत्री)

रखा जाता है। संवेदनशील एवं अति दोहित श्रेणी मे वर्कीकृत श्रेणियों को डार्क जोन मे सम्मिलित किया जाता है।

इस हेतु राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 05.04.2013 को प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभि. एवं भूजल विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आहुत की गई तत्पश्चात् उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन केन्द्र के स्तर पर किया गया। राज्य स्तर पर वर्ष 2009 एवं वर्ष 2011 में भूजल आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। भूजल आकलन रिपोर्ट वर्ष 2009 की तुलना में 2011 में जिन अतिदोहित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में परिवर्तन पाया गया है उसकी सूची संलग्न है। (Annex. 1)

(2) वर्ष 2011 से 2015 तक के जिलेवार औसत भूजल स्तर के आंकड़ों की सूची संलग्न है। (Annex. 2)

(3) जी हां। लगातार भू-जल दोहन में बढ़ोतरी होने के कारण भू-जल स्तर नीचे जा रहा है तथा डार्क जोन क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होने पर कृषि विभाग द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार सहायता दी जाती है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु -

(i) प्रदेश में जल संरक्षण हेतु राज्य जल नीति माह फरवरी 2010 में लागू कर दी गई है जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित करना राजस्थान जल नीति 2010 में शामिल किया गया है।

(ii) भू-जल मितव्यता हेतु लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।

(iii) भू-जल दोहन पर नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर गम्भीर स्थिति वाले क्षेत्रों को अधिसूचित घोषित किया जाता है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(1)पी.एच.ई./2010-पार्ट-प्रथम दिनांक 14.7.2011 के द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर को उस जिले में नये नलकूप/ बोरवेल/भूजल दोहन की यूनिट खोदने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम एवं नियन्त्रक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। (Annex.-3)

(iv) महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत भू-जल पुनर्भरण हेतु संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## उप तहसील बज्जू (बीकानेर) का तहसील में क्रमोन्नयन

273. **श्री भंवरसिंह** (कोलायत) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1, 2 व 3 का दिनांक 31 अगस्त, 2015 को राजस्व विभाग में विलय कर दिया गया है? जिससे राजस्व तहसील कोलायत का क्षेत्राधिकार प्रदेश की अन्य तहसीलों के क्षेत्राधिकार से दोगुना हो गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में 50 किमी की दूरी पर स्थित उप तहसीलों को पूर्ण तहसीलों का दर्जा दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उप-तहसील बज्जू को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत का कार्य क्षेत्र बीकानेर जिले के अन्य उपखण्ड कार्यालयों से दोगुना है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार बज्जू में उपखण्ड अधिकारी का पद स्वीकृत कर कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उपनिवेशन तहसील कोलायत नं. 1, 2 व 3 का दिनांक 31.08.15 को राजस्व विभाग में विलय कर दिया गया है। कुल 661 चक/ग्रामों (635 चक व 26 ग्राम) का क्षेत्रफल सम्मिलित होने से राजस्व तहसील कोलायत का भौगोलिक क्षेत्रफल बढ़ा है।

(2) मा. मुख्यमंत्री महो. द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई बजट घोषणा संख्या 196 के अनुसार राज्य में तहसीलों को पंचायत समितियों के सह सीमान्त क्षेत्राधिकार कर समान मुख्यालय कायम किये जाने के क्रम में पुनर्गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोंपरान्त उप तहसील बज्जू को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में जनहित एवं प्रशासनिक हित में उचित निर्णय लिया जावेगा।

(3) जी हां। उपनिवेशन क्षेत्र के विलय होने से भौगोलिक दृष्टि से अन्य उपखण्ड कार्यालयों की बजाय उपखण्ड कोलायत का कार्यक्षेत्र बड़ा हो गया है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव राज्य स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

## प्रदेश में दुधारू पशुओं की खरीद हेतु ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना

274. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में प्राथमिक दुग्ध समितियों के माध्यम से दुधारू पशुओं की खरीद हेतु पशुपालकों को 1 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है?

(2) क्या सरकार प्रदेश के पशुपालकों को दुधारू पशुओं की खरीद हेतु 1 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विकास नीति तैयार की जाकर पशुपालकों के रोजगार के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उपाय किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस हेतु सरकार की कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्राथमिक दुग्ध समितियों के माध्यम से दुधारू पशुओं की खरीद हेतु पशुपालकों को 1 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने हेतु आरसीडीएफ स्तर पर परियोजना प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। पशुपालन एवं डेयरी विकास नीति के अन्तर्गत प्राथमिक दुग्ध समितियों के माध्यम से दुधारू पशुओं की खरीद हेतु पशुपालकों को रुपये 1 लाख ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने हेतु आरसीडीएफ स्तर पर परियोजना प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जिससे पशुपालकों को रोजगार उपलब्ध होगा एवं उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी सम्भव हो सकेगा।

## सीकर जिले में श्रम कल्याण की योजनाओं के लम्बित आवेदन

275. **श्री गोरधन** (धोद) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण की कौन-कौनसी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा उक्त योजना की पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले में कौन-कौनसी योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2013 से 31 जनवरी, 2016 तक कितने व्यक्तियों के आवेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं

(श्री गोरधन)
व कितने व्यक्ति लाभान्वित हुये तथा कितने शेष हैं? शेष निस्तारण सरकार द्वारा कब तक कर दिया जायेगा? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) श्रम विभाग के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा संचालित योजनाओं की पात्रता व शर्तें एवं आवेदन की प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) सूचनाओं का संधारण जिलेवार किया जाता है, विधान सभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता है। सीकर जिले में मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 31 जनवरी, 2016 तक प्राप्त लाभान्वित तथा शेष आवेदनों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है। शेष आवेदनों का निस्तारण शीघ्र किया जाएगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## डूंगरपुर-आसपुर में विकास की योजनाएं

**276. श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है प्रदेश में विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर व आसपुर वर्तमान में आर्थिक एवं रोजगार तथा कृषि क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर व आसपुर में आर्थिक एवं रोजगार तथा कृषि क्षेत्र में विकास कार्य कराये जा रहे हैं। जनजाति क्षेत्रों में विकास करने हेतु प्रत्येक विभाग अपनी वार्षिक योजना का 13 प्रतिशत राशि का प्रावधान कर, व्यय करता है। इसमें आर्थिक विकास, रोजगार एवं कृषि क्षेत्र का विकास भी शामिल है। इसके साथ ही जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इन विधान सभा क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रम संचालित करता है। इन कार्यक्रमों में कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, मत्स्य पालन, स्वरोजगार हेतु अनुदान इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा सामान्य क्षेत्र के मुकाबले मापदण्डों को शिथिल कर सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत है।

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## मावली में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की योजना

340. **श्री दलीचन्द डांगी** (मावली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मां-बाड़ी केन्द्र खोलने के क्या नियम हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में कितने ग्राम, ढाणियों व कस्बों में मां-बाड़ी केन्द्र संचालित हैं?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मावली में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति बाहुल्य ऐसे ढाणियां/फले जहां निवासरत जनजाति के बालक/बालिकाएं जो आयु वर्ग 6 से 12 वर्ष के हैं, जिस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा हेतु 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना होता है। उसी जगह प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रों का चयन किया जाता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बालक/बालिकाएं जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं ऐसी ढाणियां/फले को मां-बाड़ी केन्द्र संचालित कर शिक्षा से जोड़ना है एवं समुदाय की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता सम्बंधी जागरूकता पैदा करना।

बजट की उपलब्धता व केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

(2) वर्तमान में विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र मावली में कोई भी मां-बाड़ी केन्द्र संचालित नहीं किया जा रहा है।

(3) मावली विधान सभा क्षेत्र में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र क्षेत्रीय मांग एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर खोलने पर विचार किया जावेगा।

## उदयपुर ग्रामीण में माडा योजनान्तर्गत आबंटित राशि

341. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री फूलसिंह मीणा)

(1) प्रदेश में माडा योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृति के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 से अब तक विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में किस-किस ग्राम पंचायत से कितनी-कितनी राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुये व कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायतवार आबंटित की गई तथा आबंटित राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत क्या-क्या कार्य करवाये जा सकते हैं तथा उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें उक्त योजना के तहत आती हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माडा क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य की स्वीकृति के लिये सम्बन्धित गांव का माडा क्षेत्र में चयनित होना आवश्यक है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत संचालित योजनाओं में राशि की उपलब्धता एवं योजनाओं की गाइड लाइन अनुसार अनुमत होने पर 5.00 लाख रु. तक की राशि के कार्य जिला स्तर पर एवं इससे अधिक राशि के कार्य राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात स्वीकृत किये जाते है। सम्बन्धित आदेश की प्रति परिशिष्ट -अ पर संलग्न है।

(2) माडा क्षेत्र हेतु उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से अब तक स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जिलों को राशि का आबंटन विधान सभा क्षेत्र अथवा ग्राम पंचायतवार नहीं किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के माडा क्षेत्र में प्राप्त अन्य प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) माडा क्षेत्र में विभाग द्वारा विभिन्न मदों में संचालित योजनाओं की सूची परिशिष्ट- द पर संलग्न है।

विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में माडा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों/ गांवों की सूची परिशिष्ट- य पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में गौ विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना

342. **श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपने नीति पत्र में पंचगव्य शोध, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण, गौ पालन एव गौ आधारित चिकित्सा व खेती आदि विषयों पर शोध, क्रियान्वयन एवं बढ़ावा प्रदान करने के लिये कामधेनु विश्वविद्यालय अथवा गौ विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उल्लेख किया गया है?

(2) क्या सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप प्रदेश में गौ विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) पंचगव्य शोध, गौसंवर्धन, गौसंरक्षण, गौपालन एवं गौ आधारित चिकित्सा खेती आदि विषयों पर गौ केन्द्रित व्यवस्थाओं के शोध एवं क्रियान्वयन हेतु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीन एक पृथक विंग की स्थापना किये जाने का निर्णय हुआ है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्मों के बीजों का वितरण

343. **श्री खेमाराम** (सुजानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्मों के बीजों का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में चूरू जिले में वितरित बीजों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वितरण किये जाने हेतु तहसील स्तर पर कितना-कितना बीज आबंटन किया जाता है तथा इसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उन्नत बीज वितरण का लाभ समस्त कृषकों को मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार समस्त कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(श्री खेमाराम)

(5) क्या उक्त वितरित बीजों के आबंटन रजिस्टर का एवं अन्य तरीके से भौतिक सत्यापन किया गया है? क्या यह सही है कि बीज कम्पनियों द्वारा बताये गये मानदण्डानुसार किसानों को उपज प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत तीन वर्षों में जिला चूरू में वितरित बीजों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य में मिनीकिट/प्रदर्शन आयोजन एवं अनुदानित दर पर सामान्य बुआई हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों का जिलेवार आबंटन कृषि आयुक्तालय स्तर से किया जाता है। तत्पश्चात् जिला स्तर पर जिला परिषद से विभिन्न योजनाओं में पंचायत समिति हेतु बीज का आबंटन, अनुमोदन एवं पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में योजनाओं के तहत बीज वितरण का अनुमोदन पंचायत समिति से कराया जाता है। बीज वितरण के मापदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(3) विभिन्न योजनाओं के तहत मिनीकिट/प्रदर्शन आयोजन हेतु बीज का वितरण आबंटित लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। अनुदानित दर पर सामान्य वितरण हेतु प्रमाणित बीज कृषक द्वारा योजना के दिशा-निर्देश एवं निर्धारित अधिकतम सीमा अनुसार केवीएसएस/जीएसएस/बीज संस्थाओं के अधिकृत विक्रेताओं से प्राप्त किया जाता है।

(4) राज्य सरकार का यह प्रयास है कि समस्त कृषकों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध हो। इस हेतु रबी एवं खरीफ सीजन से पूर्व बीज की आवश्यकता का आकलन किया जाकर कार्य योजना तैयार की जाती है तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बीज संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त बीज की उपलब्धता कराई जाती है। बीज संस्थाओं द्वारा उक्त बीज उनके डीलर नेटवर्क यथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति, निजी बीज विक्रेता केन्द्र आदि के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध/विक्रय किया जाता है।

(कृषि मंत्री)

(5) विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत आबंटित एवं वितरित बीज का योजना दिशा-निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। बीज कंपनियों द्वारा वितरित बीज से वांछित उपज प्राप्त नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण की मौके पर जांच करायी जाती है एवं सम्बन्धित बीज विक्रेता/ कंपनी के विरुद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## सिकराय में बागवानी के लिए अनुदान

**344. श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों को फलदार व फूलदार एवं औषधीय पौधों की बागवानी के लिए सरकार द्वारा ऋण व अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो इसके क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? योजनाओं सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन किसानों को कितना-कितना अनुदान व ऋण दिया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान दिया जाता है। विभाग द्वारा कृषकों को ऋण नहीं दिया जाता है।

राज्य में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने हेतु किसानों को फलदार, फूलदार एवं औषधीय पौधों की कृषि के लिये मिशन फार इन्टीग्रेटेड डवलमेंट आफ हार्टीकल्चर उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं राज्य योजना के तहत अनुदान दिया जाता है। इन योजनाओं के तहत फलदार, फूलदार एवं औषधीय पौधों पर देय अनुदान के मानदण्ड परिशिष्ट-1 से 4 पर संलग्न हैं।

(2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषकों को फलदार बगीचों की स्थापना हेतु विधान सभा क्षेत्र सिकराय में मार्च-2013 से दिसम्बर-2015 तक अनुदान उपलब्ध करवाया गया।

(कृषि मंत्री)

लाभान्वित कृषकों का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बहरोड़ में कृषकों के हितार्थ संचालित योजनाएं

**345. डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कृषकों के हितार्थ कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत दो वर्षों में कितने कृषकों को किस-किस योजना में लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में कृषकों के हितार्थ कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-1 व विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर एवं उद्यान विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने हेतु मिशन फार इन्टीग्रेटेड डवलपमेन्ट आफ हार्टीकल्चर उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सौर उर्जा आधारित पम्प परियोजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना, राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्तर्गत औषधीय पादप मिशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा गत दो वर्षों क्रमश: 2013-14 एवं 2014-15 में योजनावार लाभान्वित कृषकों की सूचना क्रमश: परिशिष्ट-4, 5 एवं 6 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कोटा जिले में जब्त (पशुओं की) सोनोग्राफी मशीन को रिलीज करने की कार्यवाही

**346. श्री विद्याशंकर नन्दवाना** (पीपल्दा) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में पशुओं की सोनोग्राफी हेतु सरकार द्वारा सोनोग्राफी मशीन दी गई है? यदि हां, तो कब?

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा उक्त मशीन को पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत सीज कर दिया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि सोनोग्राफी मशीन के अभाव में पशुओं की सोनोग्राफी करने में परेशानी आ रही है? यदि हां, तो उक्त मशीन को रिलीज करवाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले के बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, कोटा में दिनांक 28.02.2014 को सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध हुई है।

(2) जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, कोटा की सोनोग्राफी की मशीन को पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत दिनांक 27.09.2014 को सीज किया गया है।

(3) जी हां। सोनोग्राफी मशीन को रिलीज करवाने हेतु उप निदेशक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, कोटा से दिनांक 01.04.2015, 24.06.2015, 05.08.2015 एवं 28.12.2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को लगातार पत्राचार कर निवेदन किया गया है।

## प्रदेश में पंजीयन नहीं कराने वाले खेल संघों के विरुद्ध कार्यवाही

347. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नए खेल अध्यादेश के बाद से खेल संघों का पंजीयन अनिवार्य किया गया था? यदि हां, तो पंजीयन नहीं करवाने वाले खेल संघों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और भविष्य में क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अप्रैल, 2013 से जनवरी, 2016 तक प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा उनमें से प्रति वर्ष कितने

(श्री कैलाश भंसाली)

खिलाड़ियों ने किस श्रेणी का पदक जीतने में सफलता पाई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रशिक्षक की कमी के कारण प्रदेश की खेल प्रतिभाएं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं? यदि हां, तो वर्तमान में कितने प्रशिक्षक किस-किस खेल में पदस्थापित हैं व किन-किन में नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खेल अध्यादेश, 2004 के पश्चात पारित खेल अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपंजीकृत संघों को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है।

(2) सरकार द्वारा अब तक खेल प्रशिक्षण की सुविधायें खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आधारभूत खेल संरचनाओं का निर्माण करवाये जाने हेतु समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 को संशोधित कर समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम, 2015 लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत सम्भाग, जिला, तहसील, पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों को न्यूनतम आधारभूत सुविधायें प्रशिक्षण हेतु निर्मित कराई जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार की राजीव गांधी खेल अभियान योजना के अन्तर्गत भी खेल सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

भविष्य में उक्त योजनाओं के विकास पर कार्य किया जायेगा।

(3) खेल अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पंजीकृत ऐसे राज्य संघ जिन्हें राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, के माध्यम से राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अप्रेल, 2013 से जनवरी, 2016 तक भाग लेने वाले खिलाडियों की संख्या की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

उल्लेखित अवधि में पदक विजेता खिलाड़ियों की वर्षवार सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में पदस्थापित 119 खेल

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

प्रशिक्षकों के द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2015-16 के अन्तर्गत 207 अल्पकालिक प्रशिक्षक वर्तमान में संविदा पर प्लेसमेंट एजेन्सी के मार्फत लगाये गये हैं। नियमित प्रशिक्षकों की सूची परिशिष्ट-घ पर एवं अल्पकालीन प्रशिक्षकों की खेलवार संख्या की सूची परिशिष्ट-ड पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जमवारामगढ़ में रीको की स्थापना

**348. श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रीको की स्थापना हेतु सरकार के पास क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौन से प्रस्ताव कब से विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावों की क्रियान्विति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रीको की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार

(3) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के सम्बन्ध में निगम के कार्यालय आदेश दिनांक 08.03.1999 एवं 08.10.2014 की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। रीको द्वारा स्थानीय उद्यमियों की मांग पर, उस क्षेत्र में नवीन उद्योगों की स्थापना की सम्भावनाओं जल ऊर्जा, खनिज की क्षेत्र में उपलब्धता, वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधायें एवं मानव संसाधन आदि बिन्दुओं के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रथम दृष्टया निर्णय लिया जाता है इस हेतु प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की टेक्नो इकोनोमिक फिजिबिलिटी एवं पर्यावरण सम्बन्धी बिन्दुओं पर भी अध्ययन किया जाता है। भूमि के चयन के सम्बन्ध

(उद्योग मंत्री)

में जो मुख्य बातें राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों, माननीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं निगम प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार मुख्यत: निम्न मानदण्ड भी ध्यान में रखे जाते हैं, वह निम्न है :-

(अ) अवाप्ति में वर्णित भूमि किसी अन्य संस्थान, एजेन्सी, कंपनी इत्यादि द्वारा न तो अवाप्तशुदा है ना अवाप्ताधीन है।

(ब) अवाप्ताधीन भूखण्ड में आबादी के निकट की तथा आबादी विस्तार के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि अवाप्ति से मुक्त रखी जा रही है।

(स) ऐसे सार्वजनिक मार्ग जल मार्ग मंदिर अथवा सार्वजनिक भूमि जिनकी अवाप्ति से कोई जन असंतोष होने की आशंका है अवाप्त नहीं किये जा रहे हैं।

(द) यह उस क्षेत्र की न्यूनतम वर्गीकरण की भूमि है तथा अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

(य) प्रस्तावित भूमि की अवाप्ति वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए सटी भूमि होने के कारण आवश्यक अथवा नहीं।

(र) सामान्यत यह संतुष्टि कर ली गयी है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में कोई व्याप्त जन अवरोध या मुकदमेबाजी की आशंकाएं नहीं हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जोधपुर जिले में काष्ठ कला एवं धातु कला के प्रशिक्षण केन्द्र

**349. श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में काष्ठ कला व धातुकला क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने हेतु तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण केन्द्र योजना का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? योजना की पात्रता एवं शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में कितने प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, कहां-कहां किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के कुल कितने प्रशिक्षणार्थियों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। तकनीकी उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योग विभाग के अधीन गठित उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में काष्ठकला व धातुकला के क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रमांक | स्थान का नाम | प्रशिक्षण योजना का नाम | कब से कब तक |
|---|---|---|---|
| 1. | जयपुर | काष्ठकला<br>धातुकला | 2003-04 से 2014-15<br>2003-04 से 2014-15 |
| 2. | जोधपुर | काष्ठकला | 2004-05 से 2012-13 |
| 3. | उदयपुर | काष्ठकला<br>धातुकला | 2004-05 से 2014-15<br>2013-14 से 2014-15 |

योजना की पात्रता एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. 18 से 35 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति
2. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
3. राजस्थान का मूल निवासी
4. प्रशिक्षण अवधि तीन माह
5. प्रशिक्षणार्थी का चयन साक्षात्कार द्वारा
6. चयनित प्रशिक्षणार्थी को 30/- रुपये प्रति दिवस की दर से स्टाइपेन्ड
7. चयनित प्रशिक्षणार्थी को 1500/- रुपये मूल्य का टूलकिट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना
8. आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में काष्ठकला एवं धातुकला में प्रशिक्षण कार्यक्रम एस.आई.एस.आई. के पुराने प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किये गये।

(3) जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र से किसी अभ्यार्थी ने इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु आवेदन नहीं किया।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

प्रश्न संख्या-350

(स्थगित)

## भोपालगढ़ में विधायक की अनुशंसा पर सड़कों का निर्माण

351. **श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में जनवरी, 2008 से जनवरी, 2016 तक विधायक की अनुशंसा पर किस-किस योजना में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विधायक की अनुशंसा पर वर्ष 2008 से जनवरी, 2016 तक कितनी नवीन डामर की सड़कों की कहा-कहां, कितने किलोमीटर व कितने किमी सड़क मरम्मत के कार्य की कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में जनवरी 2008 से जनवरी 2016 तक माननीय विधायक की अनुशंसा पर 24.5 किमी. लम्बाई के 7 कार्यों का निर्माण किया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में माननीय विधायक की अनुशंसा पर जनवरी 2008 से जनवरी 2016 तक 7 नवीन डामर सड़कों का 24.5 किमी में राशि रु. 405.35 लाख की स्वीकृतियां (विवरण परिशिष्ट-1) व मरम्मत कार्य के लिए 12 कार्यों की 53.20 किमी. में राशि रु. 628.15 लाख की स्वीकृतियां जारी की गईं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को 6 लेन करने की कार्य योजना

352. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में बदलने का कार्य अप्रैल, 2009 में शुरू किया गया था? यदि हां, तो इस प्रोजेक्ट पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई तथा कितने कि.मी. सड़क का निर्माण पूर्ण हो गया है?

(श्री जोगाराम पटेल)

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर टोल वसूली का कार्य प्रारम्भ हो चुका है? यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू हुआ व जनवरी, 2016 तक कुल कितनी राशि का टोल वसूला जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को 6 लेन में बदलने का कार्य भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा किया जा रहा है। भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उत्तर (परिशिष्ट-1) के अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

''जी हां। यह एक बी.ओ.टी. (टोल) प्रोजेक्ट है। बी.ओ.टी. (टोल) प्रोजेक्ट पर सरकार की तरफ से परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया जाता है। अब तक कुल 225.200 किमी. में से 214.420 किमी. का छह लेनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।''

(2) जी हां। एन.एच.-8 जयपुर-गुड़गांव के चार लेनीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् से टोल वसूली की जा रही है, जो वर्ष 2009 से छह लेनीकरण कार्य के साथ भी पूर्ववत चल रहा है। छह लेनीकरण परियोजना के अन्तर्गत 31.01.2016 तक कुल वसूली गई टोल राशि रु. 3105.73 करोड़ है। वर्षवार विवरण निम्न है:-

| वर्ष | कुल टोल संग्रहण (रु. करोड़) एनएचएआई के हिस्से सहित |
|---|---|
| 2009-10 | 314.69 |
| 2010-11 | 371.79 |
| 2011-12 | 414.82 |
| 2012-13 | 461.44 |
| 2013-14 | 512.07 |
| 2014-15 | 544.15 |
| 2015-16 (upto 31-01-2016) | 468.77 |
| **कुल योग** | **3105.73** |

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पीलीबंगा के चक खोसेवाला में बस स्टैण्ड का निर्माण

353. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत सरावांवाला के चक खोसेवाला (10PBN-A) गोलूवाला-पीलीबंगा मुख्य सड़क के पास स्थित है? यदि हां, तो क्या सरकार चक खोसेवाला (10PBN-A) के लिए बस स्टैण्ड स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा ग्राम पंचायत सारावांवाला के चक खोसेवाला (10PBN-A) गोलूवाला-पीलीबंगा मुख्य सड़क के पास है।

चक खोसेवाला (10PBN-A) के पश्चात स्टैण्ड पीलीबंगा की दूरी मात्र 02 कि.मी. एवं चक खोसेवाला (10PBN-A) से पूर्व स्टैण्ड रमाना चक की दूरी मात्र 01 कि.मी. है। इस कारण चक खोसेवाला (10PBN-A) को राजस्थान परिवहन निगम वाहनों के लिए स्टैण्ड स्वीकृत किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

## बयाना के प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं से वंचित गांव

354. **श्री बच्चू सिंह** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में ऐसे कितने गांव एवं ढाणियां हैं, जो प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री एवं अन्य सड़क योजनाओं से वंचित हैं? गांववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना-रूपवास विधान सभा क्षेत्र में जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर 13 गांव, जनगणना वर्ष 2001 के बाद घोषित 5 गांव, जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 9 गांव सड़क से जुड़ने से वंचित हैं। सड़क से जुड़ने से 137 ढाणियां वंचित हैं। गांव/ढाणीवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1, 2, 3 व 4 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) सड़क से जुड़ने से वंचित गांव/ढाणियों को जोड़ा जाना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, पारस्परिक प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नागौर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ाईकरण की कार्य योजना

355. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नागौर जिले में निर्माण हो चुकी सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर पुनः सुधार हेतु सरकार के पास कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किस-किस सड़क की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नागौर जिले में चिमरानी ग्राम से राजस्व ग्राम बलाया तथा खरनाल ग्राम से मुंडियाड़ तक की क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण कर चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनहित की मांग को देखते हुए नागौर जिले के राजस्व ग्राम हिलोड़ी से भटनोखा तथा चीताणी ग्राम से धवा वाया नोखा-चादावता तक के कच्चे मार्गों का डामरीकरण अथवा सी.सी. रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बढ़ते वाहनों के आवागमन एवं सुलभ यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए राज्य राजमार्ग संख्या 63 की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कर कुचेरा से ग्राम कंकड़ाय तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर 5 वर्ष की गारण्टी अवधि में मरम्मत करने की जिम्मेदारी संवेदक की होती है। पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् इन सड़कों की मरम्मत राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से करवाई जाती है। नागौर जिले में विगत दो वर्षों में जिन सड़कों पर मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य करवाया गया है, उनका व्यय राशि सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) नागौर जिले में चिमरानी से बलाया सड़क की कुल लम्बाई 9.00 किमी. है एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त है इस सड़क के नवीनीकरण हेतु आर.आई.डी.एफ.-21 (नान पेचेबल) में रु.130.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है तथा निविदा प्राप्त कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

ग्राम खरनाल से मुन्दियाड सड़क की कुल लम्बाई 13.50 किमी. है इस सड़क पर खरनाल से पालड़ी व्यासा खण्ड की लम्बाई 7.50 किमी. है तथा इसका निर्माण वर्ष 2006-07 में करवाया गया था। सड़क के इस खण्ड पर भारी यातायात दबाव के कारण सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त है। सड़क के पालड़ी व्यासा से मुन्दियाड खण्ड की कुल लम्बाई 6.00 किमी. है तथा इसका निर्माण वर्ष 2011-12 में करवाया गया था एवं वर्तमान में सड़क की स्थिति संतोषप्रद है।

क्षतिग्रस्त सड़क के भाग खरनाल से मुन्दियाड के पुन: निर्माण एवं चौड़ाई बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार की पारस्परिक प्राथमिकता, नीतिगत निर्णय एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) नागौर जिले के राजस्व गांव हिलोड़ी से लेकर भटनोखा तथा चीताणी ग्राम से लेकर धवा होते नोखा चांदावता तक कच्चे मार्ग पर डामरीकरण अथवा सी.सी. रोड बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त सड़कों के कार्य कराया जाना राज्य सरकार की पारस्परिक प्राथमिकता, नीतिगत निर्णय एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(4) राज्य राजमार्ग-63 की 42 किमी. लम्बाई (किमी. 87/0 से 129/0) नागौर जिले में स्थित है एवं सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

राज्य राजमार्ग संख्या-63 का कुचेरा से ग्राम कंकडाय (किमी. 90/0 से 129/0) तक का भाग वर्तमान में 3.75 मीटर चौड़ाई में है व सड़क की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्थिति संतोषजनक है। सड़क के चौड़ाईकरण का कार्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## ईसाली ग्राम पंचायत (मारवाड़ जंक्शन) में शौचालय निर्माण हेतु प्राप्त आवेदन

356. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में देसूरी पंचायत समिति क्षेत्र के मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में शौचालय निर्माण हेतु कितने परिवारों के आवेदन प्राप्त हुए कितने आवेदन स्वीकृत हुए तथा कितने शौचालय भौतिक रूप से निर्मित हुए? अस्वीकृत आवेदनों की कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में ईसाली ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? क्या सभी आवेदन स्वीकृत होकर निर्माण हो चुका है? निर्माण कार्यों के भुगतान की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) गत 2 वर्षो में देसूरी पंचायत समिति क्षेत्र में शौचालय निर्माण हेतु आवेदनों का विवरण निम्नानसुार है :-

| ग्रा.पं. का नाम | ग्रा.पं. से प्राप्त आवेदन | स्वीकृत आवेदन की संख्या | भौतिक रूप से निर्मित कुल शौचालय की संख्या | यू.सी. के आधार पर किये गये भुगतान की संख्या | अस्वीकृत आवेदन यदि है |
|---|---|---|---|---|---|
| केसूली | 577 | 577 | 516 | 123 | नहीं |
| डायलाना कलां | 620 | 620 | 535 | 225 | नहीं |
| बागोल | 375 | 375 | 324 | 211 | नहीं |
| कोट सोलंकीयान | 668 | 668 | 610 | 302 | नहीं |
| मगरतलाब | 650 | 650 | 560 | 73 | 20 निरस्त |
| सांसरी | 219 | 219 | 165 | 44 | नहीं |
| पनोता | 338 | 338 | 326 | 113 | नहीं |

(पंचायती राज मंत्री)

नोट:- ग्राम पंचायत मगरतलाब में स्वीकृति में नामों की दोहरी पुनरावृति होने के कारण 20 नाम निरस्त किये गये। निरस्त की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है

(2) ग्राम पंचायत ईसाली में शौचालय निर्माण हेतु 847 आवेदन प्राप्त हुये एवं 847 की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 32 परिवारों की दोहरी स्वीकृति जारी हो जाने से निरस्त की गई। जिसका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है शेष 815 स्वीकृतियों में से 740 का भुगतान कर दिया गया है। 75 परिवारों की यू.सी./सी.सी. प्राप्त नहीं हुई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को भू-उपयोग परिवर्तन करने का अधिकार

357. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के सम्बन्ध में बढ़ते न्यायिक विवादों की रोकथाम हेतु स्वायत्त शासन विभाग की तर्ज पर ग्राम पंचायतों से नामान्तरण कार्यवाही कराये जाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आबादी भूमियों के भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी अधिकार किस अथारिटी के पास विद्यमान हैं? क्या सरकार इस कार्य के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं का ध्यान रखकर नियम बनाने पर विचार किया जावेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा आबादी भूमि का पर्यटन इकाइयों के लिये उपयोग परिवर्तन करने हेतु भूमि क्षेत्रफल के आधार पर प्राधिकृत अधिकारियों को अधिकृत किया गया है, अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

पर्यटन इकाइयों के अतिरिक्त आबादी भूमियों के उपयोग परिवर्तन

(पंचायती राज मंत्री)

सम्बन्धी अधिकार राज्य सरकार के पास विद्यमान है। इस सम्बन्ध में नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में मनरेगा के तहत मानव दिवसों का निर्धारण

358. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कितने मानव दिवसों का श्रम विभिन्न जिलों के ग्रामीणों को उपलब्ध कराया गया तथा कितने जिलों में 100 दिन का रोजगार कितने श्रमिकों ने पूरा किया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक क्रमश: 2203.38 लाख, 1838.56 लाख, 1686.18 लाख तथा 2027.47 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। योजनान्तर्गत प्रति परिवार 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है ना कि श्रमिकों को। सृजित मानव दिवस तथा 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## करौली जिले में इन्दिरा/मुख्यमंत्री आवासों की बकाया किश्तों का भुगतान

359. **श्री रमेश** (सपोटरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) करौली जिले में गत तीन वर्षों में इन्दिरा/मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के अन्तर्गत कितने आवास स्वीकृत किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गत तीन वर्षों में स्वीकृत सभी इन्दिरा आवास व मुख्यमंत्री आवासों के निर्माण कार्यों की द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि का हस्तान्तरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में इन आवासों की बकाया किश्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो कितने लाभार्थियों को?

(श्री रमेश)

(4) भौतिक सत्यापन नहीं होने के क्या कारण हैं एवं अब कब तक भौतिक सत्यापन पूर्ण कर किश्त का भुगतान कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त के लिए कौन दोषी हैं? सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) करौली जिलें में विगत तीन वर्षों में इन्दिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में आवास स्वीकृत किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-

| वर्ष | इन्दिरा आवास स्वीकृत | मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना |
|---|---|---|
| 2013-14 | 2093 | 6193 |
| 2014-15 | 9657 | 0 |
| 2015-16 | 1067 | 0 |

(2) विगत तीन वर्षो में इन्दिरा आवास एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में परिशिष्ट-अ के अनुसार आवास की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त जारी की गई। जिन आवास निर्माण कार्यों की यूसी/सीसी प्राप्त हो गई है उन्हें द्वितीय/तृतीय किश्त जारी कर दी गई है। शेष निर्माण कार्यों की यूसी/सीसी प्राप्त कर द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि हस्तांतरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। कुछ प्रकरणों में भौतिक सत्यापन के अभाव में आवासों की बकाया किश्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। बकाया किश्तों के भुगतान हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है एवं तृतीय पक्ष संस्थाओं के द्वारा भी आवासों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। भौतिक सत्यापन में विलम्ब हेतु दोषी ग्राम सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है। इसके कारण विगत 3 माह में 11038 लाभार्थियों को द्वितीय/तृतीय किश्तें जिला परिषद द्वारा जारी की गई हैं।

(4) भौतिक सत्यापनकर्ता की लापरवाही रही है जिसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर नियमानुसार प्रयास किये गये एवं दोषियों का

(ग्रामीण विकास मंत्री)

चिन्हिकरण कर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही ग्राम सेवक/विकास अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध की गई। योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण का दायित्व लाभार्थी का होता है। लाभार्थी द्वारा निर्माण किये जाने पर द्वितीय व तृतीय किश्त का भुगतान किया जा सकेगा। आवास निर्माण नहीं कर रहे लाभार्थियों को भी निर्माण के लिए प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराये जा रहे हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में अपील प्रकाशित कराई जा रही है। लाभार्थियों को डाक द्वारा योजना व किश्त हस्तान्तरण की जानकारी पत्र भेजे गये हैं।

(5) आवास निर्माण कार्य स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाने का प्रावधान है। इस कारण आवास पूर्ण करने में अधिक समय लगता है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर किश्त राशि का भुगतान किया जाता है। राशि का हस्तान्तरण की प्रक्रिया में यदि कोई उदासीनता एवं लापरवाही की जाती है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। किश्त हस्तान्तरण/भौतिक सत्यापन में विलम्ब के कारण 3 ग्राम सेवकों को निलम्बित किया है एवं विकास अधिकारी टोडाभीम, करौली, हिण्डौन एवं नादोती को नियम 17 सीसी के तहत चार्जशीट जारी की गई है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र की पंचायतों द्वारा कराये गये कार्य

360. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा किये जा रहे विकास कार्य में सरपंच द्वारा अधिकतर कार्य अपने स्थानीय गांव में ही करवा दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) बारां जिले के शाहाबाद व किशनगंज क्षेत्र में गत 2 वर्षों में ग्राम पंचायतों द्वारा किस-किस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से विकास कार्य कहां-कहां पर करवाये गये? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य वार्षिक प्लान तैयार कर ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात करवाये जाते हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायतों में विकास कार्य वार्षिक प्लान तैयार कर ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात करवाये जाने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) बारां जिले में शाहाबाद, किशनगंज में विगत 2 वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पंचायत समिति सोजत में मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्य

**361. श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति सोजत नगर द्वारा वर्ष 2010 से 2013 तक मनरेगा योजनान्तर्गत किन-किन पंचायतों में क्या-क्या कार्य करवाए गए तथा कितने कार्य पूर्ण हो गए व कितने अपूर्ण हैं?

(2) क्या उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया गया है? यदि हां, तो किस अधिकारी से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सभी कार्यों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या एजेन्सियों द्वारा किए गए कार्य जी शिड्यूल अनुसार हैं? यदि नहीं, तो क्या उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पंचायत समिति सोजत में वर्ष 2010 से 2013 तक महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 1592 कार्य कराये गए हैं जिनमें से 950 कार्य पूर्ण एवं 642 कार्य अपूर्ण हैं। कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान टास्क आधारित है। अतः माप किया जाना अनिवार्य है जो कि भौतिक सत्यापन से ही सम्भव है। कार्यों के प्रगतिरत रहने के दौरान कार्य का सत्यापन कनिष्ठ तकनीकी सहायक के द्वारा नियमित रूप से तथा सहायक अभियन्ता (ईजीएस) तथा अन्य निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान समय-समय पर किया जाता है।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

(3) जी हां।

(4) जी हां।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जायल में नये ट्यूबवैल लगाने की स्वीकृतियां

362. **डा. मंजू बाघमार** (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में गत दो वर्षों में फेलियर (Failer) ट्यूबवैल के स्थान पर नये ट्यूबवैल लगाने के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये व उनमें से कितने स्वीकृत किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल में गत 2 वर्षों में कोई भी नये ट्यूबवैल की स्वीकृति जारी नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये ट्यूबवैल लगाने की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वित्तीय वर्ष 2014-15 में नागौर जिले की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जल योजनाओं अन्तर्गत असफल नलकूपों के स्थान पर 132 नवीन नलकूपों के बनाये गये प्रस्तावों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 105 नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई। इन समस्त नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विधान सभा क्षेत्रवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 (माह फरवरी, 2016 तक) में असफल नलकूपों के स्थान पर 160 नवीन नलकूपों के बनाये गये प्रस्तावों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार 96 नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई। इस स्वीकृति के विरुद्ध 77 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष 19 नलकूपों का कार्य प्रगति पर है। विधान सभा क्षेत्रवार वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जायल में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में असफल नलकूप के स्थान पर 1 एवं अन्य योजनाओं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

में 2, इस प्रकार कुल 3 नलकूपों की स्वीकृति जारी की गई। समस्त स्वीकृत नलकूपों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। योजना अन्तर्गत पेयजल की आवश्यकता एवं भू-जल की उपलब्धता अनुसार नये नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृतियां सतत प्रक्रिया के तहत जारी की जाती हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बाड़मेर शहर में पानी के लीकेजों को ठीक करने की योजना

**363. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु जनवरी 2014 से दिसम्बर, 2015 तक कौन-कौनसी क्षेत्रीय योजनाएं (नलकूप, ओपनवेल, हैण्डपंप) स्वीकृत हुईं अथवा स्वीकृति हेतु लम्बित हैं? खण्डवार मय योजना के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर में पानी के लीकेजों को ठीक करने के लिए रिपेयर मेटेरियल की कमी है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक समुचित मेटेरियल उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पेयजल की समस्या के समाधान हेतु सरकार की हैल्पलाईन सुगम व विभाग की हैल्पलाइन पर बाड़मेर जिले की वर्तमान में पेयजल सम्बन्धी कितनी समस्याएं दर्ज हैं? खण्डवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला बाड़मेर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 की अवधि में 88, दिनांक 1 जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 की अवधि में 118, इस प्रकार कुल 206 योजनाओं/कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 4421.89 लाख की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में उक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध क्रमशः 57 एवं 40, इस प्रकार कुल 97 योजनाएं अब तक पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 109 योजनाओं पर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। खण्डवार स्वीकृत, पूर्ण की गई एवं प्रगतिरत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त जिले की विभिन्न जल योजनाओं हेतु बनाये गये 14 प्रस्ताव सक्षम स्तर पर वर्तमान में तकनीकी जांच की प्रक्रिया में हैं। इन प्रस्तावों के जांच में सही पाये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बाड़मेर शहर की जल योजना अन्तर्गत पेयजल लाइनों की लीकेजों की मरम्मत हेतु खण्डीय भण्डार, नगर खण्ड बाड़मेर में पर्याप्त रूप से सामग्री उपलब्ध है। बाड़मेर शहर की जल योजना अन्तर्गत बिछी हुई पेयजल पाइप लाइनों में दिनांक 1 जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2015 की अवधि में विभिन्न कारणों से विभिन्न स्थानों पर हुई कुल 2356 लीकेजों की मरम्मत की जाकर शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाई रखी गई।

(3) प्रदेश में पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की पेयजल सम्बन्धी शिकायतें राज्य सरकार के राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर कार्यालयवार वर्तमान में दर्ज की जा रही हैं।

दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 8 मार्च, 2016 की अवधि में बाड़मेर जिले से विभाग की पेयजल से सम्बन्धित 734 पेयजल शिकायतें दर्ज हुई हैं तथा इन शिकायतों का फिजिबिलिटी अनुसार मौके पर निराकरण किया जाकर तत्सम्बन्धी दस्तावेज उक्त पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वांछित सूचना राज्य सरकार की वैब-साइट sampark.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नवलगढ़ के गांवों के लिये पेयजल योजनाएं

**364. डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जनवरी, 2014 से अब 31 जनवरी, 2016 कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी योजना कब-कब स्वीकृत की गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में किन-किन ग्रामों/कस्बों को कब तक लाभान्वित किया जायेगा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-

(डा. राजकुमार शर्मा)

किन गांवों के लिए व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु माह जनवरी, 2014 से फरवरी, 2016 की अवधि में शहरी क्षेत्र हेतु 814 योजनाएं राशि रुपये 621.38 करोड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 9246 योजनाएं राशि रुपये 1682.01 करोड़ की स्वीकृत की गई। जिलेवार वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त इस अवधि में 6 वृहद पेयजल परियोजनाएं लागत रुपये 1970.53 करोड़ की स्वीकृत की गयी हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत शहरी जल योजनाओं के 232 संवर्धन प्रस्तावों में से 198 प्रस्तावों का क्रियान्वयन पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत 12683 ग्राम/ढाणियों के विरुद्ध अब तक 8177 ग्राम/ढाणियों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

वृहद पेयजल परियोजनाओं को लाभान्वित किये जाने का विवरण परिशिष्ट-द में सम्मिलित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के शहर नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ तथा 109 ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है। क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु 30 ग्राम/ढाणियों हेतु राशि रुपये 399.43 लाख की योजनाओं/कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गईं। उक्त स्वीकृत समस्त योजनाएं/कार्य पूर्ण किये जाकर इनके पूर्ण क्रियान्वयन पर रुपये 284.67 लाख की राशि व्यय की गई। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र के 10 ग्रामों में सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेस नलकूप निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 74.20 लाख की माह जून, 2015 में जारी की गई है तथा इनका निर्माण वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है। पेयजल की आवश्यकता, भू-जल की उपलब्धता एवं वित्तीय

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्षेत्र में जल योजनाओं का संवर्धन/पुनर्गठन का कार्य सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## किशनगढ़ बास में खारे पानी की समस्या हेतु कार्य योजना

365. **श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले के किस-किस क्षेत्र के ग्रामों में खारे व फलोराइडयुक्त पानी की समस्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजनाओं पर अब तक कब-कब, कितनी-कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में खारे पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार अलवर जिले में केवल फ्लोराइड से प्रभावित 87 ग्राम, केवल खारेपन (टी.डी.एस.) से प्रभावित 38 ग्राम तथा फ्लोराइड एवं टी.डी.एस. से संयुक्त रूप से प्रभावित 47 ग्राम, इस प्रकार कुल 172 ग्रामों के स्थानीय भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित पेयजल मानकों के अनुरूप नहीं है। वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। पेयजल गुणवत्ता प्रभावित जिले के उक्त 172 ग्रामों में निर्धारित गुणवत अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, इनमें से अब तक 76 ग्रामों हेतु दूरस्थ निर्धारित गुणवत्ता के जल स्रोत निर्मित कर योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। 8 ग्रामों हेतु स्वीकृत योजनाओं में से 7 ग्रामों की योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा एक योजना के कार्यो के निष्पादन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

41 ग्रामों में आर.ओ. संयंत्र के निर्माण की उपलब्ध स्वीकृति के विरुद्ध 22 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं एवं शेष 19 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण हेतु तथा इसके अतिरिक्त 1 ग्राम में डी-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

फ्लोरिडेशन इकाई की स्थापना के कार्य हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार वर्तमान में शेष रहे 46 ग्रामों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता के जल स्रोत चिन्हित कर अथवा अन्य उपलब्ध विकल्पों के आधार पर योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जायेगा।

उक्तानुसार स्वीकृत एवं कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार अलवर जिले के विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़ बास में केवल फ्लोराइड से प्रभावित 21 ग्राम, केवल खारेपन (टी.डी.एस.) से प्रभावित 07 ग्राम तथा फ्लोराईड एवं टी.डी.एस. से संयुक्त रूप से प्रभावित 11 ग्राम, इस प्रकार कुल 39 ग्रामों के स्थानीय भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित पेयजल मानकों के अनुरूप नहीं है।

पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के उक्त 39 ग्रामों में निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, इनमें से अब तक 21 ग्रामों हेतु दूरस्थ निर्धारित गुणवत्ता के जल स्रोत निर्मित कर योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। 2 ग्रामों हेतु योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर एवं 1 अन्य ग्राम की योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7 ग्रामों में आर.ओ. संयंत्र के निर्माण की उपलब्ध स्वीकृति के विरुद्ध 3 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं एवं शेष 4 आर.ओ. संयंत्र के निर्माण कार्य हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र के शेष रहे 8 ग्रामों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता के जल स्रोत चिन्हित कर अथवा अन्य उपलब्ध विकल्पों के आधार पर योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति बाबत निर्णय लिया जायेगा। क्षेत्र में उक्तानुसार स्वीकृत एवं कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में अंग्रेजी बबूल हटाने की कार्य योजना

366. **श्री शंकरसिंह** (ब्यावर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूरे प्रदेश में अंग्रेजी बबूल के अत्यधिक फैलाव के कारण जल संकट बढ़ रहा है?

(2) क्या सरकार नरेगा योजना के तहत प्रदेश से अंग्रेजी बबूल हटाने की योजना बनाकर अंग्रेजी बबूल मुक्त राजस्थान बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अंग्रेजी बबूल के अत्यधिक फैलाव से जल संकट बढ़ने का अध्ययन विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य अनुमत नहीं होने के कारण यह कार्य योजनान्तर्गत नहीं कराया जा सकता है।

## सूरसागर में विकास कार्यों एवं जन समस्याओं की शिकायतों का निराकरण

367. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 31 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2016 तक विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विकास कार्यों एवं जन समस्या निराकरण के कितने प्रस्ताव अथवा शिकायतें सरकार को प्राप्त हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक प्रस्ताव अथवा शिकायत के अनुरूप विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक प्रस्ताव अनुरूप अब तक की भौतिक, वित्तीय कार्य प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में जन आवश्यकताओं और जोधपुर विकास की भविष्य के परिप्रेक्ष्य में स्वप्रेरणा से कोई प्रोजेक्ट पर कार्य किया है? यदि हां, तो ऐसे प्रोजेक्ट की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में माह दिसम्बर, 2013 से माह

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

फरवरी, 2016 की अवधि में पेयजल सम्बन्धी विकास कार्यों हेतु 69 प्रस्ताव एवं जन समस्या के निराकरण हेतु 51 शिकायतें, इस प्रकार मुख्य रूप से कुल 120 प्रस्ताव/शिकायतें विभाग को प्राप्त हुईं। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्तानुसार विभाग को प्राप्त 69 प्रस्तावों में से 4 प्रस्तावों की योजना प्रस्तावित करने से पूर्व वन विभाग की सहमति आवश्यक है, 9 प्रस्तावों का सम्बन्ध जोधपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर नगर निगम से है एवं 5 प्रस्तावों पर क्रियान्वयन की आवश्यकता नहीं है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

शेष रहे 51 प्रस्तावों का क्रियान्वयन, ए.एफ.डी. द्वारा वित्त पोषित पुनर्गठित शहरी जल योजना, जोधपुर शहर एवं अमृत जल योजना/ आपातकालीन योजना, वर्ष 2016 की स्वीकृति अनुसार किया जाना है। ए.एफ.डी. परियोजना के अन्तर्गत पेयजल वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु परामर्शदात्री फर्म मैसर्स एन जे एस इंजीनियर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की नियुक्ति की जा चुकी है। इसी प्रकार अमृत योजना अन्तर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु मैसर्स वेपकोस लिमिटेड को लैटर आफ इन्टेन्ट जारी किया गया है। इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी।

इसी प्रकार विभाग को प्राप्त 51 शिकायतों में से 49 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है एवं शेष 2 शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह कार्य विभाग द्वारा नियमित संधारण कार्यों हेतु उपलब्ध राशि के तहत किया गया/जा रहा है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु विभाग द्वारा निम्न वर्णित तीन योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है :-

(अ) सूरसागर क्षेत्र सहित सम्पूर्ण जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों हेतु कम्पोजिट योजना स्वीकृत राशि रुपये 73.26 करोड़

(ब) सूरसागर क्षेत्र में पुरानी एवं प्रदूषित पाइप लाइनों को बदलने का कार्य-स्वीकृत राशि रुपये 86.89 लाख

(स) सूरसागर क्षेत्र सहित सम्पूर्ण जोधपुर शहर में पुरानी एवं प्रदूषित पाइप लाइनों को बदलने का कार्य-स्वीकृत राशि रुपये 425.06 लाख

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

## सोडाला ग्राम (जयपुर) की सीलिंग रिट पिटीशन 1416/76 रूपराज लक्ष्मी बनाम एस.डी.ओ., आमेर में न्यायालय निर्णय की पालना

368. डा. **किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सोडाला तहसील जयपुर जिला जयपुर की सीलिंग रिट पिटीशन नं. 1416/76 रूपराज लक्ष्मी बनाम एस.डी.ओ. आमेर के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा कोई निर्णय पारित किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि किसी भी पक्षकारान द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि एस.डी.ओ. आमेर द्वारा इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर जयपुर को पत्र संख्या कोर्ट/2015/9 दिनांक 05 जनवरी, 2016 भिजवाकर मार्गदर्शन चाहा गया था? यदि हां, तो जिला कलक्टर जयपुर द्वारा इस सम्बन्ध में क्या निर्देश दिये गये? एस.डी.ओ. आमेर एवं जिला कलक्टर जयपुर के मध्य हुए पत्र व्यवहार का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि एस.डी.ओ., आमेर ने न्यायालय में निर्णयों की पालना नहीं की है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है व अब कब तक पालना कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3566/1994 नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. बनाम सरकार के साथ एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 1416/1976 रूपराज लक्ष्मी बनाम उपखण्ड अधिकारी आमेर व एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3927/2001 सुरेन्द्रपाल कालोनी विकास समिति बनाम सरकार का एक साथ निर्णय दिनांक 16.12.2013 को पारित किया गया था। निर्णय की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर द्वारा उक्त रिट संख्या 1416/1976 के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, अन्य पक्षकारान द्वारा अपील की गई हो तो जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर की जानकारी में नहीं है।

इसके साथ निर्णित अन्य सिविल रिट पिटीशन सं. 3566/1994 के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में डी.बी. स्पेशल अपील 13013/2015 सरकार बनाम नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. प्रस्तुत की गई है।

(3) जी हां। उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2015/09 दिनांक 05.01.2016 द्वारा मार्गदर्शन चाहे जाने पर जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर के पत्र क्रमांक आर18बी(41)2000/सिलिंग/800 दिनांक 1.2.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रभारी अधिकारी मानते हुए अधिग्रहित भूमियों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार कब्जा राज हक लिये जाने की कार्यवाही करने का मार्गदर्शन दिया गया है। पत्रादि की प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(4) सीलिंग प्रकरण में पूर्व में उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा दिनांक 30.10.1971 को इसके पश्चात 18.10.1976 को भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये थे। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रकरण पुनः खोलने के आदेश देने पर अंतिम निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा दिनांक 08.08.1991 को जारी किया गया है, जो कि अंतिम आदेश है।

उक्त आदेशों की पालना में तहसील आमेर व तहसील चौमूं के अन्तर्गत आने वाली सीलिंग भूमियों का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा तहसील जयपुर के अन्तर्गत आने वाली सीलिंग भूमियों के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बून्दी जिले में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना

**369. श्री अशोक डोगरा** (बून्दी) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अशोक डोगरा)

(1) बून्दी जिले में कुल कितने पटवारियों के पद स्वीकृत हैं व कितने पटवारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर पटवारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में पटवारी के स्वीकृत व रिक्त व कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

| पटवारी | | |
|---|---|---|
| स्वीकृत | रिक्त | कार्यरत |
| 264 | 103 | 161 |

(2) जी हां। सरकार पटवारी के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं। राज्य के राजस्व जिलों में पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 4400 पदों की स्वीकृति जारी की जाकर राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रथम चरण की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन हेतु जिला कलक्टरों को पटवारियों का आबंटन कर दिया जावेगा।

## प्रदेश के राजकीय मन्दिरों का तिरुपति बालाजी मन्दिर की तर्ज पर विकास

370. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदेश के राजकीय मंदिरों का तिरूपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर विकास करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत क्या सरकार द्वारा मंदिरों का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो किन-किन मंदिरों का?

(3) क्या सरकार कोटा शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर एवं सूर्य मंदिर का इस योजना के तहत चयन कर तिरूपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(4) गत 5 वर्षों में कोटा जिले के राजकीय मंदिरों में कौन-कौन से विकास कार्य करवाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग के मंदिरों का तिरूपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर विकास करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) देवस्थान विभाग के मंदिरों का तिरूपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर विकास करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन नहीं होने से मंदिरों का चयन नहीं किया गया।

(3) देवस्थान विभाग के मंदिरों का तिरूपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर विकास करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन नहीं होने से कोटा शहर के नीलकंठ महादेव मंदिर एवं सूर्य मंदिर का इस योजना के तहत चयन कर तिरूपति बालाजी की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) गत 5 वर्षों में कोटा जिले में देवस्थान विभाग के मंदिरों में करवाए गए विकास कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र सं. | नाम मंदिर | कराये गये कार्यों का विवरण | करवाए गये विकास कार्य | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |
| 1 | मंदिर श्री रामचन्द्रजी | मरम्मत / जीर्णोद्धार एवं प्लास्टर कार्य | 526491 | - | - | - | - |
| 2 | मंदिर सूर्य नारायणजी अमर निवास | प्लास्टर फलोरिंग छत कार्य एवं रंग रोगन एवं सामान्य मरम्मत | 302316 | - | - | - | - |
| 3 | मंदिर श्री चन्द्र मोलेश्वर | प्लास्टर फलोरिंग छत कार्य एवं अन्य जीर्णोद्धार | 528053 | - | - | - | - |
| 4 | मंदिर श्री कूल बिहारी जी पाटनपोल | प्लास्टर फिनिशिंग, फलोरिंग दरवाजा खिड़की या छत कार्य एवं टाईल्स | - | 2000000 | - | - | - |

(श्री देवस्थान राज्य मंत्री)

| क्र सं. | नाम मंदिर | कराये गये कार्यो का विवरण | करवाए गये विकास कार्य | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |
| 5 | मंदिर श्री डाढदेवी माताजी | चौकीदार कमरा व बरामदा रसोईघर निर्माण कुंडियों की मरम्मत सेनेटरी बिजली कार्य स्टोन व स्लेटिंग का कार्य विद्युत सम्बन्धी कार्य | - | 1000000 | - | - | 19033 |
| 6 | मंदिर श्री सूजाजी अस्थल मोखापाडा (आत्म निर्भर) | प्लास्टर छत कार्य फलोरिंग कार्य डबल श्टर कंकरीट ब्लाक्स बिजली सेनेटरी एवं छत्री मरम्मत | - | 2500000 | - | - | - |
| 7 | मंदिर श्री दाउजी नान्ता | लाइट फिटिंग कार्य | - | - | - | - | 17000 |

## बाड़मेर जिले के तहसील कार्यालयों में रिक्त पद

371. **श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले के तहसील कार्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) बाड़मेर जिले की तहसील कार्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

(राजस्व राज्य मंत्री)

| क्र.सं. | नाम पद | स्वीकृत | रिक्त |
|---|---|---|---|
| 1 | तहसीलदार | 14 | 0 |
| 2 | नायब तहसीलदार | 18 | 05 |
| 3 | तहसील राजस्व लेखाकार | 19 | 16 |
| 4 | सहा. कार्या. अधीक्षक | 14 | 13 |
| 5 | लिपिक ग्रेड-I | 45 | 35 |
| 6 | लिपिक ग्रेड-II | 62 | 04 |
| 7 | च.श्रे. कर्मचारी | 185 | 101 |
| 8 | भू. अभिलेख निरीक्षक | 148 | 59 |
| 9 | पटवारी | 455 | 170 |
| 10 | वाहन चालक | 05 | 3 |
| **योग** | | **965** | **406** |

सामान्य प्रशासन मद में वर्ष 2013-14 व 2014-15 की लिपिक ग्रेड-I से सहायक कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की गई है। पदस्थापन करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। पदों को भरने की कार्यवाही जैरकार है।

## मांधल (शाहगढ़ पंचायत) में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्यवाही

372. **श्री शैतानसिंह** (पोकरण) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या जैसलमेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के मांधल (शाहगढ़ पंचायत) में अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है? यदि हां, तो उसको रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं व नहीं तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

ग्राम मांधला के खसरा नं. 49 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै.मु. मस्जिद रेकार्ड में वक्त सेंटलमेंट दर्ज हैं। उक्त धार्मिक भवन में लगभग 40 वर्षो से धार्मिक गतिविधियां मस्जिद के रूप में संचालित हैं। वर्तमान में 2 वर्ष पहले मरम्मत व जीर्णोद्धार का कार्य जन सहयोग (श्रद्धालुओं) की सहयोग

(राजस्व राज्य मंत्री)

राशि से श्री हाजी मोरण पुत्र जीयण खां मुसलमान निवासी गणेशिया द्वारा करवाया गया है। उक्त धार्मिक स्थल भवन में वर्ष में दो बार मेला भरा जाता हैं। वर्तमान में उक्त स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

## जैसलमेर जिले में श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

373. **श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में सरकार द्वारा कितने श्रमिक पंजीकृत किये गये हैं? क्या निर्धारित संख्या तक ही श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है?

(2) प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जैसलमेर जिले में गत दो वर्षों में उक्त योजनाओं से कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जैसलमेर जिले में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अन्तर्गत अब तक 11,131 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हिताधिकारी के रूप में किया गया है। जी नहीं, निर्धारित संख्या तक ही निर्माण श्रमिकों का पंजीयन नहीं किया जाता है अपितु ऐसे सभी निर्माण श्रमिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं तथा 60 वर्ष पूर्ण नहीं किये हों एवं जिसने पिछले एक वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, पंजीयन करा सकते हैं।

(2) मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित की जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जैसलमेर जिले में गत 2 वर्षों में 418 निर्माण श्रमिकों को मण्डल द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना-55

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

2. निर्माण श्रमिक के हितार्थ साइकिल सहायता योजना-217

3. शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना-128

4. प्रसूति सहायता योजना-12

5. हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना-4

6. मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना-2

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## फुलेरा में नवीन राजकीय आई.टी.आई. की स्थापना

374. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में सरकार एवं निजी स्तर पर कितनी आई.टी.आई. संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में निजी अथवा सरकारी स्तर पर आई.टी.आई. कब से कहां-कहां पर संचालित हैं व उनमें कौन-कौन से ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई राजकीय आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रदेश में वर्तमान में सरकारी स्तर पर 134 एवं निजी स्तर पर 1598 आई.टी.आई. संचालित हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सरकारी स्तर पर एक आई.टी.आई. तथा निजी स्तर पर 15 आई.टी.आई. संचालित हैं। आई.टी.आई. संचालित वर्ष एवं ट्रेड का विवरण परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में पंचायत समिति सांभर

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

लेक में सरकारी आई.टी.आई. पूर्व से संचालित है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्रदेश में श्रमिक कल्याण की योजनाओं में श्रमिकों का पंजीयन

375. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रमिक कल्याण की योजना के तहत श्रमिकों को देय लाभ किस प्रावधान के तहत दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) श्रमिकों को उक्त योजना में पंजीकृत करने हेतु कौन-कौनसे अधिकारी एवं कर्मचारियों को दायित्व सौंपा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना में सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु किये गये प्रावधानों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम,1996 के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रावधान के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

(3) निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत किए गए हैं :-

1. श्रम विभाग के अधिकारी व निरीक्षक
2. विकास अधिकारी

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

3. सा.नि. विभाग, जन स्वा. अभि. विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सहायक अभियन्ता

4. ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव/ग्राम सेवक व पंचायत स्तर के कनिष्ठ लिपिक

(4) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत देय हितलाभ, पात्रता एवं शर्तों का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

# परिशिष्ट-1

# नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

## पोकरण में जिला परिवहन कार्यालय

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पोकरण उपखण्ड जिला मुख्यालय से लगभग 110 किमी. की दूरी पर स्थित है तथा पोकरण उपखण्ड के नाचना, भारेवाला, नोख, जालुवाला, टावरीवाला व फलसून्ड आदि गांव जिला मुख्यालय से लगभग 200-250 किमी की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में हो उपखण्ड मुख्यालय पोकरण व भजियाला है। इस क्षेत्र के लोगों को परिवहन विभाग के कार्य हेतु जैसलमेर जाना पड़ता है। जिससे लोगों को समय व धन की अनावश्यक हानि के साथ भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पोकरण क्षेत्र में जिला जैसलमेर के पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या में से लगभग 1/2 वाहन पोकरण क्षेत्र के हैं, जिससे इस क्षेत्र में परिवहन कार्यालय खुलने से लोगों के समय व धन की बचत होगी साथ ही उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल पायेंगी।

पोकरण शहर एनएच-15 व एनएच-114 पर स्थित है तथा भारी संख्या में वाहनों का आवागमन लगा रहता है कि क्योंकि कांडला बंदरगाह को पंजाब-हरियाणा व हिमाचल प्रदेश को माल सप्लाई हेतु माल वाहक वाहन एनएच-15 से होकर गुजरते हैं।

विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेवजी का मेला प्रतिवर्ष रामदेवरा गांव में भादवा व माघ मास में भरता है इस मेले में सम्पूर्ण भारतवर्ष से पैदल, साइकिल, मोटर साइकिल व अन्य निजी व सरकारी वाहनों से लाखों की संख्या में यात्रियों का अवागमन होता है और बहुत सी दुर्घटनाएं रोजाना घटित होती हैं।

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसलमेर में प्रतिदिन देशी व विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में भ्रमण पर आते हैं व विश्व प्रसिद्ध मरूमेला भी यहां पर भरता है। इस दौरान लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक जैसलमेर आते हैं। जैसलमेर जाने-आने वाले पर्यटकों को पोकरण होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान भी भारी संख्या में दुर्घटनाएं घटित होती रहती है।

जिला परिवहन कार्यालय हेतु एनएच-114 व एनएच-15 आरटीडीसी मिडवे तिराहे पर पांच बीघा जमीन का आबंटन हो चुका है तथा विधायक मद से 10 लाख रुपये की लागत से कार्यालय हेतु तीन कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे राज्य सरकार पर कार्यालय खोलने हेतु भूमि व भवन हेतु ज्यादा व्यय नहीं पड़ेगा।

अत: पोकरण में परिवहन कार्यालय खुलने से लोगों के समय व धन की बचत होगी साथ ही उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल पायेंगी एवं सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

**शैतानसिंह**

(पोकरण)

## प्रदेश में आदर्श विद्यालय हेतु भूमि आबंटन प्रक्रिया का सरलीकरण

महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धित नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार द्वारा किये गये कार्य देश आजाद होने के बाद पहली बार ऐसी प्रगति राज्य में हुई है। जो गांव प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों को तरसते थे, उन गांव में आज सीनियर स्तर तक के विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्तमान सरकार द्वारा एक साथ क्रमोन्नत करना एवं संचालन करवाकर उन सभी में डी.पी.सी. से लगभग 70 प्रतिशत तक पद भर देना एक ऐतिहासिक कार्य है।

ग्रामीण क्षेत्र के गरीब एवं असहाय बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेतु कहीं भी कोई विद्यालय नहीं था। इस कारण से विद्या अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया जाता था। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षित युवाओं की एक फौज खड़ी हो जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर जनता को राहत प्रदान की है।

सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आदर्श विद्यालय स्थापित किये गये हैं। जो कक्षा 1 से 12 तक संचालित किये जा रहे हैं। यह विद्यालय पूर्व में निर्मित भवनों में ही चलाये जा रहे हैं। भवनों की स्थिति लगभग सभी विद्यालयों में जीर्ण-शीर्ण है। हां, राज्य सरकार द्वारा रमसा के तहत आवश्यकता

वाले विद्यालयों को भवन हेतु बजट आबंटित किया जा रहा है, लेकिन कई स्थानों पर विद्यालय के नवीन भवन हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है। गांव में अमूमन आबादी क्षेत्र के नजदीक औरण, गौचर भूमि के सिवाय किसी भी प्रकार की जमीन नहीं है। अत: सदन के मार्फत मेरा निवेदन रहेगा कि राज्य स्तर पर निर्णय लिया जावे, जहां भी आदर्श विद्यालय सरकार द्वारा घोषित किये गये हैं वहां पर भूमि आबंटन उसी गांव के औरण, गौचर में से बिना क्षतिपूर्ति के आबंटित की जावें। जिससे सभी आदर्श विद्यालय को आधुनिक भवन मिल सकें तथा शिक्षण कार्य सुचारु हो सके।

वर्तमान में जिस आदर्श विद्यालय को भवन बनाने हेतु बजट आबंटित किया जाता है, उस विद्यालय में भवन का निर्माण माडल विद्यालय (स्वामी विवेकानन्द माडल विद्यालय) की तर्ज पर किया जावे जिससे गांव में भी विद्यालयों के भवन बन सकें, जो हकीकत में आदर्श लगने लगे।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन रहेगा कि आदर्श विद्यालय हेतु भूमि आबंटन की प्रक्रिया का सरलीकरण करवाकर भूमि आबंटन की जावें एवं साथ ही जो भवन बनाने की स्वीकृति जारी की जावे, उसमें सवाम विवेकानंद माडल विद्यालय वर्तमान नक्शा संलग्न करके निर्माण कार्य करवाया जावे। उपरोक्त कार्य आवश्यक कदम उठाकर जनहित में किये जावे, तो शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार का कार्य मील का पत्थर साबित होगा।

धन्यवाद।

**हमीरसिंह भायल**
(सिवाना)

## सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में निदेशक भर्ती प्रक्रिया में हो रही अनियमितताएं

महोदय, मैं, सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि :-

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में उप निदेशक एवं सहायक निदेशक की भर्ती प्रक्रिया में अनेक अनियमितताएं की जा रही हैं इस सम्बन्ध में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत करवाये जाने पर भर्ती प्रक्रिया पर जांच होने तक रोक भी लगाई गई थी, परन्तु जांच पूर्ण होने

से पूर्व ही विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल के द्वारा परीक्षा आयोजन के लिए गठित कमेटी के सदस्यों की अनुपस्थिति में बैठक कर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।

अत: उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण में जांच पूरी होने तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाये।

**विजय बंसल (पप्पू बन्डा)**

(भरतपुर)

## शेरगढ़ पंचायत समितियों में रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती

महोदय,

नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति शेरगढ़, बालेसर व सेखाला में विभिन्न सेवा संवर्ग के पद रिक्त होने के कारण विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पंचायत समिति बालेसर में विभिन्न सेवा संवर्ग में स्वीकृत 98 पदों में से 35 कार्यरत व 63 पद रिक्त, पंचायत समिति सेखाला में स्वीकृत 73 पदों में से 19 कार्यरत व विकास अधिकारी सहित 54 पद रिक्त एवं पंचायत समिति शेरगढ़ में स्वीकृत 144 पदों में से 36 कार्यरत व विकास अधिकारी सहित 108 पद रिक्त चल रहे हैं।

इस प्रकार जोधपुर जिले की पंचायत समितियों में स्वीकृत पदों में से औसतन 70 फीसदी पद वर्तमान में भी रिक्त पड़े हैं। पंचायत समितियों में रिक्त पद होने से राज्य व केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, पद रिक्त होने से ज्यादातर ग्राम पंचायतों का काम किसी न किसी कर्मचारी के पास अतिरिक्त प्रभार पर है। किसी कर्मचारी के पास दो तो किसी के पास चार ग्राम पंचायतों का काम है। ऐसे हालात में वे किसी भी एक ग्राम पंचायत का काम भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सेवक के पद माने जाते हैं, जिनकी गांवों के विकास में अहम भूमिका रहती है, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवकों के पद खाली होने से ग्राम सभाओं का आयोजन समय पर नहीं हो रहा है, वहीं मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार के लिए भी आवेदन नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए जरूरी दस्तावेज समय पर जारी ही नहीं हो पा रहे हैं। इनमें जाति, मूल निवास, जन्म-मृत्यु, विवाह सहित अन्य श्रेणी के प्रमाण पत्र, जाब कार्ड, म्यूटेशन व राजस्व से जुडे अन्य कार्य शामिल हैं। इतना ही नहीं, ग्राम

पंचायतों में स्वीकृत विकास कार्यों की स्वीकृत राशि का उपयोग भी इसी वजह से पूरी तरह नहीं हो पा रहा है। इन कार्यों की यूसी समय पर जारी नहीं होने से ग्रामीणों को भुगतान भी समय पर नहीं मिल पाता हैं, नए विकास कार्यों के प्रस्ताव भी बैठक के अभाव में पारित नहीं हो पाते है। यहां तक कि पंचायत समिति की धूरी समझे जाने वाला अधिकारी का पद भी पंचायत समिति सेखाला एवं शेरगढ़ में रिक्त है। इस तरह पंचायत समितियां में विकास अधिकारी से लेकर निचले स्तर के अधिकांश अधिकारियों व कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं इनका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगताना पड़ रहा है।

अतः विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति शेरगढ़, बालेसर व सेखाला में विभिन्न सेवा संवर्ग के इन रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करावें ताकि राज्य व केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके।

**बाबू सिंह**

(शेरगढ़)

## बानसूर में सी.एच.सी. व पी.एच.सी. में रिक्त पद

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत सीएचसी व पीएचसी के रिक्त पदों को भरने के क्रम में निवेदन है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र के सीएचसी बानूसर रामपुर, नारायणपुर एवं पीएचसी हरसोरा गढी, मुण्डावरा, कराना, गुताशाहपुर आदि किसी भी पीएचसी व सीएचसी पर महिला चिकित्सक नहीं है एवं अनेक डाक्टर के पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भरने का कष्ट करें एवं सभी जगह महिला चिकित्सक नहीं लगा सकते तो कम से कम दो ब्लाक पर बानसूर और नारायणपुर में महिला चिकित्सक लगाकर गरीब जनता को अनुग्रहित करें एवं आगे आने वाली ग्रीष्म ऋतु में बुखार आदि का सीजन होता है हर वर्ष कोई ऐसी बीमारी फैलती है जिससे एक दिन बुखार होता है और तुरन्त एक दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, पिछले वर्ष भी डेंगू फैला था जिससे कई गांव के गांव उसकी चपेट में आ गये थे।

अतः सभी पीएचसी व सीएचसी पर फोगिंग मशीन उपलबध करायी जाये जिससे समय रहते डी डी टी पाउडर का छिड़काव कराया जा सके।

**शकुन्तला रावत**

(बानसूर)

## अराई (अजमेर) में नवीन राजकीय महाविद्यालय

माननीय, मैं, सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आर्कषण करना चाहूंगा कि पं.स. एवं तहसील मुख्यालय अराई (अजमेर) पर एवं इसके आसपास स्थित 20-25 ग्राम पंचायतों के 20-25 उमावि 15-20 मावि/बामावि में तथा कई निजी विद्यालयों में लगभग 1000-1100 छात्र-छात्राएं कक्षा 12 में प्रतिवर्ष शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिन्हें 12 में उत्तीर्ण करने के पश्चात उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु 30 किमी दूर स्थित किशनगढ़ (अजमेर) या 48 किमी दूरी पर स्थित मालपुरा (टोंक) या 60 किमी दूरी पर स्थित केकड़ी (अजमेर) या 45 किमी की दूरी पर स्थित दूदू (जयपुर) एवं 65 किमी की दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय अजमेर पर संचालित राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में जाना पड़ता है जिससे इन ग्रामीण बालक-बालिकाओं का अनावश्यक श्रम, समय एवं व्यय का भार पड़ रहा है। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गत वर्ष 2013 में सह-शिक्षा का एक निजी महाविद्यालय ''स्वर्ण रूप महाविद्यालय'' के संचालन की स्वीकृति दी है, जो कि वर्तमान में पर्याप्त स्थानाभाव के कारण पूर्ण रूप से अस्तित्व में नहीं होने से गत 3 शैक्षणिक वर्षो में अराई परिक्षेत्र के छात्र-छात्राओं का उच्च शिक्षा अध्ययन का लाभ देने में असमर्थ रहा है गत शैक्षणिक वर्ष 2014-15 में लगभग 300 विद्यार्थी एवं चालू शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में लगभग 350 विद्यार्थी किशनगढ़ स्थित रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय में अराई कस्बे एवं अराई तहसील के विभिन्न गांवों के अध्ययनरत रहे हैं, यदि किशनगढ़ स्थित निजी महाविद्यालयों एवं केकड़ी, मालपुरा, दूदू, सरवाड़ आदि कस्बों में संचालित निजी एवं राजकीय महाविद्यालयों में उक्त क्षेत्र के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या को भी जोडा जावे तो यह लगभग 500 से भी अधिक का आंकडा हो जाएगा। साथ ही उक्त क्षेत्र के कई ग्रामीण परिवेश के परिवारों द्वारा अपनी लाडली पुत्रियों को दूरस्थ स्थित शहरी क्षेत्रों में संचालित महाविद्यालयों में भिजवाने में संकोचवश एवं सामाजिक असमर्थता के कारण उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु नहीं भिजवा पाते हैं। ज्ञात रहे कि विधान सभा चुनाव 2013 से पूर्व आयोजित सुराज संकल्प यात्रा के दौरान उक्त अराई कस्बे में आयोज्य चुनावी सभा दिनांक 23.11.2013 को माननीया यशस्वी मुख्य मंत्री महोदयाजी ने सार्वजनिक मंच से नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की थी, जिस पर समुचित विभागीय कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है।

अतः उक्त सभा तथ्यों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप उच्च शिक्षा विभाग की आगामी शैक्षणिक सत्र 2016-17 की विभागीय कार्य योजनाओं के तहत अराई (अजमेर) में एक नवीन राजकीय महाविद्यालय के स्थापना की सक्षम विभागीय स्वीकृति प्रदान करावें। आपकी बड़ी महत्ती कृपा होगी।

**भागीरथ चौधरी**

(किशनगढ़)

## जोधपुर शहर में परकोटे के भीतर यातायात व्यवस्था

महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में परकोटे के भीतर ट्रैफिक व्यवस्था इतनी लचड़ है कि हर एक दो घण्टे के अन्तराल में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका मुख्य कारण एक तो शहरी की गलियां संकड़ी है दूसरा सम्पूर्ण बाजार शहर के परकोटे के भीतर समाया हुआ है, तीसरा यातायात विभाग एवं प्रशासन द्वारा एक तरफा यातायात का कोई बन्दोबस्त नहीं किया गया है, चौथा ऊंट छकडी, बैल छकडी, ट्रैक्टर एवं ट्रोली पर शहर के भीतरी क्षेत्र में नहीं जाने से रोकना इत्यादि। जिस कारण आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति के कारण यहां से गुजरने वाले टूव्हीलर, टैक्सी, पैदल चलने वाले नागरिकों के साथ यहां पर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को रोजाना दो चार होना पड़ता है।

पूर्व में मेरे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात, नगर निगम एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं व्यापार मण्डलों के साथ बैठक कर एक तरफा यातायात की कार्यवाही शहर में लागू करवायी गयी थी। जिसमें ट्रैक्टर ट्रोली, ऊंट एवं बैल छकड़ी वाले, एवं बड़े व्हीकल (कैम्पर) जो कि व्यापारियों का माल दुकानों पर खाली करते हैं उन्हें प्रातः 8.00 बजे से पूर्व एवं रात्रि 9.00 बजे पश्चात शहर के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश का आदेश दिया गया था। उस वक्त ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति से छुटकारा भी पाया था एवं स्थानीय नागरिकों ने भी बहुत सराहा था। परन्तु यह व्यवस्था जिला एवं पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते कुछ ही दिन चल पायी और फिर वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति बन गयी।

शहर में जगह-जगह अवैध टैक्सी स्टैण्ड, टैक्सी वालों ने अपने

मनमुताबिक ही बना लिये हैं। इसी के साथ हाथ ठेले वाले जहां चाहे खड़े हो जाते हैं उनके रोकने वाला कोई नहीं है न तो कोई नगर निगम और न ही पुलिस प्रशासन। ऐसी स्थिति में शहर की भयावह स्थिति हो गयी है। आम आदमी शहर के भीतरी बाजारों में जाने से कतराने लगा है जिस कारण यहां के व्यवसायों के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अत: सदन से मेरा आग्रह है कि जोधपुर शहर के परकोटे में यातायात की व्यवस्था सुधारने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जावे। इसी के साथ अवैध रूप से बनाए गए टैक्सी स्टैण्ड को हटाने के साथ परिवहन विभाग द्वारा घोषित टैक्सी स्टैण्ड में निर्धारित से ज्यादा टैक्सियां खड़ी नहीं हों। शहर के भीतरी क्षेत्र में एक तरफा यातायात की व्यवस्था की जावे, इसी के साथ हाथ ठेला जो जगह-जगह सड़कों पर खड़े हैं एवं जो यातायात में बाधक हैं उन्हें तुरन्त प्रभाव से वहां से हटाया जाकर यातायात व्यवस्था सुगम की जावे।

**कैलाश भंसाली**

(जोधपुर)

## देवली-उनियारा में रणथम्भौर अभयारण्य व बीसलपुर बांध के विस्थापितों को आधारभूत सुविधाएं

महोदय,

सरकार द्वारा देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र में रणथम्भौर अभयारण्य एवं बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्रामीणों को विस्थापितों के रूप में बसाया गया था किन्तु 15 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी उक्त विस्थापितों के गांवों को सरकार द्वारा राजस्व ग्राम घोषित नहीं किये जाने के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत आमली के गिर्राजपुरा उर्फ शाहपुराकलां, नासिरदा, रतनपुरा, हिसामपुर, डाबरकला, राजमहल, थावला, बीजवाड़ आदि ग्राम पंचायतों की सैकड़ो ढाणियों में विस्थापित रहते हैं।

1. उक्त ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण विस्थापित ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो रहा है। गिर्राजपुरा में विस्थापित परिवार के बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है। विस्थापितों को आबंटित भूमि की खातेदारी नहीं दी गई है। विस्थापितों को पट्टे जारी नहीं होने के कारण आवास निर्माण करवाने में भी समस्या उत्पन्न होती है। विस्थापितों को

इन्द्रा आवास योजना एवं विधवा महिलाओं को देय आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। उनको विद्युत कनेक्शन करवाने के लिए विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूं कि कृषि भूमि की खातेदारी के अभाव में कृषकों की केसीसी लिमिट नहीं बनने के कारण बैंक द्वारा देय ऋण योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही इस क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं उपचार के लिए 50 किमी दूर अन्य जिले सवाईमाधोपुर में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

2. बीसलपुर डूब क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में बीसलपुर परियोजना द्वारा लगभग 15 वर्षों पूर्व सड़कों का निर्माण करवाया गया था। जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बजट अभाव के कारण बीसलपुर परियोजना द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत एवं पुन: निर्माण नहीं हो पा रह है और न हीं उक्त सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हैण्डओवर की जा रही है।

3. बीसलपुर डूब क्षेत्र में परिवहन सेवा भी काफी खराब है देवली मुख्यालय से मात्र दो बसें संचालित हैं जो सम्पूर्ण डूब क्षेत्र को कवर नहीं कर पाती हैं1 जिससे लोगों को पूर्ण रूप से परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अत: आपसे निवेदन है कि देवली से बीजवाड एवं देवली, डाबरकला, मालेडा एवं हिसामपुर से अजमेर बस सेवा प्रारम्भ करवाई जाए। सरकार द्वारा ग्रामीणों को भूमि अवाप्त करने के लिए नियमानुसार मुआवजा तय किया गया था, परन्तु अधिकांश किसानों को कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। अत: मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उक्त आधारभूत सुविधाओं को पूर्ण करवाने की कृपा करें।

राजेन्द्र गुर्जर

(देवली-उनियारा)

## सरकारी भूमि पर आबाद बस्तियों के नियमितीकरण हेतु नीति निर्माण

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण आबादी भूमि आबंटन सम्बन्धी नियमों की

जटिलता के कारण आबादी भूमि उपलब्ध न होने के कारण किसान व अनय लोग काफी वर्षों से सरकारी भूमियों यथा गोचर, जोहड़, पायतन, वन विभाग, सिवाय चक, औरण आदि भूमियों पर सघन आबादी के रूप में बसे हुए हैं, जिन्होंने छान, छप्पर, झौंपड़ा कच्चे व पक्के मकान बनाकर आबाद है। इसमें अधिकाल परिवार पिछडे व कमजोर तथा गरीब वर्ग के हैं, जिनके लिए भूमि खरीद कर घर बसाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त सरकारी भूमियों पर बसने वाले लोगों को बेदखल करना भी संभव नहीं है। सघन रूप में बसे हुए लोगों को उजाड़ कर बेघर करना एक लोकप्रिय सरकार के लिए आसान नहीं है, बल्कि सम्भव भी नहीं होगा।

सरकारी भूमियों पर बसे हुए लोगों के पास स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज पट्टा आदि नहीं होने के कारण इन्हें पानी, बिजली, ऋण, खुर्रा, नाली आदि आधारभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, सभी सुविधाओं से वंचित होने के कारण उनका जीवन आज के युग में नकारात्मक है। जिसके कारण सरकारी योजनाओं के लक्ष्य भी समय-समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के अन्तर्गत इन्हें शौचालय निर्माण हेतु भी अनुदान नहीं मिल पा रहा है। अन्य अभियानों में भी बाधा पड़ रही है।

अत: लोक कल्याणकारी सरकार को इस सरकारी भूमियों पर वर्षों से आबाद बस्तियों के नियमितीकरण की नीति तैयार करनी चाहिए, ताकि कमजोर पिछड़े किसान वर्ग के वर्षों से आबाद जनता को मालिकाना हक पट्टा आदि मिले जिससे सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ भी मिल सके और स्वच्छ भारत व स्वस्थ भारत, निर्मल ग्राम, जल स्वावलम्बन आदि योजनाएं सफल हो सकें।

धन्यवाद।

**जयनारायण पूनियां**
(तारानगर)

## बड़ी सादड़ी के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के रिक्त पद

महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पदों के सम्बन्ध में निवेदन है कि बड़ीसादड़ी विधान सक्षा क्षेत्र में विद्यालयों के क्रमोन्नत होने के पहले लगभग 80 प्रतिशत पद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पड़े थे। वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर

सभी विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है। विद्यालयों के क्रमोन्नत होने से लगभग व्याख्याताओं के 85 प्रतिशत और वरिष्ठ अध्यापकों के 60 प्रतिशत पद रिक्त हो गये हैं। जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। पिछले सत्र में भी मैंने प्रश्न लगाया था जिसमें विधान सभा क्षेत्र में केवल 20 प्रतिशत व्याख्याता कार्यरत थे फिर भी विद्यालयों में अभी तक भी व्याख्याताओं के 85 प्रतिशत और वरिष्ठ अध्यापकों के 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं। में माननीय शिक्षा मंत्री महोदयजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों के कारण छात्रों की पढ़ाई में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। चूंकि बिना अध्यापक के छात्र पढ़ेंगे तो परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं ला पाएंगे। जिससे सरकारी भर्तियों में भी हमारे क्षेत्र के छात्र पीछे रह जाते हैं सरकारी नौकरियों में नहीं लग पाते हैं। जिससे हमारे क्षेत्र में शिक्षा एवं हर विभाग में अधिकतर पद रिक्त ही पड़े रहते हैं। इसका मुख्य कारण जब छात्रों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने का समय 12वीं कक्षा तक होता है जब अध्यापक रूपी मार्गदर्शक बच्चों को नहीं मिल पाता है और बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है फिर बच्चे हर क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। इन सब का मुख्य कारण अध्यापकों के रिक्त पद हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी को निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में भी कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि बड़ी सादडी विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में काफी पद रिक्त पड़े हैं। उन पदों को भरवाने का कष्ट कराएं।

**गौतम कुमार**

(बड़ी सादड़ी)

## निम्बाहेड़ा में वैदिक विश्वविद्यालय को एण्डोमेंट राशि जमा कराने में शिथिलता

महोदय, राजस्थान विधानसभा के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़, के अन्तर्गत लुप्त होती वैदिक संस्कृति के संरक्षण के लिये उत्तर भारत का प्रथम वैदिक विश्वविद्यालय श्री कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान द्वारा वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना का स्तुत्य प्रयास किया जा रहा है। यह संस्थान सम्पूर्ण समाज की श्रद्धा एवं विश्वास का केन्द्र है। यह संस्थान व्यावसायिक चिन्तन का नहीं होरक पूर्णरूपेण धार्मिक एवं संस्कृति रक्षण को समर्पित है।

मानीनय मुख्य मंत्रीजी के पूर्व कार्यकाल के समय राज्य सरकार द्वारा 30 एकड़ भूमि रियायती दर पर वर्ष 2008 में आबंटित की गई थी। वर्तमान में संस्थान द्वारा 1 लाख फीट से भी अधिक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें चारों वेद भवन, 500 बटुकों की आवास व्यवस्था हेतु छात्रावास, रसोईघर, प्रशासनिक भवन, 20 आचार्य हेतु निवास आदि सहित कई सुविधाओं युक्त भवनों का निर्माण किया जा चुका है साथ ही आधुनिक गौशाला संचालित है।

विश्वविद्यालय निर्माण प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एलओआई जारी कर एण्डोमेन्ट राशि रुपये दो करोड़ जमा कराने हेतु निर्देशिता किया हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि माननीया मुख्यमंत्रीजी एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी कालीचरण जी सराफ सा. भी इस परिसर का अवलोकन कर चुके हैं एवं इस विश्वविद्यालय को पूर्णता प्रदान करने के लिए आश्वासित किया है।

विगत 5000 वर्षों में इस वैदिक परम्परा का जो पतन हुआ जिसमें ऋग्वेद की 21 शाखा में से 3, यजुर्वेद की 101 शाखाओं में से 6, सामवेद की 1000 शाखाओं में से 3 एवं अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से 3 शाखाएं ही शेष बची हैं। इस प्रकार लुप्त होती हुई वेद की शाखाओं को निम्बाहेड़ा जैसे एक छोटे से स्थान पर वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना करके इस संस्थान द्वारा राष्ट्र में एक नयी सांस्कृतिक चेतना का सूत्रपात किये जाने का अमूल्य प्रयास किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से वेदों की पुनः प्रतिष्ठा होगी, साथ ही तत्सम्बन्धी अनुसंधानों को एक नयी दिशा प्रदान करने का प्रयत्न होगा।

इस विश्वविद्यालय में चारों वेदों के अध्ययन एवं शोध के साथ-साथ आयुर्वेद, धर्नुवेद, गंधर्ववेद, भारतीय शिल्प, दर्शन, संगीत, खगोल विज्ञान, आदि विषयों से सम्बन्धित शास्त्रीय एवं प्रायोगिक परम्परा का अध्ययन एवं अनुसंधान किया जावेगा इसके साथ ही पत्रकारिता, प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिक, कम्प्यूटर, एवं विधि शास्त्र के अध्ययन की भी व्यवस्था होगी।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह है कि यह विश्वविद्यालय अन्य व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की तरह से अर्थोपार्जन के लिये नहीं होकर शुद्ध रूप से धार्मिक आस्था को बढ़ाने वाला संस्कृतिरक्षण को समर्पित विश्वविद्यालय है। अतः इस विश्वविद्यालय को पूर्णता प्रदान करने के लिये निर्धारित एण्डोमेन्ट मनी राशि जमा कराने में शिथिलता प्रदान कर इस

विश्वविद्यालय को विशेष राहत दिलाते हुए इसकी पूर्णता के लिये नि:शुल्क एवं अन्य प्रकार से राजकीय सहयोग प्रदान कराएं।

सादर,

**श्रीचन्द कृपलानी**

(निम्बाहेड़ा)

## कोटा जिले के ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर सिजेरियन प्रसव की व्यवस्था

महोदय, राजस्थान विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत कोटा जिले के ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर सिजेरियन प्रसव के लिये व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में

निवेदन है कि कोटा जिले की नई जनगणना के अनुसार कोटा नगर व ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 10-10 लाख के लगभग है। मैं यहां आपका ध्यान कोटा नगर के एकमात्र महिला चिकित्सालय जेके लोन अस्पताल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां प्रतिदिन 40 से 50 डिलीवरी होती हैं, जो प्रतिमाह 1500 के लगभग बैठती हैं। इसके अतिरिक्त जिले के सभी राजकीय व निजी प्रसूति गृहों की संख्या को जोड़ा जावे तो यह लगभग 5000 पर पहुंचती हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं एवं 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिसमें से 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 2 सब सेन्टरों पर ही प्रसूति की व्यवस्था है। पूरे जिले में लगभग 45 हजार से 50 हजार के बीच प्रसूतियां राजकीय व निजी चिकित्सालयों में होती हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी लगभग दस हजार हैं। इस दस हजार की संख्या में पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानपुर, इटावा व खातौली की भागीदारी लगभग 2500 की है लेकिन इटावा सीएचसी में जहां प्रतिमाह 180 से 200 के बीच डिलेवरी होती हैं जो जेके लोन चिकित्सालय के बाद ग्रामीण क्षेत्र की सर्वाधिक संख्या है।

आज ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति को दौड़कर प्रसूति के लिये कोटा आना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जो व्यवस्थाएं हैं वह चिन्ताजनक हैं व पूरे जिले में मात्र कैथून सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ही सिजेरियन व्यवस्था हो रही है जिसकी स्थिति भी महीने में 2 से 5 तक ही सीमित है। जेके लोन के गायनो

प्रभारी डा. आर.पी. रावत के अनुसार जेके लोन में 15 से 20 सीजेरियन आपरेशन प्रतिदिन होते हैं। उसमें से 75 प्रतिशत आपरेशन ग्रामीण क्षेत्र के होना बताया गया है। खातौली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटा से 120 कि.मी. इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 80 कि.मी. दूर स्थित है। जहां इन केन्द्रों पर सिजेरियन की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय चिकित्सकों के रेफर करने के कारण 960 प्रसूताएं जेके लोन व 100 प्रसूताएं न्यू मेडिकल कालेज कोटा को रेफर की गई व लम्बे समय के कारण कई बार रास्ते में ही दुर्घटनाएं घटित होती हैं। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि जहां जिले की दूसरे नम्बर की सर्वाधिक डिलेवरियां इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होती हैं वहां सिजेरियन प्रसूति की व्यवस्था करने की कृपा करें।

**विद्याशंकर नन्दवाना**

(पीपल्दा)

# परिशिष्ट-2

## मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

**श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में उपखण्ड सांचौर मुख्यालय पर कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री तरुण राय कागा** (चौहटन) :

3. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री ओमप्रकाश** (महुवा) :

4. विधान सभा क्षेत्र महुवा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालाहेडी व सांथा में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री ललित कुमार** (किशनगंज) :

5. बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद में संचालित विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री बाबू सिंह** (शेरगढ़) :

6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड शेरगढ़ मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में शिक्षकों की कमी के कारण ग्रामीणों एवं विद्यार्थियों द्वारा तालाबंदी करने के प्रकरण प्रकाश में आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।
8. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में संचालित विद्यालयों में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।
9. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, शेरगढ़ को शास्त्री महाविद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**सुश्री कीर्तिकुमारी** (माण्डलगढ़) :

10. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के उपखण्ड पर विद्यालय भवन निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) :

11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में हाडारानी राजकीय महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में पीने के पानी, विद्युत किचन शेड, टायलेट एवं शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विद्यालयों के क्षतिग्रस्त भवन एवं कक्षा कक्षों की मरम्मत कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये खण्ड-स्तर पर स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री खेमाराम** (सुजानगढ़) :

16. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री भजनलाल जाटव** (वैर) :

17. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम झालाटाला में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

18. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम पंचायत मोलोनी व आमोली एवं अन्य ग्राम पंचायतों में नवीन बालिका विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

19. विधान सभा क्षेत्र वैर की ग्राम पंचायत चक धरसोनी में उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

20. विधान सभा क्षेत्र वैर में नवीन महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री खेमाराम** (सुजानगढ़) :

21. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

22. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के बिदासर (चूरू) में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन) :

23. विधान सभा क्षेत्र कपासन के विद्यालयों में अध्यापकों, व्याख्याताओं एवं प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

24. विधान सभा क्षेत्र कपासन के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्षों एवं अपूर्ण चारदीवारी बनाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

25. विधान सभा क्षेत्र कपासन में ग्राम पंचायत मुख्यालय करूकडा (कपासन) में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री रामचन्द्र** (डग) :

26. विधान सभा क्षेत्र डग में परापीपली, गंगधार, क्यासरा, कोल्वी हत्था गोड, बोद्ध गुफाएं इत्यादि स्थानों पर धार्मिक महत्व एवं पौराणिक धरोहर के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

27. विधान सभा क्षेत्र डग के क्यासरा में वेद विद्यालय को पूर्ण सुविधाएं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

28. विधान सभा क्षेत्र डग में बिस्तुनिया (पचपहाड़) को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री कुंजीलाल** (बामनवास) :

29. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) :

30. राजस्थान की कला एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखने वाली लंगा मागणियार जाति के शैक्षिक एवं संवर्द्धन हेतु योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

31. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुरटाला गाला को उच्च माध्यमिक में एवं मंगरा मुख्यालय पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।
32. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय उण्डखा को उच्च माध्यमिक में एवं आटी मुख्यालय पर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय आटी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।
33. प्रदेश में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती एवं विद्यार्थी मित्रों के समायोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) :

34. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पंचायत समिति के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हरिसिंह रावत** (भीम) :

35. विधान सभा क्षेत्र भीम के प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री भीमा भाई** (कुशलगढ़) :

36. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के मामाबालेश्वर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री समाराम गरासिया** (पिण्डवाडा-आबू) :

37. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
38. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के मुख्यालय पिण्डवाड़ा में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्रीमती शकुन्तला रावत** (बानसूर) :

39. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बानसूर में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।
40. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बानसूर में महाविद्यालय खोलने एवं नारायणपुर में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री सुशील कटारा** (चौरासी) :

41. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ग्राम पंचायत पोहटी खातुरात में स्वामी विवेकानन्द आवासीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

42. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ग्राम पंचायत पोहरी खातुरात कस्तूरबा बालिका छात्रावास की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की चारदीवारी बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

45. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर) :

46. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के झालामण्ड, मधुवन क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़) :

47. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय संस्कृत विद्यालय थली, नांगल बेला एवं जयचन्दपुरा को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

48. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के चारदीवारी विहीन स्कूलों की चारदीवारी निर्माण करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

49. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री शंकर सिंह** (ब्यावर) :

51. ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

52. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

53. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री छोटू सिंह** (जैसलमेर) :

54. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के स्कूलों के भवनों की मरम्मत कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. जैसलमेर जिले के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

56. जैसलमेर जिले के समस्त विद्यालयों में खेल मैदान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

57. जैसलमेर जिले के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) :

58. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घनला में एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र एवं अध्यापक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री दलीचन्द डांगी** (मावली) :

59. विधान सभा क्षेत्र मावली में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

60. विधान सभा क्षेत्र मावली में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

61. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

62. विधान सभा क्षेत्र मावली में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने एवं वंचित पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

63. विधान सभा क्षेत्र मावली में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमली स्टेशन को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेमली से मुक्त कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय आसना में समायोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हीरालाल नागर** (सांगोद) :

64. विधान सभा क्षेत्र सागोद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों को आबंटित खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

65. विधान सभा क्षेत्र सागोद के विद्यालयों में छात्रों के अनुपात से अधिक शिक्षकों को हटाकर रिक्त पदों पर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

66. विधान सभा क्षेत्र सागोद के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा कक्षों व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

67. विधान सभा क्षेत्र सागोद के पर्यटन केन्द्र ग्राम डुगरज्या एवं उदपुरिया के तालाबों का विकास करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

68. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम थुनपुर में स्थित भगवान सुखराय मन्दिर का विकास एवं निलमजड़ित शिव मन्दिर चार चौसा के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बंशीधर** (खण्डेला) :

69. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के स्कूलों में विषय अध्यापकों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) :

70. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय धर्मचन्द गांधी महाविद्यालय में स्नातक विज्ञान संकाय की कक्षाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

71. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ में महिला राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

72. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता एवं विषय अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

74. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर) :

75. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर वागड कला केन्द्र की स्थापना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

76. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय विधि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

77. डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्नातकोत्तर भौतिक एवं रसायन विज्ञान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री जयराम जाटव** (वैर) :

79. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीजवाड़ को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

80. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नेथला पंचायत समिति उमरेण को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

81. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राजकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम हाजीपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

82. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम चिकानी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) :

83. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

84. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" के तहत विद्यालयों में कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

85. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उपखण्ड मुख्यालय बड़ी सादड़ी व डूंगला में खेल मैदान पर स्टेडियम निर्माण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

86. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं) :

87. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के विभिन्न राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

88. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के दोरासर में स्वीकृत सैनिक स्कूल को शीघ्र प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

89. जिला मुख्यालय झुंझुनूं पर स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

90. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में राजकीय आर.आर. मोरारका महाविद्यालय झुंझुनूं में प्राध्यापकों के रिक्त पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा) :

91. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

92. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

93. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीवाड़ा कला एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीवाड़ा में गणित, भूगोल व विज्ञान विषय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) :

95. प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के विद्यालयों में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में विभाग में एसटी/एससी के बैक लाग को भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

98. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में महुवा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोहरा भुल्ला में कक्षा कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

**श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) :

99. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के प्रसिद्ध हल्देश्वर महादेव मंदिर में पेनोरमा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

100. सिवाना के दुर्ग को कला एवं संस्कृति विभाग में सम्मिलित कर सौन्दर्यकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

101. बाड़मेर के पर्यटक स्थलों को कला एवं संस्कृति विभाग में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

102. सिवाना के सीनियर विद्यालय में कृषि विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

103. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायतों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं सैकेण्डरी विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (सिवाना) :

104. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर के कुन्हाड़ी में नवीन महाविद्यालय खोलने एवं विभिन्न स्कूलों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि विषय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) :

105. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा विद्यालयों में कक्षा कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

**श्री नाना लाल अहारी** (खैरवाड़ा) :

106. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पर्याप्त शिक्षक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

107. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ऋषभदेव में संस्कृत विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

108. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के पाटिया सीनियर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

109. प्रदेश में पांचवी एवं आठवीं कक्षा का परीक्षा पैटर्न बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

110. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के सागवाड़ा एवं गडावण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री भागीरथ चौधरी** (किशनगढ़) :

111. प्रदेश में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8, 10 एवं 12 के बालक-बालिकाओं को भी उपखण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रोत्साहन स्वरूप टेबलेट, लैपटाप एवं साइकिल वितरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में सम्मिलित कर देश के संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के तहत समानता के अधिकार की महत्ता बनाये रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

112. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के प्रमुख कस्बे अराई में ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को समुचित उच्च शिक्षा अध्ययन का लाभ दिलाने हेतु शैक्षणिक सत्र 2016-17 में एक नवीन राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति जारी कराने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. प्रदेश के 20 जिला मुख्यालयों से अधिक जनसंख्या वाले किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर संचालित रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विधि संकाय में अध्ययन की स्वीकृति अथवा नवीन विधि महाविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

114. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के तहसील मुख्यालय अराई में नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

115. सर्वाधिक नामांकन वाला बालक विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ में पर्याप्त कक्षा-कक्षों के अभाव होने से समुचित एवं सुगम शिक्षा अध्ययन का लाभ बालकों को दिलाने हेतु मदनगंज क्षेत्र में स्थित राजकीय शार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त एवं समुचित भवन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र 2016-17 में जीव विज्ञान, वाणिज्य संकाय में अध्ययन की स्वीकृति जारी कराने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री अशोक डोगरा** (बूंदी) :

116. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के बूंदी शहर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रजत ग्रह कालोनी को उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री मान सिंह** (गंगापुर) :

117. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अहमदपुर को पुनः प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

118. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर में महुकला, श्यारोनी एवं गच्छीपुरा पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के गंगापुरसिटी में गर्ल्स कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

120. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के वजीरपुर-उपरवास में कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)** (भरतपुर) :

121. भरतपुर के महारानी श्रीजया कालेज के खेल मैदान को स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

122. भरतपुर के महारानी श्रीजया कालेज के खेल मैदान पर पुलिस द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

123. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में आर.डी. गर्ल्स पी.जी. कालेज में स्नातक में भूगोल विषय पी.जी. में केमेस्ट्री एवं राजनीतिक विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

124. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत रूधड़करन के ग्राम बझेरा के माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में एवं ग्राम पंचायत मंडरूपुर के ग्राम बराखुद के मिडिल स्कूल को माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामपाल** (बारां-अटरू) :

125. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में अटरू उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री शंकरसिंह राजपुरोहित** (आहौर) :

126. विधान सभा क्षेत्र आहौर के महाविद्यालय आहौर में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

127. विधान सभा क्षेत्र आहौर में बालिका शिक्षा को मजबूती देने हेतु पंचायत मुख्यालय पर बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) :

128. विधान सभा क्षेत्र लूणी की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा (कुड़ी), मोगड़ा कलां, दुन्दाड़ा एवं सांगरिया में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

129. विधान सभा क्षेत्र लूणी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीपरली, लूणावास खारा, मोडी जोशियान, पाल, चौखा, झालामण्ड, बड़ली, माणकलाव, चाली, सर एवं नाहरों की ढाणी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

130. विधान सभा क्षेत्र लूणी की नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालयों तनावड़ा, कांकणी, धांधिया, महोदव नगर (उन्देड़ा की ढाणी) सालोड़ी, नान्दड़ी, बम्बोर दर्जियान एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेलबा, दुदिया एवं बम्बोर पुरोहितान को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

131. विधान सभा क्षेत्र लूणी के उपखण्ड मुख्यालय लूणी में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

132. विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत झंवर में नई आई.टी.आई. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) :

133. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के माध्यमिक विद्यालय सुखपुरिया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

134. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सांगा बाबा की मूर्ती लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

135. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में संघीजी जैन मन्दिर के सौन्दर्यकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामहेत सिंह यादव** (किशनगढ़ बास) :

137. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुढीबावल, जौडिया, कतोपुर, नांगल सालिया, पाटन अहीर, खानपुर मेवान, माछरोली एवं कोलगांव में विज्ञान संकाय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीबीरानी में गृह विज्ञान एवं चित्रकला विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

138. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

139. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के सभी राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) :

140. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में मुख्य मंत्री की घोषणा "प्रत्येक पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने" को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

141. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाट बहरोड़ में साइंस विषय एवं मुण्डावर सब डिविजन हैड क्वार्टर पर बायलोजी विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) :

142. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम अणतपुरा-जैतपुरा एवं नांगल-गोविन्द के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

143. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा, किशनमानपुरा, बासा, आलीसर, विमलपुरा के विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

144. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के सभी विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

145. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा, मोरीजा, सीगोद-खुर्द एवं आठटी के विद्यालयों में कमरे निर्माण के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री प्रहलाद गुंजल** (कोटा उत्तर) :

146. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में पुरानी जीर्ण-शीर्ण इमारतों में संचालित विद्यालयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) :

147. प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अध्यापकों की नियुक्ति छात्रानुपात में करने एवं अध्यापकों को हैड क्वार्टर पर रहने हेतु पाबन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

148. प्रदेश के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन से शिक्षकों की उपस्थिति एवं उसके प्रिंट का संस्था प्रधान द्वारा वेतन बिल के साथ प्रमाणीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

149. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिक्त चल रहे पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

150. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ग्राम मोडक गांव, सातखेड़ी सुकेत के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

151. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी) :

152. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में अंग्रेजी माध्यम का माडल विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी में कृषि संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के सभी शिक्षण संस्थाओं में मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री कैलाश चौधरी** (बायतू) :

157. विधान सभा क्षेत्र बायतू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बायतू (बाड़मेर) में कृषि विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र बायतू में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, बायतू में अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र बायतू में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बायतू (बाड़मेर) में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री गोरधन** (धोद) :

160. विधान सभा क्षेत्र धोद में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थौरासी खरसाडु (पलसाना) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र धोद के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिंगरावर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र धोद में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र धोद में ग्राम शाहपुरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र धोद के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सरवड़ी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री दर्शन सिंह** (करौली) :

165. विधान सभा क्षेत्र करौली के विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव में छात्रों के भविष्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र करौली के विद्यालयों में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम ल्हावद के उच्च प्राथमिक कन्या शाला को क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम पंचायत धवाइन में सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) :

169. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में शेखावटी की प्राचीन भित्ती चित्र कला को विकसित करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. सीकर जिले के समस्त मिडिल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब पूर्ण संसाधनों सहित उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. शेखावटी के प्रसिद्ध गींदड़ नृत्य को प्रोत्साहित करने की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. जिला सीकर के विद्यालयों में खेल मैदान बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. प्रदेश में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती अनीता** (नगर) :

174. विधान सभा क्षेत्र नगर में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) :

175. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आभानेरी के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के राजेश पायलट कालेज में एस.एफ.एस में चल रहे विज्ञान एवं हिन्दी विषय का सरकारीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती अनिता कटारा** (सागवाड़ा) :

177. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पादरड़ी बड़ी सागवाड़ा में जीव विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के छोटी पादरड़ी में माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**मास्टर मामनसिंह यादव** (तिजारा) :

179. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के ग्रामों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**राजकुमारी दियाकुमारी** (सवाई माधोपुर) :

180. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में नवीन महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय और शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह पी.जी. महाविद्यालय में नये विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर) :

182. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठण्डी में कृषि विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठण्डी में अतिरिक्त राजनैतिक विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. प्रदेश में प्रायोगिक विषय के साथ पंजाबी विषय में स्नातकधारी विद्यार्थियों को बी.एड (B.ed) करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र राययिंहनगर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्कयकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) :

186. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय अल्पभाषा राजमहल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 सेक्टर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शोभावतों की ढाणी एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलेदव नगर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभाव को दूर करने हेतु

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट परिसर में शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सम्राट अशोक उद्यान में बने खुले रंगमंच को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को हस्तान्तरित कर इसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक कला प्रदर्शन और रंगमंच आयोजन के केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवांची गेट में जीव विज्ञान विषय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप नगर में विज्ञान संकाय आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालीबेरी एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कालीबेरी के संयुक्त खेल मैदान को शाला क्रीड़ा संगम की तर्ज पर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री नवनीत लाल** (घाटोल) :

191. विधान सभा क्षेत्र घाटोल हैड क्वार्टर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के गांव गनोड़ा में छात्र एवं छात्राओं के लिए संस्कृत प्रशिक्षित बी.एस.टी.सी. सेन्टर खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जगसी राम** (रेवदर) :

193. राज्य में खोले गये विवेकानन्द माडल सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की पूर्व निर्धारित स्वीकृत संख्या में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में भूगोल, विज्ञान विषयाध्यापक एवं लैब-इन्स्ट्रूमेंट्स, प्रायोगिक आइटम्स उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांतराई में बोर्ड परीक्षा केन्द्र पुन: प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के सरकारी स्कूलों में जर्जर पड़े एवं अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक, व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) :

198. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) :

199. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के ग्राम पंचायत मुख्यालय जहाज में माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़) :

200. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. राज्य की विभिन्न साहित्य, कला व संस्कृति अकादमियों को पर्याप्त अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

202. राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ में रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के प्रति बरते जा रहे भेदभाव व उपेक्षा के कारण संस्कृत शिक्षा पर पड़ रहे प्रतिकूल असर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) :

204. छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ में स्व-वित्त पोषित विज्ञान संकाय को राज्याधीन लेकर स्वीकृत करने एवं कला संकाय में संस्कृत विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, निम्बाहेड़ा में वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय में गणित विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के छोटी सादड़ी में नव क्रमोन्नत हुए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, कनेरा पंचायत समिति निम्बाहेड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री नरेन्द्र कुमार** (मण्डावा) :

209. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में सरकारी कालेज व मलसीसर तहसील में सरकारी बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

**श्री गोपाल कृष्ण** (बीकानेर-पश्चिम) :

210. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में कन्या महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा) :

211. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. टोडारायसिंह शहर के मूर्तिकला व्यवसाय को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह शहर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के मालपुरा शहर में राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) :

215. अलवर में संचालित उच्च शिक्षा महाविद्यालयों में अनुपलब्ध विषयों को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

216. राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में कुलपति की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के रेलवे पटरी पार क्षेत्र में बालिका शिक्षा हेतु सीनियर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) :

218. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में पोलीटैक्निक कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. मारवाड़ जंक्शन पर महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में रानी उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के तहसील रानी में ग्राम खिवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान एवं गणित विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री नवीन पिलानिया** (आमेर) :

222. विधान सभा क्षेत्र आमेर में महाविद्यालय एवं ग्राम पंचायतों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) :

223. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कोटड़ी में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पूर्व में खोले गये राजकीय महाविद्यालय का संचालन पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**डा. मंजू बाघमार** (जायल) :

225. विधान सभा क्षेत्र जायल के जायल में स्थित सरकारी महाविद्यालय की लाइब्रेरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र जायल के जायल में स्थित सरकारी महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. जायल स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों को (अशैक्षणिक/कम्प्यूटर शिक्षक) भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र जायल के मिडिल एवं माध्यमिक स्तर के स्कूलों में 'नैतिक शिक्षा' अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती अलका सिंह** (बांदीकुई) :

229. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आभानेरी को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के पुदरपाड़ा व पीचूपाड़ा खुर्द के विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में झाझीरामपुरा पुरामहत्व के मंदिर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा** (चाकसू) :

232. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय वार्ड नं. 1 चाकसू को उपाध्याय स्तर तक क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के विद्यालयों में अध्यापकों के सभी रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. उपखण्ड मुख्यालय चाकसू में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) :

235. प्रदेश में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा माध्यमिक शिक्षा में निर्धारित टैक्स्ट पुस्तकों में राज्य स्तर पर परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. प्रदेश में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

238. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) :

239. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सभी उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. कोटपूतली शहर में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) :

241. विधान सभा क्षेत्र सोजत के गुडा बच्छराज ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र सोजत में राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय देवली कला एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाखरा को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री रमेश** (सपोटरा) :

243. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के विद्यालयों में विषय अध्यापकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री भंवरसिंह** (कोलायत) :

246. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब को चालू करने एवं कम्प्यूटर शिक्षा प्रत्येक विद्यालय में चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों मय नवगठित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में पिछले वर्ष 2014 में विद्यार्थी मित्रों को हटाने से दो दर्जन से भी अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद होने से वहां के विद्यार्थियों को अनिवार्य शिक्षा से वंचित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

249. बजट घोषणा 2016-17 में बीकानेर में प्रस्तावित तकनीकी विश्वविद्यालय को इसी सत्र में चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. बीकानेर जिले के कोलायत ब्लाक में झझू गांव में माडल विद्यालय को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री संजीव कुमार** (भादरा) :

251. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. प्रदेश में प्रतिबंधित जिलों (डार्क जोन) से अन्य जिलों में शिक्षकों के स्थानान्तरण करने की छूट दिलवाकर नई स्थानान्तरण नीति बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

254. भादरा (जिला-हनुमानगढ़) में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र भादरा के विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) :

256. पाली शहर के नया गांव एवं मंडिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

257. पाली जिले के उपखण्ड मुख्यालय रोहट में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण) :

258. राज्य के कोटा एवं अन्य शहरों में कोचिंग लेने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा आत्महत्या के बढ़ते प्रकरणों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

259. राज्य के सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम को सी.बी.एस.ई. व एन.सी.ई.आर.टी. के समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

260. कोटा जिले में प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण हेतु विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

261. प्रदेश में राजस्थानी भाषा के संरक्षण एवं राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा) :

262. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के छीपाबड़ौद वित्त-पोषित महाविद्यालय को राजकीय दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा करें ।

**श्री मनोज कुमार** (सादुलपुर) :

263. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) :

264. राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों के गलत मुद्रण पर मुद्रकों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा विधि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 1994 से 2004 की डिग्रियां नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

265. जल महल जयपुर में बने हुए संजय शर्मा संग्रहालय को जयपुर के दर्शनीय स्थलों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

266. जयपुर शहर (पूर्व) के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा बी.एल.ओ. के कार्य के दौरान फर्जी डी.एल. प्रस्तुत कर स्कूलों से अनुपस्थित रहने वाले अध्यापकों की डी.एल. की जांच नहीं करने व स्कूल के उपस्थिति रजिस्टर व डी.एल. में अन्तर होने की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

267. जयपुर सम्भाग के दौसा जिले में तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों की द्वितीय श्रेणी में पदौन्नति के वर्ष 2015 में आदेशों में वरिष्ठता का उल्लंघन कर अनियमित पदौन्नति देने एवं पदौन्नति के वास्तविक हकदारों को अब तक पदौन्नति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

268. संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय के सेवा नियम स्कूल शिक्षा से पृथक बना कर लागू करने एवं कालेज शिक्षा के समान पृथक आयुक्तालय बनाने जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2015 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदौन्नति नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री सुरेश धाकड़** (बेगूं) :

269 विधान सभा क्षेत्र बेगूं में गंगरार के विद्यालयों में गुजराती विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

270. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री भंवर लाल** (सरदारशहर) :

271. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम मेलूसर पुरोहितान एवं मालासर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

272. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्रीमती कामिनी जिन्दल** (गंगानगर) :

273. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत मुख्यालय 21 जीजी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

274. श्रीगंगानगर शहर के वार्ड नं. 45 रविदास नगर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 3 एवं बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नं. 1 एक ही भवन में संचालित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

275. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 9 एमएल के गांव मलकानी में अघोषित रूप से बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय को पुनः प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

276. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत मुख्यालय 8 एचएच (ढिगावाली) में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) :

277. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री हीरालाल** (निवाई) :

278. विधान सभा क्षेत्र निवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाय में विज्ञान संकाय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

279. विधान सभा क्षेत्र निवाई में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शेष रहे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

280. विधान सभा क्षेत्र निवाई में तहसील मुख्यालय पीपलू में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

281. विधान सभा क्षेत्र निवाई के राजकीय महाविद्यालय निवाई में पी.जी. संकाय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर) :

282. विधान सभा क्षेत्र नागौर की बालिका सैकण्डरी विद्यालय बासनी व अलाय को सीनीयर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

283. विधान सभा क्षेत्र नागौर में मांडी बाई मिर्धा महिला महाविद्यालय में वाणिज्य व विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) :

284. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में प्रत्येक पंचायत स्तर पर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

285. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं-पीने का पानी एवं बालिका शौचालय इत्यादि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री अजीत सिंह** (टोंक) :

286. विधान सभा क्षेत्र टोंक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नं. 12 टोंक को पुलिस विभाग के अतिक्रमण से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

287. विधान सभा क्षेत्र टोंक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरन, हरचन्देड़ा, चिरोंज, गोपालपुरा, कुहाड़ाखुर्द, छाणबाससूर्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोरभाटियान में प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर लैब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

288. टोंक ब्लाक में माडल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

289. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक में स्नातकोत्तर कक्षा में जीव विज्ञान एवं संस्कृत विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

290. राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक में विज्ञान संकाय खोलने एवं पी.जी. कालेज में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री कृष्णा कड़वा** (संगरिया) :

291. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वेहरवाला कलां तहसील टिब्बी को सह-शिक्षा (को-एजुकेशन) में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

292. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय मेहरवाला तहसील टिब्बी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

293. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरानी, तहसील टिब्बी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

294. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नगराना तहसील संगरिया को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

295. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के राजकीय माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा उत्तराधा, तहसील संगरिया को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्रीमती शिमला बावरी** (अनूपगढ़) :

296. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

297. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरावाली में कृषि संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

298. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में वंचित रहे नवीन ग्राम पंचायत स्तर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

299. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सेठ बिहारी लाल राजकीय महाविद्यालय के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

300. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में लैला मंजनू दरगाह की सुविधा के विस्तार की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री गोपाल कृष्ण** (बीकानेर पश्चिम) :

301. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में राजस्थानी कला चित्रों को सभी इमारतों में प्रकाशित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री झाबर सिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) :

302. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

303. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) के संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

304. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीमाधोपुर (सीकर) में विज्ञान संकाय (जीव विज्ञान-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित) खोलने एवं शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

305. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होल्याकाबास (सीकर) में विज्ञान संकाय खोलने एवं शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

306. उपखण्ड मुख्यालय श्रीमाधोपुर (सीकर) में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) :

307. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सभी विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

308. प्रदेश के विद्यार्थी मित्रों का स्थाईकरण कर पुन: नौकरी पर रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) :

309. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर संस्कृत स्कूल प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

**श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर) :

310. विधान सभा क्षेत्र जालौर के सायला उपखण्ड क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विषय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

311. जालौर में तोपखाना स्थित राजा भोज की संस्कृत पाठशाला प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

312. राजकीय महिला महाविद्यालय जालौर में उपाचार्य का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

313. विधान सभा क्षेत्र जालौर सायला उपखण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

314. विधान सभा क्षेत्र जालौर के सायला उपखण्ड के ग्राम जीवाणा में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती सुशील कंवर** (मसूदा) :

315. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

316. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा) :

317. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के कालीबंगा में प्राचीन सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

318. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

319. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय मिराजवाला को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

320. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

321. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोड़ा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) :

322. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की बाघावास स्थित सीनियर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

323. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

324. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर स्थित महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

325. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की आकोदा, मलिकपुर एवं अणतपुरा स्थित विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

326. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) :

327. विधान सभा क्षेत्र खींवसर एवं नागौर में शिक्षकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

328. प्रदेश में वर्ष 2012 की शिक्षकों की भर्ती के 40,000 पदों को नियमित कर, नियमित वेतन श्रृंखला में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों को शिक्षा सहायकों के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

330. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री शंकर लाल शर्मा** (दौसा) :

331. राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय दौसा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

332. विधान सभा क्षेत्र दौसा की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

333. विधान सभा क्षेत्र दौसा के महिला महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) :

334. भोपालगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर नवोदय विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

335. प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अंग्रेजी के ज्ञान हेतु अंग्रेजी अध्यापक नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

336. प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री शत्रुघ्न गौतम** (केकड़ी) :

337. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सरवाड़ मुख्यालय पर ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

338. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में केकड़ी कस्बे में राजकीय पायलट माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

339. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में सावर तहसील क्षेत्र पर नवीन संस्कृत महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

340. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री राजेन्द्र सिंह भादू** (सूरतगढ़) :

341. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री अशोक** (हिण्डौली) :

342. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली (बून्दी) के उपखण्ड मुख्यालय नैंनवां में स्व-वित्तपोषित योजना में संचालित भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा महाविद्यालय नैंनवां को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री नन्दकिशोर महरिया** (फतेहपुर) :

343. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के फतेहपुर कस्बे में सरकारी कालेज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

344. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के स्कूलों में रिक्त पड़े विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

345. सीकर जिले में संचालित आदर्श सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

346. प्रदेश के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

347. फतेहपुर सहित शेखावाटी की लोक कला व संस्कृति को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) :

348. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के ग्राम पंचायत मुख्यालय जहाज में माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

349. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के ग्राम पंचायत पापड़ा मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

350. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्यू उदयपुरवाटी को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

351. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

**श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) :

352. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

353. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में स्थित पुरा महत्व के दरवाजों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

# परिशिष्ट-3

## लिखित वक्तव्य

### श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (राज्य मंत्री, पर्यटन) का मांग संख्या 24 के जवाब में सदन पटल पर रखा गया लिखित वक्तव्य

राजस्थान की सुन्दर ऐतिहासिक धरोहर, अमूल्य संस्कृति को सदैव सुरक्षित तथा संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण (ADMA) एवं ''राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण (RHPPA)'' प्रयासरत है।

संगीत एवं लोक नृत्य के संवर्द्धन के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर एवं रविन्द्र मंच, जयपुर कार्यरत है।

भाषाओं के विकास के लिए उर्दू, ब्रज, सिन्धी, पंजाबी, अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी एवं राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कार्यरत है।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर राजपूताना की भूतपूर्व रियासतों के 55 लाख ऐतिहासिक व रेवेन्यू अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कर उनका विभागीय वेबसाइट के जरिये आन-लाइन कर देश का प्रथम ई-अभिलेखाकार बन गया है। प्रदेश के 220 स्वतंत्रता सेनानियों की सचित्र दीर्घा का निर्माण करवाया गया है।

राजस्थान गौरवशाली एवं प्रेरणादायक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर वाला प्रदेश है। धरोहरों के सतत एवं समयाबद्ध संरक्षण एवं विकास हेतु ''राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण (RHPPA)'' के द्वारा मीरा बाई स्मारक मेड़ता, हाड़ी रानी स्मारक सलूम्बर, महाराजा सूरजमल स्मारक भरतपुर तथा वीर अमरसिंह राठौड़ पेनोरमा पूर्ण किये जाकर चालू कर दिये गये हैं। लोकदेवता तेजाजी का पेनोरमा, खरनाल, नागौर, गुरुवार जम्भेश्वर पेनोरमा, पीपासर, नागौर व गोगाजी के पेनोरमा, गोगामेड़ी के विस्तार का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है।

राणा सांगा स्मारक, खानवा, साहवा सरोवर, जिला चूरू, गोविन्द गुरुवार स्मृति धाम, मानगढ़, जिला बांसवाड़ा, नर्बदेश्वर धाम, सीलू, जिला जालौर, बूढा पुष्कर में फीडर निर्माण, श्री करणी माताजी का पेनोरमा, देशनोक

जिला बीकानेर लोक देवता रामवदेजी का पेनोरमा, रामदेवरा जिला जैसलमेर सुगाली माता की प्रतिमा सहित स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा, आउवा जिला पाली के पेनोरमा के निर्माण एवं विस्तार के कार्य प्रगति पर हैं।

आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बांदीकुई (दौसा) स्थित चर्च पर 81.06 लाख एवं टाटगढ़ (अजमेर) स्थित चर्च पर 97.15 लाख रुपये के विकास कार्यों के अलावा कुल 322.07 लाख रुपये के संरक्षण एवं पर्यटन विकास कार्य सम्पादित करवाये गये हैं।

रामगढ़ शेखावाटी में हैरिटेज क्लस्टर के विकास कार्यों पर 324.00 लाख रुपये की लागत के विकास कार्य प्रगति पर हैं।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा प्रदेश स्थित दस संग्रहालयों यथा-अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर, सीकर, कोटा, पाली, चित्तौड़गढ़, जोधपुर एवं झालावाड़ में संरक्षण एवं विकास कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करवायी जाकर कार्य प्रारम्भ करवाये जाने की कार्यवाही जारी है। इस क्रम में अजमेर एवं बीकानेर संग्रहालय में संरक्षण एवं विकास कार्य प्रगति पर है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा राज्य आयोजना मद में सफेद महल (वाटिका एवं महल)- भरतपुर, वैर किला-भरतपुर, प्राचीन अवशेष मउबोरदा-झालावाड़, प्राचीन अवशेष दलहनपुर-झालावाड़ कमलेश्वर महादेव मन्दिर-इन्द्रगढ़ (बून्दी), पटवा हवेली-जैसलमेर, संग्रहालय-बारां, बून्दी एवं माउन्ट आबू में संरक्षण एवं विकास कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (CSS) में स्वीकृत सांभर (जयपुर) का समग्र विकास, गागरोन किला एवं गढ़ पैलेस झालावाड़, डीग किला भरतपुर, बूंदी सर्किट, गोडवाड सर्किट एवं मत्स्य सर्किट तथा कुलधरा (जैसलमेर) में संरक्षण एवं विकास कार्य सम्पादित करवाये गये हैं। इन कार्यों पर फरवरी, 2016 तक 1097.19 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

**भावी योजनाएं :**

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा आगामी वर्ष में चौबुर्जा किला-भरतपुर में 45.50 लाख एवं रानीजी की बावड़ी, बून्दी में 75.00 लाख रुपये के लागत कार्य प्रारम्भ करवाये जायेंगे। आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नाहरगढ़, अलबर्ट हाल, जंतर-मंतर, हवामहल, विद्याधर का बाग, सिसोदिया रानी का बाग एवं परियों के बाग के विकास एवं संधारण के लिए आगामी वर्ष में 22 करोड़ 60 लाख रुपये का व्यय भी किया जाना प्रस्तावित है।

इसके साथ ही पर्यटन विभाग की परियोजना के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आमेर महल काम्प्लैक्स, आमेर स्थित सागर परिसर में पर्यटन की दृष्टि से विकास के तहत राशि रुपये 1642.90 लाख की लागत के विकास कार्य, भरतपुर के 12 दस्तावेजों के संरक्षण एवं विकास कार्य राशि 485.45 लाख एवं मेवाड़ काम्प्लैक्स में 767.23 लाख रुपये के विकास कार्य सम्पादित करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आगामी वर्ष में निम्नलिखित कार्य करवाये जायेंगे।

शौर्य उद्यान, झुन्झुनूं, संत सुन्दरदास जी का पेनोरमा, दौसा, हाड़ौती पेनोरमा, बारां, लोकदेवता पीपा जी का पेनोरमा, झालावाड़, संत रैदास का पेनोरमा, चित्तौड़गढ़, पाबूजी का पेनोरमा, कोलू जिला जोधपुर, नागरीदास जी का पेनोरमा, किशनगढ़ जिला अजमेर, राष्ट्रीय आदिवासी संग्रहालय, मानगढ़ जिला बांसवाडा, पन्ना धाय पेनोरमा, कमेरी, जिला राजसमंद, हसन खां मेवाती का पेनोरमा, अलवर, कालीबाई का पेनोरमा, माण्डावा जिला डूंगरपुर, बप्पारावल का पेनोरमा, मठाठा जिला उदयपुर, महाराणा राजसिंह पेनोरमा, राजसमंद, महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का पेनोरमा, भीनमाल, जिला जालौर एवं धन्ना भगत पेनोरमा, जिला टोंक के कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर को केन्द्र प्रवृर्तित योजनान्तर्गत राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त 75.00 लाख रुपये से जयपुर, जोधपुर व अजमेर के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं माइक्रोफिल्मिंग के कार्य आगामी वर्ष में करवाये जायेंगे।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में उपलब्ध महत्वपूर्ण दस्तावेजों को शोधकर्ताओं, पर्यटकों एवं आमजन के लिए प्रदर्शित करने के लिए आगामी वर्ष में 10 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से एक museum की स्थापना की जायेगी।

जवाहर कला केन्द्र, जयपुर द्वारा आगामी ववर्ष में साहित्य, दृश्य-कला एवं फिल्म तथा प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को अन्तरराष्ट्रीय स्तर के visual and performing arts जैसे थियेटर, संगीत एवं नृत्य का केन्द्र बनाने के लिए आगामी वर्ष में कुल 7 करोड़ रुपये के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

Rajasthan Oriental Research Institute जोधपुर में प्राचीन दुर्लभ सचित्र हस्तलिखित ग्रंथों का अमूल्य संग्रह है। इस दुर्लभ सांस्कृतिक धरोहर की पहुंच आमजन तक हो सके, इस हेतु संग्रहालय में ग्रंथों एवं चित्रों को सुसज्जित किया जायेगा। इस हेतु इस केन्द्र में 30 हजार पुस्तकों का अध्ययन करने हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से आधुनिक संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना आगामी वर्ष में की जायेगी।

कथक नृत्य की प्राचीन एवं शास्त्रीय शैली में जयपुर घराना अपनी पृथक महत्वपूर्ण पहचान रखता है। नृत्य की इस शैली के संवर्धन हेतु जयपुर कथक केन्द्र परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आगामी वर्ष में 1 करोड़ 65 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

संस्कृत भाषा एवं उसके साहित्य के विकास एवं प्रोत्साहन के लिये राजस्थान संस्कृत अकादमी, गणगौरी बाजार, जयपुर में इसके भवन को वैदिक हेरिटेज, पांडुलिपि संरक्षण एवं शोध केन्द्र के रूप में संचालित करने हेतु इस हेतु आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाती हूं कि राजस्थान का कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास है, इसको संरक्षित और समृद्ध बनाये रखने हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके लगातार प्रयत्नशील रहने से राजस्थान सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का सार्थक प्रयास करेगी।

# परिशिष्ट-4

## लिखित वक्तव्य

## श्री गजेन्द्र सिंह (उद्योग मंत्री) का मांग संख्या 24 के जवाब में सदन पटल पर रखा गया लिखित वक्तव्य

खेल विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आगामी वर्ष की कार्य योजना के तहत पूरे राज्य में व्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप से आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित कर अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है। युवाओं एवं विशेष रूप से बालिकाओं में शिक्षा के साथ-साथ खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं चारित्रिक विकास, साहस एवं तकनीकी दक्षता पैदा करना विभाग का ध्येय है।

**विभाग द्वारा अर्जित प्रमुख उपलब्धियां :-**

- खेल संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। वर्तमान में राज्य स्तर पर दैनिक भत्ता 200 रु. के स्थान पर 300 रु. तथा राष्ट्रीय स्तर पर 300 रु. के स्थान पर 500 रु. दिया जा रहा है।
- अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा 3 खेलों-बास्केटबाल, फुटबाल व हाकी में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
- क्रीड़ा परिषद के पास 119 विशेषज्ञ खेल प्रशिक्षक उपलब्ध हैं, जो पर्याप्त नहीं थे, अतः अनुबंध पर 207 अल्पकालिक प्रशिक्षक नियुक्त कर प्रशिक्षण मुहैया करवाया जा रहा है।
- सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर को हरा-भरा बनाने हेतु विभिन्न किस्मों के एक हजार पेड़-पौधे लगाये गये हैं।
- जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश अकादमी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका शिलान्यास माननीय खेलमंत्री महोदय द्वारा किया जा चुका है।
- सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में 15-16 क्रिकेट नेट्स का कार्य भी प्रगति पर है।
- सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में जागिंग ट्रैक् का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है।
- राज्य के सभी सम्भागों, जिलों एवं पंचायत स्तर पर पे एण्ड प्ले स्कीम लागू की जा चुकी है।

- राज्य के प्रतिष्ठि महाराणा प्रताप पुरस्कार'' की घोषणा की गई, जिसमें कुल 34 खिलाड़ियों को इन पुरस्कारों के लिए चयन किया गया।
- राज्य में 05 खेलों तीरंदाजी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, बास्केटबाल एवं हॉकी में टैंलेंट सर्च योजना।
- समर व विंटर ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को रु. 75 लाख, रजत को रु. 50 लाख एवं कांस्य को रु. 30 लाख की पुरस्कार राशि। एशियाई खेलों व कामनवैल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को रु. 30 लाख, रजत को रु. 20 लाख एवं कांस्य को रु. 10 लाख की पुरस्कार राशि।
- इन पदक विजेताओं को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 220 वर्गमीटर के आवासीय भूखण्ड का नि:शुल्क आबंटन।
- स्वर्ण पदक विजेता को क्लास-2 तथा रजत व कांस्य पदक विजेता को क्लास-3 के पदों पर पुलिस व खेलकूद विभाग में उपरोक्त पदों की पात्रता पूर्ण होने पर नौकरी।
- युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सम्भाग, जिला व तहसील स्तर पर आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित करने हेतु समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 चलाया जा रहा था। राज्य में पंचायत एवं ग्राम स्तर पर आधारभूत खेल सुविधाएं विकसित करने हेतु इस वर्ष समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2015 लागू किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक सम्भाग, जिला, तहसील व ग्राम पंचायत स्तर पर खेल स्टेडियम निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का प्रावधान रखा गया है।
- बालिकाओं के लिए Self Defence Training Programme ''सक्षम'' आत्मरक्षा कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में 564 विद्यालयों में किया गया, जिसमें 1.50 लाख बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इससे पूर्व गत वर्ष जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया था। इस प्रकार अब तक सक्षम कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.60 लाख बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- राजस्थान युवा बोर्ड, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार के तत्वाधान में राजस्थान में पहली बार ब्लाक, जिला, सम्भाग व

राज्य स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। ''राज्य स्तरीय युवा महोत्सव (Cultural Youth Talent Search)'' का आयोजन जयपुर में 21 व 22 दिसम्बर, 2015 को किया गया, जिसमें युवा प्रतिभाओं का चयन कर उनहें ''युवा कला रत्न पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया।

**आगामी वर्ष की प्रमुख कार्य योजनाएं :-**

- सवाई मानसिंह स्टेडियम में 500 खिलाडियों के ठहरने के लिए बहुमंजिला आधुनिक खेल भवन का 10 करोड़ रु. की लागत से निर्माण।
- 14 खेलों में जयपुर में वार्षिक खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन। इस हेतु रु. 3.34 करोड़ का व्यय।
- राज्य स्तरीय खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के श्रेष्ठ खिलाड़ियों का खेल प्रतिभा खोज योजना के तहत चयन होगा। इन खिलाड़ियों को एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति भी दी जावेगी। इस हेतु रु. 3 करोड़ का व्यय होगा।
- राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाडियों के लिए आउट-आफ-टर्न सीधे आवेदन के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में नीति बनाई जावेगी।
- पंचायत समिति बापिनी (जोधपुर), खींवसर (नागौर), सुन्हैल (झालावाड़), ग्राम भांकरवास (पाली) एवं सीसवाली (बारां) में इन्डोर हाल का निर्माण। इस हेतु रु. 4 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य के विभिन्न स्टेडियमों में निर्माण कार्यों हेतु रु. 17.41 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य में उच्च स्तरीय खेल सुविधायें विकसित करने के लिए निजी जन-सहभागिता के आधार पर खेल अकादमियों की स्थापना की योजना।
- बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना 3 वर्ष के लिए।
- कबड्डी एवं हाकी खेलों में राज्य स्तर की टीमों को बेहतर कोचिंग एवं सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु इन खेलों में से एक-एक राज्य स्तरीय टीम को रीको एवं आर.एस.एम.एम. लि. द्वारा स्पान्सरशिप।